भारतीय रिज़र्व बैंक

बुलेटिन

फरवरी 2025

खंड 79 अंक 2

संपादक समिति
मनीष कपूर
अजीत आर जोशी
रेखा मिश्र
प्रज्ञा दास
सुनिल कुमार
स्नेहल हेरवाडकर
पंकज कुमार
वी. धन्या
श्वेता कुमारी
अनिर्बन सान्याल
सुजाता कुंडू

संपादक
जी. वी. नथनएल

भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन संपादकीय समिति के
निर्देशन में आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा
मासिक आधार पर प्रकाशित की जाती है।
इसमें व्यक्त व्याख्याओं और विचारों के लिए
बैंक का केंद्रीय निदेशक मंडल उत्तरदायी नहीं है।
हस्ताक्षरित आलेखों में व्यक्त विचारों के लिए
लेखक स्वयं उत्तरदायी हैं।

© भारतीय रिज़र्व बैंक 2025

सर्वाधिकार सुरक्षित।
सामग्री के पुनः उत्पादन की अनुमति है,
बशर्ते स्रोत का उल्लेख किया जाए।

बुलेटिन की सदस्यता के लिए कृपया 'हाल के प्रकाशन' खंड देखें।

भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन को
https://bulletin.rbi.org.in पर देखा जा सकता है।

विषय-वस्तु

द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य (फरवरी 7, 2025)

गवर्नर का वक्तव्य: फरवरी 7, 2025 1

मौद्रिक नीति वक्तव्य 2024-25 मौद्रिक नीति समिति का संकल्प 5 से 7 फरवरी 2025 7

विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य 9

भाषण

देयता प्रबंधन में चुनौतियां: संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता 11
एम. राजेश्वर राव

आलेख

अर्थव्यवस्था की स्थिति 19

केंद्रीय बजट 2025-26: एक आकलन 67

भारत में सार्वजनिक व्यय की गुणवत्ता और उसका सामाजिक-आर्थिक प्रभाव 83

कृषि आपूर्ति शृंखला की गतिविधियां: रबी विपणन सत्र के दौरान
अखिल भारतीय सर्वेक्षण से प्राप्त अंतर्दृष्टि 99

वर्तमान सांख्यिकी **117**

हाल के प्रकाशन **167**

मौद्रिक नीति वक्तव्य
(5-7 फरवरी) 2024-25

गवर्नर का वक्तव्य

*गवर्नर का वक्तव्य**

संजय मल्होत्रा

मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक इस महीने की 5, 6 और 7 तारीख को संपन्न हुई। आपको यह विदित हैं कि एमपीसी की बैठक के पश्चात गवर्नर के वक्तव्य में न केवल नीतिगत दर और रुख के संबंध में एमपीसी का संकल्प शामिल होता है, बल्कि अन्य घोषणाएं और उपाय भी शामिल होते हैं, जिनका मौद्रिक और विनियामक नीतियों पर असर पड़ता है। एमपीसी का संकल्प निश्चित रूप से विभिन्न क्षेत्रों के लोगों की रुचि का विषय है, क्योंकि यह देश के लगभग सभी नागरिकों के जीवन को प्रभावित करता है। यह संकल्प एमपीसी के औचित्य और विचार प्रक्रिया को भी परिलक्षित करता है, और यह व्यवसायों, अर्थशास्त्रियों, शिक्षाविदों और वित्त जगत के लिए प्रासंगिक होता है। एमपीसी से संबंधित इन घोषणाओं के अलावा, गवर्नर का वक्तव्य रिज़र्व बैंक के लिए अपनी प्राथमिकताओं को उजागर करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है, जिस पर वह चाहता है कि विनियमित संस्थाएं अपना ध्यान केंद्रित करें। यह हितधारकों के लिए समस्या और चुनौतियों के क्षेत्रों को इंगित करने का अवसर है, जिस पर वे अपना ध्यान केंद्रित कर सकें। यह रिज़र्व बैंक के लिए महत्वपूर्ण रुचिकर क्षेत्रों पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर है। मैं विस्तृत वक्तव्य की इस प्रथा को जारी रखूँगा।

एमपीसी के संकल्प पर बोलने से पहले, मैं लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (एफआईटी) ढांचे के अनुभव पर अपने विचार प्रकट करना चाहूँगा, जिसे वर्ष 2016 में आरंभ किया गया था और 2021 में इसकी समीक्षा की गई। मेरा मानना है कि इन वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए इसका प्रदर्शन बेहतर रहा है, जिसमें महामारी के बाद की चुनौतीपूर्ण अवधि भी शामिल है। एफआईटी की शुरूआत के बाद से औसत मुद्रास्फीति कम रही है। इसके अलावा, सीपीआई मुद्रास्फीति अपनी शुरुआत से ही ऊपरी सहन-सीमा बैंड को पार करने के कुछ अवसरों को छोड़कर, ज्यादातर लक्ष्य के अनुरूप ही रही है। हम उभरती हुई संवृद्धि-मुद्रास्फीति गतिकी का प्रतिउत्तर देते हुए, ढांचे में निहित लचीलेपन का उपयोग करके अर्थव्यवस्था के सर्वोत्तम हित में समष्टि-आर्थिक परिणामों में सुधार करना जारी रखेंगे। इसके अलावा, हम नए डेटा का और अधिक उपयोग करके, प्रमुख समष्टि-आर्थिक चरों के तात्कालिक पूर्वानुमान और भावी अनुमान में सुधार करके तथा अधिक मजबूत मॉडल विकसित करके इस ढांचे के आधारभूत संरचना को और अधिक समृद्ध करने का प्रयास करेंगे।

विनियामक पक्ष पर, मैं यह उल्लेख करना चाहूँगा, विशेष रूप से चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर), बैंकों द्वारा प्रावधानीकरण के लिए अपेक्षित ऋण हानि (ईसीएल) ढांचा और कार्यान्वयन के तहत परियोजनाओं को नियंत्रित करने वाले विवेकपूर्ण मानदंडों से संबंधित कुछ प्रस्तावित विनियामक परिवर्तनों के संदर्भ में, कि हम अर्थव्यवस्था के समग्र हित में विवेकपूर्ण और आचरण-संबंधी विनियामक ढांचे को मजबूत, युक्तिसंगत और समृद्ध करना जारी रखेंगे। अर्थव्यवस्था के हित में वित्तीय स्थिरता और उपभोक्ता संरक्षण आवश्यक है। हमारा काम दोनों को बढ़ाना है। साथ ही, आर्थिक हित के लिए कौशल विकास भी आवश्यक है, जो हमारा कर्तव्य भी है। हम मानते हैं कि जिस तरह भोजन मुफ्त में नहीं मिलता, उसी तरह स्थिरता और उपभोक्ता संरक्षण बढ़ाने के लिए विनियमन भी लागत से रहित नहीं है। स्थिरता और दक्षता के बीच एक समझौता होता है। हम विनियमन तैयार करते समय इस समझौता को ध्यान में रखेंगे। हमारा प्रयास प्रत्येक विनियमन के लाभ और लागत को ध्यान में रखते हुए सही संतुलन बनाना होगा। मैं सभी हितधारकों को यह भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम विनियमन बनाने में परामर्शी प्रक्रिया जारी रखेंगे। हितधारकों के सुझाव मूल्यवान हैं और हम कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले उन पर गंभीरता से विचार करेंगे। हम यह भी सुनिश्चित करेंगे कि ऐसे विनियमों का कार्यान्वयन सुचारू रूप से हो; हम परिवर्तन के लिए पर्याप्त समय देंगे और जहां विनियमों का बड़ा प्रभाव पड़ता है, वहां कार्यान्वयन चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा।

वैश्विक आर्थिक पृष्ठभूमि चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। वैश्विक अर्थव्यवस्था ऐतिहासिक औसत[1] से निम्न गति से बढ़ रही है, भले ही उच्च आवृत्ति संकेतक व्यापार में निरंतर विस्तार[3] के

* गवर्नर का वक्तव्य: 7 फरवरी 2025।

[1] वर्ल्ड इकोनोमिक आउटलुक अपडेट, आईएमएफ (जनवरी 2025) के अनुसार, 2025 और 2026 दोनों में वैश्विक संवृद्धि दर 3.3 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जो ऐतिहासिक (2000-19) औसत 3.7 प्रतिशत से कम है।

[3] जनवरी 2025 में 51.8 पर वैश्विक समग्र पीएमआई, सेवा क्षेत्र की गतिविधि में कमी के बावजूद विस्तार क्षेत्र में बनी रही। वैश्विक विनिर्माण पीएमआई 50.1 पर रहा, जो छह महीने के संकुचन के बाद विस्तार क्षेत्र में वापस आ गया।

साथ आघात-सहनीयता[2] का संकेत देते हैं। वैश्विक अवस्फीति संबंधी प्रगति रुक रही है, जो सेवाओं की मूल्य मुद्रास्फीति से बाधित है।

अमेरिका में ब्याज दरों में कटौती के आकार और गति पर उम्मीदें कम होने के साथ, अमेरिकी डॉलर मजबूत हुआ है और बॉण्ड प्रतिफल में भी तेजी आई है। उभरते बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) में बड़े पैमाने पर पूंजी का बहिर्वाह देखा गया है, जिससे उनकी मुद्राओं का मूल्य तेजी से कम हुआ है और वित्तीय स्थिति सख्त हुई है। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में मौद्रिक नीति के अलग-अलग प्रक्षेपवक्र, भू-राजनीतिक तनाव और उच्च व्यापार एवं नीतिगत अनिश्चितताओं ने वित्तीय बाजार में अस्थिरता को बढ़ा दिया है। इस तरह के अनिश्चित वैश्विक माहौल ने ईएमई के लिए मुश्किल नीतिगत ट्रेड-ऑफ उत्पन्न कर दिया है।

भारतीय अर्थव्यवस्था, हालांकि मजबूत और आघात-सह बनी हुई है, लेकिन इन वैश्विक चुनौतियों से भी अछूती नहीं रही है, क्योंकि हाल के महीनों में भारतीय रुपया मूल्यह्रास दबाव में रहा है।[4] रिज़र्व बैंक में, हम बहुआयामी चुनौतियों का सामना करने के लिए अपने पास उपलब्ध सभी टूल्स का उपयोग कर रहे हैं।

मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के निर्णय

इस पृष्ठभूमि में, उभरती हुई समष्टि-आर्थिक और वित्तीय गतिविधियों तथा आर्थिक संभावना के विस्तृत मूल्यांकन के बाद, एमपीसी ने सर्वसम्मति से नीतिगत रेपो दर को 6.50 प्रतिशत से 25 आधार अंक घटाकर 6.25 प्रतिशत करने का निर्णय लिया। परिणामस्वरूप, स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) दर 6.00 प्रतिशत तथा सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और बैंक दर 6.50 प्रतिशत होगी। एमपीसी ने सर्वसम्मति से 'तटस्थ' रुख जारी रखने तथा संवृद्धि को समर्थन प्रदान करते हुए मुद्रास्फीति को लक्ष्य के साथ टिकाऊ आधार पर संरेखित करने पर स्पष्ट रूप से ध्यान केंद्रित करने का भी निर्णय लिया।

मैं संक्षेप में इस निर्णय के औचित्य को बताऊंगा। एमपीसी ने इस बात को ध्यान में रखा कि मुद्रास्फीति में गिरावट आई है। खाद्य पदार्थों पर अनुकूल संभावना और पिछले मौद्रिक नीति कार्रवाइयों के निरंतर प्रसारण के समर्थन से, 2025-26 में इसके और कम होने की उम्मीद है, जो धीरे-धीरे लक्ष्य के अनुरूप हो जाएगा। एमपीसी ने यह भी कहा कि हालांकि 2024-25 की दूसरी तिमाही के निचले स्तर से संवृद्धि में सुधार की उम्मीद है, लेकिन यह पिछले वर्ष की तुलना में काफी कम है। ये संवृद्धि-मुद्रास्फीति गतिकी, एमपीसी के लिए संवृद्धि को समर्थन देने हेतु नीतिगत अवसर प्रदान करती है, जबकि मुद्रास्फीति को लक्ष्य के साथ संरेखित करने पर ध्यान केंद्रित करती है। तदनुसार, एमपीसी ने नीतिगत रेपो दर को 25 आधार अंकों से घटाकर 6.25 प्रतिशत करने का निर्णय लिया।

साथ ही, वैश्विक वित्तीय बाजारों में अत्यधिक अस्थिरता और वैश्विक व्यापार नीतियों के बारे में निरंतर अनिश्चितताओं के साथ-साथ प्रतिकूल मौसम की घटनाओं ने संवृद्धि और मुद्रास्फीति की संभावना के लिए जोखिम उत्पन्न किया है। इसके लिए एमपीसी को सतर्क रहने की आवश्यकता है। तदनुसार, तटस्थ रुख जारी रखने का निर्णय लिया। इससे एमपीसी को उभरते समष्टि-आर्थिक माहौल पर प्रतिक्रिया करने के लिए लचीलापन मिलेगा।

संवृद्धि और मुद्रास्फीति का आकलन

संवृद्धि

पहले अग्रिम अनुमानों के अनुसार, चालू वर्ष के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की संवृद्धि दर 6.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष 8.2 प्रतिशत की मजबूत संवृद्धि के बाद सौम्य वृद्धि है।[5] आगे चलकर, आने वाले वर्ष में आर्थिक गतिविधि में सुधार की उम्मीद है। जलाशयों के बेहतर स्तर[6] और बेहतर रबी संभावनाओं[7] के कारण कृषि गतिविधि में तेजी बनी हुई है। इस वर्ष की दूसरी छमाही में और उसके बाद विनिर्माण

[2] सीपीबी नीदरलैंड्स, वर्ल्ड ट्रेड मॉनिटर के अनुसार नवंबर में विश्व वस्तु व्यापार की मात्रा में 3.6 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई।

[4] 6 नवंबर 2024, जिस दिन अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के परिणाम घोषित किए गए थे, से लेकर अब तक भारतीय रुपये (आईएनआर) में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 3.2 प्रतिशत की गिरावट आई है, जो मोटे तौर पर इसी अवधि के दौरान डॉलर सूचकांक में 2.4 प्रतिशत की वृद्धि को प्रतिबिंबित करता है।

[5] खनन एवं उत्खनन, विनिर्माण, तथा बिजली, गैस एवं जलापूर्ति के जीवीए में 2024-25 में क्रमशः 2.9 प्रतिशत, 5.3 प्रतिशत तथा 6.8 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है। वास्तविक निवेश के प्रमुख घटक, सकल स्थायी पूंजी निर्माण (जीएफसीएफ) में पिछले वर्ष की 9.0 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में 6.4 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है। निजी अंतिम उपभोग व्यय (पीएफसीई) में 2024-25 में 7.3 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि का अनुमान है, जबकि पिछले वर्ष यह 4.0 प्रतिशत थी। कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों का जीवीए पिछले वर्ष के 1.4 प्रतिशत से बढ़कर 2024-25 में 3.8 प्रतिशत हो गया। अप्रैल-दिसंबर 2024 के दौरान, थोक दोपहिया वाहनों की बिक्री में 11.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। अप्रैल-जनवरी 2024-25 के दौरान मनरेगा के तहत काम की मांग में 9.2 प्रतिशत की कमी आई।

[6] 30 जनवरी, 2025 तक 155 प्रमुख जलाशयों में अखिल भारतीय जल भंडारण कुल क्षमता का 64 प्रतिशत है, जबकि एक वर्ष पहले यह 52 प्रतिशत था और दशकीय औसत 55 प्रतिशत था।

[7] 31 जनवरी 2025 तक रबी की बुवाई पिछले वर्ष के स्तर के साथ-साथ सामान्य बुवाई क्षेत्रफल से क्रमशः 1.5 प्रतिशत और 4.1 प्रतिशत अधिक हो चुकी है।

गतिविधि में धीरे-धीरे सुधार होने की उम्मीद है।[8] तीसरी तिमाही के शुरुआती कॉर्पोरेट नतीजों से विनिर्माण क्षेत्र में हल्की बहाली का संकेत मिलता है।[9] खनन और बिजली क्षेत्र दूसरी तिमाही में मानसून संबंधी व्यवधानों से उबर रहे हैं। पीएमआई विनिर्माण भावी उत्पादन सूचकांक से पता चलता है कि व्यावसायिक उम्मीदें आशावादी बनी हुई हैं।[10] सेवा क्षेत्र की गतिविधि आघात-सह बनी हुई है।[11] हालाँकि, पीएमआई सेवाओं में अपने हाल के शिखर से गिरावट आई है।[12]

मांग पक्ष पर, ग्रामीण मांग में लगातार वृद्धि हो रही है, जबकि शहरी खपत में कमी बनी हुई है, तथा उच्च आवृत्ति संकेतक मिश्रित संकेत दे रहे हैं।[13] आगे चलकर, रोजगार की स्थिति में सुधार,[14] केंद्रीय बजट में कर राहत, तथा मुद्रास्फीति में कमी,[15] साथ ही स्वस्थ कृषि गतिविधि घरेलू खपत के लिए शुभ संकेत हैं। सरकारी उपभोग व्यय के सौम्य बने रहने की उम्मीद है।[16] उच्च क्षमता उपयोग स्तर,[17] मजबूत कारोबारीअपेक्षाएँ[18] और सरकारी नीति समर्थन निश्चित निवेश में वृद्धि के लिए शुभ संकेत हैं।[19] सेवा निर्यात में निरंतर उछाल वृद्धि को समर्थन देगा।[20] हालांकि, वैश्विक प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण संभावना में अनिश्चितता बनी हुई है और इससे गिरावट का जोखिम बना हुआ है। इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए, अगले वर्ष के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि 6.7 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जिसमें पहली तिमाही में 6.7 प्रतिशत, दूसरी तिमाही में 7.0 प्रतिशत, तीसरी तिमाही में 6.5 प्रतिशत और चौथी तिमाही में 6.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है। जोखिम समान रूप से संतुलित हैं।

मुद्रास्फीति

अक्तूबर में ऊपरी सहन-सीमा बैंड से ऊपर जाने के बाद, हेडलाइन मुद्रास्फीति ने नवंबर और दिसंबर में क्रमिक रूप से नरमी दर्ज की है।[21] आगे चलकर, खाद्य मुद्रास्फीति के दबाव, आपूर्ति पक्ष के किसी भी आघात के अभाव में, अच्छे खरीफ उत्पादन,[22] सर्दियों में सब्जियों की कीमतों में कमी[23] और अनुकूल रबी फसल की संभावनाओं के कारण उल्लेखनीय सौम्यता देखने को मिलेगी। मूल मुद्रास्फीति में वृद्धि की उम्मीद है, लेकिन यह मंद रहेगी। वैश्विक वित्तीय बाजारों में बढ़ती अनिश्चितता के साथ-साथ ऊर्जा की कीमतों में निरंतर उतार-चढ़ाव और प्रतिकूल मौसम की घटनाओं ने मुद्रास्फीति प्रक्षेपवक्र के लिए ऊर्ध्वगामी जोखिम को बढ़ा दिया है।[24] इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए, चालू वित्त वर्ष के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति चौथी तिमाही में 4.4 प्रतिशत के साथ 4.8 प्रतिशत रहने का अनुमान है। सामान्य मानसून को मानते हुए, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति 4.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जिसमें पहली तिमाही में 4.5

[8] पेट्रोलियम उत्पादों, लौह एवं इस्पात तथा सीमेंट कंपनियों के कमजोर परिणामों के कारण 2024-25 की दूसरी तिमाही में विनिर्माण जीवीए वृद्धि में कमी आई।

[9] 393 सूचीबद्ध निजी विनिर्माण कंपनियों के परिचालन लाभ में 2024-25 की तीसरी तिमाही के दौरान 0.9 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की मामूली वृद्धि हुई, जबकि 2024-25 की दूसरी तिमाही में 5.4 प्रतिशत की गिरावट देखी गई थी।

[10] जनवरी 2025 में पीएमआई विनिर्माण भावी उत्पादन सूचकांक दिसंबर 2024 में 62.5 से बढ़कर 65.1 हो गया। अप्रैल 2023 से भावी उत्पादन सूचकांक 60.0 से ऊपर रह रहा है।

[11] दिसंबर 2024 में ई-वे बिल में 17.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। जनवरी 2025 के दौरान जीएसटी राजस्व में 12.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई और टोल संग्रह में 14.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। दिसंबर 2024 में पेट्रोलियम उत्पादों की खपत में 2.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 24 जनवरी 2025 तक कुल बैंक ऋण और जमाराशियों में क्रमशः 12.5 प्रतिशत और 10.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

[12] जनवरी 2025 के लिए पीएमआई सेवाएं दिसंबर 2024 में 59.3 से घटकर 56.5 हो गईं।

[13] दिसंबर 2024 में घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या में 10.8 प्रतिशत और जनवरी 2025 में अब तक 14.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

[14] त्रैमासिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के अनुसार, शहरी बेरोजगारी दर पिछले वर्ष की इसी तिमाही के 6.6 प्रतिशत से घटकर 2024-25 की दूसरी तिमाही में 6.4 प्रतिशत हो गई।

[15] संयुक्त उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति अक्तूबर 2024 में 6.2 प्रतिशत से घटकर दिसंबर 2024 में 5.2 प्रतिशत हो गई।

[16] केंद्र सरकार के राजस्व व्यय (ब्याज भुगतान और सब्सिडी को छोड़कर) में 2025-26 में 5.0 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है, जबकि 2024-25 में 7.9 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है (संशोधित अनुमान)।

[17] आरबीआई के तिमाही आदेश बही, माल सूची और क्षमता उपयोग (ओबीआईसीयूएस) सर्वेक्षण के अनुसार, विनिर्माण क्षेत्र का मौसमी रूप से समायोजित क्षमता उपयोग (सीयू) 2024-25 की दूसरी तिमाही में 74.7 प्रतिशत पर है, जो दीर्घकालिक औसत 73.8 प्रतिशत से अधिक है।

[18] आरबीआई के औद्योगिक संभावना सर्वेक्षण (आईओएस) के अनुसार, विनिर्माण फर्मों ने 2024-25 की तीसरी तिमाही में मांग की स्थिति में मामूली सुधार का अनुमान लगाया है। इसके अलावा, फर्मों को 2024-25 की चौथी तिमाही में मामूली सुधार और 2025-26 की पहली छमाही में उल्लेखनीय सुधार की उम्मीद है।

[19] केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार, केंद्र सरकार के पूंजीगत व्यय में 2025-26 के दौरान 10.1 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है। प्रभावी पूंजीगत व्यय (पूंजीगत व्यय के लिए राज्य सरकारों को अनुदान सहायता सहित) का वित्तीय वर्ष के दौरान 17.4 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है।

[20] अप्रैल-दिसंबर 2024 के दौरान सेवा निर्यात में 13.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में 5.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी।

[21] अक्तूबर और दिसंबर 2024 के बीच सीपीआई हेडलाइन मुद्रास्फीति 98 आधार अंकों तक कम आई।

[22] 5 नवंबर 2024 को जारी 2024-25 के लिए खरीफ उत्पादन के पहले अग्रिम अनुमानों के अनुसार, चावल उत्पादन में 5.9 प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद है, जबकि 2023-24 की तुलना में 2024-25 में अरहर और मूंग दाल का उत्पादन क्रमशः 2.5 प्रतिशत और 19.8 प्रतिशत अधिक होने की उम्मीद है।

[23] उपभोक्ता मामला विभाग (डीसीए) के उच्च आवृत्ति वाले खाद्य मूल्य आंकड़े जनवरी 2025 में टमाटर, प्याज और आलू की कीमतों में माह-दर-माह महत्वपूर्ण सुधार का संकेत देते हैं।

[24] नवंबर 2024 में भारतीय बास्केट कच्चे तेल की कीमतों में माह-दर-माह लगभग (-) 2.8 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई, जबकि दिसंबर में इसमें 0.4 प्रतिशत की मामूली वृद्धि हुई। जनवरी 2025 में, 80 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल पर भारतीय बास्केट कच्चे तेल की कीमतों में दिसंबर 2024 की तुलना में 9.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

प्रतिशत, दूसरी तिमाही में 4.0 प्रतिशत, तीसरी तिमाही में 3.8 प्रतिशत और चौथी तिमाही में 4.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है। जोखिम समान रूप से संतुलित हैं।

बाह्य क्षेत्र

बाहरी क्षेत्र के संबंध में, भारत का चालू खाता घाटा (सीएडी) पिछले वर्ष की दूसरी तिमाही में जीडीपी के 1.3 प्रतिशत से घटकर इस वर्ष की दूसरी तिमाही में 1.2 प्रतिशत रह गया।[25] विश्व बैंक के अनुसार, 129.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुमानित अंतर्वाह के साथ भारत 2024 में वैश्विक स्तर पर धन प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना रहेगा।[26] इस वर्ष के लिए सीएडी का धारणीय स्तर के भीतर रहने की उम्मीद है। इस वर्ष 31 जनवरी तक, भारत की विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि 630.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी, जो 10 महीने से अधिक के आयात को कवर प्रदान करता है।[27] कुल मिलाकर, भारत का बाह्य क्षेत्र आघात-सह बना हुआ है क्योंकि प्रमुख संकेतक मजबूत बने हुए हैं।[28]

मैं यहाँ यह उल्लेख करना चाहूँगा कि रिज़र्व बैंक की विनिमय दर नीति पिछले कई वर्षों से एक समान रही है। हमारा घोषित उद्देश्य बाजार की कार्यकुशलता से समझौता किए बिना, व्यवस्था और स्थिरता बनाए रखना है। तदनुसार, विदेशी मुद्रा बाजार में हमारा हस्तक्षेप किसी विशिष्ट विनिमय दर स्तर या बैंड को लक्षित करने के बजाय अत्यधिक और विघटनकारी अस्थिरता को कम करने पर केंद्रित है। भारतीय रुपये की विनिमय दर बाजार की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है।

चलनिधि और वित्तीय बाज़ार की स्थितियाँ

जुलाई से नवंबर 2024 तक अधिशेष में रहने के बाद, प्रणालीगत चलनिधि - जैसा कि चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत औसत शुद्ध स्थिति द्वारा मापा जाता है - दिसंबर 2024 और जनवरी 2025 के दौरान घाटे में बदल गई। चलनिधि की निकासी मुख्य रूप से दिसंबर 2024 में अग्रिम कर भुगतान, पूंजी बहिर्वाह, विदेशी मुद्रा परिचालन और इस वर्ष जनवरी में प्रचलन में मुद्रा में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण हुई है।

यह देखा गया है कि कुछ बैंक गैर-संपार्श्विक मांग मुद्रा बाजार में ऋण देने के प्रति अनिच्छुक हैं; इसके बजाय, वे अपनी निधियों को भारतीय रिज़र्व बैंक के पास निष्क्रिय रूप से जमा कर रहे हैं। हम बैंकों से आग्रह करते हैं कि वे गैर-संपार्श्विक मांग मुद्रा बाजार में आपस में सक्रिय रूप से व्यापार करें, ताकि भारित औसत मांग मुद्रा दर (डबल्यूएसीआर) से बेहतर संकेत प्राप्त करने के लिए इसे अधिक गहरा और जीवंत बनाया जा सके।

रिज़र्व बैंक प्रणाली में पर्याप्त प्रणालीगत चलनिधि उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। हमने इस संबंध में कई कदम उठाए हैं।[29] हम उभरती हुई चलनिधि और वित्तीय बाजार स्थितियों पर नजर रखना जारी रखेंगे तथा व्यवस्थित चलनिधि स्थिति सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय रूप से उचित कदम उठाएंगे।

वित्तीय स्थिरता

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के लिए प्रणाली-स्तरीय वित्तीय मापदंड स्वस्थ बने हुए हैं।[30] जनवरी 2025 के अंत में बैंकिंग प्रणाली के लिए ऋण जमा अनुपात (सीडी अनुपात) 80.8 प्रतिशत था, जो मोटे तौर पर 30 सितंबर 2024 के समान था। बैंक के चलनिधि बफर्स पर्याप्त हैं। यद्यपि शुद्ध ब्याज मार्जिन (एनआईएम) में कमी आई है, तथापि परिसंपत्तियों पर रिटर्न (आरओए) और इक्विटी पर रिटर्न (आरओई) मजबूत हैं। एनबीएफसी के लिए प्रणाली -स्तरीय मापदंड भी स्वस्थ हैं।[31]

---

[25] भारत का चालू खाता घाटा (सीएडी) 2023-24 की दूसरी तिमाही के 11.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर (जीडीपी का 1.3 प्रतिशत) से मामूली रूप से कम होकर 2024-25 की दूसरी तिमाही में 11.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर (जीडीपी का 1.2 प्रतिशत) हो गया।

[26] https://blogs.worldbank.org/en/peoplemove/in-2024--remittance-flows-to-low--and-middle-income-countries-ar

[27] चार तिमाहियों की अवधि (2023-24 की तीसरी तिमाही से 2024-25 की दूसरी तिमाही) के दौरान वास्तविक वस्तु आयात (बीओपी आधार पर) के आधार पर।

[28] जीडीपी की तुलना में भारत का बाह्य ऋण अनुपात सितंबर 2024 के अंत में 19.4 प्रतिशत (जून 2024 के अंत में 18.8 प्रतिशत) रहा, जबकि निवल अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति (आईआईपी) जून 2024 के अंत में जीडीपी के (-) 10.3 प्रतिशत से घटकर सितंबर 2024 के अंत में जीडीपी के (-) 9.6 प्रतिशत पर आ गई।

[29] इनमें 16 जनवरी 2025 से दैनिक परिवर्ती दर रेपो नीलामी और जनवरी में खुले बाजार परिचालन (ओएमओ) के माध्यम से 58,835 करोड़ रुपये की सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद शामिल थी। इसके अतिरिक्त, 27 जनवरी 2025 को ओएमओ, विदेशी मुद्रा खरीद-बिक्री स्वैप और आज बाद में आयोजित होने वाले 56-दिवसीय परिवर्ती दर रेपो के माध्यम से टिकाऊ चलनिधि डालने के लिए उपायों के एक पैकेज की घोषणा की गई।

[30] एससीबी मापदंड : 24 जनवरी 2025 तक बकाया ऋण और जमा में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर क्रमशः 11.4 प्रतिशत और 10.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। सितंबर 2024 में 16.7 प्रतिशत का प्रणाली -स्तरीय सीआरएआर, विनियामक न्यूनतम स्तर से काफी ऊपर था। सितंबर 2024 में जीएनपीए अनुपात 2.5 प्रतिशत पर सितंबर 2023 की तुलना में 72 बीपीएस से बेहतर है। सितंबर 2024 में एसएमए-2 अनुपात 0.8 प्रतिशत था। सितंबर 2024 तक एलसीआर 128.6 प्रतिशत था। सितंबर 2024 में आरओए 1.4 प्रतिशत और आरओई 14.6 प्रतिशत था। सितंबर 2024 में एनआईएम 3.5 प्रतिशत थी, जबकि सितंबर 2023 में यह 3.7 प्रतिशत थी।

[31] एनबीएफसी मापदंड: 30 सितंबर 2024 तक एनबीएफसी का कुल सीआरएआर 26.5 प्रतिशत और टियर I सीआरएआर 24.4 प्रतिशत है। जीएनपीए अनुपात सितंबर 2023 में 2.9 प्रतिशत से बढ़कर सितंबर 2024 में 2.6 प्रतिशत हो गया। सितंबर 2023 में 2.9 प्रतिशत से सितंबर 2024 में आरओए सुधरकर 3.2 प्रतिशत हो गया। सितंबर 2023 में 22.5 प्रतिशत की तुलना में सितंबर 2024 में अग्रिमों में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर संवृद्धि 16.4 प्रतिशत रही।

रिज़र्व बैंक वित्तीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 2016 से प्रत्येक वर्ष वित्तीय साक्षरता सप्ताह मना रहा है। पिछले वर्ष, इस अभियान का उद्देश्य युवाओं को सशक्त बनाना था। इस वर्ष, समाज में महिलाओं की महत्वपूर्ण और बहुमुखी भूमिका को मान्यता देते हुए, अभियान में वित्तीय निर्णय लेने और घरेलू बजट बनाने में महिलाओं की भूमिका पर जोर दिया जाएगा। मैं सभी बैंकों से आग्रह करता हूं कि वे इस महीने की 24 तारीख से शुरू होने वाले "वित्तीय साक्षरता: महिला समृद्धि" विषय पर अभियान में सक्रिय रूप से भाग लें।

अतिरिक्त उपाय

अब मैं कुछ अतिरिक्त उपायों की घोषणा करूंगा। उनके कार्यान्वयन के लिए आवश्यक निदेश और परिपत्र अलग से जारी किए जाएंगे।

डिजिटल सुरक्षा

सबसे पहले, वित्तीय सेवाओं के तेजी से डिजिटलीकरण ने सुविधा और दक्षता ला दी है, लेकिन साइबर खतरों और डिजिटल जोखिमों के प्रति जोखिम भी बढ़ा है, जो दिन-प्रतिदिन परिष्कृत होते जा रहे हैं। डिजिटल धोखाधड़ी में वृद्धि चिंता का विषय है, जिसके लिए सभी हितधारकों द्वारा कार्रवाई की आवश्यकता है।

रिज़र्व बैंक बैंकिंग और भुगतान प्रणाली में डिजिटल सुरक्षा बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय कर रहा है। घरेलू डिजिटल भुगतान के लिए प्रमाणीकरण का अतिरिक्त कारक (एएफ़ए) की शुरूआत ऐसा ही एक उपाय है। एएफए को उन अपतटीय व्यापारियों को किए जा रहे ऑनलाइन अंतरराष्ट्रीय डिजिटल भुगतानों तक विस्तारित करने का प्रस्ताव है, जो इस प्रकार के प्रमाणीकरण के लिए सक्षम हैं।

दूसरा, भारतीय रिज़र्व बैंक भारतीय बैंकों के लिए 'bank.in' नामक विशेष इंटरनेट डोमेन लागू करेगा। इस डोमेन नाम का पंजीकरण इस वर्ष अप्रैल से शुरू होगा। इससे बैंकिंग धोखाधड़ी से बचने में मदद मिलेगी। इसके बाद वित्तीय क्षेत्र के लिए 'fin.in' डोमेन बनाया जाएगा।

बैंकों और एनबीएफसी को साइबर जोखिमों को कम करने के लिए निवारक और जासूसी नियंत्रण में निरंतर सुधार करना चाहिए। उन्हें परिचालनगत आघात सहनीयता के लिए, समय-समय पर परीक्षण के माध्यम से सुदृढ़, मजबूत घटना प्रतिक्रिया और पुनर्प्राप्ति तंत्र विकसित करना होगा।

सरकारी प्रतिभूतियों में वायदा संविदाओं का शुभारंभ

तीसरा, पिछले कुछ वर्षों में, हमने बाजार सहभागियों के लिए उपलब्ध ब्याज दर डेरिवेटिव उत्पादों के समूह का विस्तार किया है ताकि वे अपने ब्याज दर जोखिमों का प्रबंधन कर सकें। अब हम इस समूह में सरकारी प्रतिभूतियों में वायदा संविदा को शामिल करेंगे। इससे बीमा निधियों जैसे दीर्घकालिक निवेशकों को ब्याज दर चक्रों में अपने ब्याज दर जोखिम का प्रबंधन करने में सुविधा होगी। इससे उन डेरिवेटिव्स का कुशल मूल्य निर्धारण भी संभव होगा जो अंतर्निहित लिखतों के रूप में सरकारी प्रतिभूतियों का उपयोग करते हैं।

सेबी-पंजीकृत गैर-बैंक दलालों की एनडीएस-ओएम तक पहुंच

चौथा, सरकारी प्रतिभूतियों तक खुदरा निवेशकों की पहुंच बढ़ाने के लिए, रिज़र्व बैंक, सरकारी प्रतिभूतियों में द्वितीयक बाजार लेनदेन के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म एनडीएस-ओएम की पहुंच को सेबी के साथ पंजीकृत गैर-बैंक दलालों तक विस्तारित करेगा।

विभिन्न बाजार खंडों में व्यापार और निपटान समय की समीक्षा

पांचवां, पिछले कुछ वर्षों में वित्तीय बाजारों और बाजार बुनियादी ढांचे में हुए विभिन्न विकासों को देखते हुए, हम विभिन्न हितधारकों के प्रतिनिधित्व के साथ एक कार्य दल का गठन करेंगे, जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित बाजारों के व्यापार और निपटान समय की व्यापक समीक्षा करेगा। दल इस वर्ष 30 अप्रैल तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

समापन टिप्पणियाँ

निष्कर्ष के तौर पर, मौजूदा संवृद्धि-मुद्रास्फीति गतिशीलता को देखते हुए, एमपीसी ने तटस्थ रुख जारी रखते हुए महसूस किया कि वर्तमान समय में कम प्रतिबंधात्मक मौद्रिक नीति अधिक उपयुक्त है। एमपीसी अपनी प्रत्येक भावी बैठक में समष्टि-आर्थिक संभावना के नए मूल्यांकन के आधार पर निर्णय लेगी।

हम मौद्रिक नीति का संचालन करने तथा ऐसे उपाय करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो समय पर, सावधानीपूर्वक मापे गए हों तथा स्पष्ट रूप से संप्रेषित किए गए हों, ताकि अनुकूल समष्टि-आर्थिक स्थितियां बनाई जा सकें, जिससे मूल्य स्थिरता, सतत आर्थिक संवृद्धि तथा वित्तीय स्थिरता को बल मिले।

धन्यवाद। नमस्कार और जय हिन्द।

*मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2024-25 मौद्रिक नीति समिति का संकल्प 5 से 7 फरवरी 2025**

मौद्रिक नीति निर्णय

मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की 53वीं बैठक 5 से 7 फरवरी 2025 तक श्री संजय मल्होत्रा, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक की अध्यक्षता में आयोजित की गई। एमपीसी के सदस्य डॉ. नागेश कुमार, श्री सौगत भट्टाचार्य, प्रो. राम सिंह, डॉ. राजीव रंजन और श्री एम. राजेश्वर राव बैठक में शामिल हुए। वर्तमान और उभरती समष्टि-आर्थिक स्थिति के आकलन के पश्चात, एमपीसी ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि:

- चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को तत्काल प्रभाव से 25 आधार अंक घटाकर 6.25 प्रतिशत किया जाए; परिणामस्वरूप, स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) दर 6.00 प्रतिशत तथा सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और बैंक दर 6.50 प्रतिशत समायोजित हो जाएगी;
- तटस्थ मौद्रिक नीति रुख को जारी रखा जाए और संवृद्धि को समर्थन प्रदान करते हुए मुद्रास्फीति को लक्ष्य के साथ टिकाऊ आधार पर संरेखित करने पर स्पष्ट रूप से ध्यान केंद्रित किया जाए।

ये निर्णय संवृद्धि को समर्थन देते हुए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति के लिए +/- 2 प्रतिशत के दायरे में 4 प्रतिशत के मध्यम अवधि लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य के अनुरूप हैं।

संवृद्धि और मुद्रास्फीति संभावना

वैश्विक अर्थव्यवस्था ऐतिहासिक औसत से कम बढ़ रही है, यद्यपि उच्च आवृत्ति संकेतक विश्व व्यापार में निरंतर विस्तार के बीच आघात-सहनीयता का संकेत दे रहे हैं। विश्व आर्थिक परिदृश्य, अवस्फीति की धीमी गति, भू-राजनीतिक तनाव और नीतिगत अनिश्चितताओं के साथ चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। मजबूत डॉलर ने, अन्य बातों के साथ-साथ, उभरते बाजार मुद्राओं पर दबाव डालना जारी रखा है और वित्तीय बाजारों में अस्थिरता को बढ़ाया है।

घरेलू स्तर पर, प्रथम अग्रिम अनुमान (एफएई) के अनुसार, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) निजी खपत में बहाली के समर्थन से वर्ष 2024-25 में 6.4 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की दर से बढ़ने का अनुमान है। आपूर्ति पक्ष पर, संवृद्धि को सेवा क्षेत्र और कृषि क्षेत्र में बहाली का समर्थन प्राप्त है, जबकि धीमी औद्योगिक संवृद्धि एक बाधा है।

आगे देखते हुए, रबी की अच्छी संभावनाएँ और औद्योगिक गतिविधि में अपेक्षित बहाली से 2025-26 में आर्थिक संवृद्धि को समर्थन मिलना चाहिए। मांग पक्ष के प्रमुख चालकों में से, केंद्रीय बजट 2025-26 में कर राहत से घरेलू खपत के मजबूत बने रहने की आशा है। उच्च क्षमता उपयोग स्तरों, वित्तीय संस्थाओं और कॉरपोरेट्स के मजबूत तुलन-पत्र और पूंजीगत व्यय पर सरकार के निरंतर जोर से समर्थित, नियत निवेश में बहाली की आशा है। रिज़र्व बैंक के उद्यम सर्वेक्षणों और पीएमआई में रेखांकित सकारात्मक कारोबारी मनोभावों से इसकी पुष्टि होती है। आघात-सह सेवा निर्यात से संवृद्धि को समर्थन मिलता रहेगा। तथापि, भू-राजनीतिक तनाव, संरक्षणवादी व्यापार नीतियों, अंतरराष्ट्रीय कमोडिटी कीमतों में उतार-चढ़ाव और वित्तीय बाजार की अनिश्चितताओं से उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थितियां, संभावना के लिए अधोगामी जोखिम उत्पन्न कर रहीं हैं। इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए, 2025-26 के लिए वास्तविक जीडीपी संवृद्धि 6.7 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जो पहली तिमाही में 6.7 प्रतिशत, दूसरी तिमाही में 7.0 प्रतिशत तथा तीसरी और चौथी तिमाहियों में 6.5 प्रतिशत रहेगी (चार्ट 1)। जोखिम समान रूप से संतुलित हैं।

हेडलाइन मुद्रास्फीति अक्तूबर में अपने हाल के शीर्ष-स्तर 6.2 प्रतिशत से नवंबर-दिसंबर 2024 में क्रमिक रूप से कम हुई। सब्जियों की कीमत मुद्रास्फीति के अक्तूबर के उच्च स्तर से नीचे आने के कारण खाद्य मुद्रास्फीति में कमी ने हेडलाइन मुद्रास्फीति में गिरावट को बढ़ावा दिया। सभी वस्तुओं और सेवाओं के घटकों में मूल मुद्रास्फीति कम रही और ईंधन समूह में अवस्फीति जारी रही।

आगे बढ़ते हुए, खाद्य मुद्रास्फीति का दबाव, आपूर्ति पक्ष के किसी भी आघात के अभाव में, अच्छे खरीफ उत्पादन,

* 7 फरवरी 2025 को जारी किया जाएगा।

चार्ट 1: वास्तविक जीडीपी वृद्धि का त्रैमासिक पूर्वानुमान

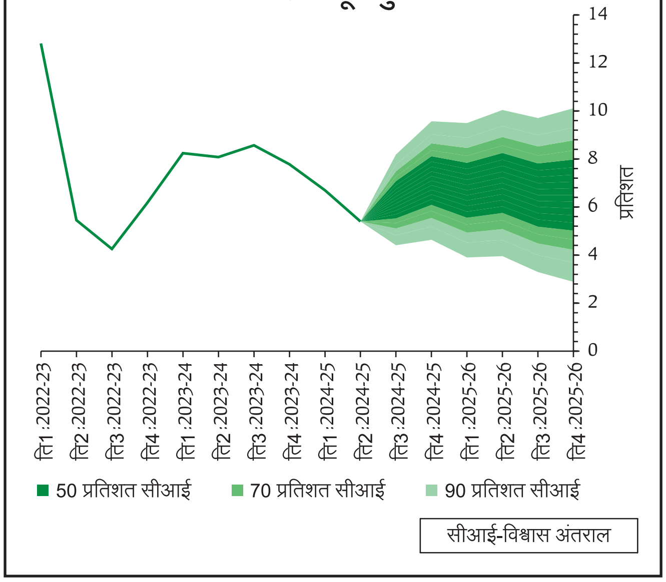

चार्ट 2: सीपीआई मुद्रास्फीति का त्रैमासिक पूर्वानुमान

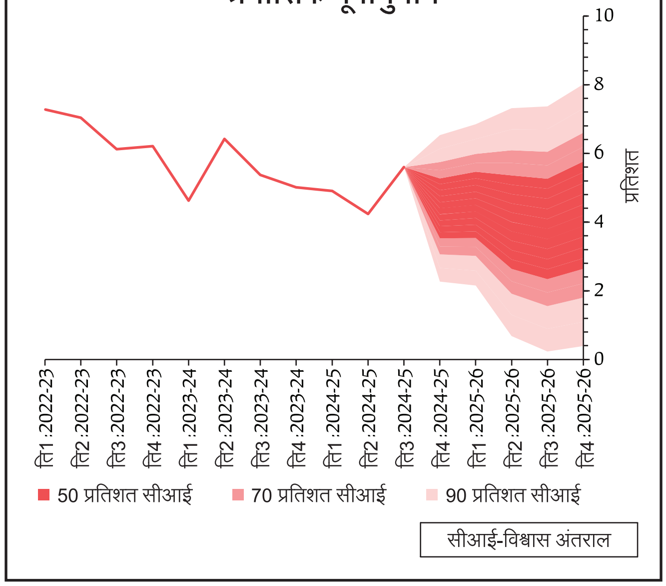

सर्दियों में सब्जियों की कीमतों में कमी और अनुकूल रबी फसल की संभावनाओं के कारण महत्वपूर्ण रूप से कम होना चाहिए। मूल मुद्रास्फीति में वृद्धि की आशा है, लेकिन यह मामूली रहेगी। वैश्विक वित्तीय बाजारों में निरंतर अनिश्चितता के साथ-साथ ऊर्जा की कीमतों में उतार-चढ़ाव और प्रतिकूल मौसम की घटनाओं से मुद्रास्फीति के लिए ऊर्ध्वगामी जोखिम है। इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए, 2024-25 के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति 4.8 प्रतिशत और चौथी तिमाही में 4.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है। अगले वर्ष सामान्य मानसून की परिकल्पना करते हुए, 2025-26 के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति 4.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जो पहली तिमाही में 4.5 प्रतिशत, दूसरी तिमाही में 4.0 प्रतिशत, तीसरी तिमाही में 3.8 प्रतिशत और चौथी तिमाही में 4.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है (चार्ट 2)। जोखिम समान रूप से संतुलित हैं।

मौद्रिक नीति निर्णयों का औचित्य

एमपीसी ने कहा कि मुद्रास्फीति में कमी आई है। खाद्य पदार्थों पर अनुकूल संभावना और पिछली मौद्रिक नीति कार्रवाइयों के निरंतर संचारण के समर्थन से, 2025-26 में इसके और कम होने की आशा है, जो धीरे-धीरे लक्ष्य से संरेखित होगी। एमपीसी ने यह भी कहा कि यद्यपि संवृद्धि के 2024-25 की दूसरी तिमाही के निचले स्तर से बहाली की आशा है, लेकिन यह पिछले वर्ष की तुलना में काफी कम है। ये संवृद्धि-मुद्रास्फीति गतिकी, एमपीसी के लिए मुद्रास्फीति को लक्ष्य के साथ संरेखित करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए संवृद्धि को समर्थन प्रदान करने के लिए नीतिगत स्थान खोलती है। तदनुसार, एमपीसी ने सर्वसम्मति से नीतिगत रेपो दर को 25 आधार अंक घटाकर 6.25 प्रतिशत करने के लिए वोट किया।

साथ ही, वैश्विक वित्तीय बाजारों में अत्यधिक अस्थिरता और वैश्विक व्यापार नीतियों के बारे में निरंतर अनिश्चितताओं के साथ-साथ प्रतिकूल मौसम की घटनाओं ने संवृद्धि और मुद्रास्फीति की संभावना के लिए जोखिम उत्पन्न किया है। इसके लिए एमपीसी को सतर्क रहने की आवश्यकता है। तदनुसार, एमपीसी ने सर्वसम्मति से तटस्थ रुख जारी रखने के लिए वोट किया। इससे एमपीसी को उभरते समष्टि-आर्थिक माहौल पर प्रतिक्रिया करने के लिए लचीलापन प्राप्त होगा।

एमपीसी की इस बैठक का कार्यवृत्त 21 फरवरी 2025 को जारी किया जाएगा।

एमपीसी की अगली बैठक 7 से 9 अप्रैल 2025 के दौरान निर्धारित है।

विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य

यह वक्तव्य (i) वित्तीय बाज़ारों; (ii) साइबर सुरक्षा; और (iii) भुगतान प्रणालियों से संबंधित विभिन्न विकासात्मक और विनियामक नीतिगत उपायों को निर्धारित करता है।

I. वित्तीय बाज़ार

1. सरकारी प्रतिभूतियों में वायदा संविदाओं की शुरुआत

पिछले कतिपय वर्षों में, भारतीय रिज़र्व बैंक, बाजार सहभागियों को उनके ब्याज दर जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए उपलब्ध ब्याज दर डेरिवेटिव (व्युत्पन्न) उत्पादों के समूह का विस्तार कर रहा है। ब्याज दर स्वैप के अलावा, ब्याज दर ऑप्शन, ब्याज दर फ्यूचर्स, ब्याज दर स्वैप्शन, वायदा दर करार आदि जैसे उत्पाद बाजार सहभागियों के लिए उपलब्ध हैं। हमें बाजार के अधिक विकास को सक्षम करने के लिए सरकारी प्रतिभूतियों में वायदा संविदाओं की अनुमति देने की आवश्यकता के बारे में प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई हैं। इस तरह की वायदा संविदाएं, बीमा निधि जैसे दीर्घकालिक निवेशकों को ब्याज दर चक्रों में अपने ब्याज दर जोखिम का प्रबंधन करने में सक्षम बनाएंगे। वे उन डेरिवेटिव के कुशल मूल्य निर्धारण को भी सक्षम करेंगे जो अंतर्निहित लिखतों के रूप में बॉण्ड का उपयोग करते हैं। इस संबंध में निदेश का मसौदा दिसंबर 2023 में जारी किया गया था। अंतिम निदेश, सार्वजनिक प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए, शीघ्र ही जारी किए जाएंगे।

2. सेबी-पंजीकृत गैर-बैंक दलालों की एनडीएस-ओएम तक पहुंच

तयशुदा लेनदेन प्रणाली-ऑर्डर मिलान (एनडीएस-ओएम) सरकारी प्रतिभूतियों में द्वितीयक बाजार लेनदेन के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। वर्तमान में, एनडीएस-ओएम तक पहुंच विनियमित संस्थाओं और बैंकों के ग्राहकों और एकल प्राथमिक व्यापारियों के लिए उपलब्ध है। पहुंच को व्यापक बनाने के उद्देश्य से, यह निर्णय लिया गया है कि सेबी के साथ पंजीकृत गैर-बैंक दलाल अपने ग्राहकों की ओर से सीधे एनडीएस-ओएम एक्सेस कर सकते हैं। ये दलाल इस संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विनियमों और शर्तों के अधीन एनडीएस-ओएम एक्सेस कर सकते हैं। आवश्यक अनुदेश अलग से जारी किए जा रहे हैं।

3. विभिन्न बाजार खंडों में व्यापार और निपटान समय की व्यापक समीक्षा

विभिन्न वित्तीय बाजार खंडों में समकालिक और पूरक बाजार और निपटान समय, कुशल मूल्य निर्धारण और चलनिधि आवश्यकताओं के अनुकूलन के लाभों को सुविधाजनक बना सकते हैं। पिछले कतिपय वर्षों में, ट्रेडिंग के बढ़ते इलेक्ट्रॉनिकीकरण, 24X5 आधार पर विदेशी मुद्रा और कतिपय ब्याज दर डेरिवेटिव बाजारों की उपलब्धता, घरेलू वित्तीय बाजारों में अनिवासियों की बढ़ती सहभागिता और 24X7 आधार पर भुगतान प्रणालियों की उपलब्धता सहित कई विकास हुए हैं। तदनुसार, रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित वित्तीय बाजारों के कारोबार और निपटान समय की व्यापक समीक्षा करने के लिए विभिन्न हितधारकों के प्रतिनिधित्व के साथ एक कार्य दल बनाने का निर्णय लिया गया है। इस कार्य दल द्वारा 30 अप्रैल 2025 तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आशा है।

II. साइबर सुरक्षा

4. 'bank.in' और 'fin.in' डोमेन के माध्यम से वित्तीय क्षेत्र में विश्वास बढ़ाना

डिजिटल भुगतान में धोखाधड़ी के बढ़ते मामले चिंता का विषय हैं। इससे निपटने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) भारतीय बैंकों के लिए 'bank.in' विशिष्ट इंटरनेट डोमेन शुरू कर रहा है। इस पहल का उद्देश्य साइबर सुरक्षा खतरों और फ़िशिंग जैसी धोखाधड़ीपूर्ण गतिविधियों को कम करना है; और, सुरक्षित वित्तीय सेवाओं को सुव्यवस्थित करना है, जिससे डिजिटल बैंकिंग और भुगतान सेवाओं में विश्वास बढ़े। बैंकिंग प्रौद्योगिकी विकास एवं अनुसंधान संस्थान (आईडीआरबीटी) विशिष्ट रजिस्ट्रार के रूप में कार्य करेगा। वास्तविक पंजीकरण अप्रैल 2025 से शुरू होंगे। बैंकों के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश अलग से जारी किए जाएंगे। आगे बढ़ते हुए, वित्तीय क्षेत्र में अन्य गैर-बैंक संस्थाओं के लिए "fin.in" जैसे एक विशिष्ट डोमेन की योजना बनाई गई है।

III. भुगतान प्रणालियाँ

5. सीमा-पारीय कार्ड नॉट प्रेजेंट लेनदेन में प्रमाणीकरण के अतिरिक्त कारक को सक्षम करना

डिजिटल भुगतान के लिए प्रमाणीकरण के अतिरिक्त कारक (एएफए) की शुरूआत ने लेन-देन की सुरक्षा को बढ़ाया है, जिससे ग्राहकों को डिजिटल भुगतान अपनाने का भरोसा मिला है। तथापि, यह आवश्यकता केवल घरेलू लेन-देन के लिए अनिवार्य है।

भारत में जारी किए गए कार्ड का उपयोग करके ऑनलाइन अंतरराष्ट्रीय लेनदेन के लिए समान स्तर की सुरक्षा प्रदान करने के लिए, अंतरराष्ट्रीय कार्ड नॉट प्रेजेंट (ऑनलाइन) लेनदेन के लिए भी एएफए को सक्षम करने का प्रस्ताव है। यह उन मामलों में सुरक्षा का एक अतिरिक्त स्तर प्रदान करेगा जहां विदेशी व्यापारी एएफए के लिए सक्षम है। हितधारकों से प्रतिक्रिया के लिए शीघ्र ही परिपत्र का मसौदा जारी किया जाएगा।

भाषण

देयता प्रबंधन में चुनौतियां: संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता
एम. राजेश्वर राव

देयता प्रबंधन में चुनौतियां: संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता*

एम. राजेश्वर राव

सबसे पहले मैं मिंट बीएफएसआई शिखर सम्मेलन और पुरस्कार के इस 17वें संस्करण में मुझे आमंत्रित करने के लिए आयोजकों को धन्यवाद देता हूँ। मुझे इस कार्यक्रम के दौरान आपके साथ जुड़ने का यह अवसर मिला है जिससे मुझे खुशी हो रही है। बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के विनियामक के रूप में मैंने सोचा कि विनियमित संस्थाओं की देनदारियों के प्रबंधन और चुनौतियों पर बात करने का यह अवसर है क्योंकि यह कम चर्चित विषय है। जमा और ऋण वृद्धि के बीच बेमेल विशेष टिप्पणी करते हुए गवर्नर दास ने पहले इस क्षेत्र में बढ़ती चुनौती की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया था। इसलिए, आपके विचार के लिए कुछ मुद्दों पर बात करूंगा।

परिचय

बैंकिंग का मुख्य कार्य है जमाराशियां स्वीकार करना है, जो आम तौर पर अल्पकालिक होती हैं, और ऋणों को वित्तपोषित करना, जिनकी परिपक्वता अवधि आम तौर पर लंबी होती है। इस प्रकार परिपक्वता रूपांतरण (मॅचुरिटी ट्रांसफोर्मेशन) वित्तीय मध्यस्थता की एक अंतर्निहित विशेषता है और बैंक इससे जुड़े जोखिमों के प्रति काफी संवेदनशील होते हैं। नतीजतन, बेहतर लाभप्रदता प्राप्त करने, चलनिधि में सुधार करने और बैंक को विभिन्न जोखिमों से बचाने के लिए आस्तियों और देनदारियों का रणनीतिक प्रबंधन महत्वपूर्ण है। ऐतिहासिक रूप से, बेसल I और II सहित विनियामक ढांचे ने तुलनपत्र के आस्ति पक्ष पर अधिक जोर दिया है, जो ऋण जोखिम प्रबंधन और पूंजी पर्याप्तता पर केंद्रित है। इस पर अधिक जोर इसलिए है क्योंकि यह माना जाता है कि ऋण चूक और आस्ति मूल्य में गिरावट बैंक की ऋण शोधन क्षमता के लिए मुख्य खतरे होते हैं। चलनिधि और वित्त पोषण जोखिम, जो मुख्य रूप से देनदारियों से उत्पन्न होते हैं, को बड़े पैमाने पर एक ऐसे मुद्दे के रूप में देखा जाता था कि बैंक किसी भी विनियामक निरीक्षण और हस्तक्षेप की आवश्यकता के बिना खुद प्रबंधन कर सकते हैं।

2008 के वैश्विक वित्तीय संकट (जीएफसी) के दौरान बैंकों को तुलनपत्र के दोनों तरफ की कमजोरियों का सामना करना पड़ा, जिसने उक्त दृष्टिकोण को चुनौती दी, और जिसके परिणामस्वरूप बैंकिंग क्षेत्र के विनियामक ढांचे में भारी बदलाव हुए। इस संकट के दौरान कई बैंकों को, पूंजी आवश्यकताओं का पालन करने के बावजूद, दिवालिया होने के कारण चलनिधि संकट का सामना करना पड़ा, जिससे अल्पकालिक देयताओं पर निर्भर रहने की कमजोरी उजागर हुई। इसने आस्ति-पक्ष की कमजोरियों के अलावा चलनिधि प्रबंधन के प्रणालीगत महत्व और विनियामक निरीक्षण की आवश्यकता को रेखांकित किया। यह नीतिगत प्रतिक्रिया एक महत्वपूर्ण परिवर्तन था जिसके कारण चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) और निवल स्थिर वित्तपोषण अनुपात (एनएसएफआर) जैसे व्यापक वैश्विक चलनिधि मानकों का निर्धारण हुआ जो अल्पकालिक और मध्यम अवधि की चलनिधि की समुत्थाशीलता को लक्षित करते हैं।

अब यह माना हुआ तथ्य है कि देयता प्रबंधन न केवल एक विनियमित इकाई (आरई) की स्थिरता और शोधन क्षमता के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह पूंजी और संवृद्धि दिशापथ (ट्राजेक्ट्री) पर उसके प्रतिलाभ को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक के रूप में भी महत्वपूर्ण है। अर्जन के नजरिए से, ऋण पर अर्जित ब्याज का स्प्रेड और निधियों की लागत बैंक की निवल आय और लाभप्रदता निर्धारित करती है।[1] इस प्रकार देयताओं की लागत का निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम) और अर्जन अनुपात पर सीधा प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए, कुल जमा में चालू और बचत खाता (सीएएसए) जमा का हिस्सा, खुदरा बनाम थोक वित्तपोषण का मिश्रण और देयताओं की अवधि वित्तपोषण लागत, और परिणामस्वरूप बैंकों की लाभप्रदता निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अलावा, किसी भी संकट के दौरान वित्तपोषण की स्थिरता होना समुत्थानशीलता की कुंजी है। इस संदर्भ में, मैं भारत में देयता प्रबंधन के उद्भव, देयता संरचना में बदलते रुझान, इकाई-विशिष्ट चुनौतियों और विनियामक अपेक्षाओं पर संक्षेप में चर्चा करना चाहूंगा।

भारत में एएलएम का उद्भव

जैसा कि आप सभी जानते हैं, 1990 के दशक के व्यापक आर्थिक सुधारों के साथ भारतीय बैंकिंग में रणनीतिक परिवर्तन हुआ। ब्याज दरों के अविनियमन और वैश्विक एकीकरण में वृद्धि

* 17 जनवरी 2025 को मुंबई में मिंट वार्षिक बीएफएसआई शिखर सम्मेलन और पुरस्कार 2025 में उप गवर्नर श्री एम. राजेश्वर राव द्वारा दिया गया मुख्य भाषण। अखिलेश गोखले, टोनी मैमन और शशांक श्रीवास्तव द्वारा दिए गए सुझावों के लिए आभार।

[1] लाभ का दूसरा मुख्य चालक प्रावधान आवश्यकता है जो आस्ति की गुणवत्ता पर निर्भर है।

ने वित्तीय संस्थानों द्वारा सामना किए जाने वाले जोखिमों को और अधिक जटिल और बड़ा बना दिया, जिसके लिए रणनीतिक प्रबंधन की आवश्यकता थी। तदनुसार, वित्तीय संस्थानों के लिए आस्ति-देयता प्रबंधन (एएलएम) पर दिशानिर्देश पहली बार फरवरी 1999 में जारी किए गए, जिसमें 2000 के दशक के अंत में और भी प्रावधान किए गए, जिसमें विवेकपूर्ण सीमाओं और प्रकटीकरण ढांचे के साथ ब्याज दर और चलनिधि जोखिम शामिल थे।

भारतीय विवेकपूर्ण ढांचे ने 2012 में 'सुदृढ़ चलनिधि जोखिम प्रबंधन के लिए बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति' (बीसीबीएस) के सिद्धांतों को शामिल किया, जिसके बाद वित्तपोषण चलनिधि के लिए दो न्यूनतम मानकों - एलसीआर और एनएसएफआर को अपनाया गया। यह देखते हुए कि एलसीआर व्यवस्था इंट्राडे चलनिधि पर नज़र नहीं रख पा रही है और वित्तीय प्रणाली के भीतर बढ़ती अंतर-निर्भरताएं भुगतान और निपटान प्रक्रियाओं को प्रभावित करने वाली चलनिधि बाधाओं को जन्म दे सकती हैं, इंट्राडे चलनिधि की निगरानी के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए। संकेन्द्रण जोखिम को कम करने और बड़े बैंकों की अनियंत्रित देयता के प्रणालीगत प्रभावों को कम करने के लिए रिज़र्व बैंक ने बहुत पहले ही वाणिज्यिक बैंकों (2007) के लिए अंतर-बैंक देयताओं (आईबीएल) पर सीमाएँ और शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) (2009) के लिए अंतर-बैंक जमा सीमाएँ निर्धारित कर दी थीं। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) (लघु वित्त बैंकों, भुगतान बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को आईबीएल के लिए विवेकपूर्ण सीमाओं के भीतर कॉल और नोटिस मनी मार्केट में उधार लेने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीमाएँ निर्धारित करने की अनुमति दी गई है। ऐसी देयता-आधारित संकेन्द्रण सीमाएं भारत के संबंध में अनोखी हैं जो इन जोखिमों के प्रति रिज़र्व बैंक की पूर्व जागरुकता को दर्शाती हैं।

देयता का स्वरूप और संवृद्धि

एससीबी के लिए जमा राशि प्राथमिक स्रोत अभी भी बनी हुई है, जिसकी राशि 217 लाख करोड़ रुपये है, जो वित्त वर्ष 2024 के अंत में कुल देनदारियों का 77 प्रतिशत थी। इसके विपरीत, पूंजीगत निधि (यानी, पूंजी, रिज़र्व और अधिशेष) और उधार, देनदारियों का लगभग 9-9 प्रतिशत है[2]। वित्त वर्ष 2016 से वित्त वर्ष 2024 के बीच के आंकड़ों की तुलना यह दर्शाती है कि जमा राशि लगभग 10 प्रतिशत की वार्षिक दर[3] से बढ़ी है जो समग्र तुलनपत्र की वृद्धि के समरूप है, और कुल देनदारियों में उनका योगदान लगभग 77 प्रतिशत पर स्थिर रहा है (चार्ट 1 और 2[4])। इस बीच, उधार 7 प्रतिशत की धीमी दर से बढ़ा है जिसके

चार्ट 1 : एससीबी देयता संरचना – मार्च 2024 के अंत में

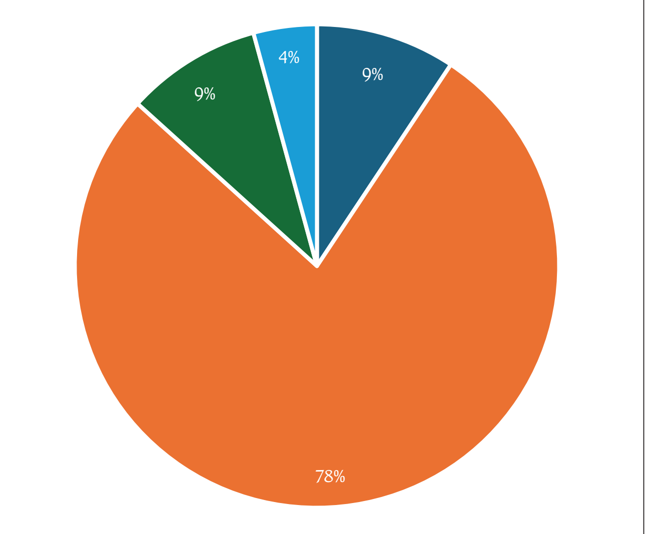

चार्ट 2 : एससीबी देयता संरचना – वि.व. 2016 से वि.व. 2024

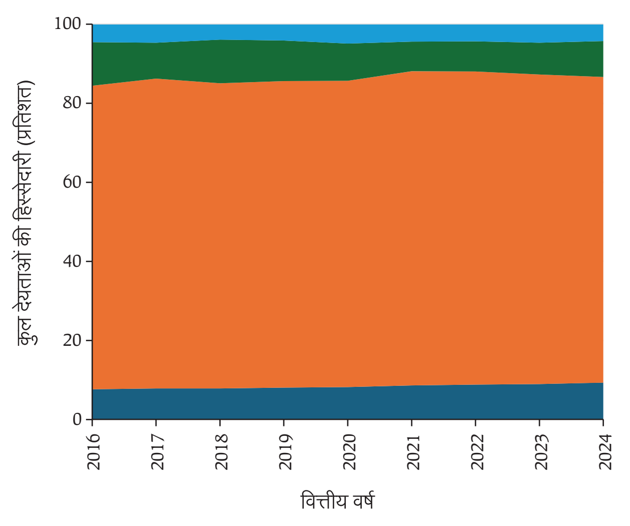

2 उधार में अन्य बातों के अलावा आरबीआई, अन्य बैंकों, संस्थानों और एजेंसियों, पूंजीगत साधनों (स्थायी ऋण साधन और टियर 2 ऋण) और अन्य बांड तथा डिबेंचर से उधार शामिल हैं। शेष देनदारियों (4.2 प्रतिशत) में अन्य देनदारियां और प्रावधान शामिल हैं।

3 संचयी वार्षिक संवृद्धि दर (सीएजीआर)।

4 स्रोत: भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति संबंधी आरबीआई रिपोर्ट, 2016 से 2024।

परिणामस्वरूप कुल देनदारियों में इसकी हिस्सेदारी 11 प्रतिशत से घटकर 9 प्रतिशत हो गई है। दूसरी ओर, पूंजी निधि में लगभग 13 प्रतिशत की वृद्धि हुई है तथा इसका हिस्सा 7.6 प्रतिशत से बढ़कर 9.3 प्रतिशत हो गया है, जो बैंकों के तुलनपत्र में सुधार दर्शाता है, जिसे उच्च लाभप्रदता तथा पूंजी जुटाने के प्रयासों से बढ़ावा मिला है।

परिपक्वता के लिहाज से, इसी अवधि के दौरान, सावधि जमा का योगदान कुल जमा के 65.8 प्रतिशत से घटकर 60.9 प्रतिशत हो गया है, जबकि बचत और चालू खाता जमा का हिस्सा क्रमशः 25.3 प्रतिशत और 8.9 प्रतिशत से बढ़कर 29.2 प्रतिशत और 9.9 प्रतिशत हो गया है। नतीजतन, सीएएसए अनुपात 34.2 प्रतिशत से बढ़कर 39.1 प्रतिशत हो गया है। इस प्रवृत्ति से एससीबी के निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम) में सुधार हुआ होगा, जो वित्त वर्ष 2015-16 के 2.6 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में 3.3 प्रतिशत हो गया (चार्ट 3[5])।

जमाराशियों के अलावा, बैंक अतिरिक्त टियर 1 (एटी1) बॉण्ड और टियर 2 बॉण्ड जैसे ऋण पूंजी साधनों के रूप में उधार राशि जुटाते हैं। इसके अलावा, बैंकों को बुनियादी ढांचे और किफायती आवास ऋणों के वित्तपोषण के लिए घरेलू दीर्घकालिक बॉण्ड जारी करने की अनुमति है और वे ईसीबी मार्ग के तहत विदेशी बाजारों में भी धन जुटा सकते हैं।

चार्ट 3 : एससीबी जमाराशि संरचना - वि.व. 2016 से वि.व. 2024

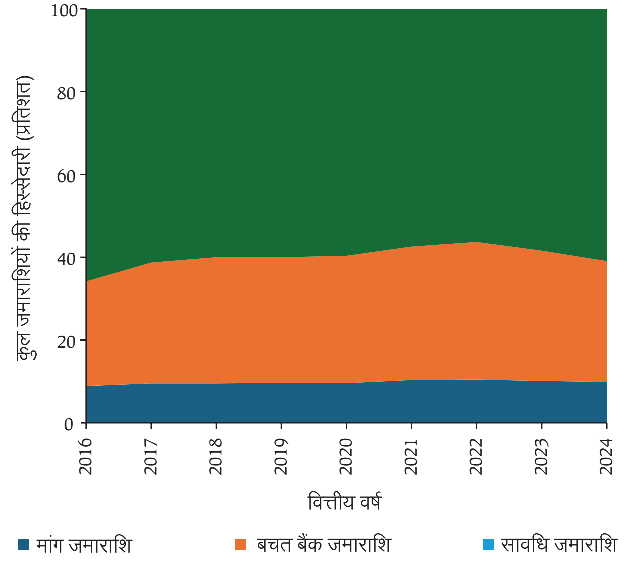

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के लिए, उधार राशियां वित्तपोषण का एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं, जो मार्च 2024 के अंत तक 34.46 लाख करोड़ रुपये या कुल देनदारियों का 68 प्रतिशत था। उधारी के भीतर, डिबेंचर और बैंकों से लिया गया उधार का अंश प्रमुख है (चार्ट 4 और 5[6])। यह स्थिति

चार्ट 4 : एनबीएफसी देयता संरचना – मार्च 2024 के अंत में

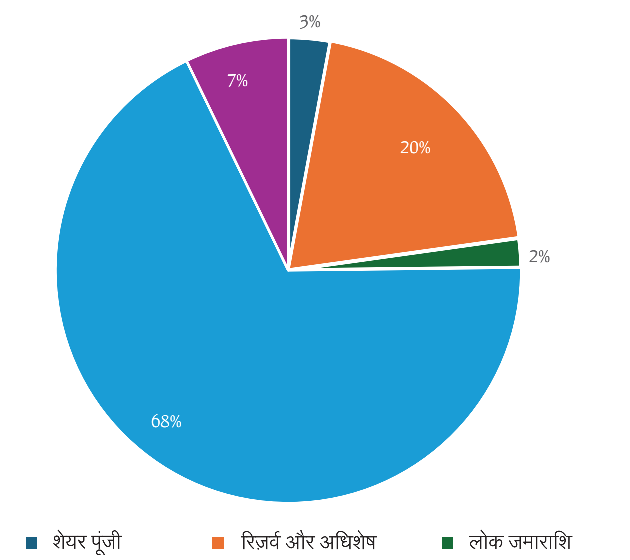

चार्ट 5 : एनबीएफसी उधार संरचना – मार्च 2024 के अंत में

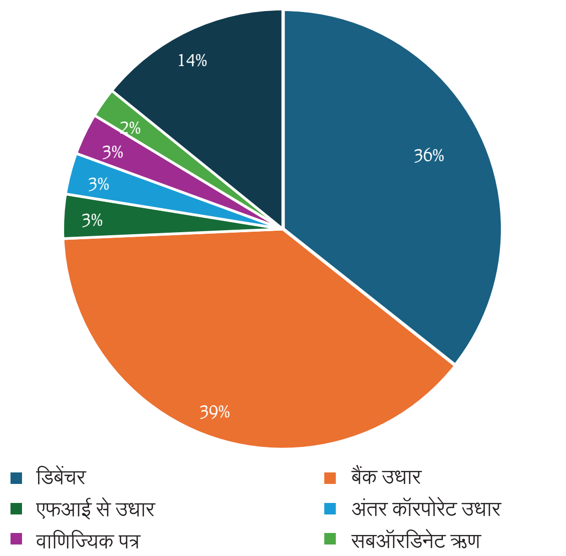

[5] स्रोत: भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति संबंधी आरबीआई रिपोर्ट, 2016 से 2024।

[6] स्रोत: भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति संबंधी आरबीआई रिपोर्ट 2023-24।

एनबीएफसी की देनदारियों को बैंकों की तुलना में अधिक बाजार संचालित और ब्याज दर परिवर्तनों के प्रति संवेदनशील बनाती है।

बदलते रुझान और चुनौतियाँ

बैंक घरेलू बचत, जो वर्तमान में भारत की सकल बचत का लगभग दो-तिहाई हिस्सा है, को प्रयोग में लाते हुए अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों को ऋण प्रदान करने में सबसे आगे हैं। हाल के रुझान बताते हैं कि परिवारों के बचत माध्यम अब बदल रहे हैं। वे बचत के लिए पारंपरिक बैंक जमाओं को छोड़ पूंजी बाजार आस्तियों की ओर जा रहे हैं (चार्ट 6 और 7[7]) । यह बदलाव कई कारकों से प्रेरित है, जिसमें वित्तीय क्षेत्र को सघन करने के लिए लक्षित प्रयास, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में वृद्धि, जो पूंजी बाजारों तक सुविधाजनक और बाधा रहित पहुंच प्रदान करता है, जनसांख्यिकीय बदलावों के कारण निवेश वरीयताओं में बदलाव, वित्तीय जागरुकता में वृद्धि और हाल की अवधि में इक्विटी बाजारों द्वारा दिए गए निरंतर उच्च प्रतिलाभ शामिल हैं। इसके अलावा, वैकल्पिक आस्ति वर्गों का उदय, उच्च प्रतिफल की खोज और पोर्टफोलियो विविधीकरण ने इस प्रवृत्ति को और बढ़ावा दिया है। पिछले दशक में[8], म्यूचुअल फंड, पेंशन और भविष्य निधि, तथा बीमा कंपनियों के ग्राहकों और प्रबंधन के तहत आस्तियों (एयूएम) की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और यह प्रवृत्ति आगे और भी बढ़ने की संभावना है। हालांकि यह प्रवृत्ति बैंकों के लिए उपलब्ध समग्र निधि को नहीं बदलेगी, लेकिन यह बैंकों के लिए निधि की लागत और मार्जिन पर प्रभाव डालने वाली जमाओं के स्वरूप को बदल सकती है।

जैसा कि पहले बताया गया है, हालांकि सीएएसए जमाराशियों में लंबी अवधि में सुधार हुआ है, लेकिन हाल में एक बदलाव यह है कि सीएएसए जमाराशियों का हिस्सा घट रहा है और सावधि जमाराशियों, विशेष रूप से उच्च ब्याज दर वाली जमाराशियों का हिस्सा बढ़ रहा है।[9] इसका बैंकों के एनआईएम और लाभप्रदता पर प्रभाव पड़ता है। हाल ही में बैंकों ने जमा प्रमाणपत्रों (सीडी) के माध्यम से अल्पावधि निधि पर अपनी निर्भरता भी बढ़ा दी है और औसत सीडी बकाया 2012[10] के स्तर पर पहुंच गया है। तथापि, बैंकों को इस तथ्य को संज्ञान में लेना चाहिए कि यदि बाजार की

चार्ट 6 : परिवार वित्तीय आस्ति प्रवाह की संवृद्धि (वि.व. 2020 से वि.व. 2024)

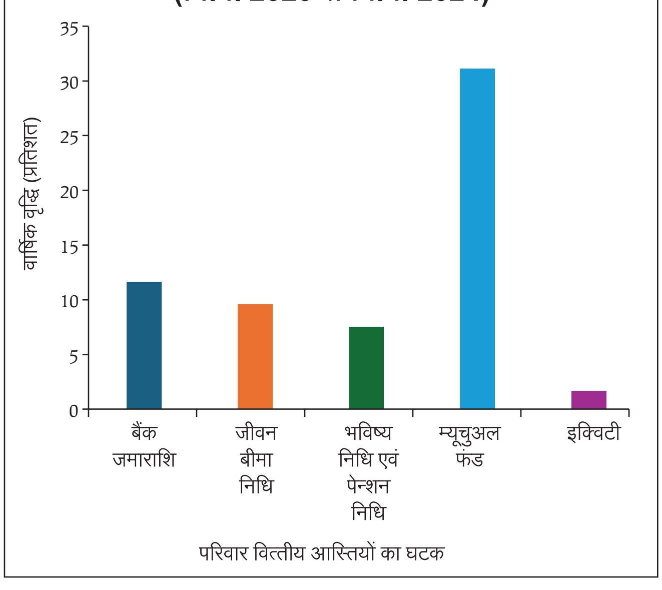

चार्ट 7 : परिवारों की वित्तीय आस्तियों के स्टॉक की हिस्सेदारी (जून 2019 से मार्च 2024)

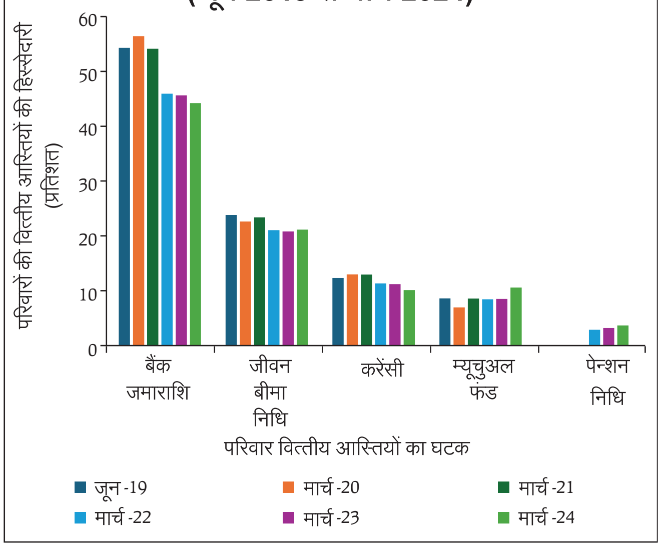

7 स्रोत: आरबीआई क्वार्टरली डेटा रिलीज़ ऑन हाउसहोल्ड फिनान्शियल सेविंग्स, आरबीआई स्टाफ गणना। टिप्पणी: (i) चार्ट 6 और 7 में घरेलू वित्तीय आस्तियों के चुनिंदा घटक शामिल हैं; (ii) चार्ट 6 घरेलू वित्तीय आस्तियों के प्रवाह का सीएजीआर प्रदान करता है।

8 उदाहरण के लिए, म्यूचुअल फंड उद्योग का एयूएम 2014 के ₹10 ट्रिलियन से बढ़कर 31 दिसंबर 2024 तक ₹66.93 ट्रिलियन हो गया है, जो 10 वर्षों में 6 गुना से अधिक की वृद्धि है। 31 दिसंबर 2024 तक खातों/फोलियो की कुल संख्या 22.50 करोड़ थी। [स्रोत: एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया (एएमएफआई) वेबसाइट]

9 सावधि जमा राशि 2024-25 की पहली छमाही में जुटाई गई वृद्धिशील जमा राशि का 82 प्रतिशत है। स्रोत: आरबीआई वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट दिसंबर 2024।

10 वित्त वर्ष 2023-24 में औसत बकाया सी.डी. 4.18 लाख करोड़ रुपये थी। स्रोत: भारतीय अर्थव्यवस्था पर आर.बी.आई. डेटाबेस (डी.बी.आई.ई.), आरबीआई स्टाफ गणनाएं।

स्थिति बिगड़ती है तो अल्पावधि देनदारियों पर अधिक निर्भरता के अपने दुष्परिणाम हो सकते हैं।

बैंक अपनी प्रतिस्पर्धी ताकत, बाजार स्थिति और व्यावसायिक प्राथमिकताओं के आधार पर देयता राशि जुटाने के लिए अलग-अलग रणनीतियों को अपनाते हैं। बहुत अधिक शाखाओं वाले बड़े बैंकों के पास कम लागत वाली, स्थिर स्वरूप की खुदरा जमा उपलब्ध हो सकती है। जबकि अधिकतर शहरी उपस्थिति वाले बैंक उच्च-निवल-मूल्य वाले व्यक्तियों (एचएनआई) और कॉरपोरेट ग्राहकों के लिए उच्च-मूल्य वाले जमा उत्पाद उपलब्ध कराकर समृद्ध ग्राहक वर्ग को लक्षित कर सकते हैं। इसके अलावा, उन्नत प्रौद्योगिकी अपनाने वाले कुछ बैंक ग्राहक बढ़ाने और जमा राशि प्राप्त करने के स्रोतों को सुव्यवस्थित करने के लिए डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का लाभ उठाते हैं, जिससे उन्हें खुदरा और कॉरपोरेट जमा, दोनों को आकर्षित करने में प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिलती है। दूसरी ओर, विशेष-कार्य बैंकों की अन्य बैंकों से जमा प्राप्त करने और थोक वित्तपोषण पर अधिक निर्भरता दिखाई देती है। निधि संबंधी प्रोफाइल में यह विविधता एएलएम में अलग प्रकार की चुनौतियां प्रस्तुत करती है, क्योंकि चलनिधि प्रबंधन, निधि लागत, और जोखिम प्रबंधन प्रत्येक व्यावसायिक रणनीति में अपनी-अपनी जटिलताएं होती हैं।

जमाराशियों का 'संस्थागतीकरण', जिसका मैंने पहले उल्लेख किया था, बैंकों के लिए एएलएम की दृष्टि से विशिष्ट चुनौतियाँ लेकर आएगा। खुदरा जमाराशियों पर निर्भरता में कमी करने और संस्थागत स्रोतों से अधिक वित्त प्राप्त करने से निधि लागत में वृद्धि होने की संभावना होगी, जो बदले में लाभप्रदता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगी। मार्जिन को बनाए रखने के प्रयास में इस बढ़ी हुई निधि लागत का असर अंततः दिए जाने वाले ऋणों के ब्याज दर पर हो सकता है। इससे या तो दिया जाने वाले ऋण की वृद्धि बाधित होगी या ऋणदाता अंडरराइटिंग मानकों को कम करने, और आय अनुपात बनाए रखने के लिए, जोखिम भरे उधारकर्ताओं को ऋण देने के लिए मजबूर हो जाएंगे। बैंकों को ऐसी कुछ प्रथाओं के जोखिमों के प्रति सतर्क रहना चाहिए जो मजबूत आर्थिक विकास के दौरान कम महत्वपूर्ण लग सकते हैं लेकिन जो आर्थिक मंदी के दौरान गंभीर परिणाम पैदा कर सकते हैं। जो बैंक थोक वित्तपोषण पर अत्यधिक निर्भर हैं वे आर्थिक तनाव के समय जोखिमों के प्रबंधन और बहिर्वाहों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। इसलिए, इन जोखिमों को कम करने के लिए देयता का प्रभावी प्रबंधन महत्वपूर्ण है।

कुछ बैंकों से संबंधित एक अन्य मुद्दा यह है कि उनकी जमा वृद्धि उनकी ऋण वृद्धि के साथ तालमेल नहीं रख पा रही है। इसके कारण ऋण वितरण के लिए थोक वित्तपोषण पर अधिक निर्भरता से जुड़े जोखिमों के बारे में विनियामक चिंताएं उप्पन्न हुई हैं। इस तरह के असंतुलनों को संभावित संरचनात्मक चलनिधि कमजोरियों के संकेतक के रूप में देखा जाता है। जबकि विनियामक बैंकिंग क्षेत्र में प्रणालीगत जोखिमों का आकलन करने के लिए एक व्यापक आर्थिक पैमाने के रूप में इन प्रवृत्तियों की निगरानी करते हैं, यह समझ लेना महत्वपूर्ण है कि व्यक्तिगत बैंकों के लिए ये संकेतक अकेले चलनिधि जोखिम को पूरी तरह से प्रदर्शित करने के लिए अपर्याप्त हैं। अल्पकालिक चलनिधि के दृष्टिकोण से एलसीआर जैसे साधन जमाराशि संबंधी स्थिरता, जमाकर्ता व्यवहार और खुदरा तथा थोक निधि के बीच अंतर-संबंध जैसे कारकों को विचार में लेते हुए अधिक सूक्ष्म दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। इन संकेतकों के बीच संबंध बहुआयामी और अक्सर विरोधाभासी होते हैं, जिससे किसी एक माप पर अकेले भरोसा न करके बैंकों की एएलएम प्रोफ़ाइल का समग्र मूल्यांकन करना आवश्यक हो जाता है।

बैंकों के विपरीत, एनबीएफसी[11] की देयता प्रोफ़ाइल, उनकी प्राथमिक गतिविधियों, विनियामक आवश्यकताओं और उनके द्वारा वित्तपोषित आस्तियों के प्रकारों द्वारा तय होती है। ऐतिहासिक रूप से यह पाया गया है कि एनबीएफसी की बुनियादी ढांचे और आवास ऋण जैसी दीर्घकालिक आस्तियों का समर्थन करने के लिए अल्पकालिक निधि पर अत्यधिक निर्भरता के परिणामस्वरूप संकट समय में चलनिधि की बड़ी कमी, निवेशकों के विश्वास में गिरावट और क्रेडिट रेटिंग में गिरावट हो सकती है, जिससे पूंजी बाजारों से ऋण प्राप्त करने की उनकी क्षमता सीमित हो सकती है। नतीजतन, एनबीएफसी प्रत्यक्ष उधार और बैंकों द्वारा डिबेंचर और वाणिज्यिक पत्रों (सीपी) की खरीद, दोनों स्वरूपों की बैंक निधि पर बहुत अधिक निर्भर हो गए, जिससे निधि का संकेंद्रण हुआ है। बैंक उधार पर एनबीएफसी की बढ़ती निर्भरता को पहचानते हुए, रिज़र्व बैंक ने नवंबर 2023 में एनबीएफसी के प्रति बैंक एक्सपोज़र के जोखिम भार को 25 प्रतिशत अंकों तक बढ़ा दिया, जिससे एनबीएफसी द्वारा लिए जाने वाले बैंक उधार में व.द.व वृद्धि को कम करने में मदद मिली है। इस कमी को पूरा

[11] रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित एनबीएफसी अलग-अलग वित्तीय संस्थाओं का एक समूह है जो विविध व्यावसायिक रणनीतियों के साथ काम करती हैं, जैसे कि निवेश ऋण, बुनियादी ढांचा वित्त, सूक्ष्म वित्त, फैक्टरिंग, कोर निवेश, आवास वित्त, नॉन-ऑपरेटिव फिनान्शियल होल्डिंग, खाता समाहर्ता, पीयर-टू-पीयर उधार और प्राथमिक डीलिंग गतिविधियाँ।

करने के लिए एनबीएफसी ने सीपी[12] और गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी)[13] के माध्यम से निधि संग्रहण को बढ़ा दिया है ।

अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुँच बनने से एनबीएफसी की घरेलू बैंकिंग प्रणाली पर निर्भरता कम हो सकती है और उन्हें निधि के लिए अधिक विकल्प मिल सकते हैं, लेकिन इससे उन्हें अतिरिक्त जोखिम भी उठाना पड़ सकता है, खास तौर पर असुरक्षित (अन-हेज्ड) मुद्रा से संबंधित जोखिम, जिससे निधि लागत में अस्थिरता और विनिमय दर में उतार-चढ़ाव के कारण संभावित चलनिधि तनाव हो सकता है। एनबीएफसी को चाहिए कि वे अपने एएलएम ढांचे में विदेशी मुद्रा हेजिंग को जोड़ें और निधि लागत में अस्थिरता को कम करने के लिए मुद्रा जोखिम पर बारीकी से नज़र रखें । उधार देने के उद्देश्य से संसाधनों को मुक्त करने के लिए प्रतिभूतिकरण के माध्यम से आस्तियों का चलनिधि परिवर्तन भी एएलएम संरचना को बेहतर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में काम कर सकता है।

विनियामक अपेक्षाएँ

अब मैं कुछ ऐसे प्रमुख मुद्दों की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं जिन पर बैंकों और एनबीएफसी द्वारा अपनाई गई एएलएम प्रथाओं और इन मुद्दों पर विनियामक अपेक्षाओं के बारे में विश्व स्तर पर व्यापक रूप से बहस हो रही है।

सबसे पहले, बैंकिंग में नवीन उत्पादों और प्रौद्योगिकियों के उदय ने निधि उपलब्धता और नकदी प्रवाह को प्रबंधित करने में उपभोक्ता के लिए कई विकल्प उपलब्ध करा दिए हैं जिससे ग्राहक व्यवहार में काफी बदलाव आया है। इसके अलावा, पारंपरिक और सोशल मीडिया के माध्यम से सूचना प्रसार के बदलते स्वरूप ग्राहक व्यवहार को बड़े पैमाने में प्रभावित कर सकते हैं, जिससे संकट संभावित रूप से बढ़ सकता है और तीव्र हो सकता है। ये कारक बढ़ी चुनौतियाँ उत्पन्न करते हैं, अत: बैंकों को सतर्क रहने और जमाराशि की स्थिरता और ग्राहक व्यवहार पर अपनी मॉडलिंग व्यवस्था की सावधानीपूर्वक समीक्षा करने की आवश्यकता है ताकि जमाराशि बनाए रखने, निकासी के स्वरूप, पूर्व-भुगतान और ब्याज दर संवेदनशीलता का बेहतर अनुमान लगाया जा सके।

दूसरा, यू.के. में देयता-संचालित निवेश (एल.डी.आई.) संकट ने अत्यधिक परस्पर जुड़े वित्तीय ढांचे में अंतर्निहित कमज़ोरियों को उजागर किया है, जहाँ एक खंड की विफलता कई क्षेत्रों में व्यापक चलनिधि चुनौतियों को जन्म दे सकती है। पारंपरिक देयता प्रबंधन मॉडल, जो अक्सर ऐतिहासिक आंकड़ों पर आधारित होते हैं, असाधारण बाजार स्थितियों द्वारा उत्पन्न जोखिमों को पर्याप्त रूप से दर्शा नहीं पाते हैं। अत:, विनियमित संस्थाओं को चाहिए कि वे अधिक परिष्कृत दबाव-परीक्षण पद्धतियाँ विकसित करें जो चरम परिदृश्यों का सामना करने की उनकी क्षमता का मूल्यांकन करती हों, जिसमें उन स्थितियों को भी शामिल किया जाए जो परस्पर जुड़े वित्तीय नेटवर्क में आघातों की तीव्रता को बढ़ाती हैं।

अंतिम बिंदु है - आकस्मिक निधि योजनाओं (सीएफपी) का महत्व। सामान्य तौर पर, आरई के पास उनकी अपनी जटिलता, जोखिम प्रोफ़ाइल, संचालन के दायरे और वित्तीय प्रणाली में उनकी भूमिका के अनुरूप एक औपचारिक आकस्मिक निधि योजना होनी चाहिए। अन्य बातों के अलावा, उसमें उपलब्ध संभावित आकस्मिक निधि स्रोतों और इन स्रोतों से प्राप्त की जा सकने वाली निधियों की मात्रा का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि केंद्रीय बैंकों के अंतिम उपाय के ऋणदाता (एलओएलआर) के रूप में कार्य को बैंकों के लिए चलनिधि आघातों से बचाने (अंतर्निहित) के लिए बीमा के रूप में माना जाता है, जिसे मुद्रा बाजार प्रतिभागी अवशोषित करने के लिए अनिच्छुक या असमर्थ होते हैं। इस बीमा का मूल्य बैंकों के चलनिधि जोखिम के साथ बढ़ता है, जिससे नैतिक जोखिम भी बढ़ता है। बैंकों को यह ध्यान में रखना होगा कि इस नैतिक जोखिम से निपटने के लिए, केंद्रीय बैंक यह निर्णय लेने का अधिकार रखते हैं कि विशिष्ट संस्थानों को आपातकालीन चलनिधि सहायता प्रदान की जाए या नहीं। यह सहायता लोक निधियों के विवेकपूर्ण उपयोग के माध्यम से संपूर्ण वित्तीय प्रणाली के लिए सुरक्षा जाल के रूप में अभिप्रेत है जो अक्सर पर्यवेक्षी हस्तक्षेप और शर्तों के साथ होती है। इसलिए, एलओएलआर कार्य को आकस्मिक निधि के नियमित घटक के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।

जहाँ तक एनबीएफसी का सवाल है, वे ऋण उपलब्ध कराने और आर्थिक संवृद्धि को समर्थन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन उनकी गतिविधियों में परिपक्वता, चलनिधि और ऋण परिवर्तन की महत्वपूर्ण मात्रा भी शामिल होती है। बैंकों के विपरीत, अधिकांश एनबीएफसी के पास सार्वजनिक जमाराशियों तक पहुँच नहीं होती है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में विनियामक दृष्टिकोण एनबीएफसी की जमाराशि लेने की गतिविधियों को हतोत्साहित करने का रहा है। बैंकों के पास

[12] वित्त वर्ष 2023-24 में एनबीएफसी के लिए बकाया सीपी में 26.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है (स्रोत: भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति संबंधी आरबीआई रिपोर्ट 2023-24)।

[13] वित्त वर्ष 2023-24 में एनबीएफसी के लिए सुरक्षा रहित बकाया डिबेंचर में 16.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है (स्रोत: भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति संबंधी आरबीआई रिपोर्ट 2023-24)।

आधिकारिक सुविधा की उपलब्धता और जमा संस्थाओं तक उनकी पहुँच है जिसके कारण उसने पास निधि के अधिक स्थिर खुदरा स्रोत हैं जबकि, एनबीएफसी अपनी निधि के लिए बैंकों और पूंजी बाजारों पर निर्भर रहेंगे। एनबीएफसी के लिए यह आवश्यक है कि वे अपने निधि स्रोतों में विविधता लाएं, और उधार लेने की लागत को कम करें और एक स्थायी विकास पथ के लिए संबंधित जोखिमों को कम करें।

निष्कर्ष

आज, हम सामूहिक रूप से 2047 तक, अपनी स्वतंत्रता की शताब्दी तक 'विकसित भारत' की आकांक्षा रखते हैं। इस महत्वाकांक्षा के लिए सतत और टिकाऊ आर्थिक संवृद्धि के साथ-साथ समुत्थानशीलता की प्रणालीगत क्षमता की आवश्यकता होती है। इस विजन के तहत महत्वाकांक्षी आर्थिक संवृद्धि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, वित्तीय आस्तियों और बैंक आस्तियों को अगले दो दशकों में लगातार और उच्च गति से विकास हासिल करने की आवश्यकता होगी, जिसके लिए वित्तीय क्षेत्र के लिए देयताओं और पूंजी में इसी तरह की वृद्धि की आवश्यकता होगी। इससे कुछ उभरती चुनौतियों का समाधान करने की आवश्यकता सामने आती है क्योंकि ग्राहक व्यवहार और वरीयताएँ गहन परिवर्तनों से गुजर रही हैं जबकि वैश्विक पारितंत्र और बाहरी कारक, जैसे कि तीसरे पक्ष की निर्भरता, और प्रौद्योगिकी बदलाव तेजी से जटिल होते जा रहे हैं, जो व्यवसाय परिदृश्य को नया रूप दे रहे हैं। सामूहिक रूप से, ये परिवर्तन आरई के लिए एक चुनौतीपूर्ण वातावरण बना रहे हैं, जिससे आरई को अपने दृष्टिकोण और व्यावसायिक रणनीतियों को फिर से जांचने की आवश्यकता होगी। यह केवल जोखिमों के प्रबंधन के बारे में नहीं है, बल्कि निधि संरचनाओं को बेहतर बनाने, स्थिरता बढ़ाने और आर्थिक संवृद्धि का समर्थन करने के अवसरों का लाभ उठाने के बारे में भी है। 2047 तक "विकसित भारत" का मार्ग काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगा कि वित्तीय प्रणाली इन प्रवृत्तियों के साथ कितनी अच्छी तरह से अनुकूलन करती है और किस प्रकार संसाधन जुटाने और देयता प्रबंधन की जटिलताओं का प्रबंधन करती है।

धन्यवाद।

आलेख

अर्थव्यवस्था की स्थिति

केंद्रीय बजट 2025-26: एक आकलन

भारत में सार्वजनिक व्यय की गुणवत्ता और उसका सामाजिक-आर्थिक प्रभाव

कृषि आपूर्ति शृंखला की गतिविधियां: रबी विपणन सत्र के दौरान
अखिल भारतीय सर्वेक्षण से प्राप्त अंतर्दृष्टि

अर्थव्यवस्था की स्थिति*

वैश्विक अर्थव्यवस्था स्थिर लेकिन मध्यम गति से बढ़ रही है, जिसमें तेजी से विकसित हो रहे राजनीतिक और तकनीकी परिदृश्यों के बीच देशों में अलग-अलग दृष्टिकोण हैं। वित्तीय बाजार अवस्फीति की धीमी गति और टैरिफ के संभावित प्रभाव से चिंतित हैं। उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) की ओर से बिकवाली का दबाव देखा जा रहा है और मजबूत अमेरिकी डॉलर के कारण मुद्रा का अवमूल्यन हो रहा है। भारत में, उच्च आवृत्ति संकेतक 2024-25 की दूसरी छमाही के दौरान आर्थिक गतिविधि की गति में क्रमिक वृद्धि की ओर इशारा करते हैं, जो आगे भी जारी रहने की संभावना है। केंद्रीय बजट 2025-26 घरेलू आय और खपत को बढ़ावा देने के उपायों के साथ-साथ पूंजीगत व्यय पर निरंतर ध्यान केंद्रित करके राजकोषीय समेकन और विकास उद्देश्यों को विवेकपूर्ण तरीके से संतुलित करता है। जनवरी में खुदरा मुद्रास्फीति पांच महीने के निचले स्तर पर आ गई, जिसका मुख्य कारण सब्जियों की कीमतों में तेज गिरावट थी।

परिचय

वैश्विक अर्थव्यवस्था राजनीतिक और तकनीकी परिदृश्यों के बीच स्थिर वृद्धि प्रदर्शित कर रही है, जिनमें से दोनों ने 2025 के दौरान अब तक नीतिगत चर्चा में प्रमुख भूमिका निभाई है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने विश्व आर्थिक परिदृश्य (डब्ल्यूईओ) के अपने जनवरी 2025 के अपडेट में अनुमान लगाया है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था 2025 में 3.3 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी, जो 2024 में 3.2 प्रतिशत के करीब है, लेकिन 21वीं सदी के पहले दो दशकों के दौरान देखी गई 3.7 प्रतिशत की औसत से कम है। विकास परिदृश्य विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में व्यापक रूप से भिन्न होते हैं - संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएस) में सुदृढ़ विकास से अन्य उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (एई) में कमजोरी की भरपाई होने की उम्मीद है। उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) के लिए, 2025 में विकास मोटे तौर पर 2024 के बराबर होने की उम्मीद है। हालाँकि, वैश्विक विकास और व्यापार परिदृश्य को उभरते अमेरिकी टैरिफ से अधोगामी जोखिम का सामना करना पड़ रहा है, जिसका समय और परिमाण अत्यधिक अनिश्चित है। अमेरिकी व्यापार नीति अनिश्चितता 2019 के अमेरिकी-चीन व्यापार युद्ध के दौरान देखे गए स्तरों तक बढ़ गई है और प्रतिबंधात्मक व्यापार नीतियों और विखंडन से वैश्विक व्यापार पैटर्न में अल्पकालिक व्यवधान के बजाय दीर्घकालिक बदलाव हो सकता है, और उपभोक्ता एवं व्यावसायिक लागतों पर ऊर्ध्वमुखी दबाव पड़ सकता है।[1]

वैश्विक वित्तीय बाजार संकट में हैं, हर आने वाली सूचना के कारण तेज उतार-चढ़ाव हो रहा है। अमेरिकी प्रशासन में बदलाव और कॉरपोरेट आय में सुधार के बाद अमेरिकी इक्विटी बाजारों में तेजी आई।[2] हालांकि, डीपसीक[3] द्वारा आर1 के लॉन्च ने ऐसे आघात उत्पन्न किए कि एक ही दिन (27 जनवरी, 2025) में इक्विटी मूल्य से 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हो गया । सरकारी बॉण्ड प्रतिफल में दोतरफा उतार-चढ़ाव जारी है। टैरिफ घोषणाओं के बाद अमेरिकी डॉलर सूचकांक में उछाल आया, जिससे उभरते बाजारों से पूंजी का बहिर्वाह हुआ और मुद्रा दबाव में तेजी आई। अधिक अनुकूल बाहरी वातावरण को बढ़ावा देने, व्यापक आर्थिक स्थिरता को बढ़ाने, संरचनात्मक बाधाओं को कम करने और जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से बचने के लिए ठोस नीतिगत कार्रवाई की आवश्यकता होगी ताकि कम आय वाले कई देशों के 2050 तक मध्यम आय की स्थिति तक नहीं पहुंच पाने के जोखिम से बचा जा सके।[4]

वैश्विक उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति (सीपीआई) 2024 में घटकर 5.7 प्रतिशत (एक साल पहले की तुलना में 100 बीपीएस

* यह आलेख रेखा मिश्र, जी.वी. नथनएल, रजनी दहिया, दुर्गा जी, अर्पिता अग्रवाल, हर्षिता केशन, रमेश गुप्ता, हरेंद्र बेहरा, नीलिमा केएम, सत्यार्थ सिंह, एलिस सेबेस्टियन, ऐट्टम अभिन्नू यादव, हर्षिता यादव, सिद्धार्थ आर्य, सत्येन्द्र कुमार, अर्चना दिलीप, अगमनी साहा, दिब्यारका चौले, श्रीतमा रे, शिवम, खुशी सिन्हा, कार्तिकेय भार्गव, युवराज कश्यप, निखिल प्रकाश कोसे, आशीष खोबरागड़े, दिलप्रीत शर्मा और अवनीश कुमार द्वारा तैयार किया गया है। । इस आलेख में व्यक्त विचार लेखकों के हैं और भारतीय रिज़र्व बैंक के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

[1] विश्व आर्थिक मंच, मुख्य अर्थशास्त्रियों का परिदृश्य, जनवरी 2025; पीटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, "ट्रम्प के धमकी भरे टैरिफ से अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको और चीन की अर्थव्यवस्थाओं को नुकसान होने का अनुमान है", 17 फरवरी, 2025; फाइनेंशियल टाइम्स, "ट्रम्प टैरिफ का खतरा वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता को बढ़ाता है, आईएमएफ ने चेतावनी दी", 11 जनवरी, 2025।

[2] अमेरिकी बेंचमार्क एसएंडपी 500 इंडेक्स 10-25 जनवरी, 2025 के दौरान 5.0 प्रतिशत बढ़ा।

[3] आर1, एक बड़ा भाषा मॉडल (एलएलएम) है, जिसे डीपसीक, एक चीनी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) कंपनी द्वारा मौजूदा एलएलएम की तुलना में बहुत कम कंप्यूटिंग शक्ति का उपयोग करके बहुत कम लागत पर विकसित किया गया है।

[4] वैश्विक आर्थिक संभावनाएँ, विश्व बैंक, जनवरी 2025।

कम) हो गई।[5] एई के मामले में गिरावट अधिक स्पष्ट थी, हालांकि हाल के प्रकाशनों ने प्रमुख एई में मुद्रास्फीति में वृद्धि दिखाई है, जिसमें सेवा मुद्रास्फीति सुदृढ़ सिद्ध हुई है। मुद्रास्फीति और विकास के अलग-अलग परिणाम मौद्रिक नीति क्रियाओं में भी परिलक्षित होते हैं - अमेरिका दरों को स्थिर रखता है, यूके और यूरो क्षेत्र कटौती का विकल्प चुनता है, और जापान अपनी दर बढ़ाता है। मुद्रा और वित्तीय बाजारों पर व्यापार संघर्षों का संभावित प्रभाव नीति निर्माताओं के सामने आने वाले विकल्पों को और भी उलझा देता है।

इस चुनौतीपूर्ण और तेजी से अनिश्चित वैश्विक वातावरण में, प्रमुख बहुपक्षीय एजेंसियों के अनुमान के अनुसार, भारतीय अर्थव्यवस्था 2025-26 के दौरान सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए तैयार है।[6] उच्च आवृत्ति संकेतक दिखाते हैं कि अर्थव्यवस्था 2024-25 की पहली छमाही में देखी गई गिरावट से दूसरी छमाही के दौरान वृद्धि में सुधार की राह पर है। औद्योगिक गतिविधि में पिछली तिमाही की तुलना में सुधार दर्ज किया गया है, जैसा कि जनवरी में क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) में परिलक्षित होता है। ट्रैक्टर की बिक्री में वृद्धि, और ईंधन की खपत में तेजी, तथा हवाई यात्री यातायात में निरंतर वृद्धि भी समग्र गति में सुधार की ओर इशारा करती है। कृषि आय में वृद्धि के कारण ग्रामीण मांग में तेजी जारी है। ग्रामीण क्षेत्रों में, फास्ट-मूविंग कंज्यूमर गुड्स (एफएमसीजी) कंपनियों की बिक्री 2024-25 की तीसरी तिमाही में 9.9 प्रतिशत बढ़ी।[7] रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए उद्यम सर्वेक्षण इस आकलन की पुष्टि करते हैं (अनुलग्नक 1)। सूचीबद्ध गैर-सरकारी गैर-वित्तीय कंपनियों ने शुरुआती परिणामों के अनुसार तीसरी तिमाही के दौरान बिक्री वृद्धि में तेजी दर्ज की। क्रमिक आधार पर, परिचालन लाभ मार्जिन भी बेहतर बिक्री वृद्धि के अनुरूप अधिक रहा है। निजी क्षेत्र के निवेश इरादे स्थिर रहे, बैंकों/वित्तीय संस्थानों (एफआई) द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं की कुल लागत 2024-25 की तीसरी तिमाही में करीब एक लाख करोड़ रुपये रही। पूंजीगत व्यय के उद्देश्य से बाहरी वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) और आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) में भी तीसरी तिमाही के दौरान वृद्धि दर्ज की गई।

केंद्रीय बजट 2025-26 में व्यय की गुणवत्ता बनाए रखते हुए उपभोग को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है, जिसमें प्रभावी पूंजीगत व्यय/जीडीपी अनुपात को 2024-25 (संशोधित अनुमान) के 4.1 प्रतिशत से बढ़ाकर 2025-26 में 4.3 प्रतिशत करने का अनुमान है।

वैश्विक व्यापार और भू-राजनीतिक परिदृश्य के बारे में अनिश्चितता का असर घरेलू इक्विटी बाजारों पर पड़ा है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) की ओर से बिकवाली के दबाव के कारण बेंचमार्क और व्यापक बाजारों में गिरावट आई क्योंकि भावनाएं कमजोर रहीं। अमेरिकी डॉलर की मजबूती के कारण भारतीय रुपये में अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं की तरह गिरावट आई है। मजबूत सूक्ष्म-वित्त आधार और बाहरी क्षेत्र की सुभेद्यता के विभिन्न उपायों में सुधार ने भारत को वैश्विक अनिश्चितता की मौजूदा लहर से उबरने में मदद की है।

जनवरी 2025 में हेडलाइन सीपीआई मुद्रास्फीति घटकर पांच महीने के निचले स्तर 4.3 प्रतिशत पर आ गई, क्योंकि खाद्य पदार्थों, खासकर सब्जियों की कीमतों में तेज गिरावट दर्ज की गई, जो बाजार में सर्दियों की फसलों के आने से प्रेरित थी। कोर (खाद्य और ईंधन को छोड़कर सीपीआई) मुद्रास्फीति ने मई 2024 से धीरे-धीरे वृद्धि दिखाई है, लेकिन 4 प्रतिशत से नीचे बनी हुई है।

फरवरी 2025 की द्विमासिक मौद्रिक नीति बैठक में, रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने नीतिगत रेपो दर को 25 आधार अंकों से घटाकर 6.25 प्रतिशत कर दिया, क्योंकि वृद्धि-मुद्रास्फीति गतिशीलता ने वृद्धि का समर्थन करने के लिए नीतिगत स्थान बनाया, जबकि मुद्रास्फीति को लक्ष्य के साथ संरेखित करने पर ध्यान केंद्रित किया। एमपीसी ने उल्लेख किया कि वैश्विक वित्तीय बाजारों में अत्यधिक अस्थिरता और वैश्विक व्यापार नीतियों के बारे में निरंतर अनिश्चितताएं, प्रतिकूल मौसम की घटनाओं के साथ, विकास और मुद्रास्फीति के परिदृश्य के लिए जोखिम पैदा करती हैं। तदनुसार, एमपीसी ने एक

[5] आईएमएफ डब्ल्यूईओ जनवरी 2025 अपडेट।

[6] आईएमएफ ने 2025 के दौरान भारत के 6.5 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है (डब्ल्यूईओ, जनवरी 2025), जबकि विश्व बैंक ने भारत की वृद्धि 6.7 प्रतिशत (जीईपी, जनवरी 2025) आंकी है।

[7] Nनीलसनआईक्यू इंडिया एफएमसीजी तिमाही स्नैपशॉट- ति4- 2024।

तटस्थ रुख जारी रखने के लिए मतदान किया, जो विकसित हो रही व्यापक आर्थिक स्थितियों पर प्रतिक्रिया करने के लिए लचीलापन प्रदान करता है।

इस पृष्ठभूमि में, लेख का शेष भाग चार खंडों में संरचित है। खंड II में वैश्विक अर्थव्यवस्था में तेजी से विकसित हो रहे घटनाक्रमों को शामिल किया गया है। खंड III में घरेलू समष्टि आर्थिक स्थितियों का आकलन किया गया है। खंड IV में भारत की वित्तीय स्थितियों का सार प्रस्तुत किया गया है, जबकि अंतिम खंड में निष्कर्ष प्रस्तुत किए गए हैं।

II. वैश्विक स्थिति

वैश्विक अर्थव्यवस्था स्थिर लेकिन मध्यम गति से बढ़ रही है, हालांकि विकास के दृष्टिकोण विभिन्न देशों में काफी भिन्न हैं। जनवरी 2025 के अपने विश्व आर्थिक परिदृश्य (डब्ल्यूईओ) अपडेट में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने अक्तूबर डब्ल्यूईओ परिदृश्य की तुलना में 10 आधार अंकों (बीपीएस) की वृद्धि के साथ 2025 के लिए विकास पूर्वानुमान को संशोधित कर 3.3 प्रतिशत कर दिया, जबकि 2026 के लिए वैश्विक विकास पूर्वानुमान को 3.3 प्रतिशत पर बरकरार रखा। विश्व बैंक ने अपने नवीनतम वैश्विक आर्थिक परिदृश्य (जीईपी) [सारणी II.1] में मोटे तौर पर इसी तरह का आकलन साझा किया है।

सारणी II.1: 2025 के लिए जीडीपी वृद्धि अनुमान – चुनिंदा एई और ईएमई

(प्रतिशत)

देश	आईएमएफ		विश्व बैंक	
	जनवरी 2025 (नवीनतम)	अक्तूबर 2024 (पिछला)	जनवरी 2025 (नवीनतम)	जून 2024 (पिछला)
विश्व*	3.3	3.2	3.2	3.2
उन्नत अर्थव्यवस्थाएँ				
यूएस	2.7	2.2	2.3	1.8
यूके	1.6	1.5	-	-
यूरो क्षेत्र	1.0	1.2	1.0	1.4
जापान	1.1	1.1	1.2	1.0
उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाएं				
ब्राज़िल	2.2	2.2	2.2	2.2
रूस	1.4	1.3	1.6	1.4
भारत*	6.5	6.5	6.7	6.7
चीन	4.6	4.5	4.5	4.1
दक्षिण अफ्रीका	1.5	1.5	1.8	1.3

नोट: *: पीपीपी भारित। #: भारत का डेटा वित्तीय वर्ष के आधार पर है।
स्रोत: आईएमएफ; और विश्व बैंक।

वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का हमारा मॉडल-आधारित पूर्वानुमान 2024 की चौथी तिमाही में वैश्विक विकास की गति में मामूली तेजी का संकेत देता है (चार्ट II.1)।

चार्ट II.1: वैश्विक जीडीपी वृद्धि का तात्कालिक अनुमान (तिमाही-दर-तिमाही)

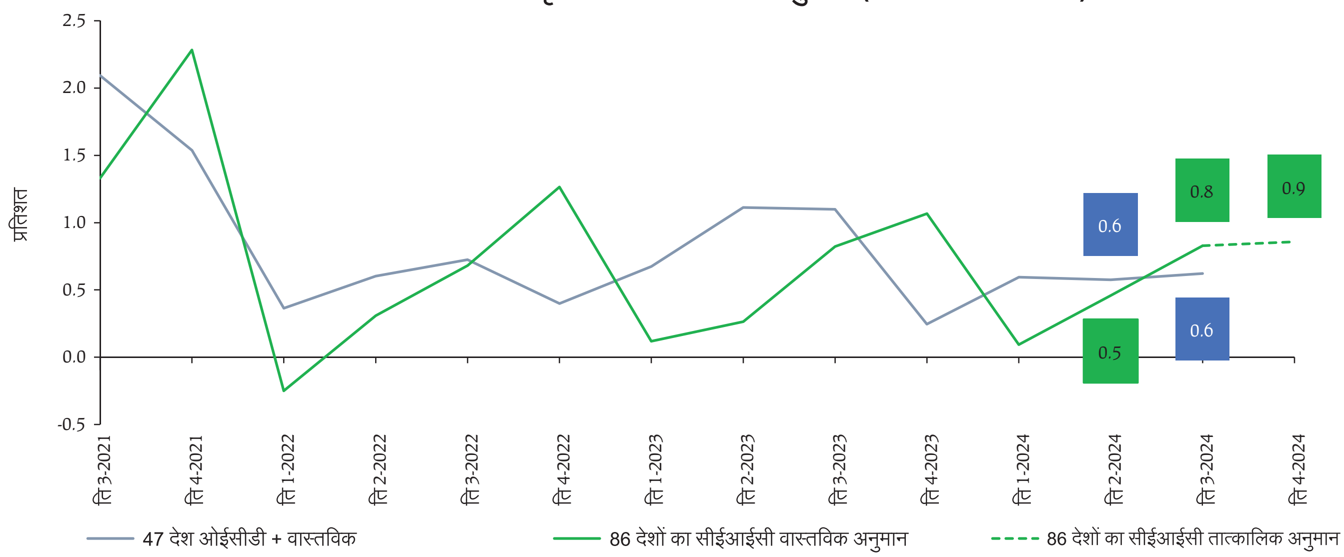

स्रोत: सीईआईसी, ओईसीडी और आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

जनवरी 2025 में वैश्विक आपूर्ति शृंखला दबाव कम हो जाएगा (चार्ट II.2ए)। भू-राजनीतिक जोखिम संकेतक ने जनवरी 2025 के मध्य में तीव्र उछाल का अनुभव किया, जो वैश्विक व्यापार संरक्षणवाद और मध्य पूर्व में तनाव दोनों से प्रेरित था। हालाँकि, बाद में इज़राइल और हमास के बीच गाजा युद्ध विराम समझौते के बाद इसमें गिरावट आई (चार्ट II.2बी)। बाल्टिक ड्राई इंडेक्स जनवरी 2025 के अंत में 23 महीने के निचले स्तर पर गिर गया – जो कि फरवरी 2023 के बाद से इसका सबसे निचला स्तर रहा - क्योंकि एशिया में पारंपरिक रूप से धीमी चंद्र नववर्ष अवधि से पहले सभी पोत खंडों में माल ढुलाई दरों में गिरावट आई। इसके साथ ही, जनवरी 2025 में शिपिंग लागत में कमी आई (चार्ट II.2सी और II.2डी)।

अमेरिका, ब्रिटेन, जापान और प्रमुख ईएमई में उपभोक्ता भावनाएँ खराब हो गईं, जबकि जनवरी 2025 में यूरो क्षेत्र में इसमें सुधार हुआ (चार्ट II.3ए और II.3बी)। प्रमुख एई में वित्तीय स्थितियाँ आसान हुईं लेकिन ईएमई में, चीन और ब्राजील में वे कठोर हो गईं (चार्ट II.3सी और II.3डी)।

वैश्विक समग्र क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) जनवरी 2025 में 12 महीने के निचले स्तर पर आ गया, क्योंकि विनिर्माण क्षेत्र में तेजी की भरपाई सेवा क्षेत्र की व्यावसायिक गतिविधि वृद्धि में मंदी से हो गई (चार्ट II.4)। जहां वैश्विक विनिर्माण पीएमआई विस्तार क्षेत्र में वापस आ कर 7 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गया, वहीं वैश्विक सेवा पीएमआई धीमी नई व्यावसायिक वृद्धि के कारण 13 महीने के निचले स्तर पर गिर गया।

जनवरी 2025 में, व्यापार नीति अनिश्चितता महामारी की शुरुआत के बाद से उच्चतम स्तर पर पहुंच गई (चार्ट II.5), जो मुख्य रूप से अमेरिकी प्रशासन में बदलाव और प्रमुख व्यापारिक साझेदारों की ओर से संभावित जवाबी उपायों के

चार्ट II.2: वैश्विक आपूर्ति शृंखला दबाव और भू-राजनीतिक जोखिमों में रुझान

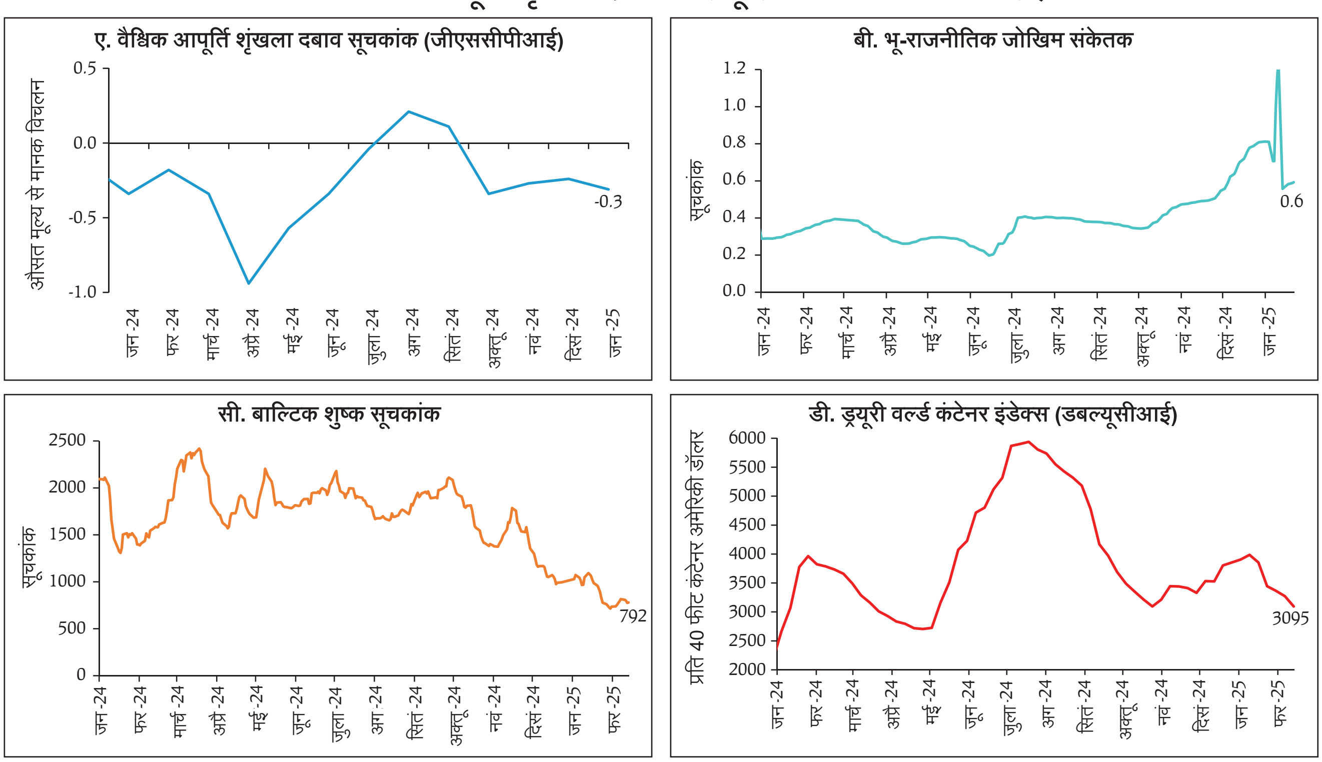

टिप्पणियाँ: 1. जीएससीपीआई परिवहन लागत और विनिर्माण संकेतकों पर डेटा दर्शाता है।
2. बाल्टिक ड्राई इंडेक्स समुद्र के रास्ते प्रमुख कच्चे माल की ढुलाई की कीमत के लिए एक बेंचमार्क प्रदान करता है और इसमें तीन उप-सूचकांक शामिल हैं जो ड्राई बल्क कैरियर के विभिन्न आकारों को मापते हैं।
3. ड्रयूरी द्वारा साप्ताहिक रूप से मूल्यांकन किया गया डबल्यूसीआई प्रमुख पूर्व-पश्चिम व्यापार मार्गों के लिए वास्तविक स्पॉट कंटेनर माल ढुलाई दरों की रिपोर्ट करता है। समग्र रूप से उक्त मान मात्रा के आधार पर 8 शिपिंग मार्गों के भारित औसत का प्रतिनिधित्व करता है और इसे प्रति 40-फुट कंटेनर अमेरिकी डॉलर में रिपोर्ट किया जाता है।

स्रोत: फेडरल रिज़र्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क; ब्लैकरॉक इनवेस्टमेंट इंस्टीट्यूट, जनवरी 2025; और ब्लूमबर्ग

चार्ट II.3: उपभोक्ता भावना और वित्तीय स्थितियाँ

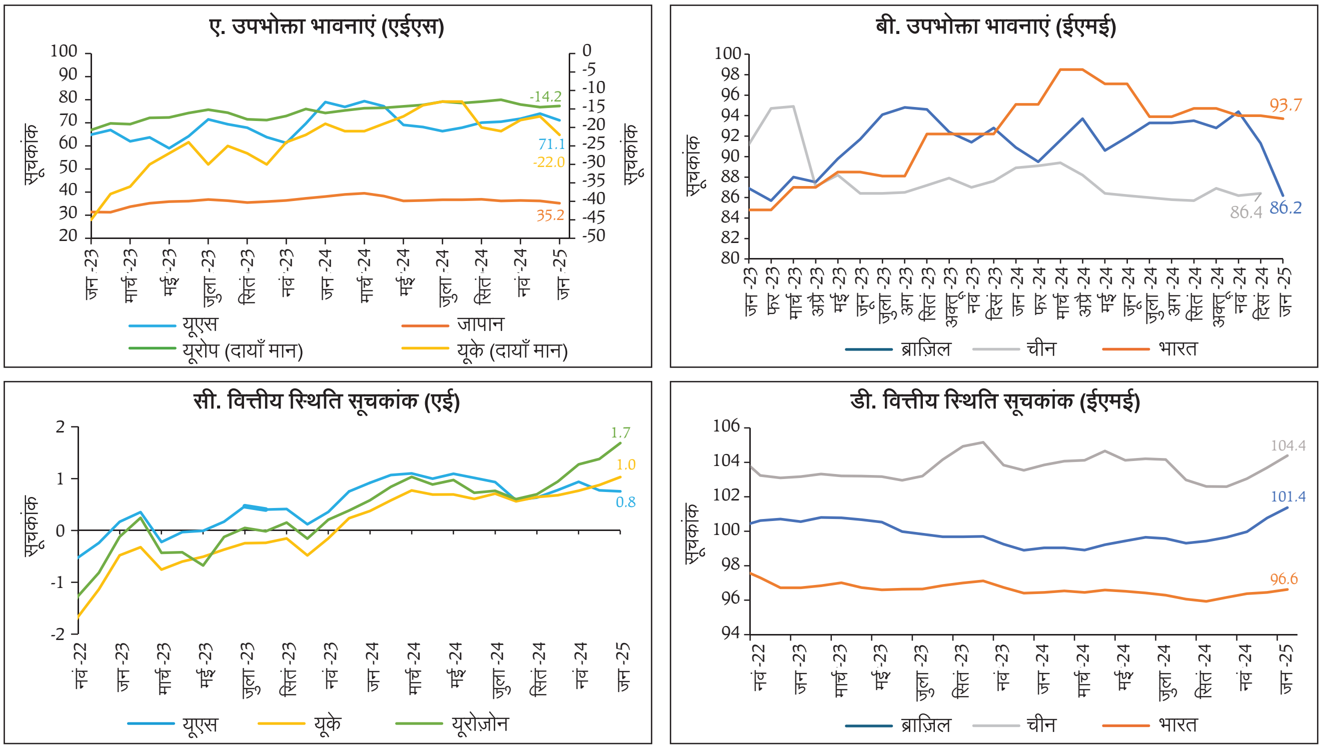

टिप्पणियाँ: 1. जापान: 50 से ऊपर का स्कोर उपभोक्ता आशावाद को दर्शाता है, 50 से नीचे का स्कोर उपभोक्ता विश्वास की कमी को दर्शाता है तथा 50 तटस्थता को दर्शाता है।
2. यूरो जोन और यूके: -100 अत्यधिक अविश्वास को दर्शाता है, O तटस्थता को दर्शाता है जबकि 100 अत्यधिक आत्मविश्वास को दर्शाता है।
3. भारत और अमेरिका: सूचकांक मूल्य जितना अधिक होगा, उपभोक्ता विश्वास भी उतना ही अधिक होगा।
4. वित्तीय स्थिति सूचकांक (गोल्डमैन सैक्स द्वारा निर्मित ईएमई से संबंधित) के लिए, 100 से नीचे का मान समायोजनात्मक है और इसके विपरीत। एई के लिए, ब्लूमबर्ग द्वारा निर्मित सूचकांक एक जेड-स्कोर है जहां एक धनात्मक मान समायोजनात्मक/आसान वित्तीय स्थितियों को इंगित करता है और इसके विपरीत।

स्रोत: ब्लूमबर्ग।

बाद नए व्यापार प्रतिबंधों, टैरिफ वृद्धि और कठोर आव्रजन नीतियों की चिंताओं से प्रेरित थी।

आईएमएफ ने विश्व व्यापार मात्रा (वस्तुओं और सेवाओं) की वृद्धि को 2025 के लिए 20 बीपीएस घटाकर 3.2 प्रतिशत

चार्ट II.4: वैश्विक क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई)

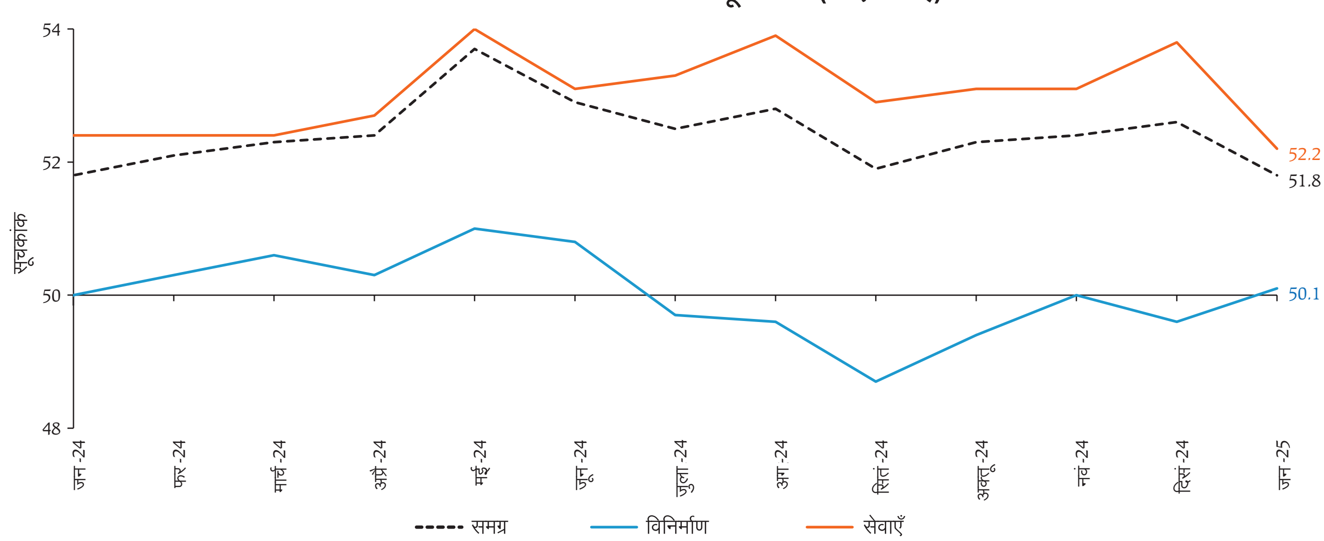

टिप्पणी: 50 का स्तर गतिविधि में कोई परिवर्तन नहीं होने को दर्शाता है तथा 50 से ऊपर का स्तर विस्तार को दर्शाता है और इसके विपरीत।

स्रोत: एस एंड पी ग्लोबल।

चार्ट II.5: नीति अनिश्चितता सूचकांक

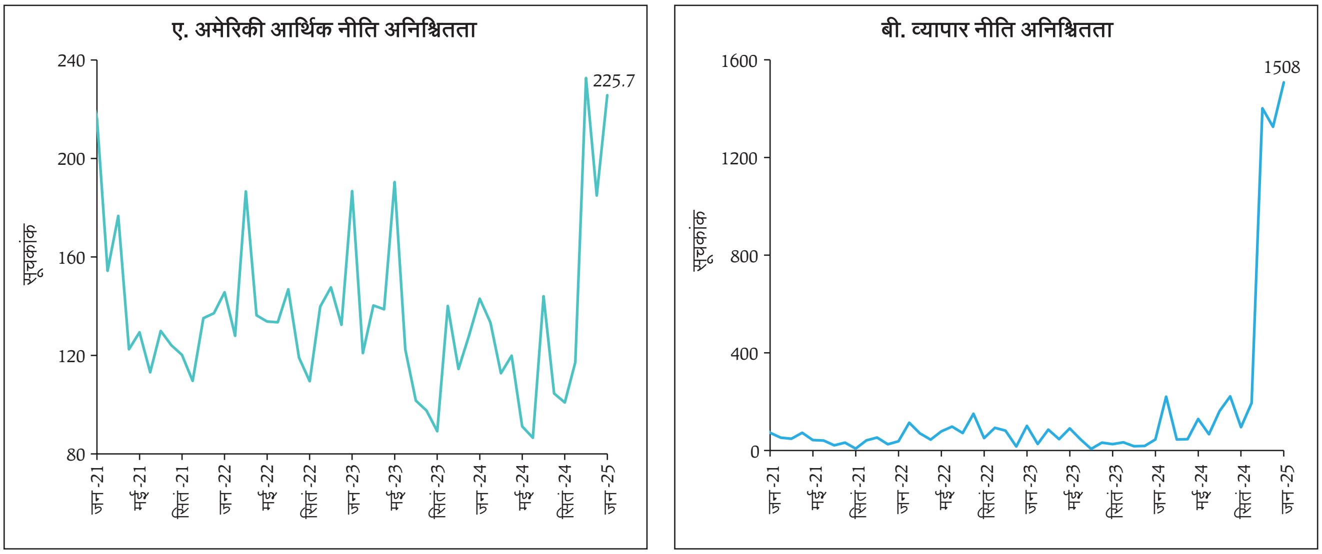

स्रोत: एनवाई फेड फ्रेड डेटाबेस; और बेकर, ब्लूम, और डेविस (2016)।

और 2026 के लिए 10 बीपीएस घटाकर 3.3 प्रतिशत कर दिया है।[8] जनवरी 2025 में नए निर्यात ऑर्डर के लिए समग्र पीएमआई संकुचन क्षेत्र में रहा, जबकि विनिर्माण निर्यात ऑर्डर में वृद्धि के कारण क्रमिक वृद्धि हुई, जिसने सेवा निर्यात ऑर्डर में गिरावट की भरपाई की। जापान, भारत और चीन के निर्यात सूचकांकों में विस्तार दर्ज किया गया, जबकि अमेरिका और यूके में संकुचन देखा गया (चार्ट II.6ए और II.6बी)।

जनवरी में वैश्विक पण्य की कीमतों में आम तौर पर बढ़ोतरी हुई है जैसा कि ब्लूमबर्ग पण्य सूचकांक में परिलक्षित होता है, जिसमें 3.6 प्रतिशत की मासिक बढ़ोतरी दर्ज की गई है (चार्ट II.7ए)। रूस के ऊर्जा क्षेत्र पर नए अमेरिकी प्रतिबंधों

चार्ट II.6: वैश्विक पीएमआई: नए निर्यात ऑर्डर

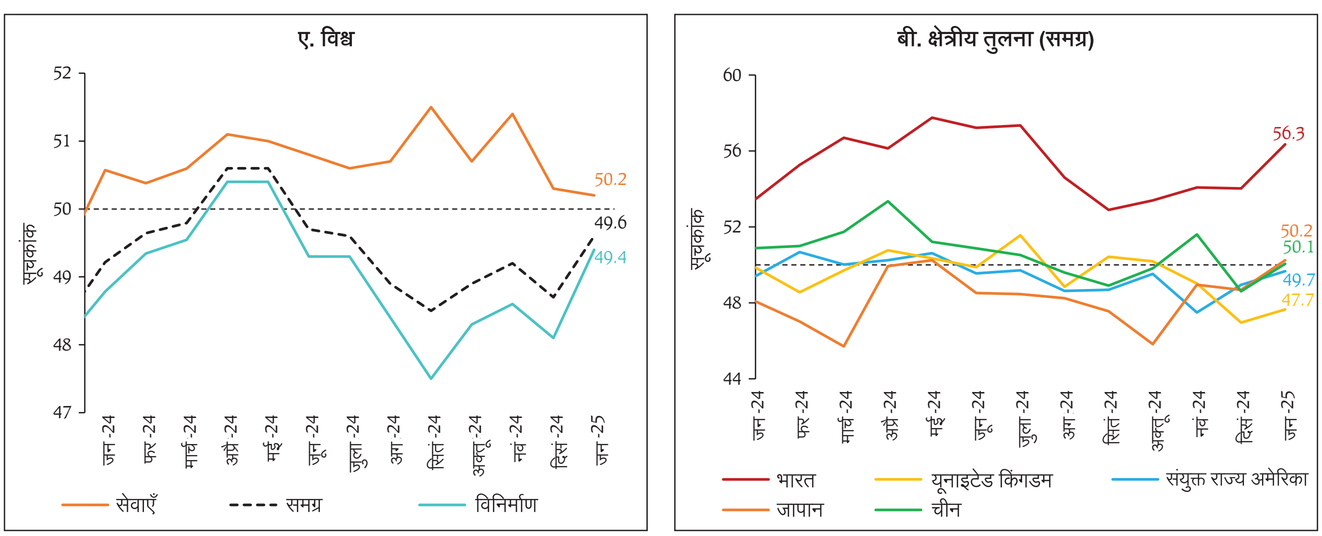

टिप्पणी: 50 का स्तर गतिविधि में कोई परिवर्तन नहीं होने को दर्शाता है तथा 50 से ऊपर का स्तर विस्तार को दर्शाता है और इसके विपरीत।
स्रोत: एस एंड पी ग्लोबल।

[8] आईएमएफ डब्ल्यूईओ जनवरी 2025 अपडेट।

चार्ट II. 7: पण्य और खाद्य वस्तुओं की कीमतें

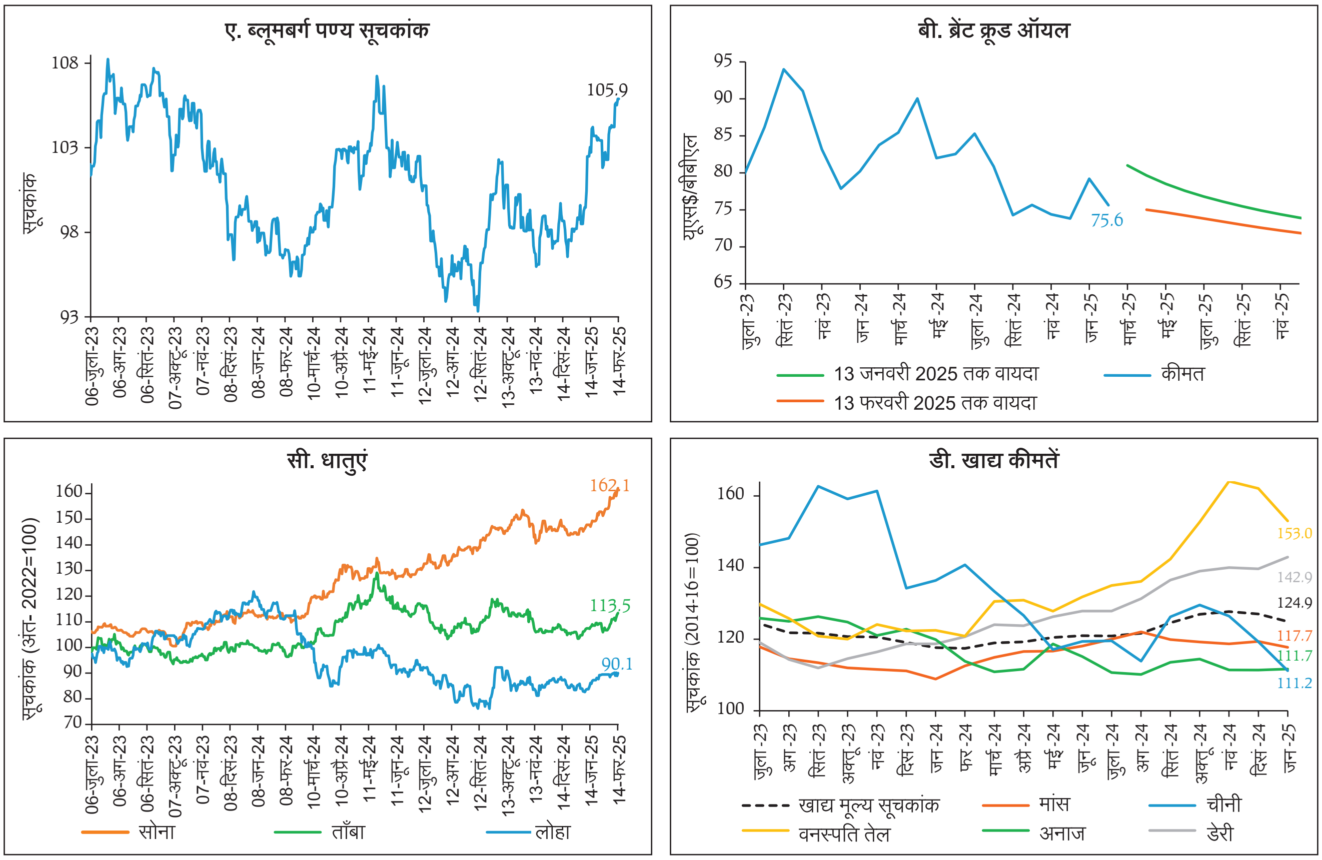

स्रोत: ब्लूमबर्ग; विश्व बैंक पिंक शीट; तथा एफएओ।

और ठंड के मौसम में मांग बढ़ने के बीच जनवरी में कच्चे तेल की कीमतों में 7.2 प्रतिशत (मासिक) की बढ़ोतरी हुई (चार्ट II.7बी)। आधार धातुओं के दुनिया के सबसे बड़े उपभोक्ता चीन द्वारा अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन उपायों का संकेत देने के बाद जनवरी में आधार धातुओं की कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई। जनवरी में कीमती धातुओं, खास तौर पर सोने की कीमतों में तेज वृद्धि दर्ज की गई, जिसे भू-आर्थिक और व्यापार अनिश्चितताओं के बीच सुरक्षित-आश्रय मांग से समर्थन मिला (चार्ट II.7सी)। एफएओ के खाद्य मूल्य सूचकांक द्वारा मापी गई खाद्य कीमतों में जनवरी 2025 में (-) 1.6 प्रतिशत की गिरावट आई, जो मुख्य रूप से चीनी, वनस्पति तेल और मांस की कीमतों में कमी के कारण हुई, जिसे डेयरी और अनाज की कीमतों में वृद्धि से आंशिक रूप से समायोजित किया गया (चार्ट II.7डी)।

अमेरिका में, सीपीआई मुद्रास्फीति दिसंबर में 2.9 प्रतिशत से जनवरी में बढ़कर 3.0 प्रतिशत (वर्ष दर वर्ष) हो गई। व्यक्तिगत उपभोग व्यय (पीसीई) अपस्फीतिकारक के संदर्भ में मुद्रास्फीति भी नवंबर में 2.4 प्रतिशत से दिसंबर में बढ़कर 2.6 प्रतिशत हो गई। यूरो क्षेत्र में हेडलाइन मुद्रास्फीति दिसंबर में 2.4 प्रतिशत से जनवरी में 2.5 प्रतिशत हो गई। जापान में मुद्रास्फीति (ताजा भोजन को छोड़कर सीपीआई) दिसंबर में बढ़कर 3.0 प्रतिशत हो गई, जबकि यूके में यह 10 बीपीएस घटकर 2.5 प्रतिशत हो गई (चार्ट II.8 ए) । ईएमई में, चीन में सीपीआई मुद्रास्फीति जनवरी में पांच महीने के उच्च स्तर 0.5 प्रतिशत पर पहुंच गई; रूस और दक्षिण अफ्रीका में भी दिसंबर में मुद्रास्फीति में वृद्धि देखी गई; अमेरिका और यूरो क्षेत्र दोनों में सेवा मुद्रास्फीति में कमी आई है, लेकिन यह उच्च स्तर पर बनी हुई है (चार्ट II.8सी और II.8डी)।

मॉर्गन स्टेनली कैपिटल इंटरनेशनल (एमएससीआई) विश्व इक्विटी सूचकांक जनवरी में 3.3 प्रतिशत (माह दर माह) बढ़

चार्ट II.8: मुद्रास्फीति - एई और ईएमई

स्रोत: ब्लूमबर्ग: और ओईसीडी।

गया, जिसमें एई इक्विटी बाजारों में ईएमई की तुलना में अधिक लाभ हुआ, भले ही नीति अनिश्चितता के कारण अस्थिरता अधिक रही (चार्ट II.9ए)। जनवरी के पहले पखवाड़े में अमेरिकी सरकार की प्रतिभूतियों पर प्रतिफल मजबूत हुआ क्योंकि कम बेरोजगारी के बीच मजबूत खुदरा बिक्री और औद्योगिक उत्पादन जैसे डेटा जारी होने से अमेरिकी अर्थव्यवस्था में अंतर्निहित मजबूती का संकेत मिला। दूसरी छमाही में प्रतिफल कम हो गया, क्योंकि मुद्रास्फीति के डेटा जारी होने और फेडरल ओपन मार्केट कमेटी (एफओएमसी) के बयान ने अनिश्चितता को कम करने में मदद की। उम्मीद से अधिक सीपीआई मुद्रास्फीति के कारण फरवरी में प्रतिफल में फिर से वृद्धि हुई (चार्ट II.9बी)। जनवरी के पहले पखवाड़े में यूएस डॉलर सूचकांक (डीएक्सवाई) में वृद्धि हुई, लेकिन बाद में इसने अपने कुछ लाभ खो दिए। नए यूएस प्रशासन द्वारा व्यापार नीति उपायों की घोषणाओं के प्रतिउत्तर में डीएक्सवाई अस्थिर रहा। ईएमई के लिए एमएससीआई मुद्रा सूचकांक ने डीएक्सवाई में उतार-चढ़ाव को प्रतिबिंबित किया, जिसमें पूंजी बहिर्वाह, विशेष रूप से इक्विटी खंड में, नीचे की ओर दबाव डाला गया (चार्ट II.9सी और II.9डी)।

विभिन्न देशों में मौद्रिक नीति कार्रवाइयों में भिन्न-भिन्न समष्टि आर्थिक स्थितियाँ प्रतिबिंबित होती हैं। एई केंद्रीय बैंकों में, यूएस, दक्षिण कोरिया और नॉर्वे ने अपनी नीतिगत दरों को अपरिवर्तित रखा। इसके विपरीत, यूरो क्षेत्र, कनाडा और स्वीडन ने जनवरी में अपनी नीतिगत दरों में 25 आधार अंकों की कटौती की, जबकि यू.के. और चेक गणराज्य ने फरवरी में अपनी प्रमुख दरों में 25 आधार अंकों की कटौती की (चार्ट II.10ए)। हालाँकि, जापान ने अपनी नीतिगत दर में 25 आधार अंकों की वृद्धि की। ईएमई केंद्रीय बैंकों में, चीन, चिली, हंगरी, कोलंबिया, मलेशिया, फिलीपींस और पेरू ने अपनी नीतिगत दरें बनाए रखीं। दक्षिण अफ्रीका और इंडोनेशिया ने जनवरी 2025 में अपनी नीतिगत दरों में 25 आधार अंकों की कटौती की,

चार्ट II.9: वैश्विक वित्तीय बाज़ार

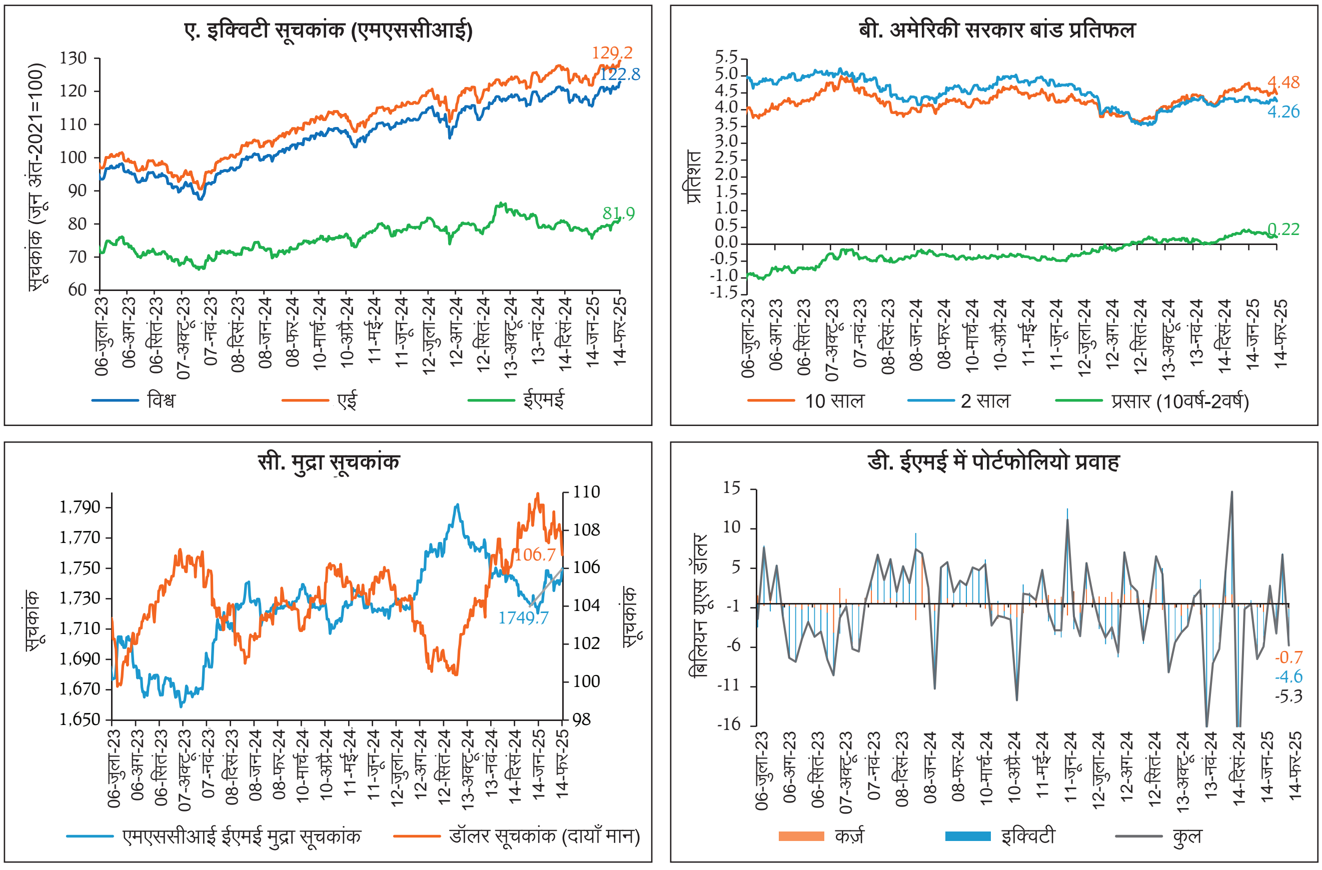

स्रोत: ब्लूमबर्ग; और आईआईएफ।

जबकि मेक्सिको और भारत ने फरवरी में अपनी बेंचमार्क दरों में क्रमशः 50 आधार अंकों और 25 आधार अंकों की कटौती की। दूसरी ओर, ब्राजील ने जनवरी में इसमें 100 आधार अंकों की वृद्धि की (चार्ट II.10बी)।

चार्ट II.10: नीति दरों में परिवर्तन

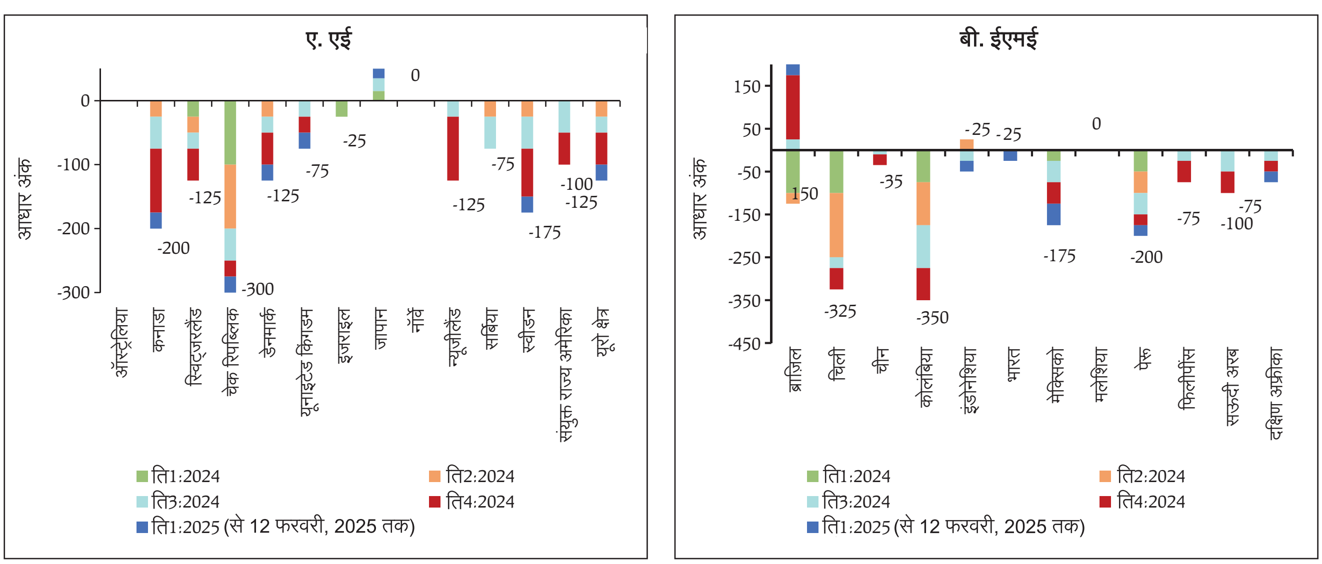

स्रोत: ब्लूमबर्ग।

III. घरेलू घटनाक्रम

भारतीय अर्थव्यवस्था उपभोग मांग और समग्र निवेश में सुधार के कारण अपनी वृद्धि की गति को पुनः प्राप्त कर रही है। जनवरी 2025 में आरबीआई के नवीनतम सर्वेक्षण के अनुसार, उपभोक्ता विश्वास आशावादी बना हुआ है, भविष्य की अपेक्षा सूचकांक (एफईआई) आशावादी क्षेत्र में दृढ़ता से बना हुआ है, हालांकि इसमें थोड़ी क्रमिक नरमी आई है, हालांकि वर्तमान स्थिति सूचकांक (सीएसआई) निराशावादी क्षेत्र में बना हुआ है (चार्ट III.1ए)। जनवरी में मामूली वृद्धि के बावजूद आपूर्ति शृंखला दबाव ऐतिहासिक औसत स्तरों से नीचे रहा (चार्ट III.1बी)। सत्ताईस उच्च आवृत्ति संकेतकों में अंतर्निहित सामान्य प्रवृत्ति को निकालकर निर्मित आर्थिक गतिविधि सूचकांक, यह दर्शाता है कि जनवरी में गतिविधि ने अपनी गति बनाए रखी और 2024-25 की चौथी तिमाही के लिए जीडीपी का अब तक का अनुमान 6.6 प्रतिशत रखा गया है (चार्ट III.1सी और चार्ट III.1डी)।

समग्र मांग

उच्च आवृत्ति संकेतक बताते हैं कि कुल मांग पहली छमाही में देखी गई मंदी से उबर रही है। जनवरी में ई-वे बिल की वृद्धि बढ़कर 23.1 प्रतिशत हो गई (चार्ट III.2ए)। टोल संग्रह में मात्रा और मूल्य दोनों के दृष्टिकोण से मजबूत वृद्धि दर्ज की गई (चार्ट III.2बी)।

जनवरी में थोक ऑटोमोबाइल बिक्री में सुधार हुआ, दो महीने की गिरावट के बाद, इसमें 2.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई (चार्ट III.3ए)। दोपहिया वाहन खंड में सुधार देखा गया, मुख्य रूप से स्कूटर की बिक्री में उछाल के कारण, हालांकि मोटरसाइकिल की बिक्री में लगातार तीसरे महीने गिरावट आई (चार्ट III.3बी)। ट्रैक्टर की बिक्री में लगातार दूसरे महीने दोहरे अंकों की वृद्धि दर्ज

चार्ट III.1: आर्थिक गतिविधि संकेतक

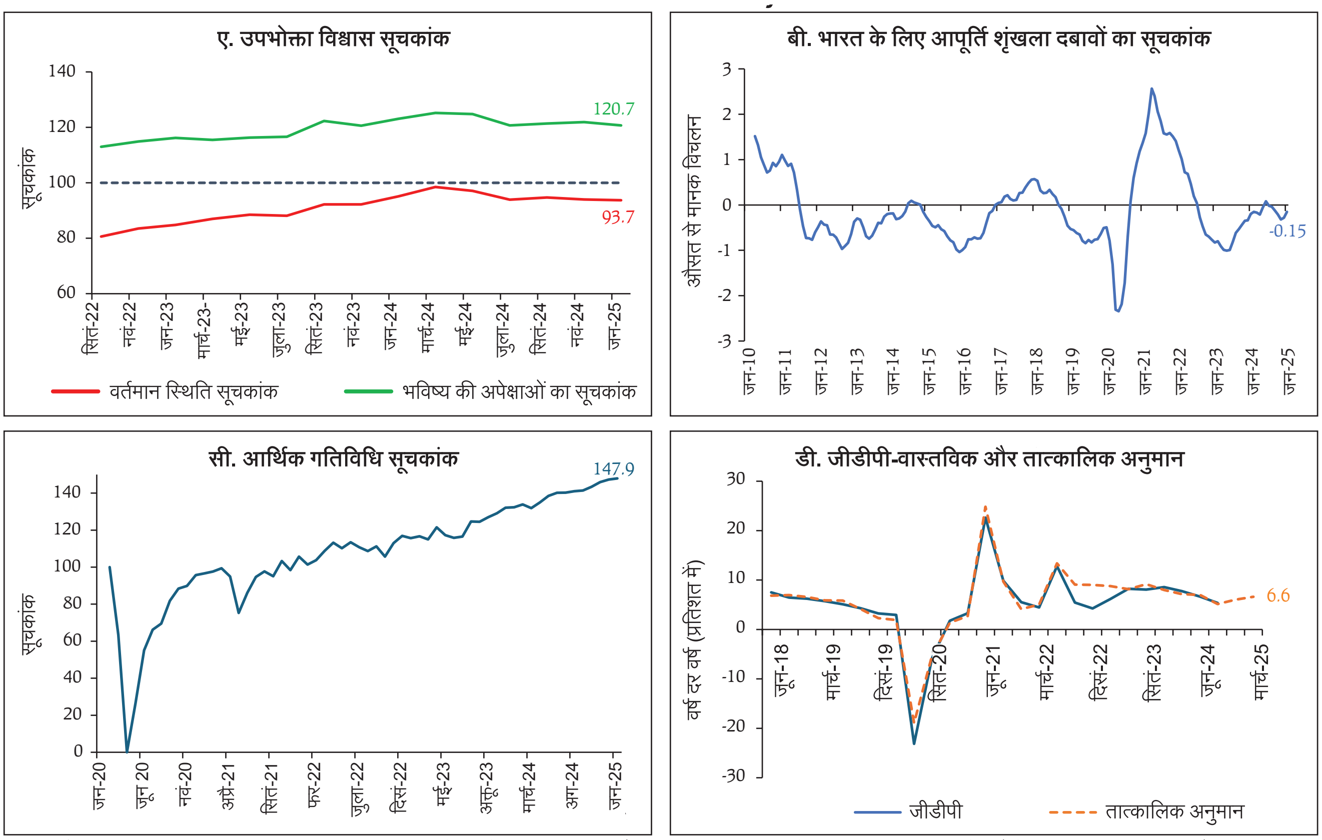

टिप्पणियाँ: 1. आर्थिक गतिविधि सूचकांक (ईएआई) का निर्माण डायनेमिक फैक्टर मॉडल का उपयोग करके आर्थिक गतिविधि के सत्ताईस उच्च आवृत्ति संकेतकों में अंतर्निहित सामान्य प्रवृत्ति को निकालकर किया जाता है। फरवरी 2020 में ईएआई को 100 और अप्रैल 2020 में 0 पर रखा गया, जो गतिशीलता प्रतिबंधों के कारण सबसे अधिक प्रभावित महीना था।
2. जीडीपी तात्कालिक अनुमान के लिए, अंतर्निहित संख्या प्रथम अग्रिम अनुमान (एफएई) से उपलब्ध है।

स्रोत: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ); और आरबीआई स्टाफ के अनुमान।

चार्ट III.2 : ई-वे बिल और टोल संग्रह

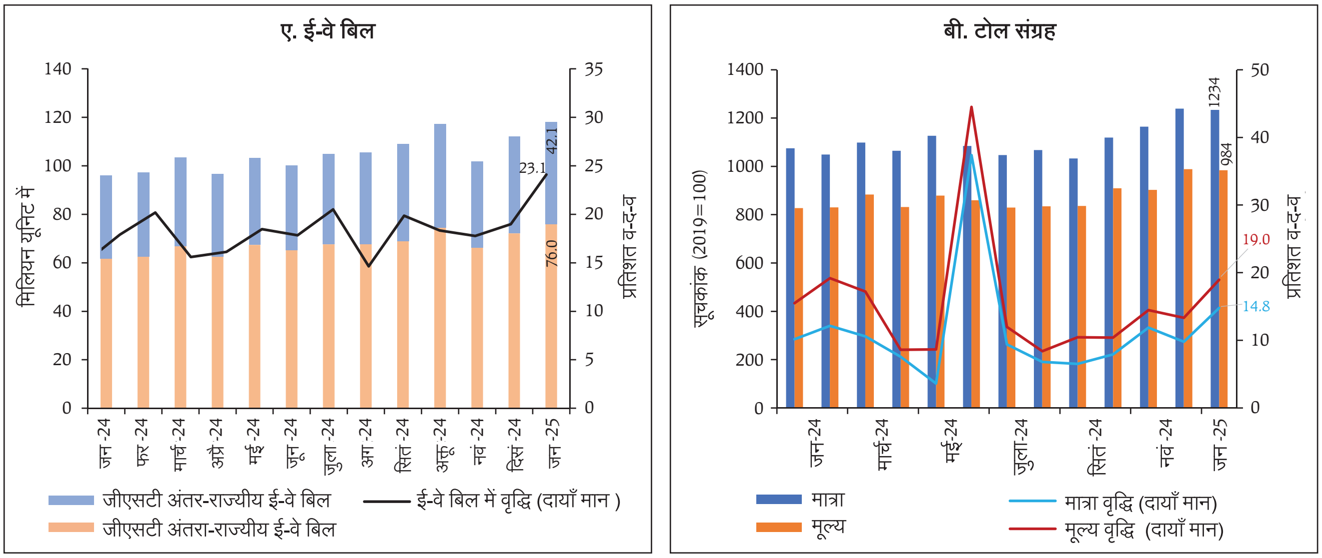

स्रोत: जीएसटीएन; आरबीआई।

की गई। जनवरी में वाहन पंजीकरण में विस्तार दर्ज किया गया, जो गैर-परिवहन और परिवहन वाहन दोनों खंडों में वृद्धि के कारण हुआ (चार्ट III.3सी)। जनवरी में पेट्रोलियम की खपत में 3.1 प्रतिशत (वर्ष दर वर्ष) की वृद्धि हुई (चार्ट III.3डी)।

चार्ट III.3: परिवहन क्षेत्र संकेतक

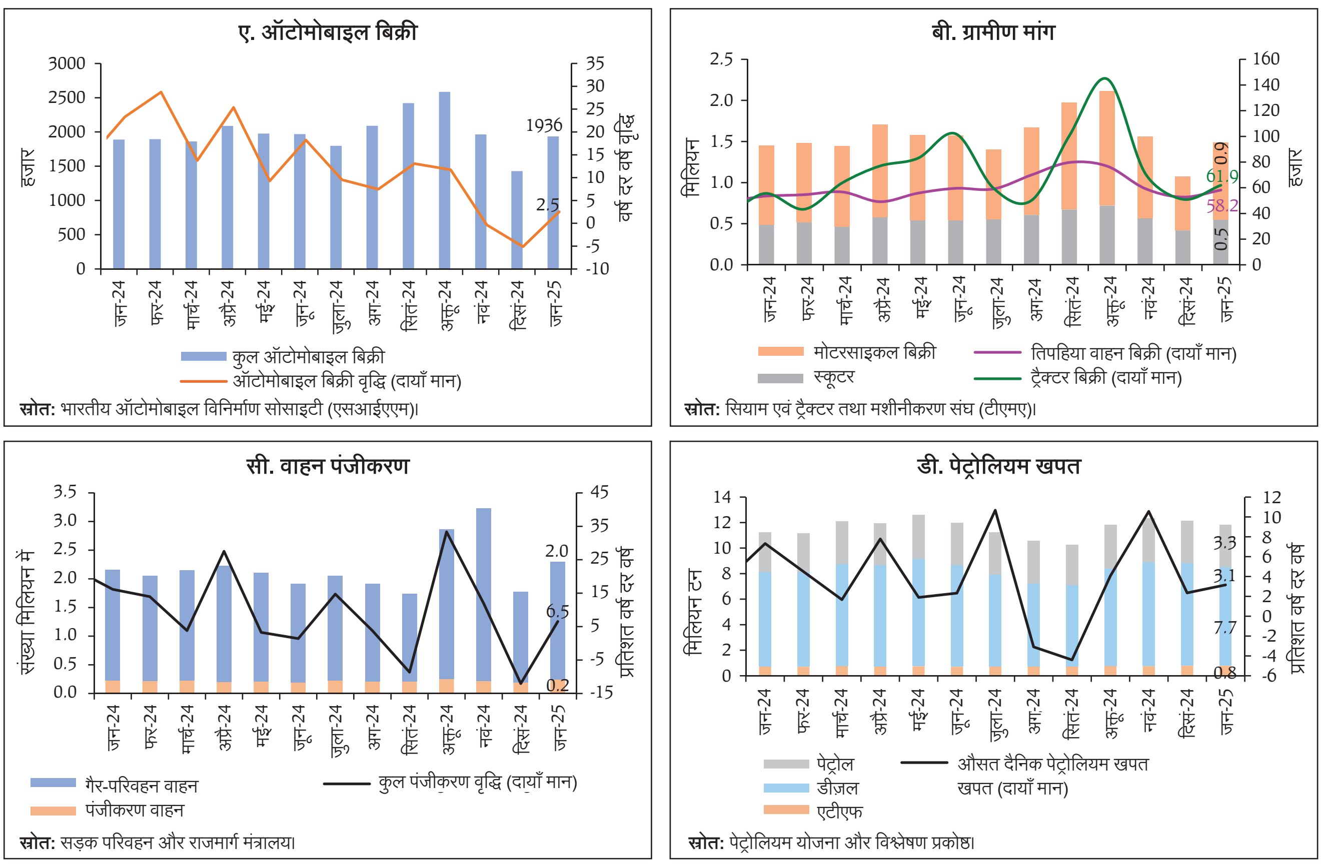

चार्ट III.4: राज्यवार इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने की दरें

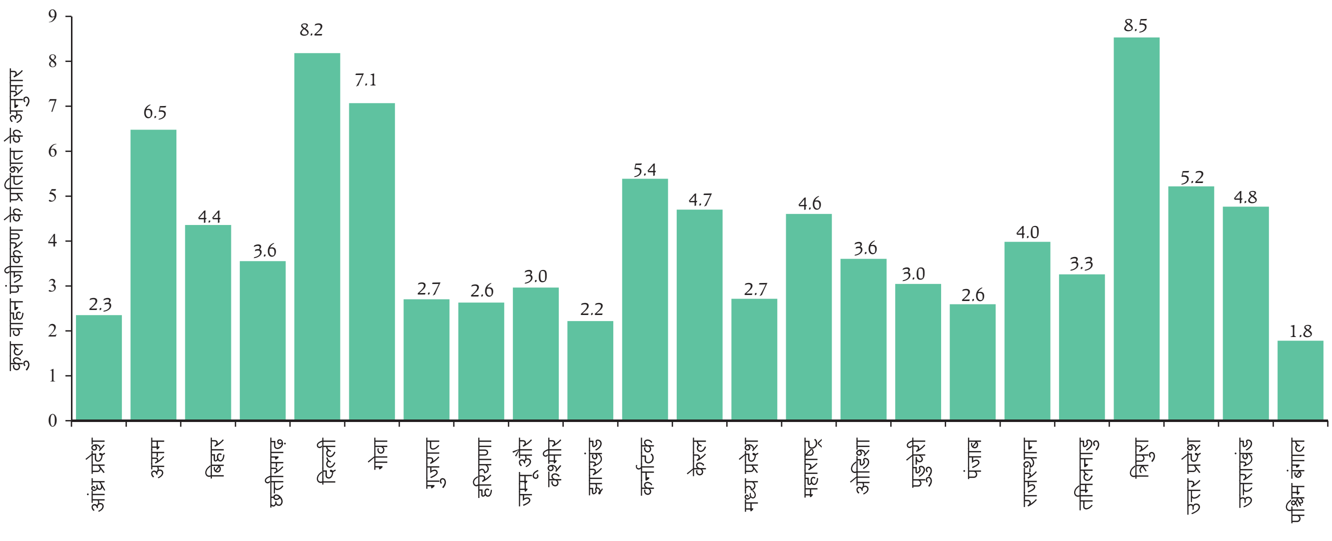

स्रोत: 'वाहन डैशबोर्ड'।

भारत में पिछले कुछ वर्षों में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को अपनाने की दर में वृद्धि देखी गई है। 2024 में, कुल वाहन पंजीकरण में ईवी की हिस्सेदारी 2021 में 2 प्रतिशत से कम से बढ़कर 7 प्रतिशत से अधिक हो गई। असम, दिल्ली, गोवा, कर्नाटक और त्रिपुरा जैसे राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में ईवी अपनाने की दर अपेक्षाकृत अधिक देखी गई है [9] (चार्ट III.4) ।

सितंबर 2024 में शुरू की गई पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट (पीएम ई-ड्राइव) योजना का उद्देश्य ईवी को अपनाने को प्रोत्साहित करना है और इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल पब्लिक चार्जिंग स्टेशन (ईवीपीसीएस) के विकास का प्रावधान किया गया है।[10] दिसंबर 2024 तक, कर्नाटक में सबसे अधिक ईवीपीसीएस थे, उसके बाद महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश (चार्ट III.5) थे।

चार्ट III.5: ईवी सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों की संख्या

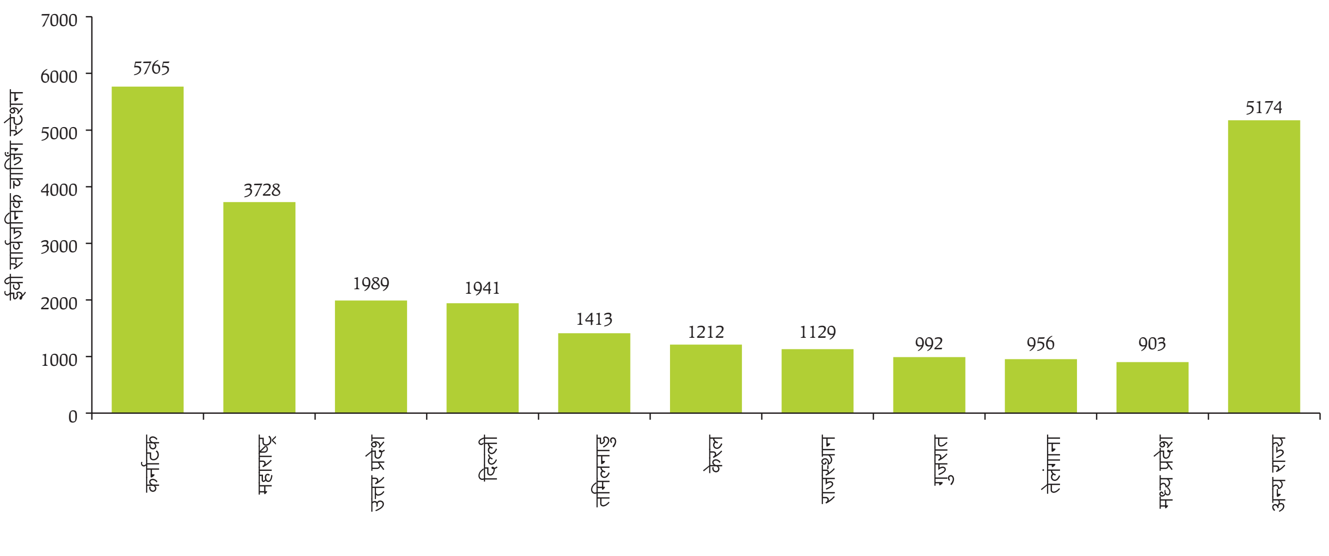

स्रोत: भारी उद्योग मंत्रालय, पीआईबी विज्ञप्ति दिनांक 20 दिसंबर, 2024।

9 जनवरी 2019 से फरवरी 2025 की अवधि के लिए संबंधित राज्य में कुल ईवी पंजीकरण को कुल वाहन पंजीकरण से विभाजित करके अपनाने की दरों की गणना की जाती है।

10 दो साल की अवधि के लिए ₹10,900 करोड़ का परिव्यय प्रदान किया गया, जिसमें से ₹2,000 करोड़ ईवीपीसीएस के लिए रखे गए हैं।

चार्ट III.6: पीएमआई रोजगार सूचकांक

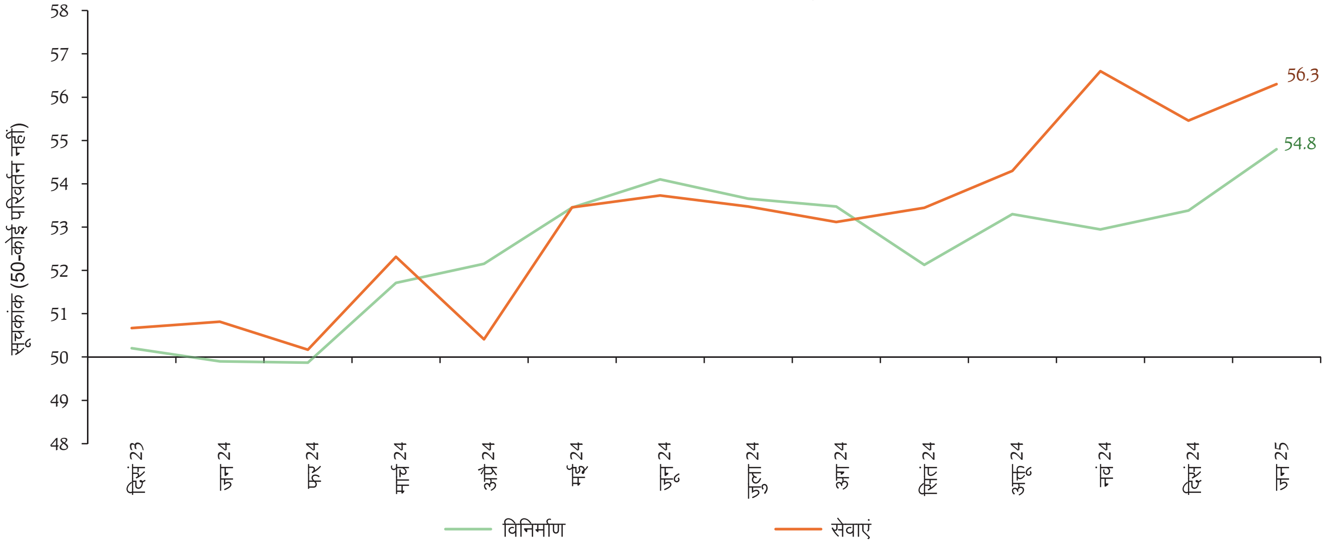

टिप्पणी: 50 से ऊपर का पीएमआई मूल्य विस्तार को दर्शाता है।
स्रोत: एस एंड पी ग्लोबल।

जनवरी 2025 में, संगठित विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार पीएमआई सर्वेक्षण की शुरुआत के बाद से रिकॉर्ड गति से बढ़ा, जबकि सेवा क्षेत्र में रोजगार सृजन भी इस शृंखला[11] में सबसे मजबूत था (चार्ट III.6)।

रबी की बुवाई करीब आने के कारण महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) के तहत काम की मांग जनवरी 2025 में लगातार तीसरे महीने 14.4 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) बढ़ी (चार्ट III.7)।

भारत का पण्य निर्यात जनवरी 2025 में 2.4 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) घटकर 36.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर रह गया, जिसका मुख्य कारण तेल निर्यात में गिरावट है (चार्ट III.8)।

चार्ट III.7: परिवारों द्वारा मनरेगा के तहत काम की मांग

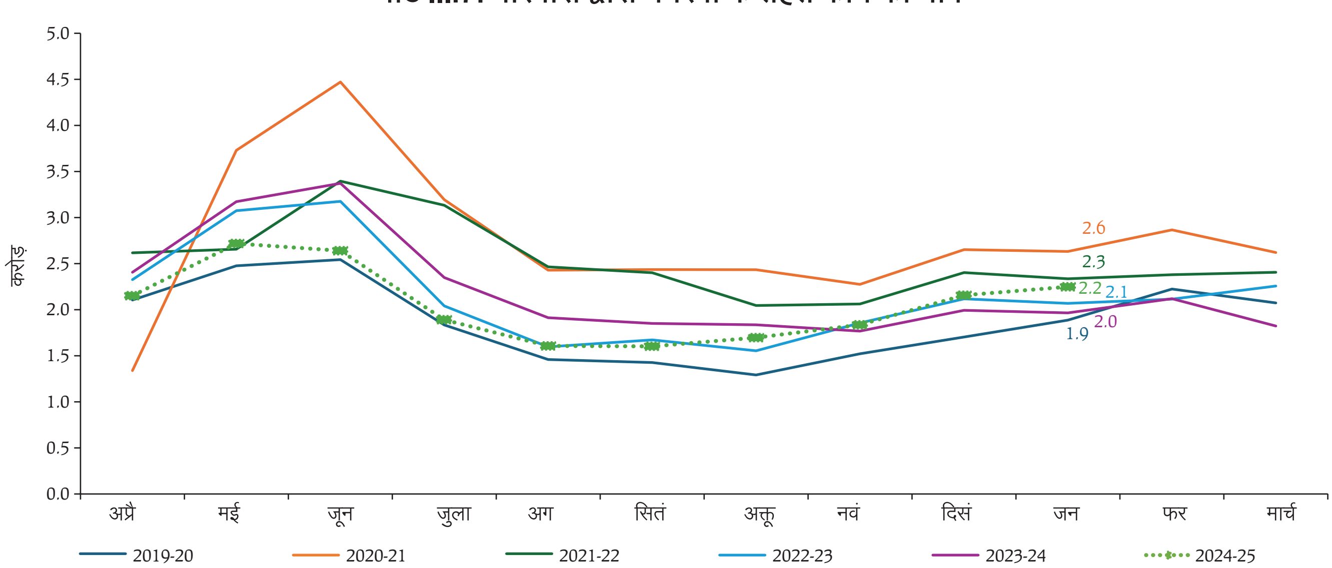

स्रोत: ग्रामीण विकास मंत्रालय।

[11] सर्वेक्षण 2005 में शुरू हुआ था।

चार्ट III.8: भारत का पण्य निर्यात

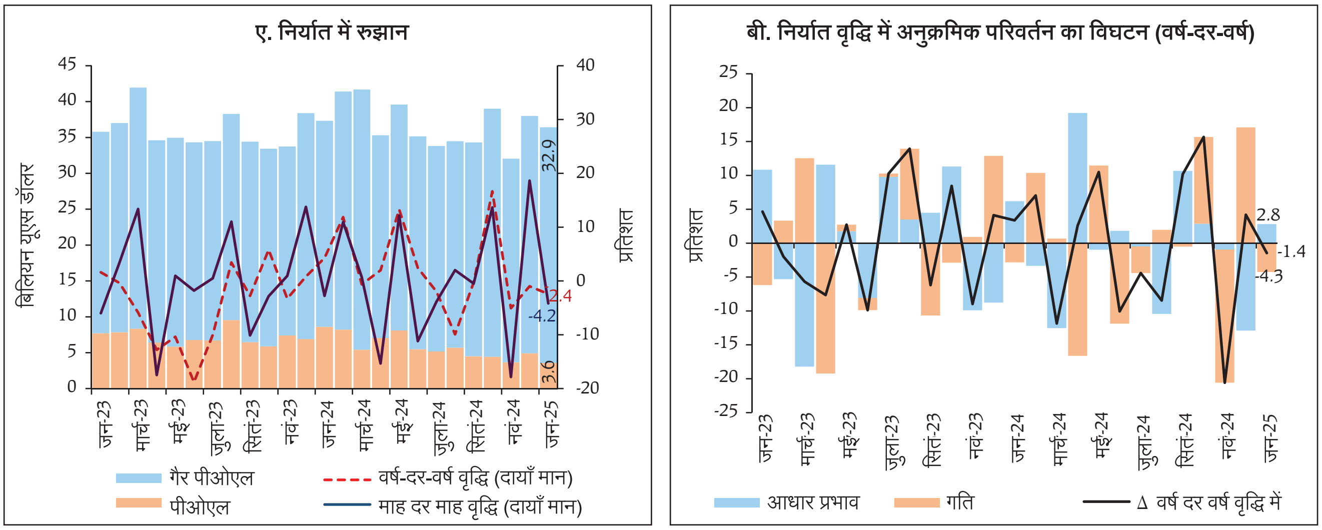

टिप्पणी: पीओएल: पेट्रोलियम, तेल और स्नेहक।
स्रोत: पीआईबी; डीजीसीआईएंडएस; तथा आरबीआई स्टाफ अनुमान।

संकुचन कुछ उत्पाद समूहों तक ही सीमित रहा क्योंकि 30 प्रमुख वस्तुओं (निर्यात बास्केट का 27.6 प्रतिशत हिस्सा) में से केवल 5 के निर्यात में साल दर साल आधार पर गिरावट आई। प्रमुख समूहों में, पेट्रोलियम उत्पादों और लौह अयस्क ने ऋणात्मक योगदान दिया, जबकि इलेक्ट्रॉनिक सामान, इंजीनियरिंग सामान और दवाओं तथा फार्मास्यूटिकल्स ने समर्थन दिया (चार्ट III.9)।

चार्ट III.9: भारत का पण्य निर्यात - सापेक्ष योगदान
(जनवरी 2024 की तुलना में जनवरी 2025)

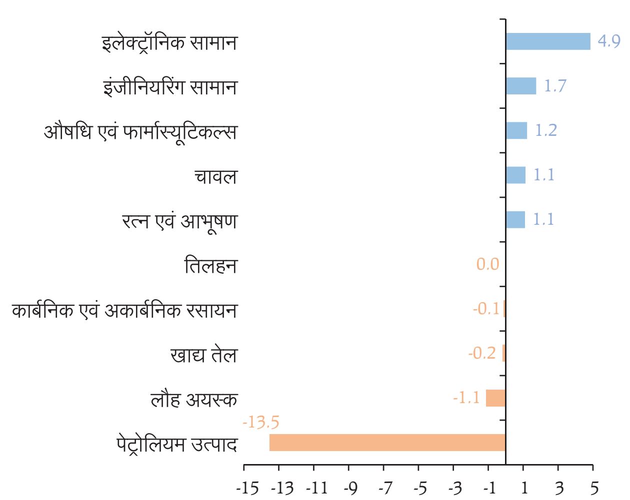

स्रोत: पीआईबी; तथा आरबीआई स्टाफ अनुमान।

अप्रैल-जनवरी 2024-25 के दौरान, भारत का व्यापारिक निर्यात 1.4 प्रतिशत बढ़कर 358.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जिसका मुख्य नेतृत्व इंजीनियरिंग सामान, इलेक्ट्रॉनिक सामान, चावल और दवाओं और फार्मास्यूटिकल्स ने किया, जबकि पेट्रोलियम उत्पादों, रत्न और आभूषण और लौह अयस्क ने निर्यात को नीचे ला दिया।

जनवरी 2025 में 20 प्रमुख गंतव्यों में से 10 को निर्यात में विस्तार हुआ। अप्रैल-जनवरी 2024-25 के दौरान, 20 प्रमुख गंतव्यों में से 15 को निर्यात में विस्तार हुआ, जिसमें अमेरिका, यूएई और नीदरलैंड शीर्ष तीन निर्यात गंतव्य रहे।

जनवरी में व्यापारिक आयात 10.3 प्रतिशत (वर्ष दर वर्ष) बढ़कर 59.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर पहुंच गया (चार्ट III.10)। 30 प्रमुख वस्तुओं में से 26 वस्तुओं (आयात बास्केट का 59.7 प्रतिशत हिस्सा) में वर्ष दर वर्ष आधार पर वृद्धि दर्ज की गई।

इलेक्ट्रॉनिक सामान, विद्युत और गैर-विद्युत मशीनरी और सोना प्रमुख समूह थे जिन्होंने धनात्मक योगदान दिया, जबकि पेट्रोलियम, कच्चे तेल और उत्पाद तथा मोती, कीमती और अर्ध-कीमती पत्थर प्रमुख समूह थे जिन्होंने ऋणात्मक योगदान दिया (चार्ट III.11)।

चार्ट III. 10: भारत का पण्य आयात

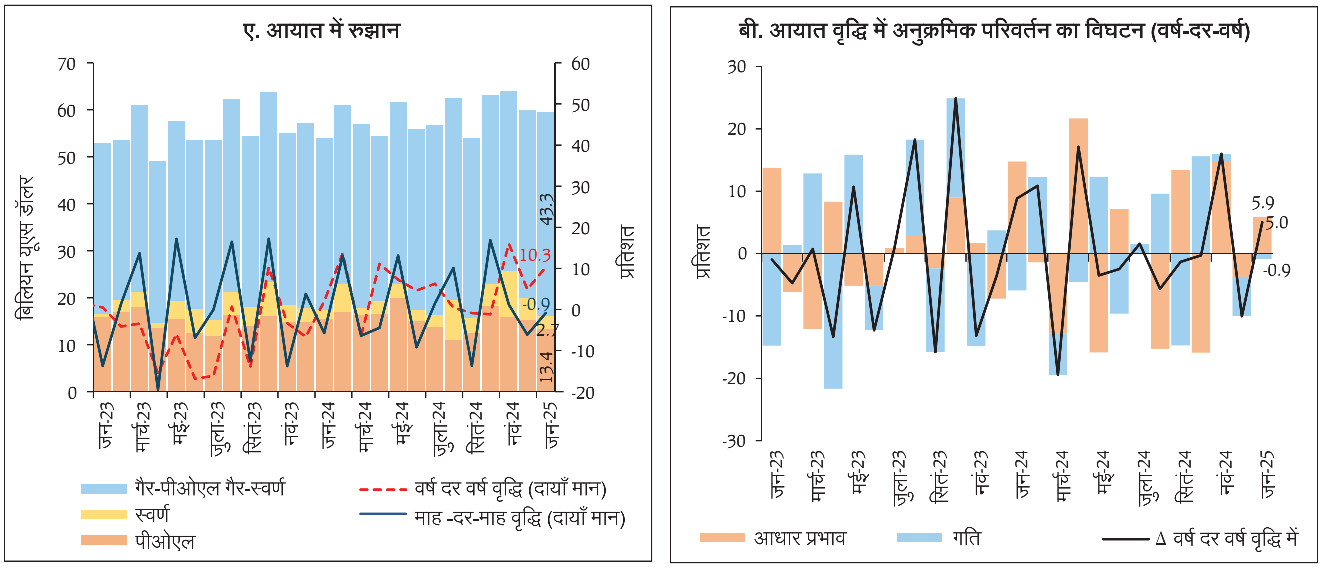

स्रोत: पीआईबी; डीजीसीआईएंडएस; तथा आरबीआई स्टाफ अनुमान।

अप्रैल-जनवरी 2024-25 के दौरान, भारत का व्यापारिक आयात 7.4 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) बढ़कर 609.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जिसमें मुख्य रूप से सोना, पेट्रोलियम, कच्चे तेल और उत्पादों तथा इलेक्ट्रॉनिक सामानों का योगदान रहा, जबकि कोयला, कोक और ब्रिकेट, आदि, मोती, कीमती और अर्ध-कीमती पत्थरों तथा लोहा और इस्पात के आयात में गिरावट आई।

जनवरी में 20 प्रमुख स्रोत देशों में से 13 से आयात बढ़ा और अप्रैल-जनवरी 2024-25 के दौरान 20 प्रमुख स्रोत देशों में से 15 से आयात बढ़ा। अप्रैल-जनवरी 2024-25 के दौरान प्रमुख स्रोत देशों यानी चीन, रूस और यूएई से आयात में वृद्धि दर्ज की गई।

जनवरी 2025 में व्यापारिक व्यापार घाटा बढ़कर 23.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो जनवरी 2024 में 16.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। जनवरी में तेल और गैर-तेल दोनों घाटा एक साल पहले की तुलना में अधिक रहा (चार्ट III.12)। जनवरी में कुल व्यापार घाटे में तेल घाटे की

चार्ट III.11: भारत का पण्य आयात - सापेक्ष योगदान

(जनवरी 2025 की तुलना में जनवरी 2024)

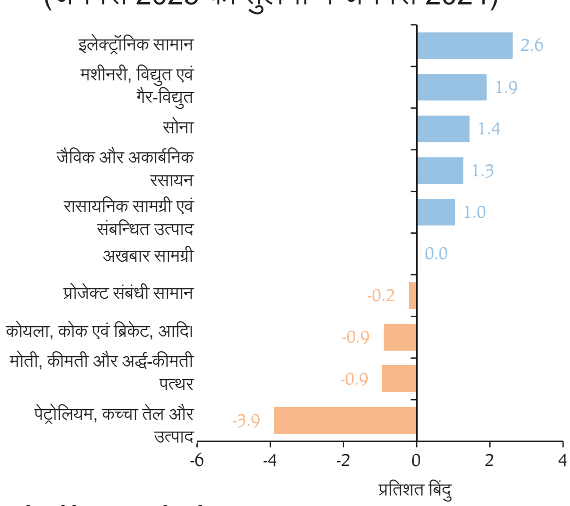

स्रोत: पीआईबी; तथा आरबीआई स्टाफ अनुमान।

चार्ट III.12: भारत के पण्य व्यापार घाटे का अपघटन

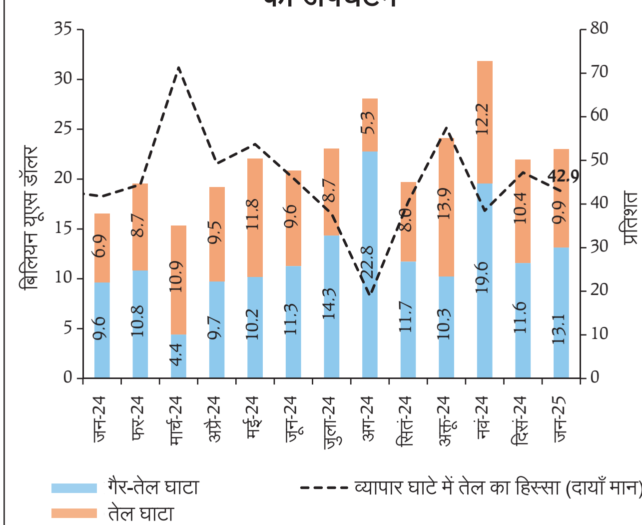

स्रोत: पीआईबी; तथा डीजीसीआईएंडएस।

चार्ट III.13: पण्य-वार माल व्यापार घाटा

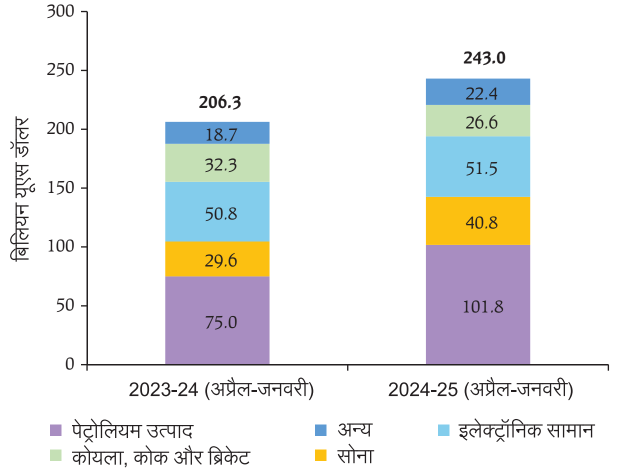

टिप्पणी: जनवरी 2025 और दिसंबर 2024 में कोयला, कोक और ब्रिकेट का निर्यात नवंबर 2024 के समान स्तर पर माना गया है।

स्रोत: पीआईबी; डीजीसीआईएंडएस; तथा आरबीआई स्टाफ अनुमान।

चार्ट III.14: सेवा निर्यात और आयात: वृद्धि दर

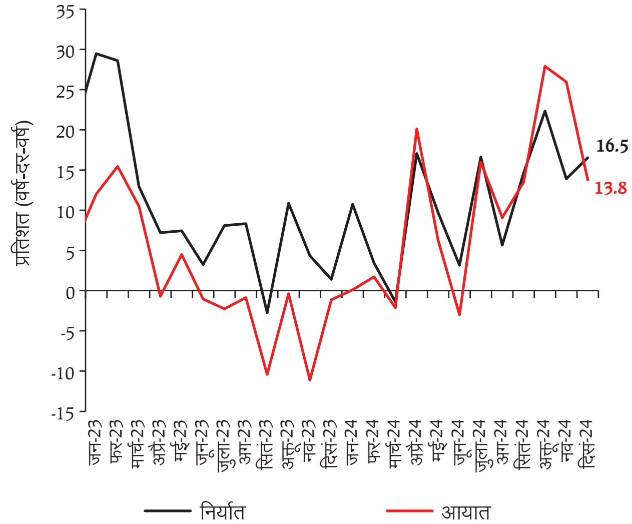

स्रोत: आरबीआई।

हिस्सेदारी 42.9 प्रतिशत थी, जबकि एक साल पहले यह 41.8 प्रतिशत थी।

अप्रैल-जनवरी 2024-25 के दौरान, भारत का पण्य व्यापार घाटा एक साल पहले के 206.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 243.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। पेट्रोलियम उत्पाद घाटे का सबसे बड़ा स्रोत थे, इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक सामान और सोना (चार्ट III.13) का स्थान रहा।

दिसंबर 2024 के दौरान, सेवाओं का निर्यात 16.5 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) बढ़कर 36.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जबकि सेवाओं का आयात 16.5 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) बढ़कर 17.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया (चार्ट III.14)। महीने के दौरान निवल सेवा निर्यात आय 19.2 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) बढ़कर 19.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई।

अप्रैल-दिसंबर 2024 के दौरान सकल राजकोषीय घाटा (जीएफडी) और राजस्व घाटा (आरडी) निरपेक्ष रूप से पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में कम था; जबकि वे संशोधित अनुमानों (आरई) के प्रतिशत के रूप में अधिक थे।[12] सकल प्राथमिक घाटा पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में निरपेक्ष रूप से और संशोधित अनुमानों के प्रतिशत के रूप में कम रहा (चार्ट III.15ए और 15बी)।

व्यय घटकों में, राजस्व व्यय में अप्रैल-दिसंबर 2024 में 7.0 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में 2.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। खाद्य और पेट्रोलियम सब्सिडी द्वारा संचालित, प्रमुख सब्सिडी पर व्यय में 10.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में 21.0 प्रतिशत की कमी आई थी। ब्याज भुगतान और सब्सिडी के बाद राजस्व व्यय में 5.6 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई, जबकि एक वर्ष पहले यह 4.5 प्रतिशत थी।

नवंबर और दिसंबर 2024[13] में पूंजीगत व्यय में सुधार हुआ, जिससे अप्रैल-दिसंबर 2024 के दौरान साल-दर-साल वृद्धि दर 1.7 प्रतिशत हो गई (चार्ट III.16ए)। शीर्ष छह मंत्रालयों में, जो 2024-25 के लिए बजटीय पूंजीगत व्यय का लगभग 95 प्रतिशत हिस्सा हैं, सड़क परिवहन और राजमार्ग, रेलवे, वित्त, और आवास एवं शहरी मामलों ने साल-दर-साल आधार पर विस्तार दर्ज किया, जबकि रक्षा और संचार ने संकुचन दर्ज

[12] लेखा महानियंत्रक (सीजीए) के अनुसार।

[13] साल-दर-साल आधार पर, पूंजीगत व्यय में नवंबर और दिसंबर 2024 के दौरान क्रमशः 21.3 प्रतिशत और 95.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

चार्ट III.15: अप्रैल-दिसंबर के दौरान केंद्र सरकार का बजटीय घाटा

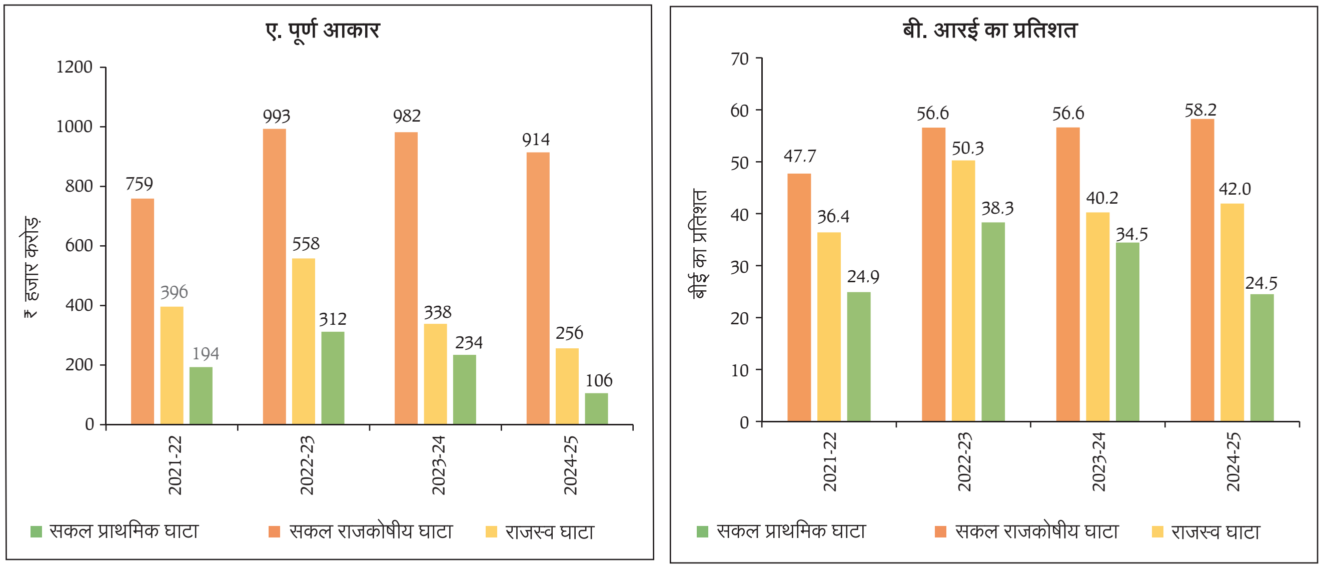

स्रोत: महालेखा नियंत्रक (सीजीए); तथा केंद्रीय बजट दस्तावेज।

किया (चार्ट III.16बी)। कुल मिलाकर, कुल व्यय में वृद्धि अप्रैल-दिसंबर 2024 के दौरान 5.8 प्रतिशत रही, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 8.4 प्रतिशत थी।

केंद्र सरकार के सकल कर राजस्व में अप्रैल-दिसंबर 2024 में 10.8 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई, जो मुख्य रूप से आयकर, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी), और सीमा शुल्क (चार्ट III.17ए) के कारण हुआ। गैर-कर राजस्व ने संशोधित अनुमान का 84.3 प्रतिशत प्राप्त किया, जो रिज़र्व बैंक से 2.11 लाख करोड़ रुपये के अधिशेष हस्तांतरण के कारण था (चार्ट III.17बी)। हालांकि, ऋणों की वसूली और विनिवेश प्राप्तियों दोनों में गिरावट के कारण गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियां संकुचित हुईं। केंद्र सरकार के निवल कर राजस्व में अप्रैल-दिसंबर 2024 के दौरान 6.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। कुल मिलाकर, कुल प्राप्तियां पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 11.9 प्रतिशत बढ़ीं।

जनवरी 2025 में जीएसटी संग्रह (केंद्र और राज्य) 12.3 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) बढ़कर ₹1.96 लाख करोड़ पर पहुंच गया

चार्ट III.16: पूंजीगत व्यय

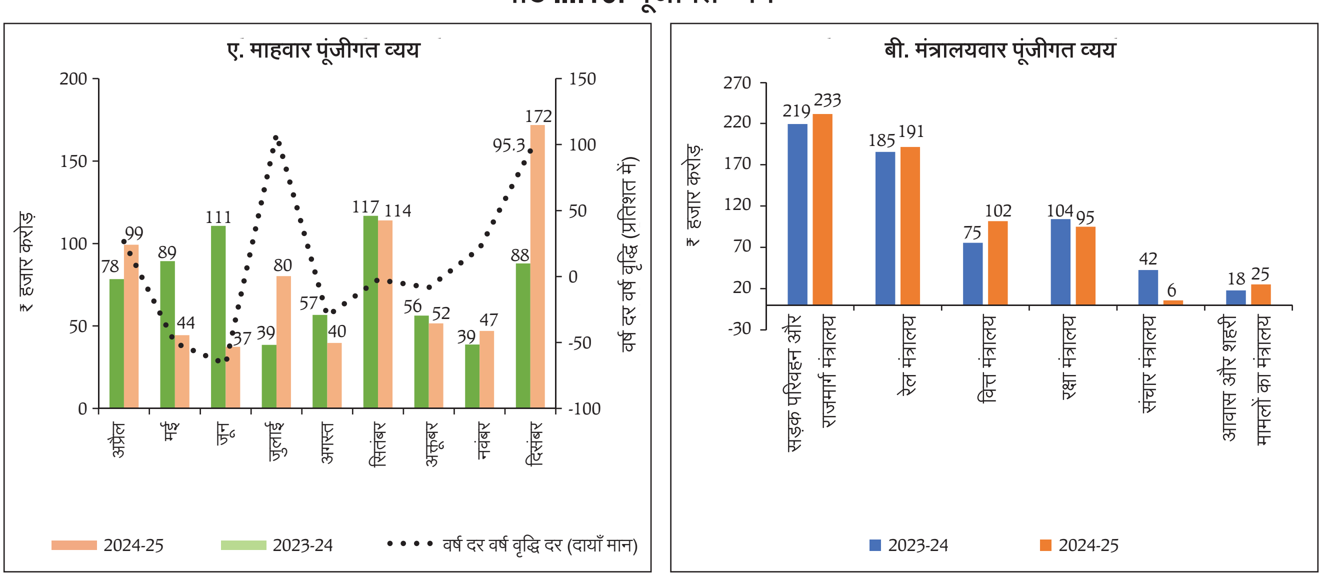

स्रोत: सीजीए।

चार्ट III.17: अप्रैल-दिसंबर के दौरान केंद्र सरकार की राजस्व प्राप्तियां

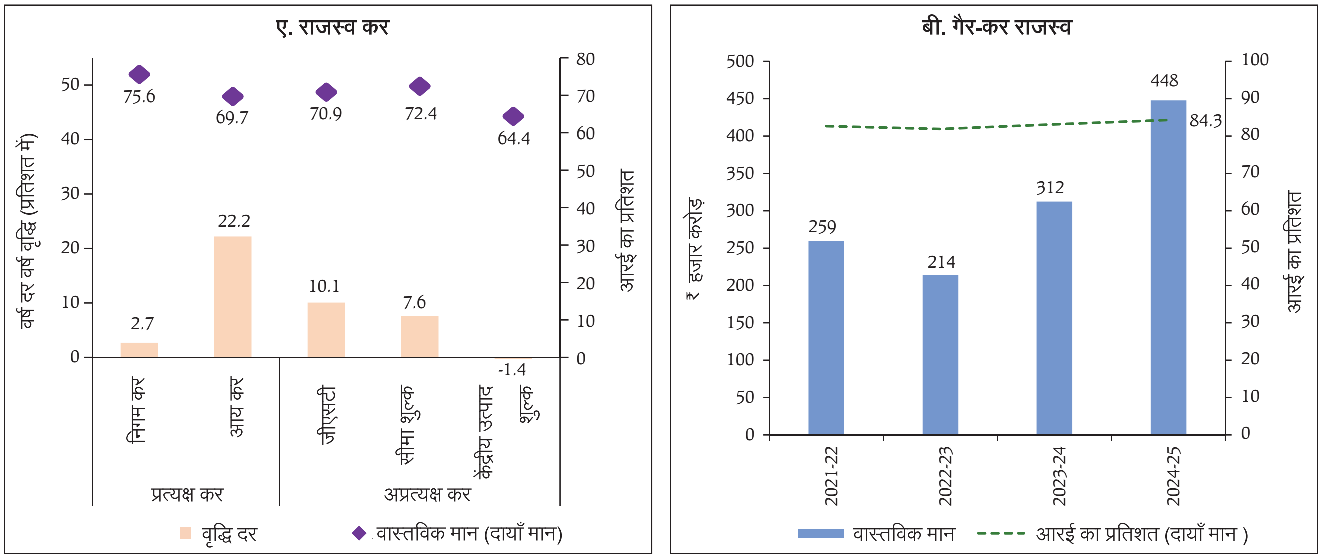

स्रोत: सीजीए।

(चार्ट III.18)। घरेलू लेन-देन[14] से संग्रह में 10.0 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई, जबकि आयात पर 19.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। जनवरी 2025 के लिए कर रिफंड में 23.9 प्रतिशत की वृद्धि के साथ, निवल जीएसटी संग्रह 10.9 प्रतिशत बढ़कर ₹1.72 लाख करोड़ हो गया। अप्रैल-जनवरी 2024-25 के लिए संचयी सकल जीएसटी संग्रह एक साल पहले इसी अवधि की तुलना में 9.4 प्रतिशत अधिक था।

जनवरी 2025 में जीएसटी संग्रह (केंद्र और राज्य) 12.3 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) बढ़कर ₹1.96 लाख करोड़ हो गया (चार्ट III.18)। घरेलू लेन-देन से संग्रह में 10.0 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई, जबकि आयात पर 19.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। जनवरी 2025 के लिए कर वापसी में 23.9 प्रतिशत की वृद्धि के साथ, निवल जीएसटी संग्रह 10.9 प्रतिशत बढ़कर ₹1.72 लाख करोड़ हो गया। अप्रैल-जनवरी 2024-25 के लिए

चार्ट III.18: जीएसटी संग्रह

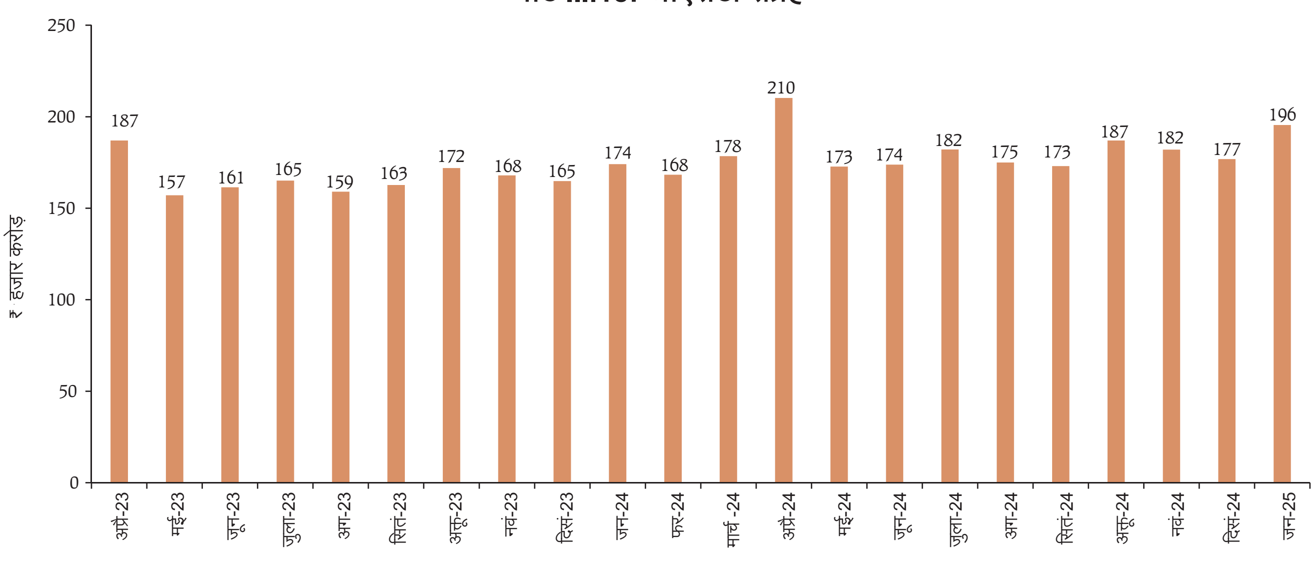

स्रोत: प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी); और जीएसटी पोर्टल।

[14] जनवरी 2025 के दौरान सकल जीएसटी संग्रह में घरेलू लेनदेन से संग्रह का हिस्सा 75.3 प्रतिशत रहा।

संचयी सकल जीएसटी संग्रह एक साल पहले के इसी अवधि की तुलना में 9.4 प्रतिशत अधिक था।

1 फरवरी, 2025 को घोषित केंद्रीय बजट 2025-26 ने राजकोषीय समेकन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की, जिसमें 2025-26 (बीई) में जीएफडी को जीडीपी के 4.4 प्रतिशत पर रखा गया, जो 2024-25 (आरई) में जीडीपी के 4.8 प्रतिशत से कम है। प्रस्तावित समेकन राजस्व व्यय को जीडीपी के 11.0 प्रतिशत (2024-25 आरई में 11.4 प्रतिशत की तुलना में) तक कम करके, पूंजीगत व्यय को जीडीपी के 3.1 प्रतिशत पर बनाए रखते हुए (जीडीपी के 4.3 प्रतिशत से अधिक प्रभावी पूंजीगत व्यय के साथ)[15] जबकि सकल कर राजस्व को जीडीपी के 12.0 प्रतिशत (2024-25 आरई में 11.9 प्रतिशत की तुलना में) तक बढ़ाने के माध्यम से प्राप्त करने की मांग की गई है। 2026-27 से 2030-31 तक, केंद्र सरकार प्रत्येक वर्ष राजकोषीय घाटे को इस प्रकार बनाए रखने का प्रयास कर रही है कि उसका ऋण घटता रहे और 31 मार्च 2031 तक ऋण सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 50 ± 1 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच जाए।

अनंतिम लेखों के अनुसार, अप्रैल-दिसंबर 2024 के दौरान बजट अनुमानों (बीई) के प्रतिशत के रूप में राज्यों के प्रमुख घाटा संकेतक पिछले वर्ष के स्तर से अधिक हैं (सारणी III.1)।

सारणी III.1: राज्यों के राजकोषीय संकेतक (अप्रैल-दिसंबर)

(बीई का प्रतिशत)

घाटा संकेतक	2022-23	2023-24	2024-25
राजस्व घाटा	4.2	52.3	98.3
सकल राजकोषीय घाटा	39.9	52.1	54.8
प्राथमिक घाटा	15.0	39.9	44.9

टिप्पणी: डेटा 23 राज्यों से संबंधित है। बीई: बजट अनुमान।
स्रोत: भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक।

राज्यों की राजस्व प्राप्तियों में 9.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो मुख्य रूप से उच्च कर राजस्व द्वारा प्रेरित थी, भले ही केंद्र सरकार से अनुदान में कमी आई (चार्ट III.19ए)। राज्यों के जीएसटी (एसजीएसटी) और राज्य उत्पाद शुल्क में वृद्धि थोड़ी कम हुई, जबकि बिक्री कर/वैट में पिछले वर्ष की तुलना में सकारात्मक बदलाव देखा गया। राज्यों के राजस्व व्यय में दोहरे अंकों की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि इस अवधि के दौरान पूंजीगत व्यय में गिरावट आई (चार्ट III.19बी)। तदनुसार, आरईसीओ[16] अनुपात पिछले वर्ष की समान अवधि के 6.0 से बढ़कर अप्रैल-दिसंबर 2024 में 7.0 हो गया।

चार्ट III.19: प्रमुख राजकोषीय प्रदर्शन संकेतक (अप्रैल-दिसंबर)

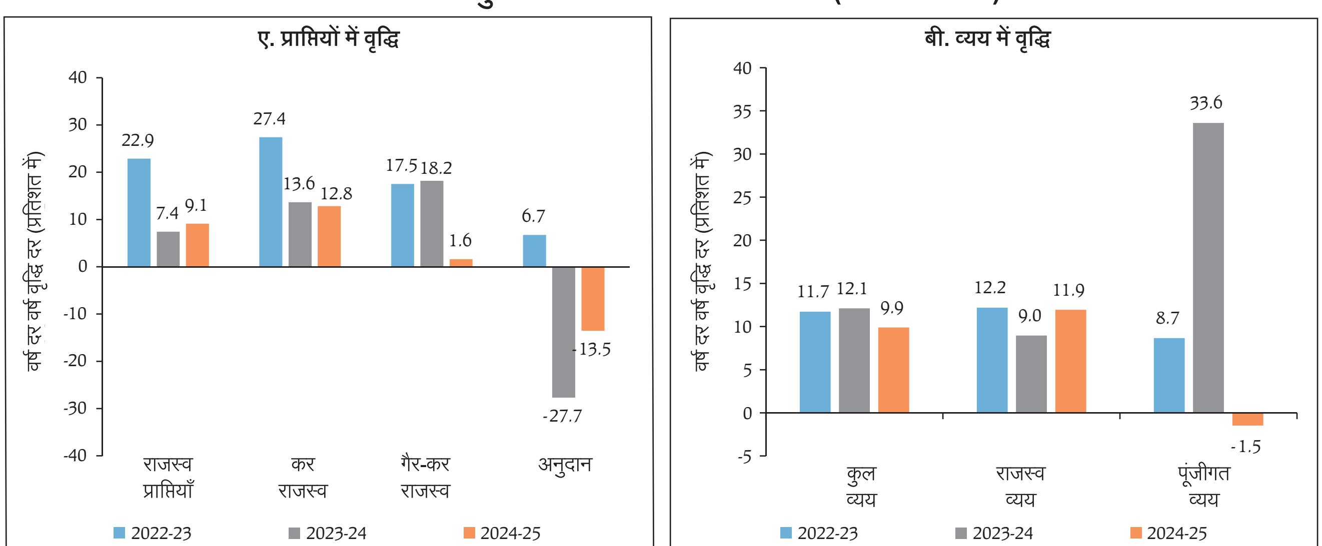

टिप्पणी: डेटा 23 राज्यों से संबंधित है।
स्रोत: सीएजी।

[15] प्रभावी पूंजीगत व्यय पूंजीगत व्यय और पूंजीगत आस्तियों के निर्माण के लिए अनुदान सहायता है।

[16] पूंजीगत व्यय के लिए राजस्व व्यय।

समग्र आपूर्ति

रबी सीजन 2024-25 के दौरान बुवाई का रकबा 661 लाख हेक्टेयर रहा, जो पिछले साल की तुलना में 1.5 प्रतिशत अधिक है। गेहूं का रकबा, जो सामान्य रबी क्षेत्र के तहत बुवाई के रकबे का लगभग आधा है, 2.1 प्रतिशत बढ़ा (चार्ट III.20)। दालों की बुवाई में वृद्धि मुख्य रूप से चने के अधिक रकबे के कारण हुई।

पहले अग्रिम अनुमानों के अनुसार, 2024-25 के दौरान बागवानी फसलों का उत्पादन 362.1 मिलियन टन रहने का अनुमान है, जो 2023-24 के अंतिम अनुमानों से 2.1 प्रतिशत अधिक है। प्याज और आलू के अधिक उत्पादन के कारण सालाना आधार पर वृद्धि हुई (चार्ट III.21)।

केंद्रीय बजट 2025-26 में कृषि में उत्पादकता और स्थिरता बढ़ाने तथा कृषि अवसंरचना में सुधार जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसमें 100 कम उत्पादकता वाले जिलों में 'प्रधानमंत्री धन- धान्य कृषि योजना' शुरू करने की घोषणा की गई है, ताकि उनकी कृषि उत्पादकता बढ़ाई जा सके, सिंचाई सुविधाओं में सुधार हो, फसल कटाई के बाद भंडारण को बढ़ाया जा सके तथा लगभग 1.7 करोड़ किसानों को दीर्घकालिक और अल्पकालिक ऋण की उपलब्धता में सुविधा हो। इसमें अरहर, उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान देते हुए 6 वर्षीय "दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन" शुरू करने की भी घोषणा की गई है।

चार्ट III.20: रबी बुवाई की स्थिति (31 जनवरी, 2025 तक)

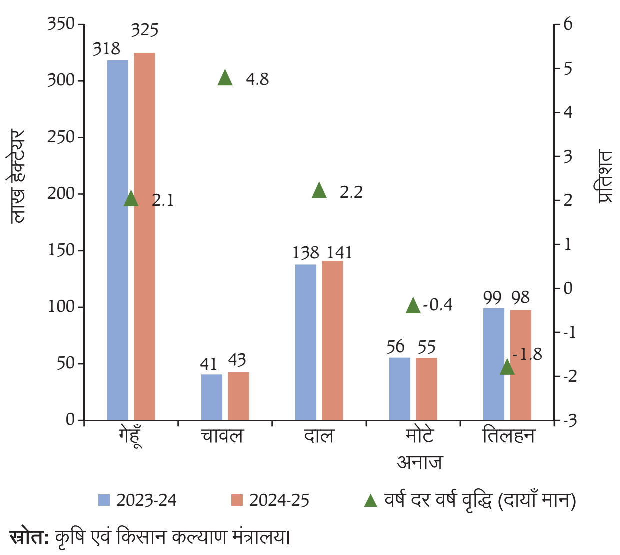

स्रोत: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

जलाशय स्तर (155 प्रमुख जलाशयों पर आधारित) कुल जलाशय क्षमता (13 फरवरी, 2025 तक) के 58 प्रतिशत पर एक आरामदायक स्थिति में बना हुआ है, जो पिछले वर्ष के साथ-साथ दशकीय औसत स्तरों (चार्ट III.22) से भी अधिक है। जलाशय की आरामदायक स्थिति देश में कम सर्दियों की बारिश (जनवरी-मार्च) से उत्पन्न रबी फसलों के लिए कुछ चिंताओं को दूर करती है[17]।

01 फरवरी, 2025 तक भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के पास चावल का स्टॉक 676 लाख टन था - जो बफर आवश्यकताओं से नौ गुना अधिक है। सरकार ने राज्य सरकारों और इथेनॉल डिस्टिलरी को बिक्री के लिए खुले बाजार बिक्री योजना (ओएमएसएस) के तहत चावल का आरक्षित मूल्य ₹2,800 प्रति क्विंटल से घटाकर ₹2,250 कर दिया। 162 लाख टन गेहूं का स्टॉक पिछले साल की तुलना में 22 प्रतिशत अधिक है और बफर मानदंडों के अनुरूप है। चालू विपणन सत्र के दौरान चावल की खरीद 443 लाख टन (16 फरवरी, 2025 तक) पिछले साल की तुलना में 3.4 प्रतिशत अधिक है (चार्ट III.23)।

चार्ट III.21: बागवानी उत्पादन

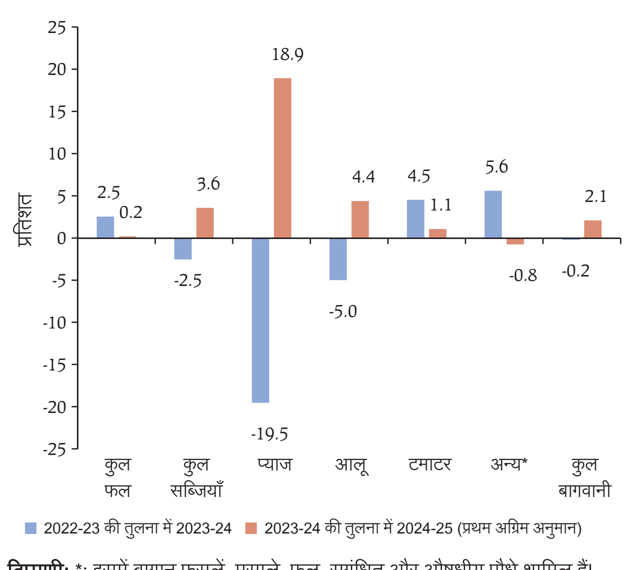

टिप्पणी: *: इसमें बागान फसलें, मसाले, फूल, सुगंधित और औषधीय पौधे शामिल हैं।
स्रोत: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

[17] 12 फरवरी, 2025 तक सर्दियों की बारिश दीर्घ अवधि के औसत से 70 प्रतिशत कम थी।

चार्ट III.22: जलाशय स्तर (13 फरवरी, 2025 तक)

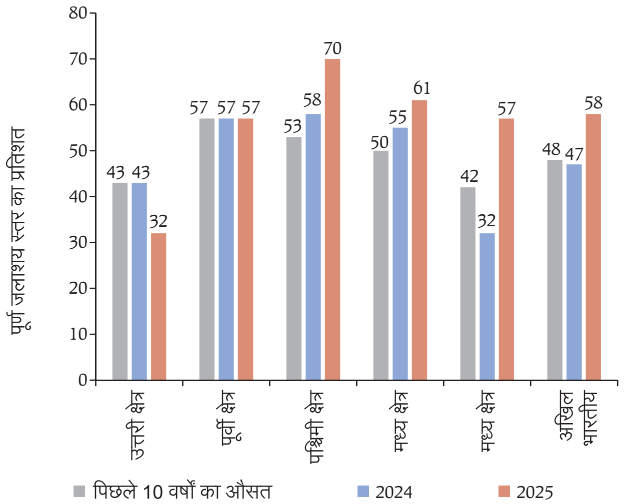

स्रोत: केंद्रीय जल आयोग।

चार्ट III.23: खाद्यान्नों की खरीद और भंडारण

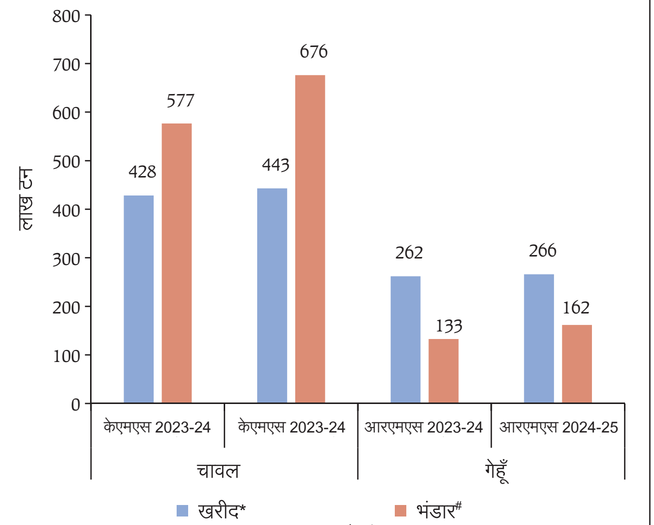

टिप्पणी: *: चावल की खरीद 16 फरवरी तक और गेहूं की खरीद 30 जून तक की स्थिति के अनुसार है; #: 01 फरवरी तक की स्थिति के अनुसार।
स्रोत: भारतीय खाद्य निगम।

भारत का विनिर्माण पीएमआई जनवरी में छह महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया, जो नए ऑर्डर (घरेलू और निर्यात) और रोजगार (चार्ट III.24ए) के कारण हुआ। हालांकि, नई व्यावसायिक गतिविधि में मंदी के कारण सेवा पीएमआई में नरमी आई (चार्ट III.24बी)। विनिर्माण के लिए व्यावसायिक उम्मीदों में सुधार हुआ, जबकि सेवाओं के लिए भविष्य के उत्पादन आकलन तीन महीने के निचले स्तर पर आ गए।

बंदरगाह यातायात दिसंबर 2024 में 3.4 प्रतिशत से बढ़कर जनवरी 2025 में 6.6 प्रतिशत हो गया, जो उर्वरकों, कंटेनरयुक्त कार्गो और अन्य विविध कार्गो द्वारा संचालित है (चार्ट III.25)।

निर्माण क्षेत्र में, जनवरी में इस्पात की खपत में वृद्धि बढ़कर 5.8 प्रतिशत (वर्ष दर वर्ष) हो गई, जबकि सीमेंट उत्पादन स्तर दिसंबर में 4.0 प्रतिशत की वृद्धि के साथ नौ महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया (चार्ट III.26)।

चार्ट III.24: क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई)

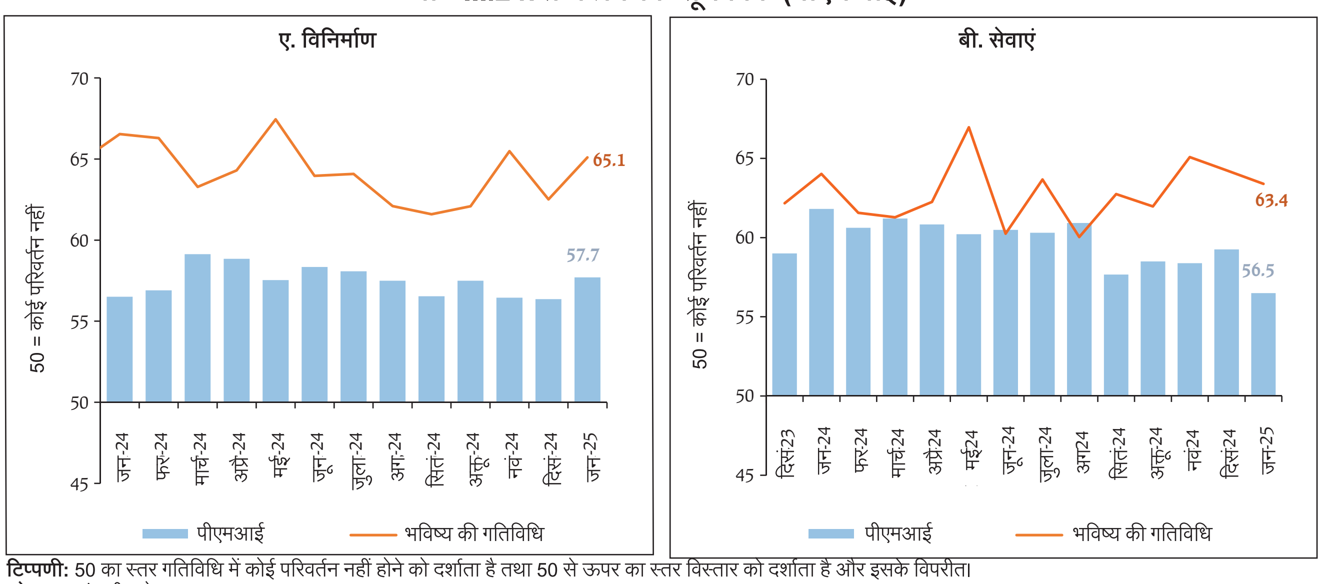

टिप्पणी: 50 का स्तर गतिविधि में कोई परिवर्तन नहीं होने को दर्शाता है तथा 50 से ऊपर का स्तर विस्तार को दर्शाता है और इसके विपरीत।
स्रोत: एस एंड पी ग्लोबल।

चार्ट III.25: पोर्ट कार्गो

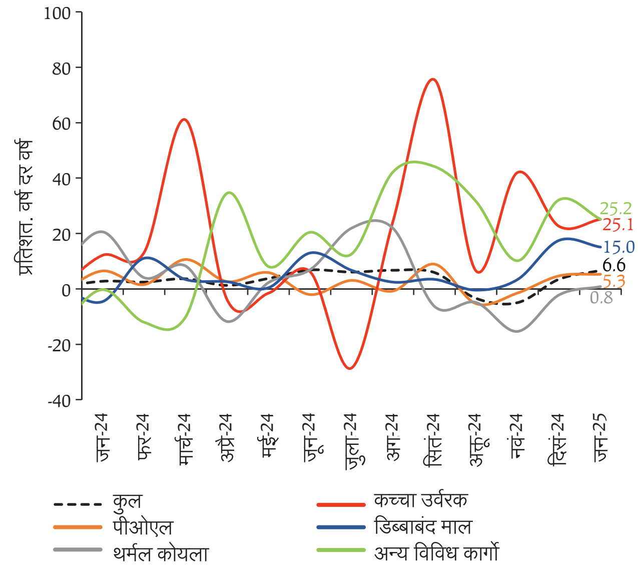

स्रोत: भारतीय बंदरगाह संघ।

चार्ट III.26: स्टील की खपत और सीमेंट उत्पादन

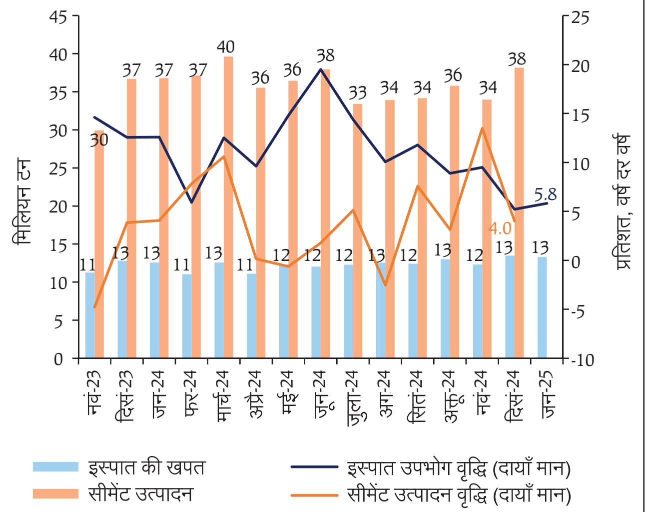

स्रोत: संयुक्त संयंत्र समिति; आर्थिक सलाहकार कार्यालय; तथा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय।

सेवा क्षेत्र के लिए उपलब्ध उच्च आवृत्ति संकेतक आर्थिक गतिविधि में सुदृढ़ दर्शाते हैं, जिसमें अधिकांश संकेतक वर्ष दर वर्ष वृद्धि में सुधार दर्शाते हैं (सारणी III.2)।

सारणी III.2 : उच्च आवृत्ति संकेतक – सेवाएँ

(वर्ष दर वर्ष प्रतिशत)

क्षेत्र	संकेतक	फर-24	मार्च-24	अप्रै-24	मई-24	जून-24	जुला-24	अग-24	सितं-24	अक्तू-24	नवं-24	दिसं-24	जन-25
शहरी मांग	यात्री वाहन बिक्री	9.5	8.9	1.2	4.3	4.9	-2.0	-1.6	-0.4	1.1	4.4	11.4	3.5
ग्रामीण मांग	दुपहिया वाहन बिक्री	34.6	15.3	30.8	10.1	21.3	12.5	9.3	15.8	14.2	-1.1	-8.8	2.1
	तीन पहिया वाहन बिक्री	8.3	4.3	14.5	14.4	12.3	5.1	8.0	6.7	-0.7	-1.3	3.5	7.7
	ट्रैक्टर बिक्री	-30.6	-23.1	-3.0	0.0	3.6	1.6	-5.8	3.7	22.4	-1.3	14.0	11.4
व्यापार, होटल, यातायात, संचार	वाणिज्यिक वाहन बिक्री	-3.8		3.5			-10.9			1.3			
	रेलवे माल ढुलाई यातायात	10.1	8.6	1.4	3.7	10.1	4.5	0.0					
	पोर्ट कार्गो यातायात	2.1	2.7	1.3	3.8	6.8	5.9	6.7	5.8	-3.4	-4.9	3.4	6.6
	घरेलू हवाई कार्गो यातायात	11.5	8.7	0.3	10.3	10.3	8.8	0.6	14.0	8.9	0.3	4.3	
	अंतरराष्ट्रीय हवाई कार्गो यातायात	30.2	22.5	16.2	19.2	19.6	24.4	20.7	20.5	18.4	16.1	10.5	
	घरेलू हवाई यात्री यातायात*	5.8	4.7	3.8	5.9	6.9	7.6	6.7	7.4	9.6	13.8	10.8	14.1
	अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्री यातायात*	19.3	15.0	16.8	19.6	11.3	8.8	11.1	11.2	10.3	10.7	9.0	9.8
	जीएसटी ई-वे बिल्स (कुल)	18.9	13.9	14.5	17.0	16.3	19.2	12.9	18.5	16.9	16.3	17.6	23.1
	जीएसटी ई-वे बिल्स (अंतरा राज्य)	21.1	15.8	17.3	18.9	16.4	19.0	13.1	19.0	18.3	5.4	17.9	23.3
	जीएसटी ई-वे बिल्स (अंतर राज्य)	15.0	10.7	9.6	13.6	16.3	19.6	12.5	17.7	14.4	44.1	17.1	22.8
	होटल कमरा बुकिंग	1.8	2.7	-1.4	-2.6	-3.1	3.6	0.7	2.1	-5.3	11.1	-0.2	
	प्रति कमरा औसत राजस्व	7.8	6.7	4.8	1.8	2.8	7.6	5.2	3.5	4.8	10.7	8.9	
	यात्री आगमन	15.8	8.0	7.7	0.3	9.0	-1.3	-4.2	0.4	-1.4			
विनिर्माण	इस्पात उपभोग	7.0	12.5	9.6	15.9	19.5	14.4	10.0	11.8	8.9	9.5	5.2	5.8
	सीमेंट उत्पादन	7.8	10.6	0.2	-0.6	1.8	5.1	-2.5	7.6	3.1	13.5	4.0	
पीएमआई संकेतक #	सेवाएँ	60.6	61.2	60.8	60.2	60.5	60.3	60.9	57.7	58.5	58.4	59.3	56.5

<< संकुचन ------------------------------------ विस्तार >>

टिप्पणी: #: डेटा स्तरों में है। *: दिसंबर 2024 के डेटा दैनिक आंकड़ों के मासिक औसत पर आधारित हैं। जुलाई-2021 से अब तक की अवधि के लिए प्रत्येक संकेतक के लिए हीट-मैप का निर्माण किया गया है।

स्रोत: एसआईएएम: रेल मंत्रालय: ट्रैक्टर और मशीनीकरण एसोसिएशन; भारतीय बंदरगाह संघ; आर्थिक सलाहकार कार्यालय: जीएसटीएन: भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण: एचवीएस एनारॉक; पर्यटन मंत्रालय: संयुक्त संयंत्र समिति; और आईएचएस मार्किट।

मुद्रास्फीति

अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई)[18] में साल-दर-साल होने वाले बदलावों के आधार पर मापी गई हेडलाइन मुद्रास्फीति, दिसंबर 2024 में 5.2 प्रतिशत से घटकर जनवरी 2025 में 4.3 प्रतिशत के पांच महीने के निचले स्तर पर आ गई (चार्ट III.27)। मुद्रास्फीति में 90 बीपीएस की गिरावट लगभग 100 बीपीएस (माह दर माह) की ऋणात्मक मूल्य गति के कारण थी, जो आंशिक रूप से लगभग 10 बीपीएस के प्रतिकूल आधार प्रभाव से समायोजित थी। खाद्य समूह ने महीने के दौरान लगभग 240 बीपीएस की ऋणात्मक गति दर्ज की, जबकि ईंधन और कोर (खाद्य और ईंधन को छोड़कर) समूहों में क्रमशः 40 और 30 बीपीएस पर धनात्मक गति थी।

जनवरी में खाद्य मुद्रास्फीति घटकर 5.7 प्रतिशत रह गई, जो दिसंबर में 7.7 प्रतिशत (वार्षिक) थी। उप-समूहों के संदर्भ में, अनाज, अंडे, सब्जियों और दालों में मुद्रास्फीति कम हुई, लेकिन तेल और वसा, फल, चीनी और मिष्ठान, गैर-अल्कोहल पेय और तैयार भोजन में वृद्धि हुई। मांस और मछली, तथा दूध और उत्पादों में मुद्रास्फीति स्थिर रही, जबकि मसालों में अपस्फीति कम हुई (चार्ट III.28)।

जनवरी में ईंधन और बिजली की कीमतों में गिरावट (-)1.4 प्रतिशत रही, जबकि दिसंबर में यह (-)1.3 प्रतिशत थी। इसका मुख्य कारण केरोसिन की कीमतों में गिरावट की उच्च दर है, जबकि एलपीजी की कीमतों में गिरावट स्थिर रही। हालांकि, बिजली की कीमतों में मुद्रास्फीति में वृद्धि दर्ज की गई।

कोर मुद्रास्फीति दिसंबर में 3.6 प्रतिशत से बढ़कर जनवरी 2025 में 3.7 प्रतिशत हो गई। उप-समूहों में, आवास, घरेलू सामान और सेवाओं, परिवहन और संचार, और व्यक्तिगत देखभाल और प्रभाव उप समूहों में मुद्रास्फीति बढ़ी; यह कपड़े और जूते, तथा स्वास्थ्य में स्थिर रही; और पान, तंबाकू एवं नशीले पदार्थों, मनोरंजन और मनोविनोद, तथा शिक्षा में कमी आई (चार्ट III.29)।

क्षेत्रीय वितरण के संदर्भ में, जनवरी 2025 में ग्रामीण और शहरी मुद्रास्फीति क्रमशः 4.6 प्रतिशत और 3.9 प्रतिशत थी। राज्य स्तर पर, मुद्रास्फीति दर 2.0 से 7.4 प्रतिशत के बीच थी। अधिकांश राज्यों में मुद्रास्फीति 6 प्रतिशत से कम दर्ज की गई (चार्ट III.30)।

फरवरी के लिए अब तक (14 तारीख तक) उच्च आवृत्ति वाले खाद्य मूल्य डेटा से पता चलता है कि चावल की कीमतें काफी हद तक अपरिवर्तित रहीं, जबकि गेहूं की कीमतों में बढ़ोतरी जारी रही। खाद्य तेल की कीमतों में और मजबूती आई

चार्ट III. 27: सीपीआई मुद्रास्फीति के रुझान और चालक

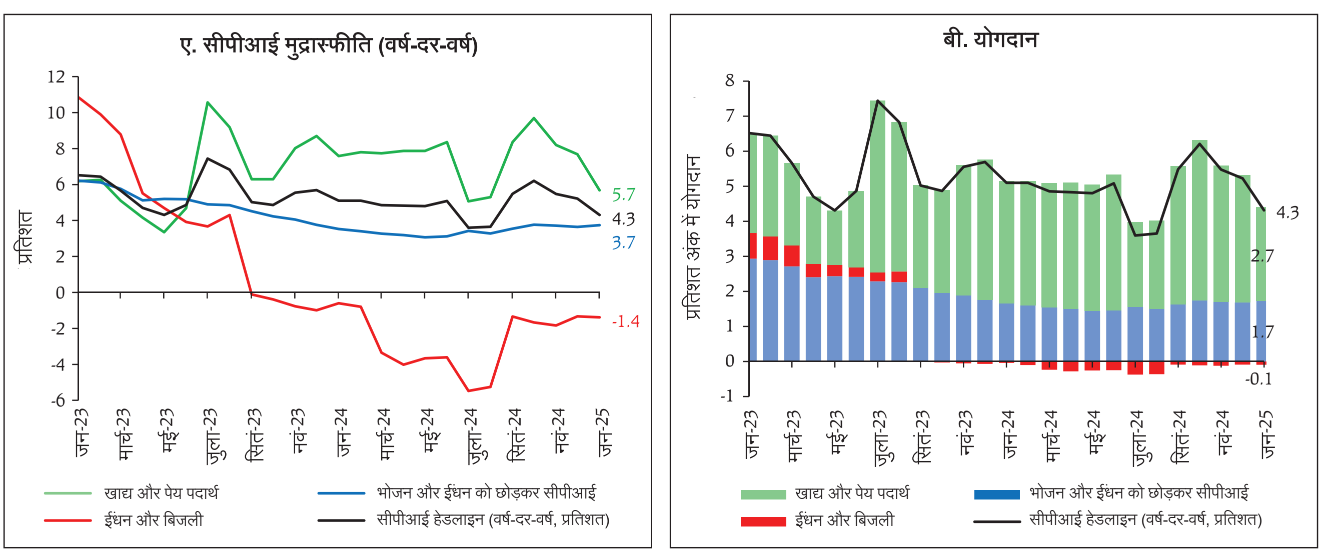

स्रोत: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ); तथा आरबीआई स्टाफ अनुमान।

[18] राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा 12 फरवरी, 2025 को जारी अनंतिम आंकड़ों के अनुसार।

चार्ट III.28: उप-समूहों में वार्षिक मुद्रास्फीति (वर्ष-दर-वर्ष) और गति (माह दर माह)

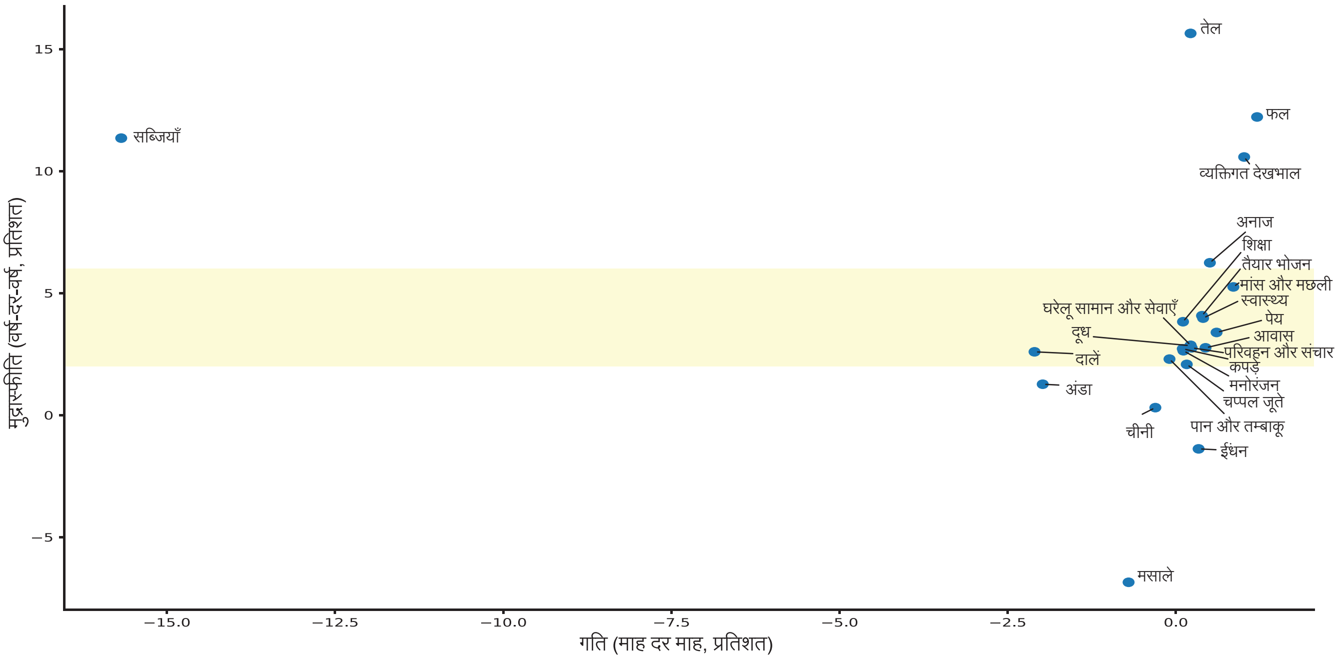

स्रोत: एनएसओ; तथा आरबीआई स्टाफ अनुमान।

जबकि दालों की कीमतों में व्यापक आधार पर नरमी दर्ज की गई। आलू, प्याज और टमाटर सहित प्रमुख सब्जियों की कीमतों में सुधार जारी रहा (चार्ट III.31)।

पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की खुदरा बिक्री कीमतें फरवरी में अब तक (14 तारीख तक) अपरिवर्तित रहीं, जबकि केरोसिन की कीमतों में वृद्धि हुई (सारणी III.3)।

चार्ट III.29: उप-समूहों में वार्षिक मुद्रास्फीति (जनवरी 2025 बनाम दिसंबर 2024)

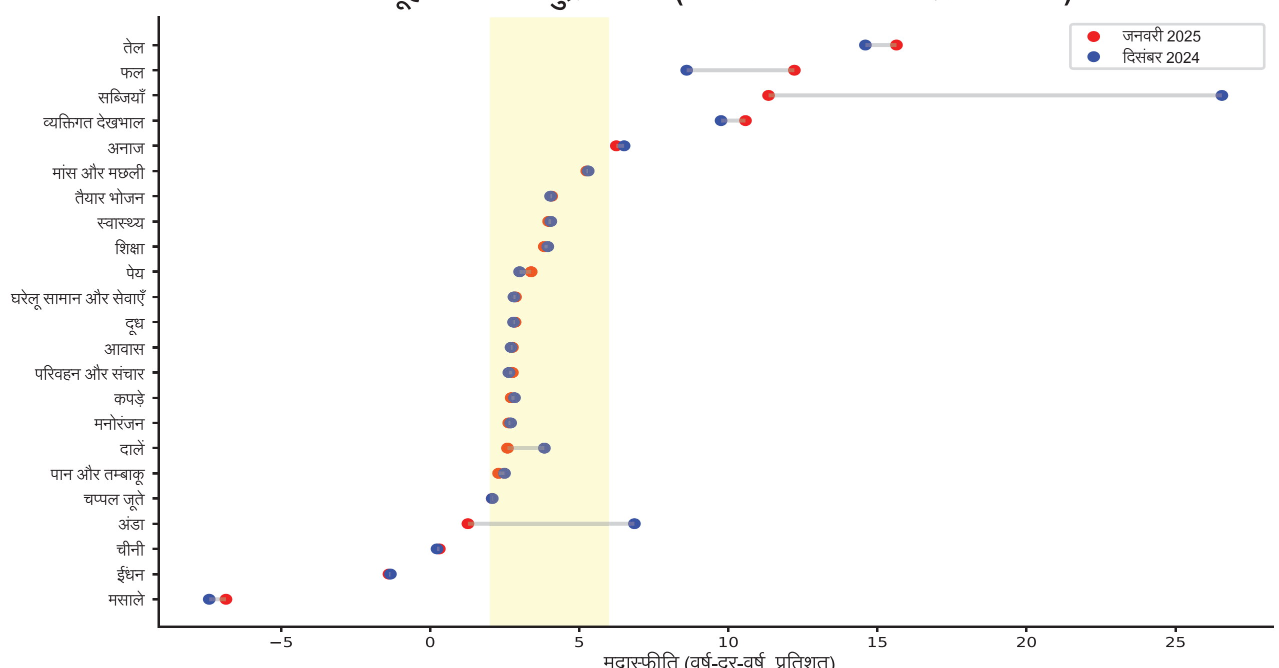

स्रोत: एनएसओ; तथा आरबीआई स्टाफ अनुमान।

चार्ट III.30: मुद्रास्फीति का स्थानिक वितरण जनवरी 2025 (सीपीआई-संयुक्त, वर्ष-दर-वर्ष), (प्रतिशत)

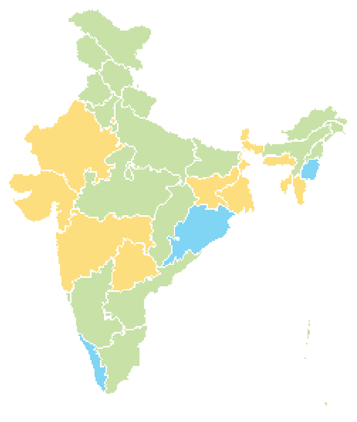

टिप्पणी : मानचित्र केवल उदाहरणार्थ है।
स्रोत: एनएसओ; तथा आरबीआई स्टाफ अनुमान।

सारणी III.3: पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें

वस्तु	इकाई	घरेलू कीमतें			माह-दर-माह (प्रतिशत)	
		दिसं-24	जन-25	फर-25^	जन-25	फर-25^
पेट्रोल	₹/लीटर	101.02	101.02	101.02	0.0	0.0
डीज़ल	₹/लीटर	90.48	90.48	90.48	0.0	0.0
केरोसीन (सब्सिडी वाला)	₹/लीटर	44.75	43.93	46.37	-1.8	5.6
एलपीजी (गैर-सब्सिडी)	₹/सिलेंडर	813.25	813.25	813.25	0.0	0.0

टिप्पणी: 1. ^: 1-14 फरवरी, 2025 की अवधि के लिए।
2. केरोसिन के अलावा, कीमतें चार प्रमुख महानगरों (दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई) में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) की औसत कीमतों को दर्शाती हैं। केरोसिन के लिए, कीमतें कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में सब्सिडी वाली कीमतों के औसत को दर्शाती हैं।
स्रोत: आईओसीएल; पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण सेल (पीपीएसी); और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

पीएमआई के अनुसार, जनवरी में विनिर्माण क्षेत्र के लिए इनपुट लागत में नरमी आई, लेकिन सेवा क्षेत्र के लिए इसमें वृद्धि हुई। विनिर्माण फर्मों में बिक्री मूल्य दबाव कम हुआ, लेकिन सेवा फर्मों के लिए इसमें वृद्धि हुई (चार्ट III.32)।

चार्ट III. 31: डीसीए आवश्यक पण्य मूल्य

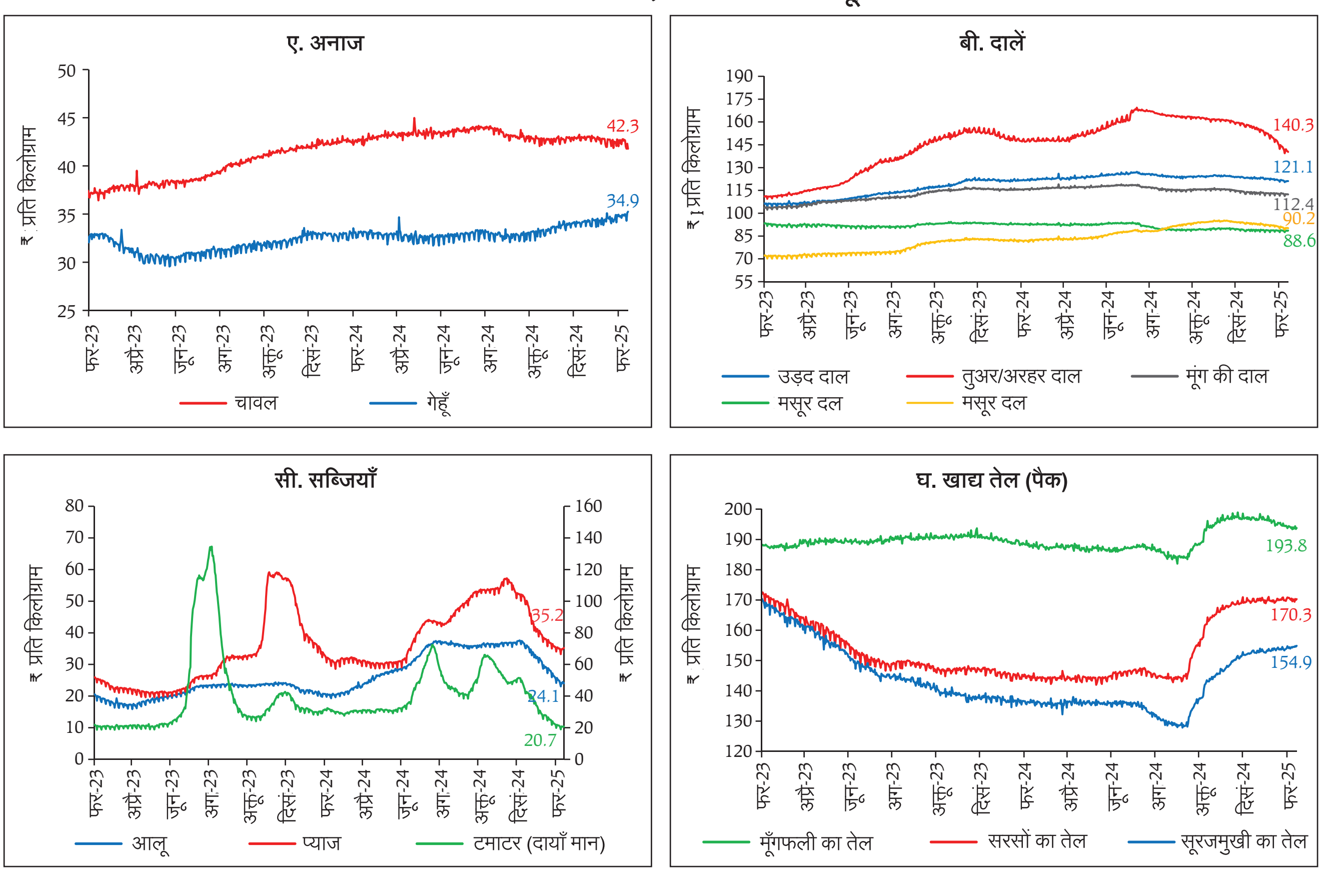

स्रोत: उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार; तथा आरबीआई स्टाफ अनुमान।

चार्ट III.32: पीएमआई: इनपुट और आउटपुट मूल्य

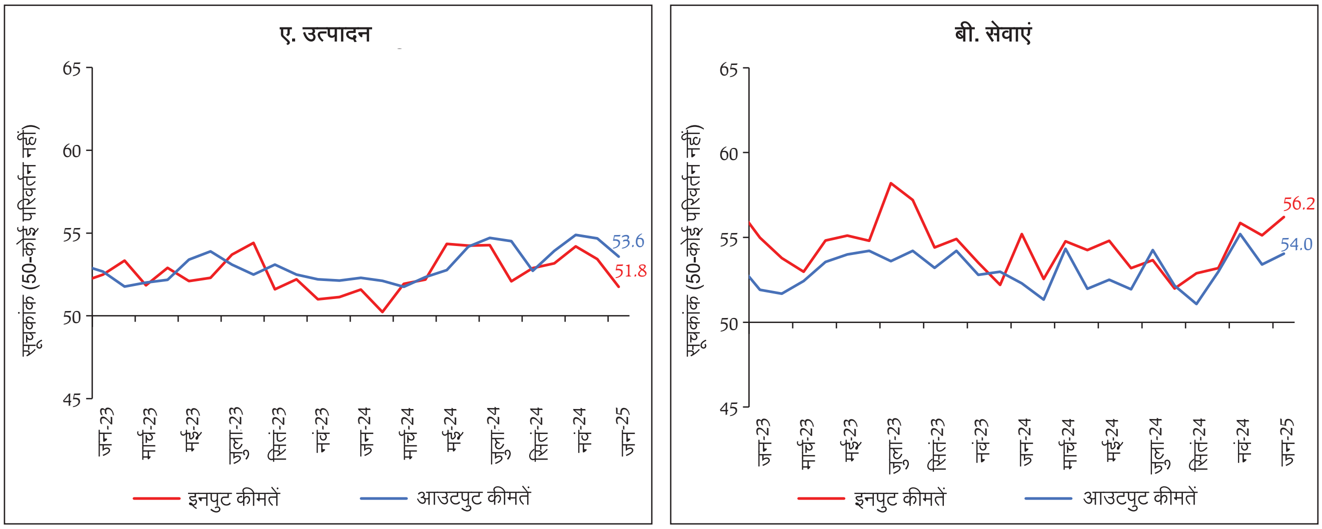

टिप्पणी: 50 का स्तर गतिविधि में कोई परिवर्तन नहीं दर्शाता है और 50 से ऊपर का स्तर विस्तार को दर्शाता है और इसके विपरीत
स्रोत: एस एंड पी।

आरबीआई के मुद्रास्फीति अपेक्षा सर्वेक्षण के जनवरी 2025 के दौर में मौजूदा मुद्रास्फीति के बारे में परिवारों की धारणा 10 बीपीएस कम होकर 8.3 प्रतिशत पर आ गई। हालांकि, अगले तीन महीनों और एक साल के लिए उनकी मुद्रास्फीति अपेक्षाएं पिछले दौर की तुलना में क्रमशः 20 बीपीएस और 10 बीपीएस बढ़ गई (चार्ट III.33)।

चार्ट III.33: परिवारों की औसत मुद्रास्फीति अपेक्षाएँ

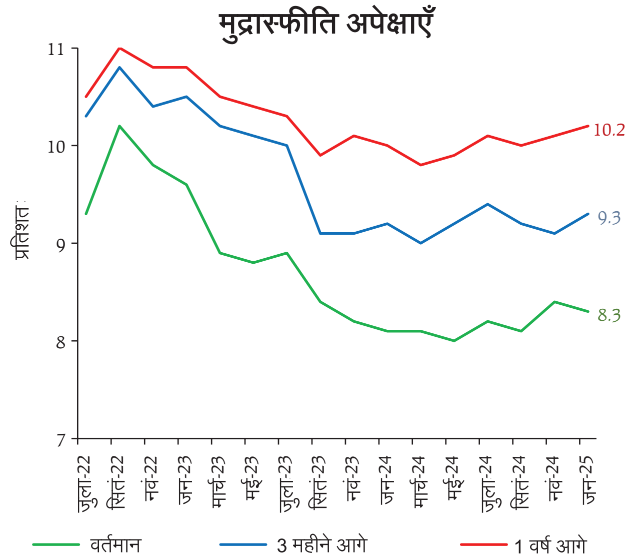

स्रोत: घरेलू मुद्रास्फीति अपेक्षा सर्वेक्षण, आरबीआई।

IV. वित्तीय स्थितियाँ

दिसंबर 2024 के मध्य से प्रणाली में चलनिधि घाटे में चली गई है, क्योंकि तिमाही के अंत में अग्रिम कर निकासी, मासिक जीएसटी भुगतान, पूंजी निकासी और मुद्रा रिसाव के कारण सरकारी नकदी शेष में वृद्धि हुई है। बाजार सहभागियों को दिन-प्रतिदिन पर्याप्त चलनिधि की उपलब्धता का आश्वासन देने के लिए, रिज़र्व बैंक ने 16 जनवरी, 2025 से प्रभावी दैनिक परिवर्तनीय दर रेपो (वीआरआर) नीलामी शुरू की। इसके अलावा, 24 जनवरी, 2025 को एक मुख्य 14-दिवसीय वीआरआर परिचालन आयोजित किया गया। चलनिधि की तंगी का संज्ञान लेते हुए, रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग प्रणाली की टिकाऊ चलनिधि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 27 जनवरी, 2025 को - खुले बाजार के संचालन, यूएसडी/आईएनआर खरीद/बिक्री स्वैप और लंबी अवधि के वीआरआर आदि कई उपायों की घोषणा की । 30 जनवरी और 13 फरवरी को सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक) की खुले बाजार में खरीद नीलामी और 31 जनवरी को यूएसडी/आईएनआर खरीद/बिक्री स्वैप ने मिलकर लगभग ₹1.04 लाख करोड़ की चलनिधि अंतर्विष्ट की। इसके अलावा, जनवरी के दौरान तयशुदा लेनदेन प्रणाली-ऑर्डर मिलान क्षेत्र (एनडीएस-ओएम) के माध्यम से जी-

सेक की रिज़र्व बैंक की खरीद ने सिस्टम में लगभग ₹0.39 लाख करोड़ की टिकाऊ चलनिधि डाली। रिज़र्व बैंक ने 7 फरवरी, 2025 को ₹50,000 करोड़ की अधिसूचित राशि के लिए 56-दिवसीय वीआरआर नीलामी आयोजित की, इसके बाद 14 फरवरी, 2025 को ₹75,000 करोड़ की अधिसूचित राशि के लिए 49-दिवसीय वीआरआर नीलामी की।

कुल मिलाकर, चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत औसत दैनिक निवल अंतर्वेशन 16 जनवरी से 13 फरवरी, 2025 के दौरान ₹1.92 लाख करोड़ रहा, जबकि 16 दिसंबर, 2024 से 15 जनवरी, 2025 के दौरान ₹1.6 लाख करोड़ का औसत निवल अंतर्वेशन दर्ज किया गया था (चार्ट IV.1)। रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए विभिन्न चलनिधि उपायों और सरकारी खर्च में वृद्धि के परिणामस्वरूप, फरवरी की शुरुआत में चलनिधि की तंगी कुछ हद तक कम हुई। 16 जनवरी से 13 फरवरी, 2025 के दौरान बैंकों द्वारा स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) के तहत औसतन ₹0.84 लाख करोड़ का निवेश किया गया, जो पिछले महीने की तुलना में अधिक है। घाटे की चलनिधि की स्थिति और एसडीएफ के तहत लगाए गए धन का सह-अस्तित्व बैंकिंग प्रणाली में चलनिधि के विषम वितरण और चुनिंदा बैंकों की बंधक रहित के मांग मुद्रा बाजार में उधार देने की अनिच्छा जैसे व्यवहार संबंधी पहलुओं का संकेत है।[19]

भारित औसत कॉल दर (डब्ल्यूएसीआर) - मौद्रिक नीति का परिचालन लक्ष्य - दैनिक वीआरआर की शुरूआत और 7 फरवरी को रेपो दर में कटौती के साथ मध्य जनवरी से मध्यम हो गया। 16 दिसंबर, 2024 से 15 जनवरी, 2025 के दौरान 6.69 प्रतिशत की तुलना में 16 जनवरी से 13 फरवरी, 2025 के दौरान यह औसतन 6.49 प्रतिशत रही (चार्ट IV.2ए)।

सावधि मुद्रा बाजार क्षेत्र में, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) द्वारा जारी 3 महीने के जमा प्रमाणपत्र (सीडी) और 3 महीने के वाणिज्यिक पत्र (सीपी) पर ब्याज दरें 16 जनवरी से 13 फरवरी, 2025 के दौरान क्रमशः 7.49 प्रतिशत और 7.88 प्रतिशत रहीं, जो 15 दिसंबर, 2024 से 15 जनवरी, 2025 के दौरान क्रमशः 7.35 प्रतिशत और 7.68 प्रतिशत थीं। 91-दिवसीय टी-बिल पर औसत प्रतिफल 15 दिसंबर, 2024 से 15 जनवरी, 2025 के दौरान 6.54 प्रतिशत से 16 जनवरी - 13 फरवरी, 2025 के दौरान 6.51 प्रतिशत तक मामूली रूप से कम रही (चार्ट IV.2 बी)।

चार्ट IV.1: चलनिधि परिचालन

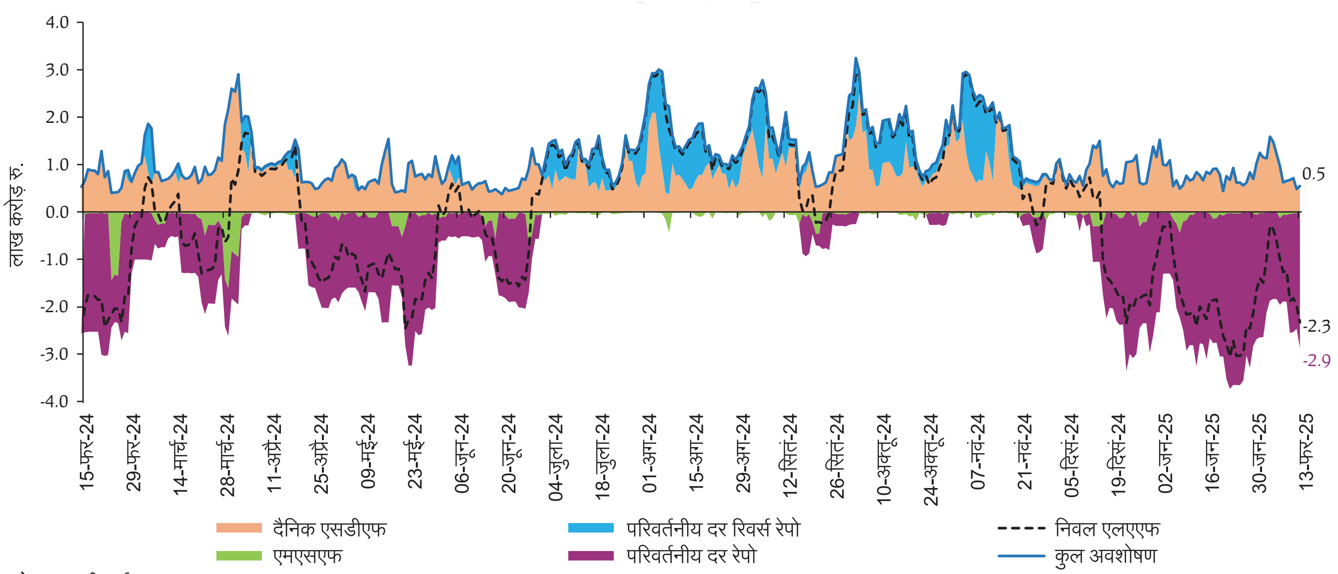

स्रोत: आरबीआई।

[19] मौद्रिक नीति वक्तव्य 2024-25, गवर्नर का वक्तव्य, 7 फरवरी, 2025।

चार्ट IV.2: पॉलिसी कॉरिडोर और मुद्रा बाजार दरें

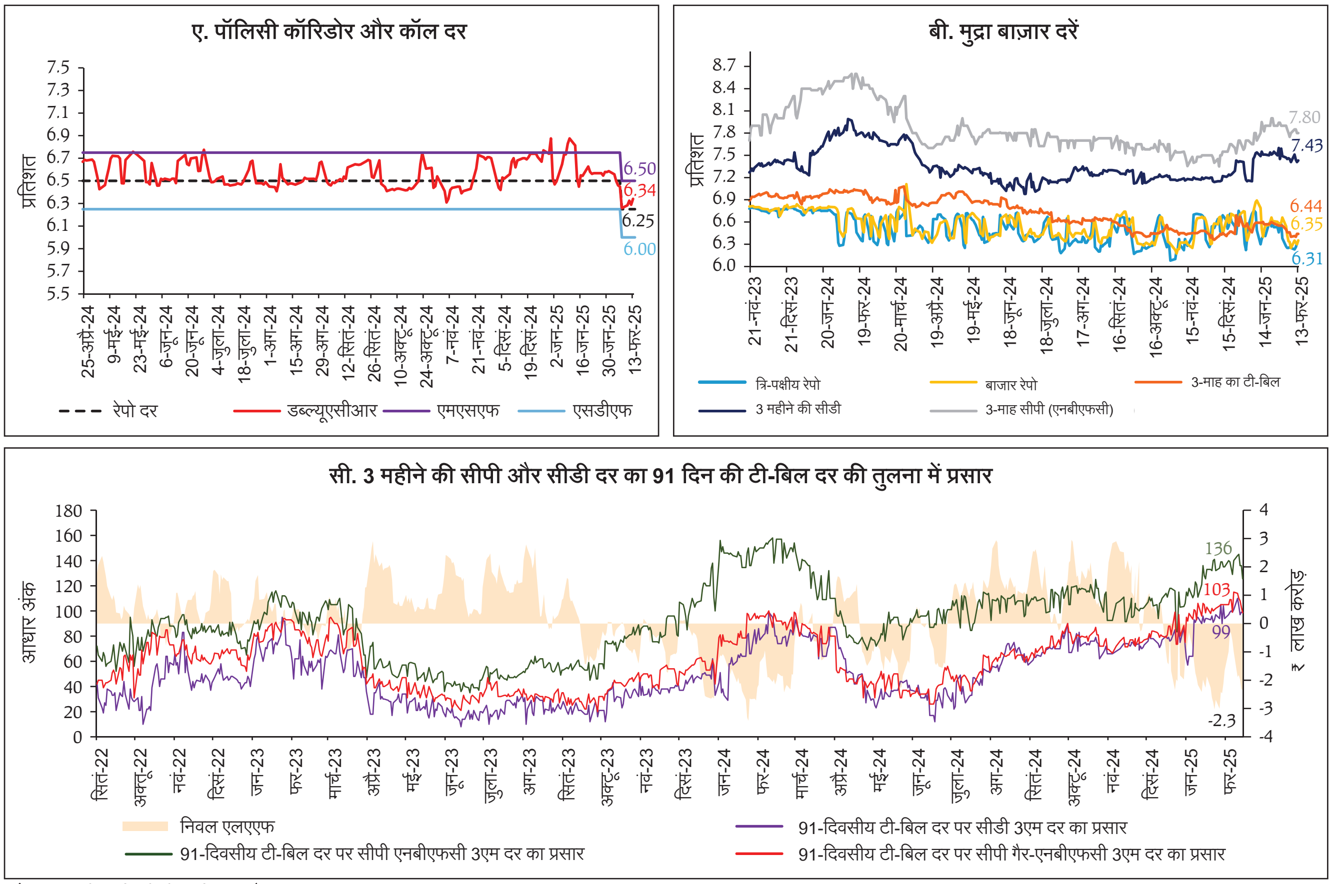

स्रोत: आरबीआई; सीसीआईएल; और ब्लूमबर्ग।

3 महीने के सीपी (एनबीएफसी) दर का 91-दिवसीय टी-बिल दर पर प्रसार पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 18 जनवरी - 14 फरवरी, 2025 के दौरान कम था। दूसरी ओर, 3 महीने के सीडी दर का 91-दिवसीय टी-बिल दर पर प्रसार बढ़ गया (चार्ट IV.2सी)।

18 जनवरी - 14 फरवरी, 2025 के दौरान सीपी की भारित औसत छूट दर (डब्ल्यूएडीआर) एक साल पहले दर्ज किए गए स्तरों से कम रही (चार्ट IV.3)। सीडी की भारित औसत प्रभावी ब्याज दर (डबल्यूएईआईआर) के लिए भी इसी तरह की प्रवृत्ति देखी गई। 18 जनवरी - 14 फरवरी, 2025 के दौरान डबल्यूएईआईआर एक साल पहले के 7.86 प्रतिशत की तुलना में 7.58 प्रतिशत कम रही क्योंकि ऋण और जमा वृद्धि के बीच का अंतर कम हो गया।

प्राथमिक बाजार में, अप्रैल 2024 से फरवरी 2025 (7 फरवरी तक) के दौरान सीडी का निर्गम 43.9 प्रतिशत (वर्ष दर वर्ष) बढ़कर 9.57 लाख करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में 6.66 लाख करोड़ रुपये था (चार्ट IV.4)। इसी तरह, 2024-25 (जनवरी तक) के दौरान सीपी का निर्गम 12.44 लाख करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 10.84 लाख करोड़ रुपये था।

10-वर्षीय जी-सेक बेंचमार्क पर प्रतिफल 15 जनवरी, 2025 को 6.85 प्रतिशत से घटकर 13 फरवरी, 2025 को 6.75 प्रतिशत हो गई। यह नरमी अमेरिका के खजाना प्रतिफल में नरमी, कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और आरबीआई के चलनिधि अंतर्वेशन परिचालन (चार्ट IV.5ए) के अनुरूप थी। प्रतिफल वक्र सम्पूर्ण अवधि में नीचे की ओर खिसक गया। 16 जनवरी और 13 फरवरी, 2025 के बीच, औसत अवधि प्रसार

चार्ट IV.3: डब्ल्यूएडीआर और डबल्यूएईआईआर

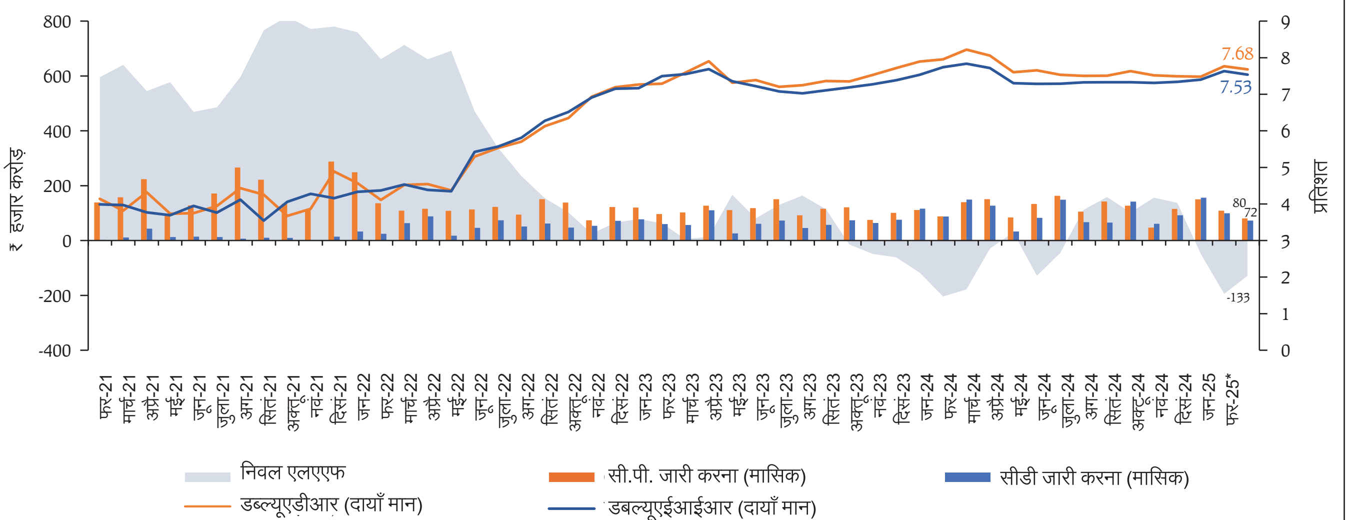

टिप्पणी: *: 14 फरवरी 2025 तक।

स्रोत: आरबीआई; और सीसीआईएल-एफटीआईआरएसी।

(10- वर्षीय जी-सेक प्रतिफल माइनस 91-दिवसीय टी-बिल प्रतिफल) पिछले महीने के 27 बीपीएस से घटकर 24 बीपीएस हो गया (चार्ट IV.5बी)।

10 वर्षीय भारतीय जी-सेक प्रतिफल का 10 वर्षीय अमेरिकी बॉण्ड पर प्रसार 14 फरवरी, 2025 को 217 बीपीएस तक गिर गया, जो सितंबर के मध्य में 314 बीपीएस और एक साल पहले 286 बीपीएस था। केंद्रीय बजट की घोषणा के बाद राजकोषीय समेकन पर सकारात्मक भावनाओं और वैश्विक सूचकांकों में भारतीय सरकारी बॉण्ड को शामिल किए जाने के बीच भारतीय बॉण्ड बाजार में प्रतिफल की अस्थिरता और कम हो गई और अमेरिकी खजाना के सापेक्ष कम रही (चार्ट IV.6)।

2024-25 (दिसंबर तक) के दौरान ₹7.25 लाख करोड़ के कॉरपोरेट बॉन्ड जारी किए गए, जो एक साल पहले ₹6.09 लाख करोड़ से ज़्यादा थे। 16 जनवरी से 13 फरवरी , 2025

चार्ट IV.4: जमा प्रमाणपत्र (सीडी) और वाणिज्यिक पत्र (सीपी) - पाक्षिक निर्गम

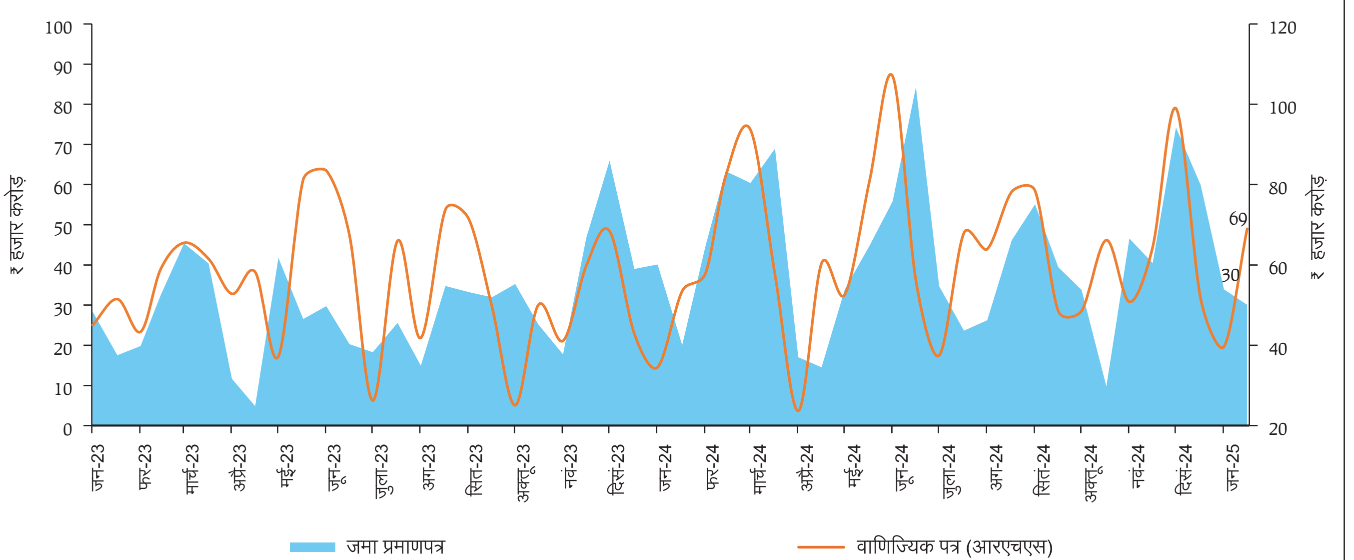

स्रोत: आरबीआई।

चार्ट IV.5: जी-सेक बाजार में विकास

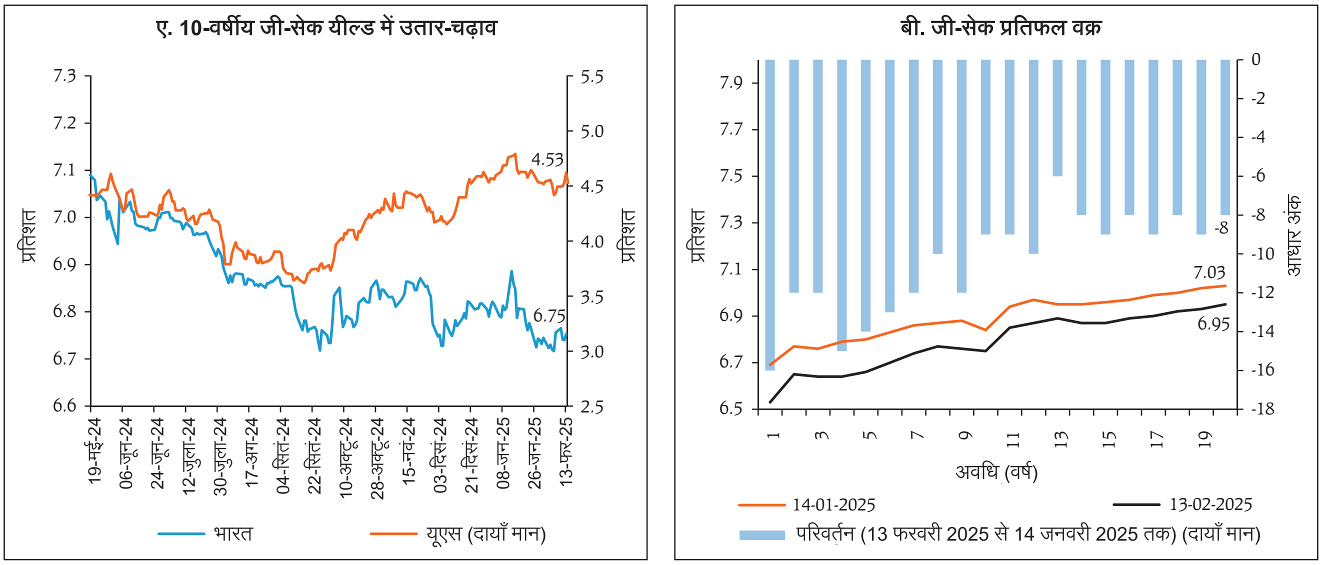

स्रोत: ब्लूमबर्ग: सीसीआईएल; तथा आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

के दौरान कॉरपोरेट बॉण्ड का प्रतिफल आम तौर पर रेटिंग और अवधि के स्पेक्ट्रम में नरम रहा, जबकि संबंधित जोखिम प्रीमियम ने मिश्रित रुझान दिखाया (सारणी IV.1)।

नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) में परिवर्तन के पहले दौर के प्रभाव को छोड़कर, आरक्षित मुद्रा (आरएम) में 7 फरवरी, 2025 तक 6.5 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि दर्ज की गई (एक वर्ष पहले 5.9 प्रतिशत) [चार्ट IV.7]। आरएम के सबसे बड़े घटक, प्रचलन में मुद्रा (सीआईसी) में वृद्धि 7 फरवरी, 2025 तक 5.3 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) रही, जबकि एक वर्ष पहले यह 3.7 प्रतिशत थी।

चार्ट IV.6: अस्थिरता और स्प्रेड-बॉण्ड बाज़ार

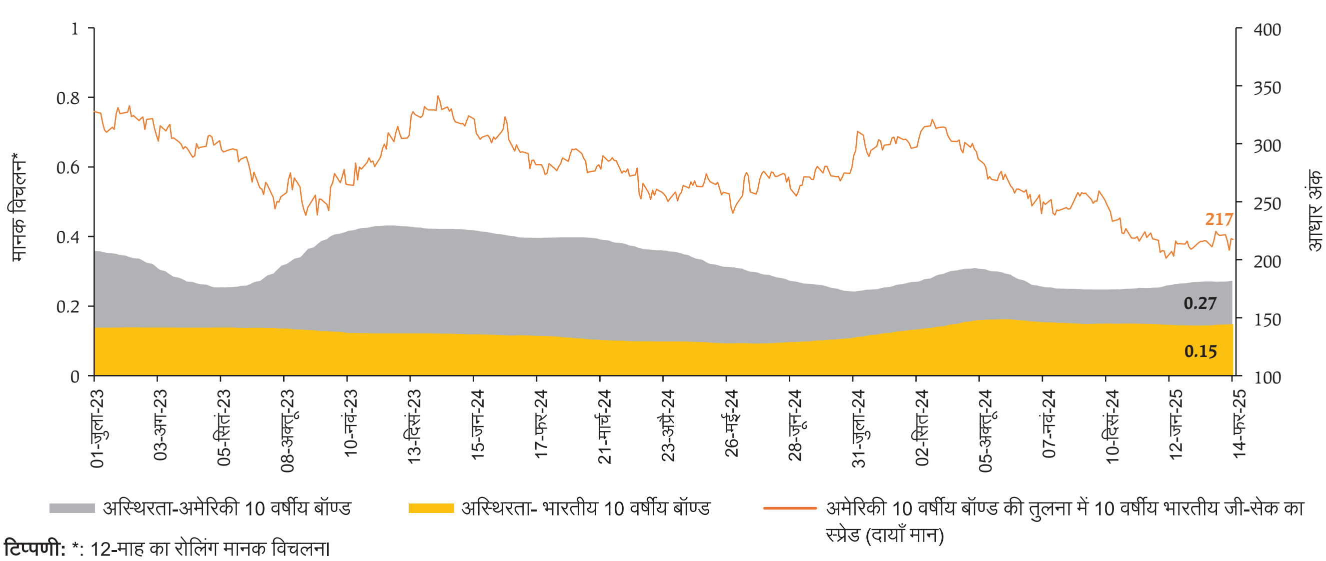

टिप्पणी: *: 12-माह का रोलिंग मानक विचलन।
स्रोत: ब्लूमबर्ग और आरबीआई स्टाफ की गणना।

सारणी IV.1: वित्तीय बाजार - दरें और प्रसार

लिखत	ब्याज दरें (प्रतिशत)			प्रसार (आधार अंक) (संबंधित जोखिम-मुक्त दर की तुलना में)		
	16 दिसंबर, 2024 – 15 जनवरी, 2025	16 जनवरी, 2025 – 13 फ़रवरी, 2025	भिन्नता (आधार अंक)	16 दिसंबर, 2024 – 15 जनवरी, 2025	16 जनवरी, 2025 – 10 फ़रवरी, 2025	उतार-चढ़ाव
1	2	3	(4 = 3-2)	5	6	(7 = 6-5)
कॉरपोरेट बॉण्ड						
(i) एएए (1-वर्ष)	7.88	7.88	0	112	117	5
(ii) एएए (3-वर्ष)	7.74	7.65	-9	92	91	-1
(iii) एएए (5-वर्ष)	7.62	7.50	-12	76	74	-1
(iv) एए (3-वर्षीय)	8.51	8.44	-7	169	170	1
(v) बीबीबी- (3-वर्ष)	12.18	12.11	-7	535	538	3

टिप्पणी: प्रतिफल और स्प्रेड की गणना संबंधित अवधि के औसत के रूप में की जाती है।
स्रोत: एफआईएमएमडीए

24 जनवरी, 2025 तक मुद्रा आपूर्ति (एम$_3$) में 9.6 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई (एक वर्ष पहले 11.0 प्रतिशत)।[20] बैंकों के पास कुल जमाराशि, जो एम$_3$ का लगभग 86 प्रतिशत है, में 10.2 प्रतिशत (एक वर्ष पहले 12.0 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) की ऋण वृद्धि 24 जनवरी, 2025 तक 12.5 प्रतिशत थी (एक वर्ष पहले 16.1 प्रतिशत) [चार्ट IV.8]।

एससीबी की जमा वृद्धि (विलय के प्रभाव को छोड़कर) 24 जनवरी 2025 को 10.6 प्रतिशत थी, जो दिसंबर 2024 के अंत में 10.2 प्रतिशत थी, जिसे जनवरी 2025 के पहले पखवाड़े में देखी गई सकारात्मक गति और अनुकूल आधार प्रभाव का समर्थन प्राप्त था (चार्ट IV.9)।

चार्ट IV.7: आरक्षित मुद्रा और प्रचलन में मुद्रा

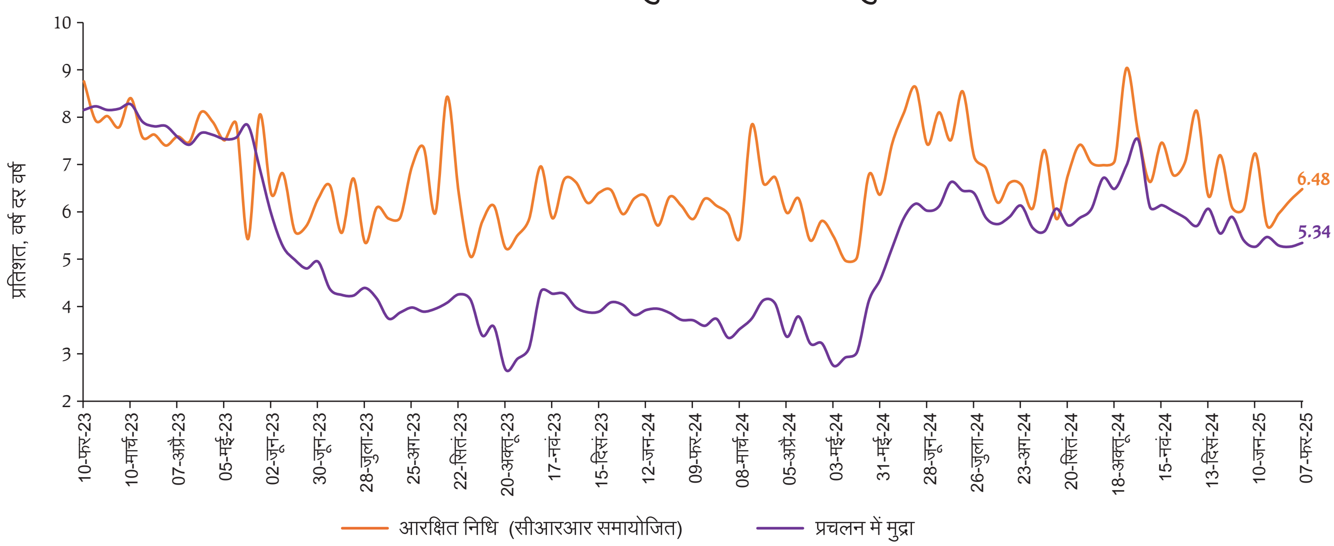

टिप्पणी: आरक्षित निधि का नवीनतम डेटा 7 फरवरी 2025 तक का है।
स्रोत: आरबीआई।

[20] किसी गैर-बैंक के बैंक में विलय के प्रभाव को छोड़कर (1 जुलाई, 2023 से प्रभावी)।

चार्ट IV.8: एम$_3$, एससीबी की वृद्धि और ऋण वृद्धि - आधार और गति प्रभाव

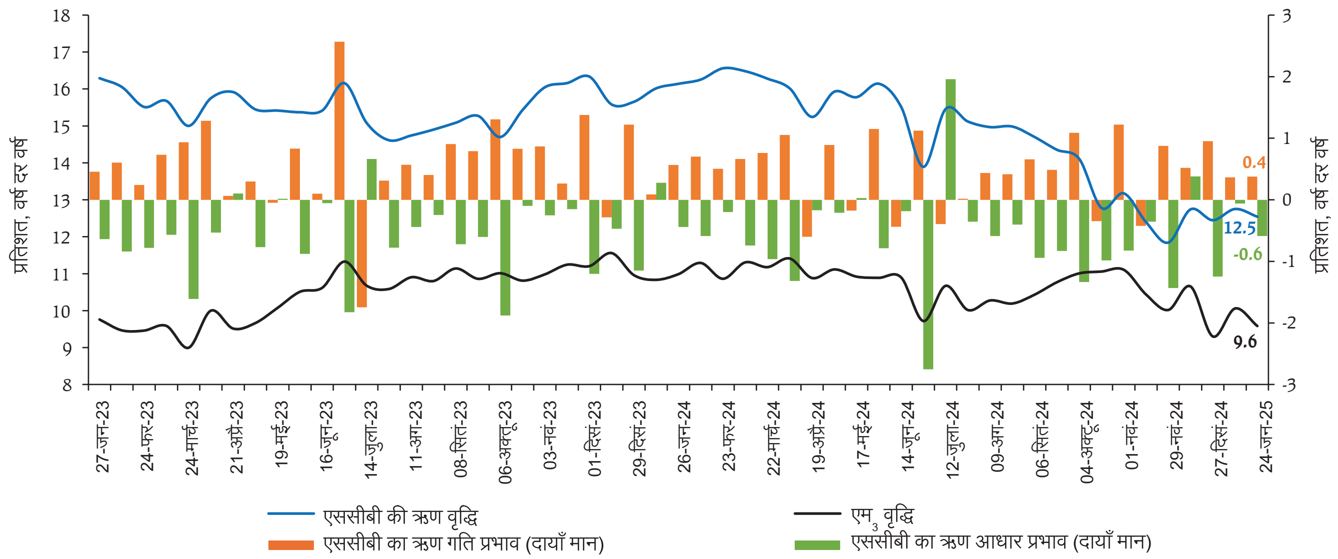

स्रोत: आरबीआई।

एससीबी का वृद्धिशील ऋण-जमा अनुपात अक्तूबर 2024 के अंत तक 80.7 प्रतिशत से बढ़कर 24 जनवरी 2025 को 91.6 प्रतिशत हो गया (चार्ट IV.10)।

दरों में तेजी से समायोजन के साथ, बाह्य बेंचमार्क-आधारित उधार दर (ईबीएलआर)[21] प्रणाली ने मौद्रिक नीति

चार्ट IV.9: एससीबी की जमा वृद्धि - गति और आधार प्रभाव

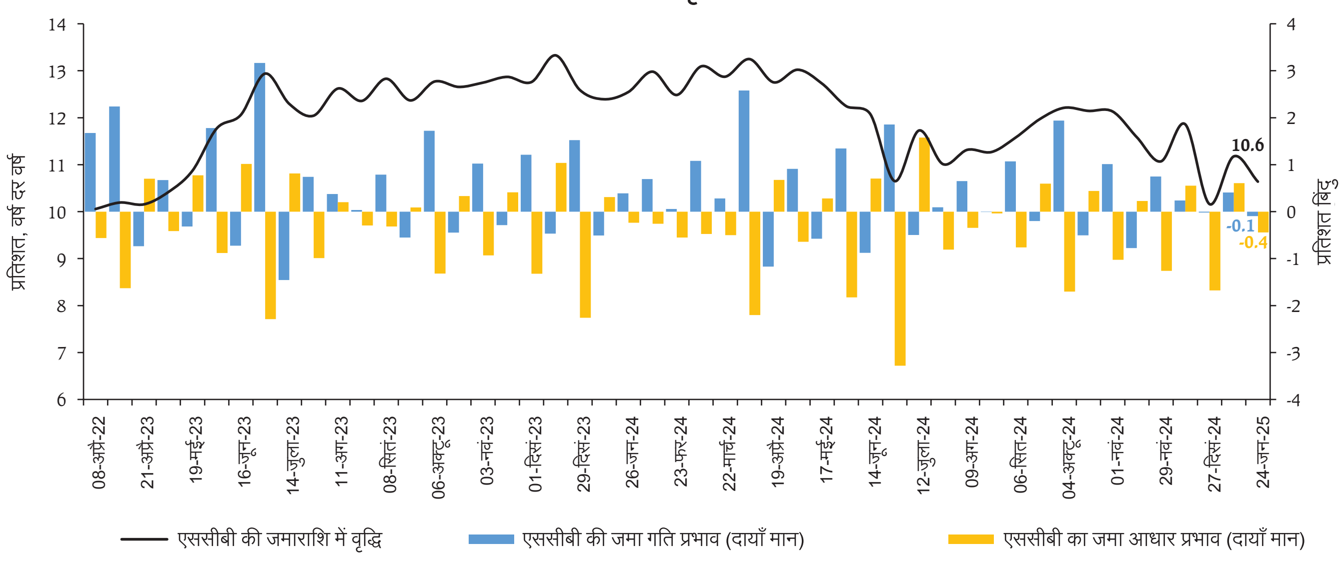

स्रोत: आरबीआई।

[21] रिज़र्व बैंक ने सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंको (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और लघु वित्त बैंकों को छोड़कर) को यह अधिदेश जारी किया कि सभी नए परिवर्तनीय दर व्यक्तिगत या खुदरा ऋण और सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) को परिवर्तनीय दर ऋण को नीतिगत रेपो दर या 3 महीने की टी-बिल दर या 6 महीने की टी-बिल दर या वित्तीय बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफबीआईएल) द्वारा प्रकाशित 1 अक्तूबर, 2019 से प्रभावी कोई अन्य बेंचमार्क बाजार ब्याज दर जैसे बाहरी बेंचमार्क से जोड़ना चाहिए। यह निर्देश 1 अप्रैल, 2020 से मध्यम उद्यमों के लिए बढ़ा दिया गया था।

चार्ट IV. 10: वृद्धिशील ऋण-जमा अनुपात

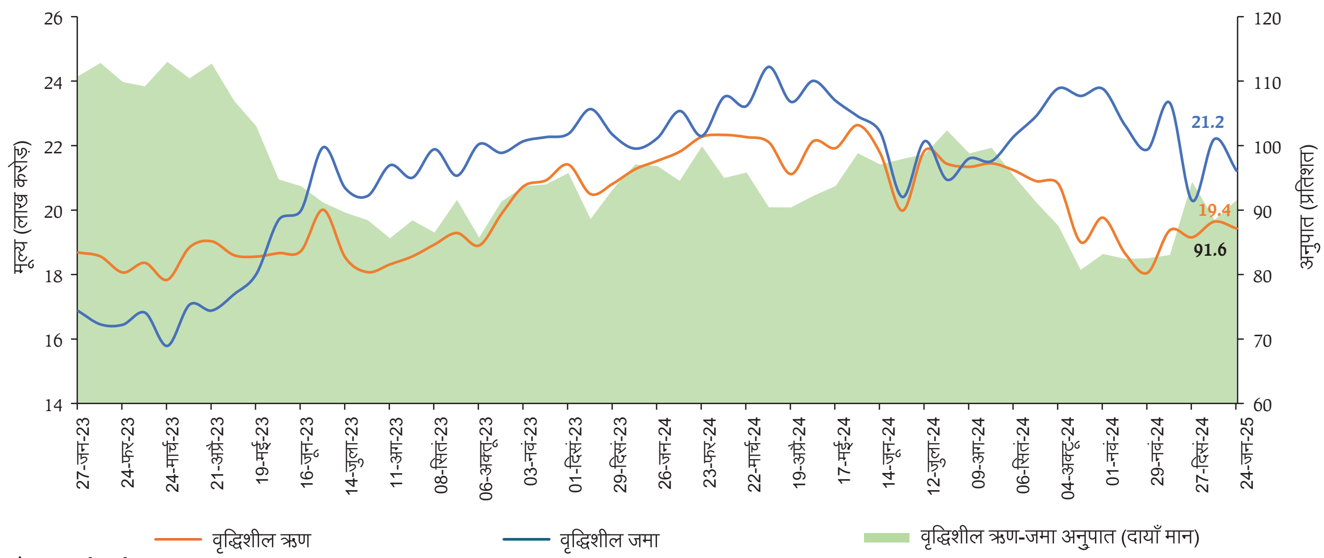

स्रोत: आरबीआई।

संचरण (आरबीआई, 2023)[22] की गति को तेज कर दिया है। फरवरी 2025 की द्विमासिक नीति में, नीति रेपो दर को 25 बीपीएस घटाकर 6.25 प्रतिशत कर दिया गया था। तदनुसार, बैंकों ने अपनी रेपो-लिंक्ड उधार दरों को नीचे की ओर समायोजित करना शुरू कर दिया है। निधि-आधारित उधार दर (एमसीएलआर) की सीमांत लागत, जिसमें लंबी समायोजन अवधि होती है और जिसे जमा दरों के साथ में संदर्भित किया जाता है, को देरी से समायोजित किए जाने की उम्मीद है। मई 2022 से जनवरी 2025 के दौरान 250 बीपीएस नीति दर वृद्धि के प्रतिक्रिया में, एससीबी के 1 वर्ष-औसत एमसीएलआर में 178 बीपीएस की वृद्धि हुई थी। परिणामस्वरूप, मई 2022 से दिसंबर 2024 के दौरान एससीबी के नए और बकाया रुपया ऋणों पर भारित औसत उधार दरों (डब्ल्यूएएलआर) में क्रमशः 174 बीपीएस और 115 बीपीएस की वृद्धि हुई (सारणी IV.2)। जमा पक्ष पर, इसी अवधि के दौरान नए और बकाया जमा पर भारित औसत घरेलू सावधि जमा दरों (डब्ल्यूएडीटीडीआर) में क्रमशः 254 बीपीएस और 197 बीपीएस की वृद्धि हुई।

बैंक समूहों में संचरण से संकेत मिलता है कि नए रुपए ऋणों पर डब्ल्यूएएलआर में वृद्धि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के लिए निजी बैंकों (पीवीबी) की तुलना में अधिक

सारणी IV.2: बैंकों की जमा और उधार दरों पर संचरण

(आधार अंक में परिवर्तन)

		सावधि जमा दरें		उधार दरें			
अवधि	रेपो दर	डब्ल्यूएडीटीडीआर - नया जमा	डब्ल्यूएडीटीडीआर - बकाया जमा	ईबीएलआर	1-वर्ष एमसीएलआर (माध्यिका)	डब्ल्यूएएलआर - नया रुपया ऋण	डब्ल्यूएएलआर - बकाया रुपया ऋण
फरवरी 2019 से मार्च 2022 तक **ढिलाई युक्त चरण**	-250	-259	-188	-250	-155	-232	-150
सख्ती की अवधि मई 2022 से दिसंबर* 2024 तक	+250	254	197	250	178	174	115

टिप्पणी: ईबीएलआर पर डेटा 32 घरेलू बैंकों से संबंधित है।
*: ईबीएलआर और एमसीएलआर पर डेटा जनवरी 2025 से संबंधित है।
डब्ल्यूएएलआर: भारित औसत उधार दर; **डब्ल्यूएडीटीडीआर:** भारित औसत घरेलू सावधि जमा दर;
एमसीएलआर: निधि की सीमांत लागत आधारित उधार दर; **ईबीएलआर:** बाहरी बेंचमार्क आधारित उधार दर।
स्रोत: आरबीआई।

[22] कश्यप, वाई., एवं अन्य., (2023)। भारत में मौद्रिक नीति संचरण: हालिया गतिशीलता, भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन, नवंबर- 2023, https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_ViewBulletin.aspx?Id=22192

चार्ट IV.11: बैंक समूहों में संचरण; उधार दरें (मई 2022 से दिसंबर 2024)

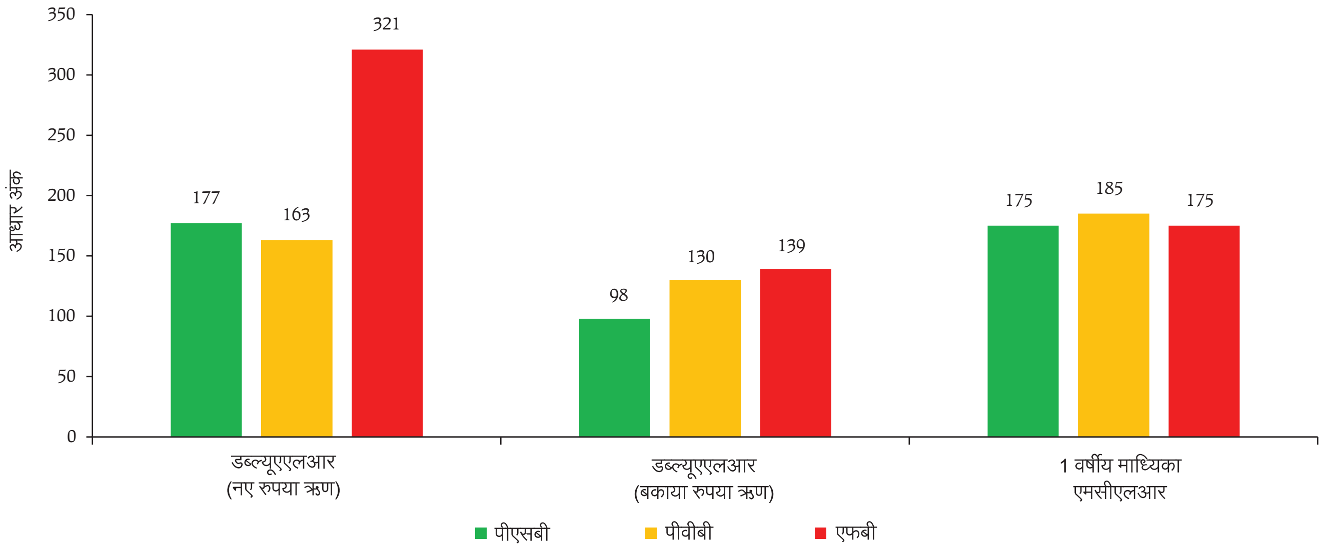

स्रोत: आरबीआई।

थी। हालांकि, बकाया ऋणों के मामले में, पीएसबी में संचरण कम था (चार्ट IV.11)। जमाराशियों में, मई 2022 और दिसंबर 2024 के दौरान पीवीबी की तुलना में पीएसबी के लिए नए और बकाया दोनों जमाराशियों के डब्ल्यूएडीटीडीआर में संचरण अधिक था (चार्ट IV.12)।

सूचीबद्ध गैर-सरकारी गैर-वित्तीय कंपनियों[23] के परिणामों के आधार पर, 2024-25 की तीसरी तिमाही के दौरान बिक्री में 7.9 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई, जो पिछली तिमाही में 5.4 प्रतिशत थी। सूचीबद्ध निजी विनिर्माण कंपनियों की बिक्री में 2024-25 की तीसरी तिमाही के दौरान 7.6 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई, जबकि पिछली तिमाही में यह 3.5 प्रतिशत थी (चार्ट IV.13)। ऑटोमोबाइल, रसायन, खाद्य और विद्युत मशीनरी उद्योग, जिनकी कुल मिलाकर विनिर्माण क्षेत्र की कुल बिक्री में लगभग 41 प्रतिशत हिस्सेदारी है, ने मुख्य रूप से

चार्ट IV. 12: बैंक समूहों में संचरण; जमा दरें (मई 2022 से दिसंबर 2024)

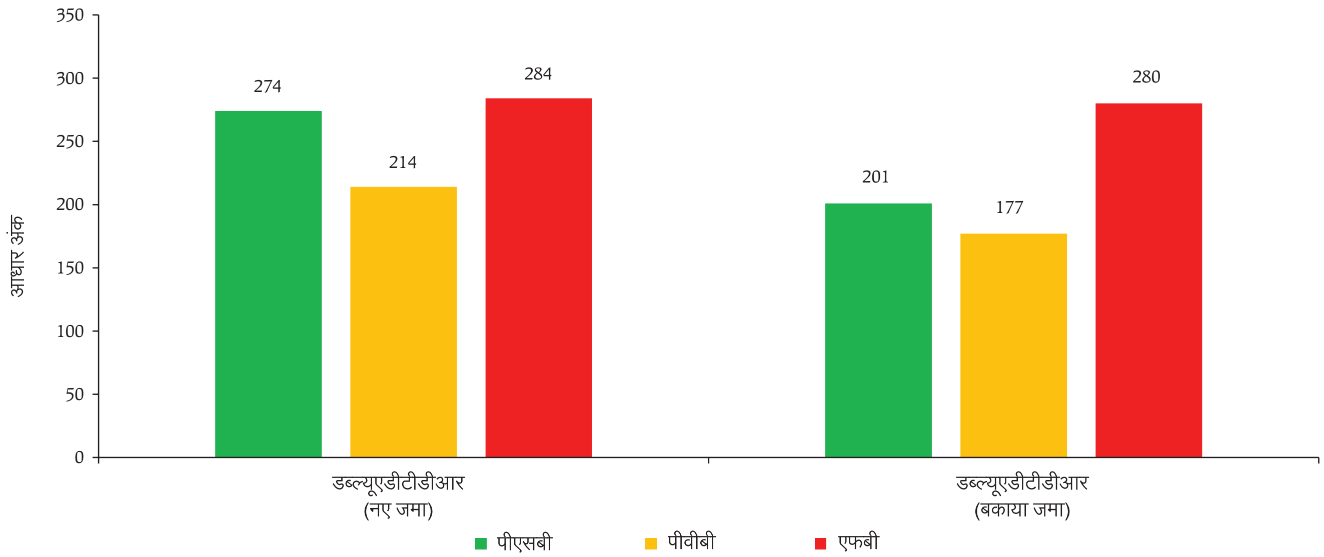

स्रोत: आरबीआई।

[23] 2263 सूचीबद्ध गैर-सरकारी गैर-वित्तीय (एनजीएनएफ) कंपनियों पर आधारित।

चार्ट IV.13: नाममात्र बिक्री वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष)

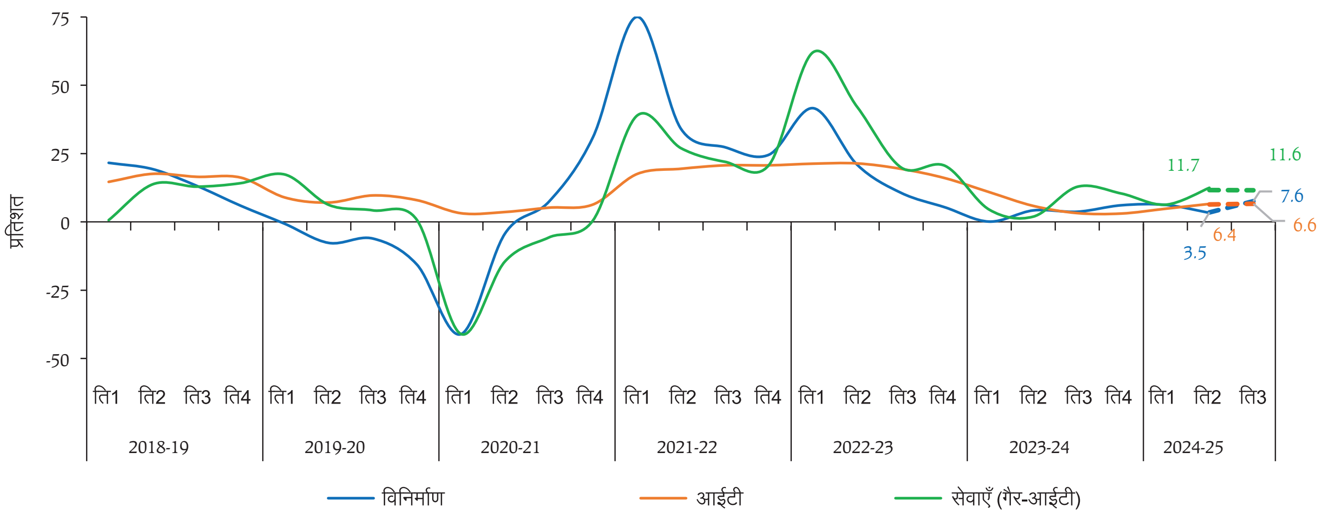

टिप्पणियाँ: (i) बिंदीदार रेखाएं 2024-25 की दूसरी और तीसरी तिमाही के दौरान उभयनिष्ठ कंपनियों की वृद्धि दर्शाती हैं।
(ii) 2263 सूचीबद्ध निजी गैर-वित्तीय कंपनियों के परिणामों के आधार पर।
स्रोत: कैपिटालाइन डेटाबेस; तथा आरबीआई स्टाफ गणना।

तीसरी तिमाही के दौरान विनिर्माण बिक्री वृद्धि में योगदान दिया। हालांकि, प्रमुख उद्योगों में पेट्रोलियम, लोहा और इस्पात तथा सीमेंट उद्योगों की बिक्री में तीसरी तिमाही के दौरान कमी आई। गैर-आईटी सेवा क्षेत्र का प्रदर्शन दोहरे अंकों की बिक्री वृद्धि से संकेत के रूप में बेहतर रहा। आईटी कंपनियों की बिक्री वृद्धि में भी थोड़ी वृद्धि हुई, लेकिन 2024-25 की तीसरी तिमाही के दौरान यह कम रही।

इनपुट लागत और अन्य खर्चों में वृद्धि के बावजूद, विनिर्माण कंपनियों के परिचालन लाभ में वर्ष-दर-वर्ष और क्रमिक आधार पर 2024-25 की तीसरी तिमाही के दौरान वृद्धि हुई। परिणामस्वरूप, पिछली तिमाही की तुलना में तीसरी तिमाही के दौरान परिचालन लाभ मार्जिन में मामूली सुधार हुआ। सेवा क्षेत्र में, 2024-25 के दौरान आईटी और गैर-आईटी सेवा क्षेत्र की कंपनियों के लिए परिचालन लाभ मार्जिन में सुधार हुआ, जो उनकी निरंतर बिक्री वृद्धि (चार्ट IV.14) के अनुरूप है।

चार्ट IV. 14: परिचालन लाभ मार्जिन

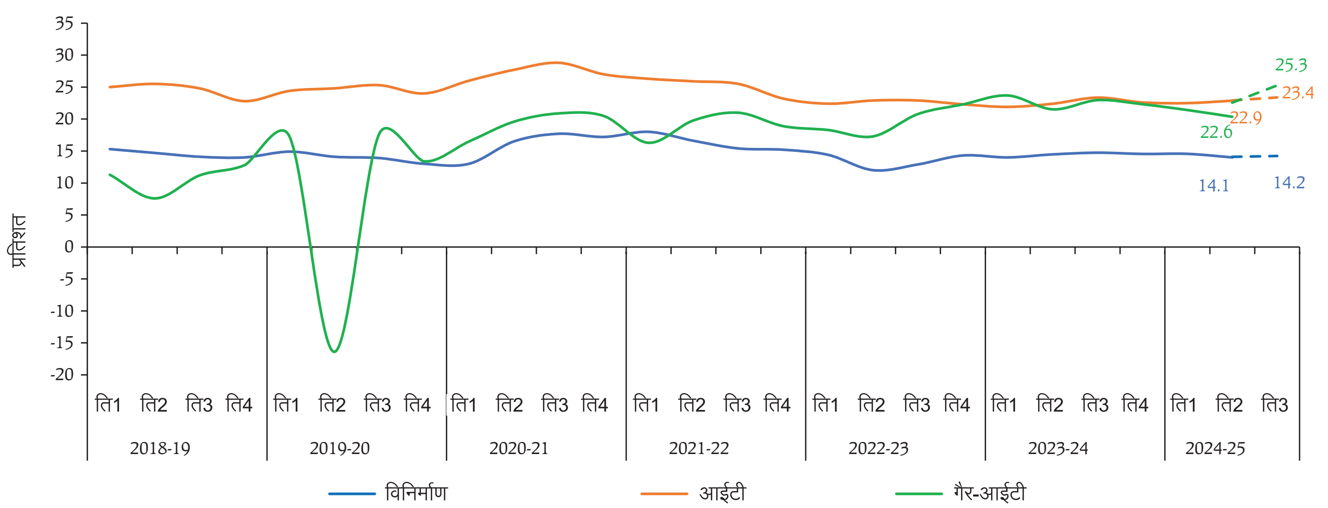

टिप्पणियाँ: (i) बिंदीदार रेखाएं 2024-25 की दूसरी और तीसरी तिमाही के दौरान उभयनिष्ठ कंपनियों की वृद्धि दर्शाती हैं।
(ii) 2263 सूचीबद्ध निजी गैर-वित्तीय कंपनियों के परिणामों के आधार पर।
स्रोत: कैपिटालाइन डेटाबेस; तथा आरबीआई स्टाफ गणना।

चार्ट IV.15: निजी कॉरपोरेट निवेश इरादे

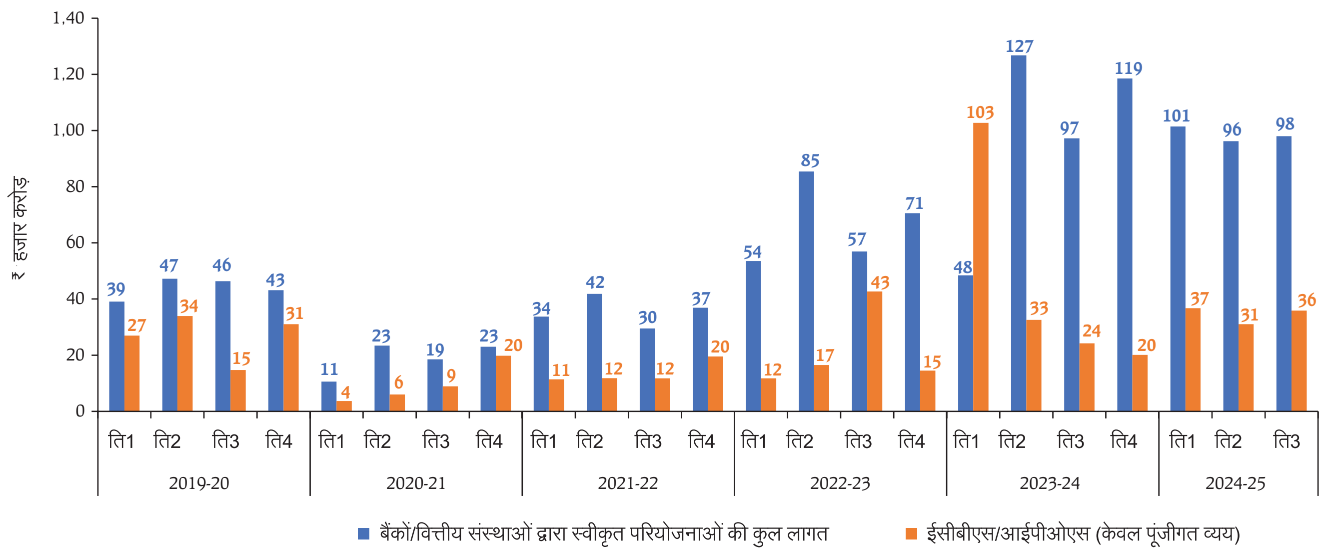

स्रोत: आरबीआई; बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से एकत्रित परियोजना वित्त पर आंकड़े; तथा आरबीआई स्टाफ की गणना।

चुनिंदा बैंकों और वित्तीय संस्थानों (एफआई) से एकत्र किए गए परियोजना वित्त डेटा से पता चलता है कि 2024-25 की तीसरी तिमाही के दौरान, बैंकों/एफआई द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं की कुल लागत लगभग ₹97,996 करोड़ थी, जो पिछली तिमाही में ₹96,226 से थोड़ी अधिक थी। लगभग 70 प्रतिशत इच्छित निवेश 'बिजली', 'धातु' और 'सड़क और पुल' उद्योगों में केंद्रित था। पूंजीगत व्यय के उद्देश्य से ईसीबी और आईपीओ के माध्यम से जुटाई गई धनराशि 2024-25 की तीसरी तिमाही के दौरान ₹35,893 करोड़ थी, जबकि पिछली तिमाही में यह ₹31,027 करोड़ थी (चार्ट IV.15)।

2024-25 की तीसरी तिमाही के दौरान, भारतीय सूचीबद्ध बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र की कंपनियों[24] ने अपनी टॉप-लाइन वृद्धि में नरमी का अनुभव किया (चार्ट IV.16)। राजस्व, जिसमें मुख्य रूप से बैंकों के मामले में ब्याज आय शामिल है, ने बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र की कंपनियों के लिए दोहरे अंकों की वृद्धि प्रदर्शित की, हालांकि पिछली तिमाही की तुलना में इसमें कुछ नरमी आई। अन्य आय की वृद्धि, जिसमें शुल्क, कमीशन, निवेश से लाभ और हानि आदि से आय शामिल है, पिछली तिमाही की तुलना में धीमी रही। वेतन वृद्धि में नरमी के बीच व्यय वृद्धि राजस्व वृद्धि की तुलना में धीमी रही। इसके अलावा, प्रावधान लागत में गिरावट के परिणामस्वरूप परिचालन लाभ की तुलना में निवल लाभ में तेज़ वृद्धि हुई।

जनवरी-फरवरी 2025 के दौरान अब तक, भारतीय इक्विटी बाजारों ने मध्यम नुकसान दर्ज किया, बीएसई सेंसेक्स 1 प्रतिशत (15 जनवरी से) घटकर 14 फरवरी, 2025 को 75,939 पर बंद हुआ (चार्ट IV.17)। व्यापक बाजार सूचकांकों

चार्ट IV. 16: सूचीबद्ध वित्तीय कंपनियों का प्रदर्शन

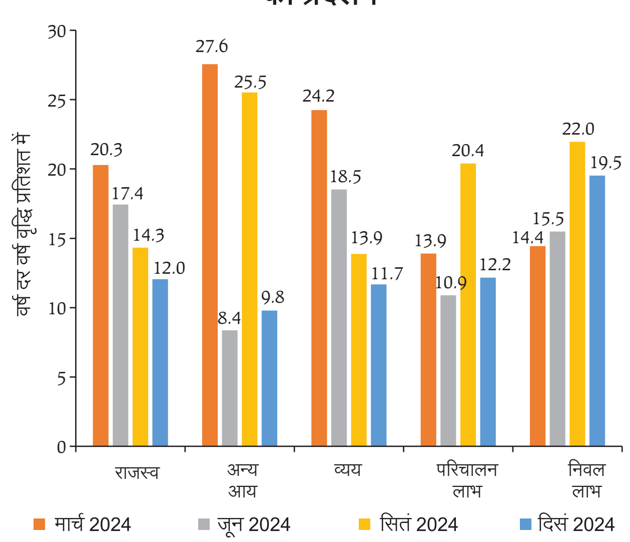

स्रोत: सीएमआईई प्रोवेस; तथा आरबीआई स्टाफ अनुमान।

24 सूचीबद्ध बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र की कंपनियों के कुल बाजार पूंजीकरण का लगभग 81 प्रतिशत हिस्सा बनाने वाली 328 कंपनियों के नमूने के आधार पर।

चार्ट IV.17: बीएसई सेंसेक्स और संस्थागत प्रवाह

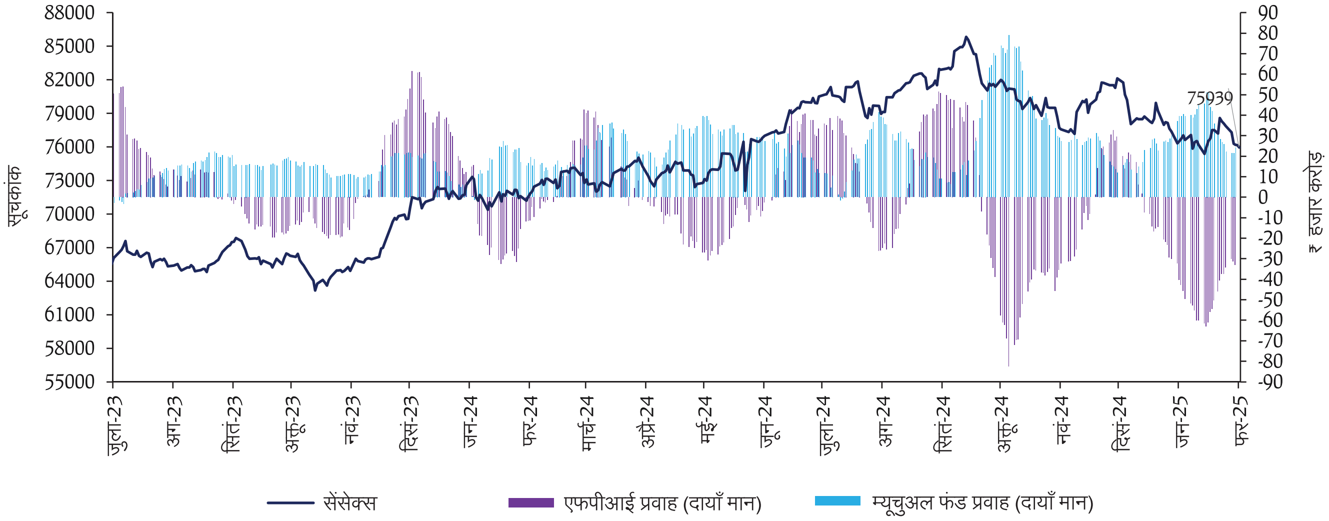

टिप्पणी: एफपीआई और एमएफ प्रवाह 15-दिवसीय रोलिंग योग के आधार पर दर्शाए जाते हैं।
स्रोत: ब्लूमबर्ग।

ने बेंचमार्क से कमजोर प्रदर्शन किया, इसी अवधि के दौरान बीएसई मिडकैप और बीएसई स्मॉलकैप सूचकांकों में क्रमशः 8.3 प्रतिशत और 11.9 प्रतिशत की गिरावट आई। जनवरी के दूसरे भाग में, बाजारों में शुरुआत में गिरावट आई क्योंकि निवेशकों ने 2024-25 की तीसरी तिमाही के लिए कॉरपोरेट आय रिलीज और यूएस आउटलुक के बारे में अनिश्चितताओं का आकलन किया। बैंकिंग प्रणाली में चलनिधि बढ़ाने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपायों की घोषणा और वैश्विक बाजारों से अनुकूल संकेतों के बीच जनवरी के अंतिम सप्ताह में बेंचमार्क ने तेज बदलाव दर्ज किया।

अप्रैल-दिसंबर 2024 के दौरान सकल आवक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) 20.6 प्रतिशत (व-द-व) बढ़कर 62.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया (चार्ट IV.18ए)। क्षेत्रों के मध्य, विनिर्माण, वित्तीय सेवाएं, बिजली और अन्य ऊर्जा,

चार्ट IV.18: प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह

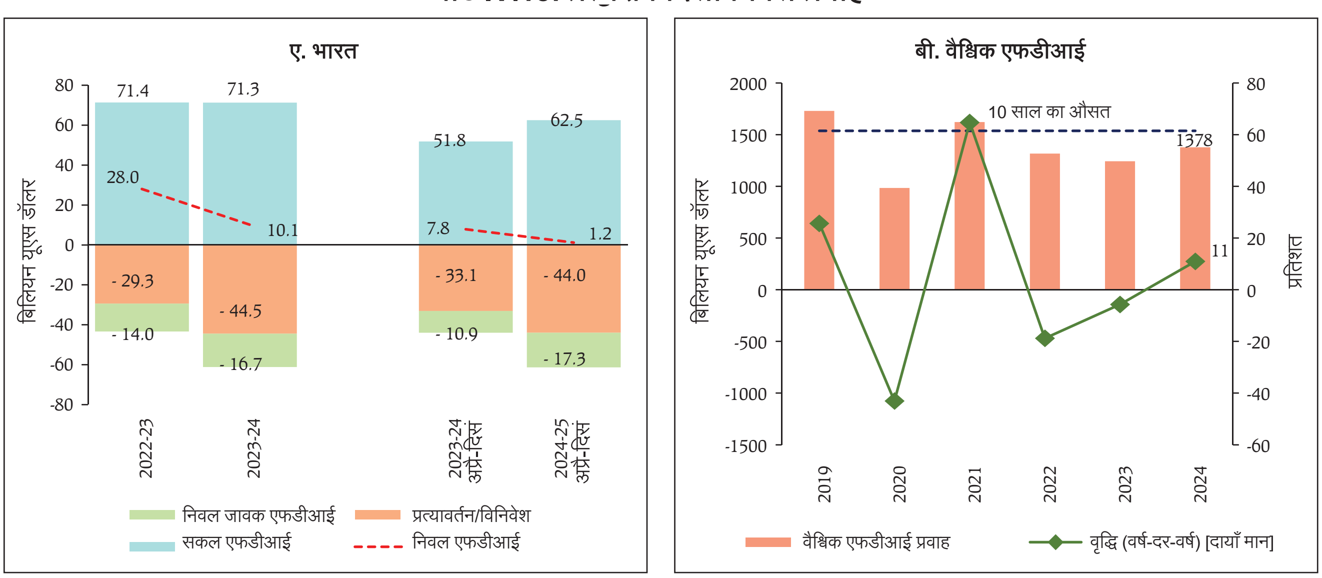

स्रोत: आरबीआई; और यूएनसीटीएडी।

और संचार सेवाओं को सकल इक्विटी अंतर्वाह का 60 प्रतिशत से अधिक हिस्सा प्राप्त हुआ। सिंगापुर, मॉरीशस, संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड और अमेरिका शीर्ष निवेश स्रोत रहे, जिनकी इस अवधि के दौरान प्रवाह में 75 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी रही। निवल आवक एफडीआई (यानी, प्रत्यावर्तन के लिए समायोजित सकल आवक एफडीआई) एक वर्ष पहले के 18.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अप्रैल-दिसंबर 2024 के दौरान थोड़ा कम होकर 18.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो प्रत्यावर्तन में वृद्धि को दर्शाता है। वैश्विक एफडीआई 2024 में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 11 प्रतिशत बढ़ा, लेकिन लगातार तीसरे वर्ष अपने 10 वर्षीय औसत से नीचे रहा (चार्ट IV.18बी)।

जनवरी 2025 में एफपीआई प्रवाह ऋणात्मक हो गए, जो वैश्विक अनिश्चितताओं में वृद्धि को दर्शाता है। निवेशकों के बीच जोखिम-विमुख रुझान के बढ़ने से 8.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर के इक्विटी बहिर्वाह के साथ 6.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवल एफपीआई बहिर्वाह दर्ज किए गए (चार्ट IV.19ए)। हालांकि, कर्ज खंड ने पुनरुद्धार के संकेत दिखाए, जिसमें 1.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवल अंतर्वाह था, जो अक्टूबर 2024 के बाद से सर्वाधिक था। 31 जनवरी 2025 को, ब्लूमबर्ग इंडेक्स सर्विसेज ने अपने ब्लूमबर्ग इमर्जिंग मार्केट (ईएम) लोकल करेंसी इंडेक्स में भारतीय सरकारी बॉण्ड को शामिल किया, जिससे कर्ज खंड में 1.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का अंतर्वाह हुआ। 2024-25 (अप्रैल-जनवरी) के दौरान, भारत में कर्ज अंतर्वाह समकक्ष अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में मजबूत रहा, जिसने औने-पौने दाम पर हुई इक्विटी बिक्री के प्रभाव को कम किया (चार्ट IV.19बी)। फरवरी 2025 (13 फरवरी तक) में, निवल एफपीआई बहिर्वाह 2.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ जारी रहा।

अप्रैल-दिसंबर 2024 के दौरान गैर-निवासी जमा (एनआरडी) के तहत निवल अंतर्वाह, एक वर्ष पहले के 9.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 13.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जिसमें सभी तीन खातों, अर्थात् अनिवासी (बाह्य) रुपया खाते [एनआर(ई)आरए], अनिवासी साधारण (एनआरओ) और विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) [एफसीएनआर (बी)] खातों में प्रवाह शामिल है। अप्रैल-दिसंबर 2024 के दौरान, निवल बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) अंतर्वाह 15.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में दर्ज किए गए प्रवाह का लगभग तीन गुना है (चार्ट IV.20)।

अप्रैल-दिसंबर 2024 के दौरान पंजीकृत कुल ईसीबी में से 40 प्रतिशत से अधिक का उपयोग पूंजीगत व्यय उद्देश्यों के लिए किया जाना था। इसके अलावा, इस अवधि में पिछले वर्ष

चार्ट IV.19: निवल पोर्टफोलियो निवेश

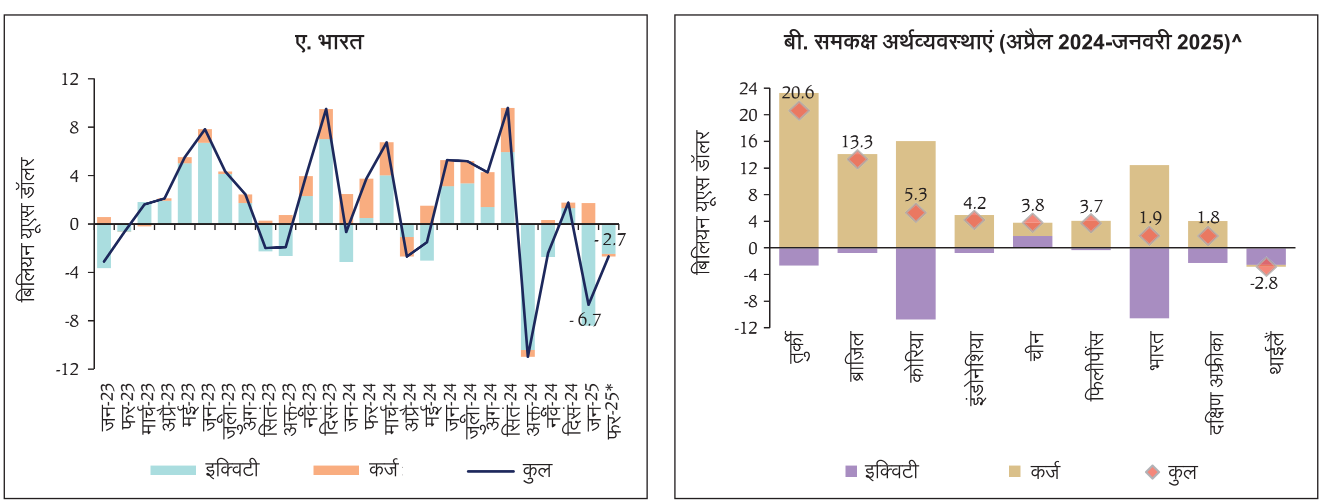

टिप्पणियाँ: 1. कर्ज में हाइब्रिड लिखतों के अंतर्गत निवेश भी शामिल है।
2.*: 13 फरवरी तक का डेटा।
3.^: भारत और अन्य देशों के लिए इक्विटी प्रवाह के आंकड़े जनवरी 2025 तक के हैं, जबकि अन्य देशों के लिए कर्ज प्रवाह दिसंबर 2024 तक के हैं।
स्रोत: नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल); तथा इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस।

चार्ट IV.20: बाह्य वाणिज्यिक उधार - पंजीकरण और प्रवाह

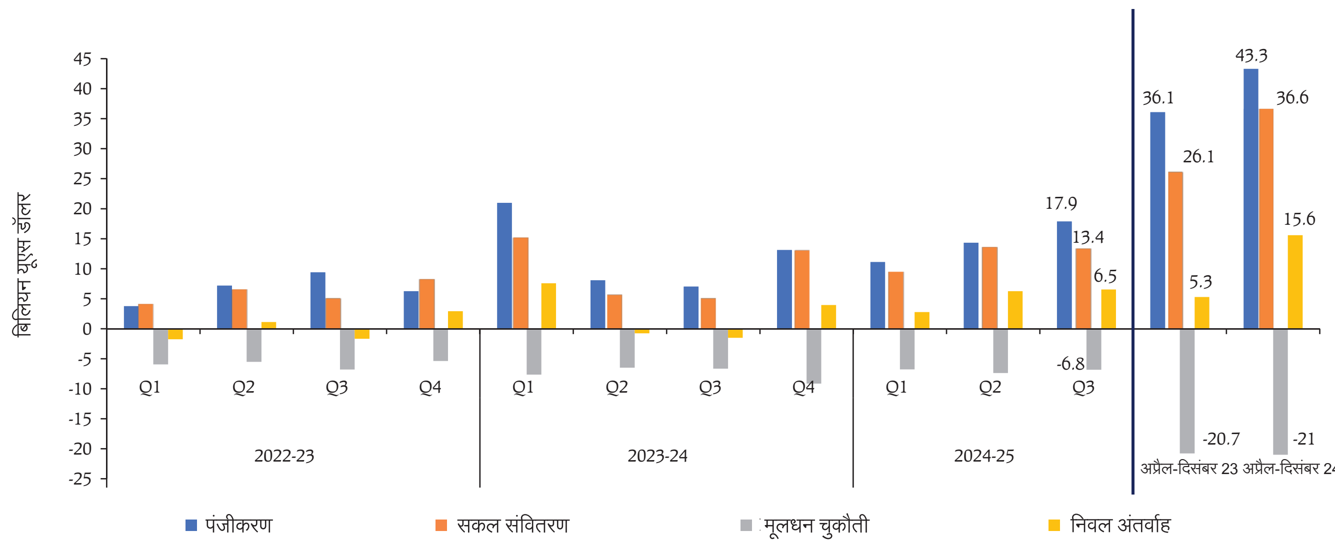

स्रोत: फॉर्म ईसीबी, आरबीआई।

की तुलना में ईसीबी/रुपया ऋणों के पुनर्वित्तपोषण में भी पर्याप्त वृद्धि देखी गई (चार्ट IV.21)।

अप्रैल-दिसंबर 2024 के दौरान, प्रभावी रूप से रक्षित (हेज किए गए) ईसीबी, यथा स्पष्ट रूप से हेज किए गए ऋण, रुपये में मूल्यवर्गित ऋण और विदेशी मूल कंपनियों से ऋण का हिस्सा पिछले वर्ष की इसी अवधि के 61.6 प्रतिशत से बढ़कर 78.1 प्रतिशत हो गया (चार्ट IV.22)। यह ऐसे एक्सपोजर की ब्याज और विनिमय दर संवेदनशीलता को प्रभावहीन करने में काफी मदद करता है।

मार्च 2024 से, वैश्विक बेंचमार्क ब्याज दरें जैसे कि सुरक्षित एकदिवसीय वित्तपोषण दर (एसओएफआर) में 85 आधार अंकों तक की गिरावट हुई है, जिससे अप्रैल-दिसंबर 2024 के दौरान ईसीबी की कुल लागत में 25 आधार अंकों की कमी आई है (चार्ट IV.23)।

चार्ट IV.21: पंजीकृत ईसीबी का अंतिम उपयोग

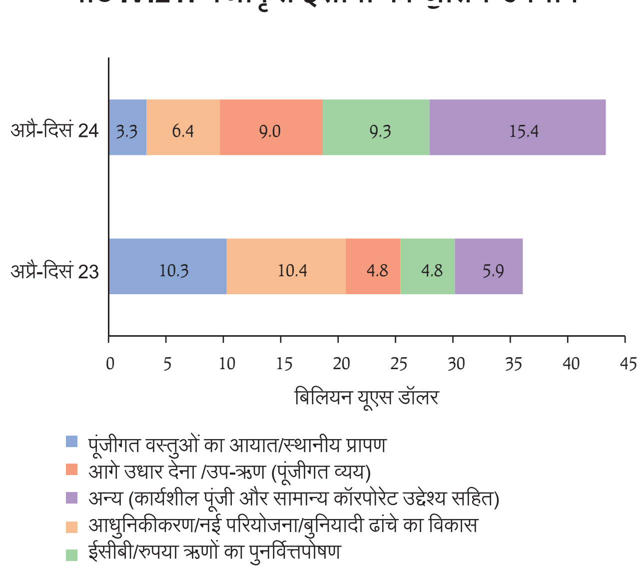

स्रोत: फॉर्म ईसीबी, आरबीआई।

चार्ट IV.22: ईसीबी समझौते - हेजिंग स्थिति

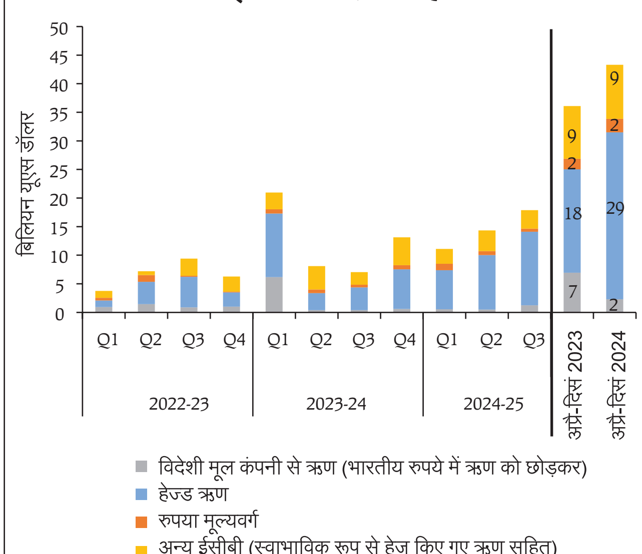

स्रोत: फॉर्म ईसीबी, आरबीआई।

चार्ट IV.23: ईसीबीएस की कुल लागत

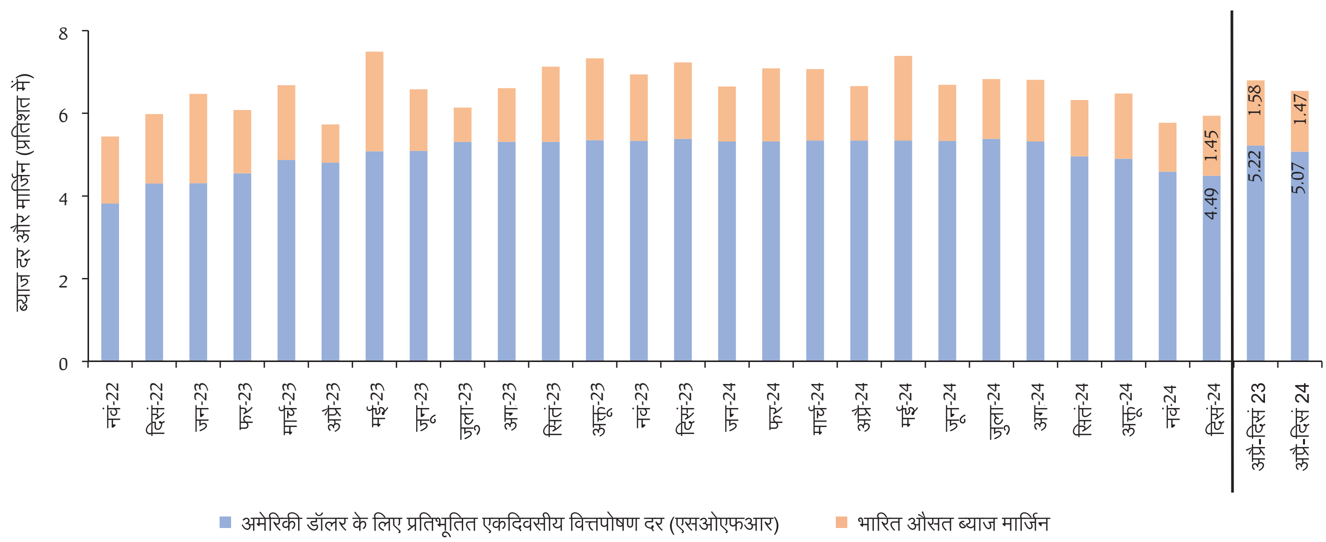

स्रोत: ईसीबी फॉर्म; तथा आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

बढ़ती वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच बढ़ते अमेरिकी डॉलर और ईएमई से एफपीआई के बहिर्वाह ने जनवरी 2025 के दौरान ईएमई मुद्राओं पर महत्वपूर्ण दबाव बनाया। जनवरी में भारतीय रुपये (आईएनआर) में 1.5 प्रतिशत (मासिक) की गिरावट आई, जो अधिकांश प्रमुख मुद्राओं में उतार-चढ़ाव के अनुरूप है (चार्ट IV.24)। वैश्विक बाजार में उथल-पुथल के माहौल में, आईएनआर में अपेक्षाकृत कम अस्थिरता देखी गई।

40-मुद्रा वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आरईईआर) के संदर्भ में, सांकेतिक प्रभावी शर्तों में भारतीय रुपये के मूल्यह्रास और ऋणात्मक सापेक्षिक मूल्य अंतर के कारण, जनवरी 2025

चार्ट IV.24: अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये और प्रमुख मुद्राओं में परिवर्तन (जनवरी 2025 से दिसंबर 2024 तक)

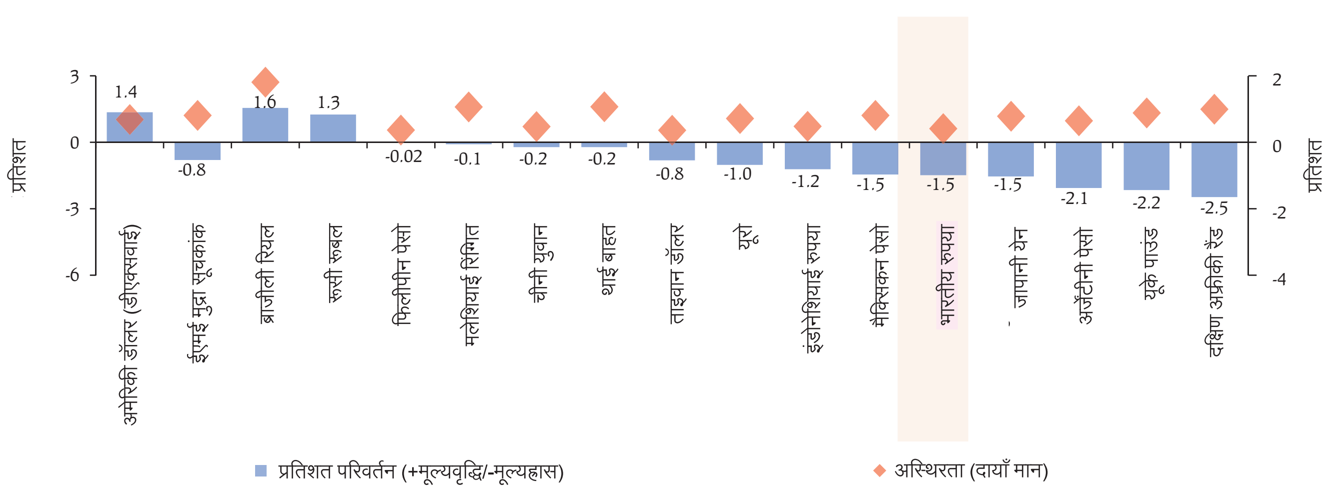

टिप्पणियाँ: अमेरिकी डॉलर (डीएक्सवाई) प्रमुख मुद्राओं (यूरो, जापानी येन, ब्रिटिश पाउंड, कनाडाई डॉलर, स्वीडिश क्रोना, स्विस फ्रैंक) की एक टोकरी के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की गतिविधियों को मापता है।
स्रोत: एफबीआईएल; थॉमसन रॉयटर्स; तथा आरबीआई स्टाफ अनुमान।

चार्ट IV.25: 40-मुद्रा वास्तविक प्रभावी विनिमय दर में हलचल

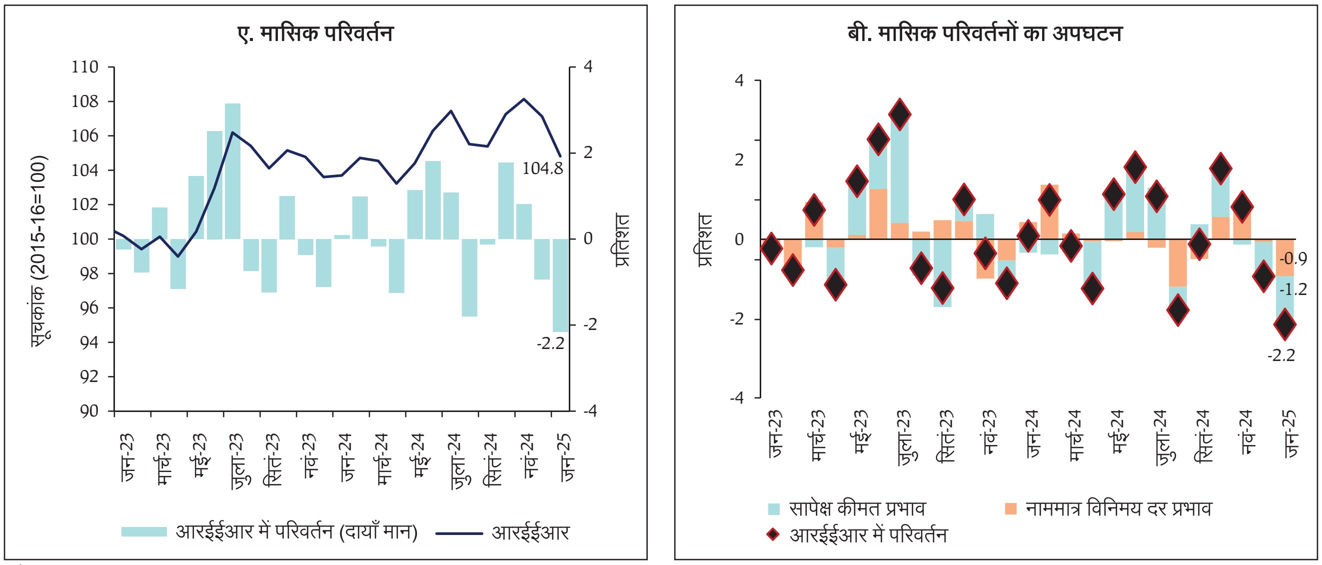

स्रोत: आरबीआई।

में भारतीय रुपये में 2.2 प्रतिशत (माह-दर-माह) की गिरावट आई (चार्ट IV.25)।

7 फरवरी 2025 तक, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 638.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो सितंबर 2024 के अंत में 10.8 महीने के आयात और 89.7 प्रतिशत बकाया बाह्य कर्ज के लिए कवर प्रदान करता है (चार्ट IV.26ए)। विभिन्न रिजर्व पर्याप्तता मेट्रिक्स के आधार पर विदेशी मुद्रा भंडार का स्तर संधारणीय बना रहा (चार्ट IV.26बी)।

भुगतान प्रणालियाँ

भारतीय रिज़र्व बैंक - डिजिटल भुगतान सूचकांक सितंबर 2024 में 465.3 पर पहुंच गया, जो देश में डिजिटलीकरण की बढ़ती पहुंच को दर्शाता है।[25] जनवरी 2025 में, डिजिटल लेनदेन

चार्ट IV.26: विदेशी मुद्रा भंडार

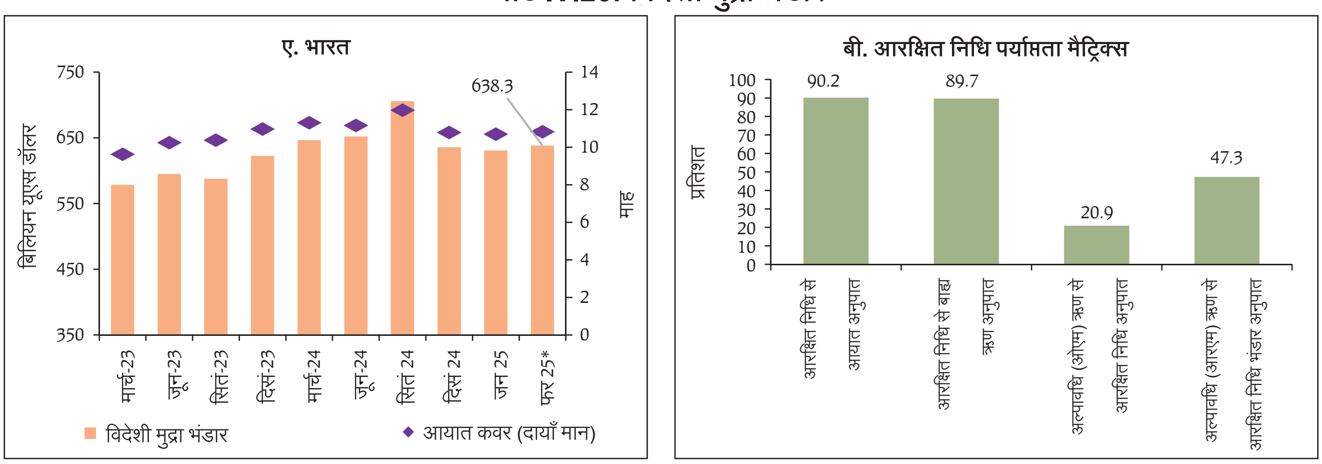

टिप्पणियाँ: 1. *: 7 फरवरी के आंकड़े।
2. दिसंबर 2024, जनवरी और फरवरी 2025 के लिए आयात कवर डेटा भुगतान संतुलन के आंकड़ों के अनुसार सितंबर 2024 को समाप्त तिमाही के लिए वार्षिक व्यापारिक आयात पर आधारित है।
3. ओएम: मूल परिपक्वता: आरएम: अवशिष्ट परिपक्वता। रिज़र्व पर्याप्तता मैट्रिक्स की गणना सितंबर 2024 के लिए नवीनतम उपलब्ध रिज़र्व डेटा और वार्षिक व्यापारिक आयात और बाहरी ऋण का उपयोग करके की गई है।

स्रोत: आरबीआई; तथा आरबीआई स्टाफ अनुमान।

[25] आरबीआई प्रेस प्रकाशनी, 29 जनवरी 2025, *"आरबीआई – सितंबर 2024 के लिए डिजिटल भुगतान सूचकांक"*।

सारणी IV.3 : चुनिन्दा भुगतान प्रणालियों में वृद्धि दर

(वर्षानुवर्ष प्रतिशत)

भुगतान प्रणाली	लेनदेन मात्रा				लेनदेन मूल्य			
	दिसं -23	दिसं-24	जन-24	जन-25	दिसं -23	दिसं -24	जन-24	जन-25
आरटीजीएस	7.1	13.8	13.1	16.1	15.7	20.6	17.1	19.1
एनईएफटी	37.5	24.5	43.4	24.5	13.0	13.2	19.8	14.3
यूपीआई	53.5	39.2	51.8	39.3	42.2	27.5	41.7	27.5
आईएमपीएस	2.7	-11.6	7.2	-12.7	17.2	5.5	18.6	7.1
एनएसीएच	10.9	28.2	22.8	17.2	4.6	27.6	21.5	22.5
एनईटीसी	13.0	9.8	10.2	14.8	18.6	13.3	15.5	19.0
बीबीपीएस	25.7	95.4	24.6	97.4	77.4	260.0	75.4	276.4

नोट: आरटीजीएस: तत्काल सकल निपटान; **एनईएफटी:** राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण; **यूपीआई:** एकीकृत भुगतान इंटरफेस; **आईएमपीएस:** तत्काल भुगतान सेवा; **एनएसीएच:** राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह; **एनईटीसी:** राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह; और **बीबीपीएस:** भारत बिल भुगतान प्रणाली।
स्रोत: आरबीआई।

ने भुगतान मोड में व्यापक संवृद्धि गति को बनाए रखा, यद्यपि खुदरा भुगतान खंडों में वृद्धि में कुछ मंदी आई (सारणी IV.3)।

जनवरी 2025 के दौरान लेन-देन की मात्रा (विप्रेषक बैंक की ओर से) में पीएसबी की हिस्सेदारी में एक वर्ष पहले दर्ज स्तरों की तुलना में वृद्धि हुई (चार्ट IV.27ए)। जनवरी 2024[27] की तुलना में जनवरी 2025 में अधिकांश बैंक श्रेणियों में प्रति 10,000 यूपीआई लेन-देन में तकनीकी अस्वीकरण[26] की संख्या कम हो गई, जो उच्च लेन-देन मात्रा के बावजूद बैंकों की प्रणालियों की बढ़ी हुई दक्षता को दर्शाती है। हालाँकि, बैंक समूहों में निष्पादन असमान रहा (चार्ट IV.27बी)।

चार्ट IV.27: यूपीआई लेनदेन में रुझान - बैंक समूहवार

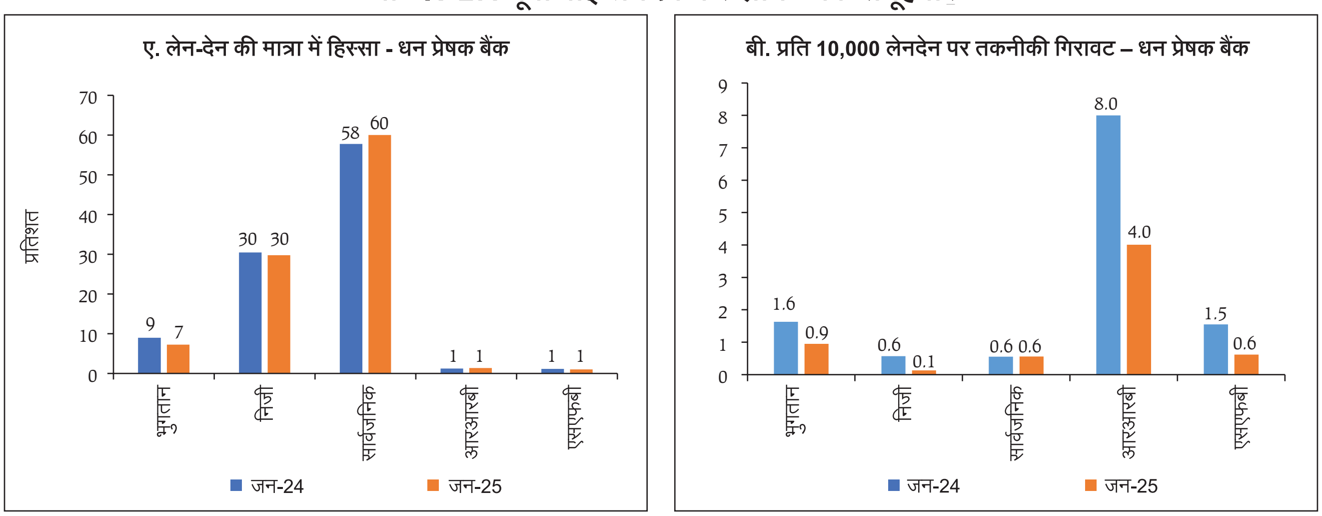

टिप्पणी: सार्वजनिक: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक; **निजी** -निजी क्षेत्र के बैंक; **एसएफबी**: लघु वित्त बैंक: **आरआरबी**: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक: **भुगतान**: भुगतान बैंक। आंकड़े भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) द्वारा शीर्ष 50 सदस्यों के लिए रिपोर्ट किए गए लेनदेन की मात्रा पर आधारित हैं।
स्रोत: एनपीसीआई; और आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

[26] तकनीकी कारणों से लेनदेन पूरा नहीं हो पाना, जैसे बैंक या एनपीसीआई की ओर से प्रणाली की अनुपलब्धता और नेटवर्क संबंधी समस्याएं।

[27] विप्रेषक बैंकों के रूप में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए, तकनीकी अस्वीकरण (टीडी) दर 0.55 से मामूली रूप से बढ़कर 0.56 हो गई। लाभार्थी बैंकों के रूप में भुगतान बैंकों के लिए, टीडी दर 0.12 से बढ़कर 0.81 हो गई।

कार्ड टोकनाइजेशन और इसका उपयोग बढ़ रहा है, 98 प्रतिशत ई-कॉमर्स लेनदेन वास्तविक कार्ड डेटा का उपयोग किए बिना संसाधित किए जा रहे हैं।[28] रिज़र्व बैंक ने 7 फरवरी 2025 के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर अपने वक्तव्य में, भारत में जारी किए गए कार्डों का उपयोग करके ऑनलाइन अंतरराष्ट्रीय लेनदेन के लिए सुरक्षा का एक अतिरिक्त स्तर प्रदान करने के लिए अंतरराष्ट्रीय कार्ड नॉट प्रेजेंट (ऑनलाइन) लेनदेन के लिए प्रमाणीकरण का अतिरिक्त कारक (एएफए) सक्षम करने का प्रस्ताव रखा है।[29] भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) भारतीय बैंकों के लिए 'bank.in' विशिष्ट इंटरनेट डोमेन भी शुरू कर रहा है ताकि साइबर सुरक्षा खतरों और फ़िशिंग जैसी द्वेषपूर्ण गतिविधियों को कम किया जा सके, और सुरक्षित वित्तीय सेवाओं को सुव्यवस्थित किया जा सके। ऑनलाइन और अन्य धोखाधड़ी को रोकने के लिए, रिज़र्व बैंक ने अपने विनियमित निकायों के लिए विनियामक निर्देश और संस्थागत सुरक्षा उपाय जारी किए हैं, जिनमें मोबाइल नंबर निरस्तीकरण सूची का उपयोग, मानक परिचालन प्रक्रियाओं का विकास तथा लेन-देन और प्रचार कॉल के लिए समर्पित नंबरिंग शृंखला शामिल हैं।[30] रिज़र्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत मौद्रिक दंड लगाने और अपराधों को कम करने के लिए रूपरेखा के तहत अनुदेशों में संशोधन करने का भी निर्णय लिया है।[31] 31 जनवरी 2025 तक, दो निकायों ने जनवरी 2025 में विनियामक सैंडबॉक्स के 'खुदरा भुगतान' विषय के लिए 'ऑन टैप' एप्लिकेशन सुविधा के तहत परीक्षण चरण को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।[32]

V. निष्कर्ष

वैश्विक अर्थव्यवस्था का सन्निकट दृष्टिकोण, अवस्फीति की धीमी गति के बीच, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की व्यापार-संबंधी नीतियों द्वारा आकार ले रहा है। ऐसी चिंताएँ हैं कि ये नीतियाँ मुद्रास्फीति को बढ़ावा दे सकती हैं, वित्तीय स्थितियाँ सख्त कर सकती हैं और बाज़ार में उथल-पुथल बढ़ा सकती हैं। यूएस आर्थिक समुत्थानशीलता और व्यापार नीति धुरी द्वारा संचालित एक मज़बूत डॉलर, उभरती अर्थव्यवस्थाओं से पूंजी बहिर्वाह को बढ़ा सकता है, जोखिम प्रीमियम में वृद्धि कर सकता है और बाह्य कमजोरियों को बढ़ा सकता है। ऐसे माहौल में अवस्फीति का "अंतिम लक्ष्य" अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है, जिसके लिए संभावित रूप से केंद्रीय बैंकों को नीतियों को पुनः समायोजित करने की आवश्यकता होगी।

भारत में, आर्थिक गतिविधि की गति बनी रहने की संभावना है, कृषि क्षेत्र के मजबूत निष्पादन से ग्रामीण मांग को और बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। शहरी मांग में भी सुधार होने की संभावना है, मुद्रास्फीति में गिरावट के साथ-साथ केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित आय कर में बड़ी छूट से प्रयोज्य आय में वृद्धि होगी। संवृद्धि के चार इंजनों - कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात - को बढ़ावा देने के लिए बजट उपायों से भारतीय अर्थव्यवस्था की मध्यमावधि संवृद्धि संभावनाओं को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। केंद्रीय बजट ने पूंजीगत व्यय पर निरंतर ध्यान केंद्रित करके राजकोषीय सुदृढ़ता और संवृद्धि उद्देश्यों को संतुलित किया है, साथ ही कर्ज समेकन के लिए एक स्पष्ट रोडमैप प्रदान करते हुए उपभोग को बढ़ावा देने के उपायों पर भी ध्यान दिया है। 7 फरवरी 2025 को अपनी बैठक में एमपीसी द्वारा रेपो दर में कटौती से घरेलू मांग को भी लाभ मिलने की उम्मीद है।

बहुतायत में खरीफ उत्पादन और बेहतर रबी बुवाई, साथ ही उच्च जलाशय स्तर और सब्जियों की कीमतों में मौसमी सर्दियों में सुधार, भविष्य में खाद्य मुद्रास्फीति के लिए शुभ संकेत हैं। जबकि मूल मुद्रास्फीति में कमी बनी हुई है, वैश्विक वित्तीय बाजारों में अनिश्चितता, ऊर्जा कीमतों में अस्थिरता और प्रतिकूल मौसम की घटनाएं मुद्रास्फीति के दिशा-पथ के लिए जोखिम उत्पन्न करती हैं।[33]

[28] आरबीआई, 2025। *भुगतान प्रणाली रिपोर्ट, दिसंबर 2024।*

[29] आरबीआई प्रेस प्रकाशनियाँ, 07 फरवरी 2025।

[30] आरबीआई अधिसूचनाएँ। 17 जनवरी 2025। *वॉयस कॉल और एसएमएस का उपयोग करके वित्तीय धोखाधड़ी की रोकथाम - विनियामक निर्देश और संस्थागत सुरक्षा उपाय।*

[31] आरबीआई अधिसूचनाएँ। 30 जनवरी 2025। *भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत मौद्रिक दंड अधिरोपित करने और अपराधों की कंपाउंडिंग करने के लिए फ्रेमवर्क।*

[32] आरबीआई प्रेस प्रकाशनी। 29 जनवरी 2025। *विनियामक सैंडबॉक्स: 'खुदरा भुगतान' विषय पर ऑन टैप एप्लिकेशन - परीक्षण चरण का समापन।*

[33] मौद्रिक नीति वक्तव्य 2024-25, मौद्रिक नीति समिति का संकल्प, 5-7 फरवरी 2025।

अनुबंध I

आरबीआई के उद्यम सर्वेक्षण से प्राप्त प्रमुख निष्कर्ष

विनिर्माण क्षेत्र में क्षमता उपयोग (सीयू) पिछली तिमाही के 74.0 प्रतिशत से मामूली रूप से बढ़कर 2024-25 की दूसरी तिमाही में 74.2 प्रतिशत हो गया। हालांकि, मौसमी रूप से समायोजित सीयू पिछली तिमाही से 110 आधार अंकों की गिरावट के साथ 74.7 प्रतिशत पर आ गया। विनिर्माताओं ने आगामी तिमाहियों में सीयू पर सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखा (चार्ट ए1 और ए2)।

चार्ट ए1: विनिर्माण क्षेत्र में क्षमता उपयोग

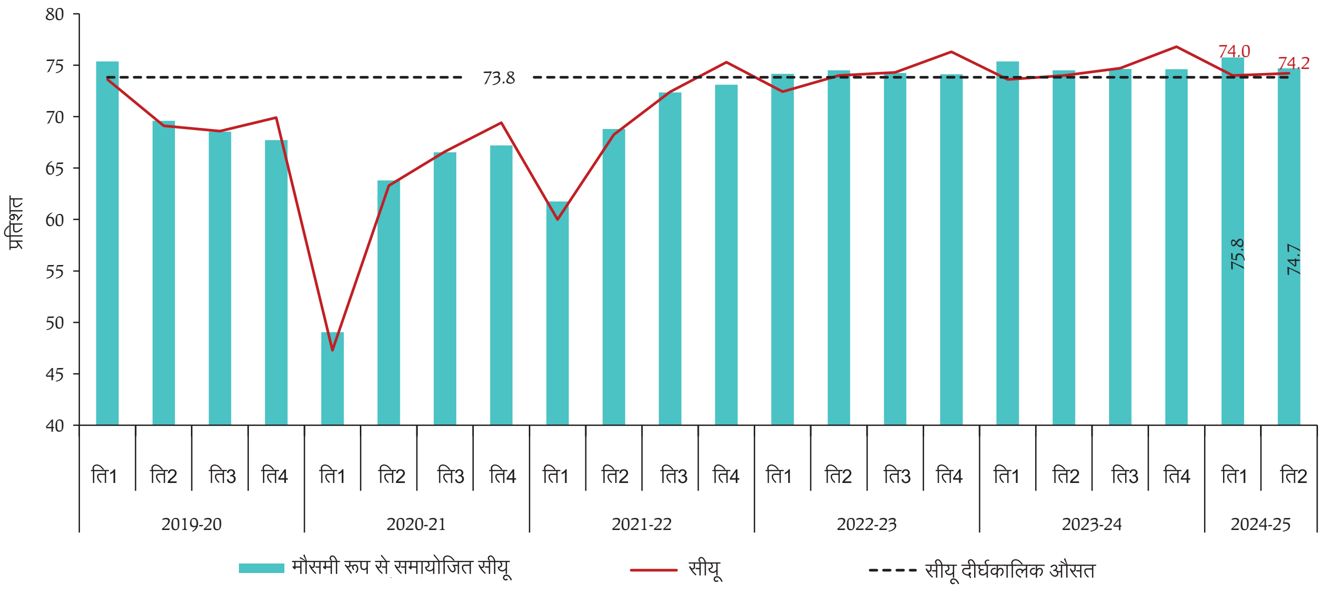

स्रोत: ऑर्डर बुक्स, इनवेंटरी और क्षमता उपयोग सर्वेक्षण, आरबीआई।

चार्ट ए2: क्षमता उपयोग पर निर्माताओं का मूल्यांकन और अपेक्षाएँ

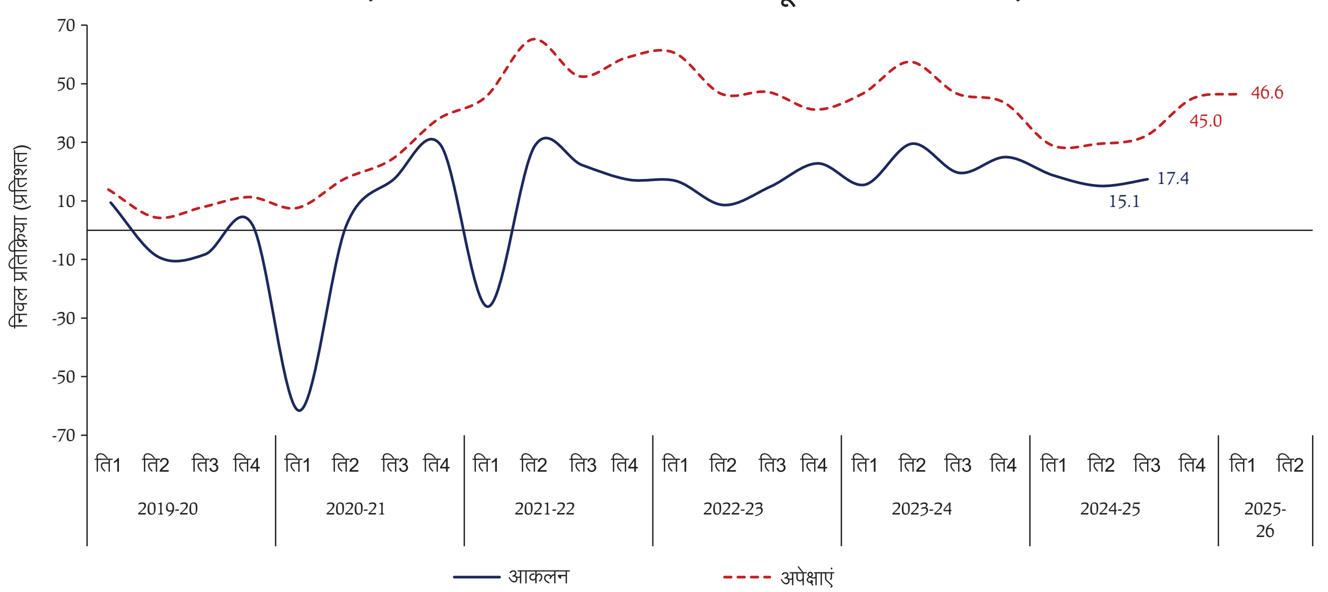

स्रोत: औद्योगिक परिदृश्य सर्वेक्षण, आरबीआई।

सभी प्रमुख क्षेत्र 2025-26 की दूसरी तिमाही तक उत्पादन/कारोबार और समग्र कारोबार स्थिति के बारे में आशावादी बने रहे (चार्ट ए3 और ए4)। रोज़गार की स्थिति मांग की स्थिति के अनुरूप है (चार्ट ए5)।

चार्ट ए3: विनिर्माण /टर्नओवर पर अपेक्षाएँ

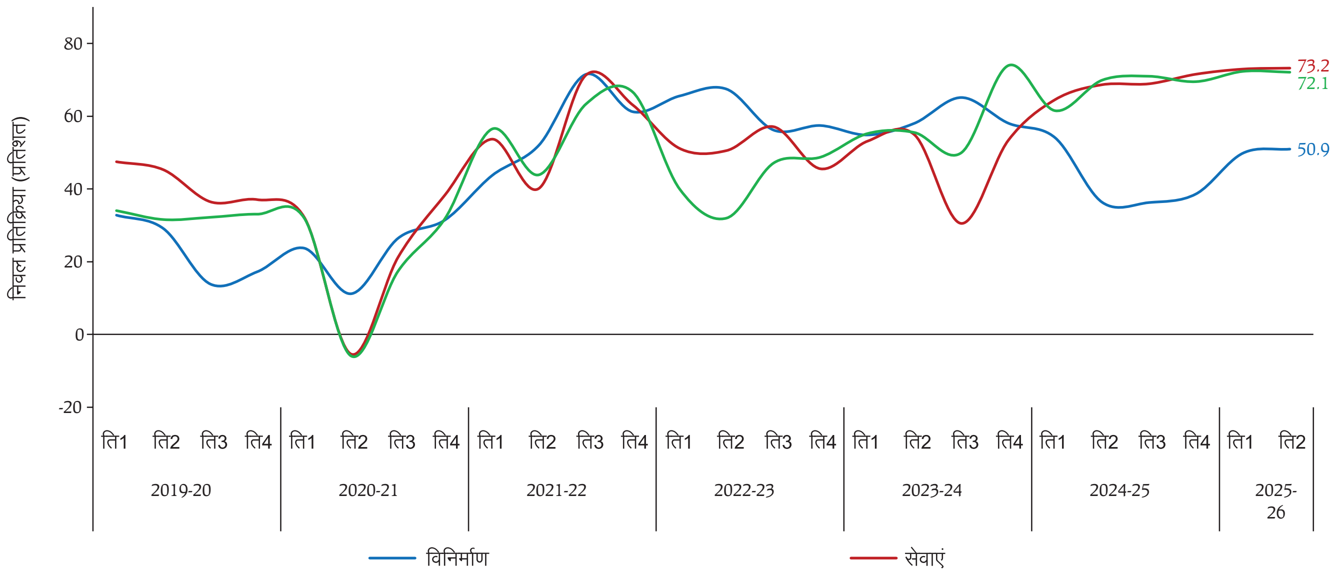

स्रोत: औद्योगिक परिदृश्य सर्वेक्षण; तथा सेवा एवं अवसंरचना परिदृश्य सर्वेक्षण, आरबीआई।

चार्ट ए4: समग्र व्यावसायिक स्थिति पर अपेक्षाएँ

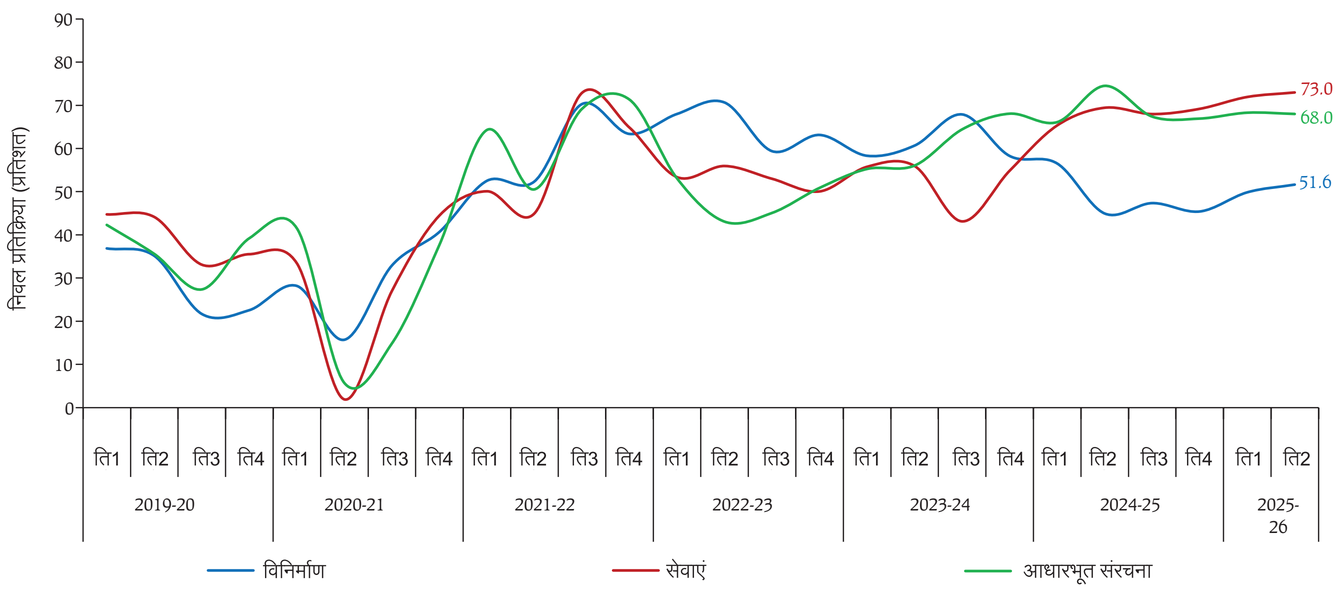

स्रोत: औद्योगिक परिदृश्य सर्वेक्षण; तथा सेवा एवं अवसंरचना परिदृश्य सर्वेक्षण, आरबीआई।

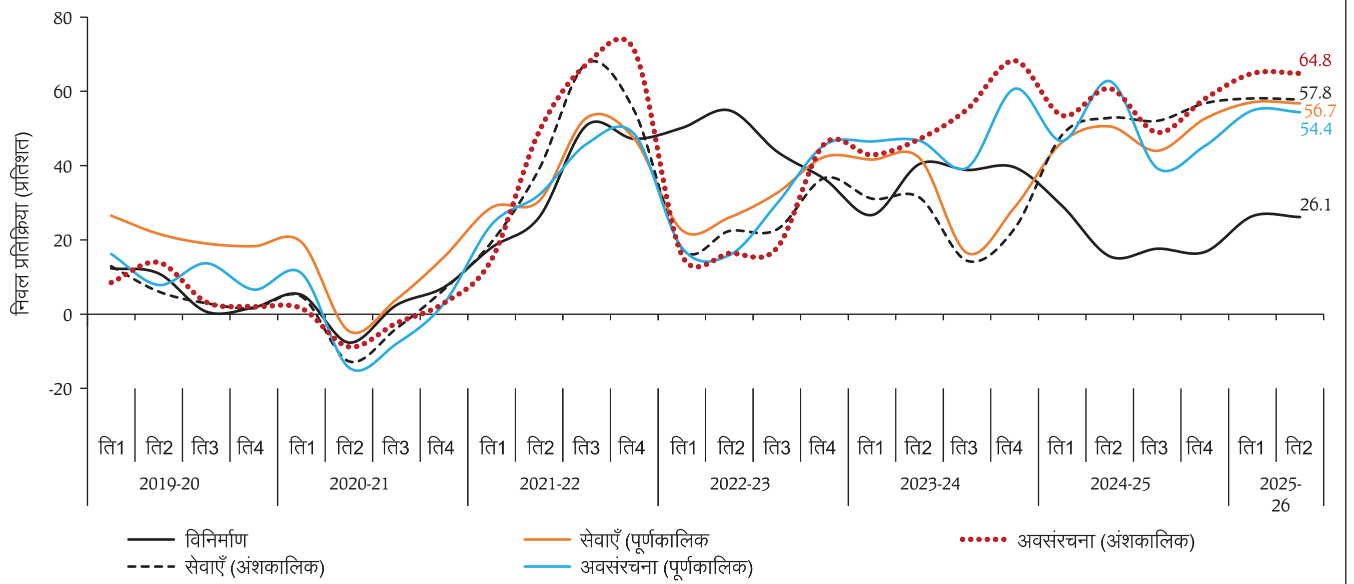

स्रोत: औद्योगिक आउटलुक सर्वेक्षण: और सेवा एवं अवसंरचना आउटलुक सर्वेक्षण। आरबीआई।

प्रमुख क्षेत्रों में उच्च इनपुट लागत का दबाव बने रहने की संभावना है (चार्ट ए6)।

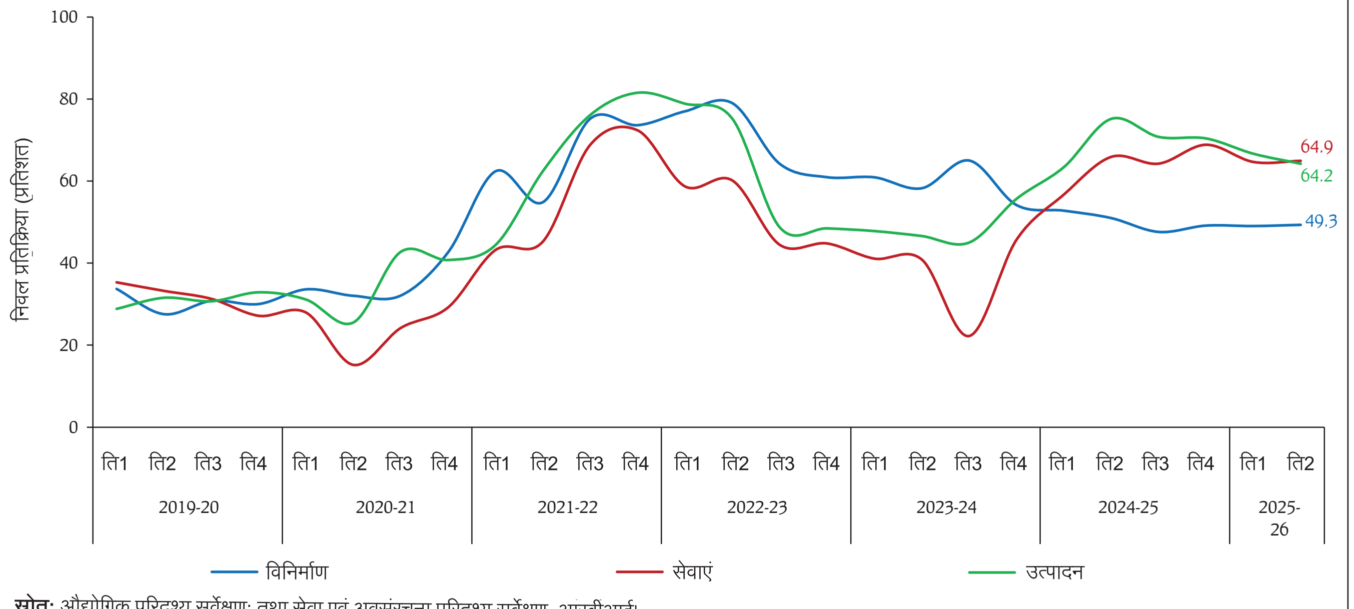

स्रोत: औद्योगिक परिदृश्य सर्वेक्षण; तथा सेवा एवं अवसंरचना परिदृश्य सर्वेक्षण, आरबीआई।

वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही में विनिर्माण क्षेत्र के लिए बिक्री मूल्य और लाभ मार्जिन में वृद्धि की गति धीमी होने की उम्मीद है। 2024-25 की चौथी तिमाही में सेवा और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र के लिए बिक्री कीमत और लाभ मार्जिन में उच्च वृद्धि की उम्मीद है (चार्ट ए7)।

चार्ट ए7: विक्रय मूल्य पर अपेक्षाएँ

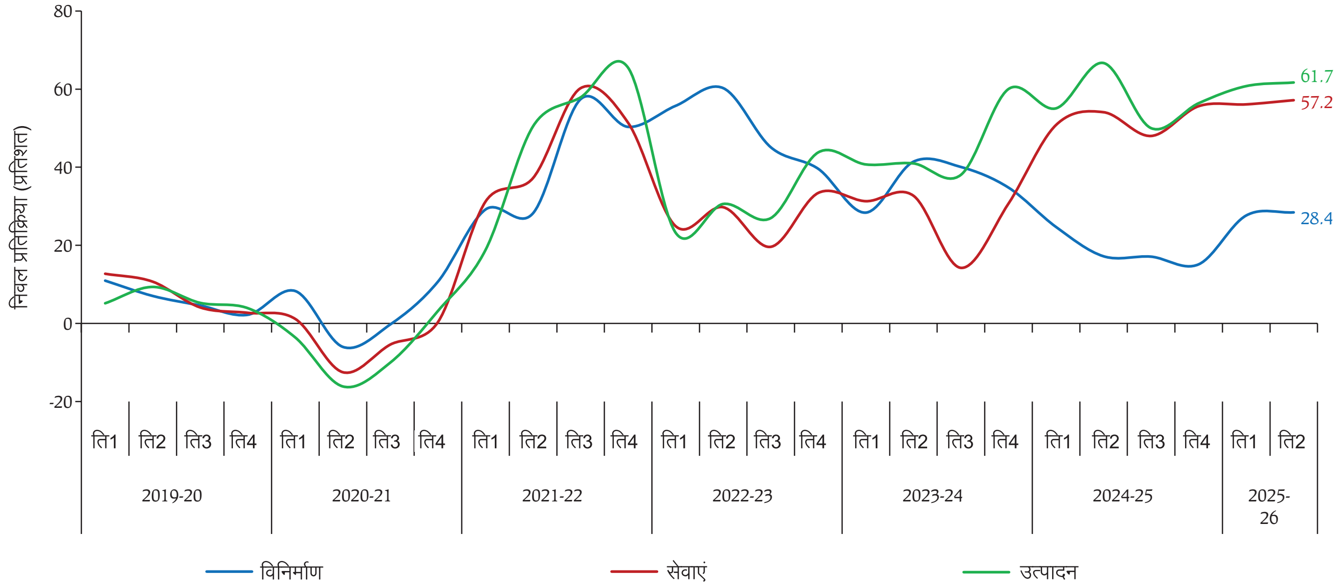

स्रोत: औद्योगिक परिदृश्य सर्वेक्षण; तथा सेवा एवं अवसंरचना परिदृश्य सर्वेक्षण, आरबीआई।

बैंकरों को उम्मीद है कि ऋण की मांग बढ़ेगी तथा प्रमुख क्षेत्रों में ऋण की शर्तें आसान होंगी (चार्ट ए8)।

चार्ट ए8: ऋण मांग पर वरिष्ठ ऋण अधिकारियों का आकलन और अपेक्षाएँ

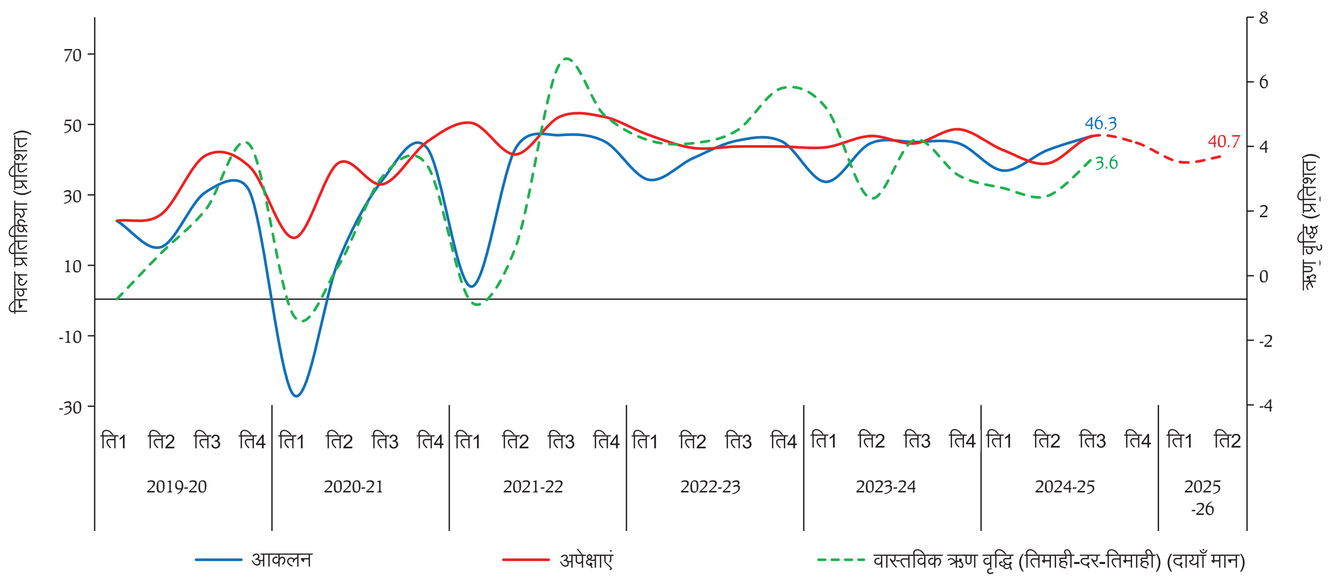

स्रोत: बैंक ऋण सर्वेक्षण, आरबीआई।

टिप्पणी: 'निवल प्रतिक्रिया' की गणना आशावाद की रिपोर्ट करने वाले और निराशावाद की रिपोर्ट करने वाले उत्तरदाताओं के प्रतिशत के बीच के अंतर के रूप में की जाती है। वृद्धि विकल्प (I) सभी मापदंडों के लिए एक आशावादी प्रतिक्रिया है, जो लागत से संबंधित मापदंडों को छोड़कर, जैसे कि कच्चे माल की लागत, आदि जहाँ कमी विकल्प (D) उत्तरदाता कंपनी के दृष्टिकोण से आशावाद को दर्शाता है।

केंद्रीय बजट 2025-26: एक आकलन

आकाश राज, हर्षिता यादव, कोवुरी आकाश यादव, आयुषी खंडेलवाल, अनूप के सुरेश और समीर रंजन बेहरा द्वारा^

केंद्रीय बजट 2025-26 'विकसित भारत' के दृष्टिकोण के अनुरूप समावेशी, दीर्घकालिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हुए राजकोषीय अनुशासन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। बजट में विकास के चार इंजनों - कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात के तहत कई उपायों की घोषणा की गई। सरकार ने खपत को समर्थन देने के उपायों के साथ-साथ पूंजीगत व्यय पर अपना ध्यान केंद्रित करना जारी रखा। सकल घरेलू उत्पाद के 4.4 प्रतिशत के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य के साथ, बजट ने राजकोषीय समेकन और विकास उद्देश्यों को विवेकपूर्ण तरीके से संतुलित किया है।

परिचय

केंद्रीय बजट 2025-26 विकास को गति देने, समावेशी विकास को सुरक्षित करने, निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देने, घरेलू भावनाओं को ऊपर उठाने और भारत के उभरते मध्यम वर्ग की खर्च करने की शक्ति को बढ़ाने पर केंद्रित है। चार प्रमुख चालक - कृषि, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई), निवेश और निर्यात - विकास को गति देने के लिए परिकल्पित हैं, जिसमें नवाचार और सुधार महत्वपूर्ण उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। बजट तत्काल सामाजिक-आर्थिक राहत और दीर्घकालिक संरचनात्मक परिवर्तन पर संतुलित ध्यान केंद्रित करता है। यह कृषि उत्पादकता और ग्रामीण समृद्धि से लेकर शहरी बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने तक दस विषयगत क्षेत्रों में लक्षित उपायों की तैनाती को रेखांकित करता है। बजट छह डोमेन - कराधान, बिजली, शहरी विकास, खनन, वित्तीय क्षेत्र और नियामक ढांचे - में सुधार के एजेंडे को स्पष्ट करता है ताकि समग्र कारक उत्पादकता को बढ़ाया जा सके और अर्थव्यवस्था में संसाधनों का अधिक कुशल आवंटन सुनिश्चित किया जा सके।

प्रत्यक्ष कर के मोर्चे पर, बजट में मध्यम वर्ग के करदाताओं पर केंद्रित ₹1 लाख करोड़ की कर राहत का प्रस्ताव है, जिससे घरेलू प्रयोज्य आय में वृद्धि होने तथा उपभोग, बचत और निवेश को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। अप्रत्यक्ष कराधान के क्षेत्र में, संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ सरलीकरण को लक्षित करते हैं तथा शुल्क व्युत्क्रमण को संबोधित करते हैं।

व्यय पक्ष पर, बजट 2025-26 में पूंजीगत व्यय के लिए ₹11.2 लाख करोड़ (जीडीपी का 3.1 प्रतिशत) निर्धारित किया गया है, जो पिछले वित्तीय वर्षों में देखी गई गति को जारी रखता है। इसी तरह, प्रभावी पूंजीगत व्यय को 2024-25 (संशोधित अनुमान) में जीडीपी के 4.1 प्रतिशत से बढ़ाकर 2025-26 में जीडीपी का 4.3 प्रतिशत करने का बजट बनाया गया है। राजस्व व्यय 2024-25 (संशोधित अनुमान) में जीडीपी के 11.4 प्रतिशत से घटकर 2025-26 (बजट अनुमान) में 11.0 प्रतिशत होने का अनुमान है। राज्य सरकारों को अपने स्वयं के पूंजीगत व्यय को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, 'पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को ऋण के रूप में विशेष सहायता' को ₹1.5 लाख करोड़ के प्रावधान के साथ बढ़ाया गया है।

केंद्रीय बजट 2025-26 (बीई) में सकल राजकोषीय घाटे (जीएफडी) को जीडीपी के 4.4 प्रतिशत पर लक्षित करके विकास की अनिवार्यताओं को राजकोषीय विवेक के साथ संतुलित करता है, जो 2024-25 में संशोधित अनुमान (आरई) 4.8 प्रतिशत से कम है, जो 2025-26 तक जीएफडी को जीडीपी के 4.5 प्रतिशत से नीचे लाने के अपने उद्देश्य पर कायम है। 2026-27 से आगे, सरकार का लक्ष्य राजकोषीय घाटे को उस प्रक्षेपवक्र पर बनाए रखना है जो सार्वजनिक ऋण-जीडीपी अनुपात में गिरावट सुनिश्चित करता है, जो मार्च 2031 तक लगभग 50 प्रतिशत तक पहुंच जाता है।

इस पृष्ठभूमि में, लेख का शेष भाग आठ खंडों में विभाजित है। खंड II में राजकोषीय घाटे के अंतर्निहित कारकों की चर्चा है, इसके बाद खंड III और IV में क्रमशः राजस्व और व्यय प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया गया है। खंड V में सरकार की बकाया ऋण स्थिति की रूपरेखा दी गई है, जबकि खंड VI में राजकोषीय घाटे

^ इस लेख को तैयार करने में उनके समग्र मार्गदर्शन के लिए लेखक श्रीमती रेखा मिश्र के आभारी हैं। लेखक भारतीय रिज़र्व बैंक के आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग से हैं। इस लेख में व्यक्त किए गए विचार लेखकों के हैं और ज़रूरी नहीं कि वे भारतीय रिज़र्व बैंक के विचारों का प्रतिनिधित्व करते हों।

के वित्तपोषण के प्रमुख स्रोतों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। खंड VII में राज्यों को संसाधनों के हस्तांतरण की जांच की गई है, जबकि खंड VIII में अंतिम टिप्पणियां प्रस्तुत की गई हैं।

II. राजकोषीय घाटा - अंतर्निहित गतिशीलता

2024-25 के लिए सकल घरेलू उत्पाद के 4.9 प्रतिशत के बजटीय जीएफडी के मुकाबले संशोधित अनुमान 4.8 प्रतिशत रखा गया है। 10 आधार अंकों का समेकन मुख्य रूप से बजटीय पूंजीगत व्यय से कम होने के कारण है (चार्ट 1)।

2025-26 (बजट अनुमान) के लिए जीएफडी जीडीपी के 4.4 प्रतिशत पर निर्धारित किया गया है।[1] 2025-26 (बजट अनुमान) बनाम 2024-25 (संशोधित अनुमान) के लिए 45 आधार अंकों के परिकल्पित समेकन को राजस्व व्यय को जीडीपी के 11.0 प्रतिशत [2024-25 (संशोधित अनुमान) में 11.4 प्रतिशत से] पर सीमित करके और पूंजीगत व्यय को जीडीपी के 3.1 प्रतिशत पर बनाए रखकर प्राप्त करने का प्रयास किया गया है, जबकि सकल कर राजस्व को जीडीपी के 12.0 प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है (2024-25 के लिए संशोधित अनुमान में जीडीपी के 11.9 प्रतिशत से) [सारणी 1]। राजस्व व्यय-पूंजीगत परिव्यय (आरई-सीओ) अनुपात-व्यय की गुणवत्ता का एक सारांश संकेतक -

चार्ट 1: राजकोषीय लक्ष्य प्राप्ति में योगदान 2025-26 (बजट अनुमान) में 4.4 पर बरकरार रखा गया है

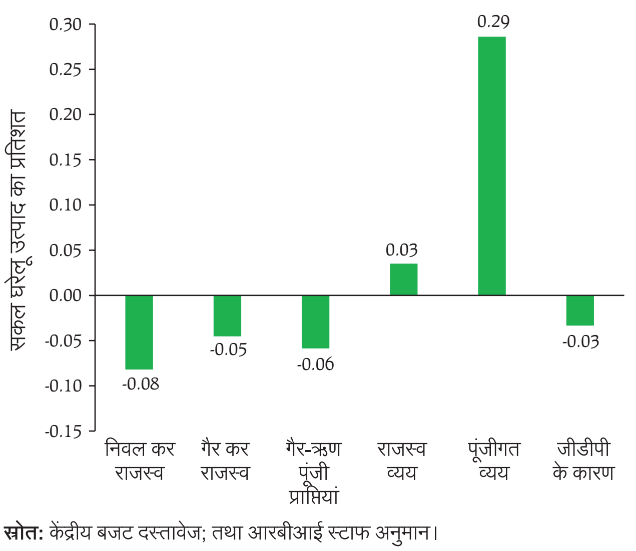

स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज; तथा आरबीआई स्टाफ अनुमान।

सारणी 1: प्रमुख राजकोषीय संकेतक[2]

(जीडीपी का प्रतिशत)

मद	2023-24	2024-25		2025-26
	वास्तविक	बीई	आरई	बीई
1	2	3	4	5
1. राजकोषीय घाटा	5.6	4.9	4.8	4.4
2. प्राथमिक घाटा	2.0	1.4	1.3	0.8
3. राजस्व घाटा	2.6	1.8	1.9	1.5
4. प्रभावी राजस्व घाटा	1.6	0.6	1.0	0.3
5. सकल कर राजस्व	11.7	11.8	11.9	12.0
6. गैर-कर राजस्व	1.4	1.7	1.6	1.6
7. राजस्व व्यय	11.8	11.4	11.4	11.0
8. पूंजीगत व्यय	3.2	3.4	3.1	3.1
जिसका कि:				
(i) पूंजीगत परिव्यय	2.7	2.8	2.6	2.5
9. प्रभावी पूंजीगत व्यय	4.2	4.6	4.1	4.3
10. ऋण	58.7	56.8	57.1	56.0

टिप्पणी: 1. प्रभावी राजस्व घाटा राजस्व घाटे और पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए अनुदान सहायता के बीच का अंतर है।
2. पूंजीगत परिव्यय पूंजीगत व्यय में से ऋण और अग्रिम राशि घटाई जाती है।
3. प्रभावी पूंजीगत व्यय पूंजीगत व्यय और पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए अनुदान सहायता का योग होता है।
4. बीई का अर्थ बजट अनुमान है, आरई का अर्थ संशोधित अनुमान है।

स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

जीएफडी का अपघटन

राजस्व घाटे (आरडी) द्वारा विनियोजित जीएफडी का हिस्सा 2018-19 से 2023-24 के दौरान औसतन लगभग 65.7 प्रतिशत से घटकर 2024-25 (संशोधित अनुमान) में 38.9 प्रतिशत रह गया, जिसे 2025-26 में और भी कम करके 33.4 प्रतिशत करने का बजट है। इसके साथ ही, जीएफडी में वृद्धि-प्रेरक पूंजीगत व्यय का हिस्सा 2024-25 (संशोधित अनुमान) में बढ़कर 54.0 प्रतिशत हो गया है और 2025-26 (बजट अनुमान) में 57.1 प्रतिशत तक पहुंचने की उम्मीद है, जो 2018-19 से 2023-24 के दौरान औसतन लगभग 35.2 प्रतिशत था (चार्ट 2)।

III. प्राप्तियां

कुल गैर-ऋण प्राप्तियों में 2024-25 (संशोधित अनुमान) में 12.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई और यह सकल घरेलू उत्पाद का 9.7 प्रतिशत रहा। कर राजस्व में मजबूत वृद्धि, रिजर्व बैंक से उच्च अधिशेष हस्तांतरण और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थानों से बेहतर लाभांश आय ने 2023-24 की तुलना में 2024-25 (संशोधित अनुमान) में प्राप्तियों के बेहतर प्रदर्शन को समर्थन दिया। 2025-26 (बजट अनुमान) के लिए, सरकार को उम्मीद है कि गैर-ऋण प्राप्तियां अपनी गति बनाए रखेंगी, जो

[1] केंद्रीय बजट में 2025-26 के लिए सकल घरेलू उत्पाद 356,97,923 करोड़ रुपये रहने का अनुमान लगाया गया है, जो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा 7 जनवरी, 2025 को जारी 2024-25 के प्रथम अग्रिम अनुमान (एफएई) 324,11,406 करोड़ रुपये से 10.1 प्रतिशत अधिक है।

[2] विस्तृत जानकारी के लिए कृपया अनुलग्नक देखें।

चार्ट 2: सकल राजकोषीय घाटे का विघटन

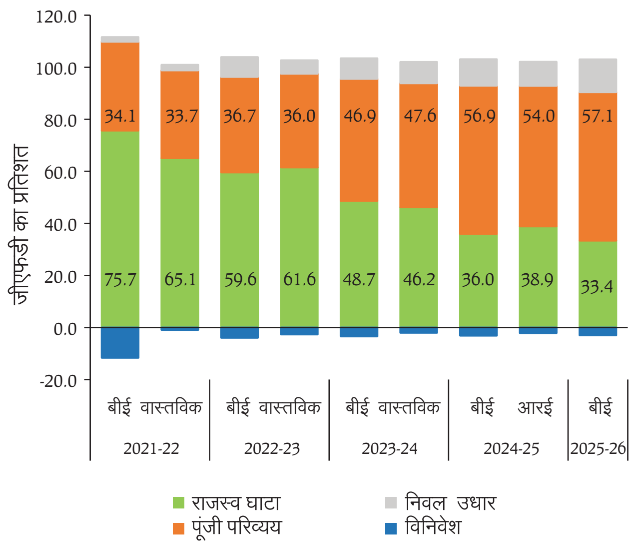

स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज।

2024-25 (संशोधित अनुमान) में सकल घरेलू उत्पाद के 9.7 प्रतिशत से बढ़कर 2025-26 (बजट अनुमान) में सकल घरेलू उत्पाद के 9.8 प्रतिशत तक पहुंच जाएगी। 2025-26 में सकल कर राजस्व में 10.8 प्रतिशत की वृद्धि का बजट है, साथ ही गैर-कर राजस्व में 9.8 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है। राज्यों को 2024-25 (संशोधित अनुमान) की तुलना में 10.5 प्रतिशत की वृद्धि के साथ, 2025-26 (बजट अनुमान) में शुद्ध कर राजस्व में 11.0 प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद है।

कर राजस्व

आयकर और जीएसटी संग्रह के कारण सकल कर राजस्व में 2023-24 की तुलना में 2024-25 (संशोधित अनुमान) में 11.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। 2025-26 के लिए, सरकार ने सकल कर राजस्व में 10.8 प्रतिशत की वृद्धि का बजट बनाया है, जिसमें कर उछाल मोटे तौर पर 2010-11 से 2018-19 के दौरान औसत के अनुरूप बना हुआ है। प्रत्यक्ष करों की उछाल 2025-26 (बजट अनुमान) में 1.25 से कम रखी गई है, जबकि 2024-25 (संशोधित अनुमान) में 1.47 है, जो आयकर राहत को दर्शाता है, जबकि सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क में लाभ के कारण अप्रत्यक्ष करों की उछाल 2024-25 (संशोधित अनुमान) में 0.73 से 2025-26 (बजट अनुमान) में 0.82 तक ठीक होने की उम्मीद है (चार्ट 3ए और बी)।

सकल कर-जीडीपी अनुपात को 2025-26 में 12.0 प्रतिशत तक बढ़ाने का बजट है, जो 2007-08 के बाद सबसे अधिक है (चार्ट 4)। बजट में नई कर व्यवस्था के तहत कर-मुक्त आय सीमा को ₹7 लाख से बढ़ाकर ₹12 लाख कर दिया गया है। इसके अलावा, सभी आय वर्गों में कर स्लैब को संशोधित किया गया है। कर राहत से डिस्पोजेबल आय में वृद्धि होने और घरेलू खपत और निवेश को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। विभिन्न उपायों के कारण कुल राजस्व में प्रत्यक्ष करों में लगभग ₹1 लाख करोड़ और अप्रत्यक्ष करों में ₹2,600 करोड़ का अनुमान है।[3]

चार्ट 3: कर उछाल में रुझान

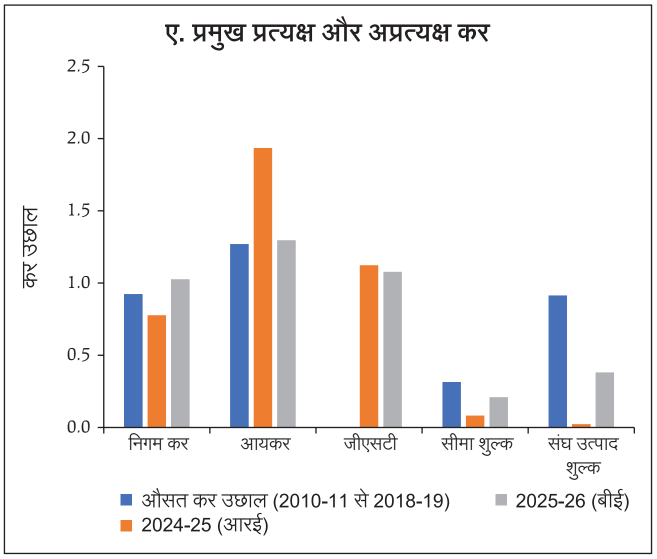

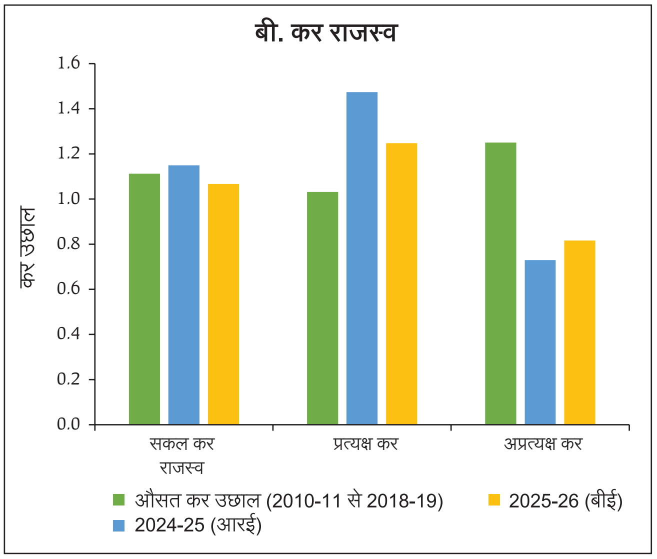

स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज; तथा आरबीआई स्टाफ अनुमान।

[3] जैसा कि वित्त मंत्री के केंद्रीय बजट 2025-26 भाषण में उल्लेख किया गया है।

चार्ट 4: कर-जीडीपी अनुपात

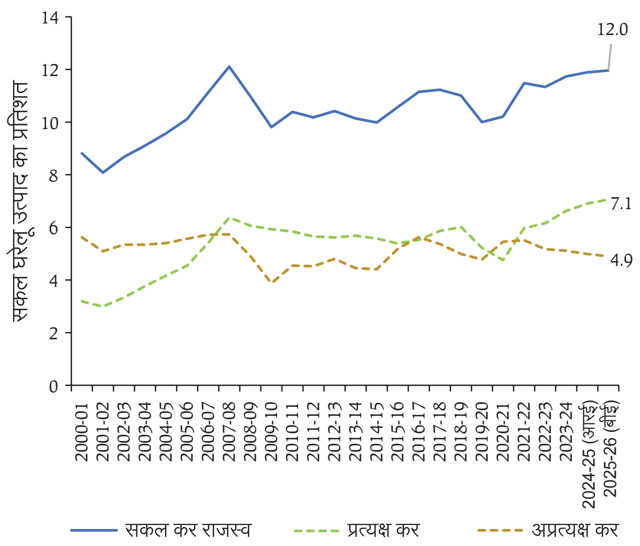

स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज; तथा आरबीआई स्टाफ अनुमान।

चार्ट 5: प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी)

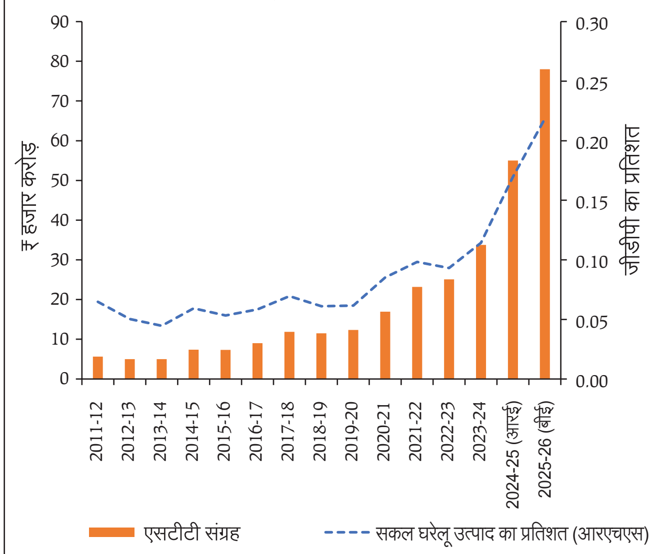

स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज; तथा आरबीआई स्टाफ अनुमान।

प्रत्यक्ष कर

14.4 प्रतिशत की वृद्धि के साथ, 2024-25 (संशोधित अनुमान) में प्रत्यक्ष कर बजट अनुमानों से ₹30,000 करोड़ अधिक हो गए। आयकर राजस्व में 18.8 प्रतिशत की वृद्धि के साथ बजट अनुमान की तुलना में कॉर्पोरेट कर संग्रह में ₹40,000 करोड़ की कमी की भरपाई हुई। 2024-25 (संशोधित अनुमान) के दौरान, प्रतिभूति लेनदेन कर ने अपने बजट अनुमान ₹37,000 करोड़ से 48.6 प्रतिशत बेहतर प्रदर्शन किया; 2025-26 (संशोधित अनुमान) में इसे 41.8 प्रतिशत और बढ़ाने का बजट है [चार्ट 5]।

2025-26 (बीई) के लिए, प्रत्यक्ष कर राजस्व में 12.7 प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद है, जबकि आयकर और कॉर्पोरेट कर में वृद्धि क्रमशः 13.1 प्रतिशत और 10.4 प्रतिशत होगी (चार्ट 6)। बजट में अनुपालन को बढ़ावा देने और कर आधार को व्यापक बनाने के उद्देश्य से विभिन्न सरलीकरण और युक्तिकरण उपायों की घोषणा की गई है।

अप्रत्यक्ष कर

2024-25 (संशोधित अनुमान) में अप्रत्यक्ष कर राजस्व में 7.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई, लेकिन यह बजटीय राशि से कम रहा, मुख्य रूप से केंद्रीय उत्पाद शुल्क में ₹14,000 करोड़ की कमी के कारण।[4] जीएसटी संग्रह बजट अनुमानों के अनुरूप था। 2025-26 (बजट अनुमान) में अप्रत्यक्ष कर संग्रह में वृद्धि 8.3 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जिसमें जीएसटी, सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क संग्रह में वृद्धि क्रमशः 10.9 प्रतिशत, 2.1 प्रतिशत और 3.9 प्रतिशत रहने का अनुमान है (चार्ट 7)।

चार्ट 6: प्रत्यक्ष कर

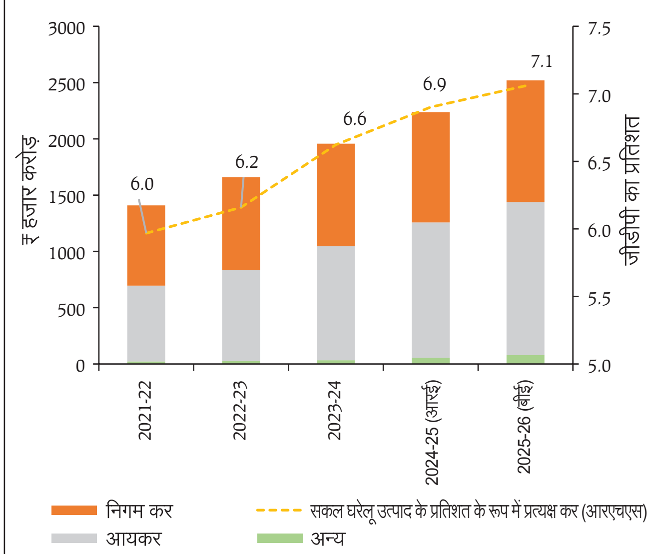

स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज; तथा आरबीआई स्टाफ अनुमान।

[4] केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कमी का कारण विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (एसएईडी) के तहत ₹7,460 करोड़ की कमी थी। जुलाई 2022 में, केंद्र सरकार ने कच्चे तेल के उत्पादन और पेट्रोल, डीजल और विमानन टरबाइन ईंधन के निर्यात पर एसएईडी की शुरुआत की। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, दिसंबर 2024 में इसे रद्द कर दिया गया (स्रोत: केंद्रीय बजट 2025-26; पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ; और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड)।

चार्ट 7: अप्रत्यक्ष कर

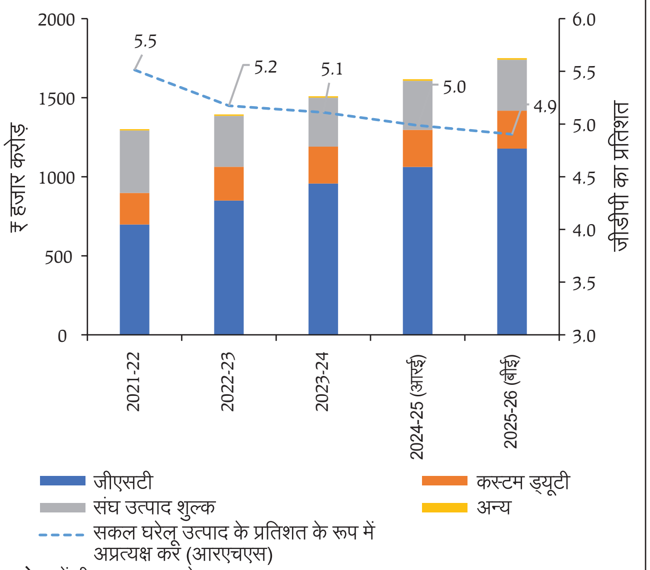

स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज।

गैर-कर राजस्व

रिजर्व बैंक से अधिक अधिशेष हस्तांतरण के समर्थन से, गैर-कर राजस्व ने 2024-25 (संशोधित अनुमान) में 32.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। 2025-26 (बजट अनुमान) के लिए, गैर-कर राजस्व वृद्धि 9.8 प्रतिशत रखी गई है, जिसका नेतृत्व सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (पीएसई) से लाभांश और मुनाफे में 25.5 प्रतिशत की वृद्धि और रिजर्व बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थानों से 9.3 प्रतिशत की वृद्धि द्वारा किया गया है (चार्ट 8)।

गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियां

2024-25 (संशोधित अनुमान) में गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियां बजट अनुमान से ₹19,000 करोड़ कम रहीं, जिसका मुख्य कारण कम विनिवेश प्राप्तियां थीं। 2025-26 (बजट अनुमान) में गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियों में 28.8 प्रतिशत की वृद्धि का बजट है, जिसमें विनिवेश लक्ष्य ₹47,000 करोड़ है (चार्ट 9)।

IV. व्यय

केंद्र सरकार के कुल व्यय में 2024-25 (संशोधित अनुमान) में 6.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, और यह मुख्य रूप से आवंटित पूंजीगत व्यय के कम उपयोग के कारण बजट अनुमान से 1.04 लाख करोड़ रुपये कम था (सारणी 2)। इसके विपरीत, राजस्व व्यय बजट अनुमानों के अनुरूप था और 2024-25 (संशोधित अनुमान) में 5.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। 2025-26 (बजट अनुमान) के लिए कुल व्यय में 7.4 प्रतिशत की वृद्धि का बजट है, जो सकल घरेलू उत्पाद का 14.2 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा। पूंजीगत व्यय में 10.1 प्रतिशत की वृद्धि के साथ सुधार होने की उम्मीद है। इसके अतिरिक्त, पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए अनुदान में 42.4 प्रतिशत की वृद्धि के कारण प्रभावी पूंजीगत व्यय में 2024-25 (संशोधित अनुमान) में 5.2 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 2025-26 में 17.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करने का बजट है। बजट में 2024-25 (बीई) की तरह 2025-26 (बीई) में भी 'पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना' के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपये का आवंटन बरकरार रखा गया है। राजस्व

चार्ट 8: गैर-कर राजस्व के प्रमुख घटक

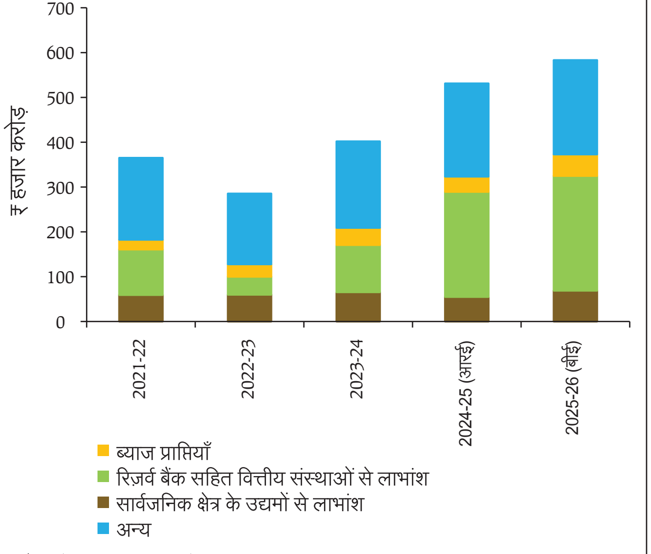

स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज।

चार्ट 9: विनिवेश - वास्तविक *बनाम* बजटीय

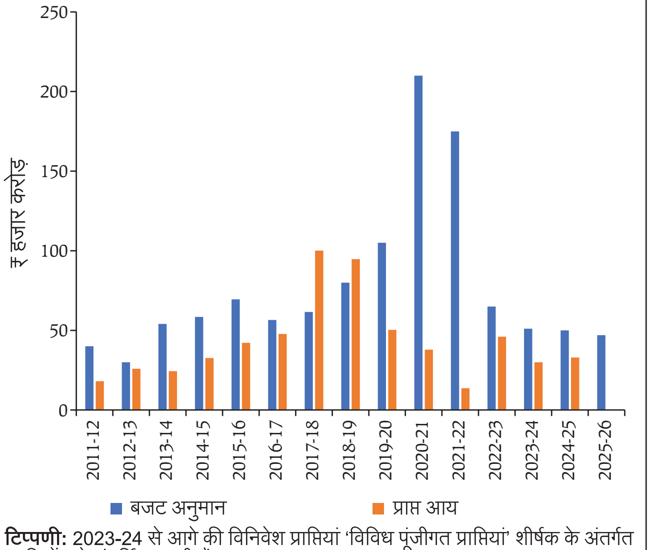

टिप्पणी: 2023-24 से आगे की विनिवेश प्राप्तियां 'विविध पूंजीगत प्राप्तियां' शीर्षक के अंतर्गत 'प्राप्तियों' को संदर्भित करती हैं।
स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज।

सारणी 2: केंद्र सरकार का व्यय

मद	₹ हजार करोड़				सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत				वृद्धि दर (प्रतिशत)		
	2023-24	2024-25 (बीई)	2024-25 (आरई)	2025-26 (बीई)	2023-24	2024-25 (बीई)	2024-25 (आरई)	2025-26 (बीई)	2023-24	2024-25 (आरई)	2025-26 (बीई)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. कुल व्यय	4,443	4,821	4,716	5,065	15.0	14.8	14.6	14.2	6.0	6.1	7.4
2. राजस्व व्यय (आरई) *(जिसका कि)*	3,494	3,709	3,698	3,944	11.8	11.4	11.4	11.0	1.2	5.8	6.7
(i) ब्याज भुगतान (आईपी)	1,064	1,163	1,138	1,276	3.6	3.6	3.5	3.6	14.6	7.0	12.2
(ii) कुल सब्सिडी (टीएस)	435	428	428	426	1.5	1.3	1.3	1.2	-24.7	-1.6	-0.4
जिसका कि:											
खाना	212	205	197	203	0.7	0.6	0.6	0.6	-22.4	-6.8	3.0
उर्वरक	188	164	171	168	0.6	0.5	0.5	0.5	-25.1	-9.0	-2.0
पेट्रोलियम	12	12	15	12	0.0	0.0	0.0	0.0	79.5	20.1	-17.7
(iii) आरई-आईपी-टीएस	1,995	2,118	2,132	2,242	6.8	6.5	6.6	6.3	2.5	6.9	5.1
(v) रक्षा (राजस्व)	303	298	313	328	1.0	0.9	1.0	0.9	12.7	3.3	4.8
3. पूंजीगत व्यय	949	1,111	1,018	1,121	3.2	3.4	3.1	3.1	28.3	7.3	10.1
4. प्रभावी पूंजीगत व्यय	1,253	1,502	1,318	1,548	4.2	4.6	4.1	4.3	19.8	5.2	17.4

स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज।

व्यय में 6.7 प्रतिशत और आरई-आईपी-टीएस में 5.1 प्रतिशत (जीडीपी का 6.3 प्रतिशत) की वृद्धि का बजट रखा गया है।

व्यय की गुणवत्ता

राजस्व व्यय - पूंजीगत परिव्यय (आरई-सीओ) अनुपात 2024-25 (आरई) और 2025-26 (बीई) दोनों में 4.4 पर अपने सबसे निचले स्तर पर रहा। सकल राजकोषीय घाटे (आरडी-जीएफडी) के प्रतिशत के रूप में राजस्व घाटा भी 33.4 प्रतिशत के अपने सर्वकालिक निम्नतम स्तर पर रहा, जो व्यय की गुणवत्ता में सुधार दर्शाता है (चार्ट 10ए और बी)।

पूंजीगत परिव्यय

पूंजीगत व्यय (ऋण और अग्रिम को छोड़कर पूंजीगत व्यय) 2024-25 (संशोधित अनुमान) में 7.6 प्रतिशत बढ़ा। यह बजट लक्ष्य से ₹70,959 करोड़ कम रहा, अन्य बातों के अलावा, आम चुनावों के चलते आदर्श आचार संहिता और मानसून के मौसम में भारी बारिश के कारण। 2025-26 (बजट अनुमान) में पूंजीगत व्यय में 5.6 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है (सारणी 3)। रेलवे, सड़क और पुलों के पूंजीगत व्यय - केंद्र के पूंजीगत व्यय के प्रमुख

चार्ट 10: व्यय की गुणवत्ता

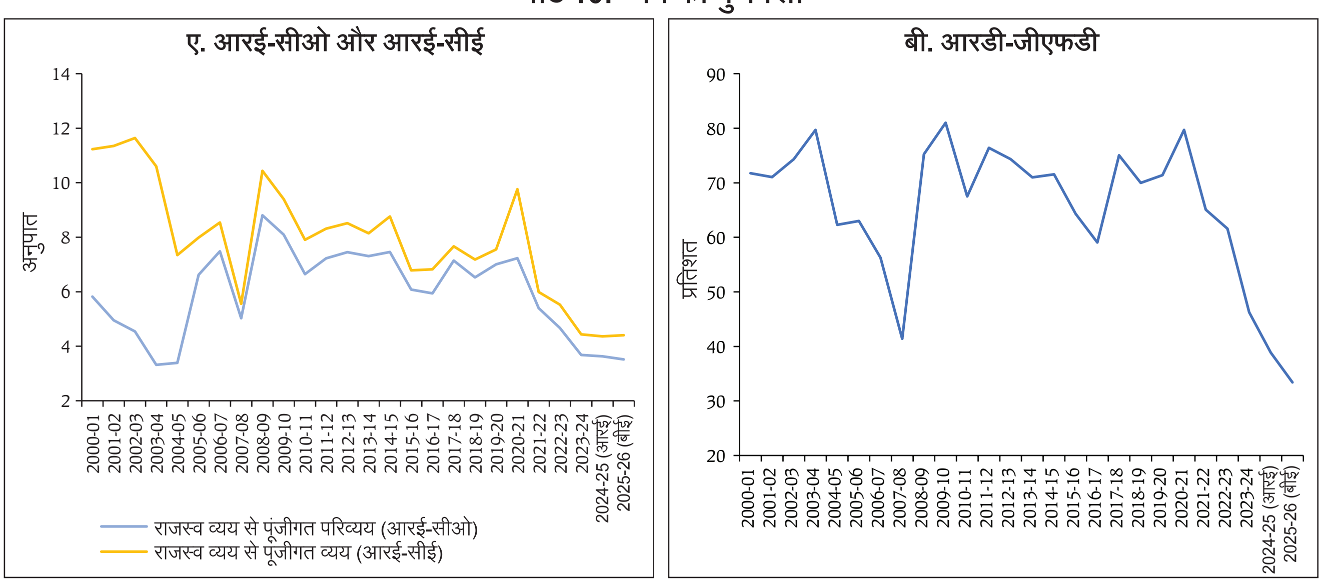

स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज।

सारणी 3: पूंजीगत परिव्यय

मद	₹ हजार करोड़				वृद्धि दर (प्रतिशत)		
	2023-24	2024-25 (बीई)	2024-25 (आरई)	2025-26 (बीई)	2023-24	2024-25 (आरई)	2025-26 (बीई)
1	2	3	4	5	6	7	8
1. कुल पूंजी परिव्यय	788	919	848	895	26.1	7.6	5.6
2. रक्षा सेवाएँ	154	172	160	180	7.9	3.4	12.9
3. पूंजीगत परिव्यय (रक्षा को छोड़कर)	634	747	688	715	31.6	8.6	3.9
(i) प्रमुख बुनियादी ढांचा *(जिनमें से)*	576	600	590	573	34.7	2.4	-2.9
भारतीय रेल	243	252	252	252	52.3	3.9	0.0
सड़कें और पुल	270	259	259	259	28.2	-4.1	0.1
संचार	61	84	75	50	8.8	24.0	-33.1
(ii) उद्योग एवं खनिज	6	6	13	12	-3.6	97.7	-3.1
(iii) विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	7	7	6	8	-8.1	-10.6	27.0
(iv) अन्य	44	133	79	122	11.2	80.0	54.3

स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज।

चालक - को 2025-26 (बजट अनुमान) में उनके 2024-25 (संशोधित अनुमान) स्तरों पर बनाए रखा गया है।

केंद्र सरकार और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का संयुक्त पूंजीगत व्यय

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसई) अपने पूंजीगत व्यय को आंतरिक और अतिरिक्त बजटीय संसाधनों (आईईबीआर) [5] और केंद्र सरकार से बजटीय सहायता के माध्यम से वित्तपोषित करते हैं, जो सरकार के कुल पूंजीगत व्यय का एक हिस्सा है। केंद्र सरकार और सीपीएसई का संयुक्त पूंजीगत व्यय 2024-25 (संशोधित अनुमान) में जीडीपी के 4.2 प्रतिशत से मामूली रूप से बढ़कर 2025-26 (बजट अनुमान) में जीडीपी के 4.3 प्रतिशत हो जाएगा [चार्ट 11]।

प्रमुख सरकारी योजनाएँ

केंद्रीय क्षेत्र के कार्यक्रमों में, पीएमजीकेएवाई को 2025-26 (बजट अनुमान) में कुल व्यय का 4.0 प्रतिशत [2024-25

चार्ट 11: केंद्र सरकार और सीपीएसई द्वारा पूंजीगत व्यय

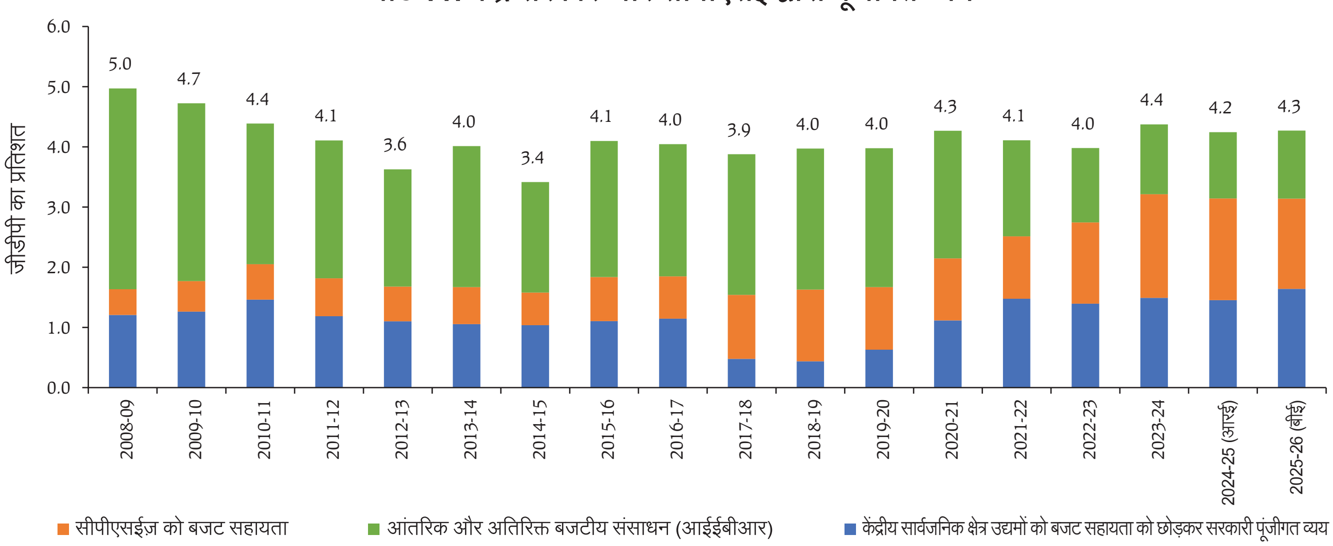

टिप्पणी: सीपीएसई के पूंजीगत व्यय में भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) शामिल नहीं है।
स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज।

[5] आईईबीआर में आंतरिक संसाधन (प्रतिधारित लाभ - सरकार को लाभांश का शुद्ध लाभ, मूल्यह्रास प्रावधान और रिजर्व और अधिशेष को आगे ले जाना) और अतिरिक्त बजटीय संसाधन (बांड, डिबेंचर, बाहरी वाणिज्यिक उधार, आपूर्तिकर्ताओं के ऋण, जमा प्राप्तियां और वित्तीय संस्थानों से सावधि ऋण जारी करने से प्राप्तियां शामिल हैं) शामिल हैं। बजटीय सहायता और आईईबीआर मिलकर सीपीएसई के पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) का वित्तपोषण करते हैं।

सारणी 4: प्रमुख सरकारी योजनाओं पर व्यय

मद	₹ हजार करोड़				कुल व्यय का प्रतिशत			वृद्धि दर (प्रतिशत)		
	2023-24	2024-25 (बीई)	2024-25 (आरई)	2025-26 (बीई)	2023-24	2024-25 (आरई)	2025-26 (बीई)	2023-24	2024-25 (आरई)	2025-26 (बीई)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
क. केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं										
1. पीएम-किसान	61	60	64	64	1.4	1.3	1.3	5.5	3.4	0
2. *प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना* (पीएमजीकेएवाई)	-	205	197	203	-	4.2	4.0	-	-	3.0
3. सड़क निर्माण कार्य	109	115	111	116	2.4	2.3	2.3	43.3	1.7	5.2
बी. केंद्र प्रायोजित योजनाएं										
1. मनरेगा	89	86	86	86	2.0	1.8	1.7	-1.8	-3.5	0.0
2. *जल जीवन* मिशन	70	70	23	67	1.6	0.5	1.3	28.0	-67.6	195.2
3. *समग्र शिक्षा*	33	38	37	41	0.7	0.8	0.8	1.0	12.7	11.5
4. राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम*	25	29	29	30	0.6	0.6	0.6	2.8	15.8	4.3
5. प्रधान मंत्री *आवास योजना*	43	85	48	78	1.0	1.0	1.5	-41.0	9.5	64.1

टिप्पणी: 1. -: उपलब्ध नहीं।
2. *: आरसीएच और स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के लिए लचीला पूल।
स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज।

(संशोधित अनुमान) में 4.2 प्रतिशत] सबसे बड़ा आवंटन प्राप्त हुआ है, जिसमें परिव्यय 3.0 प्रतिशत बढ़कर ₹2.03 लाख करोड़ हो गया है। पीएम-किसान आवंटन पिछले वर्ष के स्तर पर बनाए रखा गया है; और सड़क कार्यों के परिव्यय को 5.2 प्रतिशत बढ़ाकर ₹1.16 लाख करोड़ कर दिया गया है। केंद्र प्रायोजित योजनाओं में, मनरेगा ₹86,000 करोड़ पर अपरिवर्तित है, जल जीवन मिशन का परिव्यय ₹67,000 करोड़ (195.2 प्रतिशत वृद्धि) का बजट है। पीएम आवास योजना के परिव्यय में 64.1 प्रतिशत की वृद्धि की गई है, जिसमें केंद्र ने आवास पर अपना ध्यान केंद्रित रखा है (सारणी 4)।

हाल के वर्षों में, डीबीटी तंत्र के माध्यम से विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों के अंतर्गत लाभार्थियों को सरकार द्वारा धन हस्तांतरण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिसके परिणामस्वरूप सरकार की बचत हुई है (बॉक्स ए)।

बॉक्स ए: भारत में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण – दशकीय अनुभव

भारत में, केंद्र और राज्य सरकारें, दोनों ही कमज़ोर आबादी की सुरक्षा के लिए सामाजिक हस्तांतरण (जैसे, नकद और वस्तु हस्तांतरण) की एक विस्तृत श्रृंखला की देखरेख करती हैं। लीकेज को कम करने और यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि इच्छित लाभार्थियों को न्यूनतम लागत पर समय पर हस्तांतरण मिले, केंद्र ने 2013 में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) कार्यक्रम शुरू किया (परमासिवम और अरुण, 2018)। यह सत्यापित लाभार्थियों के बैंक खाते में सीधे सब्सिडी हस्तांतरित करता है, जिससे धन वितरण में बिचौलियों की भूमिका कम हो जाती है। लाभार्थियों के पास बैंक खाता होना अनिवार्य करने से दोहराव और लीकेज को रोका जा सकता है, जबकि आधार प्रणाली के साथ एकीकरण सत्यापन को मजबूत करता है (बरनवाल, 2016)।

डीबीटी को 1 जनवरी, 2013 को चुनिंदा जिलों में पायलट आधार पर लॉन्च किया गया था, जिसमें शुरुआत में कुछ योजनाएं शामिल थीं। 2013 में ही, केंद्र सरकार ने एलपीजी सब्सिडी भुगतान के लिए डीबीटी की शुरुआत की, इसके बाद महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस); राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी); सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस); और छात्र छात्रवृत्ति योजनाओं (परमासिवम और अरुण, 2018) जैसी प्रमुख योजनाएं शुरू की गईं। अगस्त 2015 तक, डीबीटी दुनिया का सबसे बड़ा नकद हस्तांतरण कार्यक्रम बन गया, जिसने लगभग 14 करोड़ परिवारों को प्रत्यक्ष लाभ प्रदान किया (बरनवाल, 2016)। इसी तरह, कोविड-19 महामारी के दौरान, डीबीटी ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जब भारत में

(जारी)

चार्ट ए.1: भारत में डीबीटी की प्रगति

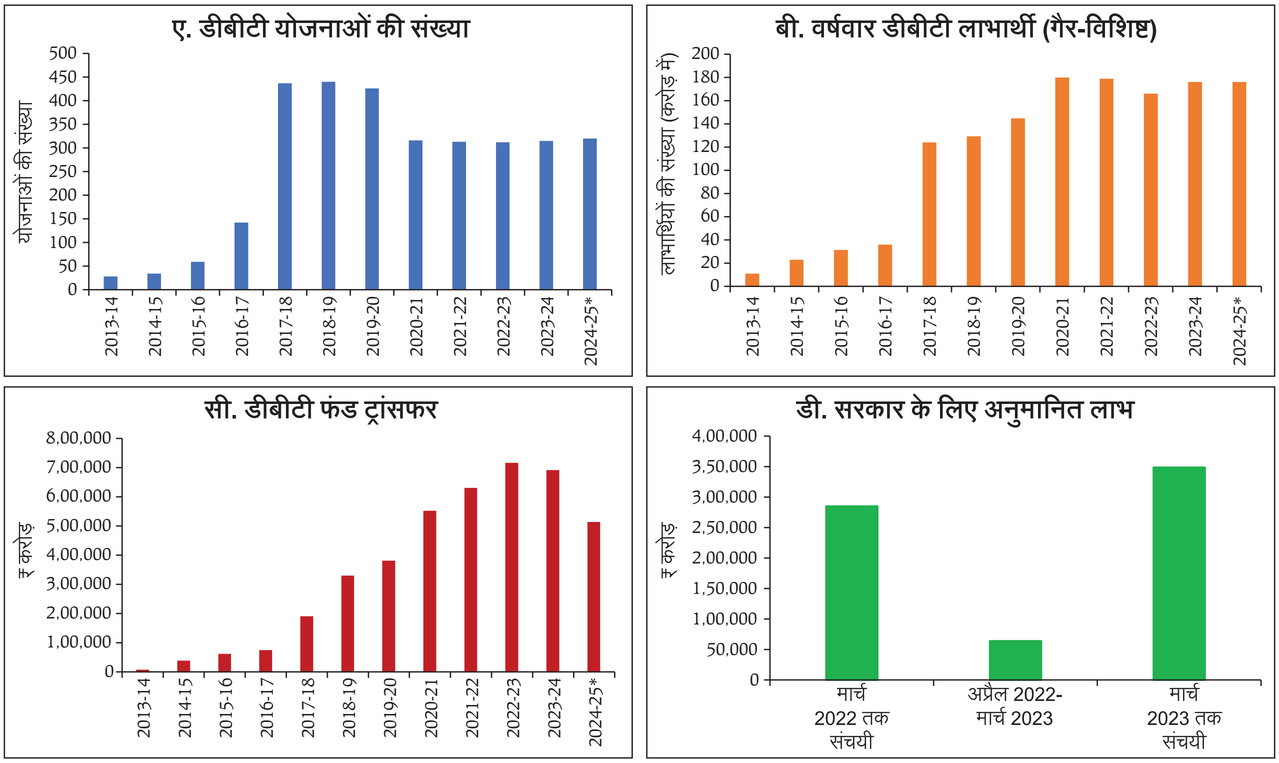

टिप्पणी: *: 2024-25 के लिए चार्ट में दर्शाए गए आंकड़े डीबीटी की आधिकारिक वेबसाइट पर फरवरी 2025 के मध्य में उपलब्ध हैं।
स्रोत: https://dbtbharat.gov.in/

नकद हस्तांतरण की गति और पैमाना अभूतपूर्व था (भट्टाचार्य और सिन्हा, 2021)।

2013-14 में 28 योजनाओं की मामूली कवरेज से, वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान केंद्र सरकार के 54 मंत्रालयों में 323 योजनाओं में डीबीटी लागू किया गया है (चार्ट ए.1ए)। लाभार्थियों की संख्या के साथ-साथ विभिन्न योजनाओं के तहत हस्तांतरित धन में भी समय के साथ उल्लेखनीय वृद्धि हुई है (चार्ट ए.1बी और ए.1सी)। इसके अलावा, डीबीटी के तहत विभिन्न सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों को शामिल करने से फर्जी और डुप्लिकेट लाभार्थियों की पहचान और उन्हें हटाने में मदद मिली है, जिसके परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण बचत हुई है (चार्ट ए.1डी)।

उदाहरण के लिए, डीबीटी के कार्यान्वयन ने उर्वरक विभाग को खुदरा विक्रेताओं को अपनी उर्वरक बिक्री में 158.1 लाख मीट्रिक टन की कमी करने में सहायता की है। इसी तरह, एमजीएनआरईजीएस के मामले में, डीबीटी के माध्यम से भुगतान ने 7.1 लाख फर्जी जॉब कार्ड को खत्म करने में मदद की है। इसी तरह, एलपीजी सब्सिडी भुगतान को डीबीटी के माध्यम से करने से 4.15 करोड़ नकली, फर्जी या निष्क्रिय एलपीजी कनेक्शन समाप्त हो गए हैं।[6] भारत द्वारा लागू किए गए डीबीटी-शैली के सार्वजनिक हस्तक्षेपों को विश्व बैंक द्वारा आपदा लचीलापन सुनिश्चित करने के लिए अन्य देशों द्वारा अपनाने की सिफारिश की गई है (विश्व बैंक, 2022)।

संदर्भ:

1. Barnwal, P. (2016). Curbing Leakage in Public Programs with Direct Benefit Transfers: Evidence from India's Fuel Subsidies and Black Market. Department of Economics, Michigan State University, April.
2. Bhattacharya, S. and Sinha, R. (2021). Intent to Implementation: Summary of Lessons from Tracking India's Social Protection Response to COVID-19 (English). Washington, D.C.: World Bank Group.
3. Paramasivam, C. and Arunkumar, G. (2018). Direct Benefit Transfer: An Innovative Approach to Financial Inclusion in India. *JETIR*, 5(12), December.
4. World Bank. (2022). The Role of Digital in the COVID-19 Social Assistance Response (English). Washington, D.C.: World Bank Group.

[6] डेटा मार्च 2023 तक का है और इसे https://dbtbharat.gov.in/ से प्राप्त किया गया है।

चार्ट 12: नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा पर कुल व्यय

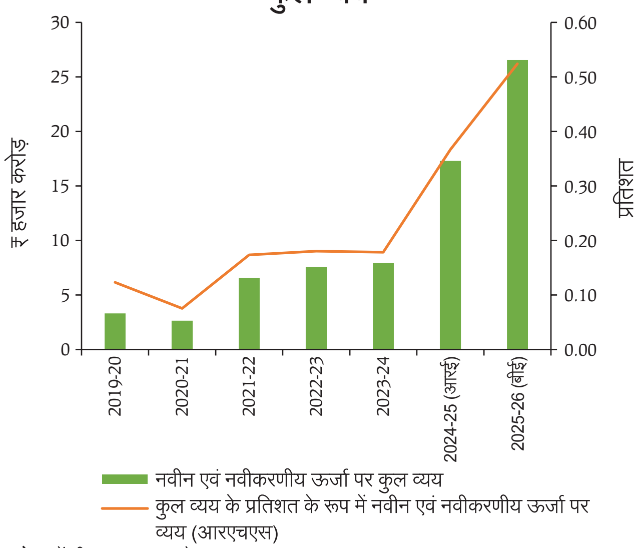

स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज।

चार्ट 13: लिंग बजट

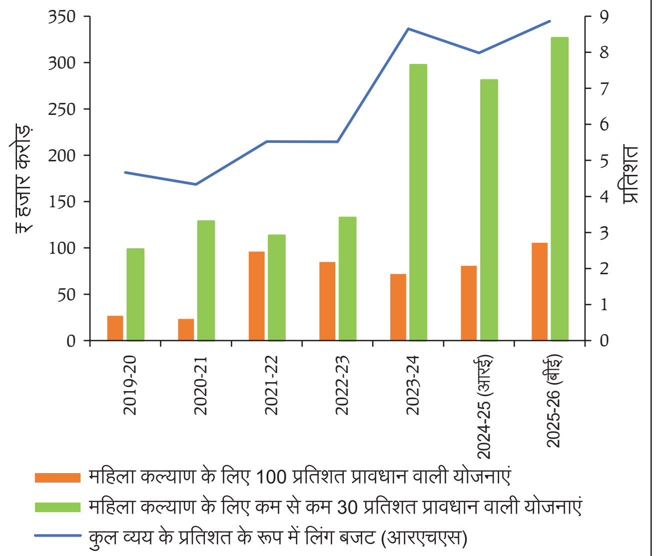

स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज।

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा पर व्यय को 2024-25 (संशोधित अनुमान) में कुल व्यय का 0.37 प्रतिशत से बढ़ाकर 2025-26 (बजट अनुमान) में 0.52 प्रतिशत करने का बजट बनाया गया है, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए आवंटन में वृद्धि से किया गया है (चार्ट 12)। केंद्र सरकार के लिंग बजट को भी 2025-26 में अपने कुल व्यय का 8.9 प्रतिशत बढ़ाने का बजट बनाया गया है, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना (चार्ट 13) द्वारा किया गया है।

V. बकाया ऋण

कोविड-19 महामारी के बीच 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद के 62.6 प्रतिशत के शिखर पर पहुंचने के बाद, केंद्र सरकार का कुल बकाया ऋण 2023-24 में 58.7 प्रतिशत से घटकर 2024-25 (संशोधित अनुमान) में सकल घरेलू उत्पाद का 57.1 प्रतिशत हो गया और 2025-26 में इसे और घटकर सकल घरेलू उत्पाद का 56.0 प्रतिशत होने का बजट है। राजस्व प्राप्तियों के अनुपात में ब्याज भुगतान का बजट 2025-26 में 37.3 प्रतिशत रहने का अनुमान है। ब्याज दर-विकास दर अंतर (आईआरजीडी), जो ऋण स्थिरता का एक संकेतक है, अनुकूल बना हुआ है (चार्ट 14ए और बी)। आगे बढ़ते हुए, सरकार ने संकेत दिया है कि वह राजकोषीय घाटे के स्तर को बनाए रखेगी।

VI. सकल राजकोषीय घाटा वित्तपोषण

वित्तपोषण के मामले में, 2025-26 के लिए दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से सकल बाजार उधार ₹14.82 लाख करोड़ [2024-25 (संशोधित अनुमान) के ₹14.01 लाख करोड़ से लगभग 5.8 प्रतिशत की वृद्धि] का बजट रखा गया है। पिछले वर्ष के ₹10.75 लाख करोड़ की तुलना में शुद्ध बाजार उधार ₹11.54 लाख करोड़ रखा गया है।[7] बजट में 2025-26 में कुल ₹2.50 लाख करोड़ की प्रतिभूतियों के सकल स्विच का भी प्रावधान किया गया है, जबकि पिछले वर्ष के संशोधित अनुमानों में यह ₹1.47 लाख करोड़ था। सरकार ने 2025-26 के दौरान प्रतिभूतियों की किसी भी खरीद के लिए बजट नहीं रखा है। शुद्ध बाजार उधार से 2025-26 (बजट अनुमान) में जीएफडी का 73.5 प्रतिशत वित्तपोषित होने की उम्मीद है लघु बचत (एनएसएसएफ) से 3.43 लाख करोड़ रुपये की राशि 2025-26 (बजट अनुमान) में जीएफडी के 21.9 प्रतिशत का वित्तपोषण करेगी, जो 2024-25 (संशोधित अनुमान) में 4.12 लाख करोड़ रुपये (26.2 प्रतिशत) से कम है [चार्ट 15]।

[7] 2024-25 (संशोधित) के लिए निवल बाजार उधार के आंकड़ों में प्रतिभूतियों की वापस खरीद [₹ (-)88,164.01 करोड़] शामिल है।

चार्ट 14: बकाया देयताएं और ब्याज दर वृद्धि अंतर

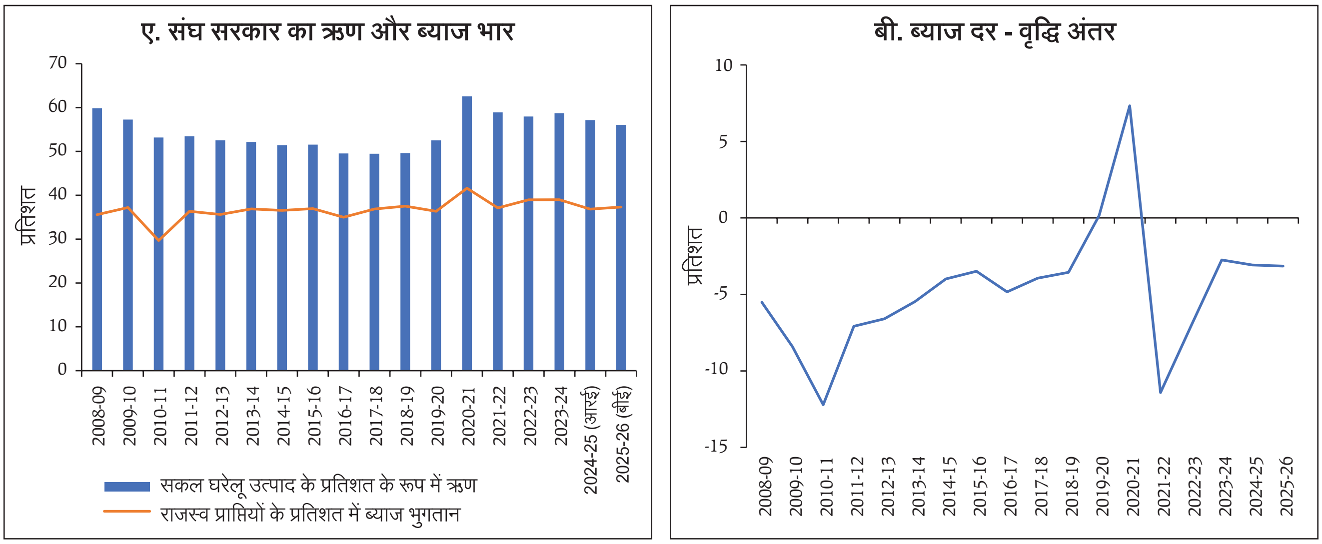

स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज; तथा आरबीआई स्टाफ अनुमान।

केंद्र सरकार की बाजार उधार आवश्यकताओं (जीडीपी के प्रतिशत के रूप में) को धीरे-धीरे महामारी-पूर्व स्तर तक कम करने से निजी क्षेत्र के लिए संसाधनों की अधिक उपलब्धता सुनिश्चित होगी (सारणी 5)।

VII. केंद्र से राज्यों को संसाधन हस्तांतरण

राज्यों को सकल हस्तांतरण में 2025-26 के लिए 12.5 प्रतिशत की वृद्धि का बजट रखा गया है [2024-25 (संशोधित अनुमान) के दौरान 10.2 प्रतिशत], जो मुख्य रूप से केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत हस्तांतरण और पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता के कारण है। राज्यों को संसाधनों का सकल हस्तांतरण 2024-25 (संशोधित अनुमान) के दौरान

चार्ट 15: वित्तपोषण के सकल स्रोत राजकोषीय घाटा

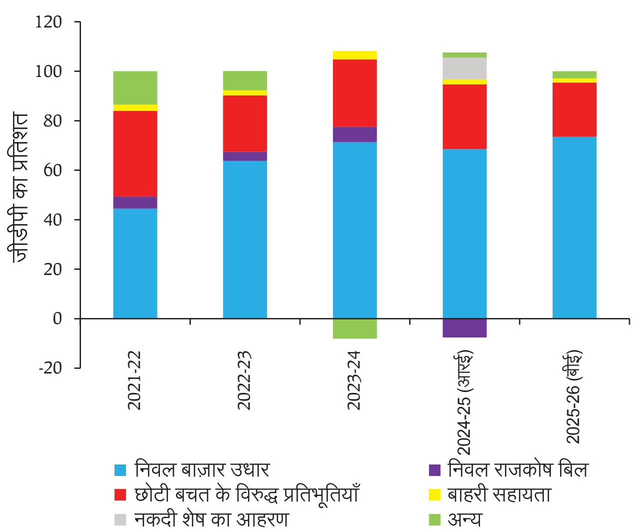

स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज।

सारणी 5: केंद्र सरकार की बाजार उधारी

(₹ करोड़)

वित्तीय वर्ष	सकल बाजार उधार	निवल बाजार उधार
2018-19	5,71,000 (3.0)	4,22,735 (2.2)
2019-20	7,10,000 (3.5)	4,73,968 (2.4)
2020-21	12,60,116 (6.3)	10,32,907 (5.2)
2021-22	9,68,382 (4.1)	7,04,097 (3.0)
2022-23	14,21,000 (5.3)	11,08,259 (4.1)
2023-24	15,43,000 (5.2)	11,77,754 (4.0)
2024-25 (आरई)	14,00,697 (4.3)	10,74,514 (3.3)
2025-26 (बीई)	14,82,000 (4.2)	11,53,834 (3.2)

टिप्पणी: 1. 2024-25 के लिए शुद्ध बाजार उधार (आरई) में प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद शामिल है।
2. 2023-24 से, प्रतिभूतियों के स्विचिंग के लिए बाजार उधार को समायोजित किया गया है।
3. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े जीडीपी के प्रतिशत के अनुसार हैं।

स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज।

चार्ट 16: राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सकल संसाधन हस्तांतरण

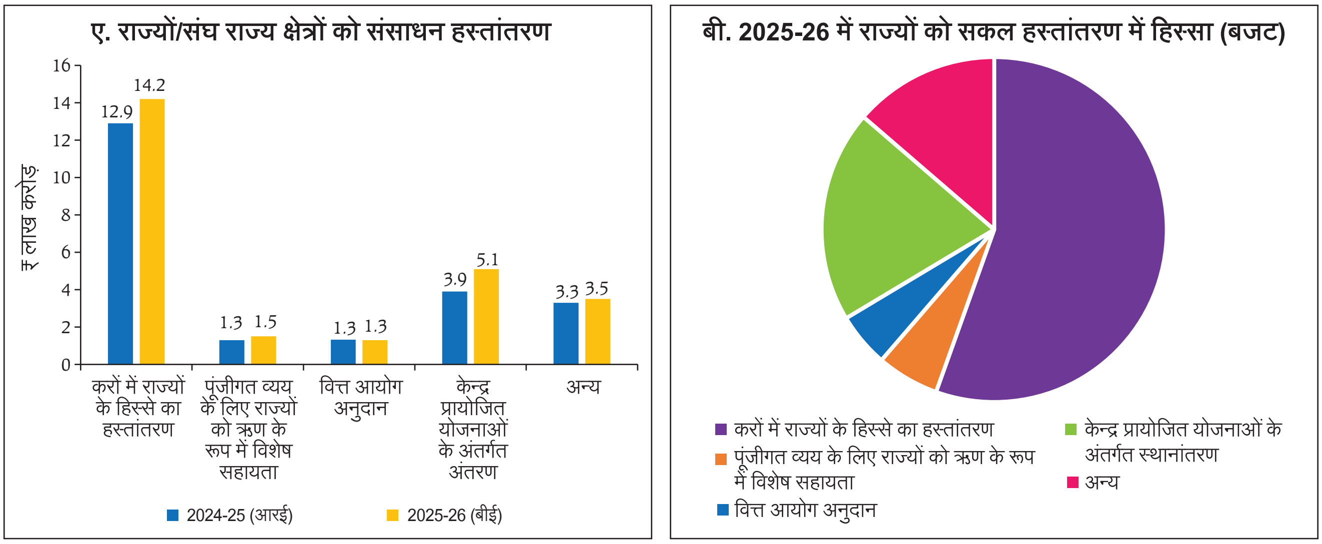

स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज।

सकल घरेलू उत्पाद के 7.0 प्रतिशत से बढ़कर 2025-26 (बजट अनुमान) के दौरान 7.2 प्रतिशत हो जाएगा। करों में राज्यों के हिस्से का हस्तांतरण सकल हस्तांतरण का सबसे बड़ा घटक है (चार्ट 16ए और बी)[8]

जबकि कर हस्तांतरण राजकोषीय हस्तांतरण की आधारशिला है, हस्तांतरण के बाद राजस्व घाटा अनुदान (आरडीजी) संरचनात्मक राजकोषीय अंतराल को पाटकर राज्य के वित्त को स्थिर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं (बॉक्स बी)।

बॉक्स बी: राजस्व घाटा अनुदान - राज्यों की राजकोषीय स्थिरता के लिए एक साधन

वित्त आयोग को अन्य बातों के साथ-साथ राजस्व की कमी और लागत असमानताओं को कम करने का कार्य सौंपा गया है जो विभिन्न राज्यों को उच्च गुणवत्ता वाली सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने में बाधा डालते हैं (राव, 2022)। इस संदर्भ में, वित्त आयोग अनुदान राज्य-विशिष्ट राजकोषीय आवश्यकताओं जैसे आपदा राहत, स्थानीय निकायों का विकास, क्षेत्रीय निवेश और राजस्व घाटा समर्थन को लक्षित करने वाले सूत्र-आधारित कर हस्तांतरण के लिए एक महत्वपूर्ण पूरक के रूप में कार्य करता है। ये अनुदान कमज़ोर राजकोषीय क्षमता वाले राज्यों को अत्यधिक उधार लिए बिना अपने व्यय दायित्वों को पूरा करने में मदद करते हैं। इनमें से, हस्तांतरण के बाद राजस्व घाटा अनुदान (आरडीजी) हस्तांतरण के बाद राजस्व की कमी को पूरा करके विशेष रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत प्रदान किए गए, आरडीजी राजकोषीय स्थिरता बनाए रखने और राज्यों को आवश्यक शासन और विकासात्मक प्रतिबद्धताओं को बनाए रखने में सक्षम बनाने में मदद करते हैं।

ऐतिहासिक रूप से, सभी वित्त आयोगों ने राज्यों के बीच राजकोषीय असंतुलन को दूर करने के लिए आरडीजी की सिफारिश की है और राज्यों के राजस्व और व्यय अंतर के मानक आकलन के आधार पर इसे आवंटित किया है। इसके अतिरिक्त, आरडीजी राज्यों को क्रमिक वित्त आयोगों द्वारा अनुशंसित कर हस्तांतरण पैटर्न में परिवर्तनों के माध्यम से संक्रमण में मदद करते हैं। वे राज्यों को जरूरतों, राजकोषीय क्षमता और शासन प्रदर्शन (वित्त आयोग - XV) के उभरते आकलन के अनुरूप अपनी राजकोषीय स्थिति को समायोजित करने का समय देते हैं।

आरडीजी नैतिक जोखिम पैदा कर सकते हैं, जहां केंद्रीय अनुदान पर निर्भरता राज्यों को महत्वपूर्ण राजकोषीय सुधारों को लागू करने से हतोत्साहित करती है, जैसे कर प्रशासन में सुधार या व्यय युक्तिकरण। क्रमिक वित्त आयोगों ने प्रत्येक राज्य की राजकोषीय आवश्यकताओं का आकलन करने के लिए एक मानक

(जारी)

8 विस्तृत जानकारी के लिए कृपया अनुलग्नक II देखें।

चार्ट बी.1: राज्यों का राजस्व घाटा: वास्तविक *बनाम* आर.डी. अनुदान के बिना

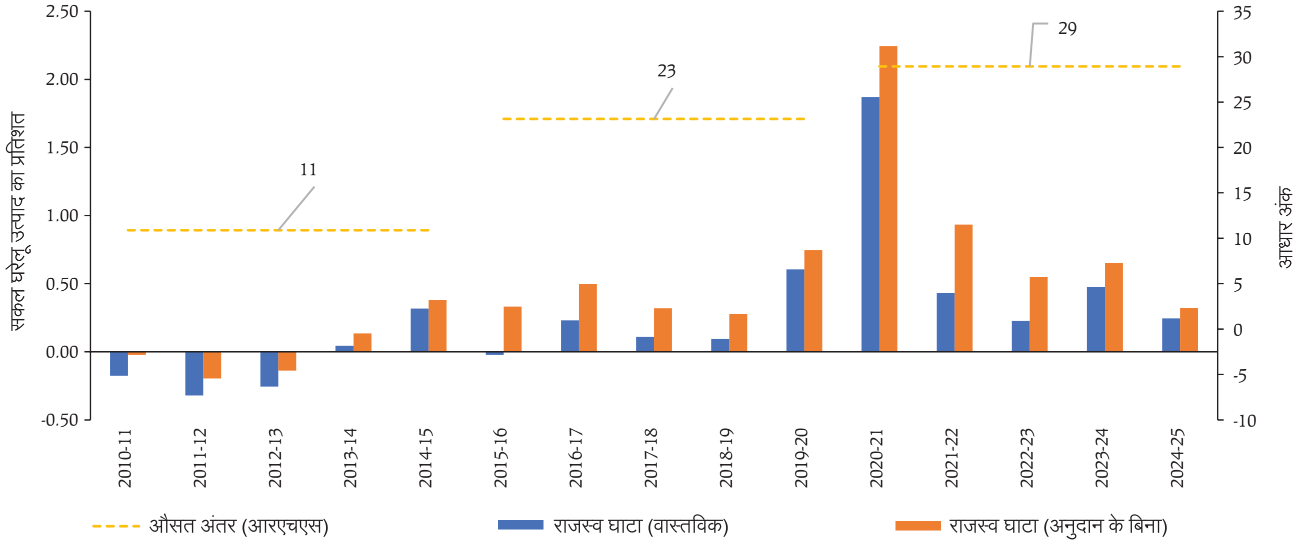

स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज; और रिजर्व बैंक के राज्य वित्त: 2024-25 के बजट का अध्ययन।

दृष्टिकोण अपनाकर इन चिंताओं को कम करने की कोशिश की है। एक सरल अंतर-भरने के दृष्टिकोण के विपरीत, जो अनजाने में अपर्याप्त राजस्व प्रयास या अत्यधिक खर्च को पुरस्कृत कर सकता है, यह मानक ढांचा राजकोषीय क्षमता में संरचनात्मक कमियों को ठीक करता है जबकि राजकोषीय अपव्यय को हतोत्साहित करता है (रेड्डी और रेड्डी, 2019)। पंद्रहवें वित्त आयोग ने सिफारिश की थी कि राज्यों को समय के साथ अपने हस्तांतरण के बाद के राजस्व अंतराल को समाप्त करना चाहिए। नतीजतन, अनुशंसित राजस्व घाटा अनुदान पहले वर्ष में ₹1.18 लाख करोड़ से घटकर अपने पुरस्कार अवधि के अंतिम वर्ष में ₹13,705 करोड़ हो गया अनुदानों में चरणबद्ध कटौती से राज्यों को अपने हस्तांतरण-पश्चात राजस्व घाटे को समाप्त करने के लिए अपने राजकोषीय प्रबंधन में उपयुक्त समायोजन करने के लिए उचित समय मिलेगा (राव, 2021)।

आर.डी.जी. वाले और बिना आर.डी.जी. वाले राज्यों के समग्र राजस्व घाटे का विश्लेषण राज्य के वित्त पर उनके स्थिर प्रभाव को उजागर करता है। महामारी की शुरुआत ने राज्य के वित्त पर अतिरिक्त दबाव डाला, और आर.डी.जी. ने संबंधित राजकोषीय आघात को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आर.डी.जी. के बिना, राज्यों को 2020-25 की अवधि (चार्ट बी.1) के दौरान 29 आधार अंकों से अधिक राजस्व घाटे का सामना करना पड़ता, जिससे उधारी में वृद्धि या व्यय में कटौती की आवश्यकता होती, जिससे सार्वजनिक सेवा वितरण और विकास व्यय कमजोर होता।

पिछले 15 वर्षों में, आरडीजी ने राज्यों को अपने घाटे को औसतन सकल घरेलू उत्पाद के 0.2 से 0.3 प्रतिशत तक कम करने में मदद की है, जिससे अत्यधिक उधारी को रोका जा सका है और स्थिर सार्वजनिक व्यय को सक्षम किया जा सका है। आरडीजी सहित केंद्रीय हस्तांतरण, राजकोषीय संघवाद का समर्थन करने के लिए एक आवश्यक तंत्र बना हुआ है और राज्यों को राजकोषीय जिम्मेदारी बनाए रखते हुए अपने विकासात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है।

संदर्भ:

1. Government of India (2020). *Report of the Fifteenth Finance Commission. Volume 1.* Ministry of Finance, Government of India.
2. Rao, M. G. (2021). Fiscal Transfers in Pandemic Times. *Economic and Political Weekly, 56*(33).
3. Rao, M. G. (2022). *Studies in Indian Public Finance.* Oxford University Press.
4. Reddy, Y. V., and Reddy, G. R. (2018). *Indian Fiscal Federalism.* Oxford University Press.
5. Various Finance Commission Reports.

सारणी 6: राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वित्त आयोग (एफसी) अनुदान

मद	₹ लाख करोड़		कुल एफसी अनुदान में हिस्सा (प्रतिशत में)		वृद्धि (प्रतिशत में)	
	2024-25 (आरई)	2025-26 (बीई)	2024-25 (आरई)	2025-26 (बीई)	2024-25 (आरई)	2025-26 (बीई)
वित्त आयोग (एफसी) अनुदान	1.3	1.3	-	-	-14.4	4.4
1. स्थानीय निकायों के लिए अनुदान - शहरी निकाय	0.2	0.3	16.5	19.7	-1.1	24.6
2. स्थानीय निकायों के लिए अनुदान - ग्रामीण निकाय	0.5	0.5	35.4	36.6	-4.8	7.9
3. स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अनुदान	0.1	0.2	8.0	11.5	117.9	49.4
4. हस्तांतरण के बाद राजस्व घाटा अनुदान	0.2	0.1	19.3	10.3	-52.6	-44.0
5. अन्य*	0.3	0.3	20.8	21.9	11.7	9.9

टिप्पणी: 'अन्य' में नए शहरों के विकास के लिए अनुदान, साझा नगरपालिका सेवाओं के लिए अनुदान, राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के लिए अनुदान सहायता और राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के लिए अनुदान सहायता शामिल हैं।
स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज।

वित्त आयोग ने 2025-26 में अनुदान में 4.4 प्रतिशत की वृद्धि का बजट रखा है, जिसका मुख्य कारण स्थानीय निकायों (शहरी और ग्रामीण दोनों) के लिए अनुदान में वृद्धि के साथ-साथ स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अनुदान में वृद्धि है (सारणी 6)।

बजट में राज्यों के पूंजीगत व्यय और सुधार से जुड़े प्रोत्साहनों के लिए 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण के तहत 1.5 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। शासन और नगरपालिका सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए शहरी क्षेत्र के सुधारों को प्रोत्साहित किया जाएगा। बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने की दिशा में, राज्यों को भारत बुनियादी ढांचा परियोजना विकास निधि के तहत पीपीपी परियोजनाओं के लिए धन प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। बजट में राज्य-स्तरीय बिजली वितरण और बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए प्रमुख बिजली क्षेत्र सुधारों का प्रस्ताव है। राज्यों को बिजली वितरण कंपनियों की वित्तीय सेहत और दक्षता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके समर्थन के लिए, सुधार करने वाले राज्यों को सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 0.5 प्रतिशत अतिरिक्त उधार लेने की अनुमति दी जाएगी।

राज्यों के साथ साझेदारी में कई क्षेत्र-विशिष्ट पहलों की घोषणा की गई है। कृषि में, प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना, ग्रामीण समृद्धि और लचीलापन कार्यक्रम और सब्जियों और फलों के लिए व्यापक कार्यक्रम जैसी योजनाओं को लागू करने के लिए राज्यों की भागीदारी की मांग की गई है। जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ा दिया गया है, जिसमें ग्रामीण जल आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए राज्यों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। केंद्र सरकार चुनौती-आधारित मोड के माध्यम से 50 पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए राज्यों के साथ भागीदारी करेगी। राज्यों को फंडिंग के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए बुनियादी ढांचे के लिए भूमि प्रदान करनी होगी।

VIII. निष्कर्ष

केंद्रीय बजट 2025-26 'विकसित भारत' के दृष्टिकोण के अनुरूप समावेशी, दीर्घकालिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हुए राजकोषीय अनुशासन के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। इस उद्देश्य की ओर, बजट ने विकास के चार इंजनों - कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात के तहत नवाचार और संरचनात्मक सुधारों द्वारा प्रेरित कई उपायों की घोषणा की है। सरकार ने उपभोग बढ़ाने वाले उपायों के साथ-साथ पूंजीगत व्यय पर अपना ध्यान केंद्रित करना जारी रखा है, जिससे अर्थव्यवस्था को अपनी विकास गति में सुधार करने में मदद मिलेगी। सकल घरेलू उत्पाद के 4.4 प्रतिशत के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य के साथ, बजट समेकन और विकास उद्देश्यों को संतुलित करता है। सरकार व्यापक आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने के लिए आगे चलकर मध्यम अवधि के राजकोषीय लंगर के रूप में ऋण/जीडीपी अनुपात का उपयोग करेगी।

अनुलग्नक I: केंद्रीय बजट 2025-26 - प्रमुख राजकोषीय संकेतक

मद	₹ लाख करोड़					सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत			वृद्धि दर		
	2022-23	2023-24	2024-25 (बीई)	2024-25 (आरई)	2025-26 (बीई)	2023-24	2024-25 (आरई)	2025-26 (बीई)	2023-24	2024-25 (आरई)	2025-26 (बीई)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. प्रत्यक्ष कर	1,660	1,956	2,207	2,237	2,520	6.6	6.9	7.1	17.9	14.4	12.7
(i) निगम	826	911	1,020	980	1,082	3.1	3.0	3.0	10.3	7.6	10.4
(ii) आय	809	1,011	1,150	1,202	1,360	3.4	3.7	3.8	25.0	18.8	13.1
(iii) प्रतिभूति लेनदेन कर	25	34	37	55	78	0.1	0.2	0.2	34.7	62.8	41.8
2. अप्रत्यक्ष कर	1,394	1,509	1,633	1,616	1,750	5.1	5.0	4.9	8.2	7.1	8.3
(i) जीएसटी	849	957	1,062	1,062	1,178	3.2	3.3	3.3	12.7	10.9	10.9
(ii) सीमा शुल्क	213	233	238	235	240	0.8	0.7	0.7	9.3	0.8	2.1
(iii) उत्पाद शुल्क	323	309	324	310	322	1.0	1.0	0.9	-4.2	0.2	3.9
3. सकल कर राजस्व (1+2)	3,054	3,466	3,840	3,853	4,270	11.7	11.9	12.0	13.5	11.2	10.8
4. राज्यों को असाइनमेंट	948	1,129	1,247	1,287	1,422	3.8	4.0	4.0	19.1	13.9	10.5
5. एनसीसीडी स्थानान्तरण	8	9	9	10	10	0.0	0.0	0.0	9.7	9.5	8.0
6. शुद्ध कर राजस्व (3-4-5)	2,098	2,327	2,583	2,557	2,837	7.9	7.9	7.9	10.9	9.9	11.0
7. गैर-कर राजस्व	285	402	546	531	583	1.4	1.6	1.6	40.8	32.2	9.8
(i) लाभांश और लाभ	100	171	289	289	325	0.6	0.9	0.9	71.0	69.3	12.3
(ii) ब्याज प्राप्तियां	28	38	38	34	48	0.1	0.1	0.1	37.4	-11.0	40.2
8. राजस्व प्राप्तियां (6+7)	2,383	2,729	3,129	3,088	3,420	9.2	9.5	9.6	14.5	13.2	10.8
9. गैर ऋण पूंजी प्राप्तियां	72	60	78	59	76	0.2	0.2	0.2	-17.2	-1.3	28.8
(i) विविध पूंजी प्राप्तियां	46	33	50	33	47	0.1	0.1	0.1	-28.1	-0.4	42.4
(ii) ऋण की वसूली	26	27	28	26	29	0.1	0.1	0.1	1.9	-2.4	11.5
10. कुल प्राप्तियां (उधार को छोड़कर) (8+9)	2,455	2,789	3,207	3,147	3,496	9.4	9.7	9.8	13.6	12.8	11.1
11. राजस्व व्यय (आरई)	3,453	3,494	3,709	3,698	3,944	11.8	11.4	11.0	1.2	5.8	6.7
(i) ब्याज भुगतान (आईपी)	929	1,064	1,163	1,138	1,276	3.6	3.5	3.6	14.6	7.0	12.2
(ii) कुल सब्सिडी (टीएस) *जिसका कि:*	578	435	428	428	426	1.5	1.3	1.2	-24.7	-1.6	-0.4
खाना	273	212	205	197	203	0.7	0.6	0.6	-22.4	-6.8	3.0
उर्वरक	251	188	164	171	168	0.6	0.5	0.5	-25.1	-9.0	-2.0
पेट्रोलियम	7	12	12	15	12	0.0	0.0	0.0	79.5	20.1	-17.7
(iii) आरई-आईपी-टीएस	1,947	1,995	2,118	2,132	2,242	6.8	6.6	6.3	2.5	6.9	5.1
12. पूंजीगत व्यय (i + ii)	740	949	1,111	1,018	1,121	3.2	3.1	3.1	28.3	7.3	10.1
(i) पूंजीगत परिव्यय	625	788	919	848	895	2.7	2.6	2.5	26.1	7.6	5.6
(ii) ऋण एवं अग्रिम	115	161	192	171	226	0.5	0.5	0.6	39.8	6.0	32.3
13. कुल व्यय (11+12)	4,193	4,443	4,821	4,716	5,065	15.0	14.6	14.2	6.0	6.1	7.4
14. सकल राजकोषीय घाटा (13-10)	1,738	1,655	1,613	1,570	1,569	5.6	4.8	4.4	-4.8	-5.1	-0.04

स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज

अनुलग्नक II: केंद्र से राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्र शासित प्रदेशों को संसाधन हस्तांतरण

मद	₹ लाख करोड़			सकल हस्तांतरण के प्रतिशत के रूप में			वृद्धि दर		
	2023-24	2024-25 (आरई)	2025-26 (बीई)	2023-24	2024-25 (आरई)	2025-26 (बीई)	2023-24	2024-25 (आरई)	2025-26 (बीई)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. करों में राज्यों के हिस्से का हस्तांतरण	1,129	1,287	1,422	54.7	56.6	55.6	19.1	13.9	10.5
II. वित्त आयोग अनुदान	148.5	127.1	132.8	7.2	5.6	5.2	-14.0	-14.4	4.4
जिसका कि:									
1. स्थानीय निकायों के लिए अनुदान - शहरी निकाय	21.2	21.0	26.2	1.0	0.9	1.0	19.2	-1.1	24.6
2. स्थानीय निकायों के लिए अनुदान - ग्रामीण निकाय	47.3	45.0	48.6	2.3	2.0	1.9	3.6	-4.8	7.9
3. स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अनुदान	4.7	10.2	15.3	0.2	0.4	0.6	42.2	117.9	49.4
4. एसडीआरएफ के लिए अनुदान सहायता	19.4	20.6	21.6	0.9	0.9	0.8	18.4	5.8	5.0
5. राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के लिए अनुदान सहायता	4.3	5.1	5.4	0.2	0.2	0.2	21.5	20.8	5.0
6. हस्तांतरण के बाद राजस्व घाटा अनुदान	51.7	24.5	13.7	2.5	1.1	0.5	-40.1	-52.6	-44.0
III. स्थानांतरण की कुछ महत्वपूर्ण वस्तुएँ	160.3	201.1	229.0	7.8	8.8	8.9	33.1	25.5	13.9
जिसका कि:									
1. बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएँ-ऋण	31.3	34.4	42.7	1.5	1.5	1.7	11.0	9.9	24.2
2. पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को ऋण के रूप में विशेष सहायता	109.6	125.0	150.0	5.3	5.5	5.9	34.9	14.1	20.0
3. मांग के अंतर्गत विशेष सहायता - राज्यों को हस्तांतरण	11.7	18.0	10.0	0.6	0.8	0.4	408.5	53.9	-44.4
IV. राज्यों को कुल स्थानांतरण [I+II+III के अलावा]	571.3	604.5	717.0	27.7	26.6	28.0	0.8	5.8	18.6
1. केंद्र प्रायोजित योजनाएं (राजस्व)	425.3	392.7	514.4	20.6	17.3	20.1	4.8	-7.7	31.0
2. केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं	15.1	63.8	76.5	0.7	2.8	3.0	17.0	322.5	20.0
3. व्यय की अन्य श्रेणियाँ	131.0	147.9	126.0	6.3	6.5	4.9	-11.6	12.9	-14.8
4. पूंजी हस्तांतरण	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	-50.0	10100.0	1.0
V. दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू-कश्मीर को स्थानांतरण	55.2	55.9	58.5	2.7	2.5	2.3	-1.8	1.3	4.5
VI. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सकल स्थानान्तरण (I+II+III+IV+V)	2,065	2,276	2,560	100.0	100.0	100.0	10.7	10.2	12.5
VII. ऋण और अग्रिम की वसूली घटा दी गई	12.2	50.3	50.3	0.6	2.2	2.0	21.0	311.1	0.0
VIII. शुद्ध स्थानान्तरण (VI-VII)	2,053	2,225	2,510	99.4	97.8	98.0	10.7	8.4	12.8
IX. सकल स्थानान्तरण / जीडीपी (प्रतिशत)	7.0	7.0	7.2						
X. शुद्ध स्थानान्तरण / जीडीपी (प्रतिशत)	6.9	6.9	7.0						

स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज।

भारत में सरकारी व्यय की गुणवत्ता और इसके सामाजिक-आर्थिक प्रभाव

रचित सोलंकी, कोवुरी आकाश यादव, आयुषी खंडेलवाल, समीर रंजन बेहरा और अत्री मुखर्जी द्वारा ^

भारत में उदारीकरण के बाद की अवधि में राजकोषीय प्राथमिकताओं में गतिशील बदलाव देखने को मिले हैं, जिसमें बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश के साथ व्यापक आर्थिक स्थिरता की अनिवार्यताओं को संतुलित किया गया है। केंद्र और राज्यों द्वारा पूंजीगत व्यय को बढ़ावा देने की पृष्ठभूमि में, यह लेख 1991-92 से भारत के सार्वजनिक व्यय प्रक्षेपवक्र की जांच करता है, नीति सुधारों, संरचनात्मक परिवर्तनों और नीतिगत पहलों की भूमिका का विश्लेषण करता है। अध्ययन सार्वजनिक व्यय की गुणवत्ता (क्यूपीई) सूचकांक की गणना करके व्यय संरचना, आर्थिक परिणामों और विकासात्मक प्रगति के बीच परस्पर क्रिया को स्पष्ट करता है।

I. प्रस्तावना

सरकारी खर्च और इसकी संरचनात्मक संरचना आर्थिक विकास को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। निवेश की ओर खर्च प्रोफ़ाइल को फिर से उन्मुख करना, विशेष रूप से पूंजी निर्माण को वित्तपोषित करने के लिए सार्वजनिक उधार को निर्देशित करके, जीडीपी पर सकारात्मक प्रभाव डालता है (सेवर एट अल, 2011)। सार्वजनिक व्यय, जैसे कि आवश्यक सार्वजनिक वस्तुओं - शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और बुनियादी ढाँचे को बढ़ाने वाले - आम तौर पर अधिक उत्पादक होते हैं। ये व्यय न केवल निजी निवेशों को पूरक बना सकते हैं, बल्कि सतत आर्थिक विकास के लिए एक सक्षम वातावरण को भी बढ़ावा दे सकते हैं। सामाजिक सुरक्षा जाल को मजबूत करने, उद्यमशीलता को बढ़ावा देने और सार्वजनिक व्यय प्रबंधन में सुधार पर लक्षित खर्च को दीर्घकालिक विकास की आधारशिला के रूप में तेजी से पहचाना जा रहा है (मिसरा एट अल, 2021)। इसके अलावा, इन महत्वपूर्ण डोमेन के भीतर संसाधनों का इष्टतम आवंटन सुनिश्चित करना समावेशी और सतत विकास को बढ़ावा देने में सार्वजनिक खर्च की भूमिका को और मजबूत करता है (पधी एट अल, 2023)।

इस प्रकार, सार्वजनिक व्यय और इसकी गुणवत्ता व्यापक आर्थिक स्थिरता के रखरखाव के साथ विकास की अनिवार्यताओं को संतुलित करने में महत्वपूर्ण महत्व रखती है। विवेकपूर्ण राजकोषीय नीति निजी व्यय के लिए जगह बना सकती है, और जब इसे स्थायी सार्वजनिक व्यय के साथ जोड़ा जाता है, तो वे निश्चित आर्थिक लाभ प्रदान करते हैं (भारत सरकार, 2017)। हालांकि, उच्च सार्वजनिक व्यय, भले ही विकास-उन्मुख हो, महत्वपूर्ण जोखिम पैदा कर सकता है। निरंतर उच्च बजटीय घाटा राष्ट्रीय बचत को कमजोर कर सकता है, ब्याज दरों को बढ़ा सकता है, और अल्पावधि और दीर्घावधि दोनों में राष्ट्रीय आय को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है। लगातार घाटे से सरकार की विश्वसनीयता और निवेशकों का विश्वास कम होता है, जबकि बाहरी कमजोरियों, जैसे चालू खाता घाटा, जो लंबे समय तक राजकोषीय असंतुलन से उत्पन्न होता है, को बढ़ाता है (गेल और ओरज़ैग, 2003)। ये गतिशीलता जिम्मेदार राजकोषीय प्रबंधन और सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक व्यय की संरचना का निरंतर मूल्यांकन और परिशोधन करने की आवश्यकता को उजागर करती है।

राजकोषीय विवेक को विकास की अनिवार्यताओं के साथ संतुलित करने की इस पृष्ठभूमि में, सार्वजनिक व्यय की संरचना का विश्लेषण महत्वपूर्ण हो जाता है। यह लेख पिछले तीन दशकों में भारत में सार्वजनिक व्यय के प्रक्षेपवक्र की जांच करता है, और इसकी गुणवत्ता और संरचना को प्रभावित करने वाले कारकों पर ध्यान केंद्रित करता है। व्यय संरचना के वृहद आर्थिक परिणामों से संबंधों की खोज करके, अध्ययन राजकोषीय रणनीतियों को अनुकूलित करने के लिए अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। लेख को छह खंडों में व्यवस्थित किया गया है: खंड II सार्वजनिक व्यय की संरचना के उपायों की पड़ताल करता है; खंड III 1991 से 2025 तक व्यय प्रवृत्तियों का चरणबद्ध विश्लेषण प्रदान करता

^ लेखक आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग से हैं। इस आलेख में व्यक्त विचार लेखकों के हैं और ये भारतीय रिज़र्व बैंक के विचारों को नहीं दर्शाते हैं।

है; खंड IV एक अभिनव सार्वजनिक व्यय की गुणवत्ता (क्यूपीई) सूचकांक का निर्माण करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली पद्धति की रूपरेखा प्रस्तुत करता है; खंड V प्रमुख निष्कर्षों पर चर्चा करता है

II. सरकारी व्यय की गुणवत्ता मापना

सरकारी व्यय की संरचना इसकी गुणवत्ता का एक महत्वपूर्ण संकेतक है, जो दर्शाता है कि सरकारी खर्च किस तरह से सतत वृद्धि और विकास को बढ़ावा देता है। अंतिम उपभोग पर व्यय और भौतिक और मानव पूंजी निर्माण दोनों में निवेश के बीच संतुलन बनाए रखने से वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए दीर्घकालिक लाभ उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार पूंजी निर्माण के लिए समर्पित व्यय का उच्च हिस्सा दीर्घकालिक लाभ पर रणनीतिक ध्यान केंद्रित करने का संकेत देता है (मिसरा एट अल., 2021)। इसलिए, सरकार के खर्च पैटर्न की स्थिरता का आकलन करने के लिए उपभोग-आधारित और निवेश-उन्मुख व्यय के बीच संतुलन को समझना आवश्यक है।

व्यय दक्षता का मूल्यांकन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले विभिन्न मापदंडों में, सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय की मात्रा और राजस्व व्यय का पूंजीगत व्यय (आरईसीओ) से अनुपात विशेष रूप से महत्वपूर्ण बनकर उभरा है। ये उपाय इस बात की जानकारी देते हैं कि सार्वजनिक धन कैसे आवंटित किया जाता है, जिससे नीति निर्माताओं को राजस्व व्यय पर पूंजीगत व्यय को प्राथमिकता देने के संभावित लाभों का आकलन करने में मदद मिलती है। पूंजीगत व्यय पर जोर देकर, सरकारें दीर्घकालिक आर्थिक विकास और विकास परिणामों को आगे बढ़ा सकती हैं। पूंजीगत व्यय में वृद्धि से अक्सर निवेश में आनुपातिक विस्तार से अधिक वृद्धि होती है, जिससे समग्र आर्थिक प्रदर्शन पर अधिक प्रभाव पड़ता है। सार्वजनिक निवेश, विशेष रूप से, मांग को बढ़ावा देकर और उत्पादक क्षमता का विस्तार करके निजी निवेश को “भीड़ में” लाता है (बोस और भानुमूर्ति, 2015)।

इसके अलावा, पूंजीगत व्यय से जुड़ा राजकोषीय गुणक न केवल राजस्व व्यय से आगे निकल जाता है, बल्कि लंबी अवधि तक अधिक बना रहता है, जो इसकी मजबूत वृद्धि-संवर्धन क्षमता को रेखांकित करता है (जैन और कुमार, 2013; आरबीआई, 2024)। सार्वजनिक व्यय की संरचना को उन गतिविधियों के साथ जोड़ना जो सकारात्मक बाह्य प्रभाव उत्पन्न करती हैं, क्षमता निर्माण को बढ़ाती हैं, और राजकोषीय समेकन को सुदृढ़ करती हैं, राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों के बीच तालमेल को और मजबूत करती हैं (गोयल और शर्मा, 2018)। जीडीपी में पूंजीगत व्यय (सीओ) की हिस्सेदारी और कुल व्यय में इसका अनुपात जैसे प्रमुख मीट्रिक, विकास-उन्मुख सार्वजनिक व्यय के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

इसके अलावा, सार्वजनिक व्यय की कुछ श्रेणियों का उद्देश्य अर्थव्यवस्था के उत्पादन कारकों (श्रम और पूंजी) के स्टॉक को बढ़ाकर या उनकी उत्पादकता में सुधार करके आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना है। सबसे अधिक उद्धृत श्रेणियों में शिक्षा और प्रशिक्षण, सार्वजनिक अवसंरचना निवेश, अनुसंधान और विकास (जो तकनीकी उन्नति और नवाचार को बढ़ावा देता है), और स्वास्थ्य सेवा (जो स्वस्थ जीवन की अवधि को बढ़ाकर श्रम शक्ति के आकार और उत्पादकता दोनों को बढ़ाता है) शामिल हैं [यूरोपीय आयोग, 2002; 2004]। इन व्ययों को केंद्र और राज्यों के व्यय बजट में "विकास व्यय" के रूप में दर्ज किया जाता है। कुछ संदर्भों में, सब्सिडी - विशेष रूप से पोषण में सुधार के उद्देश्य से, जैसे कि खाद्य सब्सिडी - को भी विकास व्यय का हिस्सा माना जाता है, क्योंकि अच्छी तरह से लक्षित सब्सिडी कुपोषण और ग्रामीण संकट जैसी विशिष्ट विकास संबंधी बाधाओं को दूर कर सकती है, जिससे दीर्घकालिक कल्याण लाभ प्राप्त होते हैं (फैन और ब्रेज़स्का, 2012)। सरकारों द्वारा उच्च विकास व्यय, मानव पूंजी निर्माण पर इसके सकारात्मक प्रभाव के कारण, आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकता है जबकि एक साथ समानता को बढ़ावा दे सकता है और गरीबी को कम कर सकता है (आईएमएफ, 1998)। विकास व्यय में सामाजिक और आर्थिक सेवाओं का व्यापक दायरा शामिल है। सामाजिक पक्ष में, इसमें स्वास्थ्य, जल आपूर्ति, आवास, शहरी विकास, कमज़ोर वर्गों के कल्याण, पोषण और श्रम कल्याण पर व्यय

शामिल है। आर्थिक पक्ष में, कृषि, ग्रामीण विकास, सिंचाई, ऊर्जा, उद्योग, परिवहन और संचार, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण के लिए संसाधन आवंटित किए जाते हैं।

हालांकि, पूंजी निर्माण और सामाजिक क्षेत्र के विकास के लिए आवंटन बढ़ाना अक्सर राजस्व जुटाने और उधार लेने की सीमाओं से बाधित होता है। नतीजतन, सरकारों को वित्तपोषण बाधाओं के साथ खर्च की अनिवार्यता को समेटने की जरूरत है। लगातार उच्च घाटे उच्च सार्वजनिक ऋण में जमा हो सकते हैं, जो बाद के बजटों में ब्याज का बोझ बढ़ाता है। इसलिए, कुल व्यय में ब्याज भुगतान का हिस्सा पिछले खर्च की गुणवत्ता और ऋण प्रबंधन की प्रभावशीलता के एक उपयोगी संकेतक के रूप में काम कर सकता है। कुल व्यय में ब्याज भुगतान का कम अनुपात पूंजी और विकासात्मक जरूरतों के लिए दुर्लभ राजकोषीय संसाधनों को सुरक्षित रखता है। इस अनुपात का विश्लेषण खर्च की गुणवत्ता के एक प्रमुख उपाय के रूप में भी किया जाता है। निम्नलिखित अनुभाग भारत के ऐतिहासिक व्यय डेटा पर इस विश्लेषणात्मक ढांचे को लागू करता है, जो समय के साथ सार्वजनिक खर्च में बदलावों को बेहतर ढंग से समझने और उनका मूल्यांकन करने के लिए चरण-वार परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है।

III. 1991-2025 के दौरान भारत में सार्वजनिक व्यय [1]: चरण-वार विश्लेषण

भारत के सार्वजनिक व्यय की ऐतिहासिक जांच - जिसमें 1991-92 से 2024-25 तक केंद्र और राज्य दोनों शामिल हैं - महत्वपूर्ण व्यापक आर्थिक बदलावों, नीति सुधारों और संबंधित राजकोषीय विकासों द्वारा आकार दिए गए अलग-अलग चरणों को प्रकट करती है। इस अवधि को अंतरालों में विभाजित करने से व्यापक प्रक्षेपवक्र और मोड़ बिंदुओं का विश्लेषण करने के लिए एक सुसंगत रूपरेखा मिल सकती है। तदनुसार, यह खंड छह चरणों की पहचान करता है, जो दर्शाता है कि संरचनात्मक ताकतों ने सरकार के दोनों स्तरों पर सार्वजनिक व्यय की गुणवत्ता को कैसे आकार दिया है।

इसलिए, यह अवधिकरण व्यापक आर्थिक चक्रों, नीति सुधारों और सार्वजनिक व्यय पैटर्न के बीच घनिष्ठ अंतर्संबंध को रेखांकित करता है। तीन प्रमुख संकेतकों - पूंजीगत व्यय, विकास व्यय और ब्याज भुगतान - में स्पष्ट बदलावों को 1991 के आर्थिक संकट, एफआरबीएम ढांचे की शुरूआत, 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट, उसके बाद के प्रोत्साहन उपायों, 2017 में जीएसटी की शुरूआत और 2020 के बाद महामारी के राजकोषीय निहितार्थों जैसी जानी-मानी घटनाओं से जोड़कर, "व्यय की गुणवत्ता" भारत के आर्थिक सुधार और विकास के तीन दशकों से अधिक समय में विकसित हुई है (चार्ट 1 , 2 और 3)।

चार्ट 1: पूंजीगत परिव्यय

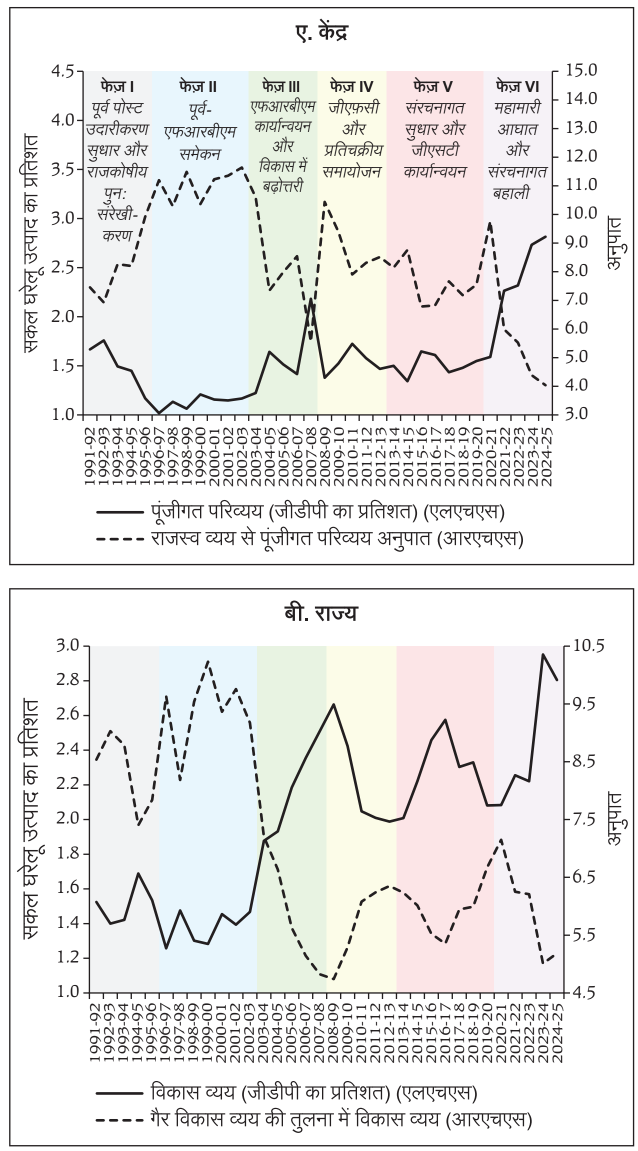

स्रोत: डीबीआईई, आरबीआई; और राज्य वित्त: बजट का एक अध्ययन।

[1] 2023-24 और 2024-25 के लिए केंद्र और राज्यों से संबंधित डेटा क्रमशः संशोधित अनुमान (सं.अ.) और बजट अनुमान (ब.अ.) हैं।

चार्ट 2: विकास व्यय

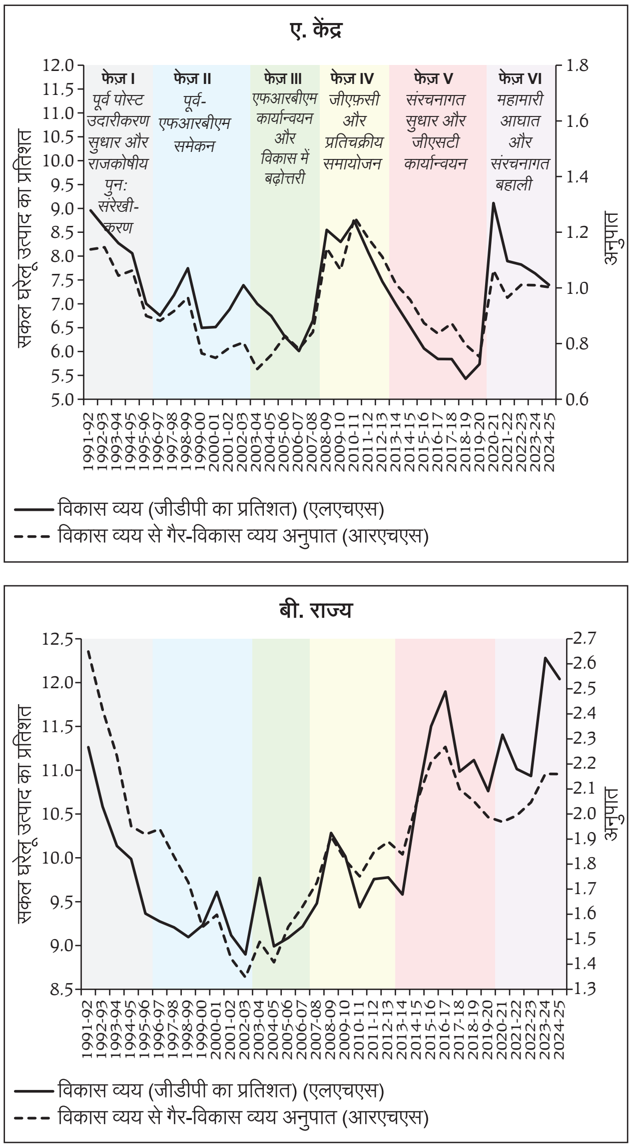

स्रोत: डीबीआईई, आरबीआई; और राज्य वित्त: बजट का एक अध्ययन।

चार्ट 3: ब्याज भुगतान

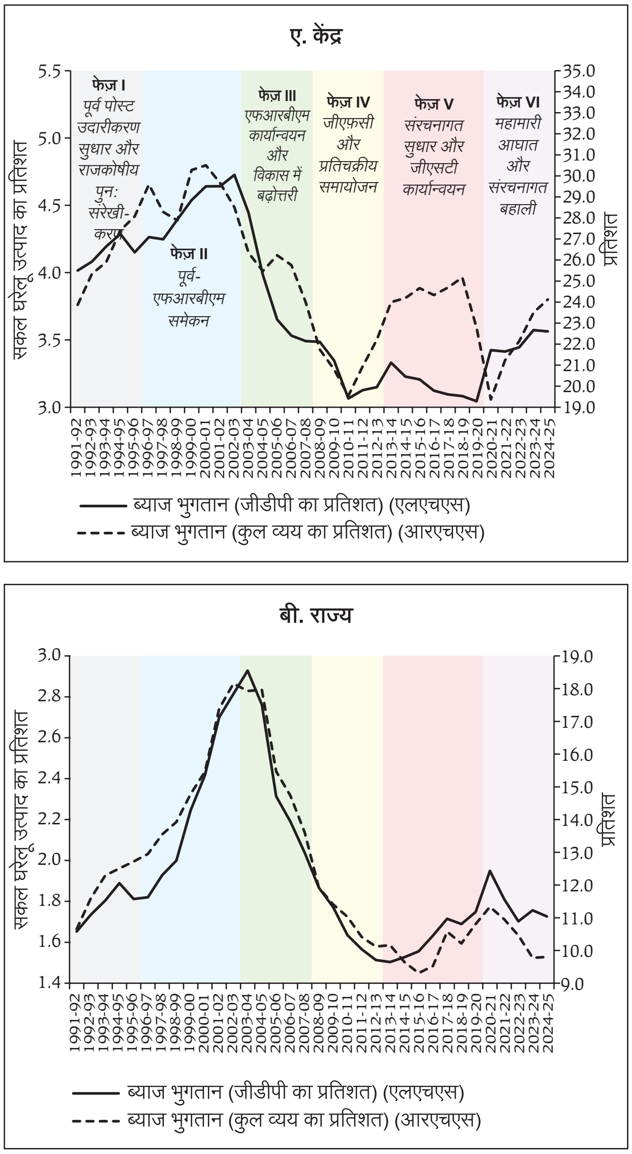

स्रोत: डीबीआईई, आरबीआई; और राज्य वित्त: बजट का एक अध्ययन।

विश्लेषण से पता चलता है कि 1990 के दशक के अंत में और वैश्विक वित्तीय संकट के आसपास केंद्र के पूंजीगत व्यय में उल्लेखनीय गिरावट आई थी, लेकिन 2000 के दशक के मध्य में और फिर कोविड के बाद की अवधि में इसमें उल्लेखनीय वृद्धि हुई। राज्य-स्तरीय पूंजीगत व्यय में आम तौर पर लंबे समय में वृद्धि हुई है, जो राज्यों के लिए बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक वस्तुओं में निवेश करने की बढ़ती अनिवार्यता को दर्शाता है, जो बेहतर राजस्व प्रवाह (विशेष रूप से उच्च कर हस्तांतरण के बाद) द्वारा पूरक है। केंद्र और राज्यों दोनों के लिए विकास व्यय, 1990 के दशक में शुरुआती गिरावट के बाद, नीति प्राथमिकताओं और मैक्रो-राजकोषीय वातावरण दोनों से प्रभावित होकर समय के साथ धीरे-धीरे स्थिर या बढ़ा है। ब्याज भुगतान, जो 1980 और 1990 के दशक की शुरुआत में ऋण बोझ के कारण शुरू में अधिक था, निरंतर विकास और राजकोषीय समेकन की अवधि के दौरान केंद्र और राज्यों दोनों के लिए धीरे-धीरे कम हो गया, हालांकि केंद्र के ब्याज भुगतान

संरचनात्मक रूप से राज्यों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण बने हुए हैं, विशेष रूप से कुल व्यय के सापेक्ष। इस पृष्ठभूमि के साथ, प्रत्येक चरण की प्रमुख विशेषताओं का अधिक विस्तार से विश्लेषण किया गया है।

चरण I (1991-92 से 1995-96): उदारीकरण के बाद के शुरुआती सुधार और राजकोषीय पुनर्गठन

यह चरण भारत के भुगतान संतुलन संकट से उदार आर्थिक ढांचे की ओर संक्रमण के साथ मेल खाता है। केंद्र ने औद्योगिक लाइसेंसिंग को खत्म कर दिया, आयात नियंत्रण में ढील दी और अधिक वैश्विक एकीकरण को बढ़ावा दिया। जबकि इन उपायों ने आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा दिया, सार्वजनिक वित्त पर दबाव बना रहा।

केंद्र का पूंजीगत व्यय 1991-92 में सकल घरेलू उत्पाद के 1.7 प्रतिशत से घटकर 1995-96 में 1.2 प्रतिशत रह गया। इस बीच, राजस्व व्यय-से-पूंजीगत व्यय (आरईसीओ) अनुपात 7.5 से बढ़कर 9.9 हो गया, जो पूंजी निवेश के सापेक्ष चालू व्यय में वृद्धि को दर्शाता है। इसी तरह, स्थिरीकरण प्रक्रिया के दौरान विवेकाधीन व्यय को नियंत्रित करने के प्रयासों के बीच, विकास व्यय (डीई) सकल घरेलू उत्पाद के 2.0 प्रतिशत तक गिर गया। इन व्यय प्रतिबंधों के बावजूद, ब्याज भुगतान (आईपी) उच्च स्तर पर रहा, जो सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 4.0 - 4.2 प्रतिशत था, और कुल व्यय में उनका हिस्सा 23.9 प्रतिशत से बढ़कर 28.1 प्रतिशत हो गया।

राज्य वित्त ने भी कुछ भिन्नता के साथ इसी तरह का पैटर्न प्रदर्शित किया। पूंजीगत व्यय सकल घरेलू उत्पाद के 1.5 प्रतिशत के आसपास रहा, जिसे आरईसीओ अनुपात में मामूली सुधार से समर्थन मिला, जो 8.5 से थोड़ा कम होकर 7.8 हो गया। फिर भी, विकास व्यय सकल घरेलू उत्पाद के 11.3 से घटकर 9.4 प्रतिशत हो गया; इस अवधि के दौरान केंद्र से हस्तांतरण में कमी आई। ब्याज भुगतान में भी वृद्धि हुई, जो कुल व्यय के हिस्से के रूप में 10.7 से बढ़कर 12.7 प्रतिशत हो गया, जो बढ़ते ऋण-सेवा दायित्वों को दर्शाता है और सुधार के बाद के शुरुआती वर्षों के दौरान राज्य-स्तरीय राजकोषीय स्थिति में धीरे-धीरे तनाव का संकेत देता है।

चरण II (1996-97 से 2002-03): पूर्व-एफआरबीएम समेकन

इस अवधि के दौरान, सरकारें बढ़ती हुई वेतन बिलों से जूझती रहीं - केंद्र में पांचवें वेतन आयोग के पुरस्कार और कई राज्यों में समानांतर संशोधनों से प्रेरित - सुस्त राजस्व वृद्धि की पृष्ठभूमि के खिलाफ। इन दबावों ने दीर्घकालिक प्राथमिकताओं में निवेश करने की क्षमता को बाधित किया, जो दोनों स्तरों पर लगातार कम पूंजीगत व्यय में परिलक्षित होता है। हालाँकि केंद्र का पूंजीगत व्यय कभी-कभी सकल घरेलू उत्पाद के 1 प्रतिशत से ऊपर चला गया, लेकिन वेतन, सब्सिडी, ब्याज और प्रशासनिक व्यय पर अधिक व्यय के कारण विकास व्यय पर हावी होने के कारण आरईसीओ अनुपात नियमित रूप से 10 से अधिक हो गया। राज्यों को भी पूंजीगत व्यय की रक्षा करना लगातार मुश्किल होता जा रहा था।

इसके अलावा, ब्याज भुगतान ने कुल व्यय का एक बड़ा हिस्सा ग्रहण कर लिया, जिससे सार्वजनिक ऋण प्रबंधन में संरचनात्मक असंतुलन उजागर हुआ। केंद्र के लिए, कुछ वर्षों में ब्याज कुल व्यय का लगभग 30 प्रतिशत या उससे अधिक था, जबकि कई राज्यों के लिए, यह हिस्सा चरण के अंत तक 10 प्रतिशत से थोड़ा अधिक से बढ़कर लगभग पाँचवाँ हो गया। इसने सरकारों के विकास व्यय को और अधिक बढ़ा दिया, जिससे विकास और गैर-विकास व्यय का अनुपात और भी कम हो गया। भारी ऋण-सेवा लागत और सीमित राजकोषीय स्थान के इस माहौल ने समेकन के लिए संस्थागत तंत्र पर नए सिरे से बहस को बढ़ावा दिया, जिसका समापन 2000 में राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) विधेयक की शुरूआत के साथ हुआ। हालाँकि औपचारिक अधिनियमन 2003 में हुआ था, लेकिन इस चरण के दौरान रखी गई विधायी नींव ने नियम-आधारित राजकोषीय अनुशासन की आवश्यकता की बढ़ती मान्यता का संकेत दिया।

चरण III (2003-04 से 2007-08): एफआरबीएम कार्यान्वयन और विकास में तेजी

यह चरण भारत के राजकोषीय परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जो केंद्र में 2003 के एफआरबीएम अधिनियम के कार्यान्वयन और अधिकांश राज्यों द्वारा इसी तरह के राजकोषीय उत्तरदायित्व विधानों (एफआरएल) को अपनाने से प्रेरित था।

ये सुधार वैश्विक आर्थिक विस्तार, बढ़ते व्यापार एकीकरण और निजी क्षेत्र की बढ़ती गतिशीलता से प्रेरित मजबूत जीडीपी वृद्धि की अवधि के साथ मेल खाते हैं। परिणामी राजस्व उछाल ने केंद्र और राज्यों दोनों को सार्वजनिक निवेश को मजबूत करने, व्यय संरचना में सुधार करने और ऋण-संबंधी बोझ को कम करने में सक्षम बनाया।

केंद्र में, राजकोषीय उत्तरदायित्व सुधारों ने व्यय प्राथमिकताओं के संरचनात्मक पुनर्संतुलन को सुगम बनाया। पूंजीगत व्यय लगभग दोगुना हो गया, जो 2003-04 में सकल घरेलू उत्पाद के 1.2 प्रतिशत से बढ़कर 2007-08 में 2.2 प्रतिशत हो गया, जिससे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के विकास और दीर्घकालिक विकास-सक्षम परियोजनाओं को सहायता मिली। इस अवधि के दौरान आरईसीओ अनुपात 10.6 से 5.6 तक तेजी से गिर गया, जो उत्पादक निवेश के लिए बढ़े हुए राजकोषीय स्थान को दर्शाता है। विकास व्यय, सकल घरेलू उत्पाद के 6-7 प्रतिशत पर स्थिर रहते हुए, सामाजिक और आर्थिक बुनियादी ढांचे पर अधिक ध्यान देने के साथ गुणात्मक सुधार देखा गया। इसके अतिरिक्त, केंद्र का ब्याज भुगतान बोझ कम हुआ, जो 2003-04 में सकल घरेलू उत्पाद के 4.4 प्रतिशत से घटकर 2007-08 में 3.5 प्रतिशत हो गया, और कुल व्यय में इसका हिस्सा 26.3 प्रतिशत से घटकर 24.0 प्रतिशत हो गया, जो बेहतर ऋण प्रबंधन का संकेत देता है।

12वें वित्त आयोग की सिफारिशों के बाद कर हस्तांतरण और अनुदान में सुधार के कारण राज्यों के राजकोषीय समेकन और राजस्व में उछाल को बढ़ावा मिला। पूंजीगत व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, पूंजीगत व्यय जीडीपी के 1.9 प्रतिशत से बढ़कर 2.5 प्रतिशत हो गया, जो राजकोषीय बाधाओं के बावजूद बुनियादी ढांचे के विकास का समर्थन करने की राज्यों की क्षमता को दर्शाता है। आरईसीओ अनुपात में लगातार सुधार हुआ, जो बेहतर बजटीय प्रबंधन और व्यय दक्षता को दर्शाता है। विकास व्यय, जो जीडीपी का औसतन लगभग 9.5 प्रतिशत रहा, ने कई राज्यों में लचीलापन और मामूली वृद्धि दिखाई, जो शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के लिए बढ़े हुए आवंटन से प्रेरित था। इसके अलावा, जीडीपी के हिस्से के रूप में ब्याज भुगतान में गिरावट आई, जबकि कुल व्यय में उनका अनुपात 17.9 प्रतिशत से घटकर 13.6 प्रतिशत हो गया।

राजकोषीय सुधारों और उच्च आर्थिक विकास द्वारा समर्थित इन सुधारों ने सरकार के दोनों स्तरों पर विस्तारित सार्वजनिक निवेश और उच्चतर व्यय गुणवत्ता के लिए आवश्यक राजकोषीय गुंजाइश पैदा की।

चरण IV (2008-09 से 2012-13): वैश्विक वित्तीय संकट और प्रतिचक्रीय समायोजन

वैश्विक वित्तीय संकट (जीएफसी) की शुरुआत ने भारत को, अन्य देशों की तरह, अपनी राजकोषीय प्राथमिकताओं को पुनः निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया, मध्यम अवधि के समेकन लक्ष्यों के साथ प्रतिचक्रीय प्रोत्साहन को संतुलित किया। यद्यपि घरेलू बैंक और बाजार उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में अपेक्षाकृत सुरक्षित थे, वैश्विक मांग और ऋण प्रवाह में कमी ने अल्पकालिक विकास मंदी पैदा की। केंद्र ने घरेलू खपत को बढ़ाने, महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश को बनाए रखने और बाहरी झटकों से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए प्रोत्साहन उपायों - मुख्य रूप से कर कटौती और लक्षित खर्च - की शुरुआत की। इन नीतिगत विकल्पों ने राजकोषीय घाटे को बढ़ाया और अस्थायी रूप से व्यय प्रोफाइल को समर्थन उपायों की ओर झुका दिया। केंद्र का पूंजी परिव्यय शुरू में अपने संकट-पूर्व स्तर से नीचे चला गया और धीरे-धीरे ही ठीक हुआ। इस बीच, विकास व्यय ने संसाधनों के बढ़ते हिस्से को अवशोषित किया, जिससे सामाजिक और क्षेत्रीय पहल सक्षम हुईं, लेकिन समग्र राजकोषीय स्थान पर भी दबाव पड़ा। यद्यपि सकल घरेलू उत्पाद के हिस्से के रूप में ब्याज भुगतान, संकट-पूर्व प्रक्षेपवक्र के सापेक्ष मामूली रूप से कम हुआ - आंशिक रूप से पहले के ऋण प्रबंधन सुधारों से लाभ के कारण - इस कमी ने कुल व्यय में ब्याज भुगतान के हिस्से को काफी हद तक नहीं बदला, जो कम बीस के आसपास स्थिर रहा।

राज्यों ने राजस्व की कमी से जूझते हुए प्रतिचक्रीय रणनीतियां भी अपनाईं - जैसे कि बड़े पैमाने पर कल्याणकारी कार्यक्रम। पूंजीगत व्यय संकट-पूर्व शिखर से कम हुआ। फिर भी, अधिक राजस्व व्यय की ओर उप-राष्ट्रीय बदलाव ने चल रहे राजकोषीय सुधारों को पटरी से नहीं उतारा। कई राज्यों में ऋण पुनर्गठन पहल और एफआरबीएम-जैसे ढाँचों के संस्थागतकरण ने ब्याज भुगतान को कम करने में मदद की,

जिससे सामाजिक कार्यक्रमों के लिए कुछ राजकोषीय स्थान खाली हुआ। नतीजतन, भले ही सार्वजनिक निवेश योजनाएँ संकट-पूर्व स्तरों पर पूरी तरह से ठीक नहीं हुईं, लेकिन समन्वित प्रोत्साहन उपायों और विवेकपूर्ण ऋण प्रबंधन पर जोर देने से राज्यों को अपने राजकोषीय स्वास्थ्य के दीर्घकालिक क्षरण को रोकने में मदद मिली।

चरण V (2013-14 से 2019-20): संरचनात्मक सुधार और जीएसटी रोलआउट

इस अवधि के दौरान, भारत ने कई परिवर्तनकारी नीतिगत पहल कीं - जिसमें 14वें वित्त आयोग द्वारा विनिवेश में उल्लेखनीय वृद्धि (विभाज्य पूल के 32 प्रतिशत से 42 प्रतिशत तक) और 2017 में माल और सेवा कर (जीएसटी) की शुरूआत शामिल है। इन सुधारों का उद्देश्य राजकोषीय संघवाद को मजबूत करना, अप्रत्यक्ष कराधान को सुव्यवस्थित करना और वित्तीय पारदर्शिता को सुदृढ़ करना था। हालाँकि, अंतरिम अवधि में, कुछ संक्रमणकालीन अनिश्चितताएँ थीं, विशेष रूप से राज्यों के लिए जो नए राजस्व-साझाकरण व्यवस्था और मुआवज़ा ढाँचों को अपना रहे थे।

केंद्रीय स्तर पर, पूंजीगत व्यय आम तौर पर सकल घरेलू उत्पाद के 1.3 और 1.6 प्रतिशत के बीच रहा, जो बुनियादी ढांचे और परिसंपत्ति निर्माण के लिए एक मापा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आरईसीओ अनुपात में वृद्धिशील सुधारों के बावजूद, राज्यों को हस्तांतरण बढ़ने के कारण केंद्र का विकास व्यय कम हो गया। जबकि ब्याज भुगतान सकल घरेलू उत्पाद के 3.0 से 3.3 प्रतिशत के आसपास मँडरा रहा था, वे कुल व्यय का एक बड़ा हिस्सा अवशोषित करना जारी रखते थे, जिससे विकासात्मक व्यय के लिए जगह सीमित हो जाती थी। 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के बाद संसाधन आवंटन में बदलाव के कारण केंद्र और राज्यों के बीच विकास व्यय में अंतर बढ़ गया। उच्च हस्तांतरित निधि वाले राज्यों ने सामाजिक क्षेत्र व्यय और पूंजीगत परिव्यय को प्राथमिकता दी। अतिरिक्त हस्तांतरित संसाधनों के साथ-साथ मुख्य बुनियादी ढांचे और सामाजिक कार्यक्रमों पर नीतिगत फोकस ने विकास व्यय को सकल घरेलू उत्पाद के 10 से 12 प्रतिशत के आसपास बनाए रखने में मदद की। ब्याज भुगतान काफी हद तक नियंत्रित रहा, जो विवेकपूर्ण उधार प्रथाओं और अपेक्षाकृत स्थिर ऋण प्रोफाइल का संकेत देता है।

चरण VI (2020-21 से 2024-25): महामारी का झटका और बुनियादी ढांचे पर केंद्रित रिकवरी

इस अवधि में कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न गहन आर्थिक व्यवधान और उसके बाद बुनियादी ढांचे के नेतृत्व वाले पुनरुद्धार की ओर बदलाव शामिल है। केंद्र ने बड़े पैमाने पर राजकोषीय हस्तक्षेपों - प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण, आपातकालीन स्वास्थ्य आवंटन, तनावग्रस्त क्षेत्रों के लिए तरलता उपायों - के साथ संकट का जवाब दिया, जबकि विकास को प्रोत्साहित करने के लिए उच्च पूंजीगत व्यय की ओर रुख किया। यह नीति विकल्प जीडीपी में पूंजीगत व्यय के बढ़ते हिस्से (2020-21 में 1.6 प्रतिशत से 2024-25 (बीई) तक 2.8 प्रतिशत) और आरईसीओ अनुपात में समवर्ती गिरावट में परिलक्षित होता है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि केंद्र का प्रभावी पूंजीगत व्यय (यानी, पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए अनुदान पर परिव्यय सहित) 2024-25 (बीई) में जीडीपी के 4.6 प्रतिशत पर रखा गया था। इस प्रकार, राजकोषीय संरचना अधिक निवेश-केंद्रित हो गई है, जिसका उद्देश्य रोजगार और औद्योगिक पुनरुद्धार पर बुनियादी ढांचे के गुणक प्रभावों का दोहन करना है। हालांकि महामारी से संबंधित उधार में वृद्धि हुई, लेकिन उच्च ऋण-सेवा लागत प्रबंधनीय रही।

राज्य स्तर पर, विस्तारित उधार सीमा और राजस्व की कमी ने राजकोषीय निर्णयों को आकार दिया। कई राज्यों ने स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सुरक्षा और पूंजीगत कार्यों में अतिरिक्त संसाधनों को लगाया, जिससे महामारी शमन और मध्यम अवधि के विकासात्मक उद्देश्यों दोनों को प्रभावी ढंग से बढ़ावा मिला। परिणामस्वरूप, राज्य-स्तरीय पूंजीगत व्यय में वृद्धि हुई, जिससे आरईसीओ अनुपात में कमी आई और रिकवरी के लिए आवश्यक क्षेत्रों में विकासात्मक व्यय को बनाए रखा गया। ऋण स्टॉक जमा होने के बावजूद, अधिकांश राज्यों ने स्थिर ब्याज भार बनाए रखा, जो विवेकपूर्ण ऋण प्रबंधन प्रथाओं और अपेक्षाकृत सौम्य ब्याज दर के माहौल को दर्शाता है। कुल मिलाकर, यह अवधि राजकोषीय नीति की आधारशिला के रूप में लक्षित बुनियादी ढांचे के निवेश की ओर एक रणनीतिक बदलाव को रेखांकित करती है, जिसे केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर सावधानीपूर्वक संतुलित उधार रणनीतियों द्वारा समर्थित किया जाता है।

पिछले विश्लेषण से भारत में सार्वजनिक व्यय की बदलती प्रकृति के बारे में जानकारी मिलती है। हालाँकि, संकेतकों की बहुलता और उनके विभिन्न प्रक्षेप पथ, दीर्घकालिक विकास और स्थिरता को बढ़ावा देने में सार्वजनिक संसाधनों की प्रभावशीलता का आकलन करना चुनौतीपूर्ण बनाते हैं। समग्र सूचकांकों का उपयोग अक्सर कई, परस्पर जुड़े कारकों को एक एकल, सुव्यवस्थित उपाय में संयोजित और सारांशित करने के लिए किया जाता है, जिससे विभिन्न अवधियों में सार्थक तुलना और प्रवृत्ति आकलन की सुविधा मिलती है (चेन एट अल, 2021)। इन संकेतकों को एक एकल मात्रात्मक बेंचमार्क में एकीकृत करके, ऐसा सूचकांक समय के साथ बदलावों को ट्रैक करने के लिए एक स्पष्ट, वस्तुनिष्ठ ढांचा प्रदान कर सकता है (बदुल्लाहवेगे और एटिगेल, 2021)। निम्नलिखित अनुभाग सार्वजनिक व्यय की गुणवत्ता (QPE) सूचकांक के निर्माण की रूपरेखा तैयार करते हैं और इसके प्रदर्शन का विश्लेषण करते हैं, इस पर प्रकाश डालते हैं कि यह सार्वजनिक व्यय की गुणवत्ता की बहुआयामी प्रकृति को कितनी प्रभावी ढंग से दर्शाता है।

IV. सार्वजनिक व्यय सूचकांक की गुणवत्ता: डेटा और कार्यप्रणाली

केंद्र और राज्यों दोनों के लिए सार्वजनिक व्यय की गुणवत्ता (क्यूपीई) सूचकांक का निर्माण और विश्लेषण करने के लिए 1991- 92 से 2022 - 23 तक के वार्षिक राजकोषीय आंकड़ों का उपयोग किया गया है। डेटासेट में प्रमुख चर शामिल हैं जो सार्वजनिक खर्च की गुणवत्ता का प्रतिनिधित्व करते हैं। डेटा भारतीय अर्थव्यवस्था पर रिज़र्व बैंक के डेटाबेस (DBIE) और रिज़र्व बैंक के वार्षिक प्रकाशन "राज्य वित्त: बजट का एक अध्ययन" के साथ प्रकाशित ई-स्टेट्स डेटाबेस से प्राप्त किए गए हैं। चर में शामिल हैं (i) पूंजीगत परिव्यय से जीडीपी (सीओजीडीपी) अनुपात, (ii) राजस्व व्यय से पूंजीगत परिव्यय (आरईसीओ) अनुपात, (iii) विकास व्यय से जीडीपी (डीईजीडीपी) अनुपात, (iv) विकास व्यय से कुल व्यय (डीईटीई) अनुपात, और (v) ब्याज भुगतान से कुल व्यय (आईपीटीई) अनुपात। आरईसीओ का व्युत्क्रम वर्तमान वित्तीय स्थान पर पिछले उधारों के प्रभाव को दर्शाता है। उच्च IPTE अनुपात या तो उच्च ब्याज भुगतान या कम कुल व्यय आधार (या दोनों) से उत्पन्न हो सकता है। किसी भी परिदृश्य में, उच्च IPTE पूंजी और विकासात्मक व्यय के लिए कम राजकोषीय हेडरूम को दर्शाता है। वर्षों और चरों में तुलना सुनिश्चित करने के लिए, डेटा को z-स्कोर परिवर्तन का उपयोग करके मानकीकृत किया गया है:

$$z_{it} = \frac{x_{it} - \mu_i}{\sigma_i}$$

जहाँ z_{it} में चर i का मानकीकृत मान है, t, μ_i और σ_i चर i के माध्य और मानक विचलन हैं।

इन चरों को व्यय गुणवत्ता के एकल माप में एकत्रित करने के लिए, एक गतिशील कारक मॉडल (DFM) का उपयोग किया गया था। DFM विशेष रूप से कई देखे गए चरों को एक एकल अव्यक्त कारक में संयोजित करने के लिए उपयुक्त हैं जो व्यय गुणवत्ता की अंतर्निहित गतिशीलता को पकड़ता है। वे मानते हैं कि कुछ संख्या में अनिर्धारित कारक देखे गए समय श्रृंखला के एक बड़े सेट में सामान्य पैटर्न की व्याख्या कर सकते हैं (स्टॉक और वॉटसन, 2016)। इस अध्ययन में, DFM से प्राप्त समग्र सूचकांक सार्वजनिक व्यय की समग्र गुणवत्ता को मापने और ट्रैक करने का एक तरीका प्रदान करता है। मॉडल बहुभिन्नरूपी समय श्रृंखला की जटिलता को बाहरी चर और छिपे हुए कारकों के रैखिक संयोजनों के रूप में देखे गए चरों को व्यक्त करके कम करता है। गणितीय रूप से, DFM मानकीकृत चरों में साझा रुझानों को कैप्चर करने वाले एक अव्यक्त कारक (f_t) *को निकालता है:*

$$y_t = \lambda_i f_t + \epsilon_t$$

$$f_t = \varnothing_i f_{t-1} + \mu_t$$

जहाँ y_t व्यय की गुणवत्ता के संकेतकों का एक सदिश है, λ_i और $\varnothing_i$ पैरामीटर हैं और ϵ_t और μ_t त्रुटि पद हैं। ये छिपे हुए कारक एक सदिश स्वप्रतिगामी प्रक्रिया का पालन करते हैं। स्टॉक और वॉटसन (1989, 1991) का अनुसरण करते हुए, DFM के मापदंडों का अनुमान कलमन फ़िल्टर का उपयोग करके लगाया जाता है, ताकि लॉग संभावना दृष्टिकोण को प्राप्त और कार्यान्वित किया जा सके। केंद्र और राज्यों के लिए अलग-अलग सूचकांक बनाए गए, जिसमें स्थिरता बनाए रखने के लिए एक ही पद्धति का उपयोग किया गया।

अनुमानित कारक भार, सरकारी व्यय की अंतर्निहित गुणवत्ता के साथ विभिन्न व्यय घटकों के संबंध को उजागर करते हैं (अनुबंध सारणी 1)। उल्लेखनीय रूप से, पूंजीगत व्यय और विकास व्यय महत्वपूर्ण भार प्रदर्शित करते हैं, जो व्यय के स्वरूप को आकार देने में उनकी केंद्रीय भूमिका को दर्शाता है। अप्रकट कारक की निरंतरता व्यय गुणवत्ता में एक स्थिर अंतर्निहित संरचना को इंगित करती है, जो समय के साथ सूचकांक की संगतता को मजबूत बनाती है।

प्रतिगमन मॉडल

केंद्रीय और समग्र राज्य, दोनों स्तरों पर सूचकांक के अलावा, परिणाम चरों के साथ अपने संबंधों का आकलन करने के लिए अलग-अलग राज्यों के लिए भी सूचकांक की गणना की जाती है। ग्लोबल डेटा लैब से प्राप्त उप-राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा और स्वास्थ्य पर मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) को परिणाम चर के रूप में माना जाता है। एचडीआई स्वास्थ्य सूचकांक और एचडीआई शिक्षा सूचकांक के लिए दो प्रतिगमन समीकरणों का अलग-अलग अनुमान लगाया गया है। पैनल फ्रेमवर्क में फिक्स्ड इफेक्ट्स मॉडल का उपयोग प्रतिगमन समीकरणों का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। डेटा की उपलब्धता और संगति के कारण, 2001-02 से 2022-23 की अवधि के दौरान 16 प्रमुख राज्यों2 के डेटा पर विचार किया गया है। व्यय सूचकांक की गुणवत्ता के अलावा, मुख्य प्रतिगमन समीकरण में प्रति व्यक्ति आय और सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) में कृषि का हिस्सा शामिल है, जिसे नियंत्रण चर के रूप में लिया जाता है क्योंकि अर्थव्यवस्था की संरचना और राज्यों के आय स्तर से सामाजिक परिणामों पर प्रभाव पड़ने की उम्मीद है।

$$y_{it} = \alpha + \beta_1 QPE_{it} + \beta_2\, Per\ capita\ income_{it} + \beta_3 Agriculture\ share_{it} + \mu_{it}$$

जहाँ समय 't' पर राज्य 'i' के लिए y_{it} स्वास्थ्य या शिक्षा का मानव विकास सूचकांक है, QPE_{it}, समय 't' पर राज्य 'i' के लिए सरकारी व्यय की गुणवत्ता का सूचकांक है, $Per\ capita\ income_{it}$ और $Agriculture\ share_{it}$ समय 't' पर राज्य 'i' के लिए क्रमशः राज्यों की अर्थव्यवस्था के आय स्तर और संरचना को दर्शाते हैं। β प्रतिगमन गुणांकों को और μ_{it} एरर टर्म को संदर्भित करता है।

V. अनुभवजन्य निष्कर्ष

केंद्र और राज्यों के लिए क्यूपीई सूचकांक प्रवत्तियाँ

क्यूपीई सूचकांक का क्रमिक विकास, पिछले खंड में चर्चा किए गए चरों के ऐतिहासिक पैटर्न के अनुरूप है। प्रारंभिक चरण

चार्ट 4: केंद्र के लिए सार्वजनिक व्यय की गुणवत्ता सूचकांक

स्रोत: आरबीआई स्टाफ अनुमान।

2 असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।

चार्ट 5: राज्यों के लिए सार्वजनिक व्यय सूचकांक की गुणवत्ता

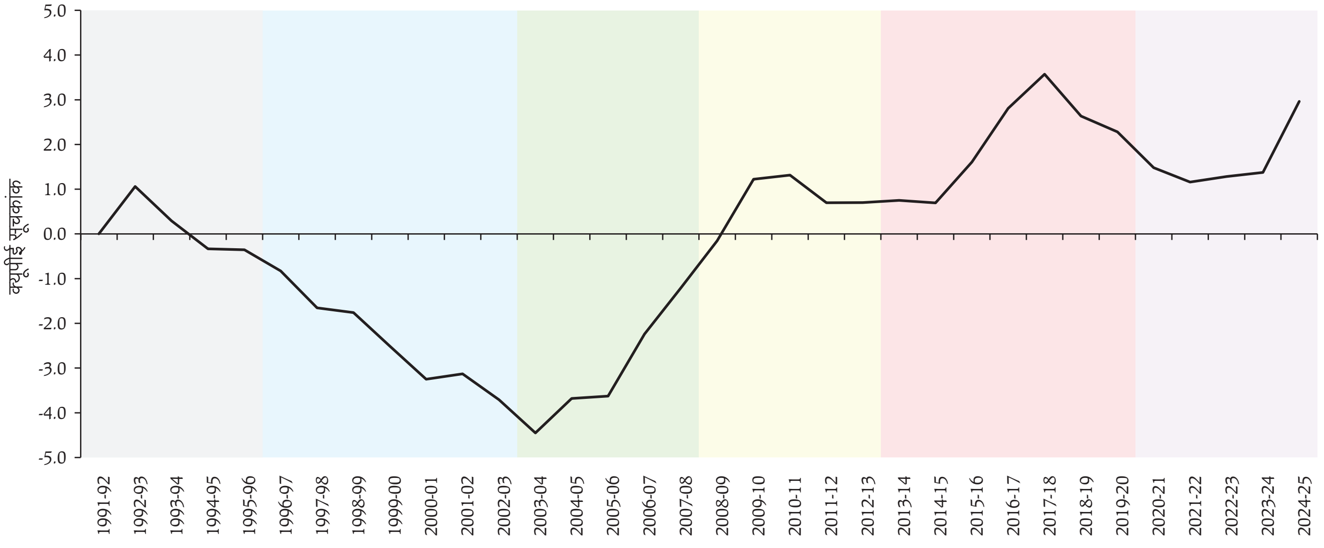

स्रोत: आरबीआई स्टाफ अनुमान।

के दौरान, दोनों स्तरों की सरकारों द्वारा सामना किए जाने वाले राजकोषीय दबावों के बीच केंद्र के सूचकांक (चार्ट 4) में थोड़ा सुधार हुआ, जबकि राज्यों के सूचकांक (चार्ट 5) में मामूली गिरावट आई। राजकोषीय सुदृढ़ता को प्राथमिकता दिए जाने के कारण सार्वजनिक निवेश में कमी आई। बाद के चरण में, दोनों सूचकांकों में तीव्र गिरावट देखी गई, जो पांचवें वेतन आयोग के कार्यान्वयन, बढ़ते ब्याज भुगतान और पूंजीगत परिव्यय पर राजस्व व्यय के निरंतर प्रभुत्व के संयुक्त प्रभाव को दर्शाती है।

2008 के वैश्विक वित्तीय संकट से पहले के वर्षों में राजकोषीय उत्तरदायित्व सुधारों और आर्थिक संवृद्धि ने तीसरे चरण के दौरान दोनों सूचकांकों में उल्लेखनीय सुधार किया। राज्यों को अधिक राजकोषीय हस्तांतरण और कर उछाल में वृद्धि से लाभ हुआ, जिससे बेहतर राजकोषीय परिणाम सामने आए। यह चरण राजकोषीय विवेक और आर्थिक वृद्धि के फायदे दर्शाता है। हालाँकि, 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट ने केंद्र को प्रोत्साहन पैकेजों सहित प्रतिचक्रीय राजकोषीय उपायों को अपनाने के लिए प्रेरित किया, जिससे घाटा अस्थायी रूप से बढ़ गया। बाद के वर्षों में, समेकन प्रयासों ने सूचकांकों को नियंत्रित किया। राज्यों के लिए, पूंजीगत परिव्यय संकट-पूर्व उच्चतम स्तर से कम हो गया, हालाँकि राजस्व व्यय में वृद्धि – जो कि विशेष रूप से सब्सिडी के कारण थी - चिंता का विषय बनी रही।

अगले चरण में राज्यों के सूचकांक में सुधार देखा गया, जो 14वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं द्वारा प्रेरित था, जिसने राज्यों को संसाधन हस्तांतरण में उल्लेखनीय वृद्धि की। इसने राज्य स्तर पर विकास व्यय को बढ़ाया, लेकिन केंद्र के व्यय हिस्से में एक साथ गिरावट आई। इस अवधि के दौरान, 2017 में वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) की शुरूआत ने राजस्व-सहभाजन ढांचे को मौलिक रूप से बदल दिया। हालाँकि इन विकासों ने शुरू में राज्यों को लाभान्वित किया, लेकिन केंद्र को राजस्व की कमी और सब्सिडी के दबाव से बढ़ती राजकोषीय चुनौतियों का सामना करना पड़ा।

कोविड-19 महामारी के कारण अभूतपूर्व राजकोषीय प्रोत्साहन उपाय किए गए, जिससे शुरू में घाटा बढ़ गया। हालांकि, सार्वजनिक निवेश पर नए सिरे से जोर देने और 2021-22 से केंद्रीय बजट में पूंजीगत व्यय पर अधिक ध्यान देने से बाद में बहाली को समर्थन मिला। राज्यों ने सुदृढ़ता

दर्शायी, विशेषकर 2010 के बाद, और बढ़े हुए हस्तांतरण एवं जीएसटी की शुरूआत से सहायता मिली। प्रमुख सुधार - जैसे कि राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम और जीएसटी - ने राजकोषीय परिणामों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो स्थायी लोक वित्त के लिए संरचनात्मक उपायों के महत्व को उजागर करते हैं।

क्यूपीई सूचकांक और मानव विकास परिणाम

क्यूपीई सूचकांक मजबूत आर्थिक और विकासात्मक परिणामों के साथ सकारात्मक संबंध दर्शाता है। केंद्र और राज्यों, दोनों के लिए बढ़ते क्यूपीई सूचकांक की अवधि उच्च जीडीपी वृद्धि और मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) के बेहतर निष्पादन के दौर के साथ अतिव्यापित होती है (चार्ट 6ए और 6बी)। इसके अलावा, राज्य अपने क्यूपीई सूचकांक और एचडीआई में सुधार के बीच अधिक निकटता प्रदर्शित करते हैं, जो विकास व्यय के लिए संसाधनों के प्रभावी आबंटन का संकेत देता है। क्यूपीई सूचकांक और प्रमुख परिणाम संकेतकों के बीच सकारात्मक सहसंबंध, सरकारी व्यय की गुणवत्ता और समग्र समष्टि-आर्थिक और विकासात्मक प्रगति के बीच महत्वपूर्ण संबंध को रेखांकित करता है।

चूंकि राज्यों के क्यूपीई सूचकांक और एचडीआई का आपस में अधिक मजबूत संबंध है, इसलिए परिणाम चर के रूप में शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ संबंध की जांच करने के लिए सरकारी व्यय की गुणवत्ता का राज्यवार सूचकांक तैयार किया जाता है। चूंकि एचडीआई सूचकांक में स्वास्थ्य, शिक्षा और आय के तीन उप-सूचकांक शामिल हैं, इसलिए हम राज्य-स्तरीय परिणाम चर को मापने के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सूचकांक का उपयोग करते हैं। राज्यवार क्यूपीई सूचकांक और परिणाम संकेतकों (स्वास्थ्य और शिक्षा सूचकांक) के बीच संबंध धनात्मक है (चार्ट 7)।

अनुभवजन्य रूप से संबंध स्थापित करने के लिए, शिक्षा और स्वास्थ्य सूचकांकों के लिए दो अलग-अलग प्रतिगमन मॉडलों का अनुमान लगाया गया है। जीएसडीपी में कृषि के

चार्ट 6: जीडीपी वृद्धि और एचडीआई सूचकांक के साथ क्यूपीई सूचकांक का संबंध

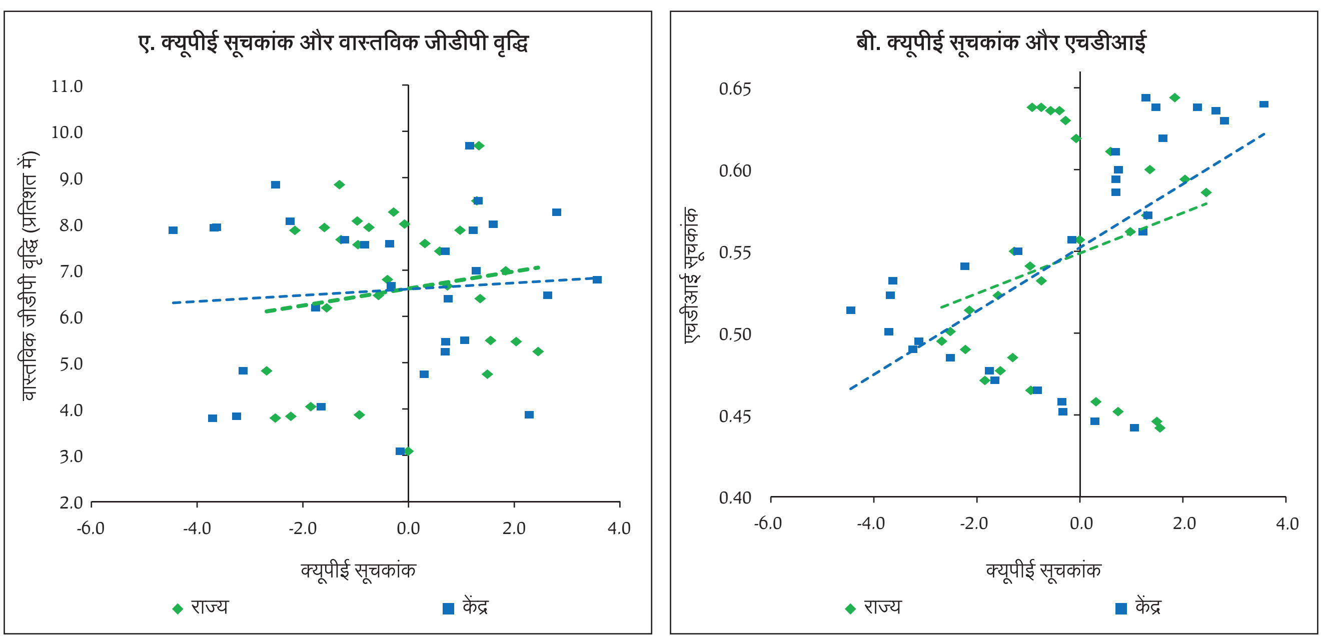

स्रोत: आरबीआई स्टाफ अनुमान।

चार्ट 7: राज्यों के क्यूपीई सूचकांक तथा एचडीआई स्वास्थ्य और शिक्षा सूचकांक

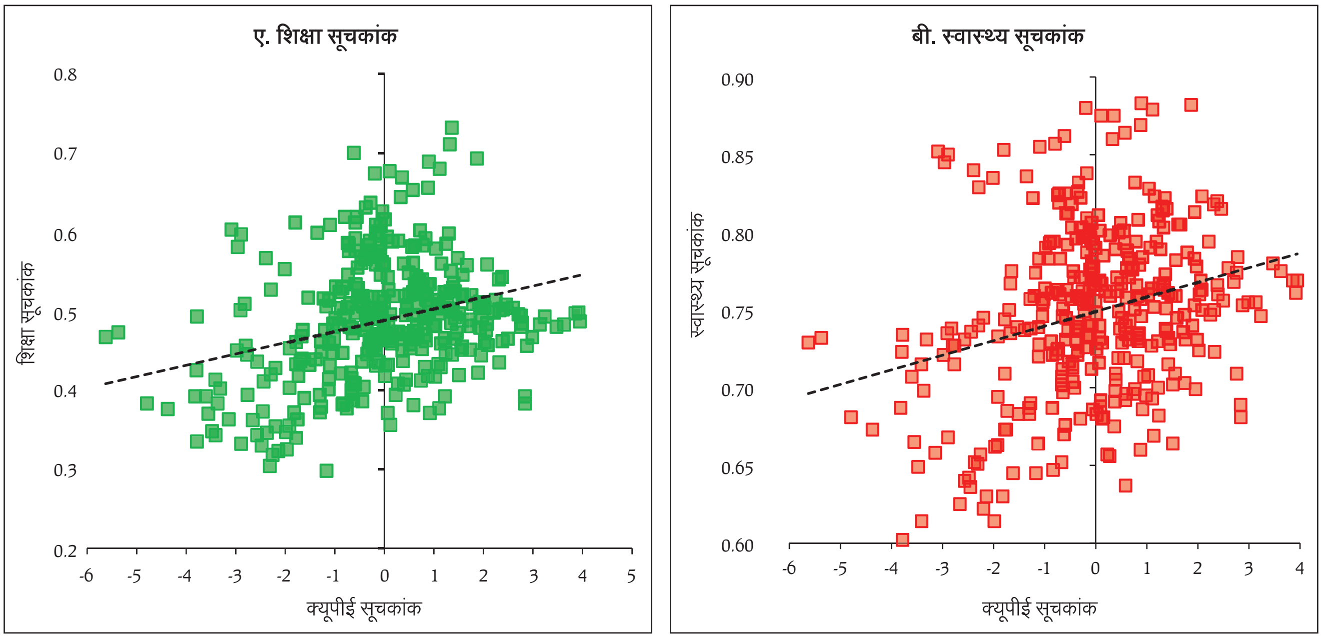

स्रोत: आरबीआई स्टाफ अनुमान।

हिस्से को छोड़कर सभी चर लघुगणक रूप में लिए गए हैं। प्रतिगमन में दो नियंत्रण चरों पर विचार किया गया है - प्रति व्यक्ति आय और जीएसडीपी में कृषि का हिस्सा, जो क्रमशः आर्थिक विकास के स्तर और राज्य की अर्थव्यवस्था की संरचना को दर्शाता है। इन दो चरों को नियंत्रित करते हुए, हम पाते हैं कि व्यय सूचकांक की गुणवत्ता का (स्वास्थ्य और शिक्षा सूचकांक द्वारा प्रॉक्सी किए गए) परिणाम संकेतकों पर धनात्मक प्रभाव पड़ता है (सारणी 1)।

सारणी 1: प्रतिगमन परिणाम

चर	शिक्षा सूचकांक	स्वास्थ्य सूचकांक
क्यूपीई (लॉग)	0.01* (0.00)	0.01* (0.00)
प्रति व्यक्ति जीएसडीपी (लॉग)	0.09* (0.01)	0.02* (0.00)
कृषि का हिस्सा	-0.003* (0.00)	-0.00* (0.00)
स्थिरांक	-1.28* (0.07)	-0.42* (0.05)
प्रेक्षण	336	336

टिप्पणी: (i) मानक त्रुटियाँ कोष्ठक में दी गई हैं।
(ii) * एक प्रतिशत के स्तर पर प्रतिगमन गुणांक के महत्व को इंगित करें।
स्रोत: आरबीआई स्टाफ अनुमान।

VI. निष्कर्ष

इस अध्ययन में किए गए विश्लेषण का उद्देश्य, 1991-92 से भारत में सरकारी व्यय के दिशा-पथ और गुणवत्ता का मूल्यांकन करना था, जिसमें यह समझने पर ध्यान केंद्रित किया गया था कि नीतिगत सुधारों, समष्टि-आर्थिक बदलावों और संकट के लिए प्रतिक्रियाओं ने व्यय संरचना तथा संवृद्धि, राजकोषीय स्थिरता और विकासात्मक परिणामों के लिए इसके निहितार्थों को कैसे प्रभावित किया। सरकारी व्यय (क्यूपीई) सूचकांक की गुणवत्ता का निर्माण करके, इस अध्ययन ने भारत के राजकोषीय विकास के विभिन्न चरणों में पूंजीगत परिव्यय, राजस्व व्यय, विकास व्यय और कर्ज-चुकौती बोझ के बीच परस्पर क्रिया का पता लगाते हुए व्यय दक्षता का आकलन करने का प्रयास किया।

विश्लेषण से पता चलता है कि भारत की व्यय संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं, जो संरचनात्मक सुधारों और बाह्य आघातों से प्रभावित हुए हैं। उदारीकरण के बाद के चरण (1991-95) में पूंजीगत और विकासात्मक व्यय की कीमत पर राजकोषीय सुदृढ़ता देखी गई, जबकि एफआरबीएम से पहले के वर्ष (1996-2003) बढ़ते कर्ज के बोझ और अवरुद्ध सार्वजनिक निवेश द्वारा चिह्नित थे। राजकोषीय उत्तरदायित्व ढांचे (2003-

08) के कार्यान्वयन के साथ उच्च पूंजीगत परिव्यय, बेहतर आरईसीओ अनुपात और कम ब्याज भुगतान हुआ, जिसने नियम-आधारित अनुशासन के लाभों को रेखांकित किया। बाद के चरणों ने वैश्विक वित्तीय संकट (2008-13) और जीएसटी के संक्रमणकालीन प्रभावों और बढ़े हुए राजकोषीय हस्तांतरण (2013-20) के दौरान प्रतिचक्रीय उपायों को संतुलित करने की चुनौतियों को उजागर किया। महामारी-जन्य चरण (2020-25) ने इंफ्रास्ट्रक्चर के नेतृत्व वाली बहाली की ओर एक रणनीतिक झुकाव दर्शाया, जिसमें केंद्र और राज्य, दोनों ने उच्च उधार के बावजूद संवृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए पूंजीगत व्यय को प्राथमिकता दी। क्यूपीई सूचकांक व्यय की गुणवत्ता और सामाजिक-आर्थिक परिणामों के बीच सकारात्मक सहसंबंध को रेखांकित करता है। उच्च क्यूपीई की अवधि, मजबूत जीडीपी वृद्धि और मानव विकास सूचकांक में सुधार के साथ संरेखित होती है। हालांकि, बाहरी आघातों के कारण अस्थायी रूप से लाभ में गिरावट आयी, जबकि सब्सिडी के दबाव और ब्याज के बोझ ने राजकोषीय संभावना को सीमित कर दिया। इसके अतिरिक्त, अलग-अलग राज्य स्तर पर व्यय की गुणवत्ता का शिक्षा और स्वास्थ्य परिणामों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

संक्षेप में, यह अध्ययन इस बात की पुष्टि करता है कि विवेकपूर्ण व्यय संरचना - पूंजी निर्माण और विकासात्मक परिव्यय को प्राथमिकता देना – संवृद्धि और इक्विटी को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। हाल ही में इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश और राजकोषीय अनुशासन पर जोर देने से समुत्थानशीलता बढ़ी है, और दीर्घकालिक धारणीयता हासिल करने के लिए रणनीतिक निवेश के साथ तत्काल खर्च की जरूरतों को संतुलित करना आवश्यक है। एफआरबीएम अधिनियम और जीएसटी जैसे संस्थागत सुधार राजकोषीय परिणामों को मजबूत करने में सहायक सिद्ध हुए हैं।

संदर्भ

Badullahewage, P., and Attygalle, D. (2021). "Modelling a Multilevel Data Structure Using a Composite Index". *American Journal of Applied Mathematics and Statistics*, 9(3), 75-82.

Bose, S., & Bhanumurthy, N. R. (2015). "Fiscal multipliers for India". *Margin: The Journal of Applied Economic Research*, 9(4), 379-401.

Chen, R., Ji, Y., Jiang, G., Xiao, H., Xie, R., and Zhu, P. (2021). "Composite Index Construction with Expert Opinion". *Journal of Business & Economic Statistics*, 41(1), 67–79. https://doi.org/10.1080/07350015.2021.2000418.

European Commission (2002). "Public finances in EMU — 2002". *European Economy No. 3/2002.*

European Commission (2004), "Public finances in EMU – 2004, Part IV: Quality of public finances: what role within the EU framework for economic policy coordination?", *European Economy No. 3/2004, pp. 179-217.*

Gale, W. G., & Orszag, P. R. (2003). "Economic effects of sustained budget deficits". *National Tax Journal.* 56(3), 463-485.

GoI (2017) "FRBM Review Committee Report".

Goyal, A., & Sharma, B. (2018). "Government expenditure in India: Composition and multipliers". *Journal of Quantitative Economics*, 16, 47-85.

Fan, S., and Brzeska, J. (2016). "Sustainable food security and nutrition: Demystifying conventional beliefs". *Global Food Security*, Volume 11.

IMF (1998). "Public Spending on Human Development" by Sanjeev Gupta, Benedict Clements, and Erwin Tiongson. *Finance and Development*, Number 3, Volume 35, September.

Jain, R. and Kumar, P. (2013). "Size of Government Expenditure Multipliers in India: A Structural VAR Analysis", *RBI Working Paper* 07 / 2013, September.

Misra, S., Behera, S. R., Seth, B. & Sood, S. (2021), "Fiscal Framework and Quality of Expenditure in India", RBI Bulletin, June.

Padhi, I., Mishra, R., Behera S. R. and Rath, D. P. (2023). "Quality of Public Expenditure and Economic Growth: An Empirical Assessment at Sub-National Level". RBI Bulletin, July.

Rath, D. P., Seth. B., Behera, S. R., and Suresh, A. K. (2023). "Capital Outlay of Indian States: An Empirical Assessment of its Role and Determinants". RBI Bulletin, April.

RBI (2024). "State Finances: A Study of Budgets of 2024-25".

Sever, I., Drezgic S. & Blazic, H. (2011). "Budget Spending and Economic Growth in Croatia – Dynamics and Relationships Over the Past Two Decades". Zbornikradova Ekonomskog fakulteta u Rijeci: časopis zaekonomsku teoriju i praksu, Vol. 9(2): 291–331.

Stock, J. H., & Watson, M. W. (1989), "New Indexes of Coincident and Leading Economic Indicators", *NBER Macroeconomics Annual*, 4: 351-394.

Stock, J. H., and M. W. Watson. (1991), "A Probability Model of the Coincident Economic Indicators". *In Leading Economic Indicators: New Approaches and Forecasting Records, ed. K. Lahiri and G. H. Moore, 63–89.* Cambridge: Cambridge University Press.

Stock, J. H., & Watson, M. W. (2016), "Dynamic Factor Models, Factor-augmented Vector Autoregressions, and Structural Vector Autoregressions in Macroeconomics", *In Handbook of Macroeconomics (Vol. 2, pp. 415-525).* Elsevier.

अनुबंध सारणी 1: केंद्र और राज्यों के लिए क्यूपीई सूचकांक के लिए फैक्टर लोडिंग

चर	फैक्टर लोडिंग	
	केंद्र	राज्य
पूंजीगत परिव्यय-जीडीपी अनुपात	0.28	0.25
पूंजीगत परिव्यय की तुलना में राजस्व व्यय अनुपात का प्रतिलोम	0.27	0.26
विकास व्यय-जीडीपी अनुपात	0.33	0.26
विकास व्यय-गैर-विकास व्यय अनुपात	0.44	0.23
कुल व्यय की तुलना में गैर-ब्याज भुगतान व्यय अनुपात	0.47	0.34

टिप्पणी: सभी फैक्टर लोडिंग एक प्रतिशत के स्तर पर सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण हैं।
स्रोत: आरबीआई स्टाफ अनुमान।

कृषि आपूर्ति शृंखला की गतिविधियां: रबी विपणन मौसम के अखिल भारतीय सर्वेक्षण से प्राप्त अंतर्दृष्टि

राजीब दास, ऋषभ कुमार, मोनिका सेठी, लव कुमार शांडिल्य और एलिस सेबेस्टियन ^

इस अध्ययन में किसानों, व्यापारियों और खुदरा विक्रेताओं को शामिल करते हुए अखिल भारतीय सर्वेक्षण के आधार पर प्रमुख रबी फसलों के संबंध में खुदरा खाद्य मूल्य निर्धारण की गतिशीलता का उल्लेख है। उपभोक्ता मूल्यों में किसानों की हिस्सेदारी चुनिंदा फसलों में 40 से 67 प्रतिशत के बीच होने का अनुमान है, जिसमें सबसे अधिक हिस्सा गेहूं उत्पादकों का है। खुदरा विक्रेताओं की कीमतें आमतौर पर व्यापारियों की तुलना में अधिक पाई जाती हैं। हालांकि कृषि आपूर्ति शृंखला भुगतान में नकद लेनदेन हावी है, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान ने पिछले समान सर्वेक्षणों की तुलना में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की है। अनुभवजन्य विश्लेषण से पता चलता है कि आपूर्ति शृंखला की अक्षमताओं और कटाई के बाद होने वाले नुकसानों को कम करने के लिए किए गए नीतिगत हस्तक्षेप, जैसे कि बाजार के बुनियादी ढांचे में वृद्धि और कोल्ड स्टोरेज क्षमता का विस्तार, किसानों और उपभोक्ताओं को लाभान्वित कर सकता है।

परिचय

खाद्य कीमतें कई अर्थव्यवस्थाओं, विशेष रूप से उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में समग्र मुद्रास्फीति का एक महत्वपूर्ण चालक बनी हुई हैं। साथ ही, आपूर्ति शृंखला के विभिन्न खंडों में पर्याप्त जानकारी - जो उचित नीति हस्तक्षेप विकसित करने में एक महत्वपूर्ण घटक है, की कमी मूल्य निर्धारण की गतिशीलता की समझ को सीमित करती है। आपूर्ति शृंखला के बारे में सूक्ष्म जानकारी प्राप्त होने से हितधारकों के बीच विश्वास बढ़ सकता है जिससे बाजार की दक्षता भी बढ़ती है (ईयू, 2024; भारत सरकार, 2025)। कृषि आपूर्ति शृंखला में कई प्रकार के लोग शामिल होते हैं, जैसे कि किसान, एग्रीगेटर, व्यापारी, कमीशन एजेंट, प्रोसेसर, थोक विक्रेता और खुदरा विक्रेता, जो उपभोक्ता तक अंतिम कृषि-वस्तु पहुँचाने में अपनी जरूरी भूमिका निभाते हैं। एक कुशल कृषि आपूर्ति शृंखला मूल्य निर्धारण तंत्र में पारदर्शिता बनाए रखती है और आपूर्ति शृंखला में लागत संरचनाओं, मार्जिन और मूल्य संवर्धन के बारे में जानकारी उपलब्ध कराती है। विभिन्न देशों ने कृषि आपूर्ति शृंखला की दक्षता में सुधार करने के लिए कदम उठाए हैं, जैसे कि खाद्य आपूर्ति शृंखला में किसानों की स्थिति को मजबूत करने और सभी हितधारकों के बीच विश्वास बनाने के लिए यूरोपीय संघ (ईयू) की ईयू एग्री फूड चेन ऑब्जरवेटरी(एएफसीओ) की पहल। हाल के वर्षों में भारत सरकार द्वारा कृषि आपूर्ति शृंखला में सुधार के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं, जैसे कि राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-एनएएम), किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन, कृषि अवसंरचना कोष, कृषि विपणन अवसंरचना योजना, एकीकृत कोल्ड चेन, खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण अवसंरचना योजना, सब्जियों और फलों के लिए व्यापक कार्यक्रम (विवरण अनुबंध 1 में)।

इस संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्रमुख खरीफ फसलों के संबंध में 2018 और 2022 में कृषि आपूर्ति शृंखला की गतिशीलता का अध्ययन करने के लिए अखिल भारतीय सर्वेक्षण किए थे। इन सर्वेक्षणों का उद्देश्य उपभोक्ता मूल्यों में किसानों की हिस्सेदारी का अनुमान लगाकर और नीतिगत उपायों की विभिन्न चुनौतियों और प्रभावकारिता के बारे में आपूर्ति शृंखला में प्रतिभागियों की धारणा को समझ कर प्रमुख खरीफ फसलों में खुदरा स्तर पर मूल्य निर्धारण प्रक्रिया का आकलन करना था। इस अध्ययन में प्रमुख रबी फसलें, यानी गेहूं, चना, मसूर और सरसों शामिल है। रबी सीजन में विशेष रूप से उगाई जाने वाली ये फसलें सीपीआई बास्केट का लगभग 5 प्रतिशत और

^ लेखक आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग (डीईपीआर), भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) से हैं। लेखक डॉ. डी. सुगंधी, क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था निगरानी प्रभाग और डीईपीआर क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकारियों के प्रति अखिल भारतीय सर्वेक्षण के संचालन में उनके द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी और सहायता के लिए आभारी हैं। लेख में व्यक्त किए गए विचार लेखकों के हैं और वे भारतीय रिज़र्व बैंक के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

सीपीआई खाद्य बास्केट का 11 प्रतिशत हिस्सा हैं। जहां तक संभव हुआ, 2018 के पिछले सर्वेक्षणों (भोई एवं अन्य, 2022) और (सुगंथी *एवं अन्य*, 2024) के निष्कर्षों की तुलना भी की गई है।

लेख का शेष भाग चार खंडों में विभाजित है। खंड II में रबी फसलों के महत्व और बदलते मार्जिन पर शैलीगत तथ्य दिए गए हैं। खंड III में सर्वेक्षण पद्धति और व्याप्ति का वर्णन है। खंड IV में मुख्य सर्वेक्षण निष्कर्ष और अनुभवजन्य विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है, और खंड V में निष्कर्षात्मक अवलोकन प्रस्तुत किए गए हैं।

II. शैलीगत तथ्य

रबी का मौसम

भारत के कृषि वर्ष (जुलाई-जून) में दो प्रमुख मौसम शामिल हैं: खरीफ और रबी।[3] खरीफ फसलों की बुवाई, जिसके लिए गर्म और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है, जून के पहले सप्ताह के आसपास, दक्षिण-पश्चिम मानसून की शुरुआत के साथ शुरू होती है और सितंबर के अंत तक समाप्त हो जाती है। रबी (सर्दियों) के मौसम की बुवाई अक्टूबर में शुरू होती है और फरवरी के पहले सप्ताह तक जारी रहती है और आमतौर पर इसके लिए ठंडी और शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है। वार्षिक खाद्यान्न उत्पादन में रबी सीजन का लगभग 48 प्रतिशत हिस्सा होता है।

फसल के हिसाब से देखें तो गेहूं, दलहनों में चना और मसूर, तथा तिलहनों में रेपसीड और सरसों रबी सीजन के दौरान उगाई जाने वाली प्रमुख रबी फसलें हैं। पिछले कुछ वर्षों में रबी फसलों का क्षेत्र और उपज में वृद्धि हुई है (चार्ट 1)।

पिछले दो वर्षों में रबी की फसलों को जलवायु परिवर्तन और भू-राजनीतिक तनावों[4] के संदर्भ में विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। खाद्य मुद्रास्फीति और अस्थिरता से जुड़े प्रभावों के साथ, इन चुनौतियों ने कई घरेलू और व्यापार-संबंधी नीतिगत हस्तक्षेपों को जरूरी बना दिया है। बाजार मध्यस्थों द्वारा अपने मार्कअप को तय करते समय उनके व्यवहार का विश्लेषण मुद्रास्फीति की गतिशीलता के आकलन और दृष्टिकोण को मजबूत करने में मदद कर सकता है।

2022 और 2018 के पिछले खरीफ सर्वेक्षणों के अनुरूप, द्वितीयक डेटा का उपयोग करके मार्जिन की गणना करके खुदरा और मंडी कीमतों के बीच मूल्य अंतर के रुझानों की जांच की गई है। खुदरा कीमतों के प्रतिशत के रूप में मार्जिन में, समय के साथ-साथ गेहूं में कुछ वृद्धि और अन्य फसलों में गिरावट के रूप में, भिन्नता रही है (चार्ट 2)। कई कारणों से फसलों का मार्जिन अलग-अलग हो सकता है, जैसे कि लेन-देन की लागत, परिवहन के दौरान अपव्यय, होल्डिंग चक्र की अवधि, मंडी-स्तरीय प्रतिस्पर्धा और बुनियादी ढांचा सुविधाएं।

चूंकि समग्र स्तर पर मार्जिन आम तौर पर आपूर्ति शृंखला (अर्थात, व्यापारी और खुदरा विक्रेता) के विभिन्न चरणों और उत्पादन, तथा उपभोग केंद्रों के बीच मार्क-अप[6] को शामिल नहीं करता, इसलिए खेत से खुदरा स्तर तक मूल्य निर्धारण का गहन विश्लेषण महत्वपूर्ण हो जाता है। जबकि 2022 और 2018 के पिछले सर्वेक्षण खरीफ फसलों पर केंद्रित थे, वर्तमान सर्वेक्षण में रबी फसलों को शामिल किया गया है, जिससे एक महत्वपूर्ण डेटा की कमी पूरी हो जाती है।

III. सर्वेक्षण का उद्देश्य, व्याप्ति और कार्यप्रणाली

सर्वेक्षण का उद्देश्य

वर्तमान अध्ययन में एक बाजार संरचना का प्रयोग किया गया है जिसमें व्यापारियों और खुदरा विक्रेताओं को किसानों

---

[1] पिछले दो खरीफ सर्वेक्षणों से ओवरलैप होने वाली फसलों में टमाटर, प्याज, आलू (टीओपी) और चावल शामिल हैं।

[2] निष्कर्ष नमूने में शामिल बातों और सर्वेक्षण के समय के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हो सकते हैं।

[3] फसल का तीसरा मौसम जायद (गर्मी) मौसम है। हालांकि, इसका हिस्सा बहुत कम है, और इस मौसम के लिए अलग से डेटा रिपोर्टिंग हाल ही में शुरू हुई है। यह अध्ययन डेटा की लंबी समय शृंखला प्राप्त करने के लिए इसे रबी के साथ जोड़ने की पुरानी प्रथा का अनुसरण करता है।

[4] रूस और यूक्रेन गेहूं और खाद्य तेल बाजारों में प्रमुख वैश्विक सहभागी हैं, तथा दोनों देशों के बीच भू-राजनीतिक तनाव के कारण इन वस्तुओं की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिसका असर भारत में घरेलू कीमतों पर भी पड़ा है।

[5] खुदरा मूल्य अंतिम उपभोक्ता द्वारा भुगतान किए जाते हैं और मंडी मूल्य किसान द्वारा प्राप्त मूल्य को दर्शाते हैं, इसलिए मार्जिन की गणना दोनों के बीच के अंतर के रूप में की गई है। मार्जिन को खुदरा कीमतों के प्रतिशत के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

[6] मार्क-अप कुल लागत के प्रतिशत के रूप में राजस्व और कुल लागत (लेन-देन लागत सहित) के बीच का अंतर है।

चार्ट 1: रबी फसलें

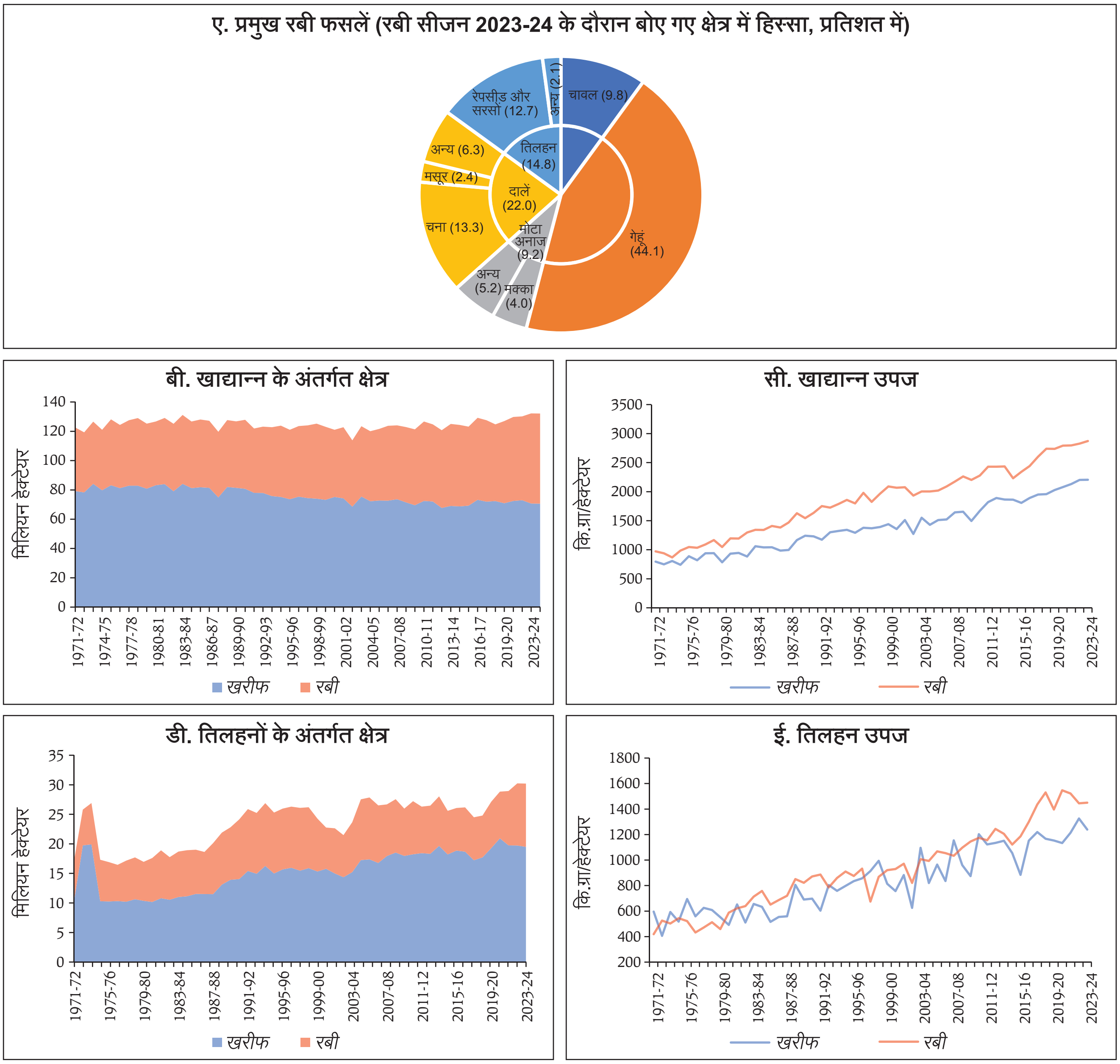

स्रोत: कृषि सांख्यिकी एक नज़र में, 2023, कृषि सांख्यिकी के लिए एकीकृत पोर्टल; तथा इकॉनोमिक एंड पॉलिटिकल रीसर्च फाउंडेशन।

और उपभोक्ताओं के बीच मध्यस्थ के रूप में माना गया है, जैसा कि 2018 और 2022 में किए गए पिछले आरबीआई सर्वेक्षणों में किया गया था।[7] अध्ययन का प्राथमिक उद्देश्य उपभोक्ता कीमतों में विभिन्न बाजार प्रतिभागियों की हिस्सेदारी का आकलन करना[8] , कृषि बिक्री/व्यापार में विभिन्न भुगतान साधनों के उपयोग का अनुमान लगाना, कृषि आपूर्ति शृंखला में मौजूदा चुनौतियों के प्रति विभिन्न हितधारकों की धारणाओं को समझना और नीति उपायों की प्रभावकारिता का आकलन करना है।

[7] कृषि आपूर्ति शृंखलाओं की अंतर्निहित जटिलता को देखते हुए फसलों और क्षेत्रों में बिचौलियों की संख्या और भूमिकाओं में भिन्नता को ध्यान में लेते हुए यह अध्ययन आपूर्ति शृंखला प्रतिभागियों को तीन व्यापक समूहों (किसान, व्यापारी और खुदरा विक्रेता) में वर्गीकृत करता है। हालांकि अन्य बिचौलियों के अस्तित्व को स्वीकार किया जाता है, यह वर्गीकरण स्थिरता सुनिश्चित करने और तुलनात्मक विश्लेषण को सुविधाजनक बनाने के लिए किया गया था।

[8] किसी वस्तु की मूल्य शृंखला का अध्ययन करने के लिए, एक ही स्थान पर बिचौलियों के बीच एक ही वस्तु की कीमतों का पता लगाने के बजाय बिचौलियों और केंद्रों के बीच औसत कीमतों का उपयोग किया गया है।

चार्ट 2: प्रमुख खाद्य वस्तुओं के लिए *मंडी* कीमतें *बनाम* खुदरा कीमतें

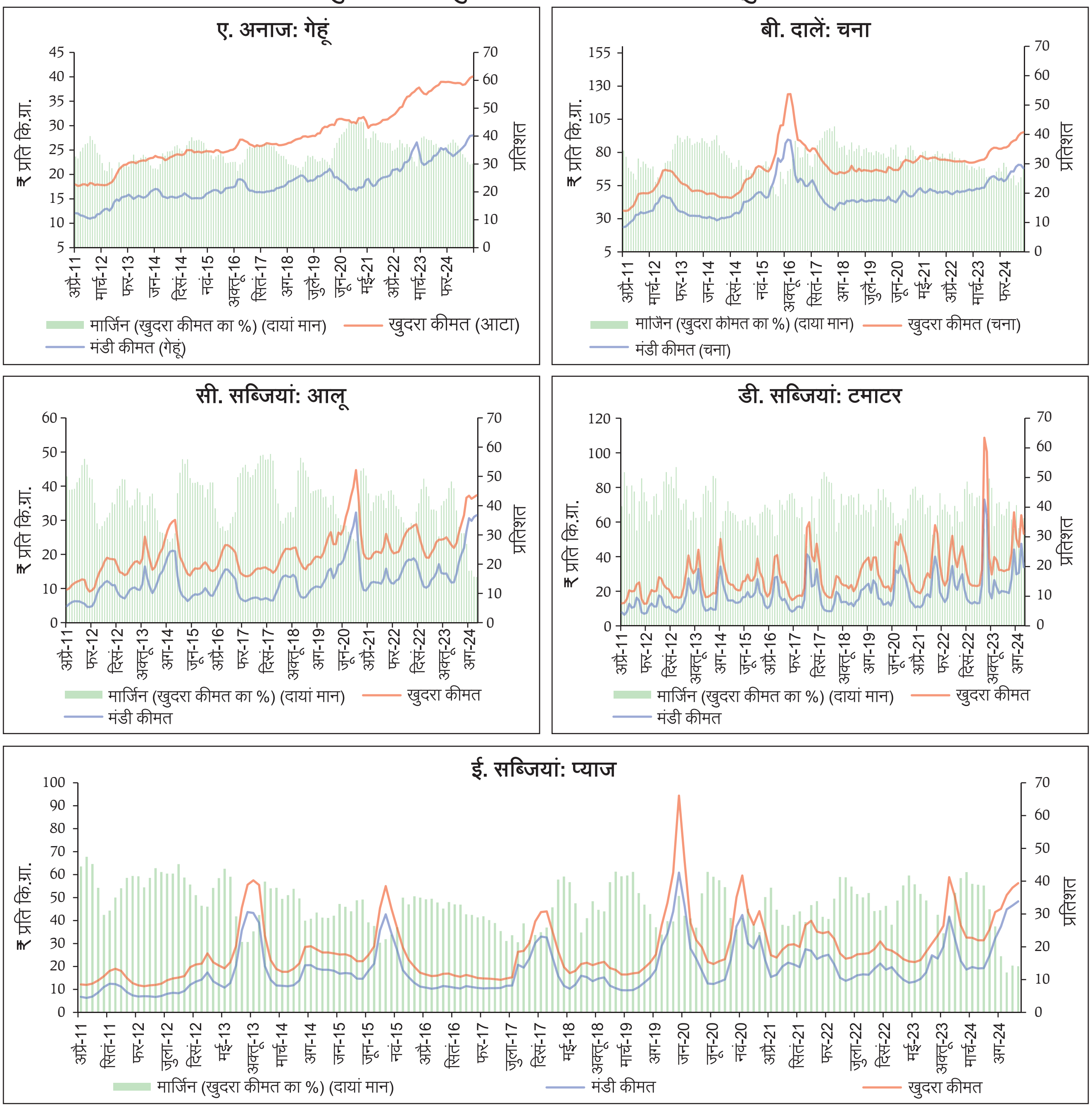

स्रोत: एगमार्कनेट (मंडी कीमतें) और उपभोक्ता मामले विभाग (खुदरा कीमतें)।

सर्वेक्षण पद्धति

सर्वेक्षण में किसानों, व्यापारियों और खुदरा विक्रेताओं के लिए तीन अलग-अलग प्रश्नावली का उपयोग करके 12 रबी फसलों के लिए 18 राज्यों में 86 केंद्रों में मंडियों/गांवों को शामिल किया गया। इसमें विभिन्न उपभोग और उत्पादन केंद्रों के 10,699 उत्तरदाता शामिल थे (सारणी 1)। सर्वेक्षण मई-जुलाई 2024 के दौरान चुनिंदा उत्पादन और उपभोग केंद्रों में अलग-अलग आयोजित किया गया था, जिसमें उत्पादन केंद्रों की आपूर्ति शृंखला गतिशीलता में अंतर को ध्यान में रखा गया था, जो मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों तक सीमित थे और उपभोग केंद्र ज्यादातर शहरी बस्तियों में थे।

सारणी 1: सर्वेक्षणों की व्यापकता

सर्वे राउंड	मंडी/केंद्र (उत्तरदाताओं की संख्या)				वस्तुएँ
	खंड	उपभोग केंद्र	उत्पाद केंद्र	कुल	
2024 *(रबी)*	किसान	-	3800	3800	अनाज: चावल, गेहूं और मक्का दालें: चना और मसूर तिलहन: रेपसीड और सरसों फल और सब्जियां: आम, प्याज, आलू, टमाटर और फूलगोभी मसाले: लहसुन
	खुदरा विक्रेता	2447	570	3017	
	व्यापारी	2953	929	3882	
	कुल	**5400**	**5299**	**10699**	
2022 *(खरीफ)*	किसान	-	2134	2134	अनाज: धान/चावल दालें: अरहर, मूंग, उड़द तिलहन: मूंगफली, सोयाबीन फल और सब्जियां: सेब, केला, नारियल, प्याज, आलू, टमाटर, हरी मिर्च और बैंगन मसाले: हल्दी
	खुदरा विक्रेता	3640	648	4288	
	व्यापारी	3787	960	4747	
	कुल	**7427**	**3742**	**11169**	
2018 *(खरीफ)*	किसान	1147	1664	2811	अनाज: धान/चावल दालें: तूर, मूंग, उड़द, बंगाल चना तिलहन: मूंगफली, सोयाबीन फल और सब्जियां: सेब, केला, नारियल, प्याज, आलू, टमाटर, हरी मिर्च और बैंगन मसाले: हल्दी, लाल मिर्च
	खुदरा विक्रेता	2356	1052	3408	
	व्यापारी	2176	1008	3184	
	कुल	**5679**	**3724**	**9403**	

स्रोत: प्राथमिक सर्वेक्षण।

उत्तरदाताओं का चयन करने के लिए द्वी-स्तरीय नमूना प्रणाली का उपयोग किया गया। उत्पादन केंद्रों को चयनित रबी फसलों में उनके उत्पादन हिस्से के आधार पर चुना गया। उत्पादन केंद्रों में मंडियों को पहले स्तर की इकाइयों के रूप में रखा गया, और व्यापारी तथा खुदरा विक्रेता (मंडी के भीतर और मंडी के 5 किमी के भीतर) दूसरे स्तर की इकाइयाँ थीं। भाग लेने वाले किसानों[9] को पहले से चिह्नित मंडियों के पास के गाँवों से चुना गया, उसके बाद किसान परिवारों का चयन किया गया। दूसरे चरण की चयन प्रक्रिया यादृच्छिक थी। व्यापारियों और खुदरा विक्रेताओं के लिए प्रति किलोग्राम अनुमानित लागत और लाभ मार्जिन से संबंधित आउटलेयर को हटाकर डेटासमूह को छोटा किया गया।[10]

IV. सर्वेक्षण निष्कर्ष और अनुभवजन्य विश्लेषण

सर्वेक्षण के निष्कर्ष

सर्वेक्षण के अंतर्गत शामिल फसलों के लिए उपभोक्ता मूल्यों में किसानों की औसत हिस्सेदारी 40 प्रतिशत से 67 प्रतिशत के बीच है और गैर-नाशवान फसलों के लिए हिस्सेदारी आम तौर पर अधिक है (चार्ट 3)। गेहूं के मामले में किसानों की हिस्सेदारी सबसे अधिक, अर्थात 67 प्रतिशत है जो एक अधिसूचित वस्तु[11] है जिसके लिए किसानों द्वारा सार्वजनिक खरीद प्रणाली के माध्यम से उपज का बड़ा हिस्सा बेचा जाता है। 2024 के सर्वेक्षण में लगभग एक-चौथाई उत्तरदाता गेहूं किसानों ने खरीद प्रणाली के तहत सरकार को अपनी उपज बेचने का उल्लेख है। न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएमपी) पर खरीद किसानों को एक सुनिश्चित बाजार विकल्प प्रदान करती है। इस अध्ययन में 67 प्रतिशत का अनुमान उपलब्ध साहित्य के अनुरूप है जो बताता है कि उपभोक्ता मूल्य में गेहूं किसानों की हिस्सेदारी 53 प्रतिशत से 74 प्रतिशत के बीच है (आरएएसीपी, 2016 और कुमार एवं अन्य, 2023)।

दालों में मसूर की दाल के उत्पादकों को उपभोक्ताओं द्वारा खर्च किए गए रुपये का लगभग 66 प्रतिशत और चने के लिए लगभग 60 प्रतिशत[12] प्राप्त होता है। मसूर की दाल के उत्पादन

[9] वर्ष 2022 में किये गये सर्वेक्षण के अनुसार केवल उत्पादन केन्द्रों के किसानों को ही इसमें शामिल किया गया।

[10] हालांकि व्यापक प्रश्नावली स्वरूप, मजबूत नमूनाकरण और उत्तरदाताओं के टेलीफोन पर सत्यापन के माध्यम से प्रतिक्रियाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया गया है, फिर भी प्राथमिक सर्वेक्षणों की अंतर्निहित सीमाएं जैसे कि सामाजिक वांछनीयता पूर्वाग्रह अभी भी मौजूद हो सकते हैं। अध्ययन में इस्तेमाल किया गया डेटा स्व-रिपोर्ट किया गया डेटा है और इसलिए, संभावित रिकॉल एरर के अधीन है। इसके अलावा, डेटा को कम किए जाने के कारण कुछ जानकारी कम हो सकती है।

[11] कृषि उपज बाजार समिति (एपीएमसी) अधिनियम क्षेत्र में उत्पादित कृषि वस्तुओं को अधिसूचित करता है और यह प्रावधान करता है कि इन वस्तुओं की पहली बिक्री केवल एपीएमसी के तत्वावधान में अधिनियम के तहत स्थापित एपीएमसी द्वारा लाइसेंस प्राप्त कमीशन एजेंटों के माध्यम से की जाती है (भारत सरकार, 2015)।

[12] जोस एवं अन्य. (2024) में चने के लिए किसानों का हिस्सा 75 प्रतिशत अनुमानित किया गया था।

चार्ट 3: उपभोक्ता कीमतों में किसानों की हिस्सेदारी

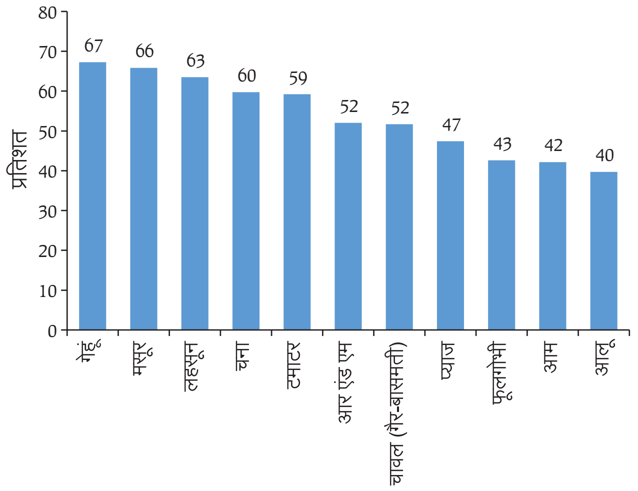

टिप्पणी: रेपसीड, सरसों (आर एंड एम), गेहू और धान13 मे किसानो के हिस्सेदारी को गणना के लिए रूपांतरण कारकों का उपयोग किया गया है। मक्का को हटा दिया गया है क्योंकि खुदरा उपभोक्ता में इस उपज की अधिक खपत नहीं है (केवल 13 प्रतिशत[14])।

स्रोत: लेखकों की गणनाएं 2024 के सर्वेक्षण डेटा पर आधारित हैं।

को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों की अधिक हिस्सेदारी वांछनीय है, क्योंकि यह मुख्य रूप से छोटे भूमि वाले किसानों द्वारा उगाया जाता है और इसके लिए आयात पर महत्वपूर्ण निर्भरता है (मलिक एवं अन्य., 2021)। तिलहन के भीतर देखें तो, सर्वेक्षण के परिणामों ने रेपसीड और सरसों (आर एंड एम) के लिए किसानों की हिस्सेदारी 52 प्रतिशत बताई, जो कि लायेक एवं अन्य. (2021) द्वारा बताए गए 55 प्रतिशत अनुमान के अनुरूप है। सोयाबीन के बाद क्षेत्र और उत्पादन के मामले में आर एंड एम दूसरे क्रमांक पर हैं और वे भारत के कुल खाद्य तेल बास्केट में सबसे अधिक योगदान देते हैं (भारत सरकार, 2022)। सरकार किसानों के लिए एक सुनिश्चित बाजार उपलबध कराने के लिए सार्वजनिक खरीद प्रणाली के माध्यम से इसे खरीदने में भी सक्रिय है।

नाशवान वस्तुओं (फल और सब्ज़ियाँ) की कीमतों में किसानों की हिस्सेदारी लगभग 40-63 प्रतिशत होने का अनुमान है। नाशवान वस्तुओं के मामले में उपभोक्ता कीमतों में हिस्सेदारी तत्समय की मांग-आपूर्ति स्थितियों के आधार पर व्यापक रूप से कम-अधिक हो सकती है। मौजूदा साहित्य से पता चलता है कि फलों और सब्जियों के मामले में किसानों की हिस्सेदारी अंतिम कीमत के 30-50 प्रतिशत के दायरे में होती है (गांधी और नंबूदरी, 2002; भोई एवं अन्य., 2019; दास एवं अन्य., 2024)। नाशवान उत्पादों की विशेषता यह है कि वे अल्प समय तक टिकते हैं, उनका उत्पादन मौसमी होता हैं, उनकी गुणवत्ता और मात्रा अलग-अलग होती है, उनकी रसद संबंधी खास ज़रूरतें होती हैं, गुणवत्ता मानक, मांग और लागत संबंधी अनिश्चितताएँ होती हैं, जलवायु परिस्थितियों और आपूर्ति शृंखला के कार्यपूर्णता समय (लीड टाइम) पर निर्भरता होती है जो बाज़ारों में उनकी समय पर और पर्याप्त उपलब्धता के बारे में अनिश्चितताएँ पैदा करती हैं (डुआर्टे, 2024)। भारत में फलों और सब्जियों की आपूर्ति शृंखला में कई असंगठित बिचौलिए शामिल हैं जो आपूर्ति शृंखला में उत्पादों, निधि और सूचना के प्रवाह की पहचान करने में मुश्किलें पैदा करते हैं, जो उपभोक्ता कीमतों में किसानों की हिस्सेदारी को कम कर सकते हैं (पाटीदार एवं अन्य., 2018)। किसानों की कम हिस्सेदारी भी किसानों के लिए पारंपरिक अनाज फसलों से विविधता लाने में बाधा बन सकती है। वर्तमान सर्वेक्षण के अनुसार, टमाटर को छोड़कर, सभी सर्वेक्षण किए गए फलों और सब्जियों के लिए व्यापारियों और खुदरा विक्रेताओं की संयुक्त हिस्सेदारी आधे से अधिक होने का अनुमान है।

पिछले खरीफ दौर और इस रबी दौर के सर्वेक्षण में जिन फसलों का सर्वेक्षण किया गया था, उनमें से चावल की खुदरा कीमतों में किसानों की हिस्सेदारी इस सर्वेक्षण में लगभग 52 प्रतिशत होने का अनुमान है।[15] 2022 और 2018 के खरीफ सर्वेक्षणों के दौरान क्रमशः 45 और 49 प्रतिशत हिस्सेदारी थी। टीओपी (टमाटर, प्याज, आलू) मुख्य रूप से रबी की फसलें हैं। रबी सर्वेक्षण में उपभोक्ता कीमतों में किसानों की हिस्सेदारी भी मोटे तौर पर पिछले दो खरीफ सर्वेक्षणों के अनुमानों के बराबर है (चार्ट 4)।

व्यापारियों और खुदरा विक्रेताओं का मार्क-अप

कृषि मूल्य शृंखला में मूल्य निर्धारण के संबंध में, अर्थात, किसानों की कीमत प्राप्ति और खुदरा विक्रेताओं द्वारा लगाए गए मूल्य के बीच यह देखा गया कि किसानों, व्यापारियों और

[13] तिलहन (यहाँ आर एवं एम) किसानों द्वारा बीज के रूप में बेचे जाते हैं, लेकिन अंतिम उपभोक्ता उन्हें तेल के रूप में खरीदते हैं। इसके अलावा, खली (तेल निकालने के बाद बचा हुआ पदार्थ) का उपयोग मवेशियों, मुर्गी पालन या मछली पालन के लिए चारे के रूप में किया जाता है। तदनुसार, किसान के हिस्से की गणना करते समय, तेल के खुदरा मूल्य को बीज के बराबर (0.4 की रूपांतरण दर पर) में परिवर्तित किया गया है। इसी तरह, धान मिलिंग के बाद चावल में परिवर्तित हो जाता है जिसे फिर खुदरा स्तर पर अंतिम उत्पाद के रूप में बेचा जाता है। गेहूँ को भी आम तौर पर साबुत अनाज के रूप में नहीं बेचा जाता है, बल्कि खुदरा स्तर पर आटे के रूप में खरीदा जाता है। तदनुसार, चावल के मामले में 0.67 की रूपांतरण दर और गेहूँ के मामले में मूल्य अंतर (लगभग ₹4/किग्रा) किसानों के हिस्से की गणना करते समय लागू किया गया है।

[14] भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान (https://iimr.icar.gov.in/?page_id=51)।

[15] चावल मुख्य रूप से खरीफ फसल है। खरीफ चावल और रबी (जायद सहित) चावल का कुल चावल उत्पादन में क्रमशः लगभग 80 प्रतिशत और 20 प्रतिशत हिस्सा है।

चार्ट:4 उपभोक्ता कीमतों में किसानों की हिस्सेदारी (खरीफ की तुलना में रबी सर्वेक्षण)

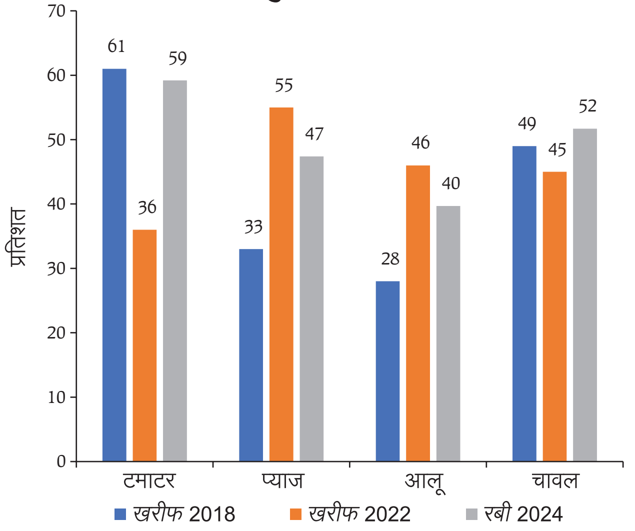

स्रोत: लेखकों की गणनाएं खरीफ और रबी सर्वेक्षण डेटा पर आधारित हैं।

खुदरा विक्रेताओं को लेन-देन के दौरान विभिन्न शुल्कों का भुगतान करना पड़ता है। किसानों को कटाई के बाद मुख्य रूप से कमीशन और मंडी शुल्क, लोडिंग/अनलोडिंग शुल्क, पैकिंग, वजन और ग्रेडिंग शुल्क देना होता है। व्यापारियों और खुदरा विक्रेताओं के संबंध में, उनके मार्क-अप को प्रभावित करने वाले कारकों में सदस्यता शुल्क, परिवहन लागत, दुकान किराया, स्थानीय कर और भंडारण लागत शामिल हैं।

व्यापारियों और खुदरा विक्रेताओं के मार्क-अप, अर्थात कुल लागत (उत्पादों की लागत और लेन-देन की लागत) को घटाकर प्रतिशत के रूप में प्राप्ति, भंडारण लागत में भिन्नता जैसे कारकों के कारण भिन्न फसलों के लिए भिन्न हो सकते हैं जो होल्डिंग चक्र की अवधि, पारगमन के दौरान फसल के अपव्यय और गुणवत्ता तथा उपज की शेल्फ-लाइफ पर निर्भर करते हैं। सर्वेक्षण में शामिल वस्तुओं में खुदरा विक्रेताओं के मार्क-अप का अनुमान लगभग 7-25 प्रतिशत था, जो आम तौर पर उत्पादन और उपभोग, दोनों केंद्रों में व्यापारियों (5-23 प्रतिशत) की तुलना में अधिक था। इसके अलावा, नाशवान वस्तुओं के के संबंध में व्यापारियों और खुदरा विक्रेताओं के मार्क-अप गैर-नाशवान वस्तुओं की तुलना में अधिक पाए गए (चार्ट 5)। ये सर्वेक्षण निष्कर्ष अन्य हालिया अध्ययनों (गुलाटी एवं अन्य, 2022) के अनुरूप हैं। इस सर्वेक्षण में उत्पादन केन्द्रों में आलू के लिए व्यापारियों का मार्कअप का अधिक होना सर्वेक्षण अवधि के दौरान थोक मूल्यों में वृद्धि का प्रतिबिंब हो सकता है, जो खुदरा मूल्यों में वृद्धि से अधिक है।

पिछले सर्वेक्षणों और इस सर्वेक्षण में शामिल आम फसलों के संबंध में, व्यापारियों और खुदरा विक्रेताओं के मार्क-अप पिछले

चार्ट:5 व्यापारियों और खुदरा विक्रेताओं के मार्क-अप

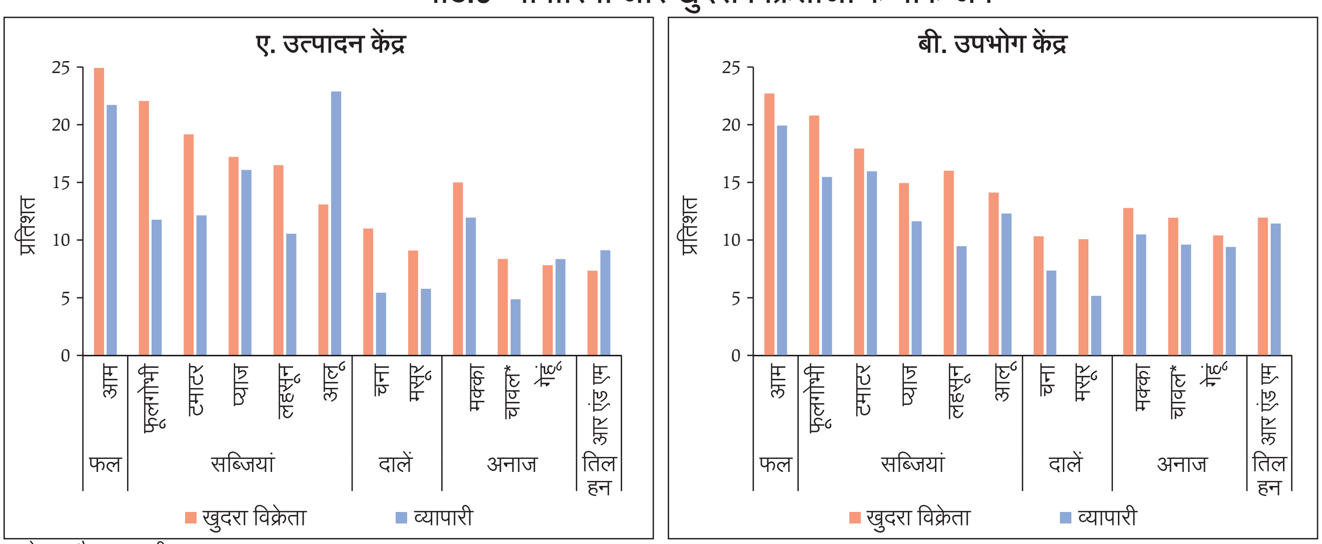

*: केवल गैर बासमती चावल।
आर एंड एम: रेपसीड और सरसों
स्रोत: लेखकों की गणनाएं 2024 के सर्वेक्षण डेटा पर आधारित हैं।

[16] *रबी* सीजन में कुल आलू उत्पादन का 90 प्रतिशत उत्पादन होता है।

सर्वेक्षण परिणामों (चार्ट 6)[17] की तुलना में आम तौर पर कम हुए हैं। साथ ही, ग़ौर किया जाए कि टीओपी मुख्य रूप से रबी की फसलें हैं। इन वस्तुओं में व्यापारियों और खुदरा विक्रेताओं का कम मार्क-अप होना इस मौसम के दौरान नाशवान उपज की अत्यधिक उपलब्धता का प्रतिबिंब हो सकता है (जोस एवं अन्य., 2021)। इसके अलावा, सरकार के हालिया नीतिगत उपायों, जैसे कि प्याज का बफर स्टॉक रखना और बाहरी व्यापार विनियमन, मदर डेयरी, *सफल* और केंद्रीय भंडार जैसे खुदरा दुकानों के माध्यम से आपूर्ति और टीओपी सब्जियों के लिए मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) की स्थापना के कारण बिचौलियों का मार्क-अप नियंत्रित हो सकता है।

भुगतान साधनों का उपयोग

सर्वेक्षण में किसानों, व्यापारियों और खुदरा विक्रेताओं द्वारा लेन-देन के लिए भुगतान साधनों के उपयोग पर डेटा भी एकत्र किया गया और प्राप्त आंकड़ों से पता चलता है कि नकद भुगतान उनके संबंधित कुल भुगतानों में सबसे ज्यादा हिस्सा रखता है – किसान लगभग 72 प्रतिशत, व्यापारी 45 प्रतिशत और खुदरा विक्रेता 61 प्रतिशत। हालांकि, 2022 के सर्वेक्षण की तुलना में इस हिस्सेदारी में 7-13 प्रतिशत अंकों की गिरावट आई है, लेकिन ध्यान दिया जाए कि दोनों सर्वेक्षणों में शामिल फसल अलग-अलग हैं। साथ ही, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान का उपयोग, हालांकि व्यापारियों के मामले में सबसे अधिक है, देश में भुगतान के बढ़ते डिजिटलीकरण के अनुरूप सभी आपूर्ति शृंखला एजेंटों के संबंध में बढ़ गया है[18]। सर्वेक्षण के अनुसार, 18-31 प्रतिशत प्रतिसूचनाएं भुगतान के इलेक्ट्रॉनिक तरीकों के लिए थीं (चार्ट 7)। नकदी आधारित मूल्य शृंखला और बाजार की बाधाओं के कारण किसानों का प्रतिलाभ घट सकता है (एपीईसी, 2017)। कृषि भुगतानों को डिजिटल बनाने से किसानों के लिए सामान प्रदाताओं से सीधी खरीद

चार्ट:6 व्यापारियों और खुदरा विक्रेताओं के 2024 और पिछले सर्वेक्षणों के मार्क-अप की तुलना

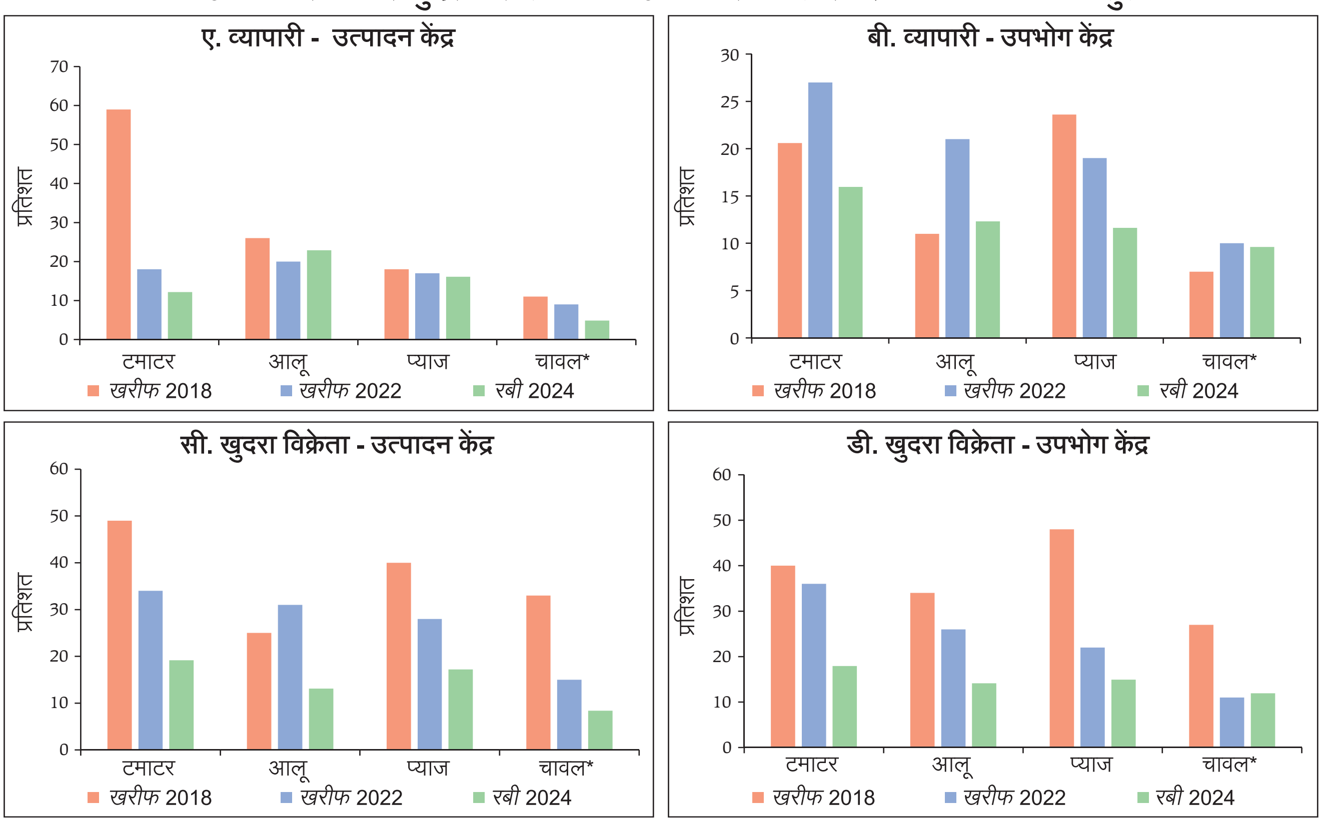

*: केवल गैर बासमती चावल।

स्रोत: लेखकों की गणनाएं 2018, 2022 और 2024 के सर्वेक्षण डेटा पर आधारित हैं।

[17] पिछले सर्वेक्षणों से इस अध्ययन की तुलना कृषि विपणन मौसम में परिवर्तन के अधीन है, क्योंकि पिछले सर्वेक्षण *खरीफ* विपणन मौसम के दौरान आयोजित किए गए थे।

[18] 2022 के सर्वेक्षण के दौरान रिपोर्ट किए गए इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के उपयोग में 2018 के सर्वेक्षण की तुलना में व्यापारियों के संबंध में 3 गुना से अधिक और खुदरा विक्रेताओं के संबंध में 5 गुना वृद्धि परिलक्षित हुई (सुगंथी एवं अन्य., 2024)।

चार्ट:7 भुगतान के माध्यम

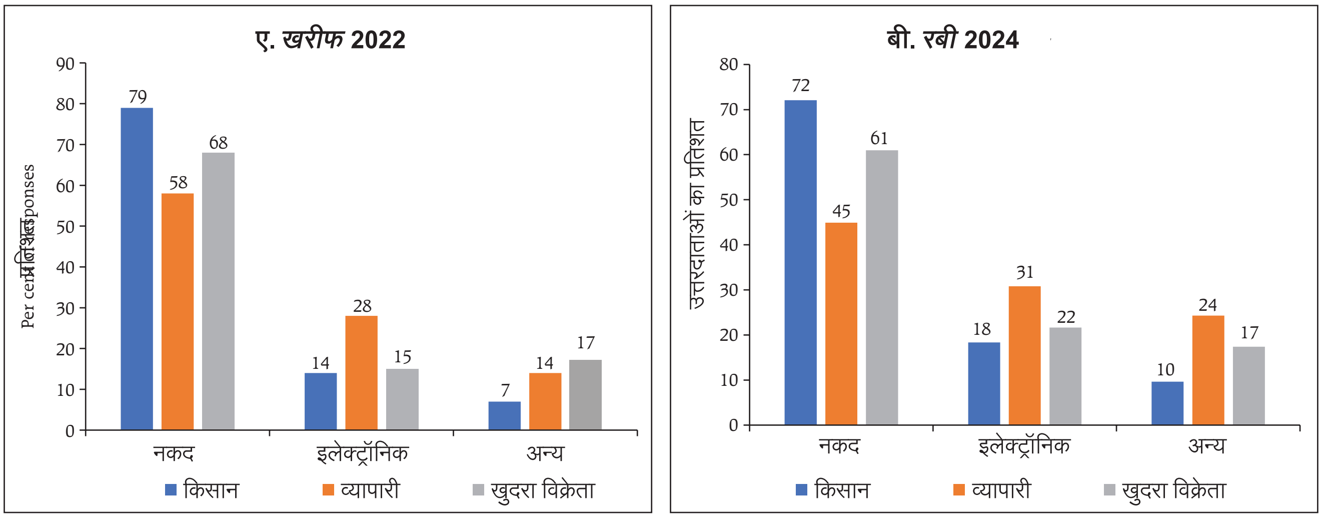

नोट: चार्ट 7ए में 'अन्य' में क्रेडिट और वाउचर पर प्रतिदेय रसीदें शामिल हैं; तथा चार्ट 7बी में 'अन्य' में प्रतिदेय रसीदें, चेक और क्रेडिट लेनदेन शामिल हैं।
स्रोत: लेखकों की गणना खरीफ 2022 और रबी 2024 सर्वेक्षण आंकड़ों पर आधारित है।

और उपभोक्ताओं को सीधे बेचना आसान हो सकता है, जिससे किसानों का आय संबंधी आघातों के प्रति अधिक लचीलापन, विशेष रूप से प्रतिकूल मौसम की घटनाओं और जलवायु परिवर्तन के प्रति उनकी बढ़ती संवेदनशीलता के मद्देनजर, विकसित होगा, (विश्व बैंक, 2024)।

मूल्य अस्थिरता

रबी सर्वेक्षण 2024 के अनुसार, सर्वेक्षण किए गए 85 प्रतिशत खुदरा विक्रेताओं का मानना था कि कीमतों में अचानक वृद्धि हो जाने के पीछे आपूर्ति आघात मुख्य कारण हैं, इसके बाद मौसमी कारक हैं (चार्ट 8 ए)। इस बात का समर्थन किसान

चार्ट: 8 कृषि फसल मुद्रास्फीति और कीमतों में अस्थिरता संबंधी अध्ययन

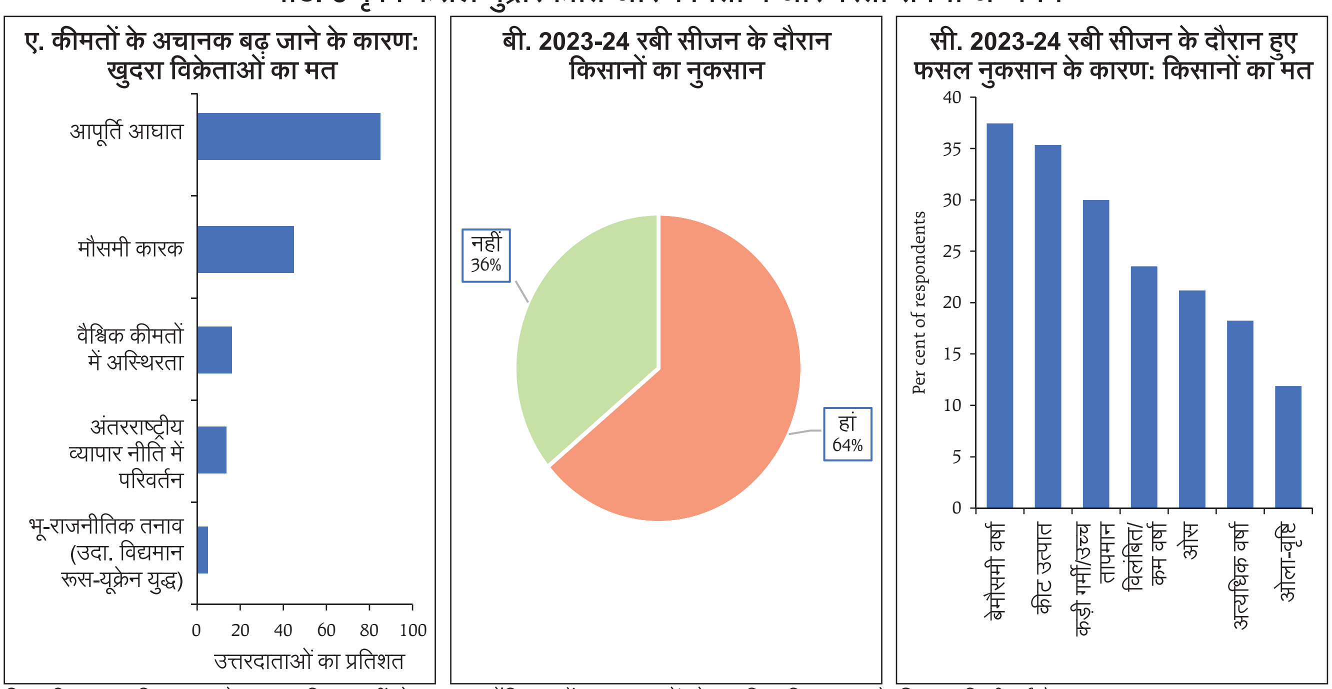

टिप्पणी: उत्तर प्रतिशत का योग 100 प्रतिशत नहीं हो सकता क्योंकि प्रश्न में उत्तरदाताओं को एकाधिक विकल्प चुनने की अनुमति दी गई है।
स्रोत: लेखकों की गणनाएं 2024 के सर्वेक्षण डेटा पर आधारित हैं।

उत्तरदाताओं ने भी किया है, जिनमें से 64 प्रतिशत ने 2023-24 के रबी मौसम के दौरान किसी न किसी रूप में फसल अपव्यय का अनुभव किया है। लगभग 37 प्रतिशत किसानों ने बेमौसम बारिश को अपव्यय का प्राथमिक कारण, उसके बाद कीट हमले और अत्यधिक गर्मी को कारण बताया (चार्ट 8बी और 8सी)। मौसम का पूर्वानुमान और सिंचाई की उपलब्धता प्राथमिक कारक हैं जो किसानों का फसल-बुवाई का तरीका निर्धारित करते हैं (चार्ट 9)।

सर्वेक्षण के अनुसार, व्यापारियों और खुदरा विक्रेताओं ने अन्य फसलों की तुलना में फलों और सब्जियों में अधिक अपव्यय होने की सूचना दी है (चार्ट 10)। फलों और सब्जियों के मामले में 10 प्रतिशत से अधिक उत्पादन की बर्बादी (अपव्यय) प्रमुख बताई गई। अपर्याप्त भंडारण सुविधाएँ, बिजली कट जाना, कृषि क्षेत्रों के लिए खराब बुनियादी ढाँचा और भारत में अपर्याप्त सड़क और राजमार्ग नेटवर्क कटाई के बाद के अधिक अपव्यय का कारक हैं जिसके 20-44 प्रतिशत की सीमा में होने का अनुमान है (कुमार एवं अन्य., 2020; कुमार और अग्रवाल, 2023; रईस और श्योरान, 2023; एनएचबी 2021 और डुआर्टे, 2024)।

मूल्य दबावों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने हाल के वर्षों में कई फसल-विशिष्ट नीतिगत हस्तक्षेप किए हैं जैसे कि भंडारण सीमा लागू करना, कुछ निर्यातों को प्रतिबंधित करना, कुछ आयातों को उदार बनाना और घरेलू बाजार में पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए खुले बाजार में बिक्री करना। सर्वेक्षण में शामिल खुदरा विक्रेताओं में से 59 प्रतिशत के अनुसार इस तरह के हस्तक्षेप कुछ समय के लिए मूल्य दबावों को रोकने में प्रभावी हो सकते हैं। इसके अलावा, कुल उत्तरदाताओं में से लगभग आधे उत्तरदाताओं ने बाहरी व्यापार और भंडारण संबंधी किए गए उपायों को प्रभावी बताया (चार्ट 11)।

चार्ट 9: किसान के फसल बुआई निर्णय को प्रभावित करने वाले कारक

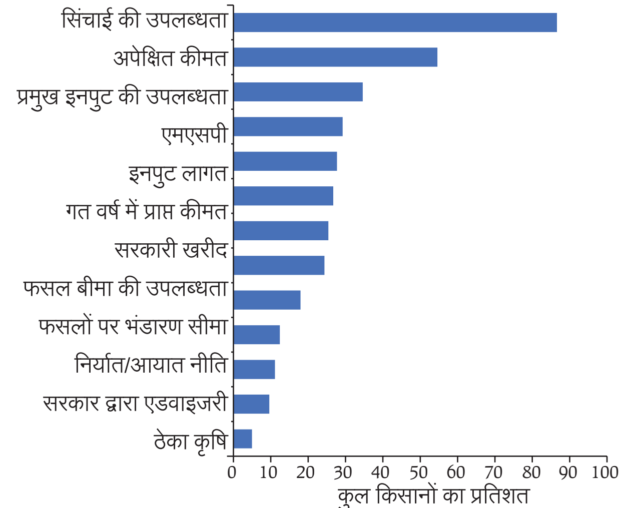

टिप्पणी: उत्तर प्रतिशत का योग 100 प्रतिशत नहीं हो सकता क्योंकि प्रश्न में उत्तरदाताओं को एकाधिक विकल्प चुनने की अनुमति दी गई है।
स्रोत: लेखकों की गणनाएं 2024 के सर्वेक्षण डेटा पर आधारित हैं।

चार्ट 10: कृषि आपूर्ति शृंखला में नुकसान की मात्रा: व्यापारियों और खुदरा विक्रेताओं का मत

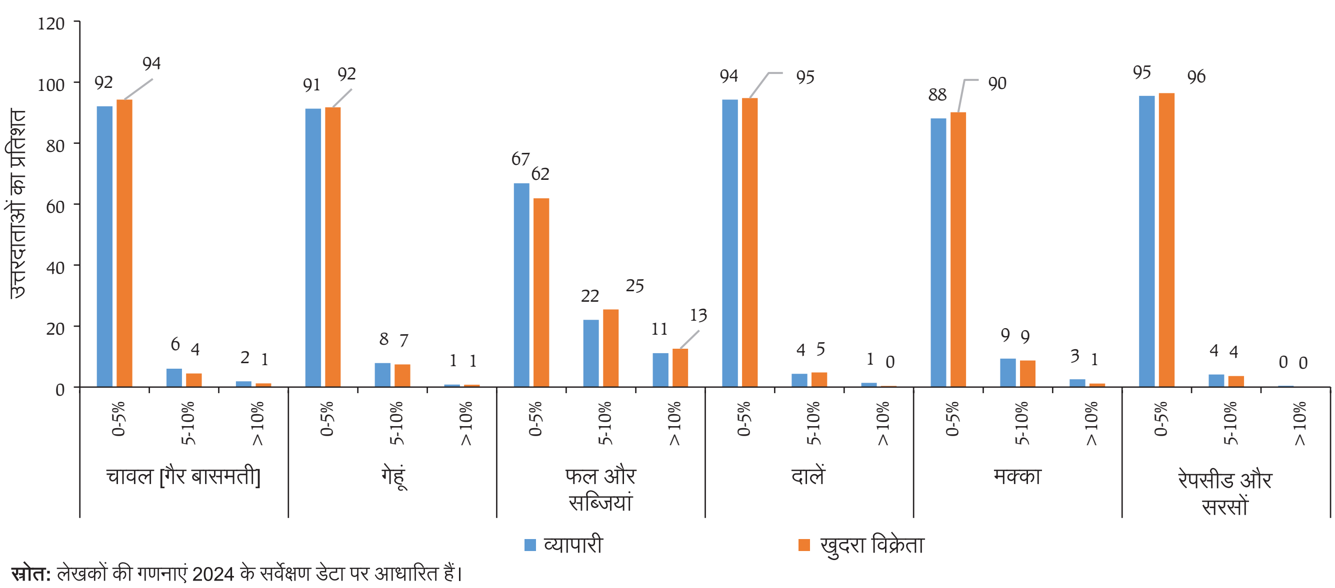

स्रोत: लेखकों की गणनाएं 2024 के सर्वेक्षण डेटा पर आधारित हैं।

चार्ट 11: मुद्रास्फीति प्रबंधन में अल्पावधि नीतिगत उपायों का महत्व: खुदरा विक्रेताओं का मत

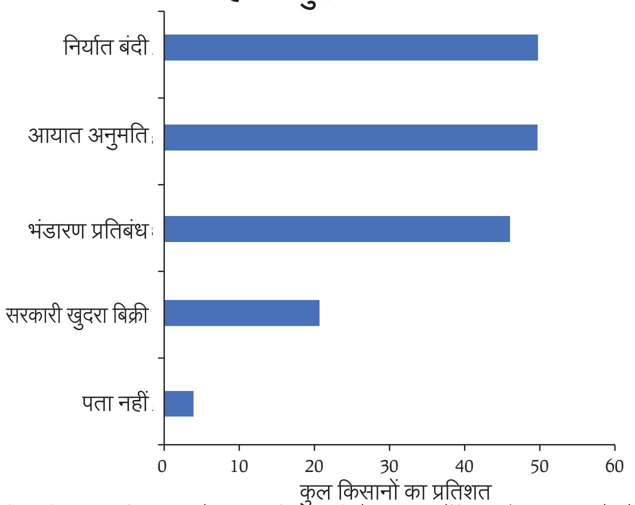

टिप्पणी: उत्तर प्रतिशत का योग 100 प्रतिशत नहीं हो सकता क्योंकि प्रश्न में उत्तरदाताओं को एकाधिक विकल्प चुनने की अनुमति दी गई है।
स्रोत: लेखकों की गणनाएं 2024 के सर्वेक्षण डेटा पर आधारित हैं।

चार्ट 12: बाजार कीमतों के बारे में किसानों को प्राप्त जानकारी का स्रोत

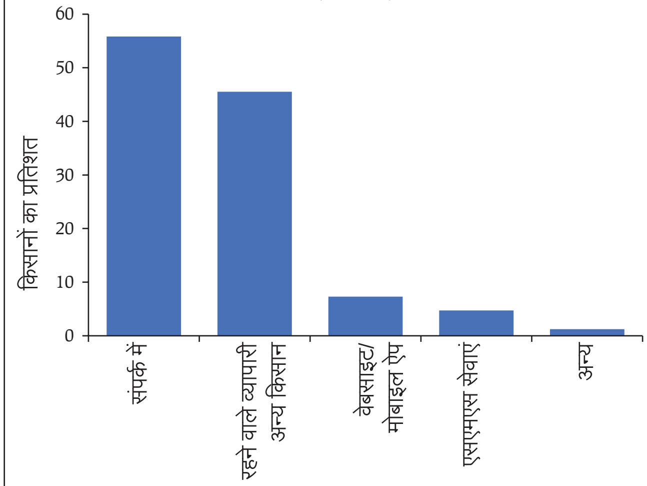

टिप्पणी: उत्तर प्रतिशत का योग 100 प्रतिशत नहीं सकता क्योंकि प्रश्न में उत्तरदाताओं को एकाधिक विकल्प चुनने की अनुमति दी गई है।
स्रोत: लेखकों की गणनाएं 2024 के सर्वेक्षण डेटा पर आधारित हैं।

कृषि विपणन

बाजार मूल्यों के बारे में समय पर और विश्वसनीय जानकारी किसानों को उनकी उपज बेचने में मदद कर सकती है। सर्वेक्षण के अनुसार, लगभग 76 प्रतिशत किसानों को मौजूदा बाजार मूल्यों के बारे में जानकारी थी और उन्होंने इसे मुख्य रूप से अपने संपर्क में रहने वाले व्यापारियों से प्राप्त किया था (चार्ट 12)। किसानों और अन्य आपूर्ति शृंखला प्रतिभागियों के बीच व्यापारी मुख्य अंतर्संबंध का काम करते हैं अत: वे बाजार की जानकारी के प्रमुख स्रोत होते हैं।

कृषि-उत्पादों के विपणन में सुधार के लिए उत्तरदाता किसानों की मुख्य नीतिगत अनुशंसा में 'गांवों में अधिक बाजारों का निर्माण' शामिल था, जबकि व्यापारियों ने व्यापार नीति के उदारीकरण को सबसे आवश्यक बताया (चार्ट 13)। यद्यपि कृषि विपणन नीतिगत महत्व के मुख्य क्षेत्रों में से एक

चार्ट 13: कृषि विपणन में सुधार के लिए सुझाव

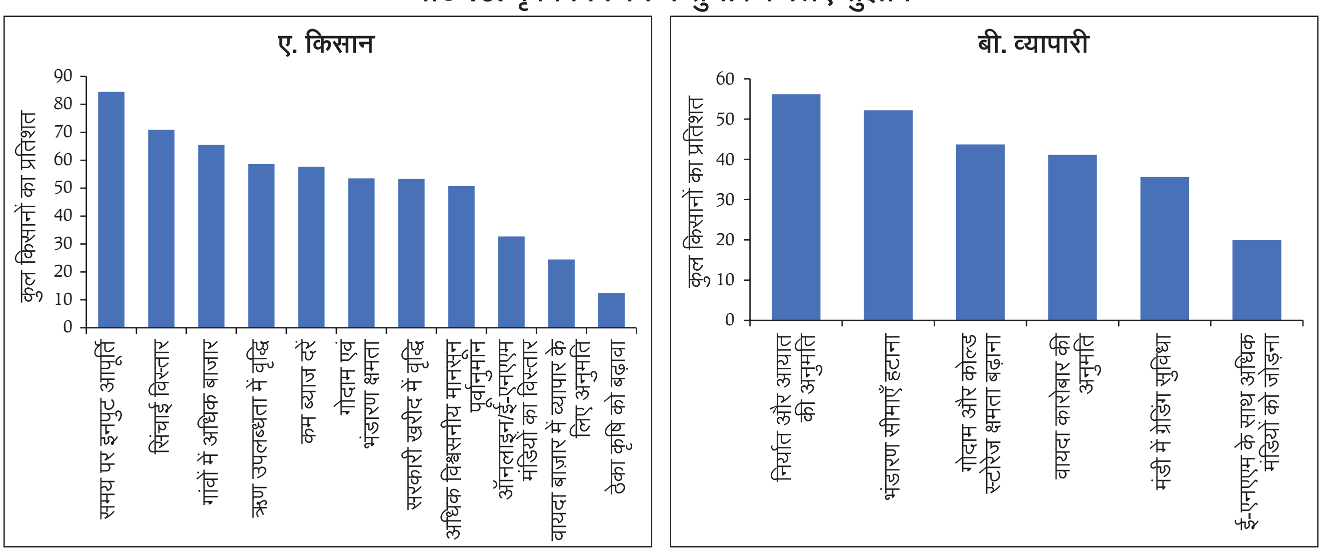

टिप्पणी: उत्तर प्रतिशत का योग 100 प्रतिशत नहीं हो सकता क्योंकि प्रश्न में उत्तरदाताओं को एकाधिक विकल्प चुनने की अनुमति दी गई है।
स्रोत: लेखकों की गणनाएं 2024 के सर्वेक्षण डेटा पर आधारित हैं।

रहा है, लेकिन 'कृषि' एक राज्य विषय है, इसलिए राज्यों के बीच विनियमन, इच्छा और आम सहमति के विभिन्न स्तरों के कारण ऐसी नीतियों को लागू करना अक्सर कठिन हो जाता है (भारत सरकार, 2024)। बजटीय आवंटन में कृषि के लिए सरकारी व्यय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा आपूर्ति शृंखला विकास के बजाय उर्वरक और बिजली जैसी इनपुट सब्सिडी के लिए अधिक आवंटित किया जाता है (ज़फ़र एवं अन्य., 2023)।

अनुभवजन्य निष्कर्ष

कृषि आपूर्ति शृंखला में मार्क-अप प्रत्येक चरण में वर्धित मूल्य के महत्वपूर्ण संकेतक हैं। जबकि अत्यधिक मार्क-अप से खाद्य कीमतें बढ़ सकती हैं, कम मार्क-अप हितधारकों की लाभप्रदता को प्रभावित कर सकता है (भट्टाचार्य, 2016)। इस सर्वेक्षण के पिछले दौर पर आधारित लेख में व्यापारियों के मार्क-अप को प्रभावित करने वाले कारकों को समझने के लिए एक अनुभवजन्य अभ्यास किया गया था (सुगंथी एवं अन्य., 2024)। इस अध्ययन में सर्वेक्षण से एकत्र किए गए डेटा के आधार पर खुदरा विक्रेताओं के स्तर पर मार्क-अप के निर्धारकों की पहचान करने का प्रयास किया गया है। निम्नलिखित समीकरण का प्रयोग करके ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन का उपयोग किया गया है:

$$M_{idc} = \alpha + \beta_1 R_i + \beta_2 S_i + \beta_3 TC_i + \beta_4 D_i + \beta_5 W_i + \beta_6 (W_i \times P_c) + \beta_7 (E_d \times P_c) + \beta_8 N_i + \beta_9 CT_i + \beta_{10} C_c + \beta_{11} P_c + \varepsilon_{idc}$$

जहां, i, d और c क्रमश: 'खुदरा विक्रेता', 'जिला' और 'पण्य' को प्रदर्शित करते हैं।

यहाँ, M_{idc} मार्क-अप है, जिसे खुदरा विक्रेताओं के संबंध में कुल लागत के प्रतिशत के रूप में विक्रय मूल्य में से कुल लागत (लेन-देन लागत सहित) घटाकर परिभाषित किया गया है। R_i, खुदरा विक्रेताओं की जनसांख्यिकीय प्रोफ़ाइल, जैसे - आयु, शिक्षा और लिंग का प्रतिनिधित्व करता है; S_i पिछले वर्ष की तुलना में पण्य आपूर्ति में बदलाव के बारे में खुदरा विक्रेता की धारणा का प्रतिनिधित्व करता है; TC_i प्रति किलोग्राम पर होने वाली लेनदेन लागत है; और D_i खरीद के बिंदु से खुदरा विक्रेता आउटलेट की दूरी को दर्शाता है। W_i अनुभव की गई अपव्यय की सीमा के बारे में खुदरा विक्रेता की धारणा को दर्शाता है; N_i, खुदरा विक्रेता द्वारा बेची गई वस्तुओं की संख्या का प्रतिनिधित्व करता है; E_d डमी चर है जो जिले में बहुत अधिक, अधिक और बहुत कम (संचयी) वर्षा के संदर्भ में चरम मौसम की घटनाओं की जानकारी प्राप्त करता है। CT_i खुदरा विक्रेता के आउटलेट स्थान (उत्पादन/उपभोग केंद्र) के लिए निश्चित प्रभाव का प्रतिनिधित्व करता है। C_c तथा P_c क्रमशः विशिष्ट पण्यों तथा पण्य की प्रकृति (नाशवान/गैर-नाशवान) के लिए नियत प्रभाव को निरूपित करते हैं तथा ε_{idc} अवशिष्ट है। यहां तीन मॉडल प्रकार पेश किए गए हैं। मॉडल 1 (M1) बुनियादी समीकरण के रूप में कार्य करता है, मॉडल 2 (M2) अपव्यय के कई स्तरों पर पण्य (नाशवान/गैर-नाशवान) के स्वरूप के साथ अपव्यय की अंतःक्रिया ($W_i \times P_c$) का प्रयोग करता है। इसके अलावा, मॉडल 3 (M3) अपव्यय को चरम मौसम की घटनाओं से बदल देता है और अंतःक्रिया चर ($E_d \times P_c$) का उपयोग करके नाशवान वस्तुओं के मार्क अप पर इन घटनाओं के प्रभाव को समझने का प्रयास करता है।

रिग्रेशन विश्लेषण से पता चलता है कि खुदरा विक्रेता नाशवान वस्तुओं (फलों और सब्जियों) के मामले में उच्च खुदरा कीमतों के माध्यम से अपव्यय से हुए नुकसान लागत को उपभोक्ताओं से वसूल कर सकते हैं, जबकि गैर-नाशवान वस्तुओं के मामले में ऐसा नहीं होता। तदनुसार, जबकि समग्र स्तर पर उत्पाद के अपव्यय से मार्क-अप नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं (मॉडल 1), नाशवान वस्तुओं के लिए प्रभाव सकारात्मक होता है (मॉडल 2) [सारणी 2]। इससे पता चलता है कि खुदरा विक्रेता नाशवान वस्तुओं के लिए उच्च मार्क-अप प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें कटाई के बाद अपव्यय की घटना और उत्पाद अंतर अपेक्षाकृत अधिक है (गुलाटी *एवं अन्य*।, 2022)। इसके अलावा, जैसा कि मॉडल 2 में संकेत दिया गया है, अपव्यय की सीमा के साथ-साथ मूल्य बढ़ता प्रतीत होता है।

[19] कृषि बाजारों को मजबूत करने के लिए सरकार ने एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाने के लिए ई-एनएएम की शुरुआत की, जिससे कृषि वस्तुओं की पारदर्शिता और मूल्य निर्धारण में सुधार हुआ। इसके अलावा, सरकार ने किसानों को सीधे खरीदारों से जोड़ने के लिए मौजूदा ग्रामीण हाटों को अच्छी तरह से सुसज्जित ग्रामीण कृषि बाजारों में अपग्रेड करने के लिए कदम उठाए हैं। इसके अलावा, किसानों को सीधे बाजार तक पहुंच प्रदान करने के लिए, एफपीओ को देश भर के उपभोक्ताओं को अपनी उपज ऑनलाइन बेचने के लिए ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) पोर्टल पर जोड़ा गया है।

मॉडल 3 से भी यही पता चला है जिसमें अपव्यय डमी को चरम मौसम स्थिति डमी से बदल दिया गया है।[20] मौसम की गड़बड़ी अक्सर फसल कटाई के बाद होने वाले अपव्यय और तापमान नियंत्रित भंडारण और परिवहन सुविधाओं की पर्याप्त उपलब्धता के अभाव में आपूर्ति शृंखला की बर्बादी के प्रमुख कारणों में से एक होती है (चोंकौआंग एवं अन्य., 2024)। यह पाया गया कि उच्च लेन-देन लागत होने (परिवहन, श्रम, किराया) से मार्क-अप कम हो जाता है। जनसांख्यिकीय चरों में, पुरुष खुदरा विक्रेताओं को विभिन्न मॉडल प्रकारों में उच्च मार्क-अप प्राप्त होता है।

सारणी 2: खुदरा विक्रेताओं के मार्क-अप के निर्धारक: रिग्रेशन परिणाम

आश्रित चर: मार्कअप (लॉग)	मॉडल 1 (M1)	मॉडल 2 (M2)	मॉडल 3 (M3)
जनसांख्यिकीय चर			
लॉग (आयु, वर्ष)	0.11 (0.04)**	-0.05 (0.06)	-0.03 (0.05)
शिक्षा (डमी, एसएससी और ऊपर = 1)	0.20 (0.03)***	-0.01 (0.04)	0.01 (0.04)
लिंग (डमी, पुरुष = 1)	0.19 (0.06)***	0.15 (0.08)*	0.11 (0.06)*
पिछले वर्ष की तुलना में उच्च आपूर्ति (डमी, उच्चतर = 1)	-0.06 (0.05)	-	-
लॉग (लेनदेन लागत, रु./किग्रा)	-0.06 (0.02)***	-0.10 (0.02)***	-0.04 (0.02)**
खरीद के स्थान से दूरी (1 यदि 10 किमी से अधिक)[21]	-0.07 (0.05)	-0.09 (0.06)	-0.04 (0.05)
अपव्यय (1 यदि >2%)	-0.43 (0.06)***	-	-
अपव्यय (डमी, आधार: 0-2%)***नाशवान** (डमी)			
अपव्यय (2-5%)*नाशवान	-	1.15 (0.11)***	-
अपव्यय (5-10%)* नाशवान	-	1.25 (0.13)***	-
अपव्यय (>10%)*नाशवान	-	1.46 (0.11)***	-
चरम मौसम (डमी#)***नाशवान** (डमी)	-	-	2.20 (0.11)***
खुदरा विक्रेता द्वारा बेची गई वस्तुओं की संख्या (लॉग)	0.03 (0.01)***	0.01 (0.01)	0.02 (0.01)***
अंतरोधन (इंटरसेप्ट)	1.23 (0.22)***	2.62 (0.27)***	2.42 (0.20)***
केंद्र निश्चित प्रभाव (उत्पादन/खपत)	Yes	Yes	Yes
कमोडिटी फिक्स्ड इफेक्ट	Yes	-	-
नाशवान वस्तु निश्चित प्रभाव	-	Yes	Yes
Adj. आर स्क्वायर	0.57	0.23	0.56
आब्ज़ संख्या	2287	2287	2287

***,**&*: महत्व का स्तर क्रमशः 1%, 5% और 10%।
#: अधिक/बहुत अधिक/अत्यधिक कम वर्षा।
टिप्पणी: कोष्ठक में आंकड़े ठोस मानक त्रुटियां हैं, जो जिला स्तर पर एकत्रित की गई हैं।
स्रोत: लेखकों के अनुमान 2024 के सर्वेक्षण डेटा पर आधारित हैं।

[20] ए. https://seller.globallinker.com/bizforum/article/the-supply-chain-and-its-impact-on-agricultural-food-waste-in-india/8925#/overlay/signup/articleview/8925
बी. https://www.wri.org/insights/climate-adaptation-agricultural-supply-chains

[21] यद्यपि सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्व नहीं है, खुदरा दुकानों से खरीद केन्द्रों की दूरी मार्कअप के साथ नकारात्मक रूप से जुड़ी हुई प्रतीत होती है।

V. निष्कर्ष

यह लेख मई-जुलाई 2024 के दौरान प्रमुख रबी फसलों के अखिल भारतीय सर्वेक्षण के आधार पर किसानों, व्यापारियों और खुदरा विक्रेताओं के बीच भारत की कृषि आपूर्ति शृंखला के बारे में जानकारी प्रदान करता है। सर्वेक्षण के परिणाम बताते हैं कि सर्वेक्षण में शामिल फसलों की उपभोक्ता कीमतों में किसानों की हिस्सेदारी 40 प्रतिशत से 67 प्रतिशत के बीच है, जिसमें गेहूं उत्पादकों को सबसे अधिक हिस्सा मिलता है। नाशवान फसलों (फलों और सब्जियों) में किसानों की हिस्सेदारी कम होती है और गैर-नाशवान फसलों की तुलना में व्यापारी/खुदरा विक्रेता का मार्क-अप अधिक होता है। उपभोक्ता कीमतों में व्यापारियों और खुदरा विक्रेताओं की संयुक्त हिस्सेदारी नाशवान फसलों (टमाटर को छोड़कर) में आधे से अधिक है। खरीफ सीजन की तुलना में रबी सीजन के दौरान टीओपी फसलों के संबंध में व्यापारियों और खुदरा विक्रेताओं के मार्क-अप कम पाए गए जिससे रबी सीजन के दौरान नाशवान फसल की बहुतायत से उपलब्धता का असर परिलक्षित होता है। हालांकि कृषि आपूर्ति शृंखला में भुगतान में नकद लेनदेन का आधिक्य है, लेकिन 2024 के सर्वेक्षण में इलेक्ट्रॉनिक भुगतान में सभी प्रतिभागियों के संदर्भ में 2018 और 2022 के पिछले सर्वेक्षणों की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। रबी की बुवाई के बारे में किसानों के निर्णय में मौसम का पूर्वानुमान और सिंचाई की उपलब्धता सबसे महत्वपूर्ण कारक प्रतीत होते हैं।

सर्वेक्षण डेटा का उपयोग करते हुए मार्क-अप का अनुभवजन्य विश्लेषण यह दर्शाता है कि उच्च लेन-देन लागत (परिवहन, श्रम, किराया) खुदरा विक्रेताओं के मार्क-अप को कम कर देती है, जबकि नाशवान उत्पादों में फसल-पश्चात होने वाला उच्च घाटा खुदरा विक्रेताओं द्वारा उपभोक्ताओं के माध्यम से वसूला जा सकता है।

कुल मिलाकर, सर्वेक्षण के निष्कर्ष और विश्लेषण से पता चलता है कि कोल्ड स्टोरेज और परिवहन प्रणालियों में निवेश बढ़ाकर बाजार के बुनियादी ढांचे को और मजबूत करने से कृषि आपूर्ति शृंखला को और अधिक कुशल बनाया जा सकता है और कटाई के बाद होने वाले अपव्यय को कम किया जा सकता है। प्रौद्योगिकी और हितधारकों के बीच बेहतर सहयोग ऐसे बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, जिससे अंततः उत्पादकों के साथ-साथ उपभोक्ताओं को भी लाभ होगा।

References

Bhattacharya, R. (2016). How does Supply Chain Distortion affect Food Inflation in India?. National Institute of Public Finance and Policy.

Bhoi, B., Kundu, S. Kishore, V and Suganthi, D. (2019). Supply Chain Dynamics and Food Inflation in India. RBI Bulletin, October.

Das, R., Roy, R., Gupta, S., Bordoloi, S., Kumar, R., Mohan, R. and Gulati, A. Price Dynamics and Value Chain of Fruits in India: A Study of Grapes, Bananas and Mangoes. RBI WPS (DEPR), 06/2024.

Duarte, A.L.C.M., Rodrigues, V.P., & Costa, L.B.M. (2024). The Sustainability Challenges of Fresh Food Supply Chains: An Integrative Framework. Environment, Development and Sustainability. April. (doi: 10.1007/s10668-024-04850-9).

EU (2024). https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/agri-food-supply-chain/market-transparency_en (European Commission).

Gandhi, V.P. and Namboodiri, N.V. (2002). Fruit and Vegetable Marketing and its Efficiency in India: A Study of Wholesale Markets in the Ahmedabad Area. Indian Institute of Management. Ahmedabad.

Government of India (GoI) (2015). *Chapter 08: A National Market for Agricultural Commodities- Some Issues and the Way Forward.* Economic Survey (2014-15), Ministry of Finance.

Government of India (GoI) (2025). *Chapter 04: Price and inflation:- understanding the dynamics.* Economic Survey (2024-25), Ministry of Finance.

Government of India (GoI) (2024). *National Policy Framework on Agricultural Marketing (Draft).* Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare. (https://www.dmi.gov.in/Documents/DraftNationalPolicyFrameworkOnAgriculturalMarketingPublicComments.pdf)

Government of India (GoI) (2022). PM Formalisation of Micro Food Processing Enterprises Scheme. E-Newsletter. Mustard Special. November. (https://pmfme.mofpi.gov.in/pmfme/newsletters/enewsmustardspecial1.html)

Gulati, A., Wardhan, H. and Sharma, P. (2022). Tomato, Onion and Potato (TOP) Value Chains. Agricultural Value Chains in India, 33.

Jose, J., Kishore, V. and Bhoi, B.B. (2021). COVID-19 Impact on Food Price Mark-ups in India. RBI Bulletin.

Jose, S., Gupta, S., Prasad, M.K., Das, S., George, A.T., Sonna, T., Suganthi, D. and Gulati, A. (2024) Pulses Inflation in India: A Study of Gram, Tur and Moong. RBI WPS (DEPR), 07/2024.

Kumar, A. and Agrawal, S. (2023). Challenges and Opportunities for Agri-Fresh Food Supply Chain Management in India. Computers and Electronics in Agriculture. Volume 212. (doi: 10.1016/j.compag.2023.108161).

Kumar, A., Mangla, S., Kumar, P. and Karamperidis, S. (2020). Challenges in Perishable Food Supply Chains for Sustainability Management: A Developing Economy Perspective, Business Strategy and the Environment, 29(5). pp. 1809-1831. (doi: 10.1002/bse.2470).

Kumar, S., Bhargava, H., Singh, P., Singh, J. and Verma, S.K. (2023). Economic Analysis of Marketing Channel of Wheat Production in Hardoi District of Western Uttar Pradesh, India. Asian Journal of Agricultural Extension, Economics &Sociology. Volume 41. Issue 10. pp140-148.

Malik, D.P., Devi, M. and Reddy, A.A. (2022). Global Status of Lentil Production with Special Reference to India. Indian Journal of Agricultural Sciences 92 (4). April.

National Horticulture Board (2021). National International Year of Fruits and Vegetables. October. (https://www.nhb.gov.in/KnowledgeCenter/IFVY-Presentation-Nov.pdf)

Patidar, R., Agrawal, S. and Pratap, S. (2018). Development of Novel Strategies for Designing Sustainable Indian Agri-Fresh Food Supply Chain. Indian Academy of Sciences. Sadhana 43:167. (doi: 10.1007/s12046-018-0927-6).

Rais M. and Sheoran, A. (2015). Scope of Supply Chain Management in Fruits and Vegetables in India. Journal of Food Processing & Technology. 6: 427. (doi: 10.4172/2157-7110.1000427).

Rajasthan Agricultural Competitiveness Project (RACP) (2016). Value Chain Analysis- Wheat. Prepared by Grant Thornton. Delhi.

Roy, R., Gupta, S., Wardhan, H., Sarkar, S., Tewari, S., Bansal, R., Bhatia S. and Gulati, A (2024). Vegetables Inflation in India: A Study of Tomato, Onion and Potato (TOP). RBI WPS (DEPR), 08/2024.

Saini, S., Khatri, P. and Hussain, S. (2024). Change in Farmers Stocking and Marketing Decisions: Findings from Survey of Gram and Mustard Farmers in Madhya Pradesh and Rajasthan. Arcus Research Report 4. New Delhi. March.

Singh, R.K., Patil, T., Pandey, D. and Sawarkar, A.N. (2021). Pyrolysis of Mustard Oil Residue: A Kinetic and Thermodynamic Study. Bioresource Technology. Volume 339, November.

Suganthi, D., Kumar, R. and Sethi, M. (2024). Agriculture Supply Chain Dynamics: Evidence from Pan-India Survey. RBI Bulletin, January.

Tchonkouang, R. D., Onyeaka, H. and Nkoutchou, H. (2024). Assessing the Vulne*rabi*lity of Food Supply Chains to Climate Change-Induced Disruptions. *Science of the Total Environment*, 171047.

Villacis, A.H., Kopp, T and Mishra, A.K. (2024). Agricultural Marketing Channels and Market Prices: Evidence from High-Value Crop Producers in India. Economic Analysis and Policy. Volume 81. pp 1308-1321. (https://doi.org/10.1016/j.eap.2024.02.004).

World Bank (2024). Data from the Global Findex 2021: Digitalizing Agricultural Payments in Sub-Saharan Africa. Regional Note. November. (https://www.worldbank.org/en/publication/globalfindex/brief/data-from-the-global-findex-2021-digitalizing-agricultural-payments-in-sub-Saharan-africa).

Zafar, S., Aarif, M. and Tarique, M. (2023). Input Subsidies, Public Investments and Agricultural Productivity in India. *Futur Bus J* **9**, 54 (2023).

अनुलग्नक 1: कृषि आपूर्ति शृंखला में सुधार के लिए सरकारी योजनाएं

कृषि आपूर्ति शृंखला में सुधार के लिए सरकार ने हाल के वर्षों में विभिन्न योजनाएं लागू की हैं। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं इस प्रकार हैं:

1. ई-एनएएम

ई-राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-एनएएम), एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है, जिसे 2016 में शुरू किया गया था। यह कृषि उपज बाजार समिति (एपीएमसी) मंडियों को आपस में जोड़कर कृषि पण्यों के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाता है। वर्तमान में, 23 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों की 1410 मंडियाँ ई- ई-एनएएम पर एकीकृत हैं।

2. कृषि विपणन अवसंरचना (एएमआई) योजना

एएमआई योजना ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भंडारण क्षमता को बढ़ाने के लिए गोदामों और गोदामों के निर्माण या नवीनीकरण में सहायता करती है। 1 अप्रैल 2001 को योजना की शुरुआत की गई और तब से लेकर 30 जून 2024 तक 27 राज्यों में 940 लाख टन की संयुक्त क्षमता वाली कुल 48,512 भंडारण अवसंरचना परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिसके लिए 4,735 करोड़ रुपये की सब्सिडी वितरित की गई है।

3. कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ) योजना

एआईएफ योजना का उद्देश्य कृषि अवसंरचना विकास के लिए निवेश आकर्षित करना है, जिसके लिए 2025-26 तक कुल 1 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। इस योजना के तहत, कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउस, ग्रेडिंग और सॉर्टिंग यूनिट और ई-मार्केटिंग प्लेटफॉर्म जैसे फार्म-गेट इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश के लिए रियायती ब्याज दरों पर ऋण प्रदान किया जाता है। जनवरी 2025 तक, इस योजना के तहत 89,028 परियोजनाओं के लिए 53,687 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।

4. एकीकृत कोल्ड चेन, खाद्य प्रसंस्करण और परिरक्षण अवसंरचना योजना

एकीकृत कोल्ड चेन, खाद्य प्रसंस्करण और परिरक्षण अवसंरचना योजना का उद्देश्य खेत से उपभोक्ता तक संपर्क स्थापित करके कृषि, बागवानी, डेयरी, मछली और समुद्री उत्पाद, पोल्ट्री और मांस उत्पादों के लिए एक मजबूत कोल्ड चेन सुविधा की स्थापना की सुविधा प्रदान करना है, ताकि कुशल भंडारण, परिवहन और न्यूनतम प्रसंस्करण के माध्यम से अपव्यय को कम किया जा सके। अगस्त 2024 की स्थिति के अनुसार देश में 396 लाख मीट्रिक टन क्षमता वाले 8,698 कोल्ड स्टोरेज हैं। इसके अलावा, भारत सरकार ने विशेष रूप से नाशवान कृषि-बागवानी वस्तुओं की आवाजाही को पूरा करने के लिए *किसान रेल* शुरू की है।

5. प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना

वर्ष 2025-26 के बजट में अल्प उत्पादकता वाले 100 जिलों में 'प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना' शुरू करने की घोषणा की गई है, जिसमें पंचायत और ब्लॉक स्तर पर फसल-उपरांत भंडारण बढ़ाने के उपाय किए जाएंगे।

6. सब्जियों और फलों के लिए व्यापक कार्यक्रम

वर्ष 2025-26 के बजट में राज्यों के साथ साझेदारी के साथ किसानों के लिए उत्पादन, कुशल आपूर्ति, प्रसंस्करण और लाभकारी मूल्य को बढ़ावा देने के लिए सब्जियों और फलों के लिए एक व्यापक कार्यक्रम की भी घोषणा की गई। कार्यान्वयन और किसान उत्पादक संगठनों और सहकारी समितियों की भागीदारी के लिए उपयुक्त संस्थागत तंत्र भी स्थापित किए जाएंगे। सरकार ने उच्च मूल्य वाले नाशवान बागवानी उत्पादों सहित एयर कार्गो के लिए बुनियादी ढांचे और गोदाम को उन्नत करने की भी घोषणा की।

वर्तमान सांख्यिकी

चुनिंदा आर्थिक संकेतक

भारतीय रिज़र्व बैंक

मुद्रा और बैंकिंग

मूल्य और उत्पादन

सरकारी खाते और खज़ाना बिल

वित्तीय बाजार

बाह्य क्षेत्र

भुगतान और निपटान प्रणालियाँ

आवसरिक शृंखलाएं

विषयवस्तु

संख्या	शीर्षक	पृष्ठ
1	चुनिंदा आर्थिक संकेतक	119
	भारतीय रिज़र्व बैंक	
2	भारतीय रिज़र्व बैंक - देयताएं और आस्तियां	120
3	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा चलनिधि परिचालन	121
4	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अमेरिकी डॉलर का क्रय/विक्रय	122
4ए	भारतीय रिज़र्व बैंक के बकाया वायदे का (अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार) परिपक्वता विश्लेषण (मिलियन अमेरिकी डॉलर)	123
5	भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थायी सुविधाएं	123
	मुद्रा और बैंकिंग	
6	मुद्रा स्टॉक मात्रा	124
7	मुद्रा स्टॉक (एम$_3$) के स्रोत	125
8	मौद्रिक सर्वेक्षण	126
9	कुल चलनिधि राशियाँ	127
10	भारतीय रिज़र्व बैंक सर्वेक्षण	128
11	आरक्षित मुद्रा- घटक और स्रोत	128
12	वाणिज्यिक बैंक सर्वेक्षण	129
13	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के निवेश	129
14	भारत में कारोबार - सभी अनुसूचित बैंक और सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	130
15	प्रमुख क्षेत्रों द्वारा सकल बैंक ऋण का विनियोजन	131
16	सकल बैंक ऋण का उद्योग-वार विनियोजन	132
17	भारतीय रिज़र्व बैंक में राज्य सहकारी बैंकों के खाते	133
	मूल्य और उत्पादन	
18	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधारः 2012=100)	134
19	अन्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	134
20	मुंबई में सोने और चांदी का मासिक औसत मूल्य	134
21	थोक मूल्य सूचकांक	135
22	औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आधारः 2011-12=100)	139
	सरकारी खाते और खज़ाना बिल	
23	केन्द्र सरकार के खाते - एक नज़र में	139
24	खज़ाना बिल - स्वामित्व का स्वरूप	140
25	खज़ाना बिलों की नीलामी	140
	वित्तीय बाजार	
26	दैनिक मांग मुद्रा दरें	141
27	जमाराशि प्रमाण-पत्र	142
28	वाणिज्यिक पत्र	142
29	चुनिंदा वित्तीय बाजारों में औसत दैनिक टर्नओवर	142
30	गैर-सरकारी पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के नए पूंजी निर्गम	143

संख्या	शीर्षक	पृष्ठ
	बाह्य क्षेत्र	
31	विदेशी व्यापार	144
32	विदेशी मुद्रा भंडार	144
33	अनिवासी भारतीयों की जमाराशियाँ	144
34	विदेशी निवेश अंतर्वाह	145
35	निवासी भारतीयों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) के अंतर्गत जावक विप्रेषण	145
36	भारतीय रुपये का सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर (एनईईआर) और वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आरईईआर) सूचकांक	146
37	बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) - पंजीकरण	147
38	भारत का समग्र भुगतान संतुलन (मिलियन अमेरिकी डॉलर)	148
39	भारत का समग्र भुगतान संतुलन (₹ करोड़)	149
40	बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण (मिलियन अमेरिकी डॉलर)	150
41	बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण (₹ करोड़)	151
42	भारत की अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति	152
	भुगतान और निपटान प्रणालियाँ	
43	भुगतान प्रणाली संकेतक	153
	आवसरिक श्रृंखलाएं	
44	लघु बचत	155
45	केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों के स्वामित्व का स्वरूप	156
46	केन्द्र और राज्य सरकारों की संयुक्त प्राप्तियां और संवितरण	157
47	विभिन्न सुविधाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा ली गई वित्तीय सहायता	158
48	राज्य सरकारों द्वारा किए गए निवेश	159
49	राज्य सरकारों की बाज़ार उधारियां	160
50 (ए)	हाउसहोल्ड की वित्तीय आस्तियों और देयताओं का प्रवाह-लिखत-वार	161
50 (बी)	हाउसहोल्ड की वित्तीय आस्तियों और देयताओं का स्टॉक-चुनिंदा संकेतक	164

टिप्पणियां: .. = उपलब्ध नहीं।

– = शून्य/नगण्य

प्रा/अ = प्रारंभिक/अनंतिम   आंसं = आंशिक रूप से संशोधित

सं. 1: चुनिंदा आर्थिक संकेतक

मद	2023-24	2023-24		2024-25	
		ति1	ति2	ति1	ति2
	1	2	3	4	5
1 वास्तविक क्षेत्र (% परिवर्तन)					
1.1 आधार मूल्यों पर जीवीए	7.2	8.3	7.7	6.8	5.6
1.1.1 कृषि	1.4	3.7	1.7	2.0	3.5
1.1.2 उद्योग	9.3	5.0	13.6	7.4	2.1
1.1.3 सेवाएं	7.9	10.4	6.9	7.7	7.1
1.1ए अंतिम खपत व्यय	3.8	4.6	4.1	6.3	5.7
1.1बी सकल नियत पूंजी निर्माण	9.0	8.5	11.6	7.5	5.4
	2023-24	2023		2024	
		नवं.	दिसं.	नवं.	दिसं.
	1	2	3	4	5
1.2 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक	5.9	2.5	4.4	5.0	3.2
2 मुद्रा और बैंकिंग (% परिवर्तन)					
2.1 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक					
2.1.1 जमाराशियाँ	12.9	13.5	12.6	11.1	10.2
	(13.5)	(14.2)	(13.3)	(10.7)	(9.8)
2.1.2 ऋण#	16.3	16.7	15.6	11.8	12.4
	(20.2)	(21.1)	(20.0)	(10.6)	(11.2)
2.1.2.1 गैर-खाद्यान्न ऋण#	16.3	16.8	15.8	11.8	12.4
	(20.2)	(21.3)	(20.1)	(10.6)	(11.1)
2.1.3 सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	11.1	15.6	15.6	9.5	11.1
	(12.8)	(17.7)	(17.6)	(8.4)	(10.1)
2.2 मुद्रा स्टॉक मात्रा					
2.2.1 आरक्षित मुद्रा (एम0)	5.6	6.7	6.0	7.1	4.9
2.2.2 स्थूल मुद्रा (एम3)	11.1	11.2	11.0	11.1	9.3
	(9.0)	(11.8)	(11.5)	(10.8)	(9.0)
3 अनुपात (%)					
3.1 आरक्षित नकदी निधि अनुपात	4.50	4.50	4.50	4.50	4.25
3.2 सांविधिक चलनिधि अनुपात	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00
3.3 नकदी-जमा अनुपात	5.0	5.2	5.2	5.1	4.7
	(5.0)	(5.2)	(5.2)	(5.1)	(4.7)
3.4 ऋण-जमा अनुपात	78.1	77.2	77.1	77.7	78.7
	(80.3)	(79.6)	(79.5)	(79.5)	(80.4)
3.5 वृद्धिशील ऋण-जमा अनुपात#	95.8	92.3	89.1	72.8	86.1
	(113.4)	(118.8)	(111.9)	(69.8)	(82.6)
3.6 निवेश-जमा अनुपात	29.5	29.8	29.5	29.6	29.8
	(29.8)	(30.2)	(29.8)	(29.7)	(29.9)
3.7 वृद्धिशील निवेश-जमा अनुपात	25.8	27.8	24.7	29.9	32.6
	(28.4)	(31.8)	(28.2)	(28.1)	(30.8)
4 ब्याज दरें (%)					
4.1 नीति रेपो दर	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50
4.२ स्थायी रिवर्स रेपो दर	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35
4.3 स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) दर*	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25
4.4 सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर	6.75	6.75	6.75	6.75	6.75
4.5 बैंक दर	6.75	6.75	6.75	6.75	6.75
4.6 आधार दर	9.10/10.25	8.95/10.10	8.95/10.25	9.10/10.40	9.10/10.40
4.7 एमसीएलआर (एक दिन के लिए)	8.00/8.60	7.95/8.50	7.95/8.50	8.15/8.45	8.15/8.45
4.8 मीयादी जमा दर >1 वर्ष	6.50/7.25	6.00/7.25	6.50/7.25	6.00/7.25	6.00/7.25
4.9 बचत जमा दर	2.70/3.00	2.70/3.00	2.70/3.00	2.70/3.00	2.70/3.00
4.10 मांग मुद्रा दर (भारित औसत)	6.85	6.79	6.81	6.70	6.71
4.11 91-दिवसीय खज़ाना बिल (प्राथमिक) प्रतिफल	-	6.96	6.93	6.49	6.55
4.12 182-दिवसीय खज़ाना बिल (प्राथमिक) प्रतिफल	7.28	7.16	7.16	6.66	6.70
4.13 364-दिवसीय खज़ाना बिल (प्राथमिक) प्रतिफल	7.31	7.15	7.13	6.65	6.69
4.14 10-वर्षीय सरकारी प्रतिभूतियों सममूल्य प्रतिफल (एफबीआईएल)	7.31	7.31	7.20	6.79	6.76
5 संदर्भ दर और वायदा प्रीमियम					
5.1 भा.रु.-अमेरिकी डालर हाजिर दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	83.37	83.37	83.12	84.50	85.59
5.2 भा.रु.-यूरो हाजिर दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	90.22	90.93	92.00	89.36	89.11
5.3 अमेरिकी डॉलर का वायदा प्रीमियम 1-माह (%)	1.00	0.95	1.23	1.94	3.70
3-माह (%)	1.11	1.12	1.65	1.98	2.91
6-माह (%)	1.31	1.47	1.51	2.18	2.61
6 मुद्रास्फीति (%)					
6.1 अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	5.4	5.6	5.7	5.5	5.2
6.2 औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	5.19	5.0	4.9	3.9	-
6.3 थोक मूल्य सूचकांक	-0.7	0.4	0.9	2.2	2.4
6.3.1 प्राथमिक वस्तुएं	3.5	5.2	5.7	5.5	6.0
6.3.2 ईंधन और बिजली	-4.7	-4.1	-1.4	-4.0	-3.8
6.3.3 विनिर्मित उत्पाद	-1.7	-0.8	-0.8	2.1	2.1
7 विदेशी व्यापार (% परिवर्तन)					
7.1 आयात	-5.3	-3.3	-6.6	16.0	4.9
7.2 निर्यात	-3.1	-3.3	0.8	-5.1	-1.0

टिप्पणी : फाइनेंसियल बेंचमार्क इंडिया प्रा. लि. (एफबीआईएल) ने भारतीय रिज़र्व बैंक के 31 मार्च 2018 के परिपत्र एफएमआरडी.डीआईआरडी.7/14.03.025/ 2017-18 के अनुसार 31 मार्च 2018 से जी सेक बेंचमार्क का प्रकाशन शुरू किया है। एफबीआईएल ने 10 जुलाई 2018 से संदर्भ दरों का प्रसार शुरू किया है।

#: 3 दिसंबर 2021 से 18 नवंबर 2022 तक सभी पखवाड़ों के लिए चुनिंदा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) द्वारा बैंक ऋण वृद्धि और संबंधित अनुपात को पिछली रिपोर्टिंग त्रुटियों के लिए समायोजित किया जाता है।

कोष्टकों में दिए गए आंकड़ों में एक गैर-बैंक के बैंक के साथ विलय का प्रभाव शामिल है।

*: दिनांक 8 अप्रैल 2022 की प्रेस प्रकाशनी सं. 2022-2023/41 के अनुसार।

भारतीय रिज़र्व बैंक

सं. 2: भारतीय रिज़र्व बैंक - देयताएं और आस्तियां*

(₹ करोड़)

मद	अंतिम शुक्रवार/शुक्रवार की स्थिति						
	2024-25	2024	2025				
		जन.	जन. 03	जन. 10	जन. 17	जन. 24	जन. 31
	1	2	3	4	5	6	7
1 निर्गम विभाग							
1.1 देयताएं							
1.1.1 संचलन में नोट	3482333	3386320	3525972	3554284	3558938	3564296	3564965
1.1.2 बैंकिंग विभाग में रखे गए नोट	11	13	12	11	14	10	12
1.1/1.2 कुल देयताएं (जारी किए गए कुल नोट) या आस्तियां	**3482344**	**3386333**	**3525984**	**3554295**	**3558952**	**3564306**	**3564977**
1.2 आस्तियां							
1.2.1 स्वर्ण	162996	149322	203530	206786	211605	212741	217109
1.2.2 विदेशी प्रतिभूतियां	3318885	3236716	3322233	3347167	3347062	3351157	3347525
1.2.3 रुपया सिक्का	463	296	221	342	285	407	343
1.2.4 भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियां	-	-	-	-	-	-	-
2 बैंकिंग विभाग							
2.1 देयताएं							
2.1.1 जमाराशियाँ	1782333	1734444	1373553	1444233	1399704	1525243	1446595
2.1.1.1 केंद्र सरकार	101	100	101	101	101	101	101
2.1.1.2 बाजार स्थिरीकरण योजना		-	-	-	-	-	-
2.1.1.3 राज्य सरकारें	42	42	42	42	42	42	42
2.1.1.4 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	1008618	933808	908538	930602	897242	889895	924083
2.1.1.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	10092	8039	8502	7814	7798	7918	7772
2.1.1.6 गैर-अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	6412	4935	4887	4744	4638	4701	4567
2.1.1.7 अन्य बैंक	48725	47419	45270	45584	45309	45901	46275
2.1.1.8 अन्य	545400	593671	322155	350161	333913	463478	362067
2.1.1.9 भारत के बाहर के वित्तीय संस्थान	162944	146428	84056	105184	110661	113207	101688
2.1.2 अन्य देयताएं	1804747	1732677	1926522	1926074	1989935	2002933	2034572
2.1/2.2 कुल देयताएं या आस्तियां	**3587080**	**3467121**	**3300075**	**3370307**	**3389639**	**3528176**	**3481167**
2.2 आस्तियां							
2.2.1 नोट और सिक्के	11	13	12	11	14	10	12
2.2.2 विदेशों में धारित राशियाँ	1480408	1345848	1392917	1296048	1306132	1320797	1344426
2.2.3 ऋण और अग्रिम							
2.2.3.1 केन्द्र सरकार	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3.2 राज्य सरकारें	2300	12810	36637	14620	23623	20495	19332
2.2.3.3 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	266021	337637	130502	292649	262197	354098	256989
2.2.3.4 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3.5 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3.6 नाबार्ड	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3.7 एक्जिम बैंक	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3.8 अन्य	12398	3174	7917	8546	13918	20797	20988
2.2.3.9 भारत के बाहर की वित्तीय संस्थाएं	162650	145120	83484	104009	109927	112893	101053
2.2.4 खरीदे और भुनाए गए बिल							
2.2.4.1 आंतरिक	-	-	-	-	-	-	-
2.2.4.2 सरकारी खज़ाना बिल	-	-	-	-	-	-	-
2.2.5 निवेश	1365425	1360963	1256837	1257276	1267735	1290478	1319974
2.2.6 अन्य आस्तियां	297868	261555	391769	397148	406092	408607	418394
2.2.6.1 स्वर्ण	272028	245322	372000	376786	385567	387637	396899

* डेटा अनंतिम हैं।

सं. 3: भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा चलनिधि परिचालन

(₹ करोड़)

दिनांक	चलनिधि समायोजन सुविधा						स्थायी चलनिधि सुविधाएं	ओएमओ (एकमुश्त)		निवल अंतर्वेशन (+)/ अवशोषण (-) (1+3+5+7+9-2-4-6-8)
	रेपो	रिवर्स रेपो	परिवर्तन-शील रेपो दर	परिवर्तन-शील रिवर्स रेपो दर	एमएसएफ	एसडीएफ		विक्रय	क्रय	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
दिसं. 1, 2024	-	-	-	-	2145	40879	-	-	-	-38734
दिसं. 2, 2024	-	-	-	-	1450	99633	-	-	-	-98183
दिसं. 3, 2024	-	-	-	-	1246	108694	-1501	-	-	-108949
दिसं. 4, 2024	-	-	-	-	3287	75455	-968	-	-	-73136
दिसं. 5, 2024	-	-	-	-	5041	54725	1051	-	-	-48633
दिसं. 6, 2024	-	-	-	-	7066	76733	1199	-	-	-68468
दिसं. 7, 2024	-	-	-	-	5179	57178	-	-	-	-51999
दिसं. 8, 2024	-	-	-	-	59	44956	-	-	-	-44897
दिसं. 9, 2024	-	-	40630	-	826	73311	-	-	-	-31855
दिसं. 10, 2024	-	-	-	-	8844	53024	-	-	-	-44180
दिसं. 11, 2024	-	-	25005	-	5314	85961	-	-	-	-55642
दिसं. 12, 2024	-	-	-	-	1231	98910	-	-	-	-97679
दिसं. 13, 2024	-	-	75004	-	31070	140196	-	-	-	-34122
दिसं. 14, 2024	-	-	-	-	21036	75236	-	-	-	-54200
दिसं. 15, 2024	-	-	-	-	17896	89924	-	-	-	-72028
दिसं. 16, 2024	-	-	75775	-	24824	76241	-	-	-	24358
दिसं. 17, 2024	-	-	73193	-	295	90072	-	-	-	-16584
दिसं. 18, 2024	-	-	-	-	1734	61125	-1439	-	-	-60830
दिसं. 19, 2024	-	-	-	-	3280	52003	1016	-	-	-47707
दिसं. 20, 2024	-	-	150004	-	4838	64844	674	-	-	90672
दिसं. 21, 2024	-	-	-	-	13552	50583	-	-	-	-37031
दिसं. 22, 2024	-	-	-	-	11972	46614	-	-	-	-34642
दिसं. 23, 2024	-	-	111281	-	258	104798	-	-	-	6741
दिसं. 24, 2024	-	-	37953	-	314	105859	-	-	-	-67592
दिसं. 25, 2024	-	-	-	-	9210	99023	-	-	-	-89813
दिसं. 26, 2024	-	-	-	-	913	119377	-	-	-	-118464
दिसं. 27, 2024	-	-	213570	-	31127	61909	-	-	20	182808
दिसं. 28, 2024	-	-	-	-	17087	48120	-	-	-	-31033
दिसं. 29, 2024	-	-	-	-	16460	50576	-	-	-	-34116
दिसं. 30, 2024	-	-	83238	-	385	99913	-	-	-	-16290
दिसं. 31, 2024	-	-	50004	-	298	138004	8375	-	-	-79327

सं. 4: भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अमेरिकी डॉलर का क्रय/विक्रय

i) तटीय/ अपतटीय ओटीसी खंड में परिचालन

मद	2023-24	2023	2024	
		दिसं.	नवं.	दिसं.
	1	2	3	4
1 विदेशी मुद्रा का निवल क्रय/विक्रय (मिलियन अमेरिकी डॉलर) (1.1-1.2)	41271	2067	-20228	-15150
1.1 क्रय (+)	194296	31730	30880	53898
1.2 विक्रय (-)	153025	29663	51108	69048
2 संविदा दर पर ₹ के बराबर (₹ करोड़)	339528	17234	-170630	-128753
3 संचयी (मार्च के अंत से) (मिलियन अमेरिकी डॉलर)	41271	17515	-20956	-36106
(₹ करोड़)	339528	142319	-177653	-306406
4 माह के अंत में बकाया निवल वायदा विक्रय (-)/क्रय (+) (मिलियन् अमेरिकी डॉलर)	-541	2184	-58850	-67938

ii) मुद्रा वायदा खंड में परिचालन

मद	2023-24	2023	2024	
		दिसं.	नवं.	दिसं.
	1	2	3	4
1 विदेशी मुद्रा का निवल क्रय/विक्रय (मिलियन अमेरिकी डॉलर) (1.1-1.2)	0	0	0	0
1.1 क्रय (+)	7930	1397	3926	3552
1.2 विक्रय (-)	7930	1397	3926	3552
2 माह के अंत में बकाया निवल मुद्रा वायदा विक्रय (-)/क्रय (+) (मिलियन अमेरिकी डॉलर)	-1080	-1558	-2968	-3450

सं. 4ए: भारतीय रिज़र्व बैंक के बकाया वायदे का (अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार) परिपक्वता विश्लेषण (मिलियन अमेरिकी डॉलर)

मद	31 दिसंबर 2024 तक		
	दीर्घ (+)	अल्प (-)	निवल (1-2)
	1	2	3
1. 1 माह तक	250	34060	-33810
2. 1 माह से अधिक और 3 माह तक	0	24253	-24253
3. 3 माह से अधिक और 1 वर्ष तक	0	9875	-9875
4. 1 वर्ष से अधिक	0	0	0
कुल (1+2+3+4)	**250**	**68188**	**-67938**

सं. 5: भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थायी सुविधाएं

(₹ करोड़)

मद	रिपोर्टिंग अंतिम शुक्रवार की स्थिति							
	2023-24	2024						2025
		जन. 26	अग. 23	सितं. 20	अक्तू. 18	नवं. 29	दिसं. 27	जन. 24
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 सीमांत स्थायी सुविधा	49906	32611	1818	21731	4216	18513	31127	3232
2 अनुसूचित बैंकों के लिए निर्यात ऋण पुर्नवित्त								
2.1 सीमा	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 बकाया	-	-	-	-	-	-	-	-
3 प्राथमिक व्यापारियों के लिए चलनिधि सुविधा								
3.1 सीमा	9900	4900	9900	9900	9900	9900	9900	9900
3.2 बकाया	9810	3174	8541	8547	7223	8428	8459	9556
4 अन्य								
4.1 सीमा	76000	76000	76000	76000	76000	76000	76000	76000
4.2 बकाया	-	-	-	-	-	-	-	-
5 कुल बकाया (1+2.2+3.2+4.2)	59716	35785	10359	30278	11439	26941	39586	12788

मुद्रा और बैंकिंग

सं. 6: मुद्रा स्टॉक मात्रा

(₹ करोड़)

मद	मार्च 31 /माह के रिपोर्टिंग अंतिम शुक्रवार/रिपोर्टिंग शुक्रवार की बकाया स्थिति				
	2023-24	**2023**	**2024**		
		दिसं. 29	**नवं. 29**	**दिसं. 13**	**दिसं. 27**
	1	2	3	4	5
1 जनता के पास मुद्रा (1.1 + 1.2 + 1.3 - 1.4)	3410276	3256115	3444217	3476238	3459713
1.1 संचलन में नोट	3477795	3330296	3510709	3535571	3524608
1.2 रुपये सिक्के का संचलन	32689	31853	34676	34676	34676
1.3 छोटे सिक्कों का संचलन	743	743	743	743	743
1.4 बैंकों के पास नकदी	101185	106881	102752	95625	101225
2 जनता की जमाराशियाँ	2681424	2661541	2821629	2850537	2812342
2.1 बैंकों के पास मांग जमाराशियाँ	2586888	2580490	2718636	2751293	2710713
2.2 रिजर्व बैंक के पास 'अन्य' जमाराशियाँ	94536	81051	102993	99244	101629
3 एम1 (1+2)	**6091700**	**5917655**	**6265846**	**6326776**	**6272055**
4 डाकघर बचत बैंक जमाराशियाँ	195777	216978	200889	200889	200889
5 एम2 (3+4)	**6287477**	**6134633**	**6466735**	**6527665**	**6472944**
6 बैंकों के पास मीयादी जमाराशियाँ	18739918	18338335	20182384	20195916	20240455
	(18848160)	(18459622)	(20251544)	(20263731)	(20307146)
7 एम3 (3+6)	24831618	24255990	26448230	26522691	26512510
	(24939860)	(24377277)	(26517391)	(26590507)	(26579200)
8 कुल डाकघर जमाराशियाँ	1313366	1258895	1379283	1379283	1379283
9 एम4 (7+8)	26144984	25514885	27827513	27901974	27891793
	(26253226)	(25636172)	(27896674)	(27969790)	(27958483)

कोष्ठक में दिए गए आंकड़ों में एक गैर-बैंक के बैंक में विलय का प्रभाव शामिल है।

सं. 7: मुद्रा भंडार (एम$_3$) के स्रोत

(₹ करोड़)

स्रोत	मार्च 31 / माह के रिपोर्टिंग अंतिम शुक्रवार/रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2023-24	2023	2024		
		दिसं. 29	नवं. 29	दिसं. 13	दिसं. 27
	1	2	3	4	5
1 सरकार को निवल बैंक ऋण	**7512016**	**7171807**	**8035414**	**8048578**	**7850250**
1 सरकार को निवल बैंक ऋण (विलय सहित)	(7603571)	(7272617)	(8086633)	(8099444)	(7901119)
1.1 आरबीआई का सरकार को निवल ऋण (1.1.1-1.1.2)	1193213	979659	1242346	1239095	1000891
1.1.1 सरकार पर दावे	1370428	1360482	1287452	1301462	1276034
1.1.1.1 केन्द्र सरकार	1363828	1357903	1270987	1272718	1254193
1.1.1.2 राज्य सरकारें	6600	2579	16465	28744	21841
1.1.2 आरबीआई के पास सरकार की जमाराशियाँ	177215	380824	45106	62366	275143
1.1.2.1 केन्द्र सरकार	177172	380781	45064	62324	275101
1.1.2.2 राज्य सरकारें	42	43	42	42	42
1.2 सरकार को अन्य बैंक ऋण	6318803	6192149	6793069	6809483	6849360
1.2 सरकार को अन्य बैंक ऋण (विलय सहित)	(6410358)	(6292959)	(6844287)	(6860349)	(6900228)
2 वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण	**16672145**	**16136616**	**17835267**	**17900969**	**18090813**
2 वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण (विलय सहित)	(17202832)	(16709688)	(18291281)	(18346470)	(18529356)
2.1 आरबीआई का वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण	14406	5080	10463	10271	10519
2.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को अन्य बैंकों द्वारा दिया गया ऋण	16657739	16131536	17824804	17890698	18080294
2.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को अन्य बैंक ऋण (विलय सहित)	(17188426)	(16704608)	(18280818)	(18336199)	(18518837)
2.2.1 वाणिज्यिक बैंकों द्वारा बैंक ऋण	15901477	15388871	17052942	17141380	17304495
2.2.1 वाणिज्यिक बैंकों द्वारा बैंक ऋण (विलय सहित)	(16432164)	(15961944)	(17508956)	(17586881)	(17743037)
2.2.2 सहकारी बैंकों द्वारा बैंक ऋण	738194	725337	753253	730523	757258
2.2.3 वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों द्वारा अन्य प्रतिभूतियों में निवेश	18068	17327	18610	18794	18541
2.2.3 वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों द्वारा अन्य प्रतिभूतियों में निवेश (विलय सहित)	(18068)	(17327)	(18610)	(18794)	(18541)
3 बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां (3.1 + 3.2)	**5567245**	**5337666**	**5775605**	**5750833**	**5690829**
3.1 आरबीआई की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां (3.1.1-3.1.2)	5240824	5038109	5408898	5384126	5324122
3.1.1 सकल विदेशी आस्तियां	5241083	5038371	5409166	5384388	5324384
3.1.2 विदेशी देयताएं	259	261	268	262	262
3.2 अन्य बैंकों की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	326421	299557	366707	366707	366707
4 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	**33432**	**32596**	**35419**	**35419**	**35419**
5 बैंकिंग क्षेत्र की निवल गैर-मौद्रिक देयताएं	**4953219**	**4422695**	**5233476**	**5213108**	**5154801**
5 बैंकिंग क्षेत्र की निवल गैर-मौद्रिक देयताएं (विलय सहित)	(5467219)	(4975291)	(5671548)	(5641660)	(5577522)
5.1 आरबीआई की निवल गैर-मौद्रिक देयताएं	1789875	1792947	1901186	1915858	1890916
5.2 अन्य बैंकों की निवल गैर-मौद्रिक देयताएं (अवशिष्ट)	3163344	2629748	3332290	3297250	3263885
5.2 अन्य बैंकों की निवल गैर-मौद्रिक देयताएं (अवशिष्ट) (विलय सहित)	(3677343)	(3182344)	(3770362)	(3725802)	(3686606)
एम$_3$ (1+2+3+4-5)	**24831618**	**24255990**	**26448230**	**26522691**	**26512510**
एम$_3$ (1+2+3+4-5) (विलय सहित)	(24939860)	(24377277)	(26517391)	(26590507)	(26579200)

कोष्ठक में दिए गए आंकड़ों में एक गैर-बैंक के बैंक में विलय का प्रभाव शामिल है।

सं. 8: मौद्रिक सर्वेक्षण

(₹ करोड़)

मद	मार्च 31/माह के रिपोर्टिंग अंतिम शुक्रवार/रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2023-24	2023	2024		
		दिसं. 29	नवं. 29	दिसं. 13	दिसं. 27
	1	2	3	4	5
समग्र मौद्रिक राशियाँ					
एनएम$_1$ (1.1 + 1.2.1+1.3)	6091700	5917655	6265846	6326776	6272318
एनएम$_2$ (एनएम$_1$ + 1.2.2.1)	14424855	14081095	15223357	15287032	15252461
एनएम$_2$ (एनएम$_1$ + 1.2.2.1) (विलय सहित)	(14473564)	(14135674)	(15254479)	(15317549)	(15282471)
एनएम$_3$ (एनएम$_2$ + 1.2.2.2 + 1.4 = 2.1 + 2.2 + 2.3 - 2.4 - 2.5)	25387764	24817697	27122450	27105392	27183290
एनएम$_3$ (एनएम$_2$ + 1.2.2.2 + 1.4 = 2.1 + 2.2 + 2.3 - 2.4 - 2.5) (विलय सहित)	(25496006)	(24938984)	(27191610)	(27173207)	(27249981)
1 घटक					
1.1 जनता के पास मुद्रा	3410276	3256115	3444217	3476238	3459977
1.2. निवासियों की कुल जमाराशियाँ	21105009	20721466	22624216	22662975	22666584
1.2. निवासियों की कुल जमाराशियाँ (विलय सहित)	(21213252)	(20842754)	(22693377)	(22730790)	(22733275)
1.2.1 मांग जमाराशियाँ	2586888	2580490	2718636	2751293	2710713
1.2.2 निवासियों की सावधि जमाराशियाँ	18518121	18140977	19905580	19911682	19955872
1.2.2 निवासियों की सावधि जमाराशियाँ (विलय सहित)	(18626364)	(18262264)	(19974741)	(19979497)	(20022562)
1.2.2.1 अल्पावधि सावधि जमाराशियाँ	8333155	8163440	8957511	8960257	8980142
1.2.2.1 अल्पावधि सावधि जमाराशियाँ (विलय सहित)	(8381864)	(8218019)	(8988633)	(8990774)	(9010153)
1.2.2.1.1 जमा प्रमाण-पत्र (सीडी)	369399	342514	493598	484414	499061
1.2.2.2 दीर्घावधि सावधि जमाराशियाँ	10184967	9977537	10948069	10951425	10975729
1.2.2.2 दीर्घावधि सावधि जमाराशियाँ (विलय सहित)	(10244500)	(10044245)	(10986107)	(10988724)	(11012409)
1.3 आरबीआई के पास 'अन्य' जमाराशियाँ	94536	81051	102993	99244	101629
1.4 वित्तीय संस्थाओं से मांग/सावधि निधीयन	777942	759065	951023	866935	955100
2 स्रोत					
2.1 देशी ऋण	25295986	24396448	27060933	27154284	27103156
2.1 देशी ऋण (विलय सहित)	(25918227)	(25070331)	(27568166)	(27650651)	(27592567)
2.1.1 सरकार को निवल बैंक ऋण	7512016	7171807	8035414	8048578	7850250
2.1.1 सरकार को निवल बैंक ऋण (विलय सहित)	(7603571)	(7272617)	(8086633)	(8099444)	(7901119)
2.1.1.1 सरकार को निवल आरबीआई ऋण	1193213	979659	1242346	1239095	1000891
2.1.1.2 बैंकिंग प्रणाली द्वारा सरकार को ऋण	6318803	6192149	6793069	6809483	6849360
2.1.1.2 बैंकिंग प्रणाली द्वारा सरकार को ऋण (विलय सहित)	(6410358)	(6292959)	(6844287)	(6860349)	(6900228)
2.1.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण	17783970	17224641	19025519	19105706	19252905
2.1.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण (विलय सहित)	(18314656)	(17797714)	(19481533)	(19551207)	(19691448)
2.1.2.1 वाणिज्यिक क्षेत्र को आरबीआई ऋण	14406	5080	10463	10271	10519
2.1.2.2 बैंकिंग प्रणाली द्वारा वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण	17769564	17219561	19015056	19095435	19242386
2.1.2.2 बैंकिंग प्रणाली द्वारा वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण (विलय सहित)	(18300250)	(17792634)	(19471070)	(19540936)	(19680929)
2.1.2.2.1 अन्य निवेश (गैर-एसएलआर प्रतिभूतियां)	1089184	1074161	1177017	1189721	1146977
2.2 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	33432	32596	35419	35419	35683
2.3 बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	5110820	4977214	5289237	5372827	5300111
2.3.1 आरबीआई की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	5240824	5038109	5408898	5384126	5324122
2.3.2 बैंकिंग प्रणाली की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	-130004	-60896	-119661	-11299	-24011
2.4 पूंजी खाता	3912897	4020302	4401596	4397734	4396751
2.5 अन्य मदें (निवल)	1653576	1120855	1299617	1487955	1281628

कोष्ठक में दिए गए आंकड़ों में एक गैर-बैंक के बैंक में विलय का प्रभाव शामिल है।

सं. 9: चलनिधि समग्र राशियाँ

(₹ करोड़)

समग्र राशियाँ	2023-24	2023	2024		
		दिसं.	अक्तू.	नवं.	दिसं.
	1	2	3	4	5
1 एनएम$_3$	**25387764**	**24817697**	**26808015**	**27122450**	**27183290**
	(25496006)	(24938984)	(26880587)	(27191610)	(27249981)
2 डाकघर जमाराशियाँ	729246	708478	732774	732774	732774
3 एल$_1$ (1 + 2)	**26117010**	**25526175**	**27540789**	**27855224**	**27916064**
	(26225252)	(25647462)	(27613361)	(27924384)	(27982755)
4 वित्तीय संस्थाओं की देयताएं	85150	68815	68842	66263	73559
4.1 सावधि मुद्रा उधार	2375	1305	31	26	16
4.2 जमा प्रमाण-पत्र	70245	54485	55520	52765	59920
4.3 सावधि जमाराशियाँ	12531	13025	13291	13473	13622
5 एल$_2$ (3 + 4)	**26202160**	**25594990**	**27609631**	**27921487**	**27989623**
	(26310403)	(25716277)	(27682202)	(27990647)	(28056313)
6 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पास जनता की जमाराशियाँ	102994	101152	..	..	102994
7 एल$_3$ (5 + 6)	**26305155**	**25696142**	**..**	**..**	**28092617**

टिप्पणी : 1. संभव है कि पूर्णांकन के कारण कॉलम के आंकड़ों का जोड़ कुल के बराबर न हो।
2. कोष्ठक में दिए गए आंकड़ों में एक गैर-बैंक के बैंक में विलय का प्रभाव शामिल है।

सं. 10: भारतीय रिज़र्व बैंक सर्वेक्षण

(₹ करोड़)

मद	मार्च 31/माह के रिपोर्टिंग अंतिम शुक्रवार/रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2023-24	2023	2024		
		दिसं. 29	नवं. 29	दिसं. 13	दिसं. 27
	1	2	3	4	5
1 घटक					
1.1 संचलन में मुद्रा	3511461	3362995	3546969	3571864	3561202
1.2 आरबीआई के पास बैंकरों की जमाराशियाँ	1025449	1001281	1087967	1050455	1000260
1.2.1 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	956011	939847	1023815	986172	939428
1.3 आरबीआई के पास 'अन्य' जमाराशियाँ	94536	81051	102993	99244	101629
आरक्षित मुद्रा (1.1+1.2+1.3=2.1+2.2+2.3-2.4-2.5)	4631446	4445327	4737929	4721563	4663090
2 स्रोत					
2.1 आरबीआई के देशी ऋण	1147066	1167569	1194797	1217875	1194202
2.1.1 सरकार को निवल आरबीआई ऋण	1193213	979659	1242346	1239095	1000891
2.1.1.1 केन्द्र सरकार को निवल आरबीआई ऋण (2.1.1.1.1+2.1.1.1.2+2.1.1.1.3+2.1.1.1.4-2.1.1.1.5)	1186655	977122	1225923	1210394	979092
2.1.1.1.1 केन्द्र सरकार को ऋण और अग्रिम	-	-	-	-	-
2.1.1.1.2 खज़ाना बिलों में निवेश	-	-	-	-	-
2.1.1.1.3 दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	1363369	1357627	1270656	1272522	1253916
2.1.1.1.3.1 केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियां	1363369	1357627	1270656	1272522	1253916
2.1.1.1.4 रुपया सिक्के	459	276	330	196	278
2.1.1.1.5 केन्द्र सरकार की जमाराशियाँ	177172	380781	45064	62324	275101
2.1.1.2 राज्य सरकारों को निवल आरबीआई ऋण	6557	2537	16423	28701	21798
2.1.2 बैंकों पर आरबीआई के दावे	-60553	182830	-58011	-31491	182792
2.1.2.1 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को ऋण और अग्रिम	-60553	182830	-58011	-31491	182792
2.1.3 वाणिज्यिक क्षेत्र को आरबीआई के ऋण	14406	5080	10463	10271	10519
2.1.3.1 प्राथमिक व्यापारियों को ऋण और अग्रिम	9358	3167	8428	8209	8459
2.1.3.2 नाबार्ड को ऋण और अग्रिम	-	-	-	-	-
2.2 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	33432	32596	35419	35419	35683
2.3 आरबीआई की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	5240824	5038109	5408898	5384126	5324122
2.3.1 स्वर्ण	439319	402148	565949	577133	566843
2.3.2 विदेशी मुद्रा आस्तियां	4801522	4635979	4842966	4807011	4757296
2.4 पूंजी खाता	1589134	1727402	1812747	1808345	1803583
2.5 अन्य मदें (निवल)	200741	65545	88439	107514	87333

सं. 11: आरक्षित मुद्रा - घटक और स्रोत

(₹ करोड़)

मद	2023-24	मार्च 31/माह के रिपोर्टिंग अंतिम शुक्रवार/रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया					
		2023	2024				
		दिसं. 29	नवं. 29	दिसं. 6	दिसं. 13	दिसं. 20	दिसं. 27
	1	2	3	4	5	6	7
आरक्षित मुद्रा (1.1 + 1.2 + 1.3 = 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 - 2.6)	4631446	4445327	4737929	4758974	4721563	4711531	4663090
1 घटक							
1.1 संचलन में मुद्रा	3511461	3362995	3546969	3562515	3571864	3562017	3561202
1.2 भा.रि.बैं. के पास बैंकरों की जमाराशियाँ	1025449	1001281	1087967	1097391	1050455	1047111	1000260
1.3 भा.रि.बैं. के पास 'अन्य' जमाराशियाँ	94536	81051	102993	99069	99244	102403	101629
2 स्रोत							
2.1 सरकार को निवल रिज़र्व बैंक ऋण	1193213	979659	1242346	1317861	1239095	1026598	1000891
2.2 बैंकों को रिज़र्व बैंक ऋण	-60553	182830	-58011	-69168	-31491	167651	182792
2.3 वाणिज्यिक क्षेत्र को रिज़र्व बैंक ऋण	14406	5080	10463	10077	10271	10404	10519
2.4 भा.रि.बैं. की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	5240824	5038109	5408898	5393378	5384126	5326888	5324122
2.5 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	33432	32596	35419	35419	35419	35419	35683
2.6 भा.रि.बैं. की निवल गैर मौद्रिक देयताएं	1789875	1792947	1901186	1928593	1915858	1855429	1890916

सं. 12: वाणिज्यिक बैंक सर्वेक्षण

(₹ करोड़)

मद	माह के रिपोर्टिंग अंतिम शुक्रवार / माह के रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2023-24	2023	2024		
		दिसं. 29	नवं. 29	दिसं. 13	दिसं. 27
	1	2	3	4	5
1 घटक					
1.1 निवासियों की कुल जमाराशियाँ	20145188	19769396	21671501	21716094	21711317
	(20253430)	(19890683)	(21740662)	(21783910)	(21778008)
1.1.1 मांग जमाराशियाँ	2443853	2437504	2576789	2610222	2569573
1.1.2 निवासियों की सावधि जमाराशियाँ	17701334	17331892	19094713	19105873	19141745
	(17809577)	(17453179)	(19163873)	(19173688)	(19208435)
1.1.2.1 अल्पावधि सावधि जमाराशियाँ	7965600	7799351	8592621	8597643	8613785
1.1.2.1.1 जमा प्रमाण-पत्र (सीडी)	369399	342514	493598	484414	499061
1.1.2.2 दीर्घावधि सावधि जमाराशियाँ	9735734	9532541	10502092	10508230	10527960
1.2 वित्तीय संस्थाओं से मांग/सावधि निधीयन	777942	759065	951023	866935	955100
2 स्रोत					
2.1 देशी ऋण	23019606	22357890	24722187	24843409	25002766
	(23641847)	(23031773)	(25229419)	(25339776)	(25492177)
2.1.1 सरकार को ऋण	6014054	5888955	6487128	6505486	6544381
	(6105610)	(5989765)	(6538347)	(6556353)	(6595249)
2.1.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण	17005551	16468935	18235059	18337922	18458385
	(17536238)	(17042007)	(18691073)	(18783423)	(18896928)
2.1.2.1 बैंक ऋण	15901477	15388871	17052942	17141380	17304495
	(16432164)	(15961944)	(17508956)	(17586881)	(17743037)
2.1.2.1.1 गैर-खाद्यान्न ऋण	15878397	15345733	17001688	17089074	17248356
	(16409083)	(15918805)	(17457702)	(17534575)	(17686899)
2.1.2.2 प्राथमिक व्यापारियों को निवल ऋण	22904	14127	13498	15279	15378
2.1.2.3 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश	949	737	565	504	498
2.1.2.4 अन्य निवेश (गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों में)	1080222	1065199	1168055	1180758	1138015
2.2 वाणिज्यिक बैंकों की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां (2.2.1-2.2.2-2.2.3)	-130004	-60896	-119661	-11299	-24011
2.2.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	241661	258410	339002	444723	443646
2.2.2 अनिवासी विदेशी मुद्रा प्रत्यावर्तनीय मीयादी जमाराशियाँ	221796	197358	276804	284234	284584
2.2.3 ओवरसीज़ विदेशी मुद्रा उधार	149868	121947	181858	171789	183074
2.3 निवल बैंक रिज़र्व (2.3.1+2.3.2-2.3.3)	893350	852099	1172693	1101641	845902
2.3.1 भा.रि.बैं. के पास शेष	931483	939847	1023815	986172	939428
2.3.2 उपलब्ध नकदी	89433	95082	90867	83978	89267
2.3.3 भा.रि.बैं. से ऋण और अग्रिम	127566	182830	-58011	-31491	182792
2.4 पूंजी खाता	2299592	2268729	2564679	2565219	2568998
2.5 अन्य मदें (निवल) (2.1+2.2+2.3-2.4-1.1-1.2)	560230	351904	588016	785503	589242
2.5.1 अन्य मांग और मीयादी देयताएं (2.2.3 का निवल)	787560	815183	839816	971762	813552
2.5.2 निवल अंतर-बैंक देयताएं (प्राथमिक व्यापारियों से इतर)	197781	174722	135044	132994	132284

कोष्ठक में दिए गए आंकड़ों में एक गैर-बैंक के बैंक में विलय का प्रभाव शामिल है।

सं. 13: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के निवेश

(₹ करोड़)

मद	22 मार्च, 2024 की स्थिति	2023	2024		
		दिसं. 29	नवं. 29	दिसं. 13	दिसं. 27
	1	2	3	4	5
1 एसएलआर प्रतिभूतियां	6106558	5990503	6538915	6556857	6595747
	(6015003)	(5889692)	(6487697)	(6505991)	(6544879)
2 अन्य सरकारी प्रतिभूतियाँ (गैर-एसएलआर)	177136	180084	157432	157393	157392
3 वाणिज्यिक पत्र	61175	57466	60547	60586	60991
4 निम्नलिखित द्वारा जारी शेयर					
4.1 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम	8475	8751	13340	13369	13268
4.2 निजी कॉरपोरेट क्षेत्र	77722	81517	96761	96620	97535
4.3 अन्य	5624	5605	7503	7491	7490
5 निम्नलिखित द्वारा जारी बांड / डिबेंचर					
5.1 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम	103070	94289	121897	122634	127626
5.2 निजी कॉरपोरेट क्षेत्र	287596	289204	231855	231302	232626
5.3 अन्य	124690	111242	155237	155052	157698
6 निम्नलिखित द्वारा जारी लिखत					
6.1 म्यूचुअल फंड	62499	56810	134778	147641	92068
6.2 वित्तीय संस्थाएं	172340	181283	188704	188670	191321

टिप्पणी : कॉलम सं. (1), (2) व (3)में दिया गया डेटा अंतिम है और कॉलम सं.(4) व (5)में दिया गया डेटा अनंतिम है।

1. 14 जुलाई 2023 के बाद के डेटा में, एक गैर-बैंक के बैंक के साथ विलय के प्रभाव शामिल हैं।
2. कोष्ठक में दिए गए आंकड़ों में विलय के प्रभाव शामिल नहीं है।

सं. 14: भारत में कारोबार - सभी अनुसूचित बैंक और सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक

(₹ करोड़)

मद	अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार (मार्च के संबंध में) / अंतिम शुक्रवार की स्थिति							
	सभी अनुसूचित बैंक				सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक			
	2023-24	2023	2024		2023-24	2023	2024	
		दिसं.	नवं.	दिसं.		दिसं.	नवं.	दिसं.
	1	2	3	4	5	6	7	8
रिपोर्टिंग बैंकों की संख्या	210	210	208	208	137	137	135	135
1 बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं	**554117**	**528876**	**441174**	**461496**	**549351**	**524747**	**436037**	**456515**
1.1 बैंकों से माँग और मीयादी जमाराशियाँ	298452	269437	278500	296174	294471	266043	273722	291575
1.2 बैंकों से उधार राशि	182566	189114	137620	138393	182429	189078	137597	138334
1.3 अन्य माँग और मीयादी देयताएं	73100	70324	25053	26929	72452	69626	24718	26606
2 अन्य के प्रति देयताएं	**22664868**	**22240106**	**24464102**	**24491884**	**22190597**	**21784236**	**23990270**	**24014317**
2.1 कुल जमाराशियाँ	20932067	20525354	22473475	22522349	20475226	20088041	22017466	22062591
	(20823825)	(20404067)	(22404315)	(22455658)	(20366984)	(19966754)	(21948305)	(21995901)
2.1.1 माँग	2492916	2485497	2625490	2617452	2443853	2437504	2576789	2569573
2.1.2 मीयादी	18439151	18039857	19847985	19904896	18031373	17650537	19440677	19493019
2.2 उधार	782260	763584	955899	959775	777942	759065	951023	955100
2.3 अन्य माँग और मीयादी देयताएं	950541	951168	1034728	1009761	937428	937130	1021781	996626
3 रिज़र्व बैंक से उधार	**222716**	**271352**	**21293**	**244697**	**222716**	**271352**	**21293**	**244697**
3.1 मीयादी बिल / वचन पत्रों की जमानत पर	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 अन्य	222716	271352	21293	244697	222716	271352	21293	244697
4 उपलब्ध नकदी और रिज़र्व बैंक के पास शेषराशि	1043272	1056932	1137407	1051004	1020916	1034929	1114682	1028694
4.1 उपलब्ध नकदी	91886	97605	93455	91928	89433	95082	90867	89267
4.2 रिज़र्व बैंक के पास शेषराशि	951386	959326	1043952	959076	931483	939847	1023815	939428
5 बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां	**455057**	**430787**	**379361**	**410612**	**374474**	**364152**	**314490**	**339609**
5.1 अन्य बैंकों के पास शेषराशि	246384	247269	247862	271169	198327	202063	195672	216738
5.1.1 चालू खाते में	12010	13515	12102	16333	8971	10360	9524	13938
5.1.2 अन्य खातों में	234373	233755	235760	254836	189357	191703	186147	202800
5.2 माँग और अल्पसूचना पर मुद्रा	39614	34891	27828	30173	12355	17201	19091	18342
5.3 बैंकों को अग्रिम	51325	45516	39301	42099	48368	44105	38641	40682
5.4 अन्य आस्तियां	117734	103111	64369	67172	115424	100782	61086	63847
6 निवेश	**6256962**	**6139074**	**6691504**	**6747371**	**6106558**	**5990503**	**6538915**	**6595747**
	(6165407)	(6038263)	(6640285)	(6696503)	(6015003)	(5889692)	(6487697)	(6544879)
6.1 सरकारी प्रतिभूतियां	6249319	6132448	6683596	6739533	6105610	5989765	6538351	6595249
6.2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	7643	6625	7908	7839	949	737	565	498
7 बैंक ऋण	**16866336**	**16386269**	**17959742**	**18194821**	**16432164**	**15961944**	**17508956**	**17743037**
	(16335650)	(15813197)	(17503728)	(17756278)	(15901477)	(15388871)	(17052942)	(17304495)
7ए खाद्यान्न ऋण	75472	92344	101871	106755	23081	43139	51254	56139
7.1 ऋण, नकदी-ऋण और ओवरड्राफ्ट	16565348	16094103	17646243	17870643	16134303	15672642	17198615	17422048
7.2 देशी बिल - खरीदे गए	60471	52280	69789	73546	60467	52269	68351	72063
7.3 देशी बिल- भुनाए गए	199761	198816	206353	212904	197358	196536	205253	211819
7.4 विदेशी बिल - खरीदे गए	16662	17624	15424	15770	16412	17404	15186	15551
7.5 विदेशी बिल - भुनाए गए	24094	23446	21934	21957	23624	23093	21550	21557

टिप्पणी: कॉलम सं. (4) व (8) में दिया गया डेटा अनंतिम है।

1. जुलाई 2023 के बाद के डेटा में एक गैर-बैंक के बैंक के साथ विलय के प्रभाव शामिल हैं।
2. कोष्ठक में दिए गए आंकड़ों में विलय के प्रभाव शामिल नहीं है।

सं. 15: प्रमुख क्षेत्रों द्वारा सकल बैंक ऋण का विनियोजन

(₹ करोड़)

उद्योग	बकाया स्थिति				वृद्धि (%)	
	मार्च 22, 2024	2023	2024		वित्तीय वर्ष में अब तक	वर्ष-दर-वर्ष
		दिसं. 29	नवं. 29	दिसं. 27	2024-25	2024
	1	2	3	4	%	%
I. बैंक ऋण (II+III)	**16432164**	**15961944**	**17509171**	**17742873**	**8.0**	**11.2**
	(15901477)	(15388871)	(17053157)	(17304330)	(8.8)	(12.4)
II. खाद्यान्न ऋण	**23081**	**43139**	**51254**	**56139**	**143.2**	**30.1**
III. गैर-खाद्यान्न ऋण	**16409083**	**15918805**	**17457917**	**17686734**	**7.8**	**11.1**
	(15878397)	(15345733)	(17001903)	(17248192)	(8.6)	(12.4)
1. कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियां	**2071251**	**1991008**	**2223467**	**2239028**	**8.1**	**12.5**
2. उद्योग (सूक्ष्म और लघु, मध्यम और बड़े)	**3652804**	**3594212**	**3813094**	**3854429**	**5.5**	**7.2**
	(3635810)	(3576973)	(3798411)	(3842044)	(5.7)	(7.4)
2.1 सूक्ष्म और लघु	726315	702319	757300	771039	6.2	9.8
2.2 मध्यम	303998	290336	340525	348108	14.5	19.9
2.3 बड़े	2622490	2601557	2715269	2735282	4.3	5.1
3. सेवाएं	**4592227**	**4443778**	**4853884**	**4962520**	**8.1**	**11.7**
	(4490467)	(4324463)	(4775839)	(4888308)	(8.9)	(13.0)
3.1 परिवहन परिचालक	230175	223095	249795	252966	9.9	13.4
3.2 कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	25917	26706	31348	31582	21.9	18.3
3.3 पर्यटन, होटल और रेस्टरां	77513	76621	79088	80218	3.5	4.7
3.4 शिपिंग	7067	6976	7521	7102	0.5	1.8
3.5 विमानन	43248	44326	46446	45979	6.3	3.7
3.6 पेशेवर सेवाएं	167234	156386	184913	189578	13.4	21.2
3.7 व्यापार	1025752	974551	1081553	1111227	8.3	14.0
3.7.1 थोक व्यापार[1]	538744	506039	568471	584857	8.6	15.6
3.7.2 खुदरा व्यापार	487008	468512	513082	526370	8.1	12.3
3.8 वाणिज्यिक स्थावर संपदा	469013	458080	514894	520913	11.1	13.7
	(400470)	(373674)	(461690)	(470949)	(17.6)	(26.0)
3.9 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसी)[2] जिसमें से	1548027	1520234	1575306	1621767	4.8	6.7
3.9.1 आवास वित्त कंपनियां (एचएफसी)	325626	328787	322240	319910	-1.8	-2.7
3.9.2 सार्वजनिक वित्त संस्थाएं (पीएफआई)	226963	212038	196793	218657	-3.7	3.1
3.10 अन्य सेवाएं[3]	998281	956803	1083020	1101188	10.3	15.1
	(978198)	(935526)	(1066187)	(1084711)	(10.9)	(15.9)
4. व्यक्तिगत ऋण	**5331290**	**5173253**	**5734856**	**5794866**	**8.7**	**12.0**
	(4919468)	(4737443)	(5372892)	(5442956)	(10.6)	(14.9)
4.1 उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं	23713	24284	24698	24012	1.3	-1.1
4.2 आवास	2718715	2637781	2908672	2931739	7.8	11.1
	(2331935)	(2228347)	(2568430)	(2601206)	(11.5)	(16.7)
4.3 मीयादी जमाराशि की जमानत पर अग्रिम	125239	118330	131221	140998	12.6	19.2
4.4 शेयरों और बॉण्डों की जमानत पर व्यक्तियों को अग्रिम	8492	8025	8274	9791	15.3	22.0
4.5 क्रेडिट कार्ड बकाया	257016	251843	288997	291087	13.3	15.6
4.6 शिक्षा	119380	114955	131629	133140	11.5	15.8
4.7 वाहन ऋण	573398	563475	605587	613302	7.0	8.8
4.8 स्वर्ण आभूषण पर ऋण[4]	102562	100723	164556	172581	68.3	71.3
4.9 अन्य व्यक्तिगत ऋण	1402775	1353837	1471222	1478217	5.4	9.2
	(1377966)	(1327844)	(1449564)	(1456900)	(5.7)	(9.7)
5. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र (मेमो)						
(i) कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियां[5]	2081856	2005383	2210312	2236648	7.4	11.5
(ii) सूक्ष्म और लघु उद्यम[6]	1974191	1914264	2092196	2145252	8.7	12.1
(iii) मध्यम उद्यम[7]	490703	469534	556186	575433	17.3	22.6
(iv) आवास	755222	747897	752576	751317	-0.5	0.5
	(660572)	(649904)	(667694)	(667336)	(1.0)	(2.7)
(v) शिक्षा ऋण	62235	61823	62645	62993	1.2	1.9
(vi) नवीकरणीय ऊर्जा	5991	5389	7458	8034	34.1	49.1
(vii) सामाजिक अवसंरचना	2613	2567	1095	999	-61.8	-61.1
(viii) निर्यात ऋण	12855	12411	12668	12352	-3.9	-0.5
(ix) अन्य	61336	53282	54682	55134	-10.1	3.5
(x) नेट पीएसएलसी- एसएफ /एमएफ सहित कमजोर वर्ग	1647778	1571355	1734996	1748608	6.1	11.3

टिप्पणियाँ:

(1) डेटा अनंतिम है। बैंक ऋण, खाद्य ऋण और गैर-खाद्य ऋण डेटा धारा-42 रिटर्न पर आधारित हैं, जिसमें सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एससीबी) शामिल हैं, जबकि क्षेत्रीय गैर-खाद्य ऋण डेटा क्षेत्र वार और उद्योग वार बैंक क्रेडिट (एसआईबीसी) रिटर्न पर आधारित हैं जिसमें चुनिंदा बैंकों के लेखांकन के आधार पर महीने के आखिरी रिपोर्टिंग शुक्रवार से संबंधित सभी एससीबी द्वारा दिए गए कुल गैर-खाद्य ऋण के लगभग 95 प्रतिशत को शामिल किया गया है।

(2) 28 जुलाई 2023 के बाद के डेटा में एक गैर-बैंक के बैंक के साथ विलय का प्रभाव शामिल है। कोष्ठक में दिए गए आंकड़ों में विलय के प्रभाव शामिल नहीं है।

1. थोक व्यापार में खाद्य ऋण संघ के बाहर के खाद्य खरीद ऋण शामिल है।
2. एनबीएफसी के अंतर्गत एचएफसी, पीएफआई, माइक्रोफाइनेंस संस्थाएं (एमएफआई), स्वर्ण ऋण से जुड़ी एनबीएफसी और अन्य शामिल हैं।
3. "अन्य सेवाओं" के अंतर्गत म्यूचुअल फंड, एनबीएफसी और एमएफ के अलावा बैंकिंग व वित्त तथा अन्य सेवाएं जो सेवाओं के अंतर्गत अन्यत्र नहीं दर्शाए गए हैं।
4. मई 2024 से, एक बैंक ने कृषि ऋण की एक श्रेणी के वर्गीकरण को खुदरा खंड के अंतर्गत "स्वर्ण आभूषणों पर ऋण" में बदल दिया है।
5. प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत "कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों" में प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋण प्रमाणपत्र (पीएसएलसी) भी शामिल हैं।
6. प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत ''सूक्ष्म और लघु उद्यम'' में उद्योग और सेवा क्षेत्रों में सूक्ष्म और लघु उद्यमों को ऋण शामिल है और इसमें पीएसएलसी भी शामिल हैं।
7. प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत ''मध्यम उद्यम'' में उद्योग और सेवा क्षेत्रों में मध्यम उद्यमों को ऋण शामिल है।

सं. 16: सकल बैंक ऋण का उद्योग-वार विनियोजन

(₹ करोड़)

उद्योग	बकाया स्थिति				वृद्धि (%)	
	मार्च 22, 2024	2023	2024		वित्तीय वर्ष में अब तक	वर्ष-दर-वर्ष
		दिसं. 29	नवं. 29	दिसं. 27	2024-25	2024
	1	2	3	4	%	%
2 उद्योग (2.1 से 2.19)	3652804	3594212	3813094	3854429	5.5	7.2
	(3635810)	(3576973)	(3798411)	(3842044)	(5.7)	(7.4)
2.1 खनन और उत्खनन (कोयला सहित)	54166	54890	53357	53892	-0.5	-1.8
2.2 खाद्य प्रसंस्करण	208864	191449	197552	211986	1.5	10.7
2.2.1 चीनी	26383	16773	16925	19889	-24.6	18.6
2.2.2 खाद्य तेल और वनस्पति	19700	21411	20296	21798	10.7	1.8
2.2.3 चाय	5692	5952	6509	6470	13.7	8.7
2.2.4 अन्य	157089	147313	153822	163829	4.3	11.2
2.3 पेय पदार्थ और तंबाकू	31136	28296	30182	30669	-1.5	8.4
2.4 वस्त्र	256048	250038	259458	264055	3.1	5.6
2.4.1 सूती वस्त्र	99199	95797	95498	98163	-1.0	2.5
2.4.2 जूट से बने वस्त्र	4280	4187	4295	4340	1.4	3.6
2.4.3 मानव - निर्मित वस्त्र	45111	45396	47526	48251	7.0	6.3
2.4.4 अन्य वस्त्र	107458	104657	112138	113303	5.4	8.3
2.5 चमड़ा और चमड़े से बने उत्पाद	12588	12131	12519	12804	1.7	5.5
2.6 लकड़ी और लकड़ी से बने उत्पाद	23839	23384	25805	26601	11.6	13.8
2.7 काग़ज़ और काग़ज़ से बने उत्पाद	46426	45500	51174	51508	10.9	13.2
2.8 पेट्रोलियम, कोयला उत्पाद और आण्विक ईंधन	132356	131320	144756	139840	5.7	6.5
2.9 रसायन और रासायनिक उत्पाद	249347	246363	263302	263647	5.7	7.0
2.9.1 उवर्रक	37569	36026	31143	31829	-15.3	-11.6
2.9.2 औषधि और दवाइयां	81036	80276	87569	88026	8.6	9.7
2.9.3 पेट्रो केमिकल्स	23157	22774	30373	26038	12.4	14.3
2.9.4 अन्य	107584	107287	114217	117754	9.5	9.8
2.10 रबड़, प्लास्टिक और उनके उत्पाद	90420	87677	97032	98914	9.4	12.8
2.11 कांच और कांच के सामान	12090	11347	12517	12507	3.5	10.2
2.12 सीमेन्ट और सीमेन्ट से बने उत्पाद	59757	60244	61614	61541	3.0	2.2
2.13 मूल धातु और धातु उत्पाद	384447	382538	428244	432757	12.6	13.1
2.13.1 लोहा और स्टील	273803	270611	304598	306185	11.8	13.1
2.13.2 अन्य धातु और धातु से बने उत्पाद	110645	111927	123647	126572	14.4	13.1
2.14 सभी अभियांत्रिकी	196643	190076	223986	227079	15.5	19.5
2.14.1 इलेक्ट्रानिक्स	43175	42761	52123	50108	16.1	17.2
2.14.2 अन्य	153468	147315	171863	176972	15.3	20.1
2.15 वाहन, वाहन के पुर्जे और परिवहन उपस्कर	113185	110441	113753	115180	1.8	4.3
2.16 रत्न और आभूषण	84860	88740	87031	87797	3.5	-1.1
2.17 निर्माण	133520	131979	142057	143789	7.7	8.9
2.18 इन्फ्रास्ट्रक्चर	1304096	1301712	1312607	1314369	0.8	1.0
2.18.1 बिजली	644042	645147	651955	656191	1.9	1.7
2.18.2 दूरसंचार	138192	140178	122704	124624	-9.8	-11.1
2.18.3 सड़क	318072	316917	333166	325833	2.4	2.8
2.18.4 हवाई अड्डा	7280	7184	8407	8733	20.0	21.6
2.18.5 बंदरगाह	6681	6891	6116	6282	-6.0	-8.8
2.18.6 रेलवे	13062	11439	11376	13325	2.0	16.5
2.18.7 अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर	176767	173956	178884	179380	1.5	3.1
2.19 अन्य उद्योग	259016	246088	296148	305493	17.9	24.1

टिप्पणी : 28 जुलाई 2023 के बाद के डेटा में एक गैर-बैंक के बैंक के साथ विलय का प्रभाव शामिल है। कोष्ठक में दिए गए आंकड़ों में विलय के प्रभाव शामिल नहीं है।

सं. 17: भारतीय रिज़र्व बैंक में राज्य सहकारी बैंकों के खाते

(₹ करोड़)

मद	रिपोर्टिंग अंतिम शुक्रवार (मार्च के संबंध में)/अंतिम शुक्रवार/रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति								
	2023-24	2023	2024						
		नवं. 24	सितं. 27	अक्तू. 04	अक्तू. 18	अक्तू. 25	नवं. 01	नवं. 15	नवं. 29
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
रिपोर्टिंग बैंकों की संख्या	33	33	34	34	34	34	34	34	34
1 कुल जमाराशियाँ (2.1.1.2+2.2.1.2)	**138788.9**	**134731.3**	**133236.7**	**131961.9**	**131965.1**	**132037.8**	**132552.8**	**138073.1**	**138154.1**
2 मांग और मीयादी देयताएं									
2.1 मांग देयताएं	**30226.7**	**25612.9**	**27646.4**	**26781.0**	**25419.0**	**25724.0**	**25854.5**	**26021.8**	**26562.1**
2.1.1 जमाराशियाँ									
2.1.1.1 अंतर-बैंक	9101.3	6378.6	7743.1	7544.4	7243.0	7210.1	7147.7	7239.1	6670.1
2.1.1.2 अन्य	15000.4	13811.7	13473.1	13625.5	13121.6	13179.2	13327.5	13293.6	13187.7
2.1.2 बैंकों से उधार	130.0	299.8	179.9		190.0	639.7	574.6	449.8	1454.3
2.1.3 अन्य मांग देयताएं	5995.0	5122.8	6250.3	5611.1	4864.4	4695.0	4804.7	5039.2	5249.9
2.2 मीयादी देयताएं	**198141.8**	**172169.3**	**181476.5**	**176057.8**	**177986.9**	**177577.6**	**177539.8**	**178177.3**	**176625.0**
2.2.1 जमाराशियाँ									
2.2.1.1 अंतर-बैंक	72308.4	49028.6	59406.1	55990.1	56392.3	56169.6	55653.7	51788.5	50047.3
2.2.1.2 अन्य	123788.5	120919.6	119763.6	118336.4	118843.5	118858.6	119225.3	124779.5	124966.4
2.2.2 बैंकों से उधार	673.6	819.7	1143.3	683.0	1712.2	1460.2	1591.7	651.9	651.9
2.2.3 अन्य मीयादी देयताएं	1371.3	1401.4	1163.5	1048.5	1038.9	1089.2	1069.1	957.3	959.5
3 रिज़र्व बैंक से उधार	0.0						0.0	0.0	0.0
4 अधिसूचित बैंक/ सरकार से उधार	95914.5	80417.0	87696.9	87889.0	89225.0	88927.0	89398.0	173712.9	112111.7
4.1 मांग	27317.7	21638.3	23412.8	25815.3	25217.3	24980.3	25033.3	102827.6	45109.3
4.2 मीयादी	68596.8	58778.7	64284.1	62074.0	64007.2	64224.1	64364.7	70885.3	67002.4
5 उपलब्ध नकदी और रिज़र्व बैंक के पास शेषराशि	**16263.7**	**10725.0**	**12368.8**	**12171.0**	**12371.3**	**11411.6**	**13169.8**	**12004.2**	**11145.5**
5.1 उपलब्ध नकदी	960.0	684.5	780.9	781.6	838.2	818.0	828.9	772.6	821.1
5.2 रिज़र्व बैंक के पास शेषराशि	15303.7	10040.5	11587.9	11389.5	11533.2	10593.6	12340.9	11231.6	10324.4
6 चालू खाते में अन्य बैंकों के पास शेषराशि	**2088.1**	**1598.5**	**1658.2**	**1178.6**	**1229.3**	**1135.9**	**1084.0**	**1035.0**	**1118.1**
7 सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	**77700.5**	**73325.1**	**73488.7**	**74364.4**	**73111.6**	**73805.6**	**74545.3**	**75275.2**	**75074.9**
8 मांग और अल्प सूचना पर मुद्रा	**34355.3**	**21174.1**	**15615.3**	**17561.1**	**17854.6**	**16692.6**	**16150.3**	**15588.7**	**12457.8**
9 बैंक ऋण (10.1+11)	**135141.9**	**127421.9**	**138973.3**	**135277.0**	**135003.0**	**136490.2**	**136802.8**	**167629.4**	**166666.0**
10 अग्रिम									
10.1 ऋण, नकदी-ऋण और ओवरड्राफ्ट	**134936.8**	**127336.5**	**138795.8**	**135082.7**	**134807.4**	**136282.1**	**136593.9**	**167432.0**	**166480.4**
10.2 बैकों से प्राप्य राशि	142185.2	125133.8	143516.4	139711.1	141859.4	142706.5	143073.6	113950.8	111546.4
11 खरीदे और भुनाए गए बिल	205.1	85.4	177.5	194.2	195.6	208.1	208.9	197.4	185.6

कीमत और उत्पादन

सं. 18: उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार: 2012=100)

समूह/उप समूह	2023-24			ग्रामीण			शहरी			मिश्रित		
	ग्रामीण	शहरी	मिश्रित	जन. 24	दिसं.24	जन.25 (अ)	जन.24	दिसं.24	जन.25 (अ)	जन.24	दिसं.24	जन.25 (अ)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 खाद्य और पेय पदार्थ	**185.9**	**192.7**	**188.4**	**187.7**	**203.9**	**198.8**	**194.2**	**209.4**	**204.6**	**190.1**	**205.9**	**200.9**
1.1 अनाज और उत्पाद	181.4	181.7	181.5	187.5	198.9	199.8	187.1	196.5	197.5	187.4	198.1	199.1
1.2 मांस और मछली	213.0	221.3	215.9	209.9	219.1	220.9	219.4	228.7	230.8	213.2	222.5	224.4
1.3 अंडा	185.4	189.5	187.0	204.8	209.8	206.1	206.1	215.8	210.8	205.3	212.1	207.9
1.4 दूध और उत्पाद	181.4	181.5	181.4	182.6	187.3	187.7	182.8	187.9	188.2	182.7	187.5	187.9
1.5 तेल और चर्बी	165.3	158.7	162.9	161.2	189.0	189.0	155.8	174.6	175.6	159.2	183.7	184.1
1.6 फल	172.1	179.9	175.7	169.7	189.0	192.1	174.5	192.4	193.8	171.9	190.6	192.9
1.7 सब्जी	183.9	229.9	199.5	179.9	242.4	203.6	226.2	289.2	245.6	195.6	258.3	217.8
1.8 दाल और उत्पाद	192.2	196.5	193.7	202.5	212.4	207.8	207.7	217.4	213.0	204.3	214.1	209.6
1.9 चीनी और उत्पाद	126.2	128.1	126.9	129.7	130.0	129.6	131.0	132.7	132.4	130.1	130.9	130.5
1.10 मसाले	238.0	228.4	234.8	245.9	229.0	227.3	235.5	224.1	222.9	242.4	227.4	225.8
1.11 गैर नशीले पेय पदार्थ	180.7	168.2	175.5	182.3	186.7	187.7	169.8	175.5	176.6	177.1	182.0	183.1
1.12 तैयार भोजन, नाश्ता, मिठाई	193.3	200.9	196.8	195.0	201.2	201.7	203.1	211.7	212.9	198.8	206.1	206.9
2 पान, तंबाकू और मादक पदार्थ	**202.0**	**207.1**	**203.3**	**203.2**	**208.7**	**208.2**	**208.9**	**212.2**	**212.6**	**204.7**	**209.6**	**209.4**
3 कपड़ा और जूते	**192.9**	**181.5**	**188.4**	**194.6**	**199.4**	**199.7**	**183.1**	**187.8**	**188.1**	**190.0**	**194.8**	**195.1**
3.1 कपड़ा	193.5	183.5	189.6	195.3	200.4	200.6	185.1	190.0	190.3	191.3	196.3	196.5
3.2 जूते	189.4	170.2	181.4	190.4	193.7	193.9	171.8	175.6	176.0	182.7	186.2	186.5
4 आवास	--	**176.7**	**176.7**	--	--	--	**177.6**	**181.7**	**182.5**	**177.6**	**181.7**	**182.5**
5 ईंधन और बिजली	**183.0**	**178.9**	**181.4**	**184.1**	**182.3**	**183.1**	**175.7**	**170.5**	**170.6**	**180.9**	**177.8**	**178.4**
6 विविध	**181.7**	**173.7**	**177.8**	**183.4**	**190.8**	**191.5**	**175.2**	**182.0**	**182.6**	**179.4**	**186.5**	**187.2**
6.1 घरेलू सामान और सेवा	181.5	171.8	176.9	182.9	187.0	187.3	173.0	178.3	178.8	178.2	182.9	183.3
6.2 स्वास्थ्य	190.8	185.2	188.7	193.2	200.2	200.8	187.8	194.5	195.4	191.2	198.0	198.8
6.3 परिवहन और संचार	171.1	161.4	166.0	172.0	176.7	177.2	162.1	165.8	166.1	166.8	171.0	171.4
6.4 मनोरंजन	175.8	171.1	173.2	177.2	181.5	181.6	172.2	176.7	177.0	174.4	178.8	179.0
6.5 शिक्षा	184.0	179.1	181.1	185.8	192.2	192.5	180.8	187.9	188.0	182.9	189.7	189.9
6.6 व्यक्तिगत देखभाल और संबंधित सामन	186.3	187.4	186.8	188.6	206.3	208.4	189.9	208.0	210.2	189.1	207.0	209.1
सामान्य सूचकांक (सभी समूह)	**185.6**	**182.4**	**184.1**	**187.3**	**198.4**	**196.0**	**183.5**	**192.0**	**190.6**	**185.5**	**195.4**	**193.5**

स्रोत : केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार।

अ: अनंतिम

सं. 19: अन्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

मद	आधार वर्ष	योजक कारक	2023-24	2023	2024	
				दिसं.	नवं.	दिसं.
	1	2	3	4	5	6
1 औद्योगिक कामगार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	2016	2.88	137.9	138.8	144.5	
2 कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	1986-87	5.89	1229	1257	1320	1320
3 ग्रामीण श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	1986-87	-	1240	1267	1331	1331

स्रोत: श्रम ब्यूरो, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार।

सं. 20: मुंबई में स्वर्ण और चांदी का मासिक औसत मूल्य

मद	2023-24	2023	2024	
		दिसं.	नवं.	दिसं.
	1	2	3	4
1 मानक स्वर्ण (₹ प्रति 10 ग्राम)	60624	62173	76221	76195
2 चांदी (₹ प्रति किलोग्राम)	72243	73926	90230	89265

स्रोत: मुंबई में स्वर्ण और चांदी के मूल्य के लिए इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन लि. मुंबई।

सं. 21: थोक मूल्य सूचकांक

(आधारः 2011-12=100)

पण्य वस्तुएँ	भार	2023-24	2024			2025
			जन.	नवं.	दिसं.(अ)	जन.(अ)
	1	2	3	4	5	6
1 सभी पण्य	**100.000**	**151.4**	**151.2**	**156.4**	**155.4**	**154.7**
1.1 प्राथमिक वस्तुएं	**22.618**	**183.0**	**181.4**	**197.9**	**193.8**	**189.9**
1.1.1 खाद्य वस्तुएं	**15.256**	**191.3**	**188.8**	**213.7**	**207.4**	**199.9**
1.1.1.1 खाद्यान्न (अनाज+दाल)	3.462	193.8	199.4	214.7	213.8	213.2
1.1.1.2 फल और सब्जियाँ	3.475	210.2	189.6	271.9	244.7	210.8
1.1.1.3 दूध	4.440	180.3	182.3	185.2	185.8	187.2
1.1.1.4 अंडा, मांस और मछली	2.402	172.1	168.7	173.1	174.7	174.7
1.1.1.5 मसाले	0.529	235.4	246.2	244.3	240.2	232.6
1.1.1.6 अन्य खाद्य वस्तुएं	0.948	189.5	196.5	216.8	213.7	217.1
1.1.2 खाद्येतर वस्तुएं	**4.119**	**162.4**	**162.6**	**162.8**	**166.3**	**167.4**
1.1.2.1 फाइबर	0.839	168.0	162.9	159.4	159.5	161.7
1.1.2.2 तिलहन	1.115	185.0	183.1	185.6	182.8	183.0
1.1.2.3 अन्य खाद्येतर वस्तुएं	1.960	134.9	133.6	140.1	140.8	142.7
1.1.2.4 पुष्पोत्पादन	0.204	279.7	328.6	270.0	349.3	343.7
1.1.3 खनिज	**0.833**	**217.7**	**223.7**	**229.4**	**229.6**	**230.1**
1.1.3.1 धात्विक खनिज	0.648	204.2	207.3	219.8	219.9	219.1
1.1.3.2 अन्य खनिज	0.185	265.0	281.0	263.2	263.5	268.8
1.1.4 कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस	**2.410**	**153.6**	**151.7**	**146.7**	**141.9**	**150.9**
1.2 ईंधन और बिजली	**13.152**	**152.0**	**154.9**	**149.9**	**149.9**	**150.6**
1.2.1 कोयला	**2.138**	**136.4**	**136.2**	**135.5**	**135.6**	**135.6**
1.2.1.1 कुकिंग कोयला	0.647	143.4	143.4	143.4	143.4	143.4
1.2.1.2 नॉन-कुकिंग कोयला	1.401	124.8	125.8	125.8	125.8	125.8
1.2.1.3 लिग्नाइट	0.090	267.6	246.6	230.9	231.2	231.2
1.2.2 खनिज तेल	**7.950**	**159.0**	**159.1**	**154.0**	**153.9**	**155.0**
1.2.3 बिजली	**3.064**	**145.0**	**157.2**	**149.4**	**149.4**	**149.7**
1.3 विनिर्मित उत्पाद	**64.231**	**140.2**	**139.7**	**143.1**	**143.0**	**143.2**
1.3.1 खाद्य उत्पादों का विनिर्माण	**9.122**	**160.5**	**160.3**	**177.5**	**176.7**	**177.0**
1.3.1.1 मांस का परिरक्षण और प्रसंस्करण	0.134	145.3	145.6	154.1	155.4	156.8
1.3.1.2 मछली, क्रस्टेशियन, मोलस्क और उनके उत्पादों का प्रसंस्करण एवं परिरक्षण	0.204	142.9	140.8	148.9	143.9	145.1
1.3.1.3 फल और सब्जियों का परिरक्षण और प्रसंस्करण	0.138	130.4	128.6	132.7	133.3	132.8
1.3.1.4 सब्जियां और पशु तेल एवं चर्बी	2.643	145.0	140.2	183.2	183.7	186.6
1.3.1.5 डेयरी उत्पाद	1.165	179.1	179.2	182.0	182.0	182.0
1.3.1.6 अनाज मिल के उत्पाद	2.010	175.6	181.2	190.4	190.2	189.6
1.3.1.7 स्टार्च और स्टार्च के उत्पाद	0.110	157.1	164.2	169.0	165.8	164.5
1.3.1.8 बेकरी उत्पाद	0.215	165.4	166.5	173.1	173.5	174.7
1.3.1.9 चीनी, गुड़ और शहद	1.163	134.6	137.9	138.1	136.1	138.3
1.3.1.10 कोकोआ, चॉकलेट और चीनी कन्फेक्शनरी	0.175	139.8	142.4	160.6	166.6	168.3
1.3.1.11 मैक्रोनी, नूडल्स, और कूसकूस और उसके जैसे मैदे से बने उत्पाद	0.026	149.9	150.0	158.1	166.4	161.0
1.3.1.12 चाय और कॉफी उत्पाद	0.371	176.2	161.8	190.2	180.1	161.8
1.3.1.13 प्रसंस्कृत मसाले और नमक	0.163	192.1	199.2	194.5	192.7	193.8
1.3.1.14 प्रसंस्कृत तैयार खाद्य पदार्थ	0.024	146.3	147.6	152.8	153.4	155.5
1.3.1.15 स्वास्थ्य पूरक	0.225	179.1	175.3	192.0	189.0	189.6
1.3.1.16 पशु के लिए तैयार खाद्य	0.356	208.3	207.1	205.6	202.3	200.4
1.3.2 पेय पदार्थों का विनिर्माण	**0.909**	**131.5**	**132.4**	**134.7**	**134.6**	**134.4**
1.3.2.1 शराब और स्पिरीट	0.408	133.3	134.3	137.1	137.0	136.9
1.3.2.2 माल्ट लिकर और माल्ट	0.225	135.6	136.8	139.1	139.1	138.9
1.3.2.3 शीतल पेय, मिनरल वॉटर और बोतलबन्द पानी का उत्पादन	0.275	125.5	125.8	127.7	127.3	127.1
1.3.3 तंबाकू उत्पादों का विनिर्माण	**0.514**	**173.5**	**174.2**	**177.0**	**177.0**	**177.4**
1.3.3.1 तंबाकू के उत्पाद	0.514	173.5	174.2	177.0	177.0	177.4

सं. 21: थोक मूल्य सूचकांक (जारी)

(आधारः 2011-12=100)

पण्य वस्तुएँ	भार	2023-24	2024			2025
			जन.	नवं.	दिसं.(अ)	जन.(अ)
	1	2	3	4	5	6
1.3.4 वस्त्र विनिर्माण	**4.881**	**134.6**	**134.0**	**136.1**	**136.9**	**136.9**
1.3.4.1 धागों की कताई और वस्त्र तैयार करना	2.582	120.1	118.7	120.8	120.7	120.6
1.3.4.2 बुनाई और तैयार वस्त्र	1.509	157.5	157.9	158.7	161.4	160.9
1.3.4.3 बुने हुए और क्रोशिए से बना कपड़ा	0.193	120.0	118.0	122.7	123.5	124.1
1.3.4.4 कपड़ों को छोड़कर निर्मित वस्त्र सामग्री	0.299	156.6	157.8	159.7	161.5	161.7
1.3.4.5 डोरियाँ, रस्सी, सुतली और नेटिंग	0.098	139.2	137.5	143.2	144.4	146.1
1.3.4.6 अन्य वस्त्र	0.201	129.6	130.8	136.8	134.0	136.7
1.3.5 तैयार वस्त्र का विनिर्माण	**0.814**	**150.8**	**150.9**	**153.7**	**154.4**	**154.1**
1.3.5.1 फर से बने वस्त्रों को छोड़कर, तैयार वस्त्र (बुने हुए) का विनिर्माण	0.593	148.7	148.5	151.0	151.6	151.4
१.३.५.२ बुने हुए और क्रोशिए से बने वस्त्र	0.221	156.6	157.5	161.2	161.8	161.3
1.3.6 चमड़ा और संबंधित उत्पाद का विनिर्माण	**0.535**	**124.1**	**123.5**	**125.8**	**125.6**	**126.3**
१.३.६.१ चमड़े की टैनिंग और ड्रेसिंग; ड्रेसिंग और फर की रंगाई	0.142	107.3	103.9	108.1	108.2	108.9
1.3.6.2 सामान, हैंडबैग, काठी और हार्नेस	0.075	140.9	141.1	142.6	142.4	142.4
1.3.6.3 जूते-चप्पल	0.318	127.7	128.1	129.8	129.4	130.3
१.३.७ लकड़ी व लकड़ी और कॉर्क के उत्पादों का विनिर्माण	**0.772**	**146.6**	**148.1**	**148.5**	**149.0**	**149.3**
1.3.7.1 आरा मिलिंग और लकड़ी के उत्पाद	0.124	137.8	136.1	142.9	142.3	141.6
1.3.7.2 विनियर शीट, प्लायवुड, लैमिन बोर्ड, पार्टिकल बोर्ड और अन्य पैनल और बोर्ड का विनिर्माण	0.493	146.1	148.6	147.2	148.1	148.7
1.3.7.3 बिल्डरों की बढ़ईगीरी	0.036	206.4	210.1	214.2	214.6	214.5
1.3.7.4 लकड़ी के डिब्बे	0.119	139.8	139.8	139.8	140.0	140.4
1.3.8 कागज़ और कागज़ के उत्पादों का विनिर्माण	**1.113**	**140.3**	**138.7**	**138.5**	**138.9**	**139.4**
1.3.8.1 लुगदी, कागज़ और पेपर बोर्ड	0.493	147.6	145.6	143.4	143.1	143.9
1.3.8.2 लहरदार कागज़ और पेपर बोर्ड और कागज़ के पात्र और पेपर बोर्ड	0.314	140.9	141.6	148.5	148.9	149.6
1.3.8.3 कागज़ की अन्य सामग्री और पेपर बोर्ड	0.306	128.0	124.7	120.2	122.0	121.5
1.3.9 मुद्रण और रिकार्डेड मीडिया का पुनरुत्पादन	**0.676**	**182.3**	**184.5**	**186.7**	**188.2**	**189.8**
1.3.9.1 मुद्रण	0.676	182.3	184.5	186.7	188.2	189.8
1.3.10 रसायन और रासायनिक उत्पादों का विनिर्माण	**6.465**	**136.9**	**135.4**	**136.4**	**136.4**	**136.7**
1.3.10.1 मूल रसायन	1.433	139.9	137.1	138.6	139.3	139.3
1.3.10.2 उर्वरक और नाइट्रोजन यौगिक	1.485	142.8	141.4	143.5	143.0	143.4
1.3.10.3 प्लास्टिक और प्राथमिक रूप में सिंथेटिक रबड़	1.001	132.3	131.2	133.2	132.8	133.5
1.3.10.4 कीटनाशक और अन्य एग्रोकेमिकल उत्पाद	0.454	132.8	131.2	129.3	128.8	129.2
1.3.10.5 पेन्ट, वार्निश और समान कोटिंग, मुद्रण स्याही और मैस्टिक्स	0.491	143.7	143.2	138.5	139.0	139.2
1.3.10.6 साबुन और डिटर्जेंट, सफाई और चमकाने की सामग्री, इत्र और शौचालय सफाई की सामग्री	0.612	139.7	138.9	139.9	140.4	140.4
1.3.10.7 अन्य रासायनिक उत्पाद	0.692	134.4	133.5	135.3	134.9	135.0
1.3.10.8 मानव निर्मित फाइबर	0.296	103.6	102.3	103.0	103.9	104.3
1.3.11 फार्मास्यूटिकल्स, औषधीय रसायन और वनस्पति उत्पाद का विनिर्माण	**1.993**	**142.9**	**143.0**	**144.1**	**144.1**	**145.0**
1.3.11.1 फार्मास्यूटिकल्स, औषधीय रसायन और वनस्पति उत्पाद	1.993	142.9	143.0	144.1	144.1	145.0
1.3.12 रबड़ और प्लास्टिक उत्पादों का विनिर्माण	**2.299**	**127.5**	**127.2**	**128.6**	**129.1**	**129.3**
1.3.12.1 रबड़ टायर और ट्यूब, रबड़ टायर की रिट्रीडिंग और पुनर्निर्माण	0.609	113.7	113.7	116.7	117.1	116.9
1.3.12.2 रबड़ के अन्य उत्पाद	0.272	107.3	107.7	111.7	111.9	112.4
1.3.12.3 प्लास्टिक उत्पाद	1.418	137.3	136.8	137.0	137.5	137.9
1.3.13 अन्य अधात्विक खनिज उत्पादों का विनिर्माण	**3.202**	**134.7**	**134.4**	**131.4**	**131.3**	**131.8**
1.3.13.1 कांच और कांच उत्पाद	0.295	163.8	164.2	162.1	163.4	163.5
1.3.13.2 आग रोधक उत्पाद	0.223	119.7	119.1	123.5	125.3	125.3
1.3.13.3 मिट्टी से बनी भवन निर्माण सामग्री	0.121	123.9	116.2	127.5	123.3	131.9
1.3.13.4 चीनी मिट्टी और चीनी मिट्टी के उत्पाद	0.222	122.3	123.3	124.6	124.6	124.9
1.3.13.5 सीमेन्ट, चूना और प्लास्टर	1.645	137.3	137.2	130.1	129.5	130.0

सं. 21: थोक मूल्य सूचकांक (जारी)

(आधारः 2011-12=100)

पण्य वस्तुएँ	भार	2023-24	2024			2025
			जन.	नवं.	दिसं.(अ)	जन.(अ)
	1	2	3	4	5	6
1.3.13.6 कंक्रीट, सीमेन्ट और प्लास्टर से बनी वस्तुएं	0.292	137.7	137.7	139.6	139.7	139.6
1.3.13.7 पत्थरों को काटना, आकार देना और संवारना	0.234	130.3	131.7	135.2	135.9	135.5
1.3.13.8 अन्य अधात्विक खनिज उत्पाद	0.169	102.4	101.4	93.7	94.2	94.1
1.3.14 मूल धातुओं का विनिर्माण	**9.646**	**141.0**	**138.8**	**138.6**	**137.6**	**137.1**
1.3.14.1 स्टील तैयार करने में प्रयुक्त सामग्री	1.411	140.3	135.5	132.1	130.2	129.3
1.3.14.2 मेटेलिक आयरन	0.653	153.6	150.8	138.7	133.4	131.8
1.3.14.3 नरम इस्पात - अर्ध निर्मित इस्पात	1.274	119.9	117.2	117.5	116.9	116.7
1.3.14.4 नरम इस्पात - लंबे उत्पाद	1.081	141.3	138.3	140.2	139.5	138.7
1.3.14.5 नरम इस्पात - चपटे उत्पाद	1.144	143.4	140.6	131.9	129.6	129.9
1.3.14.6 स्टेनलेस स्टील के अतिरिक्त एलॉय स्टील-आकार	0.067	137.6	133.1	133.7	132.3	132.8
1.3.14.7 स्टेनलेस स्टील - अर्ध निर्मित	0.924	136.4	131.8	126.8	129.0	127.7
1.3.14.8 पाइप और ट्यूब	0.205	169.7	166.8	163.5	162.7	164.1
1.3.14.9 कीमती धातु सहित अलौह धातु	1.693	144.8	145.0	157.7	156.6	157.3
1.3.14.10 कास्टिंग	0.925	141.0	142.7	145.4	146.2	144.8
1.3.14.11 स्टील से गढ़ी वस्तुएं	0.271	173.3	174.6	172.8	172.1	172.4
1.3.15 मशीनरी और उपकरणों को छोड़कर गढ़े हुए धातु उत्पादों का विनिर्माण	**3.155**	**138.6**	**137.8**	**135.3**	**136.1**	**135.4**
1.3.15.1 इमारती धातु उत्पाद	1.031	132.3	132.8	129.3	130.9	130.2
1.3.15.2 धातु से बने टैंक, जलाशय और डिब्बे	0.660	157.6	153.9	146.9	147.6	147.4
1.3.15.3 वाष्प चालित जनरेटर, सेंट्रल हीटिंग हॉट वाटर बॉयलरर्स को छोड़कर	0.145	106.3	106.4	111.3	112.5	111.1
1.3.15.4 धातु की फोर्जिंग, दबाना, स्टैम्पिंग और रोल फॉरमिंग, पाउडर धातुकर्म	0.383	141.4	141.6	141.5	140.6	137.9
1.3.15.5 कटलरी, हस्त चालित उपकरण और सामान्य हार्डवेयर	0.208	108.4	109.3	102.2	102.4	102.5
1.3.15.6 अन्य गढ़े हुए धातु उत्पाद	0.728	143.8	142.8	144.3	145.1	144.8
1.3.16 कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल उत्पादों का विनिर्माण	**2.009**	**119.3**	**119.5**	**121.3**	**121.2**	**121.5**
1.3.16.1 इलेक्ट्रॉनिक पुरजे	0.402	115.0	114.2	117.3	118.4	118.3
1.3.16.2 कंप्यूटर और संबंधित उपकरण	0.336	135.3	135.1	133.6	132.6	132.7
1.3.16.3 संचार उपकरण	0.310	136.1	139.7	145.9	146.2	146.3
1.3.16.4 उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स	0.641	103.6	102.8	100.2	100.0	100.0
1.3.16.5 मापने, जांचने, नेविगेशन और नियंत्रण उपकरण	0.181	113.8	114.0	120.9	121.1	121.9
1.3.16.6 हाथ घड़ी और दीवार घड़ी	0.076	157.2	159.3	172.7	167.7	172.7
1.3.16.7 विभासन, विद्युत चिकित्सकीय एवं विद्युत उपचारात्मक उपकरण	0.055	108.3	109.0	115.2	116.5	116.1
1.3.16.8 ऑप्टिकल उपकरण और फोटोग्राफिक उपकरण	0.008	103.8	103.1	108.7	108.7	108.9
1.3.17 इलेक्ट्रिकल उपकरण का विनिर्माण	**2.930**	**131.4**	**132.1**	**133.8**	**134.1**	**134.1**
1.3.17.1 विद्युत मोटर्स, जनरेटर, ट्रांसफार्मर और बिजली वितरण और नियंत्रण संबंधी उपकरण	1.298	130.1	131.4	132.5	133.4	133.1
1.3.17.2 बैटरी और एक्युम्युलेटर	0.236	137.8	138.9	141.7	141.3	140.9
1.3.17.3 डेटा संचरण या छवियों के सजीव प्रसारण के लिए फाइबर ऑप्टिक केबल	0.133	123.4	123.1	117.5	118.0	116.8
1.3.17.4 अन्य इलेक्ट्रानिक और बिज़ली के वायर और केबल	0.428	146.1	145.9	154.5	154.1	154.8
1.3.17.5 वायरिंग संबंधी चीजें और बिजली के प्रकाश और सजावट के उपकरण	0.263	116.8	117.7	117.8	117.6	117.9
1.3.17.6 घरेलू उपकरण	0.366	133.8	134.0	131.8	131.8	132.0
1.3.17.7 अन्य इलेक्ट्रिकल उपकरण	0.206	120.9	120.6	124.8	125.1	124.7
1.3.18 मशीनरी और उपकरणों का विनिर्माण	**4.789**	**129.0**	**129.8**	**130.5**	**130.6**	**131.0**
1.3.18.1 इंजन और टर्बाइन, एयरक्राफ्ट, वाहन और दुपहिया वाहनों के इंजन को छोड़कर	0.638	128.9	129.7	133.6	132.5	133.3
1.3.18.2 तरल बिजली उपकरण	0.162	131.9	132.1	134.6	134.7	135.6
1.3.18.3 अन्य पंप, कंप्रेसर, नल और वाल्व	0.552	117.4	118.0	118.7	118.8	118.8
1.3.18.4 बेयरिंग, गियर्स, गेयरिंग और ड्राइविंग उपकरण	0.340	127.7	129.6	128.1	129.0	129.7
1.3.18.5 ओवन, फर्नेस और फर्नेस बर्नर	0.008	83.7	85.3	86.5	86.9	87.4
1.3.18.6 माल उठाने एवं चढ़ाने – उतारने वाले उपकरण	0.285	128.6	129.0	130.0	129.9	129.6

सं. 21: थोक मूल्य सूचकांक (समाप्त)

(आधारः 2011-12=100)

पण्य वस्तुएँ	भार	2023-24	2024			2025
			जन.	नवं.	दिसं.(अ)	जन.(अ)
	1	2	3	4	5	6
1.3.18.7 कार्यालय मशीनरी और उपकरण	0.006	130.2	130.2	130.2	130.2	130.2
1.3.18.8 सामान्य प्रयोजन के अन्य उपकरण	0.437	145.2	146.1	142.8	142.7	142.0
1.3.18.9 कृषि और वानिकी मशीनरी	0.833	142.5	144.1	145.6	145.8	146.7
1.3.18.10 धातु निर्माण करनेवाली मशीनरी और मशीन टूल्स	0.224	122.5	122.0	123.1	123.1	123.1
1.3.18.11 खनन, उत्खनन और निर्माण के लिए मशीनरी	0.371	88.6	88.7	89.5	90.0	91.0
1.3.18.12 खाद्य, पेय और तंबाकू प्रसंस्करण के लिए मशीनरी	0.228	124.4	124.2	126.0	126.2	126.9
1.3.18.13 कपड़ा, परिधान और चमड़े के उत्पादन से जुड़ी मशीनरी	0.192	137.2	135.7	138.2	141.3	141.6
1.3.18.14 अन्य विशेष प्रयोजनों के लिए मशीनरी	0.468	144.7	145.7	144.3	144.1	143.9
1.3.18.15 अक्षय ऊर्जा उत्पादन मशीनरी	0.046	70.8	70.7	68.6	68.8	69.0
1.3.19 मोटर वाहन, ट्रेलरों और अर्ध-ट्रेलरों का विनिर्माण	**4.969**	**128.4**	**128.5**	**129.4**	**129.8**	**130.1**
1.3.19.1 मोटर वाहन	2.600	128.5	128.3	129.7	130.5	131.0
1.3.19.2 मोटर वाहन पुरजे और सहायक उपकरण	2.368	128.2	128.7	129.0	129.1	129.0
1.3.20 अन्य परिवहन उपकरणों का विनिर्माण	**1.648**	**143.1**	**143.4**	**145.7**	**145.8**	**145.7**
1.3.20.1 जहाजों और तैरने वाली – वस्तुओं का निर्माण	0.117	163.7	163.7	177.9	177.9	188.4
1.3.20.2 रेलवे इंजन और रोलिंग स्टॉक	0.110	107.4	110.4	107.8	108.4	108.4
1.3.20.3 मोटर साइकल	1.302	144.7	144.8	147.0	147.0	146.0
1.3.20.4 साइकल और अवैध गाड़ी	0.117	137.9	138.2	133.3	135.1	134.4
1.3.20.5 अन्य परिवहन उपकरण	0.002	159.2	159.6	162.9	163.7	165.7
1.3.21 फर्नीचर का विनिर्माण	**0.727**	**159.6**	**160.0**	**162.9**	**161.3**	**161.8**
1.3.21.1 फर्नीचर	0.727	159.6	160.0	162.9	161.3	161.8
1.3.22 अन्य विनिर्माण	**1.064**	**158.2**	**160.8**	**183.8**	**183.1**	**186.9**
1.3.22.1 आभूषण और संबंधित सामग्री	0.996	157.9	160.9	185.3	184.6	188.8
1.3.22.2 संगीत उपकरण	0.001	187.0	190.6	205.2	200.6	197.2
1.3.22.3 खेल के सामान	0.012	155.2	155.3	167.8	167.9	167.7
1.3.22.4 खेल और खिलौने	0.005	159.6	159.9	163.6	163.5	164.4
1.3.22.5 चिकित्सा और दंत चिकित्सा उपकरण और संबंधित सामग्री	0.049	163.1	161.2	158.6	158.6	156.5
2 खाद्य सूचकांक	**24.378**	**179.8**	**178.1**	**200.2**	**195.9**	**191.4**

स्रोत: आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार।

सं. 22: औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आधारः 2011-12=100)

उद्योग	भार	2022-23	2023-24	अप्रैल-दिसंबर		दिसंबर	
				2023-24	2024-25	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7
सामान्य सूचकांक	100.00	138.5	146.7	144.4	150.2	152.3	157.2
1 क्षेत्रवार वर्गीकरण							
1.1 खनन	14.37	119.9	128.9	122.9	127.0	139.5	143.1
1.2 विनिर्माण	77.63	137.1	144.7	142.7	148.4	151.6	156.2
1.3 बिजली	7.99	185.2	198.3	199.0	209.8	181.6	192.8
2 उपयोग आधारित वर्गीकरण							
2.1 मूल वस्तुएं	34.05	139.2	147.7	145.2	150.8	151.9	157.7
2.2 पूंजीगत माल	8.22	100.3	106.6	103.6	108.9	103.8	114.5
2.3 मध्यवर्ती माल	17.22	149.4	157.3	155.2	162.2	159.8	169.3
2.4 इन्फ्रास्ट्रक्चर/निर्माण वस्तुएं	12.34	160.7	176.3	172.7	183.2	180.3	191.7
2.5 उपभोक्ता टिकाऊ माल	12.84	114.5	118.6	116.6	126.8	114.5	124.0
2.6 उपभोक्ता गैर-टिकाऊ माल	15.33	147.7	153.7	152.8	150.5	179.7	166.0

स्रोत: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार।

सरकारी लेखा और खजाना बिल

सं. 23: केन्द्र सरकार का लेखा - एक नज़र में

(₹ करोड़)

मद	वित्तीय वर्ष	अप्रैल-दिसंबर			
	2024-25 (संशोधित अनुमान)	2024-25 वास्तविक आंकड़े	2023-24 वास्तविक आंकड़े	बजट अनुमानों का प्रतिशत	
				2024-25	2023-24
	1	2	3	4	5
1 राजस्व प्राप्तियां	**3087960**	**2290710**	**2042289**	**74.2**	**75.6**
1.1 कर राजस्व (निवल)	2556960	1843053	1729931	72.1	74.4
1.2 करेतर राजस्व	531000	447657	312358	84.3	83.1
2 गैर कर्ज पूंजीगत प्राप्तियां	**59000**	**27295**	**29650**	**46.3**	**52.9**
2.1 ऋण की वसूली	26000	18301	19597	70.4	75.4
2.2 अन्य प्राप्तियां	33000	8994	10053	27.3	33.5
3 कुल प्राप्तियां (लिए गए उधार को छोड़कर) (1+2)	**3146960**	**2318005**	**2071939**	**73.7**	**75.2**
4 राजस्व व्यय जिसमें से :	3698058	2546757	2380587	68.9	67.2
4.1 ब्याज भुगतान	1137940	808313	748207	71.0	70.9
5 पूंजी व्यय	1018429	685337	673630	67.3	70.9
6 कुल व्यय (4+5)	**4716487**	**3232094**	**3054217**	**68.5**	**68.0**
7 राजस्व घाटा (4-1)	**610098**	**256047**	**338298**	**42.0**	**40.2**
8 राजकोषीय घाटा (6-3)	**1569527**	**914089**	**982278**	**58.2**	**56.6**
9 सकल प्राथमिक घाटा [8-4.1]	**431587**	**105776**	**234071**	**24.5**	**34.5**

स्रोत: महालेखानियंत्रक (सीजीए), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार और अंतरिम केंद्रीय बजट 2025-26।

सं. 24: खज़ाना बिल - स्वामित्व का स्वरूप

(₹ करोड़)

मद	2023-24	2023	2024					
		दिसं. 29	नवं. 22	नवं. 29	दिसं. 6	दिसं. 13	दिसं. 20	दिसं. 27
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 91-दिवसीय								
1.1 बैंक	18054	9694	3054	3848	3875	3966	4311	8030
1.2 प्राथमिक व्यापारी	22676	16909	9025	9398	10342	8735	10210	6404
1.3 राज्य सरकारें	5701	24851	79060	82560	84296	86046	95646	109146
1.4 अन्य	88670	75897	81021	78354	75883	75899	81079	88165
2 182-दिवसीय								
2.1 बैंक	84913	79976	40000	42525	42131	42959	46651	49106
2.2 प्राथमिक व्यापारी	87779	60167	32689	30551	29378	29890	33579	34108
2.3 राज्य सरकारें	4070	8887	12265	11265	11265	10265	6515	8515
2.4 अन्य	102311	78861	78212	80824	84891	86751	81370	80386
3 364-दिवसीय								
3.1 बैंक	91819	102529	78510	75027	75344	77042	76504	76181
3.2 प्राथमिक व्यापारी	159085	177911	108012	106748	105794	104793	105013	104156
3.3 राज्य सरकारें	41487	44909	35829	35933	34438	35686	35632	35184
3.4 अन्य	165095	168561	169478	171225	168862	165165	162483	160663
4 14-दिवसीय मध्यवर्ती								
4.1 बैंक								
4.2 प्राथमिक व्यापारी								
4.3 राज्य सरकारें	318736	198774	190890	188494	126670	174019	182802	173736
4.4 अन्य	442	1780	1357	551	1729	546	1074	449
कुल खज़ाना बिल (14 दिवसीय मध्यवर्ती खज़ाना बिल को छोड़कर)#	871662	849151	727154	728257	726498	727197	738993	760045

14 दिवसीय मध्यवर्ती खज़ाना बिल बिक्री योग्य नहीं है, ये बिल 91 दिवसीय, 182 दिवसीय और 364 दिवसीय खज़ाना बिलों जैसे नहीं है। इन बिलों का स्वरूप मध्यवर्ती है, क्योंकि राज्य सरकारों के दैनिक न्यूनतम नकदी शेष में कमी को पूरा करने के लिए इन्हें परिसमाप्त किया जाता है।

टिप्पणी: प्राथमिक व्यापारियों (पीडी) में पीडी कारोबार करने वाले बैंक शामिल हैं।

सं. 25: खज़ाना बिलों की नीलामी

(राशि करोड़ ₹ में)

नीलामी की तारीख	अधिसूचित राशि	प्राप्त बोलियां			स्वीकृत बोलियाँ			कुल निर्गम (6+7)	कट-ऑफ मूल्य (₹)	कट-ऑफ मूल्य पर निहित प्रतिफल (प्रतिशत)
		संख्या	कुल अंकित मूल्य		संख्या	कुल अंकित मूल्य				
			प्रतियोगी	गैर-प्रतियोगी		प्रतियोगी	गैर-प्रतियोगी			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
91-दिवसीय खज़ाना बिल										
2024-25										
नवं. 27	7000	93	19172	10028	49	6972	10028	17000	98.41	6.4929
दिसं. 4	7000	112	23634	9796	34	6941	9796	16737	98.42	6.4287
दिसं.11	7000	109	27635	9591	35	6959	9591	16550	98.42	6.4478
दिसं.18	7000	106	25391	9625	33	6975	9625	16600	98.41	6.4726
दिसं.26	7000	80	23077	13523	32	6977	13523	20500	98.39	6.5489
182-दिवसीय खज़ाना बिल										
2024-25										
नवं. 27	6000	96	20278	1015	38	5985	1015	7000	96.79	6.6599
दिसं. 4	6000	66	22335	1530	11	5970	1530	7500	96.84	6.5386
दिसं. 11	6000	78	13477	1216	57	5984	1216	7200	96.81	6.6100
दिसं. 18	6000	107	20487	819	44	5981	819	6800	96.80	6.6400
दिसं. 26	6000	93	19875	2019	33	5981	2019	8000	96.77	6.7000
364-दिवसीय खज़ाना बिल										
2024-25										
नवं. 27	6000	72	14513	119	41	5994	119	6114	93.78	6.6545
दिसं. 4	6000	91	19692	119	23	5986	119	6106	93.89	6.5295
दिसं. 11	6000	82	16529	1285	42	5987	1285	7272	93.84	6.5780
दिसं. 18	6000	96	18029	137	51	5965	137	6102	93.80	6.6300
दिसं. 26	6000	88	23340	1672	21	5991	1672	7662	93.75	6.6878

वित्तीय बाजार

सं. 26: दैनिक मांग मुद्रा दरें

(वार्षिक प्रतिशत)

स्थिति के अनुसार	दरों का दायरा	भारित औसत दरें
	उधार लेना / उधार देना	उधार लेना / उधार देना
	1	2
दिसंबर 02 ,2024	5.10-6.65	6.51
दिसंबर 03 ,2024	5.10-6.50	6.44
दिसंबर 04 ,2024	5.10-6.60	6.42
दिसंबर 05 ,2024	5.10-6.75	6.54
दिसंबर 06 ,2024	5.50-6.75	6.52
दिसंबर 07 ,2024	5.50-6.70	6.15
दिसंबर 09 ,2024	5.50-6.75	6.56
दिसंबर 10 ,2024	5.50-6.85	6.67
दिसंबर 11 ,2024	5.50-6.90	6.70
दिसंबर 12 ,2024	5.50-6.80	6.62
दिसंबर 13 ,2024	5.50-6.85	6.68
दिसंबर 16 ,2024	5.50-6.90	6.70
दिसंबर 17 ,2024	5.10-6.85	6.70
दिसंबर 18 ,2024	5.10-6.85	6.69
दिसंबर 19 ,2024	5.10-6.90	6.71
दिसंबर 20 ,2024	5.10-7.00	6.74
दिसंबर 21 ,2024	5.50-6.80	6.14
दिसंबर 23 ,2024	5.10-6.90	6.74
दिसंबर 24 ,2024	5.10-6.90	6.71
दिसंबर 26 ,2024	5.10-6.85	6.66
दिसंबर 27 ,2024	5.10-7.00	6.77
दिसंबर 30 ,2024	5.10-7.00	6.74
दिसंबर 31 ,2024	5.10-7.25	6.87
जनवरी 1, 2025	5.10-6.70	6.52
जनवरी 2, 2025	5.10-6.60	6.47
जनवरी 3, 2025	5.10-6.75	6.50
जनवरी 4, 2025	5.75-6.60	6.12
जनवरी 6, 2025	5.10-6.80	6.64
जनवरी 7, 2025	5.10-6.95	6.73
जनवरी 8, 2025	5.10-7.05	6.74
जनवरी 9, 2025	5.10-7.05	6.82
जनवरी 10, 2025	5.10-7.10	6.87
जनवरी 13, 2025	5.70-7.10	6.81
जनवरी 14, 2025	5.50-6.75	6.52
जनवरी 15, 2025	5.10-6.70	6.45

टिप्पणी: नोटिस मुद्रा सहित।

सं. 27: जमा प्रमाण-पत्र

मद	2023	2024				2025	
	दिसं. 29	नवं. 15	नवं. 29	दिसं. 13	दिसं. 27	जन. 10	जन. 24
	1	2	3	4	5	6	7
1 बकाया राशि (₹ करोड़)	344752.77	489838.50	491658.72	488257.46	494416.56	493930.59	499396.94
1.1 पखवाड़े के दौरान जारी (₹ करोड़)	38992.46	46552.33	40434.94	74226.34	59838.75	33890.42	30080.60
2 ब्याज दर (प्रतिशत)	7.27-7.98	6.98-7.85	6.98-7.60	6.96-7.75	7.02-7.85	7.05-7.48	7.07-7.88

सं. 28: वाणिज्यिक पत्र

मद	2023	2024			
	दिसं. 31	नवं. 15	नवं. 30	दिसं. 15	दिसं. 31
	1	2	3	4	5
1 बकाया राशि (र करोड़)	364181.25	448862.80	445122.05	463801.30	435779.45
1.1 पखवाड़े के दौरान रिपोर्ट किए गए (₹ करोड़)	42874.35	50771.85	64504.65	98956.25	51524.05
2 ब्याज दर (प्रतिशत)	7.02-12.13	6.99-13.77	7.00-12.61	7.00-11.89	6.98-12.00

सं. 29: चुनिंदा वित्तीय बाजारों में औसत दैनिक कारोबार

(₹ करोड़)

मद	2023-24	2023	2024					
		दिसं. 29	नवं. 22	नवं. 29	दिसं. 6	दिसं. 13	दिसं. 20	दिसं. 27
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 मांग मुद्रा	17761	17285	14474	14605	15780	21252	21302	18396
2 नोटिस मुद्रा	2550	5238	331	4241	3744	213	4378	177
3 मीयादी मुद्रा	871	598	895	1743	843	720	896	539
4 त्रिपक्षीय रेपो	601363	708714	707471	939435	719747	695288	825455	698889
5 बाजार रेपो	574534	512436	493723	585745	512219	521188	616987	452238
6 कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो	1817	1207	4588	5114	5835	5302	6123	8475
7 फोरेक्स (यूएस मिलियन डॉलर)	95115	121622	108061	123525	128628	135496	129131	130014
8 भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां	90992	52022	76147	83490	161875	135854	92916	63621
9 राज्य सरकारों की प्रतिभूतियां	6102	6640	5307	4154	8593	6813	7900	10874
10 खज़ाना बिल								
10.1 91-दिवसीय	5378	7661	3669	1988	2217	3692	3586	6006
10.2 182-दिवसीय	6079	5339	3533	3800	1887	2802	2153	3089
10.3 364-दिवसीय	4307	5623	3550	3800	2706	2906	1851	2669
10.4 नकदी प्रबंधन बिल			0	0	0	0	0	0
11 कुल सरकारी प्रतिभूतियां (8+9+10)	112858	77285	92206	97232	177278	152067	108407	86258
11.1 भारतीय रिज़र्व बैंक	492	46	15	213	320	286	666	306

सं. 30: गैर-सरकारी सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों के नए पूंजी निर्गम

(राशि ₹ करोड़ में)

प्रतिभूति और निर्गम का प्रकार	2023-24		2023-24 (अप्रै.-दिसं.)		2024-25 (अप्रै.-दिसं.) *		दिसं. 2023		दिसं. 2024 *	
	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 इक्विटी शेयर	**339**	**80942**	**243**	**57411**	**368**	**189018**	**33**	**9572**	**48**	**31119**
1.1 पब्लिक	272	65832	195	50873	261	172137	31	9534	34	27031
1.2 राइट्स	67	15110	48	6538	107	16881	2	38	14	4088
2 बॉण्ड और डिबेंचर	**44**	**16342**	**32**	**12932**	**32**	**6628**	**6**	**2014**	**3**	**722**
3 कुल (1+2+3)	**383**	**97284**	**275**	**70343**	**400**	**195646**	**39**	**11586**	**51**	**31841**
3.1 पब्लिक	316	82174	227	63805	293	178765	37	11548	37	27753
3.2 राइट्स	67	15110	48	6538	107	16881	2	38	14	4088

टिप्पणी: 1. अप्रैल 2020 से इक्विटी निर्गमों का मासिक डेटा उनकी लिस्टिंग की तारीख के आधार पर संकलित किया गया है।

2. संख्याओं के पूर्णांकन के कारण कॉलम के आंकड़े कुल में न जुड़ पाने की संभावना है।

3. सारणी में केवल इक्विटी और कर्ज के सार्वजनिक और अधिकार निर्गमों को शामिल किया गया है। इसमें ऋण के निजी स्थानन, अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन और अधिमानी आबंटन के आंकड़े शामिल नहीं हैं।

स्रोत: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी)।

* : आंकड़े अनंतिम है।

बाह्य क्षेत्र

सं. 31 : विदेशी व्यापार

मद	इकाई	2023-24	2023	2024				
			दिसं.	अग.	सितं.	अक्तू.	नवं.	दिसं.
		1	2	3	4	5	6	7
1 निर्यात	₹ करोड़	3618952	319716	289305	287578	327712	270298	323039
	मिलियन यूएस $	437072	38391	34484	34314	39000	32039	38011
1.1 तेल	₹ करोड़	696850	57369	47817	37764	37175	30891	41787
	मिलियन यूएस $	84157	6889	5700	4506	4424	3662	4917
1.2 तेल से इतर	₹ करोड़	2922102	262347	241488	249814	290537	239406	281252
	मिलियन यूएस $	352915	31502	28784	29808	34576	28378	33094
2 आयात	₹ करोड़	5616042	475950	524948	452606	530437	538792	509477
	मिलियन यूएस $	678215	57152	62571	54005	63125	63865	59948
2.1 तेल	₹ करोड़	1480232	124422	92396	104574	153628	134229	129782
	मिलियन यूएस $	178733	14940	11013	12478	18283	15911	15271
2.2 तेल से इतर	₹ करोड़	4135810	351528	432552	348032	376809	404562	379695
	मिलियन यूएस $	499482	42211	51558	41527	44842	47954	44677
3 व्यापार शेष	₹ करोड़	-1997090	-156235	-235643	-165028	-202725	-268494	-186438
	मिलियन यूएस $	-241143	-18760	-28087	-19691	-24125	-31825	-21937
3. 1 तेल	₹ करोड़	-783382	-67054	-44579	-66811	-116453	-103338	-87995
	मिलियन यूएस $	-94576	-8052	-5314	-7972	-13859	-12249	-10354
3. 2 तेल से इतर	₹ करोड़	-1213708	-89181	-191064	-98217	-86272	-165156	-98443
	मिलियन यूएस $	-146567	-10709	-22774	-11719	-10267	-19577	-11583

टिप्पणी: सारणी में डेटा अनंतिम हैं।
स्रोत : वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय तथा वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय।

सं. 32: विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियां

मद	इकाई	2024		2025				
		फर. 02	दिसं. 27	जन. 03	जन. 10	जन. 17	जन. 24	जन. 31
		1	2	3	4	5	6	7
1 कुल आरक्षित निधियां	**₹ करोड़**	**5161947**	**5476869**	**5443633**	**5380402**	**5404532**	**5426706**	**5461741**
	यूएस $ मिलियन	**622469**	**640279**	**634585**	**625871**	**623983**	**629557**	**630607**
1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	₹ करोड़	4572053	4721047	4679273	4607932	4617658	4636524	4656917
	यूएस $ मिलियन	551331	551921	545480	536011	533133	537891	537684
1.2 स्वर्ण	₹ करोड़	398786	566843	575530	583572	597172	600379	614007
	यूएस $ मिलियन	48088	66268	67092	67883	68947	69651	70893
	मात्रा (मीट्रिक टन)	812.33	876.18	876.18	877.14	877.14	877.14	879.01
1.3 एसडीआर	एसडीआर मिलियन	13688	13705	13705	13705	13705	13705	13705
	₹ करोड़	150849	152881	152818	152861	154015	153955	154942
	यूएस $ मिलियन	18190	17873	17815	17781	17782	17861	17889
1.4 आईएमएफ में आरक्षित भाग की स्थिति	₹ करोड़	40260	36097	36012	36037	35687	35848	35875
	यूएस $ मिलियन	4860	4217	4199	4195	4122	4154	4141

* अंतर यदि कोई हो, तो पूर्णांकन की वजह से है।
टिप्पणी : आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में निर्दिष्ट बॉण्डों में निवेश, भारत सरकार द्वारा रिज़र्व बैंक को अंतरित एसडीआर तथा सार्क और एसीयू करेंसी स्वैप व्यवस्था के अंतर्गत प्राप्त विदेशी मुद्रा शामिल नहीं हैं। अमेरिकी डॉलर में दिखाई गई विदेशी मुद्रा को आस्तियों में रिज़र्व में रखी गैर यूएस मुद्राओं (जैसे यूरो, स्टर्लिंग, येन और ऑस्ट्रेलिया डॉलर) के मूल्यवृद्धि/मूल्यह्रास के लिए शामिल किया गया है। विदेशी मुद्रा धारिता को रुपया - अमेरिकी डॉलर आरबीआई धारिता दरों पर रुपए में परिवर्तित किया गया है।

सं. 33: अनिवासी भारतीयों की जमाराशियाँ

(मिलियन अमेरिकी डॉलर)

योजना	बकाया				प्रवाह	
	2023-24	2023	2024		2023-24	2024-25
		दिसं.	नवं.	दिसं. (अ)	अप्रै-दिसं.	अप्रै-दिसं. (अ)
	1	2	3	4	5	6
1 एनआरआई जमाराशियाँ	**151879**	**146909**	**162697**	**161804**	**9338**	**13333**
1.1 एफसीएनआर (बी)	25733	22815	32040	32198	3452	6465
1.2 एनआर (ई) आरए	98624	97692	100666	99565	2916	3572
1.3 एनआरओ	27522	26403	29992	30041	2970	3296

अ: अनंतिम।

सं. 34: विदेशी निवेश अंतर्वाह

(मिलियन अमेरिकी डॉलर)

मद	2023-24	2023-24	2024-25 (अ)	2023	2024 (अ)	
		अप्रै.-दिसं.	अप्रै.-दिसं.	दिसं.	नवं.	दिसं.
	1	2	3	4	5	6
1.1 निवल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (1.1.1-1.1.2)	**10129**	**7846**	**1180**	**-656**	**-2630**	**707**
1.1.1 भारत में प्रत्यक्ष निवेश (1.1.1.1-1.1.1.2)	**26807**	**18760**	**18487**	**1312**	**-97**	**2461**
1.1.1.1 सकल अंतर्वाह / सकल निवेश	**71279**	**51821**	**62483**	**4628**	**5373**	**6838**
1.1.1.1.1 इक्विटी	45817	33055	41385	2495	2370	4458
1.1.1.1.1.1 सरकारी (एसआईए/एफआईपीबी)	585	327	1848	103	72	1248
1.1.1.1.1.2 भारतीय रिज़र्व बैंक	31826	21067	27367	1278	1676	1543
1.1.1.1.1.3 शेयरों का अधिग्रहण	12013	10643	11457	993	537	1583
1.1.1.1.1.4 अनिगमित निकायों की इक्विटी पूंजी	1394	1018	712	121	85	85
1.1.1.1.2 पुनर्निवेशित आय	19768	14435	16873	1718	1996	1996
1.1.1.1.3 अन्य पूंजी	5694	4330	4225	414	1007	383
1.1.1.2 प्रत्यावर्तन / विनिवेश	**44472**	**33061**	**43996**	**3316**	**5470**	**4377**
1.1.1.2.1 इक्विटी	41334	30401	42311	2924	5088	4299
1.1.1.2.2 अन्य पूंजी	3137	2660	1685	392	382	77
1.1.2 भारत द्वारा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (1.1.2.1+1.1.2.2+ 1.1.2.3-1.1.2.4)	**16678**	**10914**	**17307**	**1968**	**2533**	**1754**
1.1.2.1 इक्विटी पूंजी	9111	5902	9861	902	1020	1164
1.1.2.2 पुनर्निवेशित आय	5786	4339	4474	482	482	482
1.1.2.3 अन्य पूंजी	5406	3591	5581	773	1230	640
1.1.2.4 प्रत्यावर्तन / विनिवेश	3624	2918	2608	189	200	532
1.2 निवल संविभागीय निवेश (1.2.1+1.2.2+1.2.3-1.2.4)	**44081**	**32690**	**9252**	**9555**	**-2379**	**1712**
1.2.1 जीडीआर/एडीआर	-	-	-	-	-	-
1.2.2 एफआईआई	44626	33047	9107	9442	-2396	1766
1.2.3 अपतटीय निधियां और अन्य	-	-	-	-	-	-
1.2.4 भारत द्वारा संविभागीय निवेश	544	357	-145	-114	-17	54
1 विदेशी निवेश अंतर्वाह	**54210**	**40535**	**10432**	**8899**	**-5008**	**2419**

अ: अनंतिम।

सं. 35: वैयक्तिक निवासियों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) के अंतर्गत जावक विप्रेषण

(मिलियन अमेरिकी डॉलर)

मद	2023-24	2023	2024		
		दिसं.	सितं. अक्तू.	नवं.	दिसं.
	1	2	3	4	5
1 एलआरएस के अंतर्गत जावक विप्रेषण	**31735.74**	**2402.07**	**2408.01**	**1946.43**	**2315.96**
1.1 जमाराशियाँ	916.45	26.64	39.06	40.21	48.10
1.2 अचल संपत्ति की खरीद	242.51	12.17	24.96	23.53	30.14
1.3 इक्विटी / कर्ज में निवेश	1510.89	101.43	149.34	85.79	179.34
1.4 उपहार	3580.27	190.77	216.30	216.51	229.47
1.5 दान	11.31	0.71	0.66	0.62	0.63
1.6 यात्रा	17006.27	1548.65	1454.66	1113.78	1323.64
1.7 निकट संबंधियों से संबंधित खर्चे	4611.53	219.71	283.75	276.78	279.02
1.8 चिकित्सा उपचार	79.62	7.79	8.49	7.49	5.13
1.9 विदेश में शिक्षा	3478.65	267.56	221.18	172.40	210.20
1.10 अन्य	298.23	26.65	9.62	9.32	10.31

सं. 36: भारतीय रुपये का सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर (एनईईआर) और वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आरईईआर) सूचकांक

मद	2022-23	2023-24	2024		2025
			जन.	दिसं.	जन.
	1	2	3	4	5
40- मुद्रा समूह (आधार: 2015-16 = 100)					
1 व्यापार आधारित भारांक					
1.1 नीर	91.20	90.75	90.70	91.69	90.84
1.2 रीर	102.78	103.71	103.70	107.13	104.82
2 निर्यात आधारित भारांक					
2.1 नीर	93.01	93.13	93.24	94.02	93.23
2. 2 रीर	101.10	101.23	101.21	103.92	101.75
6- मुद्रा समूह (व्यापार-भारित)					
1 आधार : 2015-16 =100					
1.1 नीर	85.93	83.62	83.15	82.78	82.02
1.2 रीर	101.80	101.66	101.74	104.64	102.76
2 आधार : 2022-23 = 100					
2.1 नीर	100.00	97.31	96.76	96.33	95.45
2.2 रीर	100.00	99.86	99.94	102.79	100.93
मेमो मदें					
आईएनआर-यूएसडी दर	80.36	82.79	83.12	84.99	86.27
भारत की सीपीआई मुद्रास्फीति (प्रतिशत में)	6.7	5.4	5.1	5.2	4.3

टिप्पणियाँ: 1. एनईईआर और आरईईआर पर वार्षिक डेटा, विनिमय दरों के वार्षिक औसत पर आधारित हैं, जबकि मासिक डेटा विनिमय दरों के मासिक औसत पर आधारित हैं।

2. वर्ष 2023-24 और 2024-25 के लिए अब तक के डेटा अनंतिम हैं।

सं. 37: बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) - पंजीकरण

(राशि मिलियन यूएस$ में)

मद	2023-24	2023	2024	
		दिसं.	नवं.	दिसं.
	1	2	3	4
1 स्वचालित मार्ग				
1.1 संख्या	1188	95	82	112
1.2 राशि	29461	3693	1398	6234
2 अनुमोदन मार्ग				
2.1 संख्या	33	3	4	12
2.2 राशि	19748	1450	1435	3309
3 कुल (1+2)				
3.1 संख्या	1221	98	86	124
3.2 राशि	49209	5143	2833	9543
4 भारित औसत परिपक्वता (वर्षो में)	5.60	4.90	5.80	4.50
5 ब्याज दर (प्रतिशत)				
5.1 अस्थिर दर के ऋणों@ के लिए वैकल्पिक संदर्भ दर पर भारित औसत मार्जिन	1.66	1.85	1.18	1.45
5.2 सावधि दर के ऋणों के लिए ब्याज दर की सीमा	0.00-27.00	0.00-10.50	0.00-11.00	0.00-10.60
उधारकर्ता श्रेणियाँ				
I. कॉरपोरेट विनिर्माण	15836	519	1419	3685
II. कॉरपोरेट - बुनियादी संरचना	15916	2623	372	533
ए) परिवहन	1505	240	0	0
बी) ऊर्जा	3513	1963	60	0
सी) पानी और सफाई व्यवस्था	33	0	0	0
डी) संचार	6309	0	0	0
ई) सामाजिक और वाणिज्यिक बुनियादी संरचना	115	0	0	0
एफ) अन्वेषण, खनन और रिफाइनरी	2480	420	312	530
जी) अन्य उप-क्षेत्र	1961	0	0	3
III. कॉरपोरेट सेवा क्षेत्र	1526	58	256	685
IV. अन्य संस्थाएं	1728	750	0	3
ए) एसईज़ेड में इकाई	1	0	0	3
बी) सिडबी	0	0	0	0
सी) एक्जिम बैंक	1727	750	0	0
V. बैंक	0	0	0	0
VI. वित्तीय संस्थान (एनबीएफसी के अलावा)	20	0	0	-
VII. एनबीएफसी	13361	1131	743	4614
ए) एनबीएफसी - आईएफसी / एएफसी	7734	700	75	3042
बी) एनबीएफसी - एमएफआई	531	11	0	0
सी) एनबीफसी - अन्य	5096	420	668	1572
VIII. गैर -सरकारी संगठन (एनजीओ)	0	0	0	0
IX. सूक्ष्म वित्त संस्था (एमएफआई)	0	0	0	0
X. अन्य	822	62	43	23

टिप्पणी: ईसीबी/विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉण्ड (एफसीसीबी) के लिए आवेदनों के आधार पर जिन्हें निर्धारित अवधि के दौरान ऋण पंजीकरण संख्या आबंटित की गई है।

@ 01 जुलाई, 2023 से लागू, बेंचमार्क दर को बदलकर वैकल्पिक संदर्भ दर कर दिया गया है।

सं. 38: भारत का समग्र भुगतान संतुलन

(मिलियन यूएस$)

मद	जुला-सितं 2023			जुला-सितं 2024 (अ)		
	जमा	नामे	निवल	जमा	नामे	निवल
	1	2	3	4	5	6
समग्र भुगतान शेष (1+2+3)	**438441**	**435922**	**2519**	**553557**	**534943**	**18614**
1 चालू खाता (1.1+1.2)	**231670**	**242956**	**-11286**	**245671**	**256854**	**-11182**
1.1 पण्य	**108254**	**172799**	**-64544**	**103967**	**179285**	**-75319**
1.2 अप्रत्यक्ष मदें (1.2.1+1.2.2+1.2.3)	**123416**	**70158**	**53258**	**141705**	**77568**	**64137**
1.2.1 सेवाएं	83352	43411	39940	93493	48943	44550
1.2.1.1 यात्रा	7482	8662	-1180	7635	9367	-1732
1.2.1.2 परिवहन	7054	7277	-223	8792	9188	-396
1.2.1.3 बीमा	828	821	7	902	786	116
1.2.1.4 जी.एन.आई.ई.	140	244	-104	147	316	-169
1.2.1.5 विविध	67848	26408	41440	76017	29287	46730
1.2.1.5.1 सॉफ्टवेयर सेवाएं	39570	4333	35237	44164	4539	39624
1.2.1.5.2 कारोबार सेवाएं	21472	13673	7799	25176	15548	9628
1.2.1.5.3 वित्तीय सेवाएं	2069	1183	887	2190	1265	926
1.2.1.5.4 संचार सेवाएं	887	365	522	519	497	21
1.2.2 अंतरण	28147	3221	24926	31938	2829	29109
1.2.2.1 आधिकारिक	23	267	-244	28	265	-237
1.2.2.2 निजी	28124	2954	25170	31910	2564	29346
1.2.3 आय	11917	23526	-11608	16274	25796	-9522
1.2.3.1 निवेश आय	10158	22609	-12451	14279	24774	-10494
1.2.3.2 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	1760	917	843	1995	1023	972
2 पूंजी खाता (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	**205807**	**192966**	**12841**	**307885**	**277368**	**30518**
2.1 विदेशी निवेश (2.1.1+2.1.2)	**128572**	**124460**	**4112**	**203323**	**185710**	**17612**
2.1.1 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश	16586	17420	-834	21214	23452	-2238
2.1.1.1 भारत में	15722	12686	3036	20666	15622	5044
2.1.1.1.1 इक्विटी	9877	12278	-2401	13847	15016	-1169
2.1.1.1.2 पुनर्निवेशित आय	4740		4740	5559		5559
2.1.1.1.3 अन्य पूंजी	1105	409	697	1261	606	655
2.1.1.2 विदेश में	864	4734	-3870	548	7830	-7282
2.1.1.1.1 इक्विटी	864	1683	-820	548	4313	-3765
2.1.1.1.2 पुनर्निवेशित आय	0	1446	-1446	0	1514	-1514
2.1.1.1.3 अन्य पूंजी	0	1604	-1604	0	2003	-2003
2.1.2 संविभाग निवेश	111986	107040	4947	182108	162258	19850
2.1.2.1 भारत में	111127	105841	5286	181433	161618	19815
2.1.2.1.1 एफआईआई	111127	105841	5286	181433	161618	19815
2.1.2.1.1.1 इक्विटी	101529	97937	3593	160273	149590	10683
2.1.2.1.1.2 ऋण	9598	7905	1693	21160	12028	9132
2.1.2.1.2 एडीआर / जीडीआर	0	0	0	0	0	0
2.1.2.2 विदेश में	859	1198	-339	675	640	35
2.2 ऋण (2.2.1+2.2.2+2.2.3)	**29728**	**26453**	**3274**	**38662**	**31126**	**7536**
2.2.1 बाह्य सहायता	2601	1800	802	3727	1581	2146
2.2.1.1 भारत द्वारा	9	49	-40	8	30	-22
2.2.1.2 भारत को	2592	1751	842	3720	1551	2168
2.2.2 वाणिज्यिक उधार	7464	10422	-2958	17443	15416	2027
2.2.2.1 भारत द्वारा	2853	3926	-1073	5059	8028	-2969
2.2.2.2 भारत को	4612	6496	-1884	12384	7388	4996
2.2.3 भारत को अल्पावधि	19662	14232	5430	17492	14129	3363
2.2.3.1 खरीदार और आपूर्तिकर्ता का ऋण > 180 दिन	17632	14232	3400	14817	14129	688
2.2.3.2 आपूर्तिकर्ता का 180 दिन तक का ऋण	2030	0	2030	2675	0	2675
2.3 बैंकिंग पूंजी (2.3.1+2.3.2)	**34020**	**29686**	**4333**	**52432**	**46345**	**6087**
2.3.1 वाणिज्यिक बैंक	34020	29614	4405	52112	46345	5767
2.3.1.1 आस्तियां	8673	11210	-2538	17627	18853	-1226
2.3.1.2 देयताएं	25347	18404	6943	34485	27492	6993
2.3.1.2.1 अनिवासी जमाराशियाँ	21257	18048	3209	28921	22753	6167
2.3.2 अन्य	0	72	-72	319	0	319
2.4 रुपया कर्ज चुकौती	**0**	**1**	**-1**	**0**	**2**	**-2**
2.5 अन्य पूंजी	**13488**	**12365**	**1123**	**13469**	**14184**	**-716**
3 भूल-चक	**963**	**0**	**963**	**0**	**722**	**-722**
4 मौद्रिक गतिविधियां (4.1+4.2)	**0**	**2519**	**-2519**	**0**	**18614**	**-18614**
4.1 आई.एम.एफ.	0	0	0	0	0	0
4.2 विदेशी मुद्रा भंडार (वृद्धि - / कमी +)	0	2519	-2519	0	18614	-18614

टिप्पणी: प्रा: प्रारंभिक

सं. 39: भारत का समग्र भुगतान संतुलन

(₹ करोड़)

मद	जुला-सितं 2023			जुला-सितं 2024 (अ)		
	जमा	नामे	निवल	जमा	नामे	निवल
	1	2	3	4	5	6
समग्र भुगतान शेष (1+2+3)	**3624220**	**3603401**	**20819**	**4636946**	**4481027**	**155919**
1 चालू खाता (1.1+1.2)	**1915021**	**2008316**	**-93295**	**2057901**	**2151571**	**-93670**
1.1 पण्य	**894849**	**1428380**	**-533531**	**870890**	**1501809**	**-630919**
1.2 अदृश्य मदें (1.2.1+1.2.2+1.2.3)	**1020172**	**579936**	**440236**	**1187011**	**649762**	**537249**
1.2.1 सेवाएं	688997	358846	330151	783157	409979	373178
1.2.1.1 यात्रा	61845	71601	-9756	63958	78464	-14506
1.2.1.2 परिवहन	58311	60151	-1840	73649	76965	-3316
1.2.1.3 बीमा	6842	6785	57	7553	6581	972
1.2.1.4 जी.एन.आई.ई.	1154	2018	-863	1228	2643	-1415
1.2.1.5 विविध	560846	218292	342554	636769	245326	391443
1.2.1.5.1 सॉफ्टवेयर सेवाएं	327091	35818	291272	369945	38026	331920
1.2.1.5.2 कारोबार सेवाएं	177488	113019	64469	210894	130244	80650
1.2.1.5.3 वित्तीय सेवाएं	17106	9777	7329	18349	10595	7754
1.2.1.5.4 संचार सेवाएं	7334	3015	4319	4345	4167	177
1.2.2 अंतरण	232665	26623	206042	267531	23696	243835
1.2.2.1 आधिकारिक	189	2206	-2018	232	2218	-1985
1.2.2.2 निजी	232476	24416	208060	267298	21478	245821
1.2.3 आय	98510	194468	-95957	136323	216087	-79763
1.2.3.1 निवेश आय	83966	186888	-102922	119611	207519	-87908
1.2.3.2 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	14544	7579	6965	16712	8568	8145
2 पूंजी खाता (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	**1701234**	**1595084**	**106150**	**2579045**	**2323409**	**255635**
2.1 विदेशी निवेश (2.1.1+2.1.2)	**1062795**	**1028803**	**33993**	**1703161**	**1555629**	**147532**
2.1.1 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश	137100	143996	-6896	177706	196451	-18745
2.1.1.1 भारत में	129962	104866	25096	173115	130862	42253
2.1.1.1.1 इक्विटी	81644	101488	-19844	115988	125784	-9796
2.1.1.1.2 पुनर्निवेशित आय	39181	0	39181	46563	0	46563
2.1.1.1.3 अन्य पूंजी	9137	3378	5759	10564	5078	5486
2.1.1.2 विदेश में	7138	39130	-31992	4591	65589	-60998
2.1.1.2.1 इक्विटी	7138	13916	-6778	4591	36128	-31537
2.1.1.2.2 पुनर्निवेशित आय	0	11956	-11956	0	12680	-12680
2.1.1.2.3 अन्य पूंजी	0	13258	-13258	0	16780	-16780
2.1.2 संविभाग निवेश	925695	884807	40889	1525455	1359178	166277
2.1.2.1 भारत में	918597	874902	43695	1519799	1353816	165984
2.1.2.1.1 एफआईआई	918597	874902	43695	1519799	1353816	165984
2.1.2.1.1.1 इक्विटी	839257	809559	29698	1342550	1253064	89486
2.1.2.1.1.2 ऋण	79340	65343	13997	177250	100752	76498
2.1.2.1.2 एडीआर /जीडीआर	0	0	0	0	0	0
2.1.2.2 विदेश में	7099	9905	-2806	5656	5363	293
2.2 ऋण (2.2.1+2.2.2+2.2.3)	**245733**	**218667**	**27066**	**323859**	**260732**	**63127**
2.2.1 बाह्य सहायता	21502	14877	6626	31222	13242	17979
2.2.1.1 भारत द्वारा	72	404	-331	64	247	-184
2.2.1.2 भारत को	21430	14473	6957	31158	12995	18163
2.2.2 वाणिज्यिक उधार	61702	86150	-24448	146114	129136	16979
2.2.2.1 भारत द्वारा	23582	32453	-8871	42379	67249	-24870
2.2.2.2 भारत को	38120	53697	-15577	103735	61887	41849
2.2.3 भारत को अल्पावधि	162529	117640	44888	146523	118354	28169
2.2.3.1 खरीदार और आपूर्तिकर्ता का ऋण > 180 दिन	145745	117640	28105	124117	118354	5763
2.2.3.2 आपूर्तिकर्ता का 180 दिन तक का ऋण	16783	0	16783	22406	0	22406
2.3 बैंकिंग पूंजी (2.3.1+2.3.2)	**281213**	**245392**	**35820**	**439202**	**388217**	**50985**
2.3.1 वाणिज्यिक बैंक	281213	244798	36415	436527	388217	48311
2.3.1.1 आस्तियां	71689	92667	-20978	147657	157925	-10268
2.3.1.2 देयताएं	209524	152131	57393	288870	230292	58579
2.3.1.2.1 अनिवासी जमाराशियाँ	175715	149187	26528	242259	190597	51662
2.3.2 अन्य	0	594	-594	2675	0	2675
2.4 रुपया ऋण चुकौती	**0**	**12**	**-12**	**0**	**15**	**-15**
2.5 अन्य पूंजी	**111493**	**102211**	**9282**	**112822**	**118816**	**-5994**
3 भूल-चूक	**7964**	**0**	**7964**	**0**	**6046**	**-6046**
4 मौद्रिक गतिविधियां (4.1+4.2)	**0**	**20819**	**-20819**	**0**	**155919**	**-155919**
4.1 आईएमएफ	0	0	0	0	0	0
4.2 विदेशी मुद्रा भंडार (वृद्धि - / कमी +)	0	20819	-20819	0	155919	-155919

टिप्पणी: प्रा: प्रारंभिक

सं. 40: बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण

(मिलियन यूएस $)

मद	जुला-सितं 2023			जुला-सितं 2024 (अ)		
	जमा	नामे	निवल	जमा	नामे	निवल
	1	2	3	4	5	6
1. चालू खाता (1.अ+1.आ+1.इ)	**231670**	**242934**	**-11264**	**245671**	**256828**	**-11157**
1.अ माल और सेवाएं (1.अ.क.+ 1अ.ख.)	**191606**	**216210**	**-24604**	**197459**	**228229**	**-30769**
1.अ.क. माल (1.अ.क.1 से 1अ.क.3)	**108254**	**172799**	**-64544**	**103967**	**179285**	**-75319**
1.अ.क.1 बीओपी आधार पर सामान्य वाणिज्यिक वस्तुएं	107367	160246	-52879	103981	161701	-57720
1.अ.क.2 वाणिज्यिक के अंतर्गत माल का निवल निर्यात	888	0	888	-14	0	-14
1..अ.क.3 गैर-मौद्रिक स्वर्ण		12553	-12553		17585	-17585
1.अ.ख सेवाएं (1.अ.ख.1 से 1.अ.ख.13)	**83352**	**43411**	**39940**	**93493**	**48943**	**44550**
1.अ.ख.1 अन्य के स्वामित्व वाले भौतिक इनपुट पर विनिर्माण सेवाएं	283	39	244	276	20	256
1.अ.ख.2 अन्यत्र शामिल न की गई रखरखाव व मरम्मत सेवाएं	56	308	-251	90	263	-172
1.अ.ख.3 परिवहन	7054	7277	-223	8792	9188	-396
1.अ.ख.4 यात्रा	7482	8662	-1180	7635	9367	-1732
1.अ.ख.5 निर्माण	954	677	277	1263	951	312
1.अ.ख.6 बीमा और पेंशन सेवाएं	828	821	7	902	786	116
1.अ.ख.7 वित्तीय सेवाएं	2069	1183	887	2190	1265	926
1.अ.ख.8 अन्यत्र शामिल न किए गए बौद्धिक संपत्ति के उपयोग के लिए प्रभार	422	3341	-2919	448	3877	-3428
1.अ.ख.9 दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाएं	40546	4968	35578	44772	5333	39439
1.अ.ख.10 अन्य कारोबारी सेवाएं	21472	13673	7799	25176	15548	9628
1.अ.ख.11 वैयक्तिक, सांस्कृतिक और मनोरंजन संबंधी सेवाएं	1211	2080	-869	1107	1794	-688
1.अ.ख.12 अन्यत्र शामिल न किए गए सरकारी माल और सेवाएं	140	244	-104	147	316	-169
1.अ.ख.13 अन्य जो अन्यत्र शामिल नहीं है	835	140	695	694	237	458
1.आ प्राथमिक आय (1.आ.1 से 1.आ.3)	**11917**	**23526**	**-11608**	**16274**	**25796**	**-9522**
1.आ.1 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	1760	917	843	1995	1023	972
1.आ.2 निवेश आय	8939	22196	-13257	12849	24336	-11486
1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश	2322	12281	-9959	2725	13008	-10283
1.आ.2.2 संविभाग निवेश	84	3657	-3573	78	4152	-4074
1.आ.2.3 अन्य निवेश	520	6040	-5520	1168	6953	-5785
1.आ.2.4 रिज़र्व आस्तियां	6013	217	5796	8878	223	8655
1.आ.3 अन्य प्राथमिक आय	1219	413	806	1430	438	992
1.इ द्वितीयक आय (1.इ.1+1.इ.2)	**28146**	**3198**	**24948**	**31937**	**2803**	**29134**
1.इ.1 वित्तीय निगम, वित्तेतर निगम, परिवार और एनपीआईएसएच	28124	2954	25170	31910	2564	29346
1.इ.1.1 वैयक्तिक अंतरण (निवासी और / अनिवासी परिवारों के बीच चालू अंतरण)	27335	2040	25296	31084	1803	29282
1.इ.1.2 अन्य चालू अंतरण	788	914	-126	826	761	64
1.इ.2 सामान्य सरकार	22	245	-222	27	239	-212
2. पूँजी खाता (2.1+2.2)	**151**	**202**	**-51**	**186**	**192**	**-6**
2.1 अनुत्पादित वित्तेतर आस्तियों का सकल अधिग्रहण (नामे) / निस्तारण (जमा)	9	91	-82	7	68	-61
2.2 पूँजी अंतरण	142	110	31	179	124	55
3. वित्तीय खाता (3.1 से 3.5)	**205657**	**195305**	**10352**	**307700**	**295815**	**11885**
3.1 प्रत्यक्ष निवेश (3.1अ+3.1आ)	**16586**	**17420**	**-834**	**21214**	**23452**	**-2238**
3.1अ भारत में प्रत्यक्ष निवेश	15722	12686	3036	20666	15622	5044
3.1.अ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	14617	12278	2339	19405	15016	4389
3.1.अ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश से इतर इक्विटी	9877	12278	-2401	13847	15016	-1169
3.1.अ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश	4740		4740	5559		5559
3.1.अ.2 ऋण लिखत	1105	409	697	1261	606	655
3.1.अ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक	1105	409	697	1261	606	655
3.1.आ. भारत द्वारा प्रत्यक्ष निवेश	864	4734	-3870	548	7830	-7282
3.1.आ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	864	3130	-2266	548	5827	-5279
3.1.आ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश को छोड़कर इक्विटी	864	1683	-820	548	4313	-3765
3.1.आ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश		1446	-1446		1514	-1514
3.1.आ.2 ऋण लिखत	0	1604	-1604	0	2003	-2003
3.1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक		1604	-1604		2003	-2003
3.2 संविभाग निवेश	**111986**	**107040**	**4947**	**182108**	**162258**	**19850**
3.2अ भारत में संविभाग निवेश	111127	105841	5286	181433	161618	19815
3.2.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	101529	97937	3593	160273	149590	10683
3.2.2 ऋण प्रतिभूतियां	9598	7905	1693	21160	12028	9132
3.2आ. भारत द्वारा संविभाग निवेश	859	1198	-339	675	640	35
3.3 वित्तीय डेरिवेटिव (रिज़र्व निधियों को छोड़कर) और कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन	**5476**	**7362**	**-1887**	**6359**	**11892**	**-5533**
3.4 अन्य निवेश	**71609**	**60964**	**10645**	**98018**	**79598**	**18419**
3.4.1 अन्य इक्विटी (एडीआर/जीडीआर)	0	0	0	0	0	0
3.4.2 मुद्रा और जमाराशियां	21257	18120	3137	29240	22753	6487
3.4.2.1 केंद्रीय बैंक (रुपी कर्ज मूवमेंट; एनआरजी)	0	72	-72	319	0	319
3.4.2.2 केंद्रीय बैंक को छोड़कर जमाराशियां लेनेवाले निगम (अनिवासी भारतीय जमाराशियां)	21257	18048	3209	28921	22753	6167
3.4.2.3 सामान्य सरकार			0			0
3.4.2.4 अन्य क्षेत्र			0			0
3.4.3 ऋण (बाह्य सहायता, ईसीबी और बैंकिंग पूँजी)	22828	23788	-960	44362	40589	3773
3.4.3अ भारत को ऋण	19967	19813	153	39295	32531	6764
3.4.3आ भारत द्वारा ऋण	2862	3975	-1113	5067	8058	-2991
3.4.4 बीमा, पेंशन, और मानकीकृत गारंटी योजनाएं	144	10	134	47	3	44
3.4.5 व्यापार ऋण और अग्रिम	19662	14232	5430	17492	14129	3363
3.4.6 अन्य खाते प्राप्य/देय-अन्य	7718	4814	2903	6877	2124	4753
3.4.7 विशेष आहरण अधिकार	0		0	0		0
3.5 आरक्षित आस्तियां	**0**	**2519**	**-2519**	**0**	**18614**	**-18614**
3.5.1 मौद्रिक स्वर्ण			0			0
3.5.2 विशेष आहरण अधिकार एन.ए		0	0		0	0
3.5.3 आईएमएफ में रिज़र्व निधियों की स्थिति एन.ए			0			0
3.5.4 अन्य रिज़र्व आस्तियां (विदेशी मुद्रा आस्तियां)	0	2519	-2519	0	18614	-18614
4. कुल आस्तियां / देयताएं	**205657**	**195305**	**10352**	**307700**	**295815**	**11885**
4.1 इक्विटी तथा निवेश निधि शेयर	123488	121915	1574	187308	182969	4339
4.2 ऋण लिखत	74451	66057	8394	113515	92108	21407
4.3 अन्य वित्तीय आस्तियां और देयताएं	7718	7333	385	6877	20738	-13861
5. निवल भूल-चूक	**963**	**0**	**963**	**0**	**722**	**-722**

टिप्पणी: प्रा: प्रारंभिक

सं. 41: बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण

(₹ करोड़)

मद	जुला-सितं 2023			जुला-सितं 2024 (अ)		
	जमा	नामे	निवल	जमा	नामे	निवल
	1	2	3	4	5	6
1. चालू खाता (1.अ+1.आ+1.इ)	**1915018**	**2008132**	**-93114**	**2057899**	**2151355**	**-93457**
1.अ माल और सेवाएं (1.अ.क.+ 1अ.ख.)	**1583846**	**1787226**	**-203380**	**1654047**	**1911789**	**-257742**
1.अ.क. माल (1.अ.क.1 से 1अ.क.3)	**894849**	**1428380**	**-533531**	**870890**	**1501809**	**-630919**
1.अ.क.1 बीओपी आधार पर सामान्य वाणिज्यिक वस्तुएं	887510	1324618	-437107	871011	1354507	-483496
1.अ.क.2 वाणिज्यिक के अंतर्गत माल का निवल निर्यात	7339	0	7339	-121	0	-121
1..अ.क.3 गैर-मौद्रिक स्वर्ण	0	103763	-103763	0	147303	-147303
1.अ.ख सेवाएं (1.अ.ख.1 से 1.अ.ख.13)	**688997**	**358846**	**330151**	**783157**	**409979**	**373178**
1.अ.ख.1 अन्य के स्वामित्व वाले भौतिक इनपुट पर विनिर्माण सेवाएं	2339	320	2019	2316	169	2147
1.अ.ख.2 अन्यत्र शामिल न की गई रखरखाव व मरम्मत सेवाएं	465	2544	-2078	755	2199	-1444
1.अ.ख.3 परिवहन	58311	60151	-1840	73649	76965	-3316
1.अ.ख.4 यात्रा	61845	71601	-9756	63958	78464	-14506
1.अ.ख.5 निर्माण	7887	5598	2289	10580	7963	2616
1.अ.ख.6 बीमा और पेंशन सेवाएं	6842	6785	57	7553	6581	972
1.अ.ख.7 वित्तीय सेवाएं	17106	9777	7329	18349	10595	7754
1.अ.ख.8 अन्यत्र शामिल न किए गए बौद्धिक संपत्ति के उपयोग के लिए प्रभार	3485	27618	-24133	3754	32473	-28719
1.अ.ख.9 दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाएं	335161	41064	294097	375037	44672	330366
1.अ.ख.10 अन्य कारोबारी सेवाएं	177488	113019	64469	210894	130244	80650
1.अ.ख.11 वैयक्तिक, सांस्कृतिक और मनोरंजन संबंधी सेवाएं	10012	17193	-7180	9269	15029	-5760
1.अ.ख.12 अन्यत्र शामिल न किए गए सरकारी माल और सेवाएं	1154	2018	-863	1228	2643	-1415
1.अ.ख.13 अन्य जो अन्यत्र शामिल नहीं है	6902	1160	5742	5815	1982	3834
1.आ प्राथमिक आय (1.आ.1 से 1.आ.3)	**98510**	**194468**	**-95957**	**136323**	**216087**	**-79763**
1.आ.1 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	14544	7579	6965	16712	8568	8145
1.आ.2 निवेश आय	73890	183473	-109583	107633	203850	-96217
1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश	19194	101520	-82327	22828	108966	-86138
1.आ.2.2 संविभाग निवेश	692	30227	-29535	653	34776	-34123
1.आ.2.3 अन्य निवेश	4298	49928	-45630	9783	58239	-48455
1.आ.2.4 रिज़र्व आस्तियां	49705	1797	47908	74369	1870	72499
1.आ.3 अन्य प्राथमिक आय	10076	3415	6661	11978	3669	8309
1.इ द्वितीयक आय (1.इ.1+1.इ.2)	**232662**	**26438**	**206224**	**267528**	**23480**	**244048**
1.इ.1 वित्तीय निगम, वित्तेतर निगम, परिवार और एनपीआईएसएच	232476	24416	208060	267298	21478	245821
1.इ.1.1 वैयक्तिक अंतरण (निवासी और / अनिवासी परिवारों के बीच चालू अंतरण)	225958	16860	209099	260383	15102	245281
1.इ.1.2 अन्य चालू अंतरण	6518	7557	-1039	6915	6376	539
1.इ.2 सामान्य सरकार	186	2022	-1836	230	2002	-1772
2. पूँजी खाता (2.1+2.2)	**1245**	**1668**	**-423**	**1558**	**1611**	**-53**
2.1 अनुत्पादित वित्तेतर आस्तियों का सकल अधिग्रहण (नामे) / निस्तारण (जमा)	74	755	-680	57	570	-513
2.2 पूँजी अतंरण	1170	913	257	1501	1041	460
3. वित्तीय खाता (3.1 से 3.5)	**1699992**	**1614420**	**85572**	**2577489**	**2477933**	**99556**
3.1 प्रत्यक्ष निवेश (3.1अ+3.1आ)	**137100**	**143996**	**-6896**	**177706**	**196451**	**-18745**
3.1अ भारत में प्रत्यक्ष निवेश	129962	104866	25096	173115	130862	42253
3.1.अ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	120825	101488	19336	162551	125784	36767
3.1.अ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश से इतर इक्विटी	81644	101488	-19844	115988	125784	-9796
3.1.अ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश	39181	0	39181	46563	0	46563
3.1.अ.2 ऋण लिखत	9137	3378	5759	10564	5078	5486
3.1.अ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक	9137	3378	5759	10564	5078	5486
3.1.आ. भारत द्वारा प्रत्यक्ष निवेश	7138	39130	-31992	4591	65589	-60998
3.1.आ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	7138	25872	-18734	4591	48809	-44218
3.1.आ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश को छोड़कर इक्विटी	7138	13916	-6778	4591	36128	-31537
3.1.आ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश	0	11956	-11956	0	12680	-12680
3.1.आ.2 ऋण लिखत	0	13258	-13258	0	16780	-16780
3.1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक	0	13258	-13258	0	16780	-16780
3.2 संविभाग निवेश	**925695**	**884807**	**40889**	**1525455**	**1359178**	**166277**
3.2अ भारत में संविभाग निवेश	918597	874902	43695	1519799	1353816	165984
3.2.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	839257	809559	29698	1342550	1253064	89486
3.2.2 ऋण प्रतिभूतियां	79340	65343	13997	177250	100752	76498
3.2आ. भारत द्वारा संविभाग निवेश	7099	9905	-2806	5656	5363	293
3.3 वित्तीय डेरिवेटिव (रिज़र्व निधियों को छोड़कर) और कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन	**45263**	**60858**	**-15595**	**53269**	**99618**	**-46349**
3.4 अन्य निवेश	**591934**	**503940**	**87993**	**821059**	**666767**	**154291**
3.4.1 अन्य इक्विटी (एडीआर/जीडीआर)	0	0	0	0	0	0
3.4.2 मुद्रा और जमाराशियां	175715	149782	25933	244933	190597	54337
3.4.2.1 केंद्रीय बैंक (रुपी कर्ज मूवमेंट; एनआरजी)	0	594	-594	2675	0	2675
3.4.2.2 केंद्रीय बैंक को छोड़कर जमाराशियां लेनेवाले निगम (अनिवासी भारतीय जमाराशियां)	175715	149187	26528	242259	190597	51662
3.4.2.3 सामान्य सरकार	0	0	0	0	0	0
3.4.2.4 अन्य क्षेत्र	0	0	0	0	0	0
3.4.3 ऋण (बाह्य सहायता, ईसीबी और बैंकिंग पूँजी)	188702	196637	-7935	371605	339998	31607
3.4.3अ भारत को ऋण	165048	163780	1267	329162	272501	56660
3.4.3आ भारत द्वारा ऋण	23654	32857	-9202	42443	67497	-25054
3.4.4 बीमा, पेंशन, और मानकीकृत गारंटी योजनाएं	1194	85	1109	393	25	368
3.4.5 व्यापार ऋण और अग्रिम	162529	117640	44888	146523	118354	28169
3.4.6 अन्य खाते प्राप्य/देय-अन्य	63794	39797	23998	57605	17794	39811
3.4.7 विशेष आहरण अधिकार	0	0	0	0	0	0
3.5 आरक्षित आस्तियां	**0**	**20819**	**-20819**	**0**	**155919**	**-155919**
3.5.1 मौद्रिक स्वर्ण	0	0	0	0	0	0
3.5.2 विशेष आहरण अधिकार एन.ए	0	0	0	0	0	0
3.5.3 आईएमएफ में रिज़र्व निधियों की स्थिति एन.ए	0	0	0	0	0	0
3.5.4 अन्य रिज़र्व आस्तियां (विदेशी मुद्रा आस्तियां)	0	20819	-20819	0	155919	-155919
4. कुल आस्तियां / देयताएं	**1699992**	**1614420**	**85572**	**2577489**	**2477933**	**99556**
4.1 इक्विटी तथा निवेश निधि शेयर	1020775	1007766	13008	1569010	1532662	36348
4.2 ऋण लिखत	615423	546038	69385	950874	771559	179316
4.3 अन्य वित्तीय आस्तियां और देयताएं	63794	60616	3179	57605	173712	-116108
5. निवल भूल-चूक	**7964**	**0**	**7964**	**0**	**6046**	**-6046**

टिप्पणी: प्रा: प्रारंभिक

सं. 42: अंतरराष्ट्रीय निवेश की स्थिति

(मिलियन अमेरिकी डॉलर)

मद	वित्तीय वर्ष / समाप्त तिमाही की स्थिति							
	2023-24		2023		2024			
			सितं.		जून		सितं.	
	आस्तियां	देयताएं	आस्तियां	देयताएं	आस्तियां	देयताएं	आस्तियां	देयताएं
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. विदेश/भारत में प्रत्यक्ष निवेश	242271	542931	232097	528679	246248	552865	253530	555484
1.1 इक्विटी पूंजी*	153343	511142	146159	497612	156225	520706	161504	523010
1.2 अन्य पूंजी	88927	31789	85938	31067	90023	32160	92026	32474
2. संविभाग निवेश	12162	277038	12096	259358	12103	277140	12306	293649
2.1 इक्विटी	10644	162061	8974	154634	10367	160898	10983	170934
2.2 ऋण	1517	114977	3122	104723	1736	116242	1323	122715
3. अन्य निवेश	132654	575068	120311	546182	140952	589624	146190	617176
3.1 व्यापार ऋण	33450	123662	30854	124733	32865	126576	32428	129931
3.2 ऋण	17547	221738	11962	208669	20803	224823	22147	240166
3.3 मुद्रा और जमाराशियां	53519	154787	45711	146166	57747	160628	56105	164076
3.4 अन्य आस्तियां/देयताएं	28138	74880	31784	66615	29537	77597	35510	83002
4. आरक्षित निधियाँ	646419		587714		651997		705782	
5. कुल आस्तियां/देयताएं	1033505	1395036	952218	1334219	1051300	1419629	1117808	1466309
6. निवल आईआईपी (आस्तियां - देयताएं)	-361531		-382001		-368329		-348501	

टिप्पणी: * इक्विटी पूंजी में निवेश निधि और पुनर्निवेशित अर्जन का शेयर शामिल है।

भुगतान और निपटान प्रणाली

सं. 43: भुगतान प्रणाली संकेतक

भाग I - भुगतान प्रणाली संकेतक – भुगतान तथा निपटान प्रणाली सांख्यिकी

प्रणाली	मात्रा (लाख)				मूल्य (₹ करोड़)			
	वि.व. 2023-24	2023	2024		वि.व. 2023-24	2023	2024	
		दिसं.	नवं.	दिसं.		दिसं.	नवं.	दिसं.
	1	-2	-1	0	5	2	3	4
ए. निपटान प्रणाली								
वित्तीय बाजार अवसंरचना (एफएमआई)								
1 सीसीआईएल प्रचालित प्रणाली (1.1 से 1.3)	43.04	3.41	2.61	3.78	259206893	22228644	20592498	27448820
1.1 सरकारी प्रतिभूति समाशोधन (1.10.1 से 1.1.3)	16.80	1.29	1.10	1.49	170464587	14220985	13954925	16506680
1.1.1 आउटराइट	9.51	0.69	0.54	0.84	13463848	1009116	847485	1348782
1.1.2 रेपो	4.94	0.40	0.35	0.41	76718788	5903343	5366007	6377679
1.1.3 त्रि-पक्षीय रेपो	2.35	0.20	0.20	0.24	80281951	7308526	7741434	8780219
1.2 विदेशी मुद्रा समाशोधन	24.92	2.01	1.40	2.16	80984671	7392675	5972544	9919285
1.3 रुपये के डेरिवेटिव @	1.31	0.11	0.11	0.13	7757636	614984	665029	1022855
बी. भुगतान प्रणाली								
I वित्तीय बाजार अवसंरचना (एफएमआई)	-	-	-	-	-	-	-	-
1 ऋण अंतरण - आरटीजीएस (1.1 से 1.2)	2700.16	230.39	240.29	262.29	170886670	15888778	14826882	19163587
1.1 ग्राहक लेनदेन	2686.04	229.23	239.16	261.11	152406168	14244586	13504833	17161423
1.2 अंतर्बैंक लेनदेन	14.12	1.16	1.12	1.17	18480503	1644192	1322050	2002163
II खुदरा								
2 ऋण अंतरण - खुदरा (2.1 से 2.6)	1486106.89	134755.92	170358.50	183786.41	67542859	5917191	6274182	6935632
2.1 एईपीएस (निधि अंतरण) @	3.92	0.32	0.30	0.31	261	23	14	17
2.2 एपीबीएस $	25888.17	1580.49	2250.97	2451.41	390743	27013	32384	58705
2.3 आईएमपीएस	60053.35	4987.93	4079.18	4411.64	6495652	570126	558328	601549
2.4 एनएसीएच जमा $	16227.27	1310.99	1438.33	1315.94	1525104	128244	147385	135695
2.5 एनईएफटी	72639.50	6673.93	7769.51	8307.02	39136014	3368836	3380884	3814966
2.6 यूपीआई @	1311294.68	120202.26	154820.21	167300.09	19995086	1822949	2155187	2324700
2.6.1 जिसमें से यूएसएसडी@	26.19	2.06	1.56	1.56	352	26	16	16
3 डेबिट ट्रांसफर और डायरेक्ट डेबिट (3.1 से 3.3)	18249.53	1557.74	1894.74	1905.47	1687658	152705	185643	198303
3.1 भीम आधार पे @	193.59	14.09	19.29	17.18	6112	478	629	547
3.2 एनएसीएच नामे $	16426.49	1403.46	1732.94	1738.32	1678769	151991	184814	197549
3.3 एनईटीसी (बैंक खाते से जुड़ा) @	1629.45	140.19	142.51	149.97	2777	237	200	207
4 कार्ड भुगतान (4.1 से 4.2)	58469.79	4983.15	5171.02	5614.06	2423563	213054	208387	228757
4.1 क्रेडिट कार्ड (4.1.1 से 4.1.2)	35610.15	3215.00	3936.04	4331.22	1831134	165119	169298	188086
4.1.1 पीओएस आधारित $	18614.08	1706.70	2036.02	2242.76	651911	58300	68233	73185
4.1.2 अन्य $	16996.08	1508.29	1900.02	2088.46	1179223	106819	101065	114901
4.2 डेबिट कार्ड (4.2.1 से 4.2.1)	22859.64	1768.16	1234.98	1282.84	592429	47935	39089	40671
4.2.1 पीओएस आधारित $	16477.95	1301.59	919.33	967.24	393589	32225	26756	27681
4.2.2 अन्य $	6381.69	466.56	315.65	315.60	198840	15709	12333	12990
5 प्रीपेड भुगतान लिखत (5.1 से 5.2)	78775.40	7235.20	5847.81	6377.99	283048	26173	19214	18992
5.1 वालेट	63256.69	5960.57	4462.09	4830.75	234353	21732	13130	14437
5.2 कार्ड (5.2.1 से 5.2.2)	15518.71	1274.63	1385.72	1547.24	48695	4441	6083	4556
5.2.1 पीओएस आधारित $	8429.87	709.65	663.27	684.93	11247	915	915	991
5.2.2 अन्य $	7088.84	564.98	722.45	862.31	37447	3526	5168	3565
6 पेपर-आधारित लिखत (6.1 से 6.2)	6632.10	547.23	472.48	506.56	7212333	592972	537849	587879
6.1 सीटीएस (एनपीसीआई प्रबंधित)	6632.10	547.23	472.48	506.56	7212333	592972	537849	587879
6.2 अन्य	0.00	–	–	–	–	–	–	–
कुल - खुदरा भुगतान (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	1648233.71	149079.24	183744.55	198190.49	79149461	6902095	7225275	7969563
कुल भुगतान (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	1650933.88	149309.63	183984.84	198452.78	250036131	22790873	22052158	27133149
कुल डिजिटल भुगतान (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	1644301.78	148762.40	183512.36	197946.22	242823799	22197901	21514309	26545270

भाग II - भुगतान के प्रकार तथा चैनल

प्रणाली	मात्रा (लाख)				मूल्य (₹ करोड़)			
	वि.व. 2023-24	2023	2024		वि.व. 2023-24	2023	2024	
		दिसं.	नवं.	दिसं.		दिसं.	नवं.	दिसं.
	1	2	3	4	5	6	7	8
ए. अन्य भुगतान चैनल								
1 मोबाइल भुगतान (मोबाइल ऐप आधारित) (1.1 से 1.2)	1252599.21	116329.75	144940.05	156761.97	30687088	2804467	3215460	3455692
1.1 अंतर्बैंक $	83000.56	7372.04	8518.57	9183.18	5676805	508669	598558	618348
1.2 अंतर-बैंक $	1169598.65	108957.71	136421.48	147578.78	25010283	2295798	2616902	2837344
2 इंटरनेट भुगतान (नेटबैंकिंग / इंटरनेट ब्राउज़र आधारित) @ (2.1 से 2.2)	45034.98	3836.26	3624.01	4036.42	102117736	9388620	9002230	11058871
2.1 अंतर्बैंक @	12033.28	1050.96	1024.09	1153.98	53247042	4862570	4483631	5617543
2.2 अंतर-बैंक @	33001.71	2785.31	2599.92	2882.45	48870694	4526051	4518598	5441328
बी. एटीएम								
3 एटीएम से नकद निकासी $ (3.1 से 3.3)	66440.72	5463.60	4760.71	4950.77	3259388	269288	241717	252471
3.1 क्रेडिट कार्ड का उपयोग करना $	95.80	8.19	7.75	8.12	4648	405	410	429
3.2 डेबिट कार्ड का उपयोग करना $	66001.01	5428.47	4734.61	4923.54	3241538	267843	240471	251161
3.3 प्री-पेड कार्ड का उपयोग करना $	343.90	26.94	18.35	19.11	13202	1041	837	881
4 पीओएस पर नकद निकासी $ (4.1 से 4.2)	15.18	0.66	0.28	0.29	148	6	3	3
4.1 डेबिट कार्ड का उपयोग करना $	15.06	0.66	0.27	0.26	147	6	3	3
4.2 प्री-पेड कार्ड का उपयोग करना $	0.12	0.00	0.02	0.03	1	0	0	0
5 माइक्रो एटीएम में नकद निकासी @	11754.95	929.51	898.33	910.87	314003	24592	22981	23195
5.1 एईपीएस @	11754.95	929.51	898.33	910.87	314003	24592	22981	23195

भाग III - भुगतान अवसंरचना (लाख)

प्रणाली	मार्च 2024 तक	2023	2024	
		दिसं.	नवं.	दिसं.
	1	2	3	4
भुगतान प्रणाली अवसंरचना				
1 कार्ड की संख्या (1.1 से 1.2)	10667.22	10587.85	10868.11	10990.04
1.1 क्रेडिट कार्ड	1018.03	979.05	1072.40	1080.56
1.2 डेबिट कार्ड	9649.19	9608.81	9795.72	9909.48
2 पीपीआई की संख्या @ (2.1 से 2.2)	16743.63	17544.34	15624.08	13285.65
2.1 वालेट @	13381.80	14293.01	11460.53	8904.25
2.2 कार्ड @	3361.82	3251.33	4163.55	4381.40
3 एटीएम की संख्या (3.1 से 3.2)	2.58	2.58	2.55	2.55
3.1 बैंक के स्वामित्व वाले एटीएम $	2.23	2.24	2.20	2.19
3.2 व्हाइट लेबल एटीएम $	0.35	0.34	0.35	0.36
4 माइक्रो एटीएम की संख्या @	17.55	16.89	14.43	14.67
5 पीओएस टर्मिनलों की संख्या	89.03	85.67	96.91	100.01
6 भारत क्यूआर @	62.50	59.57	63.60	63.83
7 यूपीआई क्यूआर *	3434.93	3170.66	6260.92	6334.39

@: नवंबर 2019 से नया समावेश
#: सहकारी बैंकों, एलएबी और आरआरबी द्वारा रिपोर्ट किया गया डेटा शामिल किया गया जो दिसंबर 2021 से प्रभावी है।
$: नवंबर 2019 से अलग से शुरू किया गया समावेश - अभी तक अन्य मदों का हिस्सा रहा होगा।
* सितंबर 2020 से नया समावेश; केवल स्थिर यूपीआई क्यूआर कोड शामिल है।
टिप्पणियां: 1. डेटा अनंतिम है।
2. 31 जनवरी 2020 से ईसीएस (डेबिट और क्रेडिट) एनएसीएच के साथ मिला दिया गया है।
3. कार्ड पेमेंट्स (डेबिट / क्रेडिट कार्ड्स) और प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट (पीपीआई) के लिए नवबंर 2019 के डेटा की पहले के महीनों / अवधि के साथ तलुना नहीं हो सकती है, क्योंकि डेटा की परिभाषाओं में संशोधनं के साथ अधिक ग्रेन्युलर डेटा प्रकाशित किया जा रहा है।
4. केवल घरेलू वित्तीय लेनदेन पर विचार किया गया है। नए प्रारूप में ई-कॉमर्स लेनदेन; फास्ट टैग लेनदेन; डिजिटल बिल भुगतान और एटीएम आदि के माध्यम से कार्ड-टू-कार्ड ट्रांसफर आदि शामिल हैं। इसके अलावा, असफल लेनदेन, चार्जबैक, रिवर्सल, एक्सपायर्ड कार्ड / वॉलेट को शामिल नहीं किया गया है।
भाग I-ए. निपटान प्रणाली
1.1.3: प्रतिभूति खंड के तहत त्रि-पक्षीय रेपो 05 नवंबर 2018 से चालू हो गया है।
भाग I-बी. भुगतान प्रणाली
4.1.2: 'अन्य' में ई-कॉमर्स लेनदेन और एटीएम के माध्यम से डिजिटल बिल भुगतान आदि शामिल हैं।
4.2.2: 'अन्य' में ई-कॉमर्स लेनदेन, कार्ड से कार्ड ट्रांसफर और एटीएम के माध्यम से डिजिटल बिल भुगतान आदि शामिल हैं।
5: दिसंबर 2010 से उपलब्ध।
5.1: वस्तुओं और सेवाओं की खरीद और वॉलेट के माध्यम से फंड ट्रांसफर शामिल है।
5.2.2: ऑनलाइन लेनदेन और अन्य लेनदेन के लिए पीपीआई कार्ड का उपयोग शामिल है।
6.1: तीन ग्रिडों से संबंधित - मुंबई, नई दिल्ली और चेन्नई।
6.2: 'अन्य' में गैर-एमआईसीआर लेनदेन शामिल हैं जो 21 बैंकों द्वारा प्रबंधित समाशोधन गृहों से संबंधित हैं।
भाग II-ए. अन्य भुगतान चैनल
1: मोबाइल भुगतान -
बैंकों के मोबाइल ऐप्स और यूपीआई ऐप्स के माध्यम से किए गए लेनदेन शामिल।
जुलाई 2017 के डेटा में केवल व्यक्तिगत भुगतान और मोबाइल डिवाइस का उपयोग करके शुरू किए गए, संसाधित और अधिकृत कॉर्पोरेट भुगतान शामिल हैं। अन्य कॉर्पोरेट भुगतान जो मोबाइल डिवाइस का उपयोग करके शुरू, संसाधित और अधिकृत नहीं किए गए हैं, उन्हें बाहर रखा गया है।
2: इंटरनेट भुगतान - इसमें 'नेटबैंकिंग' के माध्यम से केवल ई-कॉमर्स लेनदेन और बैंक की इंटरनेट बैंकिंग वेबसाइट का उपयोग करके वित्तीय लेनदेन शामिल हैं।
भाग II-बी. एटीएम
3.3 और 4.2: केवल बैंक द्वारा जारी पीपीआई का उपयोग करके लेनदेन से संबंधित है।
भाग III. भुगतान प्रणाली अवसंरचना
3: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) और व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटरों (डब्ल्यूएलएओ) द्वारा तैनात एटीएम शामिल हैं। डब्ल्यूएलए को अप्रैल 2014 से शामिल किया गया है।

आवसरिक श्रृंखला

सं. 44 लघु बचत

(₹ करोड़)

प्रणाली		2023-24	2023	2024		
			दिसं.	अक्तू.	नवं.	दिसं.
		1	2	3	4	5
1. लघु बचत	**प्राप्तियां**	**232460**	**16670**	**10981**	**9805**	**11133**
	बकाया	**1865029**	**1789946**	**1962367**	**1971752**	**1982465**
1.1 कुल जमाराशियां	**प्राप्तियां**	**161344**	**12386**	**8792**	**7469**	**8734**
	बकाया	**1298795**	**1247555**	**1379283**	**1386750**	**1395484**
1.1.1 डाक घर बचत बैंक जमाराशियां	प्राप्तियां	17229	2279	1062	20	1090
	बकाया	191692	213964	200889	200909	201999
1.1.2 सुकन्या समृद्धि योजना	प्राप्तियां	35174	2171	1787	1944	2244
	बकाया	157611	104859	172819	174763	177007
1.1.3 राष्ट्रीय बचत योजना, 1987	प्राप्तियां	0	0	0	0	0
	बकाया	0	0	0	0	0
1.1.4 राष्ट्रीय बचत योजना, 1992	प्राप्तियां	0	0	0	0	0
	बकाया	0	0	0	0	0
1.1.5 मासिक आय योजना	प्राप्तियां	26696	1713	1033	900	827
	बकाया	269007	263383	280416	281316	282142
1.1.6 वरिष्ठ नागरिक योजना, 2004	प्राप्तियां	38167	2197	1699	1609	1531
	बकाया	175472	169033	191465	193074	194605
1.1.7 डाक घर मीयादी जमाराशियां	प्राप्तियां	25341	2429	2121	2109	2125
	बकाया	305776	297989	326679	328786	330912
1.1.7.1 1 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	140423	135196	155580	157349	159174
1.1.7.2 2 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	11967	11265	13910	14093	14299
1.1.7.3 3 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	8932	8472	10033	10166	10308
1.1.7.4 5 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	144454	143056	147156	147178	147131
1.1.8 डाक घर आवर्ती जमाराशियां	प्राप्तियां	18713	1616	1238	1023	1025
	बकाया	197134	196491	205221	206244	207269
1.1.9 डाक घर संचयी मीयादी जमाराशियां	प्राप्तियां	0	0	0	0	0
	बकाया	0	0	0	0	0
1.1.10 अन्य जमाराशियां	प्राप्तियां	8	-19	-149	-137	-108
	बकाया	1754	1488	1440	1303	1195
1.1.11 पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन	प्राप्तियां	16	0	1	1	0
	बकाया	349	348	354	355	355
1.2 बचत प्रमाणपत्र	**प्राप्तियां**	**56069**	**3957**	**2080**	**2184**	**2226**
	बकाया	**418021**	**407244**	**434502**	**436268**	**438074**
1.2.1 राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र VIII निर्गम	प्राप्तियां	16853	1213	637	524	430
	बकाया	183905	177154	191667	192191	192621
1.2.2 इंदिरा विकास पत्र	प्राप्तियां	0	0	0	0	0
	बकाया	0	0	0	0	0
1.2.3 किसान विकास पत्र	प्राप्तियां	0	0	0	0	0
	बकाया	0	0	0	0	0
1.2.4 किसान विकास पत्र-2014	प्राप्तियां	20939	1568	783	932	1113
	बकाया	220560	216509	226662	227594	228707
1.2.5 राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र VI निर्गम	प्राप्तियां	0	0	0	0	0
	बकाया	0	0	0	0	0
1.2.6 राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र VII निर्गम	प्राप्तियां	0	0	0	0	0
	बकाया	0	0	0	0	0
1.2.7 एम.एस. प्रमाणपत्र	प्राप्तियां	18277	1176	660	728	683
	बकाया	18277	15064	23891	24620	25303
1.2.8 अन्य प्रमाणपत्र	बकाया	-4721	-1483	-7718	-8137	-8557
1.3 लोक भविष्य निधि	**प्राप्तियां**	**15047**	**327**	**109**	**152**	**173**
	बकाया	**148213**	**135147**	**148582**	**148734**	**148907**

टिप्पणी : अप्रैल 2017 से प्राप्तियों का डाटा निवल प्राप्तियाँ हैं, अर्थात सकल प्राप्तियों से सकल भुगतान को घटाने पर प्राप्त।

स्रोत : महालेखाकार, पोस्ट और टेलीग्राफ।

सं. 45 केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों के स्वामित्व का स्वरूप

(प्रतिशत)

केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां					
श्रेणी	2023		2024		
	सितं	दिसं	मार्च	जून	सितं
	1	2	3	4	5
(क) कुल (₹ करोड़ में)	**10383607**	**10538792**	**10740389**	**10946860**	**11271589**
1. वाणिज्यिक बैंक	37.96	37.55	37.66	37.52	37.55
2. सहकारी बैंक	1.52	1.49	1.47	1.42	1.35
3. गैर-बैंक प्राथमिक व्यापारी	0.66	0.67	0.66	0.70	0.77
4. बीमाकृत कंपनियां	26.05	26.16	25.98	26.11	25.95
5. म्यूच्युअल फंड	3.02	3.03	2.90	2.87	3.14
6. भविष्य निधियां	4.42	4.57	4.47	4.41	4.25
7. पेंशन निधि	4.32	4.44	4.52	4.74	4.86
8. वित्तीय संस्थाएं	0.54	0.55	0.55	0.57	0.63
9. कॉरपोरेट	1.21	1.33	1.35	1.44	1.60
10. विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक	1.61	1.92	2.34	2.34	2.80
11. भारतीय रिज़र्व बैंक	13.06	12.54	12.31	11.92	11.16
12. अन्य	5.64	5.74	5.79	5.97	5.92
12.1 राज्य सरकार	2.04	2.07	2.04	2.13	2.19

राज्य सरकारों की प्रतिभूतियां					
श्रेणी	2023		2024		
	सितं	दिसं	मार्च	जून	सितं
	1	2	3	4	5
(ख) कुल (₹ करोड़ में)	**5161642**	**5338587**	**5646219**	**5727482**	**5909490**
1. वाणिज्यिक बैंक	33.87	33.90	34.14	33.85	34.39
2. सहकारी बैंक	3.60	3.53	3.39	3.38	3.29
3. गैर-बैंक प्राथमिक व्यापारी	0.61	0.63	0.60	0.59	0.60
4. बीमाकृत कंपनियां	26.97	26.64	26.14	25.85	25.56
5. म्यूच्युअल फंड	1.86	2.00	2.09	2.08	1.93
6. भविष्य निधियां	21.70	22.00	22.35	22.94	23.02
7. पेंशन निधि	4.82	4.56	4.76	4.87	4.87
8. वित्तीय संस्थाएं	1.65	1.63	1.59	1.58	1.57
9. कॉरपोरेट	1.87	2.03	2.02	2.03	1.95
10. विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक	0.02	0.03	0.07	0.05	0.04
11. भारतीय रिज़र्व बैंक	0.69	0.66	0.63	0.62	0.60
12. अन्य	2.34	2.37	2.20	2.17	2.18
12.1 राज्य सरकार	0.27	0.27	0.25	0.26	0.26

खज़ाना बिल					
श्रेणी	2023		2024		
	सितं	दिसं	मार्च	जून	सितं
	1	2	3	4	5
(ग) कुल (₹ करोड़ में)	**925317**	**849151**	**871662**	**858193**	**747242**
1. वाणिज्यिक बैंक	56.35	57.18	58.53	47.79	44.74
2. सहकारी बैंक	1.20	1.28	1.67	1.49	1.58
3. गैर-बैंक प्राथमिक व्यापारी	0.54	1.70	1.66	2.69	2.28
4. बीमाकृत कंपनियां	5.26	5.50	5.06	5.78	5.26
5. म्यूच्युअल फंड	12.74	11.21	11.89	14.50	15.06
6. भविष्य निधियां	1.52	0.08	0.15	0.60	0.26
7. पेंशन निधि	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00
8. वित्तीय संस्थाएं	4.10	5.34	7.16	6.56	6.36
9. कॉरपोरेट	4.00	4.58	4.50	4.79	4.66
10. विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक	0.10	0.07	0.01	0.20	0.15
11. भारतीय रिज़र्व बैंक	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12. अन्य	14.17	13.06	9.36	15.59	19.65
12.1 राज्य सरकार	11.36	9.26	5.88	11.55	14.95

नोट: (-) शून्य या नगण्य को दर्शाता है

बुलेटिन के जून 2023 के संस्करण से टेबल फार्मेट संशोधित किया है।

केन्द्र सरकार दिनांकित प्रतिभूतियों में विशिष्ट प्रतिभूतियाँ और सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड शामिल हैं।

राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (यूडीएवाई) के अंतर्गत जारी विशेष बॉण्ड शामिल हैं।

वाणिज्यिक बैंकों के अंतर्गत बैंक के प्राथमिक डीलरों को शामिल किया गया है। तथापि, कुल बकाया प्रतिभूतियों में इनका हिस्सा बहुत कम है।

अन्य' श्रेणी में राज्य सरकारें, डीआईसीजीसी, पीएसयू, ट्रस्ट, केंद्रीय विदेशी बैंक, हिंदू अविभक्त परिवार/व्यक्ति आदि शामिल हैं।

सितंबर 2023 के बाद के आंकड़ों में एक बैंक का एक गैर-बैंक के साथ विलय का प्रभाव शामिल है।

सं. 46: केन्द्र और राज्य सरकारों की संयुक्त प्राप्तियां और संवितरण

(₹ करोड़)

मद	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (सं.अ.)	2024-25 (ब.अ.)
	1	2	3	4	5	6
1. कुल वितरण	**5410887**	**6353359**	**7098451**	**7880522**	**9110725**	**9800798**
1.1 विकास संबंधी	3074492	3823423	4189146	4701611	5514584	5862996
1.1.1 राजस्व	2446605	3150221	3255207	3574503	3965270	4195108
1.1.2 पूंजी	588233	550358	861777	1042159	1453849	1526993
1.1.3 ऋण	39654	122844	72163	84949	95464	140895
1.2 गैर-विकास संबंधी	2253027	2442941	2810388	3069896	3467270	3800321
1.2.1 राजस्व	2109629	2271637	2602750	2895864	3266628	3537378
1.2.1.1 ब्याज भुगतान	955801	1060602	1226672	1377807	1562660	1711972
1.2.2 पूंजी	141457	169155	175519	171131	196073	259346
1.2.3 ऋण	1941	2148	32119	2902	4569	3597
1.3 अन्य	83368	86995	98916	109015	128871	137481
2. कुल प्राप्तियां	**5734166**	**6397162**	**7156342**	**7855370**	**9054999**	**9650488**
2.1 राजस्व प्राप्तियां	3851563	3688030	4823821	5447913	6379349	7209647
2.1.1 कर प्राप्तियां	3231582	3193390	4160414	4809044	5456913	6142276
2.1.1.1 पण्य और सेवाओं पर कर	2012578	2076013	2626553	2865550	3248450	3631569
2.1.1.2 आय और संपत्ति पर कर	1216203	1114805	1530636	1939550	2204462	2506181
2.1.1.3 संघशासित क्षेत्र (बिना विधान मंडल के) के कर	2800	2572	3225	3943	4001	4526
2.1.2 गैर-कर प्राप्तियां	619981	494640	663407	638870	922436	1067371
2.1.2.1 ब्याज प्राप्तियां	31137	33448	35250	42975	49552	57273
2.2 गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियां	110094	64994	44077	62716	86733	118239
2.2.1 ऋण और अग्रिम की वसूली	59515	16951	27665	15970	55895	45125
2.2.2 विनिवेश से प्राप्त राशि	50578	48044	16412	46746	30839	73114
3. सकल वित्तीय घाटा [1-(2.1+2.2)]	**1449230**	**2600335**	**2230553**	**2369892**	**2644642**	**2472912**
3 क वित्तपोषण के स्रोत : संस्था-वार						
3क.1 घरेलू वित्तपोषण	1440548	2530155	2194406	2332768	2619811	2456959
3क.1.1 सरकार को निवल बैंक ऋण	571872	890012	627255	687904	346483	…
3क.1.1.1 सरकार को निवल भा.रि. बैंक का ऋण	190241	107493	350911	529	-257913	…
3क.1.2 सरकार को गैर-बैंक ऋण	868676	1640143	1567151	1644864	2273328	…
3क.2 बाह्य वित्तपोषण	8682	70180	36147	37124	24832	15952
3ख. वित्तपोषण के स्रोत : लिखत-वार						
3ख.1 घरेलू वित्तपोषण	1440548	2530155	2194406	2332768	2619811	2456959
3ख.1.1 बाज़ार उधार (निवल)	971378	1696012	1213169	1651076	1962969	1983757
3ख.1.2 लघु बचत (निवल)	209232	458801	526693	358764	434151	447511
3ख.1.3 राज्य भविष्य निधियां (निवल)	38280	41273	28100	13880	21386	19857
3ख.1.4 आरक्षित निधियां	10411	4545	42153	68803	52385	-33653
3ख.1.5 जमाराशियां और अग्रिम	-14227	25682	42203	51989	35819	-10138
3ख.1.6 नकद शेष	-323279	-43802	-57891	25152	55726	150310
3ख.1.7 अन्य	548753	347643	399980	163104	57374	-100684
3ख.2 बाह्य वित्तपोषण	8682	70180	36147	37124	24832	15952
4. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कुल वितरण	*26.9*	*32.0*	*30.1*	*29.2*	*30.8*	*30.0*
5. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कुल प्राप्तियां	*28.5*	*32.2*	*30.3*	*29.1*	*30.7*	*29.6*
6. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजस्व प्राप्तियां	*19.2*	*18.6*	*20.4*	*20.2*	*21.6*	*22.1*
7. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कर प्राप्तियां	*16.1*	*16.1*	*17.6*	*17.8*	*18.5*	*18.8*
8. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सकल वित्तीय घाटा	*7.2*	*13.1*	*9.5*	*8.8*	*9.0*	*7.6*

… : उपलब्ध नहीं। सं.अ. संशोधित अनुमान, ब.अ. बजट अनुमान।

स्रोत : केन्द्रीय और राज्य सरकारों का बजट दस्तावेज।

टिप्पणी : जीडीपी डेटा 2011-12 के आधार पर है। 2024-25 के लिए जीडीपी केंद्रीय बजट 2024-25 से है।

डेटा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है।

1 और 2: डेटा केंद्र सरकार (एनएसएसएफ को पुनर्भुगतान सहित) और राज्य सरकारों के निवल पुनर्भुगतान का है।

1.3: राज्यों द्वारा स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर और समनुदेशन का प्रतिनिधित्व करता है।

2: डेटा केंद्र और राज्य सरकारों के नकदी शेष में निवल भिन्नता को दर्शाता है और इसमें केंद्र और राज्य सरकारों की उधार प्राप्तियां शामिल हैं।

3ए.1.1: आरबीआई रिकॉर्ड के अनुसार डेटा।

3बी.1.1: दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से उधार।

3बी.1.2: राष्ट्रीय अल्प बचत निधि (एनएसएसएफ) द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों की विशेष प्रतिभूतियों में निवल निवेश को दर्शाता है।

नए डेटा की उपलब्धता के साथ घटकों में समायोजन के कारण यह डेटा पिछले प्रकाशनों से भिन्न हो सकता है।

3बी.1.6: केंद्र द्वारा राज्य सरकारों को अर्थोपाय अग्रिम शामिल हैं।

3बी.1.7: ट्रेजरी बिल, वित्तीय संस्थाओं से ऋण, बीमा और पेंशन निधि, विप्रेषण, नकद शेष निवेश खाता शामिल हैं।

सं.47: विभिन्न सुविधाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा ली गई वित्तीय सहायता

(₹ करोड़)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	दिसंबर 2024 के दौरान					
		विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ)		अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए)		ओवरड्राफ्ट (ओडी)	
		प्राप्त औसत राशि	सुविधा प्राप्त करने के दिनों की संख्या	प्राप्त औसत राशि	सुविधा प्राप्त करने के दिनों की संख्या	प्राप्त औसत राशि	सुविधा प्राप्त करने के दिनों की संख्या
	1	2	3	4	5	6	7
1	आंध्र प्रदेश	6228.59	31	1990.27	24	1387.58	12
2	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-
3	असम	198.83	1	-	-	-	-
4	बिहार	-	-	-	-	-	-
5	छत्तीसगढ़	-	-	-	-	-	-
6	गोवा	-	-	-	-	-	-
7	गुजरात	-	-	-	-	-	-
8	हरियाणा	671.48	23	-	-	-	-
9	हिमाचल प्रदेश	-	-	569.66	18	369.45	7
10	जम्मू और कश्मीर संघ शासित प्रदेश	-	-	334.57	1	-	-
11	झारखंड	-	-	-	-	-	-
12	कर्नाटक	-	-	-	-	-	-
13	केरल	1553.11	31	1481.92	30	402.31	9
14	मध्य प्रदेश	-	-	-	-	-	-
15	महाराष्ट्र	-	-	-	-	-	-
16	मणिपुर	104.86	30	237.83	30	83.26	10
17	मेघालय	472.99	29	6.09	2	-	-
18	मिज़ोरम	185.00	5	50.26	2	-	-
19	नगालैंड	315.96	28	-	-	-	-
20	उड़ीसा	-	-	-	-	-	-
21	पुदुचेरी	-	-	-	-	-	-
22	पंजाब	3680.79	31	142.76	6	-	-
23	राजस्थान	2669.90	16	1353.46	8	-	-
24	तमिलनाडु	-	-	-	-	-	-
25	तेलंगाना	4560.57	31	1776.29	24	591.71	15
26	त्रिपुरा	-	-	-	-	-	-
27	उत्तर प्रदेश	-	-	-	-	-	-
28	उत्तराखंड	1323.91	31	559.52	1	-	-
29	पश्चिम बंगाल	-	-	-	-	-	-

टिप्पणीयां : 1) राज्य सरकारों द्वारा समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ), गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ) और नीलामी खज़ाना बिल (एटीबी) के शेष तथा सरकारी प्रतिभूतियों में किए गए अन्य निवेशों को संपाश्विक के तौर पर रखते हुए विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ) प्राप्त की जाती है।

2) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा राज्य सरकारों को उनके अल्प कालिक नकदी असंतुलन से निपटने के लिए अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) दिया जाता है।

3) राज्य सरकारों को उनकी अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) सीमा से अधिक की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अग्रिम के तौर पर ओवरड्राफ्ट दिया जाता है।

4) प्राप्त कुल सहायता (एसडीएफ/डब्ल्यूएमए/ओडी) को उन दिनों की संख्या से भाग देने पर, जिनके लिए माह के दौरान सहायता प्राप्त हुई, औसत राशि प्राप्त होती है।

5) -: नगण्य

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक

सं. 48: राज्य सरकारों द्वारा किए गये निवेश

(₹ करोड़)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	दिसंबर 2024 के अंत तक			
		समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ)	गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ)	सरकारी प्रतिभूतियाँ	नीलामी खज़ाना बिल (एटीबी)
	1	2	3	4	5
1	आंध्र प्रदेश	11485	1132	0	0
2	अरुणाचल प्रदेश	2735	7	0	6300
3	असम	8865	90	0	0
4	बिहार	12394	-	0	20000
5	छत्तीसगढ़	7754	488	0	11387
6	गोवा	1043	454	0	0
7	गुजरात	15244	662	0	2000
8	हरियाणा	2315	1688	0	0
9	हिमाचल प्रदेश	-	-	0	0
10	जम्मू और कश्मीर संघ शासित प्रदेश	19	18	0	0
11	झारखंड	2396	-	0	830
12	कर्नाटक	20131	747	0	69457
13	केरल	3098	-	0	0
14	मध्य प्रदेश	-	1268	0	0
15	महाराष्ट्र	71372	1734	0	0
16	मणिपुर	69	139	0	0
17	मेघालय	1267	108	0	0
18	मिज़ोरम	456	63	0	0
19	नगालैंड	1877	46	0	0
20	उड़ीसा	18082	2029	116	5534
21	पुदुचेरी	575	-	0	1750
22	पंजाब	9114	0	0	0
23	राजस्थान	1774	-	0	6450
24	तमिलनाडु	3434	-	0	3612
25	तेलंगाना	7843	1715	0	0
26	त्रिपुरा	1215	27	0	25
27	उत्तरप्रदेश	4988	210	0	0
28	उत्तराखंड	10647	-	0	25000
29	पश्चिम बंगाल	13740	1026	0	500
	कुल	**233932**	**13651**	**116**	**152845**

टिप्पणियां 1. सीएसएफ और जीआरएफ कुछ राज्य सरकारों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के पास रखी गई आरक्षित निधियां हैं।
2. एटीबी में प्राथमिक बाजार में राज्य सरकारों द्वारा निवेश किए गए 91 दिनों, 182 दिनों और 364 दिनों के खजाना बिल शामिल हैं।
3. - : लागू नहीं (योजना का सदस्य नहीं)।

सं. 49: राज्य सरकारों की बाजार उधारियाँ

(₹ करोड़)

क्र.सं.	राज्य	2022-23		2023-24		2024-25						2024-25 में अब तक जुटाई गई कुल राशि	
						अक्तू		नवं		दिसं			
		ली गई सकल राशि	ली गई निवल राशि	ली गई सकल राशि	ली गई निवल राशि	ली गई सकल राशि	ली गई निवल राशि	ली गई सकल राशि	ली गई निवल राशि	ली गई सकल राशि	ली गई निवल राशि	सकल	निवल
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	आंध्र प्रदेश	57478	45814	68400	55330	6000	4000	4000	2000	4237	3237	58237	40155
2	अरुणाचल प्रदेश	559	389	902	672	-	-	400	400	395	315	795	569
3	असम	17100	16105	18500	16000	1500	1000	-	-500	1800	1100	11050	8400
4	बिहार	36800	27467	47612	29910	8000	3000	6000	3000	6000	3500	32000	19422
5	छत्तीसगढ़	2000	-2287	32000	26213	3000	2300	-	-	-	-	6500	3000
6	गोवा	1350	500	2550	1560	200	100	200	100	-	-	1050	250
7	गुजरात	43000	28300	30500	11947	1500	-500	3000	1000	4500	2000	13500	3000
8	हरियाणा	45158	28638	47500	28364	1500	750	4000	3500	2000	1150	27000	19870
9	हिमाचल प्रदेश	14000	11941	8072	5856	600	200	500	300	1000	900	6700	4750
10	जम्मू और कश्मीर	8473	5969	16337	13904	400	-40	400	400	1600	1600	11750	10410
11	झारखंड	4000	-155	1000	-2505	-	-	-	-	-	-750	-	-750
12	कर्नाटक	36000	26000	81000	63003	20000	18000	4000	1500	16000	13500	43000	29500
13	केरल	30839	15620	42438	26638	2745	1245	2249	1249	2755	2455	32002	19802
14	मध्य प्रदेश	40158	26849	38500	26264	5000	4000	5000	4250	5000	4250	30000	22900
15	महाराष्ट्र	72000	42815	110000	79738	3000	600	-	-2700	-	-3100	67000	41700
16	मणिपुर	1422	1147	1426	1076	200	-	-	-	200	200	1000	740
17	मेघालय	1753	1356	1364	912	197	197	-	-	635	535	1882	1294
18	मिज़ोरम	1315	1129	901	641	50	50	80	60	140	40	811	581
19	नगालैंड	1854	1199	2551	2016	-	-	-	-150	250	250	550	200
20	उड़ीसा	0	-7500	0	-4658	-	-500	1000	1000	-	-	1000	-500
21	पुदुचेरी	1200	698	1100	475	300	300	-	-100	350	350	900	500
22	पंजाब	45500	33660	42386	29517	3150	3150	387	387	2500	2200	32930	28176
23	राजस्थान	46057	30110	73624	49718	7000	5230	4265	3015	4800	3800	52565	36483
24	सिक्किम	1414	1320	1916	1701	1000	1000	-	-	-	-	1000	870
25	तमिलनाडु	87000	65722	113001	75970	8000	3150	9025	5400	11000	10000	78025	53175
26	तेलंगाना	40150	30922	49618	39385	4500	3700	1000	200	3500	2500	40500	31982
27	त्रिपुरा	0	-645	0	-550	-	-	-	-	-	-	-	-
28	उत्तरप्रदेश	55612	41797	97650	85335	3000	24	6000	3500	12000	8422	21000	7713
29	उत्तराखंड	3200	1450	6300	3800	500	500	500	500	1000	-	3400	2400
30	पश्चिम बंगाल	63000	42500	69910	48910	3500	2000	3000	1000	7000	5000	38000	22900
	कुल	758392	518829	1007058	717140	84842	53457	55006	29311	88662	63454	614147	409492

- : शून्य।

टिप्पणी: 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर राज्य संवैधानिक रुप से मौजूद नहीं है और उस राज्य की देयताएं जम्मू और कश्मीर के नए केंद्र शासित प्रदेश की देयताओं के रूप में बनी हुई हैं।

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक।

सं.50 (ए): हाउसहोल्ड की वित्तीय आस्तियों और देयताओं का प्रवाह- लिखत-वार

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	2021-22				
	ति1	ति2	ति3	ति4	वार्षिक
निवल वित्तीय आस्तियां(I-II)	**3,42,813**	**3,30,490**	**4,85,203**	**5,54,816**	**17,13,322**
जीडीपी का प्रतिशत	***6.6***	***5.9***	***7.7***	***8.5***	***7.3***
I. वित्तीय आस्तियां	**3,63,395**	**5,25,419**	**8,16,484**	**9,07,366**	**26,12,664**
जीडीपी का प्रतिशत	***7.0***	***9.3***	***13.0***	***13.9***	***11.1***
जिसमें:					
1. कुल जमाराशियां (ए+बी)	**(81,064)**	**2,04,486**	**4,28,035**	**2,83,634**	**8,35,091**
(ए) बैंक जमाराशि	**(1,06,429)**	**1,97,105**	**4,22,393**	**2,70,025**	**7,83,094**
i. वाणिज्यिक बैंक	(1,07,941)	1,95,442	4,18,267	2,62,326	7,68,094
ii. सहकारी बैंक	1,512	1,663	4,126	7,699	15,000
(बी) गैर-बैंक जमाराशियां	**25,365**	**7,380**	**5,642**	**13,610**	**51,997**
जिसमें से:					
अन्य वित्तीय संस्थान (i+ii)	**17,555**	**(435)**	**(2,178)**	**5,770**	**20,712**
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां	5,578	(1,371)	73	4,021	8,302
ii. आवास वित्त कंपनियां	11,977	936	(2,252)	1,748	12,410
2. जीवन बीमा निधियाँ	**1,15,539**	**1,28,277**	**1,04,076**	**1,38,998**	**4,86,889**
3. भविष्य और पेंशन निधि (पीपीएफ़ सहित)	**1,24,971**	**1,12,810**	**95,493**	**2,18,719**	**5,51,993**
4. मुद्रा	**1,28,660**	**(68,631)**	**62,793**	**1,46,845**	**2,69,667**
5. निवेश	**24,884**	**82,260**	**69,715**	**50,926**	**2,27,785**
जिसमें:					
(ए) म्यूचुअल फंड	14,573	63,151	37,912	44,964	1,60,600
(बी) इक्विटी	4,502	13,218	27,808	3,084	48,613
6. अल्प बचत (पीपीएफ़ छोड़ कर)	**50,405**	**66,218**	**56,372**	**68,243**	**2,41,238**
II. वित्तीय देयताएँ	**20,583**	**1,94,929**	**3,31,281**	**3,52,550**	**8,99,343**
जीडीपी का प्रतिशत	***0.4***	***3.5***	***5.3***	***5.4***	***3.8***
ऋण/ उधार					
1. वित्तीय निगम (ए+बी)	**20,479**	**1,94,825**	**3,31,178**	**3,52,446**	**8,98,928**
(ए) बैंकिंग क्षेत्र	**21,428**	**1,38,720**	**2,67,955**	**2,74,181**	**7,02,284**
जिसमें:					
i. वाणिज्यिक बैंक	26,979	1,40,269	2,65,271	3,37,010	7,69,529
(बी) अन्य वित्तीय संस्थान	**(949)**	**56,105**	**63,223**	**78,266**	**1,96,644**
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	(8,708)	30,151	32,177	40,003	93,623
ii. आवास वित्त कंपनियाँ	7,132	24,404	29,495	37,436	98,467
iii. बीमा कंपनियाँ	627	1,550	1,551	827	4,554
2. गैर-वित्तीय निगम (निजी कॉरपोरेट व्यापार)	**34**	**34**	**34**	**34**	**135**
3. सामान्य सरकार	**70**	**70**	**70**	**70**	**279**

सं.50 (ए): हाउसहोल्ड की वित्तीय आस्तियों और देयताओं का प्रवाह- लिखत-वार (जारी)

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	2022-23				
	ति1	ति2	ति3	ति4	वार्षिक
निवल वित्तीय आस्तियां(I-II)	**2,89,980**	**2,99,395**	**2,96,132**	**4,54,240**	**13,39,748**
जीडीपी का प्रतिशत	***4.5***	***4.6***	***4.3***	***6.4***	***5.0***
I. वित्तीय आस्तियां	**5,79,958**	**6,34,471**	**7,50,245**	**9,71,526**	**29,36,200**
जीडीपी का प्रतिशत	***8.9***	***9.8***	***10.9***	***13.6***	***10.9***
जिसमें:					
1. कुल जमाराशियां (ए+बी)	**1,85,429**	**3,17,361**	**2,80,233**	**3,25,853**	**11,08,876**
(ए) बैंक जमाराशि	**1,63,172**	**2,99,533**	**2,56,400**	**3,07,867**	**10,26,971**
i. वाणिज्यिक बैंक	1,58,613	3,00,565	2,48,460	2,84,968	9,92,606
ii. सहकारी बैंक	4,559	(1,032)	7,940	22,899	34,365
(बी) गैर-बैंक जमाराशियां	**22,257**	**17,829**	**23,833**	**17,986**	**81,905**
जिसमें से:					
अन्य वित्तीय संस्थान (i+ii)	**6,505**	**2,077**	**8,082**	**2,234**	**18,897**
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां	4,231	3,267	3,247	3,946	14,690
ii. आवास वित्त कंपनियां	2,274	(1,191)	4,835	(1,712)	4,207
2. जीवन बीमा निधियाँ	**73,298**	**1,51,677**	**1,67,522**	**1,56,613**	**5,49,109**
3. भविष्य और पेंशन निधि (पीपीएफ़ सहित)	**1,48,915**	**1,20,367**	**1,38,584**	**2,18,709**	**6,26,575**
4. मुद्रा	**66,439**	**(54,579)**	**76,760**	**1,48,990**	**2,37,610**
5. निवेश	**51,503**	**48,530**	**49,779**	**64,151**	**2,13,962**
जिसमें:					
(ए) म्यूचुअल फंड	35,443	44,484	40,206	58,955	1,79,088
(बी) इक्विटी	13,561	1,378	6,434	1,665	23,038
6. अल्प बचत (पीपीएफ़ छोड़ कर)	**54,375**	**51,115**	**37,368**	**57,211**	**2,00,068**
II. वित्तीय देयताएँ	**2,89,978**	**3,35,076**	**4,54,113**	**5,17,285**	**15,96,452**
जीडीपी का प्रतिशत	***4.5***	***5.2***	***6.6***	***7.3***	***5.9***
ऋण/ उधार					
1. वित्तीय निगम (ए+बी)	**2,89,781**	**3,34,880**	**4,53,917**	**5,17,089**	**15,95,667**
(ए) बैंकिंग क्षेत्र	**2,34,235**	**2,63,450**	**3,70,783**	**3,83,845**	**12,52,313**
जिसमें:					
i. वाणिज्यिक बैंक	2,30,284	2,61,265	3,68,305	3,31,293	11,91,146
(बी) अन्य वित्तीय संस्थान	**55,546**	**71,429**	**83,134**	**1,33,244**	**3,43,354**
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	30,532	36,650	55,792	94,565	2,17,539
ii. आवास वित्त कंपनियाँ	22,337	33,031	24,903	36,746	1,17,017
iii. बीमा कंपनियाँ	2,678	1,748	2,439	1,933	8,798
2. गैर-वित्तीय निगम (निजी कॉरपोरेट व्यापार)	**34**	**34**	**34**	**34**	**135**
3. सामान्य सरकार	**163**	**163**	**163**	**163**	**650**

सं.50 (ए): हाउसहोल्ड की वित्तीय आस्तियों और देयताओं का प्रवाह- लिखत-वार (समाप्त)

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	2023-24				
	ति1	ति2	ति3	ति4	वार्षिक
निवल वित्तीय आस्तियां(I-II)	**3,53,093**	**2,89,675**	**2,98,111**	**6,11,366**	**15,52,245**
जीडीपी का प्रतिशत	***5.0***	***4.1***	***3.9***	***7.8***	***5.3***
I. वित्तीय आस्तियां	**6,74,763**	**8,15,842**	**8,08,779**	**11,32,130**	**34,31,514**
जीडीपी का प्रतिशत	***9.6***	***11.5***	***10.7***	***14.5***	***11.6***
जिसमें:					
1. कुल जमाराशियां (ए+बी)	**2,68,925**	**4,12,388**	**2,99,372**	**4,10,559**	**13,91,244**
(ए) बैंक जमाराशि	**2,55,249**	**5,06,208**	**2,79,872**	**3,94,573**	**14,35,902**
i. वाणिज्यिक बैंक	2,46,079	5,06,700	2,82,537	3,87,313	14,22,629
ii. सहकारी बैंक	9,170	(492)	(2,665)	7,260	13,273
(बी) गैर-बैंक जमाराशियां	**13,676**	**(93,820)**	**19,499**	**15,986**	**(44,658)**
जिसमें से:					
अन्य वित्तीय संस्थान (i+ii)	**(485)**	**(1,07,982)**	**5,338**	**1,825**	**(1,01,305)**
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां	6,119	4,782	4,896	1,943	17,740
ii. आवास वित्त कंपनियां	(6,605)	(1,12,764)	442	(118)	(1,19,045)
2. जीवन बीमा निधियाँ	**1,58,358**	**1,41,413**	**1,61,192**	**1,30,036**	**5,90,999**
3. भविष्य और पेंशन निधि (पीपीएफ़ सहित)	**1,63,508**	**1,48,178**	**1,53,255**	**2,53,719**	**7,18,661**
4. मुद्रा	**(48,636)**	**(36,701)**	**56,719**	**1,46,644**	**1,18,026**
5. निवेश	**41,409**	**73,060**	**79,633**	**1,08,732**	**3,02,834**
जिसमें:					
(ए) म्यूचुअल फंड	32,086	55,769	60,135	90,973	2,38,962
(बी) इक्विटी	3,757	7,146	9,941	8,236	29,080
6. अल्प बचत (पीपीएफ़ छोड़ कर)	**91,198**	**77,504**	**58,607**	**82,441**	**3,09,751**
II. वित्तीय देयताएँ	**3,21,670**	**5,26,167**	**5,10,667**	**5,20,764**	**18,79,269**
जीडीपी का प्रतिशत	***4.6***	***7.4***	***6.7***	***6.7***	***6.4***
ऋण/ उधार					
1. वित्तीय निगम (ए+बी)	**3,21,520**	**5,26,016**	**5,10,516**	**5,20,613**	**18,78,666**
(ए) बैंकिंग क्षेत्र	**2,13,606**	**8,68,874**	**4,02,647**	**3,92,330**	**18,77,458**
जिसमें:					
i. वाणिज्यिक बैंक	2,08,027	8,75,654	3,89,898	3,82,558	18,56,136
(बी) अन्य वित्तीय संस्थान	**1,07,914**	**(3,42,858)**	**1,07,869**	**1,28,283**	**1,208**
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	81,449	59,684	85,032	1,00,836	3,27,001
ii. आवास वित्त कंपनियाँ	23,784	(4,04,294)	21,233	25,853	(3,33,424)
iii. बीमा कंपनियाँ	2,681	1,753	1,604	1,594	7,631
2. गैर-वित्तीय निगम (निजी कॉरपोरेट व्यापार)	**34**	**35**	**35**	**35**	**138**
3. सामान्य सरकार	**116**	**116**	**116**	**116**	**465**

टिप्पणियां: 1. हाउसहोल्ड की निवल वित्तीय बचत से तात्पर्य निवल वित्तीय परिसपंत्तियों से है, जिन्हें वित्तीय परिसपंत्ति और देयताओं के प्रवाह के बीच अतंर के रूप में मापा जाता है।

2. 2023-24 के लिए प्रारंभिक अनुमान और 2020-21 और 2022-23 के लिए संशोधित अनुमान।
3. एनएसओ द्वारा राष्ट्रीय आय, उपभोग व्यय, बचत और पूंजी निर्माण, 2023-24 के पहले संशोधित अनुमान जारी होने के साथ 2023-24 के प्रारंभिक अनुमानों में संशोधन किया जाएगा।
4. अन्य वित्तीय संस्थानों के अलावा गैर-बैंक जमा में राज्य ऊर्जा उपयोगिताएँ, सहकारी गैर-ऋण समितियाँ आदि शामिल हैं।
5. संभव है कि पूर्णांकन के कारण कॉलम के आंकड़ों का जोड़ कुल के बराबर न हो।

50(बी): हाउसहोल्ड के वित्तीय आस्तियों और देयताओं का स्टॉक- चुनिंदा संकेतक

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	जून-2021	सितं-2021	दिसं-2021	मार्च-2022
वित्तीय आस्तियां (ए+बी+सी+डी+ई+एफ़+जी+एच)	**2,33,27,377**	**2,39,99,280**	**2,47,08,474**	**2,54,40,650**
जीडीपी का प्रतिशत	**110.4**	**108.9**	**108.2**	**107.8**
(ए) बैंक जमाराशियाँ (i+ii)	**1,07,90,832**	**1,09,87,937**	**1,14,10,330**	**1,16,80,355**
i. वाणिज्यिक बैंक	99,53,044	1,01,48,486	1,05,66,753	1,08,29,079
ii. सहकारी बैंक	8,37,788	8,39,451	8,43,577	8,51,276
(बी) गैर-बैंक जमा				
जिसमें से:				
अन्य वित्तीय संस्थान	**2,06,509**	**2,06,074**	**2,03,896**	**2,09,665**
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	67,840	66,469	66,542	70,564
ii. आवास वित्त कंपनियाँ	1,38,669	1,39,605	1,37,353	1,39,102
(सी) जीवन बीमा निधि	**49,29,725**	**51,42,279**	**52,13,527**	**53,57,350**
(डी) मुद्रा	**27,42,897**	**26,74,266**	**27,37,059**	**28,83,904**
(ई) म्यूचुअल फंड	**18,55,000**	**20,64,364**	**21,26,112**	**21,52,141**
(एफ) सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ)	**7,57,398**	**7,62,264**	**7,67,287**	**8,34,148**
(जी) पेंशन निधि	**6,16,517**	**6,67,379**	**6,99,173**	**7,36,592**
(ज) लघु बचत (पीपीएफ को छोड़कर)	**14,28,499**	**14,94,717**	**15,51,089**	**15,86,496**
वित्तीय देयताएँ (ए+बी)	**77,43,630**	**79,38,456**	**82,69,633**	**86,22,079**
जीडीपी का प्रतिशत	**36.6**	**36.0**	**36.2**	**36.5**
ऋण/ उधार				
(ए) बैंकिंग क्षेत्र	**61,80,377**	**63,19,097**	**65,87,052**	**68,61,233**
जिसमें:				
i. वाणिज्यिक बैंक	56,47,239	57,87,508	60,52,779	63,89,789
ii. सहकारी बैंक	5,31,728	5,30,164	5,32,833	4,69,989
(बी) अन्य वित्तीय संस्थाएँ	**15,63,253**	**16,19,358**	**16,82,581**	**17,60,847**
जिसमें:				
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	7,36,312	7,66,463	7,98,641	8,38,643
ii. आवास वित्त कंपनियाँ	7,21,510	7,45,914	7,75,408	8,12,845
iii.बीमा निगम	1,05,431	1,06,981	1,08,532	1,09,359

50(बी): हाउसहोल्ड के वित्तीय आस्तियों और देयताओं का स्टॉक- चुनिंदा संकेतक (जारी)

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	जून-2022	सितं-2022	दिसं-2022	मार्च-2023
वित्तीय आस्तियां (ए+बी+सी+डी+ई+एफ़+जी+एच)	**2,56,21,348**	**2,64,23,992**	**2,71,87,716**	**2,78,44,981**
जीडीपी का प्रतिशत	**102.8**	**102.6**	**103.2**	**103.3**
(ए) बैंक जमाराशियाँ (i+ii)	**1,18,43,527**	**1,21,43,060**	**1,23,99,459**	**1,27,07,326**
i. वाणिज्यिक बैंक	1,09,87,692	1,12,88,257	1,15,36,717	1,18,21,685
ii. सहकारी बैंक	8,55,835	8,54,803	8,62,742	8,85,641
(बी) गैर-बैंक जमा				
जिसमें से:				
अन्य वित्तीय संस्थान	**2,16,170**	**2,18,247**	**2,26,328**	**2,28,562**
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	74,794	78,061	81,308	85,254
ii. आवास वित्त कंपनियाँ	1,41,376	1,40,185	1,45,020	1,43,308
(सी) जीवन बीमा निधि	**53,25,967**	**55,59,682**	**57,86,593**	**57,95,431**
(डी) मुद्रा	**29,50,343**	**28,95,764**	**29,72,524**	**31,21,514**
(ई) म्यूचुअल फंड	**20,48,097**	**22,60,210**	**23,55,316**	**23,67,793**
(एफ) सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ)	**8,51,913**	**8,58,591**	**8,64,731**	**9,39,449**
(जी) पेंशन निधि	**7,44,459**	**7,96,454**	**8,53,412**	**8,98,343**
(ज) लघु बचत (पीपीएफ को छोड़कर)	**16,40,871**	**16,91,985**	**17,29,353**	**17,86,563**
वित्तीय देयताएँ (ए+बी)	**89,11,861**	**92,46,741**	**97,00,657**	**1,02,17,746**
जीडीपी का प्रतिशत	**35.8**	**35.9**	**36.8**	**37.9**
ऋण/ उधार				
(ए) बैंकिंग क्षेत्र	**70,95,468**	**73,58,918**	**77,29,701**	**81,13,546**
जिसमें:				
i. वाणिज्यिक बैंक	66,20,073	68,81,338	72,49,643	75,80,936
ii. सहकारी बैंक	4,73,897	4,76,025	4,78,487	5,30,915
(बी) अन्य वित्तीय संस्थाएँ	**18,16,393**	**18,87,823**	**19,70,956**	**21,04,201**
जिसमें:				
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	8,69,175	9,05,825	9,61,617	10,56,182
ii. आवास वित्त कंपनियाँ	8,35,181	8,68,213	8,93,116	9,29,862
iii.बीमा निगम	1,12,037	1,13,785	1,16,223	1,18,157

50(बी): हाउसहोल्ड के वित्तीय आस्तियों और देयताओं का स्टॉक- चुनिंदा संकेतक (समाप्त)

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	जून-2023	सितं-2023	दिसं-2023	मार्च-2024
वित्तीय आस्तियां (ए+बी+सी+डी+ई+एफ़+जी+एच)	**2,87,56,851**	**2,96,44,299**	**3,07,47,010**	**3,19,86,847**
जीडीपी का प्रतिशत	**104.6**	**105.4**	**106.6**	**108.3**
(ए) बैंक जमाराशियाँ (i+ii)	**1,29,62,575**	**1,34,68,783**	**1,37,48,656**	**1,41,43,228**
i. वाणिज्यिक बैंक	1,20,67,764	1,25,74,464	1,28,57,001	1,32,44,314
ii. सहकारी बैंक	8,94,811	8,94,319	8,91,655	8,98,914
(बी) गैर-बैंक जमा				
जिसमें से:				
अन्य वित्तीय संस्थान	**2,28,077**	**1,20,095**	**1,25,432**	**1,27,257**
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	91,373	96,156	1,01,051	1,02,994
ii. आवास वित्त कंपनियाँ	1,36,703	23,939	24,381	24,263
(सी) जीवन बीमा निधि	**60,64,437**	**62,55,801**	**65,53,726**	**67,69,272**
(डी) मुद्रा	**30,72,878**	**30,36,177**	**30,92,896**	**32,39,540**
(ई) म्यूचुअल फंड	**26,26,046**	**28,29,859**	**31,56,299**	**33,87,208**
(एफ) सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ)	**9,55,061**	**9,60,344**	**9,64,852**	**10,51,376**
(जी) पेंशन निधि	**9,70,016**	**10,17,975**	**10,91,276**	**11,72,651**
(ज) लघु बचत (पीपीएफ को छोड़कर)	**18,77,761**	**19,55,265**	**20,13,873**	**20,96,314**
वित्तीय देयताएँ (ए+बी)	**1,05,39,266**	**1,10,65,282**	**1,15,75,799**	**1,20,96,412**
जीडीपी का प्रतिशत	**38.3**	**39.3**	**40.2**	**41.0**
ऋण/ उधार				
(ए) बैंकिंग क्षेत्र	**83,27,152**	**91,96,026**	**95,98,673**	**99,91,003**
जिसमें:				
i. वाणिज्यिक बैंक	77,88,962	86,64,616	90,54,514	94,37,072
ii. सहकारी बैंक	5,36,409	5,29,528	5,42,241	5,51,852
(बी) अन्य वित्तीय संस्थाएँ	**22,12,114**	**18,69,256**	**19,77,126**	**21,05,409**
जिसमें:				
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	11,37,631	11,97,315	12,82,347	13,83,183
ii. आवास वित्त कंपनियाँ	9,53,646	5,49,352	5,70,585	5,96,438
iii.बीमा निगम	1,20,837	1,22,590	1,24,194	1,25,788

टिप्पणियाँ:
1. जीडीपी के अनुपात के रूप में डेटा की गणना एनएसओ द्वारा 31 मई 2024 को जारी राष्ट्रीय आय 2023-24 के अनंतिम अनुमान के आधार पर की गई है।
2. पेंशन निधि में राष्ट्रीय पेंशन योजना की निधि शामिल है।
3. लघु बचत के साथ बकाया जमा राशि भारत सरकार के लेखा महानियंत्रक से प्राप्त की जाती है।
4. अन्य वित्तीय संस्थानों के अलावा गैर-बैंक जमा में राज्य ऊर्जा उपयोगिताएँ सहकारी गैर-ऋण समितियाँ आदि शामिल हैं। बकाया जमा के लिए आकंड़े केवल अन्य वित्तीय संस्थानों के लिए उपलब्ध हैं।
5. संभव है कि पूर्णांकन के कारण कॉलम के आंकड़ों का जोड़ कुल के बराबर न हो।

वर्तमान सांख्यिकी की व्याख्यात्मक टिप्पणियां

सारणी सं. 1

1.2 और 6 : वार्षिक आंकड़े महीनों के औसत हैं ।

3.5 और 3.7 : वित्त वर्ष में अब तक वृद्धि के अनुपात से संबंधित है।

4.1 से 4.4, 4.8, 4.9 और 5 : माह/वित्त वर्ष के अंतिम शुक्रवार से संबंधित है।

4.5, 4.6 और 4.7 : माह / वित्त वर्ष के अंतिम शुक्रवार को पांच प्रमुख बैंकों से संबंधित है।

4.10 से 4.12 : माह/ वित्त वर्ष के अंतिम नीलामी दिन से संबंधित है।

4.13 : माह/वित्त वर्ष के अंतिम दिन से संबंधित है।

7.1 और 7.2 : यूएस डॉलर में विदेशी व्यापार से संबंधित है।

सारणी सं. 2

2.1.2 : चुकता पूंजी, आरक्षित निधि और दीर्घावधि परिचालनगत निधि शामिल है।

2.2.2 : नकदी, सावधि जमाराशियाँ और अल्पावधि प्रतिभूतियाँ / बॉण्ड जैसे - आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी, शामिल है।

सारणी सं. 4

http ://nsdp.rbi.org.in के ‘रिज़र्व टैम्पलेट’ के अंतर्गत परिपक्वतावार बकाया फॉर्वर्ड संविदा की स्थिति दर्शायी गयी है।

सारणी सं. 5

अन्य अर्थात एक्सिम बैंक को विशेष पुनर्वित्त सुविधा 31 मार्च 2013 से बंद है।

सारणी सं. 6

अनुसूचित बैंकों के लिए, मार्च की समाप्ति के आंकडे रिपोर्टिंग अंतिम शुक्रवार से संबंधित हैं।

2.2 : आईएमएफ खाता सं. 1 की शेष राशि, आरबीआई कर्मचारी भविष्य निधि, पेंशन निधि, उपदान और अधिवर्षिता निधि शामिल नहीं हैं।

सारणी सं. 7 और 11

सारणी 7 में 3.1 और सारणी 11 में 2.4 : आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में निर्दिष्ट बॉण्ड शामिल हैं

सारणी सं. 8

एनएम$_2$ और एनएम$_3$ में एफसीएनआर (बी) जमाराशियां शामिल नहीं हैं।

2.4 : चुकता पूंजी और आरक्षित राशि शामिल हैं।

2.5 : बैंकिंग प्रणाली की अन्य मांग और मीयादी देयताएं शामिल हैं।

सारणी सं. 9

वित्तीय सस्थाओं में एक्जिम बैंक, सिडबी, नाबार्ड और एनएचबी शामिल हैं।

एल$_1$ और एल$_2$ मासिक आधार पर और एल$_3$ तिमाही आधार पर संकलित किए जाते हैं।

जहां आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, वहां अंतिम उपलब्ध आंकड़े पुनः दिए गए हैं।

सारणी सं. 13

कॉलम सं. (1) (2) और (3) में दर्शाये गए आंकड़े अंतिम और कॉलम सं. (4) और (5) में दर्शाए गए आंकड़े अनंतिम हैं।

सारणी सं. 14

कॉलम सं. (4) और (8) में दर्शाए गए आंकड़े अनंतिम हैं।

सारणी सं. 17

2.1.1 : राज्य सहकारी बैंकों में सहकारी सोसाइटियों द्वारा अनुरक्षित आरक्षित निधि शामिल नहीं है।

2.1.2 : आरबीआई, एसबीआई, आईडीबीआई, नाबार्ड, अधिसूचित बैंकों और राज्य सरकारों से लिए गए ऋण शामिल नहीं है।

4: आईडीबीआई और नाबार्ड से लिए गए ऋण शामिल हैं।

सारणी सं. 24

प्राथमिक व्यापारियों में, प्राथमिक व्यापारी का कारोबार करने वाले बैंक शामिल हैं।

सारणी सं. 30

प्राइवेट प्लेसमेंट और बिक्री के प्रस्ताव शामिल नहीं हैं

1 : बोनस शेयर शामिल नहीं हैं।

2 : संचयी परिवर्तनीय अधिमान शेयर और इक्वी - अधिमान शेयर शामिल हैं।

सारणी सं. 32

आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में निर्दिष्ट बॉण्डों में निवेश, भारत सरकार द्वारा रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया को अंतरित एसडीआर तथा सार्क और एसीयू करेंसी स्वैप व्यवस्था के अंतर्गत प्राप्त विदेशी मुद्रा शामिल नहीं हैं। अमेरिकी डॉलर में दिखाई गई विदेशी मुद्रा आस्तियों में रिज़र्व में रखी गैर यूएस मुद्राओं (जैसे यूरो, स्टर्लिंग, येन और ऑस्ट्रेलिया डॉलर) के मूल्यवृद्धि/मूल्यह्रास के लिए शामिल किया गया है। विदेशी मुद्रा धारिता को रुपया - अमेरिकी डॉलर आरबीआई धारिता दरों पर रुपए में परिवर्तित किया गया है।

सारणी सं. 34

1.1.1.1.2 और 1.1.1.1.1.4 : अनुमान

1.1.1.2 : नवीनतम माह के लिए अनुमान

'अन्य पूंजी' एफडीआई उद्यम की मूल और अनुषंगी संस्थाओं / शाखाओं के बीच के ऋण सबंधी लेनदेन से संबंधित है।

हो सकता है कि सूचना देने में हुए समय अंतराल के कारण ये आँकड़े भुगतान संतुलन के आंकड़ों से मेल न खाएं।

सारणी सं. 35

1.10 : पत्र-पत्रिकाओं के लिए अभिदान, विदेश में किए गए निवेशों का अनुरक्षण, छात्र ऋण चुकौती और क्रेडिट कार्ड भुगतान जैसी मदें शामिल हैं।

सारणी सं. 36

सूचकांकों में वृद्धि रुपये की मूल्यवृद्धि और विपरीत क्रम का संकेतक है। 6- मुद्राओं वाले सूचकांक के लिए, आधार वर्ष 2021-22 अस्थिर है जिसे प्रत्येक वर्ष अद्यतित किया जाता है। रीर के आंकड़े उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (संयुक्त) पर आधारित है। नीर//रीर सूचकांकों के संकलन के लिए उपयोग की जाने वाली कार्यप्रणाली का ब्यौरा आरबीआई बुलेटिन के दिसंबर 2005, अप्रैल 2014 और जनवरी 2021 के अंक में उपलब्ध है।

सारणी सं. 37

ईसीबी/विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉण्डों (एफसीसीबी) के लिए आवेदनों पर आधारित जिन्हें उस अवधि के दौरान ऋण पंजीकरण संख्या दी गई है।

सारणी सं. 38, 39, 40 और 41

इन सारणियों के संबंध में व्याख्यात्मक टिप्पणियां आरबीआई बुलेटिन 2012 के दिसंबर अंक में उपलब्ध हैं।

सारणी सं. 43

भाग I-ए. भुगतान प्रणाली

1.1.3: प्रतिभूति खंड के अंतर्गत त्रिपक्षीय रेपो का परिचालन 05 नवंबर 2018 से किया गया है।

भाग I-बी भुगतान प्रणाली

4.1.2: 'अन्य' में ई-कॉमर्स लेनदेन और एटीएम के माध्यम से डिजिटल बिल भुगतान आदि शामिल हैं।

4.2.2: 'अन्य' में ई-कॉमर्स लेनदेन, कार्ड से कार्ड अंतरण और एटीएम के माध्यम से डिजिटल बिल भुगतान आदि शामिल हैं।

5: दिसंबर 2010 से उपलब्ध है।

5.1: वॉलेट के माध्यम से माल और सेवाओं की खरीद और निधि अंतरण शामिल है।

5.2.2: ऑनलाइन लेनदेन और अन्य लेनदेन के लिए पीपीआई कार्ड का उपयोग शामिल है।

6.1: तीन ग्रिडों से संबंधित - मुंबई, नई दिल्ली और चेन्नई।

6.2: 'अन्य' में गैर-एमआईसीआर लेनदेन शामिल है जो 21 बैंकों द्वारा प्रबंधित समाशोधन गृह से संबंधित है।

भाग II-ए अन्य भुगतान चैनल

1 : मोबाइल भुगतान -

- इसमें बैंकों के मोबाइल ऐप और यूपीआई ऐप के जरिए किए गए लेनदेन शामिल हैं।
- जुलाई 2017 के बाद के डेटा में मोबाइल के माध्यम से शुरू, संसाधित और अधिकृत किए गए केवल व्यक्तिगत भुगतान और कॉरपोरेट भुगतान शामिल हैं। अन्य कॉरपोरेट भुगतान जो मोबाइल के माध्यम से शुरू, संसाधित और अधिकृत नहीं हैं, को शामिल नहीं किया गया है।

2 : इंटरनेट भुगतान - 'नेटबैंकिंग' के माध्यम से केवल ई-कॉमर्स लेनदेन और बैंक की इंटरनेट बैंकिंग वेबसाइट से किया गया वित्तीय लेनदेन शामिल है।

भाग II-बी. एटीएम

3.3 और 4.2: केवल बैंक द्वारा जारी पीपीआई से किए गए लेनदेन से संबंधित है।

भाग III. भुगतान प्रणाली अवसंरचना

3: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) और व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर्स (डब्ल्यूएलएओ) के एटीएम शामिल हैं। डब्ल्यूएलए को अप्रैल 2014 से शामिल किया गया है।

सारणी सं. 45

(-): शून्य/ नगण्य को दर्शाता है।

बुलेटिन के जून 2023 के संस्करण से टेबल फार्मेट संशोधित किया है।

राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (यूडीएवाई) के अंतर्गत जारी विशेष बॉण्ड शामिल हैं।

वाणिज्यिक बैंकों के अंतर्गत बैंक के प्राथमिक डीलरों को शामिल किया गया है। तथापि, कुल बकाया प्रतिभूतियों में इनका हिस्सा बहुत कम है।

'अन्य' श्रेणी में राज्य सरकारें, डीआईसीजीसी, पीएसयू, ट्रस्ट, केंद्रीय विदेशी बैंक, हिंदू अविभक्त परिवार/व्यक्ति आदि शामिल हैं।

सितंबर 2023 के बाद के आंकड़ों में एक बैंक का एक गैर-बैंक के साथ विलय का प्रभाव शामिल है।

सारणी सं. 46

जीडीपी डेटा वर्ष 2011-12 के आधार पर आधारित है। वर्ष 2023-24 के लिए जीडीपी केंद्रीय बज़ट 2023-24 से ली गई है। डेटा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है।
1 और 2: आंकड़े केंद्र सरकार (एनएसएसएफ की पुन: चुकौती सहित) और राज्य सरकार की निवल चुकौती से संबंधित है।
1.3: राज्य द्वारा स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थानों को दिये गये मुआवजे और कार्य से संबंधित है।
2: यह डेटा केंद्र और राज्य सरकारों की उधार प्राप्तियों सहित केंद्र और राज्य सरकारों के नकदी शेष में हुए घटबढ़ से संबंधित निवल को दर्शाते हैं।
3ए.1.1: आंकड़े भारतीय रिज़र्व बैंक के अभिलेख के अनुसार हैं।
3बी. 1.1: दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से उधारियां शामिल हैं।
3बी.1.2: राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएसएफ) की ओर से केंद्र और राज्य सरकारों की विशेष प्रतिभूतियों में किए गए निवल निवेश को दर्शाते हैं।
यह डेटा नए डेटा की उपलब्धता के साथ घटकों में समायोजन के कारण पिछले प्रकाशनों से भिन्न हो सकता है।
3बी. 1.6: केंद्र द्वारा राज्य सरकारों को दिये गये अर्थोपाय अग्रिमों सहित।
3बी. 1.7: खजाना बिल, वित्तीय संस्थानों से ऋण, बीमा और पेंशन निधि, विप्रेषण, नकदी शेष निवेश खाता सहित।

सारणी सं. 47

राज्य सरकारों द्वारा समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ), गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ) और नीलामी खज़ाना बिल (एटीबी) के शेषों तथा सरकारी प्रतिभूतियों में किए गए अन्य निवेशों को संपाश्विक के तौर पर रखते हुए विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ) प्राप्त की जाती है।
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा राज्य सरकारों को उनके अल्पकालिक नकदी असंतुलन से निपटने के लिए अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) दिया जाता है।
राज्य सरकारों को उनकी अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) सीमा से अधिक की आवश्यकता को पूरा करने के लिए ओवरड्राफ्ट दिया जाता है।
प्राप्त कुल सहायता (एसडीएफ / डब्ल्यूएमए / ओडी) को उन दिनों की संख्या से भाग देने पर, जिनके लिए माह के दौरान सहायता प्राप्त हुई, औसत राशि प्राप्त होती है।
-: नगण्य।

सारणी सं. 48

समेकित ऋणशोधन निधि (सीएसएफ) और गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ) वे आरक्षित निधियाँ हैं जो कुछ राज्य सरकारों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के पास रखी जाती हैं।
नीलामी खज़ाना बिलों (एटीबी) में राज्य सरकारों द्वारा प्राथमिक बाज़ारो में निवेश किए गए 91 दिवसीय, 182 दिवसीय तथा 364 दिनों के खज़ाना बिल शामिल हैं।
--: लागू नहीं (इस योजना का सदस्य नहीं है)।

वर्तमान सांख्यिकी के लिए अवधारणाएं और कार्यप्रणाली आरबीआई मासिक बुलेटिन की वर्तमान सांख्यिकी के लिए व्यापक मार्गदर्शिका में उपलब्ध हैं **(https://rbi.org.in/Scripts/PublicationsViewaspx?id=17618)**

'वर्तमान सांख्यिकी' का समय शृंखला डेटा https://data.rbi.org.in पर उपलब्ध है।
विस्तृत व्याख्यात्मक नोट आरबीआई द्वारा जारी प्रासंगिक प्रेस प्रकाशनियों और बैंक के अन्य प्रकाशनों/विज्ञप्तियों जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी पुस्तिका में उपलब्ध हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक के हाल के प्रकाशन

प्रकाशन का नाम	मूल्य	
	भारत में	विदेश में
1. भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन 2025	₹350 एक प्रति ₹250 एक प्रति (रियायती दर*) ₹4,000 (एक वर्ष का सदस्यता शुल्क) ₹3,000 (एक वर्ष रियायती दर*)	15 अमेरिकी डॉलर, एक प्रति 150 अमेरिकी डॉलर (एक वर्ष का सदस्यता शुल्क) (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
2. भारतीय राज्यों से संबंधित सांख्यिकी पुस्तिका 2023-24	₹550 (सामान्य) ₹600 (डाक प्रभार सहित)	24 अमेरिकी डॉलर (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
3. भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी पुस्तिका 2023-24	₹600 (सामान्य) ₹650 (डाक प्रभार सहित) ₹450 (रियायती) ₹500 (रियायती डाक प्रभार सहित)	50 अमेरिकी डॉलर (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
4. राज्य वित्तः 2024-25 के बजटों का अध्ययन	₹600 एक प्रति (कांउटर पर) ₹650 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	24 अमेरिकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
5. मुद्रा और वित्त संबंधी रिपोर्ट 2023-24	₹575 एक प्रति (कांउटर पर) ₹625 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	22 अमेरिकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
6. भारतीय रिज़र्व बैंक सामयिक पेपर खंड 45, सं. 1, 2024	₹200 एक प्रति (कांउटर पर) ₹250 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	18 अमेरिकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
7. पंचायती राज संस्थाओं का वित्त	₹300 एक प्रति (कांउटर पर) ₹350 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	16 अमेरिकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
8. भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति संबंधी रिपोर्ट 2023-24	आरबीआई बुलेटिन जनवरी, 2025 के पूरक के रूप में जारी किया गया।	
9. वार्षिक रिपोर्ट 2023-24	आरबीआई बुलेटिन जून, 2024 के पूरक के रूप में जारी किया गया।	
10. वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट-दिसंबर 2024	आरबीआई बुलेटिन जनवरी, 2025 के पूरक के रूप में जारी किया गया।	
11. मौद्रिक नीति रिपोर्ट - अक्तूबर 2024	आरबीआई बुलेटिन अक्तूबर 2024 में शामिल है।	
12. नगर निगम वित्त पर रिपोर्ट - नवंबर 2024	₹300 एक प्रति (कांउटर पर) ₹350 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	16 अमेरिकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
13. बैंकिंग शब्दावली (अंग्रेजी-हिन्दी)	₹100 एक प्रति (कांउटर पर) ₹150 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	

टिप्पणियां:

1. उपर्युक्त प्रकाशनों में से कई प्रकाशन आरबीआई की वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर उपलब्ध हैं।
2. टाइम सीरीज़ डेटा भारतीय अर्थव्यवस्था के डेटाबेस में उपलब्ध हैं (http://dbie.rbi.org.in) |
3. भारतीय रिज़र्व बैंक का इतिहास 1935-2008 (5 खंड), भारत के प्रमुख पुस्तक भंडारों में उपलब्ध हैं।

* भारत में छात्रों, अध्यापकों / व्याख्याताओं, अकादमिक / शैक्षिक संस्थाओं, सार्वजनिक पुस्तकालयों और पुस्तक विक्रेताओं को रियायत दी जाएगी बशर्ते उन्हें पात्रता प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

सामान्य अनुदेश

1. सभी संचार निम्न को संबोधित किए जाएँ:
   निदेशक, रिपोर्ट और ज्ञान प्रसार प्रभाग,
   आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग (डीआरकेडी, डीईपीआर),
   भारतीय रिज़र्व बैंक, अमर भवन, तल मंजिल,
   सर पी. एम. रोड, फोर्ट, पोस्ट बॉक्स सं. 1036. मुंबई- 400 001
   टेलीफोन: 022-2260 3000 विस्तार: 4002, ईमेल: spsdepr@rbi.org.in

2. बिक्री के लिए प्रकाशन प्रातः 10:30 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक (सोमवार से शुक्रवार) उपलब्ध हैं।

3. प्रकाशनों को कैश ऑन डिलीवरी के आधार पर नहीं दिया जाएगा।

4. एक बार बेचे गए प्रकाशनों को वापस नहीं लिया जाएगा।

5. प्रकाशन के पिछले अंक आम तौर पर उपलब्ध नहीं होते हैं।

6. जहां रियायती मूल्य का संकेत नहीं दिया गया है, भारत में छात्रों, शिक्षकों, शैक्षिक/ अकादमिक संस्थानों, सार्वजनिक पुस्तकालयों और पुस्तक विक्रेताओं के लिए 25 प्रतिशत की छूट उपलब्ध है, बशर्ते पात्रता का प्रमाण प्रस्तुत किया जाए।

7. सदस्यता शुल्क के भुगतान के लिए एनईएफटी को प्राथमिकता दी जाए और भुगतानकर्ता के नाम, सदस्यता संख्या (यदि कोई हो), खाता संख्या, तारीख और राशि सहित लेनदेन विवरण **spsdepr@rbi.org.in** पर ईमेल किया जाए या डाक द्वारा भेजा जाए।

   ए. एनईएफटी ट्रांसफर के लिए अपेक्षित जानकारी इस प्रकार है:

लाभार्थी का नाम	आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग, आरबीआई
बैंक का नाम	भारतीय रिज़र्व बैंक
शाखा और पता	फोर्ट, मुंबई
बैंक शाखा का आईएफएससी	RBIS0MBPA04
खाता प्रकार	चालू खाता
खाता संख्या	41-8024129-19

   बी. गैर- डिजिटल मोड के माध्यम से सदस्यता के मामले में, कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई के नाम पर मुंबई में देय डिमांड ड्राफ्ट/ चेक भेजें।

8. 'प्रकाशन प्राप्त न होने' संबंधी शिकायतें दो माह की अवधि के अंदर भेजी जाएं।